वार्षिक रिपोर्ट
2017-2018

सत्यमेव जयते
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

okf"k/d fjiksV/

2017-18

प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित
विबा प्रेस प्रा. लि., नई दिल्ली-20 द्वारा मुद्रित

सत्यमेव जयते

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

okf'kd fjikVl

2017-18

भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह–2017 के दौरान कलाकारों की सुन्दर प्रस्तुति

विषय सूची

v/;k; l-		i"B l[;k
	वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां	07
1	एक झलक	19
2	मंत्रालय की भूमिका और कार्य	25
3	मंत्रालय की नई पहल	29
4	सूचना क्षेत्र की गतिविधियां	35
5	प्रसारण क्षेत्र की गतिविधियां	95
6	फिल्म क्षेत्र की गतिविधियां	203
7	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	255
8	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण	257
9	मंत्रालय की सेवाओं में दिव्यांग जनों का प्रतिनिधित्व	259
10	राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग	263
11	महिला कल्याण संबंधी गतिविधियां	265
12	सतर्कता संबंधी मामले	267
13	नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र	269
14	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामले	273
15	लेखांकन और आंतरिक लेखा परीक्षा	277
16	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	285
17	कैट के फैसलों/आदेशों पर अमल	287
18	योजना परिव्यय	289
19	मीडिया इकाई–वार बजट	295
20	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सांगठनिक चार्ट	299

तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 30 जून–1 जुलाई, 2017 की मध्यरात्रि को संसद के केन्द्रीय कक्ष में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) का बज़र दबा कर शुभारंभ करते हुए

o"k dh ie[k miyfCèk;k

lpuk [kM

- भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल की समाप्ति की पूर्व संध्या 24 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'सेलेक्टेड स्पीचेज (वॉल्यूम 4) – प्रणब मुखर्जी' का विमोचन किया एवं इसकी पहली प्रति तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय को भेंट की। नव निर्वाचित राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद इस अवसर पर उपस्थित थे। यह खंड पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के चुनिंदा भाषणों की श्रृंखला में चौथा है और इसमें पांच भागों में 161 भाषण संकलित हैं।
- भारत के माननीय उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने 16 नवम्बर 2017 को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर भारतीय प्रेस परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में 'पत्रकारिता में उत्कृष्टता' के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। यह दिन भारतीय प्रेस परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह के समापन का भी था। समारोह में लब्धप्रतिष्ठ पत्रकारों श्री सैम रजप्पा और श्री भारत मिश्र को पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त रूप से 'राजा राम मोहन रॉय' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फ्लैगशिप योजनाओं तथा प्रमुख घटनाओं पर विभिन्न प्रचार माध्यमों के ज़रिए अभियान चलाए, जिनमें निम्न कार्यक्रम शामिल हैं–

- एमओडीआई (मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया) फेस्ट्स तथा 'सबका साथ सबका विकास' (एसएसएसवी) सम्मेलन – सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के अवसर पर देशभर में 27 मई 2017 से 26 जून 2017 की

नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस दिवस (16 नवबंर 2017) के अवसर पर भारतीय प्रेस परिषद के स्वर्ण जयंती समारोहों के समापन पर माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू स्मारिका का लोकार्पण करते हुए। इस अवसर पर माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी भी उपस्थित थीं।

भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के शुभारंभ के अवसर पर माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी और गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ।

अवधि में लगभग 500 विशेष पहुँच कार्यक्रम एवं प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। देश के हर राज्य की राजधानियों में 'साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है' विषय पर 22 प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।

- 'नया भारत मंथन' विषय पर ''संकल्प से सिद्धि' नवाचार–भारत छोड़ो आंदोलन की 75 वीं वर्षगांठ तथा स्वतन्त्रता दिवस समारोह 2017–के उपलक्ष्य में अनेक

सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 29 अगस्त 2017 को उदयपुर (राजस्थान) में, 'नया भारत–हम करके रहेंगे' फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए।

आयोजन किए गए। 'नया भारत संकल्प' के अंतर्गत सभी मंत्रालयों/विभागों ने विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा 'नया भारत– हम करके रहेंगे' विषय पर बनाए गए रचनात्मक पैनल के माध्यम से अपनी उपलब्धियों और कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से देशभर में लगभग 75 विश्वविद्यालयों/संस्थानों में 'ये इंडिया का टाइम है' शीर्षक कार्यक्रम के अंग के रूप में रॉक कंसर्ट्स की श्रृंखला का आयोजन किया।

- oLrq ,oa lsok dj ¼th,lVh½ & 30 जून 2017 को पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट (http://pib.nic.in/gst) पर एक विशेष पृष्ठ शुरू किया गया जो नए कर तंत्र पर सभी वांछित सूचनाओं का मंच है। जीएसटी से सम्बंधित सभी कार्यक्रमों का सभी प्रचार मंचों पर व्यापक प्रचार किया गया जिसमें माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली से बातचीत, 30 जून 2017 की अर्ध–रात्रि को संसद के केंद्रीय सभागार में जीएसटी की राष्ट्रव्यापी शुरुआत, राजस्व सचिव डॉ. हंसमुख अधिया द्वारा जीएसटी की मास्टर

क्लास, जीएसटी रेट फाइंडर एप्प की शुरुआत, जीएसटी कॉन्क्लेव इत्यादि शामिल हैं। 15 सितंबर 2017 से 02 अक्तूबर 2017 तक 'स्वच्छता ही सेवा' (एसएचएस) अभियान के अंतर्गत सूचना भवन की सफाई और रखरखाव के लिए विभिन्न प्रचार एककों के साथ 27 सितंबर 2017 को एक विशेष श्रमदान का आयोजन किया गया। मंत्रालय को 'स्वच्छ भारत अभियान' की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय का पुरस्कार प्राप्त हुआ।

Û rhljk vrjk"Vªh; ;ksx fnol ¼vkbZokbZMh½ 2017–09 जून 2017 को स्वास्थ्य सम्पादकों का सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें योग के लाभ पर प्रस्तुतीकरण दिए गए। इसके बाद योग विशेषज्ञों ने विभिन्न आसनों का जीवंत प्रदर्शन भी किया। आईवाईडी 2017 के बारे में पीआईबी की वेबसाइट पर एक माइक्रो साइट भी बनाई गई।

- *jk"Vªh; ,drk fnol& डीएवीपी ने समाचार पत्रों के लिए विज्ञापन जारी किए और समाचार पत्रों, दूरदर्शन और रेडियो के लिए प्रचार अभियान चलाए। पीआइबी ने एक विशेष वेब पृष्ठ तैयार किया एवं प्रेस और फोटो विज्ञप्तियों के साथ–साथ विशेष लेख भी जारी किए। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी) के संभागीय एककों ने विशेष सम्पर्क (आउटरीच) अभियान कार्यक्रमों का आयोजन किया। सोशल मीडिया मंचों पर व्यापक प्रचार किया गया। पुष्पांजलि (पटेल चौक पर), फोटो प्रदर्शनी (सेन्ट्रल पार्क, कनॉट प्लेस में), रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरी झंडी दिखाने का सीधा प्रसारण और व्यापक प्रचार किया गया तथा देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।

  काला धन निरोधक दिवस, मुद्रा संवर्धन अभियान, पर्यटन पर्व, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, संविधान दिवस, कौमी एकता सप्ताह, हस्तकला सहयोग शिविर इत्यादि को विभिन्न मीडिया एककों द्वारा सभी उपलब्ध मीडिया मंचों पर व्यापक प्रचार एवं कवरेज और विशद संपर्क एवं दृष्यता प्रदान की गई।

- भारत और इथियोपिया के बीच 'सूचना, संचार एवं मीडिया' के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के नागरिकों को अधिक अवसर उपलब्ध करवाने तथा लोक दायित्व विकसित करने के लिए यह समझौता रेडियो, समाचार पत्रों, टीवी और सोशल मीडिया जैसे जन संचार साधनों के उपयोग में सहयोग को प्रोत्साहित करेगा।

- तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू ने 22 मार्च, 2017 को नई दिल्ली में छठे राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए। श्री रघु राय को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार, श्री के. के. मुस्तफा को वर्ष के पेशेवर फोटोग्राफर का पु. रस्कार और श्री रवींद्र कुमार को वर्ष का अमेच्योर फोटोग्राफर पुरस्कार दिया गया। पेशेवर श्रेणी तथा अमेच्योर श्रेणी प्रत्येक में 'विशेष उल्लेख पुरस्कारों' के अंतर्गत पांच–पांच व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर श्री वेंकैया नायडू और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री राज्य वर्धन सिंह राठौर ने छठे राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार की विवरणिका भी जारी की तथा डीएवीपी और फोटो प्रभाग द्वारा लगाई गई एक प्रदर्शनी का भी उद्‌घाटन किया।

- मंत्रालय में स्वच्छता कैलेंडर चलाने के क्रम में सभी प्रकार की रद्दी और कबाड़ के निपटान से लगभग पांच करोड़ रुपये प्राप्त हुए और लगभग 90,000 वर्ग फीट क्षेत्र को मंत्रालय द्वारा सितम्बर 2016 से अगस्त 2017 की अवधि में खाली कराया गया।

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रकाशन विभाग को भारतीय प्रकाशक महासंघ (एफआईपी) द्वारा आयोजित दिल्ली पुस्तक मेला–2017 के दौरान हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के वर्ग में उत्कृष्टता के लिए 11 पुरस्कार तथा योग्यता के 02 प्रमाणपत्र प्राप्त हुए। 'फर्स्ट गार्डन ऑफ द रिपब्लिक' को अंग्रेजी कॉफी टेबल बुक श्रेणी का प्रथम पुरस्कार मिला। 'सांची की गुड़िया' को हिन्दी में बाल पुस्तक श्रेणी और हिंदी पत्रिका 'कुरुक्षेत्र' को गृह पत्रिका श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त हुआ।

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का विवरण आगे दिया जा रहा है:

- तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू ने 16 जून, 2017 को 'कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी' (सीडब्ल्यूएमजी) के 100 पुनर्मुद्रित खण्ड संसद पुस्तकालय के लिए लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन को भेंट किए। मंत्री जी ने इन 100 पुनर्मुद्रित खंडों को साबरमती आश्रम, अहमदाबाद को भी 24 जून, 2017 को आश्रम की स्थापना के शताब्दी समारोहों के अवसर पर भेंट किया। सीडब्ल्यूएमजी महात्मा गांधी के विचारों का ऐसा संकलन है जिसे उन्होंने 1884 से, जब वे 15 वर्ष की आयु के किशोर थे, से 30 जनवरी 1948 को उनके निधन तक बोला और कलमबद्ध किया था।
- 10 अप्रैल, 2017 को चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी समारोहों के अवसर पर जारी की गई 03 स्मारक पुस्तकें हैं : प्रकाशन विभाग द्वारा राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, नई दिल्ली के सहयोग से प्रका. शित 'गांधी इन चम्पारण', 'रोम्यां रोलां एंड गांधी करेसपोडेंस' तथा डी.जी. तेंदुलकर द्वारा लिखित 'महात्मा' श्रृंखला के 08 खंड।
- दुर्लभ पुस्तक 'होमेज टू महात्मा गांधी', जिसमें 30 जनवरी 1948 को गांधीजी की हत्या के बाद आकाशवाणी से प्रसारित श्रद्धाजलियां संकलित हैं, को राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, नई दिल्ली के सहयोग से पुनर्नवीकृत एवं पुनः प्रकाशित किया गया।
- 'द्विभाषी वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ– इंडिया 2018/भारत 2018' जो अपने ई–संस्करणों सहित विभिन्न मंचों पर उपलब्ध है, मुद्रित हो गया है।
- बच्चों में स्वच्छता की आदतों को बढ़ावा देने के लिए 'स्वच्छ जंगल की कहानी, दादी की जुबानी' शीर्षक से 04 मई 2017 को चार पुस्तकों के एक सेट का भी विमोचन किया गया। पुस्तकों के ये सेट 15 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किए गए।
- प्रकाशन विभाग और सस्ता साहित्य मंडल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ताकि देश की युवा पीढ़ी को भारत की समृद्ध एवं विविधतापूर्ण संस्कृति एवं इतिहास से अवगत कराने के उद्देश्य से संयुक्त रूप से पुस्तकों का प्रकाशन किया जा सके।
- प्रकाशन विभाग ने 12वीं योजना के अंतर्गत लगभग 1000 पुस्तकों का डिजिटीकरण करके लक्ष्य से अधिक कार्य संपन्न किया। इस समय इलेक. ट्रॉनिक रूप से पूरी सुगमता से सुलभ 1600 से अधिक डिजिटाइज्ड पुस्तकें हैं। अच्छे साहित्य की उपलब्धता को बढ़ावा भी देगा।
- 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के अंतर्गत प्रकाशन विभाग ने अपनी पुस्तकों के हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाओँ में अनुवाद करवाने का कार्य भी सम्पादित किया है। 12 भारतीय भाषाओं (मूल भाषा को छोड़कर) में लगभग 15 पुस्तको के प्रकाशन का कार्य विभिन्न चरणों में है। 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित भी हो गई हैं।
- अपनी पाठक संख्या में विस्तार के एक प्रयास के रूप में प्रकाशन विभाग ने वर्ष 2017 में सामयिक प्रासंगिक विषयों पर पुस्तक विमर्श कार्यक्रम/सम्मेलनों तथा विचार गोष्ठियों का भी आयोजन किया।
- 01 अगस्त 2017 को भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) ने अपने अमरावती स्थित पश्चिम क्षेत्रीय परिसर से मराठी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत की। इस हेतु भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), नई दिल्ली में हुए उद्घाटन समारोह में स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया।
- चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी समारोहों के अवसर पर गीत एवं नाटक प्रभाग ने मोतिहारी (बिहार), जहां यह सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ था, में कार्यक्रम आयोजित किए। वहां आयोजित कार्यक्रम 'सत्य स्वच्छ सुर' का उद्घाटन बिहार के तत्कालीन राज्यपाल तथा वर्तमान राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने किया। 02 अक्तूबर, 2017 को मोतिहारी में 25,000 के जन. समूह के सामने 'समर यात्रा' नाम से एक बहुत बड़ा ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।
- प्रिंट मीडिया के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, भारत के समा. चार पत्रों के महापंजीयक (आरएनआई) की वार्षिक रिपोर्ट, भारत में प्रेस (प्रेस इन इंडिया) 2016–17 को

प्रधान महानिदेशक श्री के. गणेशन ने 15 दिसंबर, 2017 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी को प्रदान किया। इस रिपोर्ट में प्रकाशन उद्योग की प्रगति, विशेषकर क्षेत्रीय भाषाओं के प्रकाशनों के ढांचे के विकास का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

- क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी) ने सरकार की तीन साल की उपलब्धियां, प्रधानमंत्री की मन की बात, हथकरघा दिवस, नए भारत का मंथन – संकल्प से सिद्धि, स्वच्छता ही सेवा, हस्त कला सहयोग शिविर, राष्ट्रीय एकता दिवस (नेशनल यूनिटी डे) जैसे विषयों पर 317 विशेष सम्पर्क कार्यक्रम (एसओपी) आयोजित किए। स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, कौशल भारत अभियान (स्किल इंडिया मिशन), मिशन इंद्रधनुष, मिशन परिवार विकास, क्षय रोग (टी.बी.) तथा कुष्ठ रोग जैसे विषयों पर भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।
- गीत और नाटक प्रभाग (एसडीडी) ने महत्वपूर्ण विषयों जैसे चम्पारण सत्याग्रह के 100 वर्ष, राज्यसभा दिवस, आजीविका मेला, किसान मेला – बुंदेलखंड सृजन, पुरी, ओडिशा में लोक मेला, नमक सत्याग्रह में ओडिशा का योगदान, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, वित्तीय समावेशन, एनडीए सरकार के तीन वर्ष, संकल्प पर्व, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, विश्व स्तनपान सप्ताह, नया भारत–हम निर्माण का संकल्प लेते हैं प्रदर्शनी, स्वच्छता ही सेवा, ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा, हस्त कला सहयोग शिविर, आतंकवाद विरोधी दिवस, विश्व जन संख्या दिवस, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, श्री अमरनाथ यात्रा 2017, समर यात्रा, भारत–पाक सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रमों जैसे देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए।

çlkj.k [kM

- सूचना एवं प्रसारण तथा वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृ. ति ईरानी ने 'मॉडल फॉर ब्रॉडकास्ट लैंडस्केप फॉर डेमोक्रेसीज' विषय पर 26 अक्तूबर, 2017 को सरदार पटेल स्मारक भाषण देते समय कहा कि श्रोताओं की संख्या का मापन लोकतान्त्रिक तरीके से होना चाहिए। साथ ही उन्होंने इससे सम्बद्ध विभिन्न पक्षों जैसे समाचार प्रसारण में वर्तमान समय में चल रही प्रवृत्तियां, लोक प्रसारक का स्वरूप, मंत्रालय

माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी नई दिल्ली से 26 अक्टूबर 2017 को सरदार पटेल स्मारक व्याख्यानमाला के अंतर्गत 'मॉडल ऑफ ब्रॉडकास्ट लैंडस्कैप फॉर डेमोक्रेसीज' व्याख्यान के प्रसारण के दौरान। इस अवसर पर माननीय सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, प्रसार भारती के अध्यक्ष श्री ए. सूर्यप्रकाश, सूचना और प्रसारण सचिव श्री एन. के. सिन्हा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

द्वारा किए जा रहे प्रयास, इस क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर इत्यादि विषयों पर भी अपनी बात रखी। यह वार्षिक भाषण श्रृंखला सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत आकाशवाणी द्वारा भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में आयोजित की जाती है।

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 236 नगरों में विभिन्न चरणों में 683 चैनलों की नीलामी करवाने के लिए अपनी स्वीकृति दी। इस नीलामी से और अधिक नगरों में एफएम रेडियो के प्रसारण में सहायता मिलेगी। एफएम तृतीय चरण की नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही सभी 29 राज्यों एवं 07 में से 06 केंद्र शासित प्रदेशों (दादर एवं नागर हवेली को छोड़कर) में एफएम रेडियो का प्रसारण निजी प्रसारणकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। इससे पूरे भारत में 10,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा। इन नीलामियों से 1100 करोड़ रुपय से अधिक का राजस्व भी प्राप्त हो सकेगा।
- मंत्रालय ने चरण 3 शहरी क्षेत्रों में एनालॉग संकेत (सिग्नल) बंद कर दिए हैं। केबल टीवी नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 11 के अंतर्गत अब प्राधिकृत अधिकारी अब मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) के उपकरणों को जब्त कर सकते हैं, यदि वे 31 जनवरी 2017 के बाद चरण 3 शहरी क्षेत्रों में एनालॉग संकेत प्रसारण जारी रखे पाए जायेंगे।
- तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू ने 16 जून 2017 को आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कार्यक्रमों की विभिन्न श्रेणियों जैसे नाटक, वृत्तचित्र, संगीतमय प्रस्तुति, बच्चों के समूहगान, राष्ट्रीय एकता के लिए लासा कौल पुरस्कार, युव वाणी, नवाचार कार्यक्रमों, खेती–किसानी सम्बन्धित कार्यक्रम तथा सर्वश्रेष्ठ सीबीएस केंद्रों के लिए डॉ. राजेंद्र कुमार तालिब पुरस्कार के लिए दिए जाते हैं। इस अवसर पर मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि विश्वसनीय एवं प्रमाणित समाचारों के लिए आकाशवाणी लोगों की पहली पसंद है और यह देश की विविधता का द्योतक है। आकाशवाणी से 23 भाषाओं और 179 बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।
- 31 जनवरी 2017 को डिजिटल रेडियो मोंडेल (डीआरएम) तथा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) के सहयोग से डिजिटल रेडियो राउंड टेबल कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। डिजिटल प्रौद्योगिकी से श्रोताओं को किफायती मूल्य पर अच्छी सुधरी हुई ध्वनि के साथ विश्वसनीय सेवाएं उपलब्ध होंगी। रेडियो प्रसारण के डिजिटीकरण चरण में आकाशवाणी ने 37 शक्तिशाली ट्रांसमीटरों की प्रौद्योगिक स्थापना एवं उनका उन्नयन पहले ही पूरा कर लिया है।
- फरवरी 2017 में तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू और यूक्रेन के सांसद तथा नेशनल काउंसिल ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, यूक्रेन के अध्यक्ष श्री इयुरी आर्टेमेंको के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक में यह बताया गया कि दोनों देशों के लोक प्रसारकों के बीच परस्पर आदान–प्रदान, विषय वस्तु तैयार करने, फिल्मों के प्रदर्शन एवं वितरण को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय हर सम्भव सहायता देगा।
- सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री एन.के. सिन्हा ने 07 नवंबर, 2017 को मकाऊ में 'द केबल एंड सैटेलाइट ब्राडकास्टिंग एसोसिएशन ऑफ एशिया (सीएएसबीएए)' की बैठक को सम्बोधित किया जहां यह बताया गया कि संचार एवं विषय वस्तु के लिए प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। उनके भाषण में उल्लिखित विषयों में लोक प्रसारक की महत्वपूर्ण भूमिका और बदलता मीडिया परिदृश्य शामिल है।
- सरकार की विभिन्न उन फ्लैगशिप योजनाओं पर दूरदर्शन ने 14 लघु फिल्में बनाई जिनका लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा जिनसे देश में रूपांतरकारी परिवर्तन हुए। दूरदर्शन की समाचार वेबसाइट (http://ddnews.gov.in) भी शुरू की गई।
- झारखंड के लिए अलग से एक दिन–रात चलने वाले दूरदर्शन चैनल की घोषणा की गई। इस चैनल की शुरुआत होने तक डीडी बिहार, डीडी रांची के लिए प्रसारण करेगा।

- अफगानिस्तान–पाकिस्तान क्षेत्र तक प्रसारण में सक्षम 100 किलोवाट के 02 नए शार्ट वेव सॉलिड स्टेट डिजिटल ट्रांसमीटर्स की भी घोषणा की गई।
- आकाशवाणी संसाधन (एआईआर रिसोर्स) ने 229 चैनलों को चरण 2 से चरण 3 में स्थानांतरित करने के लिए निजी एफएम प्रसारकों से 221 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। एआईआर रिसोर्स ने चरण 3 परियोजनाओं के बैच 1 के अंतर्गत 94 नए आशय पत्रधारियों से आधारभूत संरचना अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बैच 2 के अंतर्गत 43 आशय पत्र (एलओआई) जारी किए है और एआईआर रिसोर्स के साथ 42 आशय पत्रधारियों ने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- दूरदर्शन और दूरदर्शन समाचार ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के देश और विदेश में यात्राओं, संस्कृत और सांकेतिक भाषा में प्रधानमंत्री के मन की बात, 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्वच्छ भारत मिशन की तीसरी वर्षगांठ तथा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के समापन, भारत का 48वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, एफआईएफए अंडर 17 वर्ल्ड कप का उद्घाटन, शिलांग में 'भारत सेवाश्रम' के शताब्दी समारोह, जीएसटी परिषद की बैठक, संकल्प दिवस, नए भारत की परिकल्पना–संकल्प से सिद्धि, एक भारत श्रेष्ठ भारत, हथकरघा दिवस, विभिन्न अवसरों पर विशेष कार्यक्रम, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के विभिन्न विषयों पर हुई बैठकों व सम्मेलनों का व्यापक प्रसारण और प्रचार किया।
- आकाशवाणी (एआईआर) तथा इसके समाचार सेवा प्रभाग (एनएसडी) ने रक्षा प्रतिष्ठापन समारोह, सिविल सेवा दिवस–2017 का पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह, 52वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, 64 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग प्रदर्शन, भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का विदाई समारोह, निर्वाचित राष्ट्रपति महामहिम श्री राम नाथ कोविंद का शपथ ग्रहण समारोह, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के भाषण का प्रसारण, राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह एवं माननीय प्रधानमंत्री का राष्ट्र को सम्बोधन, अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2016, हिंदी दिवस समारोह, स्वच्छ भारत दिवस, वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान (वयोश्रेष्ठ सम्मान 2017), राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार वितरण, 48वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, प्रधानमंत्री की मन की बात, प्रधानमंत्री के विभिन्न भाषण एवं व्यापक प्रसारण किया। समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी की रिपोर्टिंग इकाई, वार्ता एवं करेंट अफेयर इकाई, न्यूजरील इकाई ने विभिन्न विषयों जैसे राष्ट्रीय एकता दिवस, मुद्रा संवर्धन अभियान, पर्यटन पर्व, नया भारत मंथन–संकल्प से सिद्धि, स्वच्छता गतिविधियां, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती समारोह पर विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण शामिल है।

fQYe [kM

- माननीय राष्ट्रपति महोदय ने 03 मई, 2017 को 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2016 प्रदान किए। प्रख्यात फिल्म निर्देशक एवं अभिनेता श्री काशिनाधुनि विश्वनाथ को वर्ष 2016 के लिए 48वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विभिन्न श्रेणियों में प्रमुख पुरस्कार विजेताओं में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी में 'कसाव' और गैर–फीचर फिल्म श्रेणी में 'फायरफ्लाई इन अबिस' रही। सम्पूर्ण मनो. रंजन करने वाली फिल्म के लिए 'सतमानम भवति' को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अक्षय कुमार को 'रुस्तम' फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया जबकि सुश्री सुरभि को मलयालम फिल्म 'मिन्नामिनुगनु–दी फायरफ्लाई' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में पुरस्कृत किया गया। मराठी चलचित्र 'वेंटिलेटर' के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन हेतु राजेश मपुस्कारवास को पुरस्कृत किया गया। अच्छी फिल्म नीति लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वाधिक फिल्म सहयोगी राज्य का पुरस्कार दिया गया वहीं झारखंड को अपनी फिल्म नीति के लिए विशेष उल्लेख से सम्मानित किया गया।

- गोवा में 20 –28 नवंबर, 2017 तक 48 वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआइ) आयोजित किया गया। आईएफएफआई –2017 में 82 देशों की 195 फिल्में प्रदर्शित की गई तथा कई विशेष वर्ग भी थे। 'वर्ष 2017 का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व' वर्ग के विशिष्ट पुरस्कार से प्रख्यात अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया तथा कनाडा के जाने–माने फिल्म निर्देशक श्री एटम इगोयन को 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड' से सम्मानित किया गया। आईएफएफआई–2017 में कनाडा को विशेष केंद्रित देश का स्थान दिया गया तथा बॉलीवुड से फिल्म जगत की जानीमानी हस्तियों ने इस समारोह की शोभा बढ़ाई। उद्घाटन समारोह में सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी और गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर मुख्य अतिथि थे जबकि फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने सभी फिल्म निर्माताओं और प्रतिनिधियों का स्वागत किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी की उपस्थिति में समापन समारोह का संचालन करन जौहर, सोनाली बेंद्रे और जायरा वसीम ने किया जबकि सलमान खान, अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ सदृश प्रख्यात फिल्म व्यक्तित्व समापन समारोह की शोभा बने। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने आईएफएफआई–2017 के लिए गोवा में मीडिया सुविधा केंद्र खोला था जहां से समारोह की कवरेज के लिए 441 मीडिया कर्मियों का प्रत्यायन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई) ने 20–28 नवंबर, 2017 की अवधि के दौरान आईएफएफआई में 'स्त्री – ट्रिब्यूट टू इंडियन वोमेनहुड' विषय पर कला अकादमी, पंजिम में 60 पोस्टरों की एक प्रदर्शनी लगाई। मंत्रालय के विभिन्न मीडिया एककों ने सभी मीडिया मंचों पर आईएफएफआई–2017 का व्यापक एवं विशद प्रचार किया।

भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2017 में अभिनेता श्री शाहरूख खान

- व्यवसाय करने की सुविधा एवं डिजिटल इंडिया के प्रधानमंत्री के स्वप्न को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 27 मार्च, 2017 को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) की ऑनलाइन फिल्म प्रमाणन प्रणाली ई–सिनेप्रमाण शुरू की गई।
- भारत और बांग्लादेश के बीच 'जनसंचार माध्यमों के क्षेत्र में सहयोग' पर समझौता ज्ञापन तथा एक 'श्रव्य–दृश्य सहनिर्माण समझौते पर 08 अप्रैल, 2017 को हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन से जहां दोनों देशों के जनसंचार एवं जनसंपर्क कर्मियों के प्रशिक्षण तथा अध्ययन यात्राओं में सहायता मिलेगी वहीं श्रव्य–दृश्य सह–निर्माण समझौते के अंतर्गत फिल्मों, वृत्तचित्रों तथा एनिमेशन फिल्मों का सह–निर्माण होगा।
- रूसी महासंघ में दूरसंचार एवं जन संचार उप मंत्री, श्री अलेक्सी वोलिन के नेतृत्व में एक रूसी प्रतिनिधिमंडल ने 03 अप्रैल, 2017 को सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर से भेंट की। बैठक में प्रतिनिधिमंडल को मंत्रालय द्वारा हाल में शुरू की गई नई पहलों जैसे फिल्म वीसा, फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) तथा एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग एंड कॉमिक्स (एवीजीसी) के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की प्रस्तावित स्थापना की जानकारी दी गई। दोनों देशों के बीच संभावित सहयोग के क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई।
- दिल्ली में भारतीय पैनोरमा फिल्म समारोह का उद्घाटन हुआ। बोबो खुराइजाम द्वारा निर्देशित वृत्तचित्र 'इमा साबित्री' तथा अक्षय सिंह द्वारा निर्देशित हिंदी फीचर फिल्म 'पिंकी ब्यूटी पार्लर' से समारोह की शुरुआत हुई। समारोह में श्री ओम पुरी के सम्मान में, जिनका जनवरी 2017 में निधन हो गया था, की पांच विशेष फिल्में भी प्रदर्शित की गईं।

- ‘राष्ट्रीय फिल्म विरासत अभियान’ के अंतर्गत फिल्म स्थिति मूल्यांकन परियोजना प्रारम्भ की गई जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए फिल्मों की समृद्ध विरासत उपलब्ध होगी।
- भारत और यूक्रेन ने फिल्म समारोहों के माध्यम और भारत द्वारा स्थापित फिल्म सुविधा कार्यालय मंचों का उपयोग करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है।
- विदेशी फिल्म निर्माताओं के देश में प्रवेश से जुड़े मामलों को सुविधाजनक बनाने के लिए वीसा की एक नई श्रेणी शुरू की गई। फिल्म वीसा और फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) दोनों का ही उद्देश्य भारत को विश्व के समक्ष एक आकर्षक फिल्म गंतव्य के रूप में प्रोत्साहित करना है।
- भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई) ने 28–30 जनवरी, 2017 के दौरान फिल्म समा. रोह निदेशालय (डीएफएफ), भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), सिम्बायोसिस इंटरनेशनल युनिवर्सिटी तथा नॉर्थ–ईस्ट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, पुणे (एनईसीओपी) के सहयोग से एक तीन दिवसीय नॉर्थ–ईस्ट फिल्म फेस्टिवल–फ्रेग. रेंस फ्रॉम दी नॉर्थ–ईस्ट का आयोजन किया। इस समारोह में पिछले वर्षों की पुरस्कृत फिल्मों तथा भारतीय पैनोरमा फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। एक भारत – श्रेष्ठ भारत’ परिकल्पना के अंतर्गत इस फिल्म समारोह को अब से प्रतिवर्ष देश के विभिन्न नगरों में भी आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
- एसोसिएशन ऑफ इंडियन युनिवर्सिटीज (एआईयू) ने फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे के 06 स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को परास्नातक उपाधि (मास्टर्स डिग्री) के समकक्ष मान्यता दी है जिससे अब छात्रों को देश एवं विदेश में अध्ययन के अवसर मिलने लगेंगे। 02 से 03 वर्ष की अवधि के इन कार्यक्रमों में सिनेमैटोग्राफी, सम्पादन, निर्देशन तथा पटकथा–लेखन, ध्वन्यांकन (साउंड रिकॉर्डिंग) और ध्वनि रचना (साउंड डिजाइन), कला–निर्देशन और निर्माण डिजाइन तथा अभिनय सामिल है।
- फिल्म एवं टेलीविजन के क्षेत्र में लघु अवधि पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे और कैनन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। प्रौद्योगिक रूप में कैनन योग्यता–उन्मुखी लघु

माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी पणजी (गोवा) में 28 नवंबर 2017 को भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के समापन समारोह में प्रख्यात फिल्म अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन को ‘फिल्म पर्सनेलिटी ऑफ दि इयर’ सम्मान प्रदान करते हुए।

पाठ्यक्रमों को सहायता देगा। ये लघु पाठ्यक्रम राज्य सरकारों, विश्व विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं की सहभागिता से चलाए जाएंगे।

- भोजपुरी फिल्म समारोह 03–05 फरवरी, 2017 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म कब होइ गवना हमार के साथ ही आईएफएफआई के भारतीय पैनोरमा खंड में चयनित दो फिल्मों, नितिन चंद्रा की 'देशवा' और मंगेश जोशी की फिल्म 'ही' का भी प्रदर्शन किया गया।

- फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) ने देशभर में विभिन्न स्थानों–जोधपुर (राजस्थान), गुरदासपुर (पंजाब), उत्तर गोवा (गोवा), डिब्रूगढ़ (असम), रायगढ़ (महाराष्ट्र), तवांग (अरुणाचल प्रदेश), दीव (दमन और दीव), लुंगलेई (मिजोरम), बीकानेर (राजस्थान), लेह लद्दाख (जम्मू–कश्मीर), राजगीर (बिहार), जबलपुर (मध्य प्रदेष), शिमला (हिमाचल प्रदेश) और चंडीगढ़ (पंजाब) में – देशभक्ति पूर्ण फिल्मों और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' फिल्म समारोहों का आयोजन किया।

- भारत में फिल्म समारोहों में भाग लेने के अतिरिक्त, फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) ने सिंगापुर में एक तीन दिवसीय भारतीय फिल्म समारोह, दिल्ली में एक यूरोपीय फिल्म समारोह, थाईलैंड में फेस्टिवल ऑफ इंडिया–2017, सियोल, (कोरिया गणराज्य) में छठा भारतीय फिल्म समारोह, लाटविया में ए डे ऑफ इंडिया, स्टॉकहोल्म कल्चरल फेस्टिवल में इंडियन फिल्म वीक तथा दिल्ली में सिंगापुर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया। डीएफएफ ने विभिन्न विषयों जैसे 'मेकिंग सिनेमा इंजॉयएबल एक्सपीरिएंस फॉर पर्सन्स विद डिसैबिलिटीज' विषय पर कार्यशाला, दिव्यांगजन सशक्तिकरण लघु फिल्म समारोह–2017, कांकेर, छत्तीसगढ़ में बाल फिल्म समारोह, तिरुअनंतपुरम में भारतीय पैनोरमा फिल्मों के प्रदर्शन हेतु सूर्य फिल्म समारोह, भारतीय पर्यावास केंद्र, नई दिल्ली में पर्यावास फिल्म समारोह, मैसूर में भारतीय पैनोरमा फिल्म समारोह, गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह और रांची, झारखंड में वन्य–जीवन फिल्म समारोह का भी आयोजन किया।

- हैदराबाद, तेलंगाना में 08 –14 नवंबर, 2017 की अवधि में बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई) द्वारा 'न्यू इंडिया' विषय पर भारत के 20वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 55 देशों से 315 फिल्मों की प्रविष्टि का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। इन फिल्मों का प्रदर्शन तेलंगाना राज्य के 43 में से 40 प्रेक्षागृहों (थिएटरों) में किया गया। 'बच्चों की दुनिया' (चिल्ड्रन्स वर्ल्ड) खंड में समारोह के दौरान 233 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। एनिमेशन, फिल्म निर्माण और किस्सागोई पर तीन कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया। विभिन्न विषयों पर विचार–विमर्श करने के लिए बाल फिल्मों, बाल कलाकारों तथा विभिन्न जनसंचार एवं संवाद मंचों पर पेशेवर व्यक्तियों को पैनल सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए तत्सम्बन्धी विषयों पर 05 खुले फोरम आयोजित किए गए।

- सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसटीआरएफआई) ने 15 मई –23 जुलाई, 2017 की अवधि में अपने ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश स्थित अस्थायी परिसर में एक 10 सप्ताह का 'जर्नी टू सिनेमा' लघु पाठ्यक्रम पूरा किया। यहाँ एक नियमित एसटीआरएफआई परिसर का प्रारम्भ करना भी भविष्य में प्रस्तावित है। एसटीआरएफआई में 14 –22 जुलाई, 2017 की अवधि में फिल्म समारोह निदेशालय और एसटीआरएफआई की सहभागिता से एक 9 दिवसीय यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया।

- बांग्लादेश सिनेमा एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट और सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसटीआरएफआई), कोलकाता के बीच छात्रों एवं अकादमी सदस्यों के आदान–प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

- 'भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) की विशेष परियोजना श्रेणी के अंतर्गत कौशल–उन्मुखी लघु अवधि पाठ्यक्रम शुरु करने के लिए जुलाई, 2017 में स्वीकृति प्राप्त हुई थी। नवाचार के अंतर्गत डिजिटल वीडियो सम्पादन के एक लघु अवधि पाठ्यक्रम के एक समूह ने सफलतापूर्वक अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और 03 माह के लघु अवधि पाठ्यक्रम का अगला समूह (बैच) प्रारम्भ हो गया है।

- फिल्म प्रभाग ने जून, 2017 में ज्योति चित्रवन परिसर, कहिलीपाड़ा, गुवाहाटी में गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र समारोह का आयोजन किया।
- वृत्तचित्र, लघु एवं एनिमेशन के लिए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (एमआईएफएफ), 2018 को अति उत्साहवर्धक उत्तर मिले हैं। स्वर्ण एवं रजत शंख पुरस्कार के लिए 792 फिल्में प्रतिस्पर्धा में हैं। इस समारोह का उद्घाटन 28 जनवरी, 2018 को मुंबई स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफार्मिंग आर्ट्स में हुआ है।
- भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे की छात्रा पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित लघु फिल्म 'आफ्टरनून क्लाउड्स' एकमात्र ऐसी भारतीय प्रस्तुति थी जिसे कांस फिल्म समारोह–2017 में प्रदर्शित किया गया था। अभिजीत खुमान द्वारा निर्देशित संस्थान के टीवी खंड के अंतिम कथा चित्र 'कल्पवृक्ष' को सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए प्रतिष्ठित 'रजत कमल' प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार गैर–फीचर फिल्म श्रेणी में इलेक्ट्रॉनिक सिनेमेटोग्राफी के छात्र अल्पेश नागर को भी दिया गया।

गीत और नाटक प्रभाग के कलाकार राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और तत्कालीन माननीय उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी के साथ

1

, d >yd

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय रेडियो, टेलीविजन, फिल्मों, समाचार पत्रों तथा मुद्रित प्रकाशनों, विज्ञापन, संवाद के पारम्परिक साधनों जैसे नृत्य और नाटक के माध्यम से जन सामान्य तक सूचनाओं के निर्बाध संचरण में सहायक बनने के लिए प्रभावशाली भूमिका निभाता है। मंत्रालय विभिन्न आयु वर्गों की मनोरंजन आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा जनमानस का ध्यान राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखरेख और परिवार कल्याण, निरक्षरता उन्मूलन एवं महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों और समाज के वंचित वर्गों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। मंत्रालय 5 खंडों में विभक्त है अर्थात सूचना खंड, प्रसारण खंड, फिल्म खंड, एकीकृत वित्तीय खंड तथा आर्थिक खंड। मंत्रालय अपनी 21 मीडिया एककों/संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, स्वशासी निकायों एवं लोक उपक्रमों के माध्यम से कार्यरत है। मंत्रालय का मुख्य सचिवालय के प्रमुख सचिव होते हैं और उनकी सहायता हेतु एक अतिरिक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार (एएस एंड एफए), एक अतिरिक्त सचिव, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, एक मुख्य लेखा नियंत्रक तथा 4 संयुक्त सचिव होते हैं। मुख्य सचिवालय में 15 पद निदेशक/उप–सचिव/वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव स्तर के, 28 पद अवर सचिव/प्रधान निजी सचिव स्तर के, 37 पद अनुभाग अधिकारी के व 286 पद अराजपत्रित कर्मचारियों के हैं।

भारतीय सूचना सेवा संवर्ग (समूह 'क' एवं 'ख') का प्रबंध भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) अनुभाग देखता है। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद अगस्त, 2016 में प्रधान महानिदेशक के 2 पद, महानिदेशक के 5 पद और अतिरिक्त महानिदेशक के 19 पद सृजित करके संवर्ग समीक्षा लागू की गई है। समन्वित संवाद सहक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए अब मंत्रालय के पास क्षेत्रीय स्तर पर अतिरिक्त महानिदेशक और संभागीय स्तर पर महानिदेशक हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य विशेषज्ञता से सूचना के प्रवाह को केंद्र से राज्यों तक मोड़ना है। इसके लिए नियमित रूप से फीडबैक लेते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि क्षेत्रीय इकाइयां राज्यों में जन सामान्य तक सामयिक एवं प्रभावपूर्ण जानकारी पहुंचाएं। इसका उद्देश्य राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार को सुदृढ़ करने के लिए संयुक्त मीडिया प्रचार अभियान चलाने हेतु

माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी नई दिल्ली में 26 अक्टूबर, 2017 को 'मॉडल ऑफ ब्रॉडकास्ट लैंडस्केप' विषय पर सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान देते हुए।

अपनी सभी मीडिया इकाइयों का पुनर्नवीनीकरण करना है जिससे कि सरकार की योजनाओं के प्रचार को मजबूत किया जा सके।

संयुक्त सचिव (नीति एवं प्रशासन) के अधीन सूचना खंड भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के संवर्ग प्रबंधन, समाचार पत्रों एवं प्रकाशन माध्यमों के नीतिगत मामले, प्रचार आवश्यकताएं, मंत्रालय का सामान्य प्रशासन और सूचना खंड के अधीन आने वाले मीडिया एककों के विषय देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस खंड में निजी इलेक्ट्रॉनिक चैनलों की प्रसारण विषयवस्तु के विनियमन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर से जुड़े मामले, निजी टीवी चैनलों को लाइसेंस दिए जाने और न्यू मीडिया सेल से जुड़े मामले देखे जाते हैं।

संयुक्त सचिव (प्रसारण) के अधीन प्रसार भारती के अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) और कार्यक्रम खंडों के प्रसारण–प्रशासन से जुड़े सभी विषय, प्रसार भारती की प्रसारण विषय–वस्तु एवं प्रसार भर्ती के सभी मामले आते हैं। यह खंड सामुदायिक रेडियो, प्रसारण विकास एवं वित्त, एफएम रेडियो, केबल टीवी का डिजिटीकरण, प्रसारण नीति और कानून निर्माण (सीटीएनए के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता एवं विज्ञापन संहिता) का कार्य भी करता है।

संयुक्त सचिव (फिल्म) के अधीन फिल्म क्षेत्र से जुड़े समस्त विषय आते हैं। यह खंड वृत्त–चित्रों के निर्माण और वितरण, प्रशिक्षण सहित फिल्म उद्योग से सम्बंधित विकास एवं प्रोत्साहन कार्य, फिल्म समारोहों का आयोजन, आयात और निर्यात विनियमन इत्यादि के कार्य देखता है।

एएस एंड एफए के अधीन एकीकृत वित्त शाखा मंत्रालय के वित्तीय पक्ष को देखती है। मुख्य लेखा परीक्षक (सीसीए) और उपसचिव (वित्त) एएस एंड एफए की सहायता करते हैं।

संयुक्त सचिव (आर्थिक शाखा) के अधीन आर्थिक शाखा योजना, बजट, योजना समन्वयन, ओ एंड एम क्रियाकलाप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विषयों की नियमित अंतराल पर मंत्रिमंडल सचिवालय को रिपोर्टिंग के कार्य देखती है।

वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार और आर्थिक सलाहकार द्वारा किए जाने वाले कार्य इस प्रकार हैं:

माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर भारतीय प्रेस परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह के समापन समारोह को संबोधित करते हुए

- प्रभावपूर्ण सहक्रिया और सुपुर्दगी, योजनाओं एवं प्रभाव तथा व्यय के परिप्रेक्ष्य में संकेतकों के सावधिक मूल्यांकन हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सभी मीडिया एककों का एकीकरण, सूचना, प्रसारण और फिल्म क्षेत्रों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की नई पहलों हेतु नीति पत्र और परिकल्पना प्रपत्र तैयार करना तथा प्रसार भारती से जुड़े विषय।
- 'एनआईसी द्वारा मॉड्यूल्स स्ट्रोक मैकेनिज्म के अनुरूप डीएवीपी द्वारा समाचार पत्रों के पीडीएफ संस्करण की नियमितता की जांच, प्रसार संख्या की आकार जांच, आरएनआई के माध्यम से समाचार पत्रों का सत्यापन, सरकार की नीतियों का राज्यों पर हुए प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए अन्तर–प्रचार माध्यम (मीडिया) प्रचार समन्वय समिति (आईएमपीसीसी) के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, सीपीजीआरएएम पोर्टल का अनुश्रवण। 'परिवहन और संचार पर मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा अनुश्रवण किए जा रहे सचिवों के क्षेत्रवार समूह (एसजीओ) से संबंधित कार्य। 'इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईइटीवाई) हेतु अन्तर–मंत्रीय समूह के लिए नोडल अधिकारी तथा नवीन भारत संहिता पोर्टल (न्यू इंडिया कोड पोर्टल) में अधिनियमों और उपनियमों को अपलोड करना। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) की वार्षिक बैठक से संबद्ध विषयों के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा गठित सचिव स्तरीय समिति (एसएलसी) की बैठक। साइबर सुरक्षा संबंधित कार्य।

lpuk ,o çlkj.k e=ky; dk xBu

मंत्रालय को उसके कार्य में 13 संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, 6 स्वायत्त शासी निकायों और 2 लोक उपक्रमों से सहयोग एवं सहायता मिलती है।

lc)@v/khuLFk dk;ky;

1. पत्र सूचना कार्यालय
2. विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय
3. भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक
4. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय
5. प्रकाशन विभाग
6. न्यू मीडिया विंग
7. गीत और नाटक प्रभाग
8. फोटो प्रभाग
9. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर
10. फिल्म प्रभाग
11. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
12. राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय
13. फिल्म समारोह निदेशालय

Lo'kklh fudk;

1. भारतीय प्रेस परिषद
2. भारतीय जन संचार संस्थान
3. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)
4. फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे
5. सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता
6. बाल चलचित्र समिति, भारत

ykd miØe

1. ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
2. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

lpuk ,o çlkj.k e=ky; dk dk;l {k=

- विदेश स्थित भारतीय नागरिकों सहित देशवासियों के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से समाचार सेवाएं
- प्रसारण और टेलीविजन का विकास
- फिल्म उद्योग का विकास एवं संवर्धन
- उद्देश्यों के लिए फिल्म समारोहों और सांस्कृतिक आदान–प्रदान का आयोजन
- भारत सरकार की ओर से विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार और उसका फीडबैक प्राप्त करना
- समाचार पत्रों के सम्बन्ध में प्रेस व पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम, 1867 को लागू करवाना
- फिल्म प्रमाणन के सम्बन्ध में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 को लागू करवाना
- प्रसारण अनुश्रवण तथा प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25वां अधिनियम)
- केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनिमयन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7वां अधिनियम)
- प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37वां अधिनियम) लागू करवाना

- भारतीय सूचना सेवा (समूह 'क' और 'ख') का संवर्ग प्रबंधन
- प्रकाशनों के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर भारत से सम्बंधित सूचनाओं का देश–विदेश में प्रचार प्रसार
- मंत्रालय के माध्यम एककों को अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता
- ऐसे लब्धप्रतिष्ठ कलाकारों, संगीतज्ञों, संगीत उपकरण वादकों, नर्तकों, रंगकर्मियों को वित्तीय सहायता देना जिन्होंने मंत्रालय की संस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।
- प्रसारण एवं समाचार सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

माननीय सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नई दिल्ली में 3 फरवरी, 2017 को भोजपुरी फिल्म समारोह के उद्घाटन के अवसर पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए।

नई दिल्ली में आशियान – भारत स्मारक शिखर सम्मेलन 2018 के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आशियान देशों के नेताओं से विचार विमर्श की दूरदर्शन द्वारा व्यापक कवरेज।

तत्कालीन माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु आकाशवाणी वार्षिक समारोह 2014–15 को नई दिल्ली में 16 जून, 2017 को संबोधित करते हुए

2 e=ky; dh Hkfedk vkj dk;l

सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की निम्नलिखित भूमिका और कार्य हैं:

I- çlkj.k uhfr ,o ç'kklu

1. देश में आकाशवाणी व दूरदर्शन प्रसारण से संबंधित सभी मामले। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनैतिक पार्टियों द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के इस्तेमाल का विनियमन और किसी बड़ी हस्ती के निधन पर राष्ट्रीय शोक के दौरान सरकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया शामिल है।
2. भारतीय निजी कंपनियों या भारतीय नागरिकों द्वारा भारत में रेडियो और टेलीविजन प्रसारण से संबंधित कानून का निरूपण और कार्यान्वयन।
3. प्रसारणों का अनुश्रवण और प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25वां) का क्रियान्वयन।
4. भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा और भारतीय प्रसारण (अभियांत्रिकी) सेवा से संबंधित सभी मामले, जब तक कि वे प्रसार भारती को न सौंप दिए जाएं।

II- dscy Vsyhfotu uhfr

1. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7वां अधिनियम)।

III- vkdk'kok.kh

1. घरेलू कार्यक्रमों, विदेशों के लिए कार्यक्रम और विदेश मे रहने वाले भारतीयों के लिए कार्यक्रम, रेडियो जर्नल्स, प्रसारण अभियांत्रिकी के क्षेत्र में शोध, विदेश प्रसारण की निगरानी, कार्यक्रम विनिमय और प्रति लेखन सेवाएं, सामुदायिक श्रवण योजना के तहत राज्य सरकारों को सामुदायिक रिसीविंग सेट इत्यादि की आपूर्ति के लिए समाचार सेवाओं से जुड़े आकाशवाणी से संबंधित सभी तरह के कार्य।
2. देशभर में रेडियो प्रसारण का विकास, रेडियो स्टेशनों और ट्रांसमीटरों की स्थापना और रखरखाव तथा प्रसारण सेवाओं का संचालन।

IV- njn'ku

1. टेलीविजन कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक तथा अन्य कार्यक्रमों का आदान–प्रदान।

17 सितंबर, 2017 को एफ.एम.टी.एक्स का कोटापुतली (राजस्थान) में माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा उद्‌घाटन

2. देशभर में टेलीविजन का विकास। इसमें दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केंद्रों तथा ट्रांसमीटरों की स्थापना और रखरखाव सहित टीवी सेवाओं का संचालन शामिल है।
3. दूरदर्शन से बाहर टीवी कार्यक्रमों के निर्माण को प्रोत्साहन।

V- fQYe

1. संघ सूची की प्रविष्टि 60 के तहत प्रदर्शनी के लिए 'सिनेमेटोग्राफ फिल्मों की मंजूरी' के प्रावधान पर अमल।
2. सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां) का क्रियान्वयन
3. थियेटरों में और थियेटरों से इतर प्रदर्शन के लिए फीचर और लघु फिल्मों का आयात।
4. फिल्म उद्योग से जुड़े सभी मुद्दे, जिनमें विकास और

प्रसार गतिविधियां भी शामिल हैं।

5. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के जरिए भारत में बनी उत्कृष्ट फिल्मों का प्रसार। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से सहायता।
6. आंतरिक और बाह्य प्रचार के लिए वृत्तचित्रों और न्यूज–रील तथा अन्य फिल्मों और फिल्म स्ट्रिप्स का निर्माण और वितरण।
7. फिल्मों और फिल्म संबंधी सामग्री का संरक्षण।
8. भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भारत की भागीदारी।
9. सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत फिल्म समारोहों का आयोजन।
10. फिल्म समितियों को प्रोत्साहन।

VI- foKkiu vkSj –'; çpkj

1. भारत सरकार की ओर से विज्ञापनों का निर्माण और उन्हें जारी करना और सरकारी विज्ञापनों के लिए विज्ञापन नीति बनाने में मदद करना।

VII- çsl

1. प्रेस के माध्यम से भारत सरकार की गतिविधियों और नीतियों की प्रस्तुति और व्याख्या।
2. प्रेस से संबंधित सूचना समस्याओं पर सरकार को सुझाव देना, प्रेस में नजर आने वाले जनमत के मुख्य मुद्दों पर सरकार को सूचित करते रहना और प्रेस व सरकार के मध्य तालमेल बनाए रखना।
3. सशस्त्र सेनाओं के लिए प्रचार करना।
4. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अनुच्छेद 95 और 96 के प्रावधानों को छोड़कर अन्य मामलों में प्रेस के साथ सरकार के सामान्य संबंधों का निर्धारण।
5. समाचार पत्रों से संबंधित प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25वां) का क्रियान्वयन।
6. प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37वां) का अनुपालन।
7. समाचार पत्रों के लिए न्यूजप्रिंट का आबंटन हेतु

माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह–2017 के समापन समारोह में कनाडा के फिल्म निर्माता अटोम इगोयान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देते हुए

प्रकाशकों के स्व–प्रमाणित दस्तावेजों का सत्यापन।

8. सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित दृश्य प्रचार और फोटो प्रलेखन।

VIII- çdk'ku

1. राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर आंतरिक और बाह्य प्रचार के लिए लोकप्रिय पत्र–पत्रिकाओं और पुस्तकों का प्रकाशन, विपणन और वितरण ताकि देश की आम जनता तथा विदेशों में रहने वालों को भारत के बारे में ताजा और सही सूचनाएं मिलती रहें।

IX- vuql/kku ,oa lanHkZ

1. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इकाइयों को ऐसी सामग्री के संकलन, संग्रहण और प्रकाशन में मदद करना जिसके लिए शोध की आवश्यकता होती है।
2. महत्वपूर्ण विषयों पर ज्ञान के सार–संग्रह की तैयारी करना और मंत्रालय की मीडिया इकाइयों को उपयोग के लिए समसामयिक और अन्य विषयों पर मार्गदर्शन और संदर्भ सामग्री तैयार करना।

X- fofo/k dk;Z

1. भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार।
2. पत्रकारों के कल्याण कोष का संचालन।
3. गायन और वाद्य संगीत, दोनों से संबंधित ऐसे प्रतिष्ठित संगीतकारों, नर्तकों और नाटककारों तथा उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देना जिन्होंने आकाशवाणी और दूसरी मीडिया इकाइयों की सफलता में बड़ा योगदान किया है मगर जो विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं।
4. एशिया–प्रशांत प्रसारण संघ, राष्ट्रमंडल प्रसारण संघ और गुट–निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल से संबंधित सभी मामले।
5. विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों समझौतों/करारों/प्रोटोकॉल से जुड़े सभी मामले यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम (आईपीडीसी) के बजट तथा नामांकन सहित सभी मुद्दे।
6. भारतीय सूचना सेवा (समूह 'क' और 'ख') का संवर्ग प्रबंधन।

माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी म्हास्वाद (महाराष्ट्र) की डॉक्टर मैडम कही जाने वाली सुश्री सुनीता कांबले को नीति आयोग द्वारा नई दिल्ली में 29 अगस्त, 2017 को आयोजित कार्यक्रम में 'वूमेन ट्रांसफॉमिंग इंडिया अवार्ड 2017' प्रदान करते हुए

3

e=ky; dh ubl igy

वर्ष 2017 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं उसके मीडिया एककों ने कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए:

- प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सस्ता साहित्य मंडल ने 14 फरवरी, 2017 को भारत के स्वतंत्रता सेनानियों, सांस्कृतिक नेताओं तथा लब्धप्रतिष्ठ विभूतियों पर पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- 15 मार्च, 2017 को फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे और कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन देश भर में कई नगरों/कस्बों में फिल्म और टेलीविजन के कई लघु अवधि पाठ्यक्रमों के द्वारा फिल्म शिक्षा को प्रोत्साहित करेगा। फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे की अनूठी पहल– फिल्म एवं टेलीविजन के क्षेत्र में भारत को कुशल बनाना (एसकेआईएफटी) के तहत प्रौद्योगिक सहयोगी के रूप में कैनन लघु अवधि पाठ्यक्रमों के लिए उत्कृष्ट कोटि के कैमरा और अन्य सहायक वस्तुऐं निशुल्क उपलब्ध कराएगा। एसकेआईएफटी के अंतर्गत देशभर में राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से कई लघु अवधि पाठ्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे।
- जन संचार और श्रव्य–दृश्य सह –निर्माण समझौते पर भारत और बंगलादेश सरकारों के बीच 08 अप्रैल, 2017 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से दोनों देशों के जन संचार कर्मियों के प्रशिक्षण/अध्ययन यात्राओं में सुविधा होगी और श्रव्य–दृश्य सह–निर्माण समझौते के अंतर्गत फिल्मों, वृत्त चित्रों और एनिमेशन फिल्मों का संयुक्त रूप से निर्माण किया जाएगा।
- प्रकाशन विभाग ने 21 जून, 2017 को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईएनजीसीए) के साथ भारत की कला एवं संस्कृति तथा तत्संबंधी विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए एक समझौते पर

माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई–2017) के उद्घाटन समारोह में

हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार विषय वस्तु सामग्री आईएनजीसीए उपलब्ध कराएगा तथा प्रकाशन विभाग इन पुस्तकों को प्रकाशित करेगा।

- संस्कृत पत्रकारिता में तीन माह का उच्च श्रेणी पाठ्यक्रम संयुक्त रूप से चलाने के लिए भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) और श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (एसएलबीएसआरएसवी) ने 20 मई, 2017 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- भारत सरकार और इथियोपिया की संघीय लोकतान्त्रिक सरकार के बीच 05 अक्टूबर, 2017 को 'सूचना, संचार और मीडिया' के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री राम नाथ कोविंद और इथियोपिया के राष्ट्रपति डॉ. मुलातु तेशोमे की उपस्थिति में हुआ। इस समझौते का उद्देश्य सूचना की बढ़ती शक्ति का उपयोग, सूचना के प्रसार हेतु संचार और मीडिया का उपयोग करना तथा समावेशी विकास के लिए दोनों देशों के बीच सम्पर्क को बढ़ाना है।

- भारत का 48वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई) गोवा में आयोजित किया गया। पहली बार समारोह में जेम्स बॉन्ड की फिल्मों का पुनरावलोकन दिखाया गया। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल द्वारा संरक्षित श्रेष्ठ कथाचित्रों का विशेष खंड और कनाडा पर केंद्रित विशेष फिल्मों का भी इस समारोह में प्रदर्शन किया गया। दूरदर्शन की 16 फिल्मों का इस समारोह में 13–28 नवंबर, 2017 के दौरान प्रदर्शन किया गया। जिन्हें आईएफएफआई की अत्यधिक सफल फिल्मों के रूप में प्रस्तुत किया गया। अनेक बेजोड़ श्रेष्ठ फिल्में भी दिखाई गई और पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं। पुरस्कार विजेताओं की फिल्मों के पुनरावलोकन भी हुए। कार्यक्रमों में भारतीय फिल्म कलाकारों की भागीदारी रही।

- तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू ने मंत्रालय की विभिन्न पहलों पर उत्तर पूर्व (गुवाहाटी), हरियाणा (चंडीगढ़), कर्नाटक (बंगलुरु), उत्तर प्रदेश (लखनऊ), तमिलनाडु (चेन्नई), झारखंड (रांची), राजस्थान (जयपुर), छत्तीसगढ़ (रायपुर), महाराष्ट्र (मुंबई), उत्तराखंड (देहरादून) तथा केंद्र शासित प्रदेश (दिल्ली) में विभिन्न मीडिया एककों के साथ समीक्षा बैठकें की। बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में चैनल डीडी छत्तीसगढ़ और डीडी झारखंड की घोषणा, छत्तीसगढ़ में तीन नए एफएम स्टेशन खोलना, एक वर्ष के भीतर उत्तराखंड के लिए 24x7 डीडी चैनल, महाराष्ट्र में भारतीय जन संचार संस्थान के क्षेत्रीय परिसर हेतु स्थान के चुनाव को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में तेजी लाना, विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में जन सम्पर्क तथा स्थानीय संस्कृति और प्रतिभाओं के लिए कार्यक्रम विकसित करना शामिल है।

- स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत मंत्रालय ने स्वयं अपने लिए तथा विभिन्न एककों के लिए निर्धारित क्रियाकलापों का एक मासिक कैलेंडर तैयार किया। स्वच्छता कैलेंडर क्रियाकलापों के अनुपालन में सितंबर 2016 से अगस्त 2017 की अवधि में सभी प्रकार के अपशिष्ट व कबाड़ के निपटान के बाद लगभग 05 करोड़ रूपये की धनराशि प्राप्त हुई और लगभग 90,000 वर्ग फीट क्षेत्र को खाली करवाया गया। इन क्रियाकलापों का उद्देश्य कार्यालयों को चाक चौबंद और स्वच्छ रखना था। इसके लिए पुरानी मिसलों (फाइलों) सहित पुराने अथवा अनुपयोगी हो चुके सामान का निपटान किया गया।

- माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यवसाय में आसानी और डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को साकार बनाने के लिए 27 मार्च, 2017 को फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) की ई –प्रमाणन प्रणाली का आरम्भ किया गया। फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया के पूर्ण रूपेण स्वचालन से सुशासन में सहायता मिलेगी और पूरी प्रक्रिया प्रभावी एवं पारदर्शी हो जाएगी।

- भारतीय खेलों के भविष्य पर विचार विमर्श के लिए डीडी स्पोर्ट्स द्वारा 'भारत में खेल उत्सवों का आयोजन' विषय पर पहली बार अपनी कोटि के अनूठे ढंग से प्रसारित 'डीडी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव' का 28 मई, 2017 को तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू द्वारा उद्घाटन किया गया।

- 28 जनवरी, 2017 को राष्ट्रीय फिल्म विरासत अभियान के अंतर्गत फिल्म स्थिति मूल्यांकन परियोजना शुरू की गई। विश्व में फिल्मों के संरक्षण के लिए अपनी

तरह की इस अनूठी परियोजना में आने वाली पीढ़ियों के लिए फिल्मों की समृद्ध विरासत का सृजन किया जाएगा। पहले चरण में एनएफएआई के पास उपलब्ध लगभग 1,32,000 फिल्म रीलों का मूल्यांकन किया जाएगा और आरएफआईडी टैगिंग के माध्यम से हर फिल्म को चिन्हित करके जांचा जाएगा।

- विदेशी फिल्म निर्माताओं के देश में प्रवेश से जुड़े मामलों को सुविधाजनक बनाने के लिए वीजा की एक नई श्रेणी शुरू की गई। फिल्म वीजा और फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) दोनों का ही उद्देश्य भारत में फिल्में बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
- शास्त्री भवन में स्थित मंत्रालय के विभिन्न स्थानों पर 40 कैमरे लगाए गए हैं। प्रवेश द्वारों पर लगाए

सीबीएफसी के ऑनलाइन फिल्म प्रमाणीकरण प्रणाली ई–सिनेप्रमाण के शुभारंभ के अवसर पर, तत्कालीन माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेकैंया नायडु। माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एवं अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित थे।

गए उपस्थिति टर्मिनल्स पर भीड़भाड़ से बचने के लिए मंत्रालय में विभिन्न स्थानों पर आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) वाले 08 टेबलेट लगाए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों में विंडो डेस्कटॉप पर्सनल कम्प्यूटर्स पर डेस्कटॉप फिंगरप्रिंट डिवाइस लगाई गई हैं।

- प्रकाशन विभाग द्वारा राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के सहयोग से पुनर्नवीकृत एवं पुनर्मुद्रित दुर्लभ पुस्तक 'होमेज टू महात्मा गांधी' में गांधी जी को दी गई वे श्रद्धांजलियां शामिल की गई हैं जो 30 जनवरी, 1948 को गांधी जी के निधन के बाद आकाशवाणी पर प्रसारित की गई थीं। इनमें अनेक गणमान्य व्यक्तियों आचार्य जेबी कृपलानी, डॉ. सीवी रमन, जवाहर लाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरोजनी नायडू इत्यादि द्वारा दी गई श्रद्धांजलियां शामिल हैं।
- पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) और इंस्टाग्राम के सहयोग से 20 अप्रैल, 2017 को बेहतर सरकारी संवाद के लिए इंस्टाग्राम पर कार्यशाला आयोजित की गई। इंस्टाग्राम द्वारा एशिया में यह अपने प्रकार की पहली कार्यशाला थी जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया मंचों पर बेहतर सरकारी संवाद और सम्पर्क के लिए इंस्टाग्राम की विभिन्न विशेषताओं और उपयोग के तरीकों से अवगत कराना था।

- फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) ने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी के सहयोग से मोतिहारी, बिहार में 14 –16 अप्रैल, 2017 की अवधि में 'महात्मा गांधी फिल्म समारोह' का आयोजन किया था। समारोह में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए चम्पारण सत्याग्रह की शताब्दी के आयोजन के अवसर पर देशभक्ति परक सात फीचर फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।
- टेलीविजन उद्योग की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) ने बड़ी फिल्मों की कथाएं रचने के लिए देश में टीवी कहानियों और वेब श्रृंखलाओं हेतु अपनी किस्म का पहला 05 माह की अवधि का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया। एफटीआईआई, पुणे ने फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई) के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में फिल्म साक्षरता बढ़ाने के लिए 'फिल्म मूल्यांकन पाठ्यक्रम' का आयोजन भी प्रारम्भ किया है। ऐसा पहला पाठ्यक्रम 11 से 14 मई, 2017 की अवधि में नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें 150 से अधिक प्रतिभागियों जिनमें मुख्यतः फिल्म निर्माता, पत्रकार, छात्र, वास्तुविद, अभियंता, विद्यालय एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक थे, शामिल हुए।
- फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे के निदेशक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 01 जुलाई, 2017 को टैगोर हॉल, श्रीनगर कश्मीर में प्रारम्भ हुए 05 दिवसीय 'कश्मीर विश्व फिल्म समारोह' के पहले संस्करण में भाग लिया और एफटीआईआई की नई सम्पर्क पहल–फिल्म और टेलीविजन में कुशल भारत (एसकेआइएफटी)' के बारे में प्रजेंटेशन दिया। एफटीआईआई ने श्रीनगर में पहली बार 5 दिन का फिल्म मूल्यांकन पाठ्यक्रम भी चलाया, जिसे कश्मीर विश्वविद्यालय के मीडिया शिक्षा अनुसंधान केंद्र (एमईआरसी) के सहयोग से आयोजित किया गया था।
- एफटीआईआई ने 05 अगस्त, 2017 को संस्थान के छात्रों की फिल्मों के मासिक सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु एक नई पहल 'पदार्पणः मोमेंट्स माइलस्टोंस' की शुरुआत की। इसका उद्घाटन संस्थान के छात्र रहे श्री शत्रुघ्न सिन्हा, सांसद ने किया। इस सम्पर्क पहल से एफटीआईआई छात्रों के कार्यों को देखने और उनके मूल्यांकन का अवसर मिलेगा।

माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ फिल्म प्रचार निदेशालय एवं राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के सहयोग से एफटीआईआई द्वारा आयोजित फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए

भारत की सिनेमाई विविधता पर प्रकाश डालता राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का वर्ष 2018 का कैलेंडर

माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर नई दिल्ली में भारतीय प्रेस परिषद स्वर्ण जयंती समापन समारोह में पुरस्कार प्रदान करते हुए। इस अवसर पर माननीय सूचना व प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी भी उपस्थित थी।

4 सूचना क्षेत्र की गतिविधियां

i= lpuk dk;ky;

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों और उपलब्धियों के बारे में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को सूचनाएं उपलब्ध कराने वाली भारत सरकार की केंद्रीय एजेंसी है। यह सरकार और विभिन्न संचार माध्यमों के बीच आपसी संपर्क के मंच की तरह कार्य करता है और जनता की प्रतिक्रियाओं के बारे में सरकार को फीडबैक भी उपलब्ध कराता है।

1- i= lpuk dk;ky; dh ifjdYiuk

सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में सूचनाएं प्रदान कर भारत के लोगों को शिक्षित करना और अधिकार संपन्न बनाना।

माननीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में 3 जून, 2017 को आयोजित प्रेस वार्ता में गृह मंत्रालय की उपलब्धियों और नई पहलों के बारे में जानकारी देते हुए

2- i= lpuk dk;ky; dk dk;Z

पत्र सूचना कार्यालय सरकार और जन संचार माध्यमों के बीच संपर्क स्थल के रूप में कार्य करता है। यह मीडिया की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार को सबसे उपयुक्त संचार रणनीतियों के बारे में सलाह देता है और सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर मीडिया में परिलक्षित होने वाली जनता की धारणा के बारे में सरकार को लगातार सूचित करता रहता है।

पत्र सूचना कार्यालय प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, फीचर लेख, बैकग्राउंडर, प्रेस ब्रीफिंग, इंटरव्यू, संवाददाता सम्मेलन, प्रेस टूर जैसे विभिन्न साधनों से सूचनाओं का प्रसार करता है। इसके लिए यह सोशल मीडिया मंचों जैसे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम आदि का भी उपयोग करते हुए अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू के साथ साथ 13 क्षेत्रीय भाषाओं में देश भर के समाचार पत्रों और मीडिया संगठनों के लिए सूचनाएं जारी करता है।

पीआईबी का अपना समाचार कक्ष/समाचार अनुश्रवण प्रकोष्ठ है जो सूचनाएं प्रदान करने की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरे साल भर कार्य करता रहता है। पत्र सूचना कार्यालय मीडिया कर्मियों को सरकारी सूत्रों से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रत्यायन सुविधा भी उपलब्ध कराता है।

3- laxBukRed <kpk

पत्र सूचना कार्यालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रधान महानिदेशक (मीडिया और संचार) इसके प्रमुख हैं और महानिदेशक, अपर महानिदेशक, निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, मीडिया और संचार अधिकारी और सूचना सहायक जैसे अधिकारी उनकी सहायता करते हैं। ये अधिकारी मंत्रालयों के आकार, महत्व और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध रहते हैं।

पत्र सूचना कार्यालय के आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनके प्रमुख अपर महानिदेशक होते हैं। इसके अलावा इसके 27 शाखा कार्यालय और एक सूचना केन्द्र भी है जो क्षेत्रीय मीडिया की सूचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

4- ihvkbZch dh çpkj lac/kh xfrfof/k;k

d- ea=ky;k@foHkkxk dk çpkj%

मंत्रालयों/विभागों से संबद्ध पीआईबी अधिकारी उनके आधिकारिक प्रवक्ता होते हैं जो उन मंत्रालयों/विभागों की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हैं, सूचनाओं का प्रसार करते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं और जरूरत पड़ने पर स्पष्टीकरण या प्रतिवाद भी दर्ज कराते हैं। वे मीडिया में संपादकीय, लेखों और टिप्पणियों के रूप में छपी जनता की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं और मंत्रालय/विभागों को जनमत से

अवगत रखने के साथ–साथ मीडिया तथा सूचना, शिक्षा और संचार नीति के बारे में सलाह देते हैं।

पीआईबी के क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के अधिकारी मुख्यालय से मिलने वाली सूचनाओं के प्रसार के साथ–साथ अपने क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों द्वारा आयोजित किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बारे में प्रचार भी करते हैं। ये अधिकारी किसी खास क्षेत्र में केंद्र सरकार की ओर से महत्वपूर्ण सूचनाओं के लगातार विशेष प्रचार–प्रसार के बारे में भी निर्णय लेते हैं। प.सू.का. के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और सचिवों के किसी राज्य/क्षेत्र के सरकारी दौरे की मीडिया कवरेज को आसान बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पीआईबी सूचनाओं के प्रसार के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए निम्नलिखित नीतियां अपनाता है:

1) राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर संचार के पारम्परिक तरीकों जैसे संवाददाता सम्मेलनों आदि का आयोजन (जिसमें वीडियो कांफ्रेंस भी शामिल हैं)।

2) महत्वपूर्ण घटनाओं और घोषणाओं के बारे में प्रेस विज्ञप्तियां और फोटो जारी करने के बाद एसएमएस एलर्ट, ट्वीट और मीडिया कर्मियों को टेलीफोन भी किए जाते हैं।

3) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इंटरव्यू, विशेष चर्चाओं आदि की व्यवस्था।

4) अपने वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन करने के साथ–साथ ट्विटर, यू–ट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और वाइन जैसे सोशल मीडिया मंचों का उपयोग।

5) प.सू.का. के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के साथ–साथ मलयालम, उड़िया, कन्नड़, तेलुगू, तमिल, पंजाबी, गुजराती, मराठी, असमी और बंगाली जैसी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के जरिए अखिल भारतीय स्तर पर प्रचार–प्रसार।

6) स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, आम बजट, आर्थिक समीक्षा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, राष्ट्रीय एकता दिवस, स्वच्छ भारत सप्ताह जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के विशेष प्रचार के इंतजाम।

7) प्रधानमंत्री कार्यालय को दैनिक मीडिया रिपोर्ट के रूप में हिंदी और अंग्रेजी में मीडिया फीडबैक भेजना, प्रत्येक मंत्रालय को संबंधित पीआईबी अधिकारियों द्वारा दैनिक मीडिया फीडबैक का प्रेषण, महत्वपूर्ण अवसरों पर विशेष फीडबैक भेजना।

8) प.सू.का. अपने मीडिया आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों समेत दूर–दराज इलाकों के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करता है।

ihvkbZch }kjk bLrseky fd, x, ehfM;k midj.k

सूचनाओं के प्रचार के लिए पीआईबी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न मीडिया उत्पाद/उपकरण इस प्रकार हैं:

मीडिया उत्पाद/सेवा/वाहन	***संख्या (1 अप्रैल से 15 नवंबर 2017 के दौरान)***
प्रेस विज्ञप्ति	63643
फोटो/ग्राफ/इंफोग्राफिक्स	10360
मीडिया आमंत्रण	692
औपचारिक संवाददाता सम्मेलन	110
वार्तालाप	47
राष्ट्रव्यापी मीडिया फीडबैक	दैनिक
विशिष्ट मुद्दों पर विश्लेषणात्मक मीडिया रिपोर्ट	दैनिक/साप्ताहिक
फीचर	149
ट्वीट्स	रोजाना 80 से 100
एसएमएस	मीडिया को एकमुश्त एसएमएस भेजे
प्रेस प्रत्यायन कार्ड जारी	311

[k- ç/kkuea=h ,dka'k

प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रचार और उसे जनसंचार माध्यमों का सहयोग प्रदान करने के लिए पत्र सूचना कार्यालय का एक अलग से एकांश है। यह एकांश साल में सारे दिन कार्य करता है और माननीय राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल सचिवालय, नीति आयोग और प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) के प्रचार का कार्य भी देखता है। इसके कार्य का स्वरूप इस प्रकार है:

अ) फीडबैक

- हिंदी और अंग्रेजी में प्रातःकालीन दो मीडिया रिपोर्ट तैयार करना

- दैनिक फीडबैक रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे तक प्रधानमंत्री आवास पर देना
- प्रधानमंत्री कार्यालय को संपादकीय और प्रति–संपादकीय के बारे में दैनिक रिपोर्ट देना
- प्रधानमंत्री कार्यालय को दैनिक और साप्ताहिक उर्दू फीडबैक रिपोर्ट
- नीति आयोग को दैनिक फीडबैक रिपोर्ट
- प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधान महानिदेशक, पीआईबी को सप्ताहिक पत्रिका रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के प्रत्येक महत्वपूर्ण भाषण के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय को सोशल मीडिया फीडबैक रिपोर्ट
- महत्वपूर्ण आयोजनों या प्रधानमंत्री के दौरे के बाद प्रेस कवरेज के विश्लेषण का सारांश
- विभिन्न मुद्दों/आयोजनों पर प्रधानमंत्री कार्यालय/प्रधान महानिदेशक, पीआईबी द्वारा वांछित राष्ट्रीय और क्षेत्रीय फीडबैक रिपोर्ट

आ) सरकारी विज्ञप्तियां

- प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के दौरान प्रेस विज्ञप्तियां: एकांश टाइम–जोन के अंतर का ध्यान रखे बिना सूचना सामग्री का तात्कालिक प्रसार करता है।
- प्रधानमंत्री के आधिकारिक भाषणों का लिप्यंतरण और मिलान करने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के परामर्श से जारी किया जाता है।
- प्रधानमंत्री के आधिकारिक फोटोग्राफ (पीआईबी के ट्विटर पर)।
- 'मन की बात' की सामग्री।
- राष्ट्रपति सचिवालय से प्राप्त प्रेस विज्ञप्तियां और भाषण।
- मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में प्रेस विज्ञप्तियां और कैबिनेट ब्रीफिंग के सिलसिले में मीडिया से तालमेल।
- नीति आयोग की प्रेस विज्ञप्तियां और आधिकारिक फोटोग्राफ्स।

इ) अनुवाद

- प्रधानमंत्री के भाषणों, प्रेस विज्ञप्तियों और फोटो कैप्शनों का हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद।
- प्रधानमंत्री के भाषणों और संदेशों का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराने के लिए मानव संसाधनों का इंतजाम किया गया है।
- पीआईबी के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के सहयोग से प्रधानमंत्री के ट्वीट्स, क्रिएटिव्ज आदि का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद।

ई) मीडिया को सुविधाएं

- प्रधानमंत्री के आयोजनों की एडवान्स्ड सिक्योरिटी लायजन मीटिंग (एएसएल) में भाग लेना और उसमें मीडिया के बारे में फैसला करना।
- प्रधानमंत्री के आयोजनों में मीडिया प्रवेश पास के लिए दिल्ली पुलिस और प्रधानमंत्री सुरक्षा के साथ संपर्क।
- राष्ट्रपति भवन के आयोजनों के लिए मीडिया पासों का वितरण।
- नीति आयोग के आयोजनों के लिए मीडिया सुविधा।

उ) वेबसाइट और अन्य गतिविधियां

- प्रधानमंत्री एकांश विभिन्न अवसरों (जैसे एनडीए सरकार के तीन साल, स्वतंत्रता दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल आदि) पर विशेष वेब पेज के डिजाइन, सामग्री और प्रदर्शन का नियमित रूप से प्रबंधन करता है।

x- lk'ky ehfM;k çdk"B

सरकारी संवाद की नोडल एजेंसी के नाते पीआईबी देश–विदेश में लगातार बढ़ रहे ऑनलाइन जनसमुदाय से जुड़ने और संपर्क साधने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है।

पीआईबी ट्विटर, फेसबुक, यू ट्यूब, वाइन, साउंडक्लाउड और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों पर मौजूद है। इसके अलावा पीआईबी एक ब्लॉग भी निकालता है। तमाम सरकारी फोटो, वीडियो और प्रेस विज्ञप्तियां विभिन्न मीडिया मंचों पर साझा की जाती हैं जिनसे हर महीने 1.5 करोड़ इम्प्रेशन प्राप्त होते हैं। समाचारों को साझा करने के अलावा पीआईबी सुशासन के लक्ष्य में योगदान के लिए सोशल मीडिया अभियान संचालित करता है जिसके लिए जनता में जागरूकता पैदा की जाती है और सरकारी नीतियों व गतिविधियों में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। सोशल मीडिया संबंधी संचार मूलतः अंग्रेजी और हिंदी में ही होता है, हालांकि क्षेत्रीय कार्यालय भी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि

lks'ky ehfM;k ij ihvkbZch dh mifLFkfr% egRoiw.kZ vkadMs

lks'ky ehfM;k eap	ihvkbZch ,dkmaV	vDrwcj 2017 esa ;wtj
Twitter	@pib_india @pibhindi	1.3 लाख से अधिक फॉलोअर 32,000 लाख से अधिक फॉलोअर
Facebook	/pibindia	1.7 लाख से अधिक फॉलोअर
YouTube	/pibindia	81,000 से अधिक फॉलोअर
Instagram	/pibindia	30,000 से अधिक फॉलोअर
Blog	pibindia.wordpress.com	1.2 लाख से अधिक विजिटर

विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से किस तरह देश के विशाल जनसमुदाय तक प्रभावी तरीके से पहुंचा जाए।

ट्विटर : पीआईबी के मुख्य ट्विटर हैंडल @PIB_India ने वर्ष के दौरान 13 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया जिसके लिए ट्विटर इंडिया की ओर से पीआईबी को शुभकामना संदेश मिला। पीआईबी नागरिकों से संपर्क करने और उनके साथ संवाद कायम करने के लिए नई किस्म की सामग्री और प्रस्तुतियों का उपयोग कर रहा है। इसके कुछ उदाहरण हैः ट्विटर वीडियो, जीआईएफ, पोल्स और ट्विटर मोमेंट्स जैसे फार्मेट का इस्तेमाल करना। @PIBHindi हैंडल के फॉलोअरों की संख्या 31,000 को पार कर गयी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर क्षेत्रीय भाषाओं की क्षमता उपयोग करते हुए पीआईबी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों ने क्षेत्रीय भाषाओं में भारत सरकार के न्यूज अपडेट्स को ट्विटर पर साझा करना शुरू कर दिया है।

फेसबुकः इस वर्ष पीआईबी के फेसबुक पेज www.facebook.com/pibindia के चाहने वालों की संख्या में शानदार बढ़ोतरी हुई है। अक्तूबर 2016 में इनकी संख्या करीब 1 लाख थी जो अक्तूबर 2017 में 1.7 लाख हो गयी है। ऐसा संचार के रचनात्मक तरीकों के उपयोग और लोगों के साथ संवाद कायम करने से संभव हुआ है। महत्वपूर्ण अवसरों पर पीआईबी के फेसबुक पेज पर प्रश्नोत्तर सत्र जैसे सोशल मीडिया कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

यूट्यूब : पीआईबी के यूट्यूब चैनल को 50 लाख से अधिक बार देखा गया और इसके 81,000 सब्सक्राइबर हैं। नई दिल्ली में पत्र सूचना कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंसों और अन्य आयोजनों, दिल्ली से बाहर के कुछ चुने हुए आयोजनों जैसे चेन्नई, जयपुर और चंडीगढ़ में आयोजित क्षेत्रीय संपादक सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह को अब स्ट्रीम करके सीधा दिखाया जाता है।

इंस्टाग्राम : पीआईबी इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है जहां ऐसे फोटो और छोटे वीडियो साझा किये जाते हैं जो लीक से थोड़ा हटकर होते हैं। अक्तूबर 2017 के अंत तक पीआईबी इंस्टाग्राम के 30 हजार से ज्यादा फॉलोअर थे।

पीआईबी ब्लॉगः www.pibindia.wordpress.com इसका उपयोग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में फीचर और सॉफ्ट स्टोरीज को साझा करने के लिए किया जाता है। अब तक इस पर 376 लेख प्रकाशित किये जा चुके हैं जिन्हें 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है।

सोशल मीडिया दिशा–निर्देश और सहयोग : अपने खुद के संपर्क का दायरा बढ़ाने के साथ–साथ पीआईबी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को

भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू नई दिल्ली में 20 अप्रैल, 2017 को सरकार के सोशल मीडिया संचार में इंस्टाग्राम की भूमिका के बारे में कार्यशाला में उद्घाटन भाषण देते हुए। इस कार्यशाला का आयोजन पीआईबी के सोशल मीडिया सैल और इंस्टाग्राम ने संयुक्त रूप से किया था।

उनकी सोशल मीडिया पर उपस्थिति दर्ज कराने और इसे बेहतर तरीके से कायम रखने में मदद कर रहा है। इसी सिलसिले में दिशानिर्देश देने के लिए पीआईबी ने

इंस्टाग्राम के सहयोग से सरकारी सम्प्रेषण में इंस्टाग्राम के कारगर उपयोग के बारे में एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसका उद्घाटन तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू ने किया।

अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव श्री अनिंदय मजूमदार पीआईबी पोर्टब्लेयर में, 14 जुलाई 2017 को आयोजित मीडिया वर्कशॉप– वार्तालाप में पत्रकारों से चर्चा करते हुए

?k- fo'k"k vk;ktuk d fy, lk'ky ehfM;k vkmVjhp vkj çpkj

मीडिया संपर्क कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में राष्ट्रीय,क्षेत्रीय और जिला स्तर पर मीडिया के साथ बातचीत के कार्यक्रम आयोजित कर सूचनाओं का प्रसार करना है। इस योजना के तहत प्रेस टूर का भी आयोजन किया जाता है ताकि सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों से संबंधित यश गाथाओं के बारे में जानकारी दी जा सके।

M- pquko d nkjku lpukvk dk çlkj

पत्र सूचना कार्यालय भारत के निर्वाचन आयोग और मीडिया के बीच कारगर संपर्क उपलब्ध कराता है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद पीआईबी पिछले आम चुनावों या विधानसभा चुनावों के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के लिए पीआईबी 'रिफरेंस हैंडबुक फॉर जनरल इलेक्शन्स' (आम चुनाव के बारे में संदर्भ पुस्तिका) और हैंडबुक ऑन एसेम्बली इलेक्शन्स (विधानसभा चुनाव के बारे में हैंडबुक) जारी करता है। इसके अलावा चुनाव की तैयारियों के दौरान भी मीडिया को चुनाव संबंधी सूचनाएं बैकग्राउंडर्स यानी पृष्ठभूमि सामग्री और फैक्टशीट नियमित आधार पर उपलब्ध करायी जाती हैं। लोकसभा के आम चुनाव और विभिन्न विधानसभाओं के चुनावों के दौरान मतदान और मतगणना प्रक्रिया की कवरेज को आसान बनाने के लिए पीआईबी निर्वाचन आयोग की ओर से नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कर्मियों को प्राधिकार पत्र जारी करता है और मतगणना के दिन निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र से मतगणना संबंधी आंकड़े हासिल कर विशेष वेबसाइट के जरिए वोटों की गिनती के रुझान और चुनाव परिणाम के बारे में ताजा सूचनाएं देता है।

5- QhMcd] Qhpj vkj QkVk lok,

पत्र सूचना कार्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्य सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में मीडिया के माध्यम से सामने आने वाली जनता की धारणा के बारे में सरकार को अवगत कराना है। पीआईबी मंत्रालयों और विभागों को जो फीडबैक रिपोर्ट उपलब्ध कराता है उनमें दिल्ली से प्रकाशित होने वाले हिन्दी और अंग्रेजी के राष्ट्रीय अखबारों से ली गयी जानकारियां, क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों से प्राप्त जानकारियां और टेलीविजन के समाचार चैनलों, वे मीडिया और पत्रिकाओं से प्राप्त जानकारियां शामिल रहती हैं।

विशेष सेवाओं के हिस्से के रूप में पीआईबी का फीडबैक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अखबारों तथा पत्रिकाओं में छपे समाचारों और संपादकीयों के आधार पर मंत्रालयों के उपयोग के लिए डेली डायजेस्ट (दैनिक सार) और विशेष सार तैयार करता है। 1 अप्रैल 2017 से 15 नवंबर 2017 तक करीब 190 डेली डायजेस्ट और स्पेशल डायजेस्ट भेजे गये। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय और विभिन्न मंत्रालयों के विभागीय प्रचार अधिकारियों को 5900 एसएमएस एलर्ट्स/मेल भी भेजे गये।

केन्द्र सरकार की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए पत्र सूचना कार्यालय ने फीचर, सफलता–गाथाएं और फोटो फीचर जारी किये। विशेष अवसरों पर राष्ट्रीय नेताओं और महान देशभक्तों के जीवन पर फीचर भी जारी किये गये। सभी फीचर क्षेत्रीय कार्यालयों को भी भेजे गये ताकि उनका अनुवाद कर स्थानीय मीडिया को उपलब्ध कराया जा सके। अप्रैल 2017 से अक्तूबर 2017 तक 149 फीचर जारी किये गये। अधिकांश फीचर जाने–माने पत्रकारों से लिखवाए गये जबकि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे अवसरों पर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर प्रकाश

पीआईबी के प्रधान महानिदेशक (एम एंड सी) श्री ए.पी. फ्रैंक नरोन्हा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 20 जून को पत्रकारों के साथ। ये पत्रकार लखनऊ में होने वाले योग कार्यक्रम के लिए जा रहे थे।

डालने के लिए कुछ विशेष लेख केन्द्रीय मंत्रियों, सचिवों, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों से विशेष लेख के रूप में प्राप्त हुए।

6- çl lfo/kk,

पत्र सूचना कार्यालय का प्रेस सुविधा स्कंध संचार माध्यमों के देशी–विदेशी प्रतिनिधियों को नई दिल्ली मुख्यालय से प्रत्यायन की सुविधाएं प्रदान करता है। इससे सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सूचनाओं तक मीडियाकर्मियों की पहुंच आसान हो जाती है और उन्हें रेलवे रियायत, सीजीएचएस सुविधाएं और पत्रकार कल्याण योजना जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का भी लाभ मिलता है।

bl Ld/k dh çe[k xfrfof/k;k bl çdkj g%

ऑनलाइन प्रत्यायन प्रणाली : प्रेस और मीडिया के पेशेवर कर्मियों को प्रत्यायन उपलब्ध कराने की एक प्रणाली 2010 में शुरू की गयी थी। इस ऑनलाइन प्रणाली को उपयोग करने वालों के लिए आसान और गतिशील बनाने के लिए इसमें लगातार बदलाव किये गये। पत्र सूचना कार्यालय ने वर्ष के दौरान प्रत्यायन की ऑनलाइन प्रणाली का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। पत्रकारों को जारी करने के लिए प्रेस प्रत्यायन कार्ड तैयार करने की इस प्रणाली का रखरखाव और संचालन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) करता है। अप्रैल 2017 से नवंबर 2017 के दौरान केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति (सीपीएसी) की बैठकों में प्रत्यायन के 160 नये मामलों पर विचार किया गया।

भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई) के लिए गोवा में मीडिया सेंटर : गोवा में भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पीआईबी ने मीडियाकर्मियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक मीडिया सुविधा केन्द्र स्थापित किया और मीडिया आयोजनों में समन्वय का कार्य भी किया। इन कार्यक्रमों में उद्घाटन और

प्रख्यात फिल्म निर्माता–निर्देशक श्री सुभाष घई पणजी (गोवा) में भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान 21 नवंबर, 2017 को पत्रकारों को संबोधित करते हुए

समापन समारोह के अलावा स्वागत, प्रजेंटेशन, मास्टर क्लासेज, खुली चर्चाएं आदि शामिल थे। समारोह के दौरान पीआईबी ने 29 प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कीं और 47 प्रेस विज्ञप्तियां जारी कीं। प्रेस कांफ्रेंसों को सीधा स्ट्रीम करके ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर प्रसारित किया गया। समारोह को कवर करने के लिए कुल 441 लोगों का प्रत्यायन किया गया था। आईएफएफआई 2017 का व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया और पीआईबी के गोवा तथा मुंबई कार्यालयों ने करीब 948 क्लिपिंग तैयार कीं।

पत्रकार कल्याण योजना : पत्र सूचना कार्यालय 'पत्रकार कल्याण कोष' योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। संशोधित योजना में मुसीबतों का सामना कर रहे पत्रकारों और उनके परिवारों को तत्काल अनुग्रह सहायता देने की व्यवस्था है। इस योजना के तहत पत्रकार को 5 लाख रुपये तक की सहायता मंजूर की जा सकती है। पत्रकार की मृत्यु होने पर संकट में पड़े परिवार को भी अनुग्रह सहायता दी जा सकती है। इसी तरह पत्रकार के स्थायी रूप से विकलांग होने पर भी मदद देने का प्रावधान है। कैंसर, गुर्दे खराब होने, हृदय रोग, दिमाग की नस फटने जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी मदद दी जाती है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के मामलों में भी वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसे सभी मामलों को पत्र सूचना कार्यालय निपटाता है और सहायता के बारे में सिफारिश स्वीकृति के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति को भेज दी जाती है।

7- vkikrdkyhu fu;=.k d{k

पीआईबी का अपना समाचार कक्ष/नियंत्रण कक्ष है जो पूरे साल 365 दिन चालू रहता है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। बिना किसी तैयारी के कम समय में प्रेस कांफ्रेंस आयोजित करने और पीआईबी केन्द्रों के जरिए उनका देश भर में साथ–साथ वेबकास्ट करने का भी इंतजाम रहता है ताकि रात 9 बजे के बाद भी अचानक कोई अप्रत्याशित घटना हो जाए तो स्थिति से निपटा जा सके। नियंत्रण कक्ष आपात स्थितियों और संकट के समय सप्ताह के सातों दिन और चौबीसों घंटे काम करता है। महत्वपूर्ण समाचार चैनलों पर नजर रखी जाती है और वरिष्ठ अधिकारियों को ताजा घटनाक्रम और गलत तरीके से की जा रही रिपोर्टिंग के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

8- 2017&18 ds nkSjku igy

i= lwpuk dk;kZy; us bl nkSjku ;s igy dha

अ) सरकार की विभिन्न पहलों और उपलब्धियों के बारे में इन्फोग्राफिक्स तैयार किये गये जिनसे बड़े सुनियोजित और आकर्षक तरीके से सूचनाएं दी जा रही हैं। इन इन्फोग्राफिक्स के बारे में प्रतिक्रिया बड़ी उत्साहजनक रही है क्योंकि सामान्य लिखित सामग्री के मुकाबले इस तरह की सामग्री को लोग ज्यादा समय तक और ध्यान से देखते हैं।

आ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में संचार के लिए उत्तरदायी पीआईबी अधिकारियों ने पत्र सूचना कार्यालय के अधिकृत ट्विटर हैंडल का उपयोग करते हुए सरकारी अपडेट्स को साझा करना शुरू कर दिया है।

इ) पीआईबी मुख्यालय में आयोजित की जाने वाली सभी प्रेस कांफ्रेंसों का अब फेसबुक, ट्विटर और पीआईबी के यूट्यूब चैनल पर सीधा स्ट्रीम करके प्रसारण किया जाता है।

9- dk;kZy; Lopkyu

पीआईबी ने कार्यालय की विभिन्न गतिविधियों के स्वचालन के लिए कई कदम उठाए:

अ) पीआईबी के नये बहुभाषी वेबसाइट के लिए सामग्री का एनआईसी द्वारा अंतिम परीक्षण किया जा रहा है।

आ) पत्रकारों के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन जारी किया गया है।

इ) पीआईबी के सम्मेलन कक्ष में सोशल मीडिया पर स्ट्रीमिंग के लिए एचडी कैमरे लगाए गये।

ई) बेसिल के जरिए ग्राफिक्स और एनेलेटिक्स की आउटसोर्सिंग की जा रही है।

उ) 1947 से 2003 तक की प्रेस विज्ञप्तियों का डिजिटल आर्काइव बनाने की प्रक्रिया जारी है।

ऊ) पीआईबी के सभी प्रचार अधिकारियों के लिए स्मार्ट उपकरण खरीदे गये हैं।

ऋ) शास्त्री भवन और राष्ट्रीय मीडिया सेंटर स्थित पीआईबी कार्यालयों को वाई–फाई के जरिए जोड़ दिया गया है।

ए) जीईएम पोर्टल के जरिए वस्तुओं की खरीद।

ऐ) पीआईबी मुख्यालय में ई–ऑफिस को लागू करने का काम आंशिक रूप से संपन्न किया गया है।

10- ihvkbZch }kjk 2017&18 esa dh x;h çeq[k xfrfofèk;k

d½ th,lVh dh 'kq#vkr

30 जून 2017 को जीएसटी की शुरुआत के दौरान संसद के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में पीआईबी ने मीडिया को इस समारोह को कवर करने के लिए आमंत्रित किया। पीआईबी के सभी क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों को 12 बजे इसके लिए तैयार रखा गया था। आयोजन के दौरान दिये गये सभी भाषणों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराया गया और व्यापक प्रचार प्रसार के लिए क्षेत्रीय मीडिया को बांटा गया। पीआईबी की सोशल मीडिया टीम ने भी इस आयोजन के बारे में सीधे ट्वीट भेजे। पीआईबी की एनआईसी टीम ने पीआईबी की वेबसाइट पर इसके वीडियो को सीधा वेबकास्ट किया। जीएसटी पर पीआईबी ने विशेष वेबपेज बनाया जिसमें जीएसटी के बारे में तमाम जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध थीं। जीएसटी के शुभारंभ और इसपर अमल को इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया समेत तमाम मीडिया मंचों पर भरपूर कवरेज मिली।

[k½ jk"Vªh; ,drk fnol

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती (31 अक्तूबर 2017) राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनायी गयी। पीआईबी ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश भर में आयोजित विभिन्न गतिविधियों का प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया मंचों से व्यापक प्रचार किया। पीआईबी ने इस सिलसिले में राष्ट्रीय एकता दिवस पर एक वेब पेज भी बनवाया। इसके अलावा प्रचार के असर को कई गुणा करने के लिए डीएवीपी, आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य मीडिया इकाइयों के साथ तालमेल कायम किया।

x½ varjk"Vªh; ;ksx fnol

लखनऊ में 21 जून 2017 को आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रव्यापी प्रचार किया गया। पृष्ठभूमि

आयुष राज्य मंत्री श्रीयुत श्रीपद यशोनायक योग के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संपादक सम्मेलन के उद्‌घाटन के अवसर पर संबोधित करते हुए। इस सम्मेलन का आयोजन पीआईबी और योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान राष्ट्रीय परिषद (आयुष मंत्रालय) ने नई दिल्ली में 9 जून, 2017 को किया था।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद्र नेशनल स्टेडियम में 31 अक्तूबर, 2017 को आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी आयोजन को प्रोत्साहित करते हुए

जानकारी, टीजर वीडियो, योग पर पुस्तिकाओं आदि के जरिए इस आयोजन से पहले व्यापक प्रचार किया गया। 9 जून 2017 को पीआईबी और आयुष मंत्रालय ने संयुक्त रूप से स्वास्थ्य संपादकों का सम्मेलन आयोजित किया। योग पर एक विशेष वेब पेज बनाया गया और मीडिया को सूचनाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए इसे लगातार अपडेट किया गया। 40 पत्रकारों के एक समूह को दिल्ली से लखनऊ ले जाया गया ताकि इस आयोजन को मीडिया में पर्याप्त कवरेज मिले। प्रेस विज्ञप्तियों को क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के साथ साझा किया गया ताकि उनको क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कर बांटा जा सके।

?k½ LoPNrk gh lsok vfHk;ku

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने 15 सितंबर से 2 अक्तूबर 2017 तक 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान चलाया जिसमें सारे देश को साफ–सफाई का खयाल रखने और शौचालयों के निर्माण के लिए प्रेरित किया गया। पीआईबी ने पखवाड़े के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफार्म से 'स्वच्छता ही सेवा' से संबंधित गतिविधियों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया। प्रधान महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय ने भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी वरिष्ठ संपादकों/संवाददाताओं से आग्रह किया कि वे इस अभियान पर विशेष ध्यान दें।

M½ i;Vu io

पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों ने 21 दिन के पर्यटन पर्व कार्यक्रम के दौरान 5 से 25 अक्तूबर 2017 तक देश भर में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए व्यापक प्रचार किया। पीआईबी मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों ने पर्यटन पर्व के दौरान 200 प्रेस विज्ञप्तियां और 250 फोटोग्राफ जारी किये।

11- ;kstuk fu"iknu 2017&18

पत्र सूचना कार्यालय का योजना निष्पादन इस प्रकार है:

v½ ehfM;k vkmVjhp dk;Øe vkSj fo'ks"k vk;kstuk dks fy, çpkj

मीडिया संपर्क कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और जिला स्तर पर मीडिया से संवाद के सत्र आयोजित कर सूचनाएं देना है। इसके अंतर्गत प्रेस टूर का भी आयोजन किया जाता है ताकि मीडियाकर्मियों को इन कार्यक्रमों की कामयाबी के बारे में जानकारी दी जा सके। चालू वित्त वर्ष में पत्र सूचना कार्यालय ने 60 वार्तालाप, 3 राष्ट्रीय/क्षेत्रीय संपादक सम्मेलन और 5 प्रेस टूर आयोजित करने का लक्ष्य रखा है। चालू साल के 4.00 करोड़ रुपये के आबंटन में से दिसंबर 2017 तक 2.91 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके थे।

vk½ i= lwpuk dk;kZy; dk vk/kqfudhdj.k

इस योजना का उद्देश्य पीआईबी की संचार और सूचना प्रसार प्रणाली का आधुनिकीकरण और उच्चीकरण करना है ताकि आधुनिक टेक्नोलॉजी का पूरा–पूरा उपयोग करते

केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में 23 अक्तूबर, 2017 को पर्यटन पर्व के रंगारंग उद्घाटन समारोह के अवसर पर ड्रम बजाते हुए

वर्ष 2017–18 के लिए 'मीडिया आउटरीच कार्यक्रम' सिलसिले में भौतिक उपलब्धियां (03.01.2018 की स्थिति)

Ø- l¡-	{k= dk uke	okrkyki	jk"Vh;@ {k=h; l¡iknd lEeyu	çl Vj
		miyfC/k;k	miyfC/k;k	miyfCèk;k
1.	म.क्षे. भोपाल	7	–	1
2.	उ.क्षे. चंडीगढ़	10	–	1
3.	द.क्षे. चेन्नई	4	–	1
4.	उ.पू.क्षे. गुवाहाटी	6	–	–
5.	द.म.क्ष. हैदराबाद	6	–	–
6.	पू.क्षे. कोलकाता	7	–	1
7.	पू.म. क्षेत्र लखनऊ	6	–	1
8.	प. क्षे. मुंबई	7	–	–
9.	मुख्यालय	–	–	4 (#)
	d|y	53	&	9

(#) अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के सिलसिले में 3 प्रेस टूर समेत

हुए मुख्यालय तथा क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों की दक्षता बढ़ाई जा सके। 2017–18 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों के लिए 5.00 करोड़ रुपये दिये गये।

क) सूचना टेक्नोलॉजी का बुनियादी ढांचा खड़ा करना और सभी अधिकारियों को संचार के आधुनिक साधन उपलब्ध कराना:

- उपभोज्य वस्तुओं की खरीद।
- वार्षिक अनुरक्षण शुल्क।
- कई उपयोग वाली रंगीन डिजिटल ऑफिस मशीनों की खरीद।
- हार्डवेयर और अन्य उपकरणों की खरीद।
- इंटरनेट डोंगल कनेक्शन के लिए भुगतान।
- लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) नेटवर्किंग आदि।
- फीडबैक और प्रभाव विश्लेषण दैनिक रिपोर्ट।

ख) सभी कार्यालयों में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराना।

ग) पीआईबी के शाखा कार्यालयों में सीधा स्ट्रीमिंग सुविधा उपलब्ध कराना

- पीआईबी के सोशल मीडिया प्रकोष्ठ को उपकरण उपलब्ध कराए गये।

घ) पीआईबी कार्यालयों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना और इसके लिए श्रमशक्ति जुटाना।

योजना के अंतर्गत अक्तूबर 2017 तक 2.18 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके थे।

ihvkbch e[;ky; esa jktHkk"kk dk c<rk mi;kx

पत्र सूचना कार्यालय के मुख्यालय में राजभाषा हिन्दी के उपयोग को बढ़ाने के सभी प्रयास लगातार किये जा रहे हैं। राजभाषा विभाग के विभिन्न आदेशों और निर्देशों पर अमल और उनके कार्यान्वयन के लिए कदम उठाये गये हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियमावली, 1976 के तहत वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में भी प्रयास जारी हैं।

प्रधान महानिदेशक (मीडिया और संचार) की अध्यक्षता में पीआईबी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति पत्र सूचना कार्यालय के विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा नीति को लागू करने की स्थिति की निगरानी करती है। इसके लिए त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं जिनमें विभिन्न मुद्दों जैसे सामान्य और प्रधानमंत्री की प्रेस विज्ञप्तियों, ट्विटर, फेसबुक आदि सोशल मीडिया मंचों पर हिन्दी के उपयोग, हिन्दी भाषा, टंकण और शीघ्रलेखन के प्रशिक्षण, सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के उपयोग को उत्तरोत्तर बढ़ावा देने की दृष्टि से अनुभागों और क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के निरीक्षण पर विचार किया जाता है। पीआईबी मुख्यालय से राजभाषा अधिकारी समय–समय पर क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में गये और उन्होंने राजभाषा नीति तथा इस बारे में नियमों के बारे में जानकारी देने के साथ–साथ कार्यालयों में उस पर अमल की स्थिति की समीक्षा की। पीआईबी की वेबसाइट द्विभाषिक (हिन्दी/अंग्रेजी) है।

2017–18 के दौरान पीआईबी ने 1 से 14 सितंबर 2017 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जिसमें विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं जैसे निबंध लेखन, अनुवाद, टिप्पण और प्रारूपण, हिन्दी का सामान्य ज्ञान, हिन्दी टंकण और एमटीएस कर्मचारियों के लिए हिंदी श्रुतलेखन आयोजित की गयीं। इनमें बड़ी संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया और कई पुरस्कार जीते। पुरस्कार वितरण समारोह में पीआईबी के प्रधान महानिदेशक (मीडिया और संचार) ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं के साथ–साथ सरकारी काम मूलतः हिंदी में करने के लिए 2016–17 की प्रोत्साहन योजना के विजेताओं को भी प्रमाणपत्र प्रदान किए।

lrdrk vuHkkx

पत्र सूचना कार्यालय के सतर्कता अनुभाग ने वर्ष 2017–18 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां कीं।

केन्द्रीय प्रशासनिक ट्राइब्यूनलों के फैसलों/आदेशों पर अमल :

क्र. सं.	मीडिया एकांश/अनुभाग	2016–17 के दौरान ट्राइब्यूनलों से प्राप्त आदेशों की संख्या	2016–17 के दौरान लागू किये गये फैसलों/आदेशों की संख्या
1.	पीआईबी (सतर्कता अनुभाग)	1	–

- शिकायत निवारण प्रणाली : श्री विद्या भूषण अरोड़ा, संयुक्त निदेशक, पीआईबी को स्टाफ/लोक शिकायत निवारण अधिकारी नामित किया गया है। इस तरह के मामलों से संबंधित सभी आवेदनों को समयबद्ध तरीके से निपटाया गया।
- महिला कल्याण गतिविधियां: कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार के मामलों को निपटाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय

द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार पीआईबी के मुख्यालय/क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समितियां (आईसीसी) गठित की गयी हैं। इन दिशानिर्देशों को अब सीसीएस (कंडक्ट) रूल्स, 1964 के तहत नियम 3सी में शामिल कर लिया गया है। समिति का स्वरूप इस प्रकार हैः

Ø-l-	uke	inuke	VsyhQku u-
1.	सुश्री नानू भसीन, निदेशक	अध्यक्ष	टेलीः 23488090 फैक्सः 23488093
2.	सुश्री विजय लक्ष्मी कासोटिया, संयुक्त निदेशक	सदस्य	टेलीः 23386977
3.	श्री विद्या भूषण अरोड़ा, संयुक्त निदेशक	पुरुष सदस्य	टेलीः 23389937
4.	सुश्री नवनीत कौर, संयुक्त निदेशक	सदस्य सचिव	टेली :23488305
5.	डॉ. प्रेमा कोहली, क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट और सदस्य विशाखा समिति (वीएलसीसी कॉरपोरेशन)	बाहरी सदस्य	मोबा. नं. 9811862338
6.	श्रीमती सोनाली दत्ता, अनुभाग अधिकारी	सदस्य	टेलीः 23381137

lrdZrk çdks"B

(1) मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में संगठन का सतर्कता संबंधी ढांचा

पीआईबी का सतर्कता संबंधी ढांचा प्रधान महानिदेशक (मीडिया और संचार) के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करता है जिसमें मदद के लिए सतर्कता अधिकारी (संयुक्त निदेशक स्तर के), उप निदेशक (सतर्कता) और अन्य अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं और क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में वहां के क्षेत्रीय प्रमुख भी उन्हें सौंपी गयी जिम्मेदारियों के तहत मदद करते हैं।

(2) अवधि के दौरान की गयी निवारणात्मक सतर्कता गतिविधियां–

(क) अवधि के दौरान किये गये नियमित और औचक निरीक्षणों की संख्या – शून्य

(3) अवधि के दौरान निगरानी और खोज गतिविधियांः

(क) निगरानी के लिए चुने गये क्षेत्रों का विवरणः

पत्र सूचना कार्यालय के सामान्य, जन संपर्क और कार्यालय स्वचालन अनुभागों को निगरानी के लिए चुना गया। इन अनुभागों के अनुभाग अधिकारियों और इनमें काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के पदों को संवेदनशील पाया गया। इनमें काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को नीति के अनुसार अदला–बदली करके तैनात किया जा रहा है।

(4) जिन मामलों में नियोक्ता प्राधिकारी राष्ट्रपति से भिन्न है उनमें दंडात्मक कार्रवाई (संख्या को 4(1) से 4(10) तक के कॉलमों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए):

(i)	अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें/संदर्भ की संख्या	05
(ii)	कितने मामलों में प्राथमिक जांच करायी गयी	शून्य
(iii)	कितने मामलों में प्राथमिक जांच रिपोर्ट मिली	शून्य
(iv)	कितने मामलों में बड़ा दंड दिया गया	शून्य
(v)	कितने मामलों में छुटपुट दंड के लिए आरोप पत्र जारी किये गये	शून्य
(vi)	कितने लोगों के खिलाफ बड़ा दंड लगाया गया	शून्य
(vii)	कितने लोगों के खिलाफ छुटपुट दंड लगाया गया	शून्य
(viii)	निलंबित किये गये लोगों की संख्या	शून्य
(ix)	कितने लोगों को चेतावनी देकर उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गयी	शून्य
(x)	कितने लोगों को नियमों के प्रावधानों के तहत समय से पहले सेवानिवृत्ति दी गयी	शून्य

lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 l lcf/kr ekey

पत्र सूचना कार्यालय के प्रशासन–1 अनुभाग को मुख्यालय में आरटीआई से संबंधित मामलों का नोडल अनुभाग नामित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार

नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए सीपीआईओ और अपीलीय अधिकारियों को भी मनोनीत किया गया है।

पत्र सूचना कार्यालय (मुख्यालय) ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 4 (ख) (1) और 4 (ख) (2) के तहत भी, (जो किसी सार्वजनिक प्राधिकारी के पास उपलब्ध तमाम सूचनाओं को स्वयं की पहल पर प्रकट करने से संबंधित है) इस तरह की सभी सूचनाएं अपने वेबसाइट पर अपलोड कर पब्लिक डोमेन में डाल कर अपना दायित्व पहले ही पूरा कर दिया है। इस सिलसिले में प्राप्त हुए, अस्वीकृत किये गये और स्थानांतरित आवेदनों/अपीलों की संख्या के बारे में त्रैमासिक रिपोर्ट सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नियमित रूप से केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर नियत समय पर अपलोड कर दी जाती है।

fgUnh vkSj mnwZ ,dka'k dh xfrfof/k;ka

हिन्दी और उर्दू एकांश की मुख्य गतिविधियों में दैनिक प्रेस राउंड अप तैयार करना शामिल है जिसमें हिन्दी/उर्दू दैनिकों की हेडलाइन्स और संपादकीय लेखों का अंग्रेजी अनुवाद किया जाता है। इसके अलावा पीआईबी की प्रेस विज्ञप्तियों, फीचर और बैकग्राउंडर्स का हिन्दी/उर्दू अनुवाद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के भाषणों तथा मैनुअल व पुस्तिकाओं का अनुवाद और मिलान आदि शामिल हैं। हिन्दी और उर्दू एकांशों ने 1 अप्रैल 2017 से 28 नवंबर 2017 तक 7501 प्रेस विज्ञप्तियां, 151 फीचर तथा बैकग्राउंडर्स हिन्दी और उर्दू में जारी किये।

foKkiu ,oa –'; çpkj funs'kky;

1955 में स्थापित विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) भारत सरकार की प्रमुख मल्टी मीडिया विज्ञापन एजेंसी है। पिछले 62 वर्षों से यह लगभग सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, स्वायत्त संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संचार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है और उन्हें एक ही स्थान पर किफायती सेवाएं उपलब्ध करा रही है। डीएवीपी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में शहरी और ग्रामीण जनता को सूचित और शिक्षित करता है और उन्हें विकास गतिविधियों में शामिल होने के बारे में प्रेरित करता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के साधनों जैसे प्रिंट मीडिया विज्ञापन, दृश्य–श्रव्य विज्ञापन, मुद्रित प्रचार, प्रदर्शनियों, बाह्य प्रचार, न्यू मीडिया और मास मेलिंग का सहारा लिया जाता है।

lxBukRed <kapk

डीएवीपी के संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत मुख्यालय में कई स्कंध हैं जैसे प्रचार अभियान, बाह्य प्रचार, मुद्रित प्रचार, प्रदर्शनी, मास मेलिंग, ऑडियो–विजुअल स्कंध, डिजायन स्टूडियो और प्रशासनिक व लेखा स्कंध।

बेंगलुरु और गुवाहाटी में निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो इन क्षेत्रों में निदेशालय की गतिविधियों में समन्वय करते हैं। डीएवीपी का देशभर में फैला 32 क्षेत्रीय प्रदर्शनी इकाइयों का एक नेटवर्क है जो सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण संचार संपर्क के रूप में कार्य करते हैं। क्षेत्रीय प्रदर्शनी इकाइयां महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर केन्द्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिए देश के दूर–दराज इलाकों में सामाजिक और विकास संबंधी विषयों पर विभिन्न प्रचार माध्यमों पर आधारित मल्टीमीडिया प्रदर्शनियां आयोजित करती हैं।

2017&18 dh nkSjku fy, x, çeq[k uhfrxr funs'k rFkk igy

चैनलों का पैनल बनाने और सरकारी विज्ञापनों की दरें तय करने के नीति–निर्देश बनाने के लिए एक नई निजी केबल और सैटेलाइट टेलीविजन चैनल विज्ञापन नीति बनाई गई और इसे 10 जुलाई, 2017 से लागू कर दिया गया। यह नीति 2012 और 2013 के नीति–निर्देशों के स्थान पर लाई गई है। नए दिशानिर्देश डीएवीपी की वेबसाइट http://davp.nic.in/writereaddata/announce/New_policy_Tv.pdf पर उपलब्ध है।

डीएवीपी की नई प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति (डीएवीपी की वेबसाइट http://davp.nic.in/writereaddata/announce/New_policy_Tv.pdf पर उपलब्ध) का उद्देश्य ऐसे समाचार पत्रों के विज्ञापन बंद कराना है जो या तो छपते ही नहीं या कभी–कभार छपते हैं। इससे सरकार के विज्ञापन बजट की बचत होगी। 1 अप्रैल, 2017 के डीएवीपी के पैनल में करीब 8000 समाचार पत्र थे। सरकार द्वारा 2017–18 में किए गए अनेक उपायों के फलस्वरूप 2819 अखबारों को पैनल से हटा दिया गया और इस तरह से पैनल में मात्र 5171 अखबार हैं। यह कार्यवाही निम्नलिखित दस्तावेजों को नही भेजने के आधार पर की गई– मासिक नियमित रिपोर्ट नहीं भेजना,

आरएनआई की वार्षिक रिटर्न और 45000 से अधिक दैनिक प्रसार संख्या वाले अखबारों के लिए अनिवार्य एबीसी/आरएनआई प्रसार पुष्टि प्रमाणपत्र। इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में प्रिंटिग प्रेसों के सख्ती से मुआयने के बाद भी पैनल से हटाने के फैसले किए गए।

2017&18 d nkjku egRoi.k xfrfof/k;k

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने महत्वपूर्ण विषयों पर कारगर व एकीकृत अभियानों के जरिए देश के सभी भागों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए अपने संपर्क का दायरा बढ़ाने तथा कामकाज में पारदर्शिता व जवाबदेही लाने की कई पहल कीं। सभी कारोबारी लेन–देन, जैसे रिलीज ऑर्डर तैयार और जारी करना, बिलों की प्राप्ति व भुगतान, निजी केबल व उपग्रह चैनलों, निजी एफएम स्टेशनों, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों तथा समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पैनलबद्ध करने के लिए आवेदनों की प्राप्ति और उनपर कार्रवाई जैसी तमाम गतिविधियां डीएवीपी के एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) मॉड्यूल के हिस्से के रूप में ऑनलाइन कर दी गई हैं।

भारत सरकार की नई प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति–2016 7 जून, 2016 से लागू हुई और इसे डीएवीपी की वेबसाइट (http://www.davp.nic.in/newspaperadvertisement.policy.html) पर 9 जून, 2016 को अपलोड किया गया। जो प्रकाशन आरएनआई/एबीसी से अपनी प्रसार संख्या का सत्यापन करवा लेते हैं, जिनके पास अपनी प्रिंटिंग प्रेस हैं, जो कर्मचारी भविष्य निधि की सदस्यता लेकर कल्याण उपाय अपनाते हैं और व्यावसायिक मानदंडों पर खरे उतरते हैं, उन्हें नीति में निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गंभीर और नियमित रूप से छपने वाले प्रकाशनों को प्रोत्साहित करने के लिए सत्यापन, अंकों को मासिक प्राप्ति और मार्किंग प्रणाली संबंधी नीति और इसके विनियम बनाकर लागू किये गए हैं। इस नीति की विभिन्न धाराओं को लागू करने के बाद कई अखबारों को विभिन्न चरणों में निलंबित/हटाया गया है।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने अपनी नीति के तहत उन अनियमित समाचार पत्र–पत्रिकाओं जिन्होंने आरएनआई को वार्षिक विवरण नहीं जमा किया है और अपनी प्रसार संख्या आरएनआई/एबीसी से सत्यापित नहीं किया है, उनके खिलाफ निम्न कदम उठाए गए हैः

क.	पीआईबी/डीएवीपी कार्यालयों में नियमित रूप से अंक न भेजना	नीति की धारा 13 और 25(ख) के अनुसार मुद्रित अंक मासिक रूप से पीआईबी/डीएवीपी में जमा न कराने वाली 804 पत्र–पत्रिकाओं को डीएवीपी ने 6 अप्रैल, 2017 से अपने पैनल से हटा दिया।
	वार्षिक विवरणी आरएनआई को न भेजना	नीति की धारा–15 (नोट–2) के अनुसार सभी पैनलबद्ध प्रकाशकों के लिए हर साल सितंबर में पिछले वित्त वर्ष के लिए आरएनआई में जमा कराई वार्षिक विवरणी की प्रतिलिपि (आरएनआई में प्राप्ति के प्रमाण समेत) भेजना जरूरी है। ऐसा न करने पर डीएवीपी, महानिदेशक पत्र–पत्रिका को निलंबित कर सकते हैं। डीएवीपी ने वर्ष 2015–16 के लिए विवरणी ऑनलाइन जमा न कराने पर 405 पत्र–पत्रिकाओं को 11 मई, 2017 से निलंबित कर दिया।
ग.	45,000 से अधिक प्रतियां बेचने वाली पत्र–पत्रिकाओं द्वारा 31 मई, 2017 तक आरएनआई/एबीसी प्रमाणपत्र न भेजा जाना	1 जून, 2017 से 1438 पत्र–पत्रिकाओं के डीएवीपी रेट कार्ड पर नीति की धारा 12 के तहत रोक लगा दी गई जिसमें कहा गया है कि ''डीएवीपी 45,000 से अधिक प्रतियां बिकने का दावा करने वाले ऐसे अखबारों को आरएनआई/एबीसी का प्रसार संख्या सत्यापन प्रमाणपत्र जमा कराए बिना दर नहीं देगी''। कई अखबारों (लगभग 1100) ने इस आशय का अनुरोध किया था कि वर्ष 2016–17 के लिए आरएनआई में जमा कराई गई वार्षिक विवरणी की प्रति वर्ष 2017–18 के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रसार संख्या में कमी की जाए। तदनुसार डीएवीपी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को 19 जून, 2017 को ऐसे अखबारों की प्रसार संख्या वार्षिक विवरणी/सीए के प्रमाणपत्र के आधार पर कम करने के बारे में एक प्रस्ताव सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजा। डीएवीपी के प्रस्ताव के उत्तर में मंत्रालय ने 30 जून 2017 को प्रसार संख्या में कमी के बारे में विचार करने की मंजूरी दी।

- स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) पर बाह्य प्रचार, न्यू मीडिया, प्रिंट और ऑडियो–विजुअल आदि माध्यमों के जरिए विभिन्न प्रकार के प्रचार अभियान चलाए गए।

- यह साल प्रदर्शनियों के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ है। अनेक अति विशिष्ट व्यक्तियों और विशिष्ट व्यक्तियों ने विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया/इनमें हिस्सा लिया। अप्रैल 2017 से अक्तूबर 2017 तक डीएवीपी ने कुल 80 प्रदर्शनियों का आयोजन किया जिनके प्रदर्शनी दिवसों की संख्या 388 रही। सत्तारूढ़ सरकार के तीन साल पूरे होने पर डीएवीपी ने देशभर में प्रत्येक राज्य की राजधानी में 'साथ है विश्वास है– हो रहा विकास है' विषय पर सरकार की उपलब्धियों के बारे में कामकाजी तालमेल के साथ व्यापक अभियान चलाया। इस विषय पर 22 प्रदर्शनियां आयोजित की गईं जिनका उद्घाटन विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों, सांसदों और अन्य जन प्रतिनिधियों ने किया या इनमें इनकी भागीदारी रही। मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली में सरोजिनी नगर के पिलंजी गांव में किया गया जिसका उद्घाटन तत्कालीन माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की उपस्थिति में किया।

- संसदीय कार्य मंत्रालय के लिए अगस्त 2017 से अक्तूबर 2017 तक 'नया भारत हम करके रहेंगे' विषय पर विशाल अभियान बड़ा सफल रहा। यह प्रदर्शनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली में आयोजित की गई और इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष माननीया श्रीमती सुमित्रा महाजन और संसदीय राज्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। इस अभियान में इस्तेमाल किये गए 65 प्रतिशत से अधिक उपकरण इलेक्ट्रॉनिक किस्म के थे जैसे एलईडी वॉल, जेस्चर वॉल, प्लाज्मा टीवी, टच स्क्रीन आदि। इसी विषय पर डीएवीपी ने 17 प्रदर्शनियों का आयोजन किया। इन प्रदर्शनियों का उद्घाटन माननीय उपराष्ट्रपति, केन्द्र सरकार के कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों ने किया या इनमें उनकी भागीदारी रही। इसके अलावा डीएवीपी ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रदर्शनियों की पूरी योजना बनाकर दी जिसके अनुसार उन्होंने प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन कर्नाटक में उडूपी में 'नया भारत हम करके रहेंगे' प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए

- इनके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में अष्टलक्ष्मी–विकास पहल, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर–सामाजिक न्याय के योद्धा, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, मेरा देश बदल रहा है–आगे बढ़ रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और शराब व मादक पदार्थों की लत जैसे विषयों पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।

- सरकार के जिन प्रमुख कार्यक्रमों पर विज्ञापन जारी किए गए उनमें शामिल हैं: आय घोषणा योजना (आईडीएस), वस्तु और सेवा कर (जीएसटी)– एक कर, एक राष्ट्र, जन धन योजना (जेडीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), एनपीएस योजना, सॉवरेन गोल्ड बांड योजना, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), नोटबंदी योजना, डिजिटल लेनदेन, गरीब कल्याण योजना और अग्रिम कर/करों की ई–फाइलिंग की योजना आदि।

- पिछले वर्षों की तरह डीएवीपी ने जनवरी, 2018 में भारत सरकार के कलैंडरों और डायरियों का मुद्रण किया। इस वर्ष 4.02 लाख दीवार कलैंडर और 41,000 डायरियां वितरित की गईं।

- xkok e Hkkjr dk vrjk"Vh; fQYe lekjkg 2017: डीएवीपी ने गोवा में आयोजित भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2017 के प्रचार–प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वर्ल्ड सिनेमा–आईएफएफआई हैंडबुक एंड कैटलॉग, इंडियन सिनेमा–आईएफएफआई कैटलॉग, और कई पुस्तिकाएं, ब्रोशर और पोस्टर छापे। आईएफएफआई, 2017 के आयोजन स्थल पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई।

- डीएवीपी ने सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद कर विभाग के लिए 1 जुलाई, 2017 से लागू हुए वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) पर प्रिंट मीडिया के जरिए आधे और पूरे पृष्ठ के विज्ञापनों के जरिए देशव्यापी सघन विज्ञापन अभियान चलाया ताकि प्रभावित पक्ष को सूचनाएं और जानकारियां मिलें। विज्ञापन में लोगों को नये टैक्स ढांचे तथा विभिन्न वस्तुओं पर लागू होने वाली दरों के बारे में जानकारी के साथ–साथ व्यापार और उद्योग संगठनों के लिए संदेश भी दिये गए। डीएवीपी ने 'साथ है विश्वास है, हो रहा विकास है' विषय पर भी आडियो–विजुअल और बाह्य प्रचार अभियान चलाया।
- निदेशालय के श्रव्य–दृश्य स्कंध के प्रमुख अभियान इस प्रकार हैं:

  स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, संकल्प से सिद्धि, कालाधन विरोधी दिवस– नोटबंदी, आयकर विवरण, भारतीय विशिष्ट प्रचार संख्या प्राधिकरण–आधार, पर्यटन पर्व, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, नियमित टीकाकरण, परिवार नियोजन, शिशु स्तनपान, मीजल–रुबेला टीकाकरण, मिशन इंद्रधनुष, ग्राम समृद्धि अभियान।

Ldi/k&okj fooj.k

vfHk;ku Ldi/k

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की अप्रैल 2017 से संचालित महत्वपूर्ण गतिविधियों का विवरण इस प्रकार हैः

- 'साथ है विश्वास है, हो रहा विकास है' अभियान : 'साथ है विश्वास है, हो रहा विकास है' विषय पर मई 2017 में मल्टीमीडिया अभियान चलाया गया और पूरे पृष्ठ का प्रिंट विज्ञापन जारी किया गया और सरकार की इस पहल और अन्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी को जन–जन तक पहुंचाया गया।

माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती जुबिन ईरानी गोवा में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान डीएवीपी और एनएफएआई द्वारा आयोजित 'स्त्री– ए ट्रिब्यूट टू इंडियन वुमनहुड' का अवलोकन करते हुए।

सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री एन.के. सिन्हा नई दिल्ली में सूचना भवन में आयोजित श्रमदान में हिस्सा लेते हुए

डीएवीपी ने ग्यारह विषयों पर फोल्डर बनाने की परिकल्पना की, डिजाइन तैयार किये और मुद्रण किया।

- एकता दौड़ और राष्ट्रीय एकता दिवस अभियान : सरदार पटेल की जयंती पर प्रिंट, टीवी, रेडियो और डिजिटल सिनेमा के जरिए मल्टीमीडिया अभियान चलाया गया।
- संकल्प से सिद्धि : यह अभियान प्रिंट, टीवी और रेडियो पर चलाया गया और इसके लिए एक थीम सांग भी तैयार किया गया। डीएवीपी ने एक शपथ भी तैयार की। 'यह इंडिया का टाइम है' विषय पर देशभर में लोकप्रिय रॉक बैंडों के जरिए शिक्षा संस्थाओं में एक रॉक कन्सर्ट भी आयोजित किया गया।
- भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह : भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के प्रचार–प्रसार के लिए मुद्रित विज्ञापनों, आउटडोर प्रचार और इंटरनेट विज्ञापनों के जरिए अभियान चलाया गया।
- भारत सरकार के दीवार कैलेंडर का आकल्पन और मुद्रणः डीएवीपी का एक प्रमुख कार्य हर नये साल पर कैलेंडर का आकल्पन, मुद्रण और वितरण करना भी है। वर्षों से ये कैलेंडर सामाजिक संदेशों को आम जनता तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम रहे हैं।
- डीएवीपी ने भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए इमेज प्रोजेक्शन यानी छवि निर्माण अभियान भी शुरू किये हैं। निदेशालय के ऑडियो–विजुअल स्कंध के साथ तालमेल से इन अभियानों को बार–बार सुचारु रूप से और शीघ्रता से चलाया गया।

कुछ प्रमुख अभियान जो कि वित्त वर्ष 2017–18 के लिए नवंबर, 2017 तक विभिन्न मंत्रालयों के अधीन किए गए हैं, निम्न मंत्रालयों के अधीन हैं:

foRr e=ky;

डीएवीपी ने वित्त मंत्रालय के विभिन्न विभागों, जैसे आयकर और पीआर, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पीएफआरडीए, आर्थिक कार्य विभाग और वित्तीय सेवा विभाग की प्रचार संबंधी गतिविधियों का संचालन किया और सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए प्रचार–प्रसार किया। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) पर जून 2017 से छेड़ा गया व्यापक अभियान एक प्रमुख गतिविधि रहा। कुछ अन्य प्रमुख योजनाएं जिनको आधार बनाकर विज्ञापन जारी किये गए इस प्रकार हैं: कर अधिनियम–अग्रिम कर, आधार को पैन से जोड़िये, आईटीआर फार्म–सहज, भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में करदाताओं का लाउंज, आय के अनुच्छेद 269 एसटी के प्रावधान, सावरेन गोल्ड बांड योजना, ऑपरेशन क्लीन मनी, सतर्कता जागरूकता, स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस), आयकर दिवस, 2017/आयकर विवरणों की ई–फाइलिंग।

विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स– जैसे प्रिंट, बस स्टॉप के जरिए आउटडोर प्रचार, रेलवे पास, होर्डिंग, मेट्रो रेल स्टेशनों, टीवी और रेडियो स्पॉट, केबल सैटेलाइट चैनल, इंटरनेट वेबसाइट, भारतीय रेलवे की वेबसाइट, जनता पर असर डालने के लिए एसएमएस और डिजिटल सिनेमा अभियान के जरिए विज्ञापन जारी किए गए डीएवीपी की भूमिका की व्यापक सराहना हुई खास तौर पर आईडीएस पर अभियान के लिए आयकर निदेशालय ने विशेष रूप से सराहना की।

okf.kT; vkSj m|ksx e=ky;

डीएवीपी ने वैश्विक प्रदर्शनी सेवाओं तथा भारत में कारोबार करने की सहूलियत पर विज्ञापन जारी किये।

fo|qr ea=ky;

विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की ओर से ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा की खपत की दृष्टि से दक्ष इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को स्टार चिन्ह देने की प्रमुख योजनाओं के बारे में मीडिया अभियान चलाया गया। अखबारों में विज्ञापन जारी कर स्कूली बच्चों के लिए ऊर्जा संरक्षण के बारे में चित्रकला प्रतियोगिता का प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश में प्रचार किया गया। डीएवीपी ने ये अभियान सफलतापूर्वक पूरे किये।

lkekftd U;k; vkSj vf/kdkfjrk

कुछ प्रमुख कार्यक्रम जिनपर विज्ञापन जारी किये गए इस प्रकार हैंः डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध कारोबार को रोकने के लिए अभियान, दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण/किट के वितरण खरीदने के लिए देशभर में आयोजित किये जाने वाले शिविरों के बारे में अभियान और मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध कारोबार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में प्रचार अभियान। मंत्रालय ने संदेशों के व्यापक प्रचार के लिए बाह्य प्रचार का सहारा लिया तथा श्रोताओं और जनमत तैयार करने वालों को लक्ष्य करके राज्य–स्तरीय अभियान चलाए।

i;ZVu ea=ky;

प्रमुख प्रचार कार्यक्रम जैसे यात्रा और पर्यटन प्रति–स्पर्धा इंडेक्स में सुधार, मुन्नार और मदुरै, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार समारोह, पर्यटन पर्व तथा अखिल भारतीय आधार पर पर्यटन पर्व का आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्रालय ने संवर्धन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजिटल मीडिया के साथ–साथ प्रिंट मीडिया का व्यापक उपयोग किया।

सिंहस्थ कुंभ, स्वच्छ भारत एप और भारत पर्व के प्रचार–प्रसार के लिए टीवी/रेडियो जैसे माध्यमों का भी उपयोग किया गया।

dkfeZd] yksd f'kdk;r vkSj isa'ku ea=ky;

परिवार पेंशनरों की जानकारी के लिए पेंशन नियमों के बारे में प्रिंट मीडिया में विज्ञापन जारी किये गए। आधार से जोड़ने के बारे में मल्टीमीडिया मंचों जैसे रेडियो से जिंगलों का प्रसारण किया गया और प्राइवेट एफएम स्टेशनों तथा आकाशवाणी से जीवन प्रमाण के उपयोग के बारे में बताया गया।

डीएआरपीजी की ओर से राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस सम्मेलन पुरस्कार पर विज्ञापन जारी किया गया। अप्रैल 2017 में सिविल सेवा दिवस के बारे में देशभर के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किये गए।

x`g ea=ky;

डीएवीपी ने गृह मंत्रालय और इसके बहुत से विभागों जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, एनडीएमए, एनआईडीएम, एसएसबी, सीआरपीएफ, सिविल सेवाएं, होम गार्ड तथा एनआईए के टेंडर, ईओआई, भर्ती विज्ञापन प्रिंट मीडिया के लिए जारी किये। महत्वपूर्ण अवसरों जैसे स्थापना दिवस, एकता दौड़ आदि के अवसर पर बड़े आकार के डिस्प्ले विज्ञापन भी जारी किये गए। देशभर में फैली इकाइयों के नियमित और बड़े पैमाने पर क्लासीफाइड विज्ञापन गृह मंत्रालय के विज्ञापनों की विशेष बात हैं। अर्धसैनिक बलों की सामरिक आवश्यकताओं को देखते हुए इन विज्ञापनों का समय पर छपना बहुत जरूरी है जिसके लिए इनपर खास तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदाओं के बचाव के लिए सुरक्षा संबंधी मानदंडों के प्रचार के लिए नियमित रूप से मल्टीमीडिया अभियान का सहारा लेता है।

oL= ea=ky;

वस्त्र मंत्रालय और इसके अंतर्गत विकास आयुक्त हस्तशिल्प और विकास आयुक्त हथकरघा जैसे विभाग अपने मास्टर क्लस्टर्स और उत्पाद बिक्री आयोजनों के प्रचार के लिए डीएवीपी के माध्यम से प्रिंट मीडिया में नियमित रूप से विज्ञापन जारी करते हैं। इसने राष्ट्रीय वस्त्र पुरस्कार और अन्य आयोजनों का भी प्रचार किया जिसमें कैबिनेट दर्जे के वस्त्र मंत्री अतिथि या वक्ता थे। विशाल वस्त्र व्यापार मेले, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, दीन दयाल हस्तकला संकुल आदि के बारे में भी विज्ञापन जारी किये गए।

ikr ifjogu] lM+d ifjogu vkSj jktekxZ ea=ky;

मंत्रालय के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन की ओर से देशभर में फैली इसकी इकाइयों की कामकाजी जरूरतों को पूरा करने के लिए डीएवीपी ने नियमित रूप से वर्गीकृत विज्ञापन जारी किये। देशभर में फैली बीआरओ इकाइयों के नियमित और बड़े पैमाने पर जारी होने वाले वर्गीकृत विज्ञापन सीमा सड़क संगठन की महत्वपूर्ण विशेषता हैं। अर्धसैनिक बलों की समयबद्ध और सामरिक

दृष्टि से महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के कारण इन विज्ञापनों पर गहरी और लगातार निगाह रखनी पड़ती है।

अप्रैल 2017 में मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। इस आयोजन के लिए डीएवीपी ने प्रिंट और टीवी जैसे माध्यमों के जरिए सफल मल्टीमीडिया अभियान संचालित किया जिसकी बड़ी सराहना हुई।

l{e] y?kq vkSj e/;e m|e ea=ky;

मंत्रालय ने देश में फैली अपनी इकाइयों के प्रशिक्षण और प्रदर्शनियों के आयोजन से संबंधित मुद्रित विज्ञापन नियमित आधार पर जारी किये। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किये जाने वाले पुरस्कार वितरण समारोहों का भी प्रचार किया गया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के डेटा बैंक, उद्यमिता दिवस, पोर्टल के शुभारंभ समारोह तथा खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा देशभर में खादी को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर भी विज्ञापन जारी किये गए।

miHkksDrk ekeyksa] [kk| vkSj lkoZtfud forj.k

'जागो ग्राहक जागो' तथा 'आईएसआई और हॉलमार्क' जैसे विषयों पर डीएवीपी द्वारा प्रिंट, बाह्य प्रचार और श्रव्य–दृश्य माध्यमों के जरिए उपभोक्ता जागरूकता अभियान संचालित किये गए।

Je vkSj jkstxkj ea=ky;

डीएवीपी ने 'बालश्रम निवारण' विषय पर मल्टीमीडिया प्रचार अभियान टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल सिनेमा और प्रिंट मीडिया के जरिए चलाया। 'यूनीवर्सल एकाउंट नंबर' विषय पर भी बाह्य प्रचार अभियान और श्रव्य–दृश्य अभियान चलाया गया। भविष्य निधि से जुड़े मुद्दों पर प्रचार अभियान संचालित किये गए।

Hkkjrh; fof'k"V igpku çkf/kdj.k

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों) की ओर से डीएवीपी ने प्रिंट, बाह्य प्रचार और श्रव्य–दृश्य अभियान संचालित किये जो आधार पंजीकरण, विभिन्न सेवाओं को आधार से जोड़ने के फायदों, पंजीयन और नवीकरण की दरों आदि पर केन्द्रित थे।

lkaf[;dh vkSj dk;ZØe fØ;kUo;u ea=ky;

मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की ओर से डीएवीपी ने सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण पर प्रिंट, डिजिटल सिनेमा और बाह्य प्रचार अभियान संचालित किये।

LokLF; vkSj ifjokj dY;k.k

मंत्रालय की ओर से परिवार नियोजन, विश्व मधुमेह दिवस, टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, भारतीय अंगदान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, गर्भाधान–पूर्व तथा प्रसव–उपरांत निदान प्रविधियाँ (पीसीपीएनडीटी), मिशन इंद्रधनुष, डेंगू, मलेरिया और जापानी एनसेफेलाइटिस, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, विश्व हैपटाइटिस दिवस और विश्व एड्स दिवस जैसे विषयों पर विज्ञापन जारी किये गए।

vk;q"k ea=ky;

आयुष मंत्रालय की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आरोग्य मेला और आयुर्वेद दिवस जैसे विषयों पर विज्ञापन जारी किये गए।

—f"k vkSj fdlku dY;k.k ea=ky;

मंत्रालय ने विश्व मात्स्यिकी दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, विश्व खाद्य दिवस और कृषि उन्नति मेला जैसे विषयों पर विज्ञापन जारी किये।

is;ty vkSj LoPNrk ea=ky;

मंत्रालय की ओर से विश्व शौचालय दिवस, संकल्प से सिद्धि, स्वच्छता ही सेवा और दरवाजा बंद जैसे विषयों पर विज्ञापन जारी किये गए।

çn'kZuh Lda/k

अप्रैल 2017 से अक्तूबर 2017 तक डीएवीपी ने कुल 80 प्रदर्शनियों का आयोजन किया जिनमें प्रदर्शनी दिवसों की संख्या 388 रही। सत्तारूढ़ सरकार के तीन साल पूरे होने पर कामकाजी तालमेल के तौर पर डीएवीपी ने देश के प्रत्येक राज्य की राजधानी में केन्द्र सरकार की उपलब्धियों पर 'साथ है विश्वास है, हो रहा विकास है' विषय से एक बड़ा प्रचार अभियान चलाया। इसी विषय पर डीएवीपी ने 22 प्रदर्शनियों का आयोजन किया जिनका या तो उद्घाटन विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों, सांसदों और अन्य जन प्रतिनिधियों के हाथों से हुआ या फिर इनमें उनकी भागीदारी रही। मुख्य समारोह नई दिल्ली में सरोजिनी नगर के पिलंजी गांव में आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन तत्कालीन माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू ने सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की उपस्थिति में किया।

'नया भारत, हम करके रहेंगे' विषय पर संसदीय कार्य

मंत्रालय की ओर से अगस्त 2017 से अक्तूबर 2017 तक एक बड़ा प्रचार अभियान चलाया गया जो बड़ा सफल रहा। इस प्रदर्शनी अभियान में डीएवीपी ने जिन उपकरणों का उपयोग किया उनमें से 65 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे एलईडी वॉल, जेस्चर वॉल, प्लाज्मा टीवी, टच स्क्रीन आदि थे। इस विषय पर डीएवीपी ने 17 प्रदर्शनियों का आयोजन किया। इन प्रदर्शनियों का उद्घाटन माननीय उप राष्ट्रपति, केन्द्र सरकार के

माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई में 'नया भारत हम करके रहेंगे' विषय पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए

कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों जैसी हस्तियों के हाथों हुआ या फिर उनकी इसमें मौजूदगी रही।

J0;&–'; Ld/k

इस निदेशालय का श्रव्य–दृश्य स्कंध भारत सरकार के विभिन्न सेवार्थी मंत्रालयों और विभागों के अनुरोध पर विभिन्न निजी केबल और सैटेलाइट चैनलों, दूरदर्शन, निजी एफएम स्टेशनों, आकाशवाणी और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के जरिए तरह–तरह के मीडिया अभियान संचालित करता है। इस समय 191 निजी केबल और सैटेलाइट चैनल, 232 निजी एफएम स्टेशन और 96 सामुदायिक रेडियो स्टेशन डीएवीपी में पैनलबद्ध हैं।

चंडीगढ़ में 'नया भारत हम करके रहेंगे' प्रदर्शनी के दौरान दर्शकों की भीड़

v,fM;k&fo t|vy ¼fuekZ.k½

डीएवीपी का ऑडियो–विजुअल (निर्माण) सेल विभिन्न सेवार्थी मंत्रालयों/विभागों के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्मों, ऑडियो–वीडियो स्पॉट्स, जिंगल, प्रायोजित रेडियो कार्यक्रमों आदि का विभिन्न भाषाओं में निर्माण करता है। ये कार्य ऑडियो–विजुअल निर्माण के लिए डीएवीपी द्वारा स्वीकृत निश्चित रेट कार्ड पर पैनल में शामिल प्रोड्यूसरों से कराया जाता है।

foRr o"kZ 2017&18 es vc rd v,fM;k&fo t|vy fuekZ.k

ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए 'बचत के सितारे दोस्त हमारे' नाम के प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम की 52 कड़ियों का अप्रैल 2017 से डीएवीपी के जरिए 20 भाषाओं में निर्माण कराया जा रहा है।

इसके अलावा 7 MkD;eVh फिल्में जिनमें भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लिए 1 फिल्म 'लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन पब्लिक ऑडिट' और एक अन्य 'एनवायर्नमेंट ऑडिट : ए कॉमनवैल्थ परस्पैक्टिव' गृह मंत्रालय के लिए वामपंथी आतंकवाद पर 3 फिल्में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 'न्यू इंडिया मंथन/संकल्प से सिद्धि तक', कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के लिए 1 फिल्म 'असिस्टेंट सेक्रेटरी स्कीम' बनायी गई है।

अप्रैल 2017 से अब तक 15 l vf/kd v,fM;k&fo t|vy Li,Vl@ft xYl तैयार किये गए हैं जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं : गृह मंत्रालय के लिए वामपंथी आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर 4 रेडियो जिंगल्स, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए कौशल विकास पर 1 रेडियो जिंगल और 1 वीडियो स्पॉट, 'एडवोकेसी' पर 1 वीडियो स्पॉट, प्रेरणा योजना पर 1 वीडियो स्पॉट, नेशनल हैल्पलाइन पर 1 वीडियो स्पॉट और विश्व जनसंख्या दिवस–2017 पर जनसंख्या स्थिरता कोष के लिए 1 वीडियो स्पॉट, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र के लिए हैपटाइटिस पर 1 रेडियो जिंगल और 1 टीवी स्पॉट, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस–2017 पर आयोजित एकता दौड़ के सिलसिले में 1 रेडियो और 1 रेडियो स्पॉट, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइफैड के लिए आदि महोत्सव पर 2 रेडियो जिंगल और 1 रेडियो स्पॉट।

U; ehfM;k Ld/k

डीएवीपी का न्यू मीडिया स्कंध भारत सरकार के सेवार्थी

मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध प्राप्त होने पर डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म जैसे डिजिटल सिनेमा, इंटरनेट वेबसाइट और एसएमएस के जरिए कई मीडिया अभियान संचालित करता है। इस समय 8 डिजिटल सिनेमा एजेंसियां, 42 इंटरनेट वेबसाइट (जिनमें indianrailway.gov.in भी शामिल है) और 8 एसएमएस एजेंसियां डीएवीपी में पंजीकृत हैं।

डीएवीपी के न्यू मीडिया विंग द्वारा चलाए गए मुख्य अभियान इस प्रकार हैं :

e=ky;	fo"k;
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	1. भारतीय मानक ब्यूरो – उपभोक्ता जागरूकता
सूचना और प्रसारण	1. भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2017
वित्त	1. पीएफआरडीए 2. अग्रिम कर देय तिथि 3. आयकर आई टी विवरणी 4. ऑपरेशन क्लीन मनी 5. किराये पर टीडीएस
रक्षा	1. भारतीय नौसेना भर्ती
पर्यटन	1. पर्यटन – सामाजिक जागरूकता 2. पर्यटन – पर्यटन हेल्पलाइन 3. पर्यटन– पर्यटन पर्व
बिजली	1. बीईई
शहरी विकास	1. स्वच्छ भारत मिशन
जनजातीय कार्य	1. आदि महोत्सव
नीति आयोग	1. यूआईडीएआई
महिला और बाल विकास	1. महिला और बाल विकास 2. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ 3. कारा (साएआरए)
श्रम और रोजगार	1. बाल श्रम
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	1. ट्रॉमा देखभाल कार्यक्रम 2. आयोडीन अल्पता की बीमारी 3. जनसंख्या स्थिरता कोष 4. आयुष

i lluy ehfM;k lsy

डीएवीपी का पर्सनल मीडिया प्रकोष्ठ पर्सनल मीडिया, जैसे रेलवे रिजर्वेशन टिकटों, बिजली के बिलों, रसोई गैस के बिलों, एक्सेस कार्डों, हवाई अड्डों के बोर्डिंग पासों आदि के जरिए मंत्रालयों/विभागों की जरूरतों व आवश्यकताओं तथा बजट व लक्षित समूह आदि को ध्यान में रखकर कई मीडिया अभियान संचालित करता है। इस समय डीएवीपी के पास 26 एजेंसियों के 20 से अधिक मीडिया संबंधी पूर्ण अधिकार हैं।

1 अप्रैल, 2017 से आगे की अवधि में विभिन्न लाभार्थी मंत्रालयों ने पर्सनल मीडिया विज्ञापनों के जरिए कई प्रमुख अभियान चलाए। पर्सनल मीडिया प्रकोष्ठ द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास तथा महिला और बाल विकास के बारे में सामाजिक संदेश देने वाले प्रमुख अभियान चलाए गए।

ckâ çpkj Ldi/k

डीएवीपी का बाह्य प्रचार स्कंध बस शैल्टरों, बस पैनलों, यूनीपोल्स, रेलों स्टेशनों/हवाई अड्डों आदि में आउटडोर मीडिया के जरिए प्रचार करता है। इस समय डीएवीपी के पास करीब 200 एजेंसियों के 100 मीडिया के एकल उपयोग का अधिकार है।

बाह्य प्रचार स्कंध के प्रमुख अभियान इस प्रकार हैं :

ea=ky;	fo"k;
डाक विभाग (संचार मंत्रालय)	1. डाक के उत्पाद और सेवा 2. डाक जीवन बीमा–पीएलआई/आरपीएलआई 3. भारतीय डाक पर अभियान 4. साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन
उपभोक्ता कार्य	1. आईएसआई चिह्न और हॉल मार्क–बीआईएस 2. उपभोक्ता कल्याण संदेश
उत्तर–पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय,	1. पर्यटन पर्व
वित्त	1. जीएसटी पर अभियान 2. सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और बिक्रीकर पर अभियान 3. सतर्कता जागरूकता सप्ताह
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	1. पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए)
पेयजल और स्वच्छता	1. पेयजल और स्वच्छता
पर्यटन	1. फीफा अंडर 17 विश्व कप, 2017
ऊर्जा	1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो संदेश
शहरी विकास	1. स्वच्छ भारत मिशन
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	1. मादक पदार्थों का दुरुपयोग 2. वरिष्ठ नागरिक
आयुष	1. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
संस्कृति	1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2017 में हुनर हाट प्रदर्शनी
राष्ट्रीय अभिलेखागार	1. चंपारण सत्याग्रह
नीति आयोग,	1. आयकर विवरणी जमा कराने में यूआईडीएआई आधार का उपयोग
महिला और बाल विकास	1. सीएआरए की परामर्श सेवाएं
पोत परिवहन	1. सागरमाला कार्यक्रम
ग्रामीण विकास	1. सामाजिक संदेश 2. पीएमएवाई(जी) और डीडीयू–जीकेवाई 3. प्रगति मैदान में आजीविका मेला (14–23 अप्रैल, 2017)
श्रम और रोजगार	1. ईपीएफओ – ईपीएफओ अभियान 2. ईपीएफओ में कर्मचारियों का पंजीयन
सूचना और प्रसारण	1. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह– 2017 2. होर्डिंग के जरिए कालेधन के खिलाफ अभियान (श्रेणी–1) 3. बाह्य प्रचार मीडिया के जरिए काले धन के खिलाफ अभियान 4. हीलियम बैलून के जरिए 'स्वच्छता' का प्रचार 5. दिल्ली में महत्वपूर्ण स्थानों पर सरकारी पहल के बारे में विज्ञापन
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	1. विश्व खाद्य दिवस, 2017 2. क्षय रोग जागरूकता संदेश 3. आयोडीनयुक्त नमक खाने के फायदे 4. नाको संदेश 5. उत्तर–पूर्वी और पर्वतीय राज्यों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाएं 6. मिशन इंद्रधनुष और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 7. सामाजिक संदेश 8. मिशन इंद्रधनुष और पीएम डायलिसिस कार्यक्रम

मीडिया प्लानिंग, रिलीज आर्डर जारी करने, अभियानों से जुड़ी पैनलबद्ध एजेंसियों से संवाद तथा बिलों के ऑनलाइन प्रेषण और भुगतान जैसी तमाम प्रक्रियाओं के लिए मीडिया प्लान बनाए जाते हैं तथा अन्य प्रक्रियाएं संपन्न की जाती हैं।

लेखा स्कंध

डीएवीपी का लेखा स्कंध हर साल करीब 950 से 1000 करोड़ रुपये के भुगतानों को निपटाता है। डीएवीपी को अपने बजट के अलावा अपने तमाम ग्राहकों – मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से धन प्राप्त होता है और इस राशि को जॉब ऑर्डर व मीडिया संगठनों को संवितरण के प्रमाण के विधिवत् सत्यापन के बाद डीएवीपी में पंजीकृत अखबारों, टेलीविजन चैनलों, रेडियो चैनलों, बाह्य प्रचार एजेंसियों, प्रोडक्शन हाउसों और प्रचार एजेंसियों को संवितरित कर दिया जाता है। भुगतानों को डीएवीपी द्वारा जारी किये गए रिलीज आर्डर की पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार विज्ञापन के प्रसारित या प्रकाशित होने की पुष्टि होने के बाद निपटान किया जाता है।

प्रमुख उपलब्धियां

लेखा स्कंध की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं

1. नये लेखांकन मॉड्यूल पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रचार के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम स्तरों का निर्माण।

2. पीएफएमएस के जरिए स्थापना अनुभाग से संबंधित बिलों और विभिन्न ग्राहक मंत्रालयों के प्राधिकार पत्रों का पीएफएमएस के जरिए सफलता पूर्वक निपटान किया जा रहा है जिससे भुगतान शीघ्रता से और सुचारु रूप से होने लगे हैं।

3. बिल बनाने और उनके भुगतान की प्रक्रिया को वेबसाइट पर देखा जा सकता है जिससे एजेंसियों के बिलों की स्थिति के बारे में पारदर्शिता आती है, खास तौर पर अगर वे किसी कारण से अस्वीकृत हो गए हों, या पारित हो गए हों या फिर वे किसी चरण में हों।

4. सभी एजेंसियों को किसी भी तरह के कार्य/अभियान के लिए शत–प्रतिशत भुगतान अब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रॉसफर (एनईएफटी/आरटीजीएस) के जरिए तत्काल कर दिया जाता है। इससे भुगतान में देरी और डाक में चेक के खोने की कोई आशंका नहीं रह गई है।

सतर्कता अनुभाग

डीएवीपी ने 30 अक्तूबर से 4 नवंबर 2017 तक 'माइ विजन–करप्शन फ्री इंडिया' (भ्रष्टाचार मुक्त भारत की मेरी परिकल्पना) विषय पर 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' आयोजित किया। इसमें सभी कर्मचारियों को निष्ठा की शपथ दिलायी गई और महत्वपूर्ण स्थानों पर बैनर और नोटिस बोर्ड लगाकर भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संदेश का प्रचार प्रसार किया गया। भ्रष्टाचार की रोकथाम और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए अखबारों, ऑडियो–विजुअल कंपनियों और प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए एजेंसियों की सेवाएं लेने के लिए उनको पैनलबद्ध करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करके इसमें तेजी लाने के लिए कदम उठाये गए हैं। ऑडियो–विजुअल कार्य के आबंटन के लिए रेंडम रोस्टर प्रणाली शुरू की गई है जिससे अब प्रोड्यूसरों ने पक्षपात करने की शिकायत करना बंद कर दी है। अखबारी विज्ञापनों के रिलीज ऑर्डर अब पब्लिक डोमेन में डाले जाने लगे हैं। प्रिंट मीडिया और ऑडियो–विजुअल विज्ञापनों के बिलों के निपटान और भुगतान की प्रक्रिया को अब एनआईसी के सहयोग से पूरी तरह स्वचालित चुस्त–दुरुस्त बिल प्रेषण प्रणाली बनायी गई है।

मुद्रित प्रचार स्कंध

मुद्रित प्रचार (पीपी) स्कंध डीएवीपी द्वारा चलाए जा रहे अभियानों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए मुद्रित सामग्री की आवश्यकता पूरी करता है। यह स्कंध मुद्रित की जाने वाली सामग्री से उत्पादन की योजना बनाने और रंगबिरंगे पोस्टर, फोल्डर, ब्रोशर, डायरी, कैलेंडर, स्टिकर, वॉल हैंगर, टेबल कैलेंडर और अन्य विभिन्न वस्तुओं के मुद्रण कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

डीएवीपी सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, बंगाली, असमिया, ओडिया, पंजाबी, उर्दू और हिन्दी में मुद्रित प्रचार सामग्री तैयार करता है। इस स्कंध के पास कार्य कराने के लिए प्रिंटरों, टाइपसैटरों और डायरी मेकरों का पैनल है जो न्यूनतम समय में कार्य पूरा कराता है जिससे खर्च में भी

किफायत होती है।

मुद्रित प्रचार स्कंध ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और अन्य विभिन्न मंत्रालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 50 कार्य किये जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की 91 प्रचार सामग्रियों की लगभग 70,02,725 प्रतियां छापी गयीं।

ekl efyax Ld/k

मास मेलिंग स्कंध को पुस्तिकाओं, फोल्डरों, पोस्टरों, पत्रकों, ब्रोशरों और प्रधानमंत्री के भाषण आदि के रूप में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और संगठनों से मुद्रित प्रचार सामग्री डाक से बड़े पैमाने पर प्रेषित करने के लिए प्राप्त होती है। इस सामग्री का वितरण संबंधित विभाग और/या अभियान के निर्देशों/आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। हर साल कैलेंडर और डायरियां छापी जाती हैं ताकि इन्हें राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और सभी मंत्रालयों तथा उनके संबद्ध कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के अति विशिष्ट लोगों और अन्य लोगों को निशुल्क बांटा जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों के लिए यह कार्य भुगतान आधार पर किया जाता है।

इस समय मास मेलिंग स्कंध के पास 499 श्रेणियों के 5,57,250 पतों का बैंक है। इस साल अब तक विभिन्न विषयों, जैसे साथ है विश्वास है – हो रहा विकास हैं, सैनिक पुनर्वास पत्रिका, मोदी सरकार के शानदार तीन साल, एम्पावरिंग इंडिया पावरिंग इंडिया, ए न्यू डायमेंशन आफ कम्यूनिकेशन, प्रधानमंत्री के भाषण, चार्टर्ड एकाउंटेंट दिवस, प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक इस्राइल यात्रा का फोल्डर, भारत और अमरीका, समर यात्रा, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2017 (विश्व सिनेमा, भारतीय सिनेमा और हैंड बुक) आदि पर प्रचार सामग्री की 59,33,032 प्रतियां वितरित की जा चुकी थीं/भेजी जा चुकी थीं।

ljdkjh foKkiu lkexzh ds fu;eu ds fy, lfefr ¼lhlhvkjth,½

माननीय उच्चतम न्यायालय के 13 मई, 2015 के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक तीन सदस्य समिति गठित की गई। समिति के सदस्य थे – श्री वी.वी.टंडन (अध्यक्ष) न्यूज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रजत शर्मा और ओगिलवी एंड माथर के कार्यकारी प्रमुख श्री पीयुष पांडे। इस समिति की सिफारिशें केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा जारी सभी प्रकार के सरकारी विज्ञापनों पर लागू होने के निर्देश थे।

इस समिति ने अप्रैल से नवंबर 2017 तक तीन बैठकें की। इसके साथ ही समिति ने कुछ मामलों में स्वतः संज्ञान भी लिया। समिति ने सरकारी विज्ञापनों की सामग्री के नियमन से जुड़े विभिन्न अदालती मामलों में मंत्रालय द्वारा तैयार की गई टिप्पणियों के मसौदे का भी अध्ययन किया।

समिति एनआईसी की मदद से अपनी वेबसाइट बना रही है। समिति की अनुमति के बाद सामग्री के बाद सामग्री की मसौदा अपलोड कर दिया जाएगा।

Hkkjr ds lekpkj i=ksa ds iath;d ¼vkj,uvkbZ½

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय (आरएनआई) की स्थापना पहले प्रेस आयोग (1953) की सिफारिश पर प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम, 1867 में संशोधन करके 1 जुलाई, 1956 में की गयी थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रूप में आरएनआई कुछ सांविधिक और कुछ गैर–सांविधिक कार्य करता है।

lxBukRed <kapk

आरएनआई का कार्यालय फिलहाल नई दिल्ली के रामकृष्ण पुरम में स्थित है जिसे चालू वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान सूचना भवन, नई दिल्ली में स्थानांतरित किया जा रहा है। इस कार्यालय के आधुनिकीकरण की कुल

माननीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्रीमती हरसिमरतकौर बादल चंडीगढ़ में डीएवीपी की प्रदर्शनी के दौरान 'संकल्प से सिद्धि' की शपथ लेते हुए

लागत 92.33 लाख रहने का अनुमान लगाया गया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने ''सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण'' के कार्यक्रम के तहत इस लागत का 70 प्रतिशत यानी 69.25 लाख रुपये की मंजूरी दे दी है। बाकी 25 प्रतिशत राशि यानी 23.08 लाख रुपये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बजट से वर्तमान कार्यक्रम ''आधारभूत ढांचे के विकास का आधुनिकीकरण'' (एमआईडीपी) से पूरा किया जाएगा।

आरएनआई के प्रमुख प्रेस पंजीयक होते हैं जिनकी मदद के लिए दो उप प्रेस पंजीयक और तीन सहायक प्रेस पंजीयक हैं। कार्यालय में शीर्षक सत्यापन, पंजीयन, प्रसार संख्या और प्रशासन के लिए अलग–अलग अनुभाग हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पुनर्गठन कार्यक्रम के तहत मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल और गुवाहाटी में आरएनआई के क्षेत्रीय कार्यालय बंद कर दिये गये हैं और पत्र सूचना कार्यालय और क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के सहायक निदेशक स्तर के अधिकारियों को पंजीयन पर्यवेक्षक के रूप में नामित किया गया है जबकि उप निदेशक/निदेशक/अपर महानिदेशक स्तर के अधिकारियों को क्रमशः सहायक/उप/अपर प्रेस पंजीयक के रूप में नामित किया गया है जो प्रेस पंजीयक के अधीक्षण और निर्देशन में अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे।

vkj,uvkbZ ds dk;Z

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यों में देश भर में प्रकाशित समाचार पत्रों और प्रकाशनों का रजिस्टर बनाना, जिला मजिस्ट्रेटों को नये समाचार पत्रों के शीर्षक की स्वीकृति के बारे में सूचित करना और समाचार पत्रों व अन्य प्रकाशनों के प्रकाशकों द्वारा भेजे गये वार्षिक विवरणों की छानबीन और विश्लेषण करना शामिल हैं। आरएनआई देश में प्रिंट मीडिया परिदृश्य के बारे में 'प्रेस इन इंडिया' नाम की रिपोर्ट हर साल 31 दिसंबर तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजता है। गैर–सांविधिक गतिविधियों के तहत आरएनआई अखबारी कागज के आयात के लिए अपने यहां पंजीकृत कागज के वास्तविक उपयोग कर्ताओं के स्व–घोषणा प्रमाणपत्रों का सत्यापन करता है और छपाई मशीनों के आयात के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्रदान करता है। आरएनआई विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापनों के लिए पंजीकृत प्रकाशनों की प्रसार संख्या का सत्यापन भी करता है।

'kh"kZd lR;kiu

आरएनआई को शीर्षकों के सत्यापन के लिए जिला मजिस्ट्रेटों से विधिवत अग्रसारित आवेदन प्राप्त होते हैं जिनका प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम के अनुच्छेद 6 के प्रावधानों के अनुसार सत्यापन किया जाता है। आवेदकों की सुविधा के लिए आरएनआई ने ऑनलाइन सुविधा की भी शुरुआत की है। आवेदक को ऑनलाइन भरे गये आवेदन का प्रिंट आउट संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में आरएनआई को अग्रसारित करने के लिए जमा कराना होता है। आरएनआई में आवेदन की प्राप्ति और शीर्षक के सत्यापन की सूचना आवेदक को एसएमएस और ई–मेल से दी जाती है। आवेदक अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी आरएनआई की वेबसाइट से जानकारी हासिल कर सकता है। शीर्षक सत्यापन के लिए भेजे गये आवेदनों की स्थिति के बारे में पत्र ऑनलाइन भेजे जाते हैं जिन्हें वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। अप्रैल 2017 से नवंबर 2017 तक आरएनआई ने 11,473 आवेदनों की शीर्षक सत्यापन के लिए जांच की जिनमें से 3,272 शीर्षक सत्यापित किये गये।

'kh"kZdksa dks MhCy,d djuk

अगर सत्यापित शीर्षक को दो साल की निर्धारित अवधि में पंजीकृत नहीं कराया गया तो शीर्षकों को आरएनआई के दिशानिर्देशों और प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम के अनुच्छेद 6 के प्रावधानों के अनुसार डीब्लॉक कर दिया जाता है (यानी प्रकाशक के नाम उनका आबंटन समाप्त कर दिया जाता है) जिससे वह शीर्षक किसी भी अन्य आवेदक के नाम से फिर से सत्यापित किया जा सकता है। 31 जनवरी 2014 से पहले सत्यापित 6,000 से अधिक ऐसे शीर्षकों को जिन्हें दो साल की निर्धारित अवधि में पंजीकृत नहीं कराया जा सका था, नवंबर 2017 में डीब्लॉक कर दिया गया।

iath;u

शीर्षक का सत्यापन हो जाने पर प्रकाशक को अपने प्रकाशन के पंजीयन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है जिसमें संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सत्यापित घोषणा आरएनआई द्वारा वांछित दस्तावेजों के साथ भेजनी होती है। प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत प्रकाशन को एक पंजीयन संख्या आबंटित कर दी

जाती है और प्रकाशक को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है। आरएनआई के रजिस्टर में इस बारे में प्रविष्टि दर्ज कर दी जाती है। 2016–17 के दौरान 4,007 प्रकाशनों का पंजीयन किया गया। 31 मार्च 2017 तक आरएनआई में पंजीकृत 1,14,820 प्रकाशनों में से 16,993 समाचार पत्र थे जबकि 97,827 पत्रिकाएं थीं। अप्रैल 2017 से नवंबर 2017 तक 4,518 पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किये गये जिनमें 3,005 नये प्रमाणपत्र और 1,502 संशोधित प्रमाणपत्र तथा 11 डुप्लिकेट यानी प्रतिलिपि प्रमाणपत्र शामिल थे।

okf"kd fooj.kh

प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम, 1867 के अनुच्छेद 19घ के अनुसार समाचार पंजीयन (केन्द्रीय) नियमावली, 1956 के अनुसार प्रकाशकों को वित्त वर्ष पूरा होने के बाद हर साल मई के आखिरी दिन या इससे पहले फार्म–II में वार्षिक विवरण प्रेस पंजीयक को भेजना होता है। इसके अलावा प्रकाशकों को अपने प्रकाशन के स्वामित्व और अन्य विवरणों की जानकारी फार्म–IV में फरवरी के आखिरी दिन के बाद प्रकाशित होने वाले पहले अंक में छापनी होती है। प्रकाशकों द्वारा भरे गये वार्षिक विवरणों के आधार पर आरएनआई आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण से देश में प्रिंट मीडिया के विकास के बारे में 'प्रेस इन इंडिया' नाम की रिपोर्ट तैयार करता है।

वार्षिक विवरण जमा कराने की ऑनलाइन प्रणाली ने 2013–14 में काम करना शुरू किया और यह सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। 2016–17 में 31,028 प्रकाशकों ने वार्षिक विवरण भरे।

dEI;Vjhdj.k

इस समय शीर्षक के लिए आवेदन ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। शीर्षक सत्यापन और पंजीयन आवेदनों के कम्प्यूटर के जरिए निपटान के साथ ही आरएनआई ने सभी सत्यापित शीर्षकों को वेबसाइट पर डालना शुरू कर दिया है जिन्हें आवेदक डाउनलोड कर सकते हैं। इस सुविधा के शुरू हो जाने से कोई भी व्यक्ति/संभावित प्रकाशक मौजूदा शीर्षक डेटाबेस को देख सकता है जो राज्य/भाषा वार उपलब्ध है। आरएनआई एक नया और उपयोग करने वालों के लिए अनुकूल वेबसाइट के विकास

माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती जुबिन ईरानी नई दिल्ली में 15 दिसंबर, 2017 को भारत के प्रेस रजिस्ट्रार के वार्षिक प्रकाशन 'प्रेस इन इंडिया 2016–17 का लोकार्पण करते हुए

के लिए कार्य कर रहा है जिसकी इन दिनों सुरक्षा की दृष्टि से जांच की जा रही है। इसके काम करना शुरू करने के बाद आरएनआई कार्यालय की कई प्रक्रियाएं, जिनमें शीर्षक के लिए आवेदन करना और पंजीयन भी शामिल हैं, पूरी तरह ऑनलाइन काम करने लगेंगी। इतना ही नहीं, सभी जिला मजिस्ट्रेटों को व्यक्तिगत लॉगइन नाम भी दिये जाएंगे जिससे वे आवेदनों को सत्यापन के बाद सीधे आरएनआई को अग्रसारित कर सकेंगे।

^çsl bu bfM;k* dk çdk'ku

प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 के अनुच्छेद 19 (जी) के अनुसार प्रेस रजिस्ट्रार केन्द्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट देते हैं जिसमें देश में पिछले साल समाचार पत्रों के बारे में प्राप्त सूचनाओं का सार संकलित रहता है। 'प्रेस इन इंडिया' नाम की यह रिपोर्ट हर साल दिसंबर के महीने में भेजी जाती है। 2013–14 से इसे डिजिटल फार्मेट में सीडी/डीवीडी के रूप में भी निकाला जा रहा है।

çlkj l[;k dk lR;kiu

प्रकाशकों द्वारा वार्षिक विवरणियों/रिपोर्टों में प्रस्तुत प्रसार संख्या संबंधी आंकड़ों की पुष्टि के लिए प्रसार संख्या के दावों की नियमित रूप से जांच/सत्यापन किया जाता है क्योंकि इसका उपयोग विभिन्न सरकारी विभाग, जिनमें विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) भी शामिल है, सरकारी विज्ञापनों के आबंटन का फैसला करते समय करते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 7.6.2016 को जारी नयी प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति के अनुसार 45,000 से अधिक प्रसार संख्या का दावा करने वाले प्रकाशनों के लिए आरएनआई/एबीसी से प्रसार संख्या का सत्यापन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई नीति के अनुपालन में प्रसार संख्या की जांच के बारे में आरएनआई के दिशानिर्देशों में 10.6.2017 को संशोधन किया गया जिससे प्रसार संख्या के सत्यापन के लिए अधिक कठोर प्रणाली का रास्ता साफ हो गया है जिससे फर्जी अखबारों को खत्म करने में मदद मिलेगी। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रसार संख्या की जांच अब आरएनआई/पीआइबी और डीएवीपी के अधिकारियों की एक टीम करती है जिन्हें प्रेस पंजीयक ऑडिटरों (चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म) के साथ नामित करते हैं। ये ऑडिटर एबीसी, सीएजी और आरबीआई के पैनलों से होते हैं।

v[kckjh dkxt

18 मई 2017 से आरएनआई द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गयी है जिसके तहत किसी अखबार द्वारा आयात किये जाने वाले अखबारी कागज की अधिकतम मात्रा निर्धारित की जाती थी। फिलहाल किसी पंजीकृत प्रकाशक को अखबारी कागज के आयात से पहले एक स्वघोषित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है जिसमें वर्ष के दौरान आयातित अखबारी कागज की मात्रा और आवेदन की तिथि तक वास्तव में इस्तेमाल किये गये कागज की मात्रा बतानी होती है। आरएनआई कार्यालय और पीआईबी के क्षेत्रीय व शाखा कार्यालय यह सुनिश्चित करने के बाद कि प्रकाशक 'वास्तविक उपयोगकर्ता' है, स्व–घोषित प्रमाणपत्र का अधिप्रमाणन करते हैं।

jkt Hkk"kk

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय ने 1–14 सितंबर 2017 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जिसमें सरकारी कामकाज में हिन्दी के उपयोग को बढ़ाने के लिए कई प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गयीं। कार्यालय में एक सहायक निदेशक (राजभाषा) और एक अनुवादक तैनात किये गये हैं जो भारत सरकार की राजभाषा नीति पर अमल और निगरानी रखने तथा अनुवाद में आवश्यक मदद करते हैं।

turk dh f'kdk;r vkj lpuk dk vf/kdkj

आरएनआई कार्यालय में जनता शिकायतों को सुनने के लिए एक प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। प्रकाशक अपनी शिकायतें ई–मेल pqrcrni@nic-in पर या सीधे आरएनआई वेबसाइट पर भेज सकते हैं। एक उप प्रेस पंजीयक को कार्यालय की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली का प्रमुख नामित किया गया है। अप्रैल से नवंबर 2017 तक आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त 516 आवेदनों का जवाब दिया गया।

ukxfjd vf/kdkjk dk ?kk"k.kki=

नागरिकों के अधिकारों का घोषणापत्र तैयार किया गया है और कार्यालय के सरकारी वेबसाइट (http://www.rni.nic.in) पर प्रदर्शित किया गया है।

12oh ;ktuk vkj mld ckn % vkj,uvkb e[;ky; dk l–<hdj.k

12वीं योजना अवधि में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम' नाम की विस्तृत योजना के अंतर्गत आरएनआई मुख्यालय को सुदृढ़ करने की योजना पर 1.65 करोड़ रुपया खर्च किया। योजना के दौरान प्रस्तावित विभिन्न लक्ष्यों में से 'वार्षिक विवरणियों की ई–फाइलिंग' के लक्ष्य को पूरी तरह हासिल कर लिया गया। इस योजना को जारी रखने के लिए संशोधित और नये लक्ष्यों के साथ एसएफसी/ईएफसी का प्रारूप मंत्रालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है जो इस प्रकार हैः

- रिकॉर्ड/दस्तावेजों का डिजिटीकरण।
- शीर्षक आवेदन का प्रेषण और डीएम द्वारा ऑनलाइन अग्रसारण।
- घोषणापत्र का ऑनलाइन प्रेषण।
- पंजीयन प्रमाणपत्र ऑनलाइन उत्पन्न करना।
- समूची पंजीयन प्रक्रिया जिसमें दस्तावेजों का ऑनलाइन प्रेषण भी शामिल है।
- पब्लिक इंटरफेस सिस्टम तैयार करना और सवालों के उत्तर देने की सार्वजनिक प्रणाली को सुदृढ़ करना।
- आरएनआई कार्यालय को सूचना भवन में स्थानांतरित करना।

बजट अनुमान 2017–18 के लिए आरएनआई को 5000 लाख रुपये केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत दिये गये हैं जिसमें से 27.53 लाख 30 नवंबर 2017 तक खर्च किये जा चुके थे।

çl vkj iLrd ith;u vf/kfu;e] 1867 % lekpkj i= vkj çdk'ku ith;u fo/k;d ¼vkj,uih½ 2017

इस समय अमल में आ रहे प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम, 1867 का उद्देश्य मुद्रण प्रेसों और अखबारों को विनियमित करना था ताकि भारत में प्रकाशित पुस्तकों और पत्र–पत्रिकाओं का पंजीयन हो सके और उनकी प्रतियां सुरक्षित रखी जा सके।

देश में समसामयिक मीडिया भारी परिदृश्य में बदलाव के संदर्भ में 1867 के प्रेस और पुस्तक पंजीयन कानून में संशोधन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 'प्रेस और पुस्तक तथा प्रकाशन पंजीयन विधेयक' तैयार किया गया जिसे नवंबर 2011 में मंत्रिमंडल की स्वीकृति से संसद में रखा गया। सूचना और टेक्नोलॉजी संबंधी स्थायी समिति ने इस विधेयक की जांच कर ली है और इसके बारे में कुछ सिफारिशें की थीं। लेकिन 15वीं लोकसभा के समापन के बाद यह विधेयक भी कालातीत हो गया। इसलिए 'समाचार पत्र और प्रकाशन पंजीयन विधेयक, 2017' नाम का एक नया विधेयक तैयार किया गया है जो 1867 के प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम का स्थान लेगा। इस समय इस विधेयक के प्रारूप पर मंत्रालय में गंभीर रूप से विचार किया जा रहा है।

{k=h; çpkj fun'kky; ¼Mh,Qih½

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय को प्रत्यक्ष संवाद और अंतर–वैयक्तिक संवाद कार्यक्रम आयोजित करके जनता के विकास के लिए भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय सूचना के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने का प्रयास करता है ताकि सरकार के कार्यक्रमों/योजनाओं का लाभ उठा सकें। डीएफपी गांवों और अर्ध–शहरी इलाकों में जनमत बनाने वाले स्थानीय नेताओं और लक्षित लाभार्थियों के साथ बातचीत, सामूहिक चर्चा, घर पर जाकर बातचीत, जनसभा आदि का आयोजन करता है। इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न हितधारियों जैसे राज्य सरकार और स्थानीय कार्यकर्ताओं, सामाजिक समूहों आदि के सहयोग से किया जाता है। ये कार्यक्रम स्थानीय भाषाओं में और लोगों के आस–पड़ोस में आयोजित किये जाते हैं इसलिए ऐसे संवाद कार्यक्रमों के असर से सरकार की योजनाओं के बारे में बेहतर समझ बनती है और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। इस तरह के प्रयासों को पारम्परिक और लोक माध्यमों तथा अन्य परम्परागत व गैर–परम्परागत तरीकों से और भी सशक्त किया जा सकता है।

हाल में डीएफपी ने अपनी गतिविधियों के संदेश के प्रचार–प्रसार के लिए ट्विटर जैसे सोशल मीडिया का उपयोग भी शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में नौजवानों तक पहुंचने के लिए यह वाट्स एप का भी इस्तेमाल कर रहा है।

डीएफपी के क्षेत्रीय कर्मी सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं

के कार्यान्वयन के बारे में फीडबैक भी भेजते हैं ताकि इन्हें लागू करने वाली एजेंसियां इसका लाभ उठा सकें।

fun'kky; d mí';

- भारत सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और उपलब्धियों के प्रचार–प्रसार के लिए अपने कर्मचारियों और सामग्री को जनता के समक्ष प्रस्तुत करना और उसे उनके फायदे के लिए बनायी गयी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी देना,
- जनता के बीच राष्ट्र के बुनियादी मूल्यों जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना,
- समाज के सबसे निचले स्तर पर लोगों के साथ तालमेल कायम करना ताकि विकास संबंधी गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और कल्याण तथा विकास कार्यक्रमों को लागू करने के बारे में अनुकूल जनमत तैयार किया जा सके।
- सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों तथा उनके कार्यान्वयन के बारे में जनता की प्रतिकिया लेना और जरूरत पड़ने पर उपयुक्त कार्रवाई तथा सुधारात्मक उपायों के लिए सरकार को सूचित करना।

2. 1 xBukRed <kpk

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय का तीन स्तरीय ढांचा है:

(1) नई दिल्ली स्थित मुख्यालय

(2) क्षेत्रीय कार्यालय, और

(3) क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां

निदेशालय के 22 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनमें से अधिकतर राज्यों की राजधानियों में हैं और 207 क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां देश भर में फैली हैं तथा ज्यादातर जिला मुख्यालयों में स्थित हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय 6 से 13 क्षेत्रीय इकाइयों को नियंत्रित करता है। क्षेत्रीय प्रचार इकाई क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी के अधीन कार्य करती है जिसकी मदद के लिए क्षेत्रीय प्रचार सहायक और मदद करने वाले अन्य कर्मचारी होते हैं।

3. b&xoul

डीएफपी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों के काम काज में सुविधा के लिए सूचना और संचार टेक्नोलाजी को अपनाया है। त्वरित और सुगम संचार के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और अधिकतर क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों को कम्प्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल फोन उपलब्ध कराये गये हैं ताकि रिपोर्ट और फीडबैक ऑनलाइन भेजा जा सके। क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए

बिहार में सीतामढ़ी जिले में बधानी (सुरसंद) में स्कूली बच्चों द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के लिए आयोजित रैली का दृश्य

कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों को खास फार्मेट में नियमित रूप से ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि रिपोर्ट तैयार की जा सकें और विश्लेषण, संदर्भ और रिकार्ड के लिए डेटाबेस बनाया जा सके।

सभी 22 क्षेत्रीय कार्यालयों – अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, केरल, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, सिलिगुड़ी और शिलांग के वेब पेज बन चुके हैं।

4- çe[k xfrfof/k;k

4.1 विशेष आउटरीच कार्यक्रम

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'विकास संचार और प्रसार' योजना के अंतर्गत 'सीधा सम्पर्क कार्यक्रम' नाम की विशेष उप–योजना का एक घटक विशेष संपर्क कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत डीएफपी की क्षेत्रीय इकाइयां किसी एक स्थान पर किसी खास विषय पर दो दिन का सघन जागरूकता कार्यक्रम मिलकर आयोजित करती हैं। विशेष संपर्क कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ऐसी जगहों की पहचान करना है जहां अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचा जा सकता है और अंतर–वैयक्तिक तरीके से जनता तक संदेश पहुंचाया जा सकता है। इस तरह के कार्यक्रम देश के सभी भागों में आयोजित किये जा रहे हैं जिनमें सीमावर्ती इलाके, वामपंथी आतंकवाद ग्रस्त इलाके और अल्पसंख्यकों की आबादी वाले क्षेत्र भी शामिल हैं।

31 अक्तूबर, 2017 तक डीएफपी इस तरह के 317 विशेष संपर्क कार्यक्रम आयोजित कर चुका था।

ये कार्यक्रम इन विषयों पर आधारित थे:

- सरकार की तीन साल की उपलब्धियां
- प्रधानमंत्री की 'मन की बात'
- हैंडलूम दिवस
- नये भारत का मंथन – संकल्प से सिद्धि
- स्वच्छता ही सेवा
- हस्त कला सहयोग शिविर
- राष्ट्रीय एकता दिवस

जागरूकता कार्यक्रमों के अन्य विषय

- स्वच्छ भारत मिशन
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
- प्रधान मंत्री जन धन योजना
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- अटल पेंशन योजना
- स्किल इंडिया मिशन

कार्यक्रमों के दौरान लोकप्रिय फिल्में दिखाने के साथ–साथ सरकार की प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में पुस्तिकाओं और पोस्टरों के रूप में जागरूकता सामग्री का वितरण किया गया। इन कार्यक्रमों के विभिन्न घटकों के प्रचार–प्रसार के लिए वाद–विवाद प्रतियोगिताओं, संगोष्ठियों, क्विज प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक गतिविधियों, छात्रों की रैलियों और सवाल–जवाब आधारित संवाद सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। सरकार की नीति और कार्यक्रमों संबंधी पहल के बारे में फीडबैक भी प्राप्त किया जा रहा है।

4.2 कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जागरूकता अभियान

क्षेत्रीय प्रचार मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए विशेष जागरूकता अभियान 10 नवंबर से 31 दिसंबर 2017 तक चला रहा है ताकि देश की प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़े।

अभियान के दौरान देश भर में क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा 70

हिमाचल प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 5 अगस्त, 2017 को क्षेत्र प्रचार निदेशालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस में छात्र–छात्राओं की भागीदारी

विशेष आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

4.3 'मिशन इंद्रधनुष, मिशन परिवार विकास, टी.बी. और कुष्ठ रोग' के विरुद्ध समन्वित अभियान

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय मिशन इंद्रधनुष, मिशन परिवार विकास, टी.बी. और कुष्ठरोग के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 27 नवंबर, 2017 से 28 फरवरी, 2018 तक विशेष जागरूकता अभियान चला रहा है। इसका उद्देश्य देश के चुने हुए उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में समाज के सबसे नाजुक और उपेक्षित वर्गों में परियोजना के मुख्य विषय के बारे में जागरूकता बढ़ाना था।

अभियान के दौरान क्षेत्रीय इकाइयां देश के उच्च प्राथमिकता/विशेष जोर वाले जिलों में उपेक्षित लोगों तक पहुंचने के लिए 220 विशेष आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं।

4.4 सीमावर्ती इलाकों में प्रचार गतिविधियां

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू–कश्मीर, मेघालय–मिजोरम–त्रिपुरा (एमएमटी), नागालैंड व मणिपुर, उत्तर–पश्चिम (पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश), राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल (उत्तर) व सिक्किम और पश्चिम बंगाल (दक्षिण) के क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों ने अपने कार्यक्षेत्र के तहत सीमावर्ती इलाकों में प्रचार अभियान चलाया। इन इकाइयों ने ग्रामीण इलाकों के लोगों को भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ने अटारी सीमा पर 23 अगस्त 2017 को 15,000 लोगों को 'संकल्प से सिद्धि' शपथ दिलाई।

4.5 वामपंथी उग्रवाद से ग्रस्त इलाकों में प्रचार गतिविधियां।

आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल (दक्षिण) में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की नौ इकाइयों ने भारत सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने का कार्य हाथ में लिया।

4.6 विशेष दिवसों पर जागरूकता कार्यक्रम

डीएफपी की क्षेत्रीय इकाइयां महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों/दिवसों/सप्ताहों के साथ ही अपनी रोजमर्रा की क्षेत्रीय गतिविधियों के दौरान भी सरकार की योजनाओं का प्रचार करती हैं।

अप्रैल से अक्तूबर 2017 तक की उपलब्धियां

1	आयोजित फिल्म प्रदर्शनी की संख्या	7917
2	आयोजित समूह चर्चाओं की संख्या	16858
3	फोटो प्रदर्शनियों की संख्या	10202
	d|y xfrfof/k;k	34977
4	फीड बैक के रूप में संकलित गाथाएं	6898
5	शामिल किये गये गांव	10017
6	श्रोताओं की कुल संख्या	3889376

çdk'ku foHkkx

çe|[k miyfC/k;k

- प्रकाशन विभाग ने 'कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी' के 100 खंडों वाले पूरे प्रमाणित सेट को करीब दो दशकों के बाद फिर से प्रकाशित कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। ये खंड वर्ष 1884 से गांधी जी के निधन के दिन तक उनके द्वारा लिखे और बोले गये शब्दों की प्रामाणिक मास्टर कॉपी हैं। 13 जून 2017 को तत्कालीन माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू ने इन खंडों का पूरा सेट माननीया लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन को संसदीय पुस्तकालय के लिए भेंट किया। श्री नायडू ने 100 खंडों का एक और सेट 24 जून 2017 को साबरमती आश्रम को भी भेंट किया।
- प्रकाशन विभाग ने 1950–70 के दशकों के दौरान प्रकाशित गांधी साहित्य को फिर से छापने की

जिम्मेदारी का कार्य भी हाथ में लिया है जिसे राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, नई दिल्ली की साझेदारी से किया जा रहा है। 10 अप्रैल 2017 को चम्पारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर तत्कालीन माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री वेंकैया नायडू ने गांधी जी के विचारों और साहित्य पर फिर से छापी गयी धरोहर के रूप में महत्वपूर्ण तीन पुस्तकों 'गांधी इन चम्पारण', 'रोम्या रोलां एंड गांधी कॉरस्पॉडेंस' और आठ खंडों की पुस्तकमाला 'महात्मा' का लोकार्पण किया।

- महात्मा गांधी की जयंती पर 'होमेज टू महात्मा' नाम की एक और पुस्तक का लोकार्पण राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय में किया गया। इसमें 30 जनवरी 1948 को गांधीजी की मृत्यु के बाद आकाशवाणी से प्रसारित सरदार वल्लभभाई पटेल और पं. जवाहर लाल नेहरू जैसे जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों और लॉर्ड माउंटबेटन जैसी हस्तियों के संदेशों को लिपिबद्ध किया गया है।
- प्रधानमंत्री ने 24 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के विदाई समारोह में उनके चुने हुए भाषणों के चौथे खंड का विमोचन किया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद उपस्थित थे। 'सेलेक्टेड स्पीचेज ऑफ प्रेजिडेंट' (चतुर्थ खंड) चार खंडों वाली इस पुस्तकमाला की आखिरी खंड है। इसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल के चौथे और पांचवे साल में दिये गये भाषण संकलित हैं। इससे पहले प्रकाशित शुरू के तीन खंडों में उनके कार्यकाल के प्रारंभ के तीन वर्षों में दिये गये महत्वपूर्ण भाषण संकलित हैं। प्रकाशन विभाग ने राष्ट्रपति भवन के

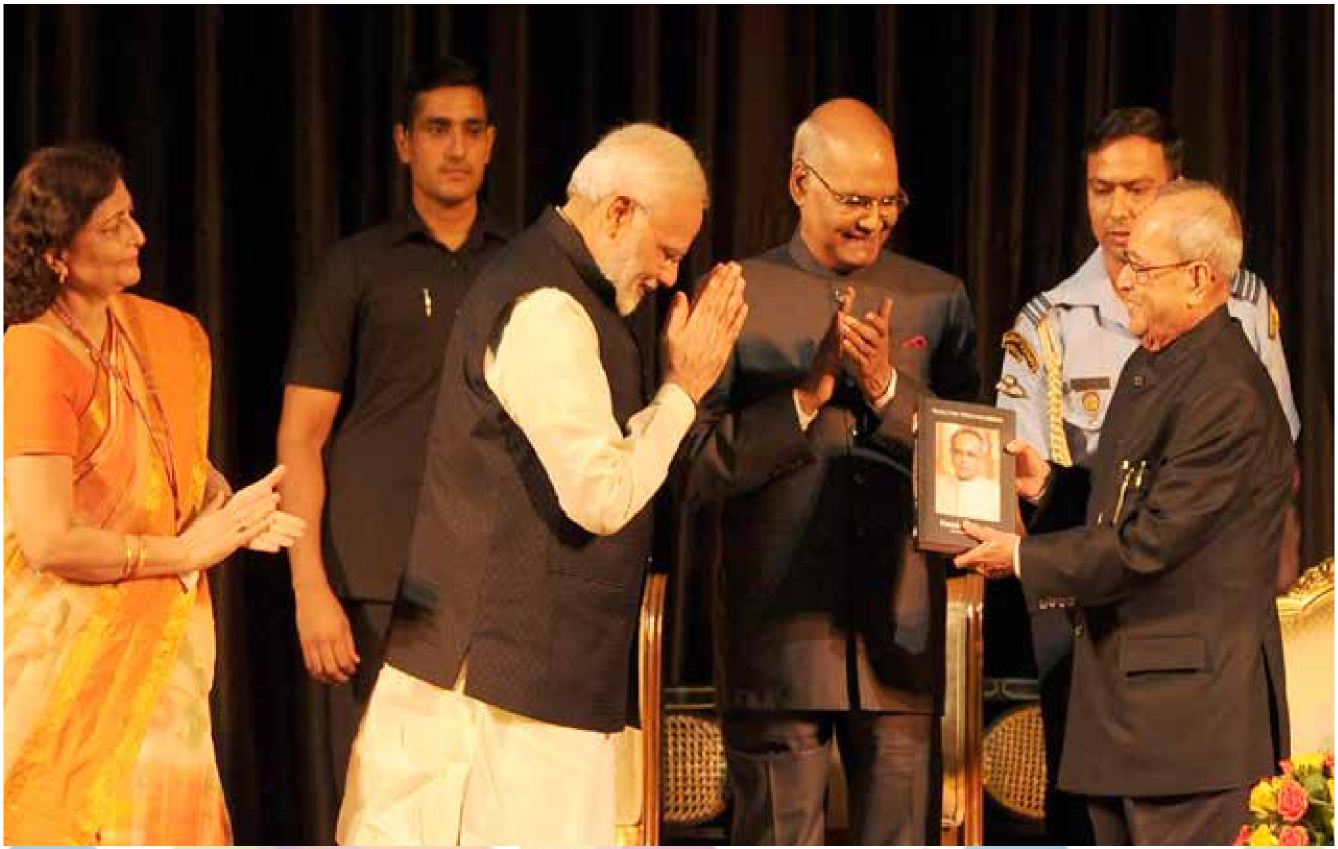

महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के चुनिंदा भाषणों के चौथे खंड को श्री मुखर्जी को समर्पित करते हुए। इस पुस्तक को प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित किया है।

सहयोग से राष्ट्रपति भवन की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाली 17 प्रतिष्ठित पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं।

- प्रकाशन विभाग के अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ इंडिया/भारत 2018 मुद्रित हो चुके हैं। इंडिया/भारत 2018 विगत वर्ष के दौरान देश और उसकी प्रगति का विस्तृत लेखा जोखा है जिसमें विकास, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, कला और संस्कृति, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा, शिक्षा और जनसंचार के साथ–साथ सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले, खेल–कूद जैसी कई महत्वपूर्ण घटनाओं का ब्यौरा रहता है।

- प्रकाशन विभाग को हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में iqLrdk d¨ çdk'ku d¨ fy, 11 iqjLdkj vkj nk mR—"Vrk çek.ki= प्राप्त हुए। अगस्त 2017 में दिल्ली पुस्तक मेले में माननीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किये। 'फर्स्ट गार्डन ऑफ द रिपब्लिक' को अंग्रेजी कॉफी टेबल बुक श्रेणी का प्रथम पुरस्कार मिला। 'सांची की गुड़िया' को हिन्दी में बाल पुस्तक श्रेणी और हिंदी पत्रिका 'कुरुक्षेत्र' को गृह पत्रिका श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त करने वाली अन्य पुस्तकों में 'भारत 2017', 'स्वच्छ जंगल की कहानी दादी की जुबानी भाग–3', 'अनफोल्डिंग इंडियन इलेक्शन्स जर्नी ऑफ द लिविंग डिमोक्रेसी', 'कोर्ट्स इन इंडिया पास्ट टू प्रजेंट', 'बाल रामायण', 'योजना (अंग्रेजी)', 'स्वच्छ अरण्येर कथा आओतार लघुकथा', 'बुद्धोपदेश (कन्नड़)', 'योजना (तेलुगू)' और कैटलॉग 2017 शामिल हैं।

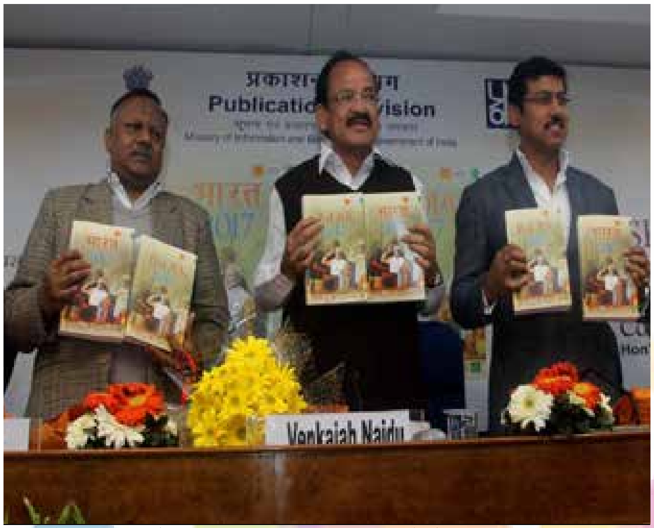

पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित 'इंडिया 2017' और 'भारत 2017' का 6 फरवरी 2017 को नई दिल्ली में लोकार्पण करते हुए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तथा तत्कालीन सूचना और प्रसारण सचिव श्री अजय मित्तल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

- बारह भारतीय भाषाओं की 15 पुस्तकें (स्रोत भाषा को छोड़कर) अनुवाद के विभिन्न चरणों में हैं। इन पुस्तकों में शामिल हैः बच्चों की पुस्तक रानी लक्ष्मी बाई, रज़िया सुल्तान, महाभारत, स्वराज्य के मंत्रदाता तिलक, सरल पंचतंत्र और लाइव्ज दैट इन्स्पायर (खंड 1–3)। यह कार्य 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' परियोजना के तहत कराया जा रहा है। इस श्रृंखला की 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं।

- प्रकाशन विभाग ने पुस्तकों के साझा प्रकाशन के लिए सस्ता साहित्य मंडल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके अंतर्गत बाल तथा किशोर पाठकों के लिए 20 प्रेरणादायक पुस्तकों का संक्षिप्त रूप में प्रकाशन किया जाएगा (इनमें से 10 प्रकाशन विभाग की और 10 सस्ता साहित्य मंडल की होंगी)। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद 7 पुस्तकें प्रकाशित भी की जा चुकी हैं।

- प्रकाशन विभाग ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के साथ भी एक समझौता किया है जिसके तहत 10 पुस्तकों को प्रकाशन के लिए चुना गया है।

- प्रकाशन विभाग ने वर्ष 2017 के दौरान समसामयिक महत्व के विषयों पर 13 पुस्तक चर्चाओं/संगोष्ठियों का आयोजन किया। इसका उद्देश्य व्यापक पाठक समुदाय तक पहुंच बनाना था। गांधी और स्वच्छता, चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष, गांधी साहित्य, महिला साहित्य, बाल साहित्य, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे विषयों पर चर्चा के लिए जाने–माने लोगों/लेखकों श्री राम बहादुर राय, डॉ. महेश शर्मा, श्री जे.स. राजपूत, श्री ए. अन्नामलाई आदि को आमंत्रित किया गया।

- प्रकाशन विभाग की प्रमुख उर्दू साहित्यिक मासिक

संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. महेश शर्मा दिल्ली पुस्तक मेले में 31 अगस्त, 2017 को प्रकाशन विभाग को उत्कृष्ट पुस्तक प्रकाशन के लिए पुरस्कृत करते हुए

पत्रिका 'आजकल' ने जुलाई 2017 में अपने प्रकाशन के 75 वर्ष पूरे कर हीरक जयंती मनाई। इस अवसर पर पत्रिका ने अपने रजत जयंती और स्वर्ण जयंती अंकों में छपे उत्कृष्ट लेखों का फिर से प्रकाशन किया। इस अवसर पर प्रकाशन विभाग की नवनिर्मित पुस्तक दीर्घा में एक गोष्ठी आयोजित की गयी जिसमें जाने–माने उर्दू लेखकों, शायरों और पत्रकारों के अलावा आजकल (उर्दू) के पूर्व संपादक भी शामिल हुए।

- मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रकाशन विभाग ने धरोहर जैसी मूल्यवान पुरानी पुस्तकों को डिजिटल फार्मेट में बदलने का काम शुरू किया। मार्च 2017 तक इस तरह की 1000 पुस्तकें डिजीटाइज की जा चुकी थीं। यह कार्य जारी है और अब डिजिटाइज्ड पुस्तकों की संख्या 1600 हो गयी है।
- प्रकाशन विभाग की मुद्रित पुस्तकों की ऑनलाइन बिक्री वित्त मंत्रालय के भारतकोष पोर्टल से अक्तूबर 2016 में शुरू हुई। अब तक 4300 किताबें इसके जरिए बेची जा चुकी हैं। इसी तरह इस पोर्टल के जरिए पत्र–पत्रिकाओं का चंदा भी ऑनलाइन लिया जा रहा है। अब तक इम्प्लायमेंट न्यूज के 14,000 और अन्य पत्रिकाओं के 36,000 नये ग्राहक भारत कोष के जरिए पैसा भेजकर बने हैं। चुनी हुई 300 ई–बुक्स अब अमेजन किंडल, गूगल प्ले बुक्स और कोबो इंडिया के माध्यम से उपलब्ध हैं। 10,000 से अधिक ई–बुक्स ई–टेलर्स के जरिए बेची गयी हैं।
- प्रकाशन विभाग ने दिल्ली पुस्तक मेले में अपनी पत्र–पत्रिकाओं तथा पुस्तकों की 15.37 लाख रुपये की रिकॉर्ड बिक्री की। पुस्तक मेले के दौरान विभिन्न विषयों पर 17 नयी पुस्तकों/हाल में पुनर्मुद्रित पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। मेले में पुस्तकों के प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए प्रकाशन विभाग के मंडप को क्षेत्रीय भाषा श्रेणी में 'गोल्ड ट्रॉफी फॉर एक्सेलेंस इन डिस्प्ले' प्रदान की गयी।
- प्रकाशन विभाग ने प्रगति मैदान में 6 जनवरी से 14 जनवरी, 2018 तक आयोजित नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में हिस्सा लिया। इस मेले के दौरान

विभाग की कुल 15 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया।

- प्रकाशन विभाग ने अपने संभावित पाठकों से संपर्क कायम करने के लिए सोशल मीडिया का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया। प्रकाशन विभाग और एम्प्लायमेंट न्यूज के ट्विटर खाते राष्ट्रीय रुझानों के अनुरूप कारगर तरीके से कार्य करते रहे। विभाग की सोशल मीडिया पर उपस्थिति में भी उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है जहां ट्विटर हैंडल पर हर महीने 1,60,000 इम्प्रैशन्स मिले हैं वहीं फेसबुक की पहुंच का दायरा 3,60,000 मासिक को पार कर गया है।

ifjp;

प्रकाशन विभाग की स्थापना 1941 में हुई थी और यह राष्ट्रीय महत्व के विषयों तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित करनेवाली पुस्तकों और पत्र–पत्रिकाओं का खजाना है। यह भारत सरकार के ऐसे प्रमुख प्रकाशन गृह के रूप में उभर कर सामने आया है जो ज्ञान के राष्ट्रीय भंडार को समृद्ध करने में निम्नलिखित तरीके से अपना योगदान कर रहा है: (1) भारत भूमि और यहां के लोगों, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास, कला और संस्कृति, जीव–जंतु और वनस्पतियों, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले आधुनिक भारत के निर्माताओं की जीवनियों, संस्कृति, दर्शन, विज्ञान, साहित्य आदि के क्षेत्र की महान हस्तियों के बारे में श्रेष्ठ पुस्तकें प्रकाशित करके भारत की धरोहर का संरक्षण और प्रदर्शन। (2) भारत के माननीय राष्ट्रपति/प्रधानमंत्रियों के भाषणों के प्रकाशन, समसामयिक विज्ञान, अर्थव्यवस्था, इतिहास और अन्य समकालीन विषयों पर भारतीय समाज और संबद्ध पाठक वर्ग पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए पुस्तकें तथा पत्रिकाएं छापना। (3) बच्चों को जानकारी देने के साथ–साथ उनका मनोरंजन करने, उन्हें देश व देशवासियों और देश की धरोहर, संस्कृति तथा समाज के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं बच्चों में मानवीय जीवन मूल्यों तथा वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास के लिए बाल साहित्य (कथा और कथेतर) का प्रकाशन।

प्रकाशन विभाग ने गांधी जी के चिंतन पर अनेक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इनमें अंग्रेजी में 100 खंडों में कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी (सीडब्ल्यूएमजी) शामिल है जो गांधीजी के लेखन के बारे में सबसे विस्तृत और प्रामाणिक माना जाता है। प्रकाशन विभाग ने गुजरात विद्यापीठ के सहयोग से गांधीवादी विद्वानों की देखरेख में कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के ई–संस्करण (ई–सीडब्ल्यूएमजी) की मास्टर कॉपी तैयार की है जो डीवीडी के सुनियोजित सेट के रूप में उपलब्ध है। इसमें किसी भी विषय को बड़ी आसानी से खोजा जा सकता है। इसे गांधी हैरिटेज पोर्टल पर भी डाला गया है। प्रकाशन विभाग और राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय गांधीवादी आदर्शों के विभिन्न पहलुओं पर कई प्रामाणिक और सुरुचिपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित करने को सहमत हुए हैं। ये पुस्तकें राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय द्वारा देश भर में गांधीवादी आदर्शों के विभिन्न पहलुओं पर आयोजित की जानेवाली विभिन्न प्रदर्शनियों पर आधारित होंगी।

प्रकाशन विभाग चार मासिक पत्रिकाएं योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती और आजकल तथा एक साप्ताहिक एम्प्लायमेंट न्यूज/रोज़गार समाचार भी प्रकाशित करता है। ये पत्र–पत्रिकाएं आर्थिक विकास, ग्रामीण पुनर्निर्माण, सामुदायिक विकास, साहित्य, संस्कृति, बाल–साहित्य जैसे समसामयिक विषयों के साथ–साथ रोजगार और नौकरी के अवसरों के बारे में जानकारी देती हैं।

laxBukRed <kpk

प्रकाशन विभाग के प्रमुख महानिदेशक (डीजी) हैं और उनकी मदद के लिए संपादकीय, व्यापार, उत्पादन और प्रशासनिक प्रभागों के प्रमुखों के साथ–साथ एक महाप्रबंधक हैं जो एम्प्लायमेंट न्यूज का कामकाज देखते हैं। प्रकाशन विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में सूचना भवन में है और इसके सेल्स इम्पोरिया नई दिल्ली (मुख्यालय), दिल्ली (पुराना सचिवालय), मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु में हैं।

çe[k xfrfof/k;k

iLrdk dk çdk'ku

वर्ष 2016–17 में प्रकाशन विभाग ने दिसंबर 2017 तक 70 पुस्तकें प्रकाशित कीं जिनमें राष्ट्रपति भवन पुस्तकमाला के अंतर्गत 'लाइफ एट राष्ट्रपति भवन 'राष्ट्रपति भवन : फ्राम

राज टू स्वराज, आर्ट एंड एंटीरियर्स ऑफ राष्ट्रपति भवन, 'अराउंड इंडियाज फर्स्ट टेबलः डायनिंग एंड एंटरटेनिंग एट राष्ट्रपति भवन।'

अंग्रेजी में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशनों में शामिल हैं– होमेज टू महात्मा, सलेक्टेड स्पीचेज ऑफ प्रेजीडेंट प्रणब मुखर्जी खंड–4, भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन, आम आदमी और संविधान, इंडिया आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एनशिएंट एंड मेडिइवल पीरियड्स, काशीः नगरी एक रूप अनेक, इंडियन डांसः थ्रू ए क्रिटिक्स आय, इंडियन कॉस्ट्यूम्स, कोर्ट्स ऑफ इंडिया, इंडियन ट्राइब्जः थ्रू दि एजेज, गालिब : कवि और मानव, भारत के गौरव, आयुर्वेदः सामान्य रोग और उपचार, संगीत मन को पंख लगाये। आधुनिक भारत के निर्माता पुस्तकमाला के अंतर्गत जिन पुस्तकों की मांग ज्यादा थी उन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में भी छपवाया गया, जैसे डॉ. केशवराम बलिराम हेडगेवार (पंजाबी), सरदार वल्लभभाई पटेल (तमिल), सुभाष चंद्र बोस (तमिल) और मदन मोहन मालवीय (बंगाली)। क्षेत्रीय भाषाओं के अन्य प्रकाशनों में माहौलियत – एक तार्रुफ (उर्दू) और द गॉस्पेल ऑफ बुद्ध (तमिल) शामिल हैं।

बाल साहित्य के अंतर्गत कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं–काका और चाची, तेनाली राम और राजगुरु, मेरे दादा दिल के राजा, गणित का जादू।

i=&if=dkvk dk çdk'ku ½ प्रकाशन विभाग कुल 18 पत्र–पत्रिकाएं प्रकाशित करता है जिनमें योजना (अंग्रेजी, हिन्दी और 11 अन्य भारतीय भाषाओं में), कुरुक्षेत्र (हिन्दी और अंग्रेजी में), आजकल (हिन्दी और उर्दू में), बाल भारती (हिन्दी में) और एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार (हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू में) शामिल हैं।

क) योजना (अंग्रेजी, हिन्दी और 11 क्षेत्रीय भाषाएं)

1957 से प्रकाशित हो रही योजना आर्थिक विकास के विषयों को समर्पित पत्रिका है जो अंग्रेजी, हिन्दी, असमिया, बंगाली, कन्नड़, मराठी, गुजराती, मलयालम, ओड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू और उर्दू में प्रकाशित होती है। इसकी कुल मासिक प्रसार संख्या 2 लाख से अधिक है। पिछले साल के दौरान पत्रिका ने समसामयिक विषयों जैसे नोटबंदी, जीएसटी, सामाजिक सुरक्षा, युवा सशक्तीकरण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और उपभोक्ता जागरूकता आदि पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया।

[k½ d#{k= ¼vxzth vkj fgUnh½

1952 से प्रकाशित हो रही कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास और आम जनता से जुड़े मुद्दों को समर्पित है और शिक्षाविदों, नियोजनकर्ताओं, एनजीओ से जुड़े लोगों और विचारकों को चिंतन का एक मंच प्रदान करती है। 2017–18 के दौरान हिन्दी और अंग्रेजी में इस पत्रिका की कुल मुद्रण संख्या प्रति अंक लगभग एक लाख प्रति थी।

2017–18 में कुरुक्षेत्र ने स्वच्छता, किसानों की आमदनी बढ़ाने, ग्रामीण स्वास्थ्य, सिंचाई और जल संरक्षण, डिजिटल ग्रामीण भारत, ग्रामीण युवाओं को कौशल संपन्न बनाने जैसे विषयों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया।

x½ vktdy ¼fgUnh vkj mnw ekfld½

1945 से प्रकाशित हो रही साहित्यिक पत्रिका आजकल में भारतीय साहित्य और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को समाहित किया जाता है। आजकल (हिन्दी) ने 'संकल्प नये भारत का', 'चम्पारण सत्याग्रह की शताब्दी' तथा हिन्दी साहित्य और राष्ट्रीय चेतना जैसे विषयों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया।

आजकल (उर्दू) मासिक ने अपने प्रकाशन के 75 वर्ष पूरे किये और जुलाई 2017 में विशेषांक निकाला जिसमें इसके रजत जयंती और स्वर्ण जयंती अंकों से लेख लिये गये।

?k½ cky Hkkjrh ¼fgUnh½

बाल भारती का प्रकाशन 1948 से हो रहा है। इसका उद्देश्य अपने लेखों, लघु कथाओं, कविताओं और चित्रकथाओं के माध्यम से बच्चों को सामाजिक मूल्यों की शिक्षा देना और उनमें वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास के साथ ही उन्हें स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना भी है। बाल भारती नयी पीढ़ी में सृजनात्मक कौशल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित करती है।

vU; çdk'kuk dk fMftVkbt'ku

मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत 1,000 से अधिक शीर्षकों को मार्च 2017 तक डिजिटाइज किया जा चुका था और अब यह आंकड़ा 1,600 को पार कर चुका है।

0;kikj vkj foi.ku

व्यापार स्कंध ने अपने बिक्री कार्यालयों और पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से पुस्तकों की बिक्री के साथ ही पुस्तक प्रदर्शनियों पुस्तक मेलों, जन सूचना अभियानों और बिक्री संवर्धन गतिविधियों में हिस्सा लिया।

¼d½ iqLrd esyk vkSj çn'kZfu;ksa esa Hkkxhnkjh

प्रकाशन विभाग ने अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 तक लखनऊ, वाराणसी, कोलकाता, न्येवेली, इरोड, नई दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, विजयवाड़ा, जयपुर, गुवाहाटी, कोच्चि, भुवनेश्वर, अहमदाबाद आदि स्थानों में आयोजित 138 महत्वपूर्ण पुस्तक मेलों में हिस्सा लिया। इसके अलावा इसने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 26 अगस्त से 3 सितंबर 2017 तक आयोजित वार्षिक दिल्ली पुस्तक मेले में भी भागीदारी निभाई। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला (6 जनवरी से 14 जनवरी, 2018) में भी प्रकाशन विभाग की भागीदारी बड़ी शानदार रही।

इसके अलावा प्रकाशन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों, जैसे लंदन पुस्तक मेला (13 से 17 मार्च 2017) और शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला (1 से 11 नवंबर 2017) में भी हिस्सा लिया।

स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, हिन्दी पखवाड़ा जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों और अवसरों पर प्रकाशन विभाग ने देश भर में फैले अपने 10 बिक्री केन्द्रों के भीतर ही पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं जयंती, स्वच्छ भारत अभियान और स्वतंत्रता संग्राम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाशन विभाग की नवनिर्मित पुस्तक दीर्घा में पुस्तक चर्चा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

प्रकाशन विभाग पुस्तकों के अलावा 21 पत्र–पत्रिकाओं का अपने मुख्यालय और आठ क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रकाशन और बिक्री भी करता है। अप्रैल 2017 से सितंबर 2017 तक पुस्तकों और पत्र–पत्रिकाओं की बिक्री तथा विज्ञापनों से प्रकाशन विभाग को प्राप्त राजस्व 6.38 करोड़ रुपये (अस्थायी–एम्प्लायमेंट न्यूज को छोड़कर) था।

,EIyk;eaV U;wt@jkstxkj lekpkj ¼vaxzsth] fgUnh vkSj mnwZ½

हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में प्रकाशित होने वाला एम्प्लायमंट

23वें दिल्ली पुस्तक मेले 2017 में प्रगति मैदान, नई दिल्ली में प्रकाशन विभाग का बुक स्टाल

न्यूज/रोजगार समाचार नौकरियों के बारे में जानकारी देने वाला प्रकाशन विभाग का सबसे महत्वपूर्ण पत्र है जिसमें एक ही स्थान पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त संगठनों और विश्वविद्यालयों आदि के रोजगार संबंधी विज्ञापन प्रकाशित होते हैं। इसमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और अन्य सार्वजनिक भर्ती संगठनों के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं और परीक्षा परिणामों संबंधी विज्ञापन भी प्रकाशित होते हैं। इसके अलावा रोजगार समाचार का संपादकीय खंड भी है जिससे युवाओं को रोजगार के बाजार में उपलब्ध विभिन्न नौकरियों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की तैयारी करने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए का मौका मिलता है। रोजगार समाचार की देशव्यापी प्रसार संख्या प्रति सप्ताह 1.80 लाख प्रतियों से अधिक है। पाठक (इंप्लायमेंट न्यूज़) रोजगार समाचार की वेबसाइट www.employmentnews.gov.in पर जाकर इसके ई–संस्करण या प्रिंट संस्करण दोनों के लिए चंदा जमा कराकर ग्राहक बन सकते हैं। इस साप्ताहिक के इस समय 16,300 ग्राहक हैं (10,500 ई–संस्करण के और 5,800 मुद्रित संस्करण के)। ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों पर भी इसकी अच्छी उपस्थिति दिखाई देती है।

वर्ष 2017–18 के दौरान जनवरी 2018 तक इसका राजस्व ₹ 23.19 करोड़ रुपये रहा। एम्प्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार ने अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 तक 4400 से अधिक विज्ञापन प्रकाशित किये।

xhr ,oa ukVd çHkkx

1- ifjp;% गीत एवं नाटक प्रभाग 'जन कला से जन चेतना' के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करने वाला सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक मीडिया एकांश है जो सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए नाटक, नृत्य–नाटिका, कठपुतली, बैले, ओपेरा, लोक व पारम्परिक गाथाओं, पौराणिक आख्यानों और मिश्रित विधाओं आदि के माध्यम से जनता के साथ अंतर–वैयक्तिक संवाद स्थापित करता है। प्रभाग का मुख्य कार्य आम जनता में सामाजिक, आर्थिक मुद्दों और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति जागरूकता और भावनात्मक लगाव पैदा करना है ताकि जीवंत मनोरंजन के माध्यम से राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो।

2- laxBukRed <kapk

- निदेशक की अध्यक्षता में प्रभाग तीन स्तरों पर कार्य करता है जो इस प्रकार हैं:

¼d½ fnYyh eq[;ky; % प्रभाग की निम्नलिखित प्रमुख इकाइयां हैं:

(1) नीति एवं समन्वय (2) प्रशासन और लेखा (3) सशस्त्र सेना मनोरंजन स्कंध (4) ध्वनि एवं प्रकाश एकांश (5) केन्द्रीय नाटक मंडली।

¼[k½ nl {ks=h; dsUæ % गीत एवं नाटक प्रभाग के दस क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, पुणे और रांची में हैं जो देश भर में कार्यक्रम संबंधी गतिविधियां संचालित करने के लिए उत्तरदायी हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र का अपना कार्यक्षेत्र निर्धारित है और इसका अध्यक्ष उप–निदेशक/उप–निदेशक (प्रभारी) होता है।

¼x½ mi&dsUæ % (अ) दरभंगा, गुवाहाटी, इम्फाल, जम्मू, जोधपुर, नैनीताल और शिमला में सहायक निदेशक की अध्यक्षता में सात सीमा केन्द्र और (आ) भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद, पटना, पुणे और श्रीनगर (जम्मू) में प्रबंधक की अध्यक्षता में छह विभागीय नाटक मंडली केन्द्र है।

3- vkmVjhp dk;Øeksa ds fy, xhr ,oa ukVd iHkkx }kjk mi;qDr lk/ku: गीत एवं नाटक प्रभाग देश भर में सरकारी योजनाओं/नीतियों के बारे में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन (आईईसी) गतिविधियां संचालित करने के लिए पारम्परिक मीडिया का उपयोग करता है। लोक और पारम्परिक जन संचार माध्यम ग्रामीण क्षेत्रों में आज की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों में भी बड़े कारगर हैं। कार्यक्रम प्रस्तुत करने में निजी पंजीकृत मंडलियों, विभागीय कलाकारों और पैनलबद्ध कलाकारों की मदद ली जाती है।

¼1½ futh iath—r eMfy;ka % इस समय कुल 1024 निजी पंजीकृत मंडलियां हैं जिनमें 3 से 11 तक कलाकार/प्रस्तुतियां देने वाले सदस्य होते हैं। ये मंडलियां क्षेत्रीय केन्द्रों के साथ संबद्ध रहती हैं और बहुत कम अवधि में इनका विस्तार किया जा सकता है। इनकी कई श्रेणियां जैसे नाटक मंडली, जादू कार्यक्रम मंडली, लोक और पारम्परिक गाथा मंडली, पौराणिक गाथा मंडली और मिश्रित विधाओं वाली मंडली आदि होती हैं। इनके दो ग्रेड यानी संवर्ग हैं जिन्हें एक घंटे के कार्यक्रम के लिए 4,000 रुपये और 5,600 रुपये शुल्क दिया जाता है।

¼2½ foHkkxh; dykdkj % नई दिल्ली स्थित मुख्यालय और विभिन्न क्षेत्रीय तथा उप–केन्द्रों में विभिन्न विधाओं जैसे, गायन, वाद्य संगीत, नाटक और पार्श्व कलाओं के प्रतिभाशाली कलाकार भी तैनात हैं।

(3) iSuyc) dykdkj % इसके अलावा कई पैनलबद्ध कलाकार भी गीत एवं नाटक प्रभाग से जुड़े हैं। पर्वतीय और जनजातीय, मरुस्थलीय, संवेदनशील और वामपंथी अतिवाद से प्रभावित इलाकों तथा देश के दूर–दराज के अन्य इलाकों में कई तरह की लोक और पारम्परिक विधाओं का उपयोग करने से यह प्रभाग इन विधाओं को पुनर्जीवित करने और बनाए रखने में भी योगदान कर रहा है। हजारों कलाकारों को उनकी अपनी भाषाओं, बोलियों और मुहावरों में उद्देश्यपूर्ण संवाद का अवसर प्रदान कर उन्हें अपने हुनर से आजीविका उपलब्ध करा रहा है।

4- mís';% सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जनता तक सूचनाओं का कारगर तरीके से

प्रचार–प्रसार करना भारत सरकार के विकास कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में मनोरंजक जीवंत कलाओं के माध्यम से सभी नागरिकों के साथ प्रभावी संवाद कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना और उन सब में, खास तौर पर ग्रामीण, वामपंथी आतंकवाद से ग्रस्त, पर्वतीय, जनजातीय, मरुस्थलीय इलाकों, छोटे कस्बों, सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले नाजुक तबके के लोगों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बतायी गयी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, साम्प्रदायिक सद्‌भाव जैसी आदर्श भावनाओं का संचार करना।

सूचना, संचार और शिक्षा के कार्यक्रमों के माध्यम से देश भर में प्रगति के लिए आवश्यक राष्ट्रीय महत्व के विषयों की ओर लोक और पारंपरिक कलाओं तथा जीवंत कला विधाओं का उपयोग करते हुए जनता का ध्यान आकर्षित करना। गीत एवं नाटक प्रभाग अंतर–वैयक्तिक इकाई होने के कारण इतिहास, कला और संस्कृति तथा विरासत के बारे में प्रामाणिक सूचनाएं उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही यह सरकार द्वारा सबके कल्याण के लिए अपनाई जानेवाली महत्वपूर्ण नीतियों/कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी लोगों तक पहुंचाता है।

5. dk;Øe çLrqr djrs le; 'kkfey fd;s x;s fo"k;: कार्यक्रमों के प्रस्तुतीकरण के दौरान सरकार के निम्नलिखित कार्यक्रमों और नीतियों के व्यापक प्रचार–प्रसार पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया : स्वच्छ भारत मिशन (एक कदम स्वच्छता की ओर)', 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत,' 'प्रधानमंत्री जन–धन योजना,' 'संकल्प पर्व,' 'स्वच्छता पखवाड़ा,' 'नया भारत हम करके रहेंगे,' 'अटल पेंशन योजना,' 'मिशन इंद्रधनुष,' 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना,' 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना,' 'सबका साथ, सबका विकास,' 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ,' 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,' 'पर्यटन संवर्धन' आदि।

इसके अलावा आलोच्य अवधि के दौरान राष्ट्रीय अखंडता और साम्प्रदायिक सद्‌भाव, सामाजिक सद्‌भाव, भाषायी सद्‌भाव, कार्यस्थल पर यौन दुर्व्यवहार, बालिकाओं के अधिकार, महिला सशक्तीकरण, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नये 15 सूत्री कार्यक्रम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी विषयों और कुपोषण के खिलाफ जागरूकता पर भी व्यापक प्रचार किया गया।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गीत एवं नाटक प्रभाग, चंडीगढ़ के कलाकार 'एक शाम शहीदों के नाम' कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए

8- ns'k ds çkFkfedrk okys {ks=k esa vçSy ls uoEcj 2017 ds nkSjku fn[kk;s x;s dk;Øeksa dk fooj.k

(I) भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में दिखाये गये कार्यक्रमों की संख्या

jkT;ksa esa ;kstuk dk;Øe ds vUrxZr dk;Øe	vçSy] 2017	ebZ] 2017	twu] 2017	tqykbZ] 2017	vxLr 2017	flr- 2017	vDrw- 2017	uo- 2017	dqy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
असम	52	78	50	42	162	88	49	63	584
अरुणाचल प्रदेश	–	–	24	12	26	23	26	–	111
मणिपुर	10	25	88	65	18	68	36	–	310
मिजोरम	–	28	10		17	20	20	–	95
मेघालय	–	08	16	15	30		30	–	99
नगालैंड	–	24	06		15	10	30	–	85
त्रिपुरा	–	10	33		10	32	40	–	125
सिक्किम	–	–	–		10		20	–	30
dqy%	62	173	227	134	288	241	251	63	1439
जम्मू (कटरा उत्सव)						18			18

विषय : 'स्वच्छ भारत मिशन – (एक कदम स्वच्छता की ओर)', 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत,' 'आजादी के 70 साल,' 'संकल्प से सिद्धि,' 'नया भारत हम करके रहेंगे,' 'प्रधानमंत्री जनधन योजना,' 'अटल पेंशन योजना,' 'मिशन इंद्रधनुष,' 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना,' 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना,' 'सबका साथ, सबका विकास,' 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ,' 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,' 'पर्यटन संवर्धन' आदि।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गीत एवं नाटक प्रभाग के कलाकार
'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए

(II) वामपंथी आतंकवाद से ग्रस्त इलाकों/चिह्नित जिलों में अप्रैल से नवंबर 2017 तक किये गये कार्यक्रम

क्रम सं.	क्षेत्रीय केन्द्र	अप्रैल से नवंबर 2017 तक वामपंथी आतंकवाद से ग्रस्त जो जिले शामिल किये गये	पूरे किये गये कार्यक्रम
1.	भोपाल	छत्तीसगढ़ (16 जिले)	70
		मध्य प्रदेश (1 जिला)	10
2.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल (04 जिले)	80
		ओड़िसा (19 जिले)	83
3.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र जिले (3 जिले)	20
4.	पुणे	महाराष्ट्र (04 जिले)	37
5.	चेन्नई	तेलंगाना (8 जिले)	64
		आंध्र प्रदेश (8 जिले)	64
		dqy%	428

(III) 'स्वच्छता ही सेवा' के तहत चलाए गये कार्यक्रमों की संख्या

क्रम सं.	गीत एवं नाटक प्रभाग के क्षेत्रीय केन्द्र	चलाए गये कार्यक्रम
1.	भोपाल	112
2.	कोलकाता	10
3.	रांची	5
4.	लखनऊ	4
5.	पुणे	38
6.	चेन्नई	2
7.	बैंगलोर	8
8.	दिल्ली	79
9.	चंडीगढ़	42
	dqy	300

vçSy ls uoacj 2017 rd ns'k dh vUrjk"Vªh; lhek {ks= esa çLrqr dk;Øeksa dh la[;k %

Ø- l-	jkT; dk uke	ftys dk uke	çLrqr dk;Øeksa dh la[;k
1	vle	धुब्री, कछार, करीमगंज, कोकराझार, बक्सा, चिरांग, उदलगुडी	102
2	fcgkj	अररिया, चंपारण (पूर्व), चंपारण (पश्चिम) किशनगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल	&
3	tEew vkSj d'ehj	जम्मू, कठुआ, पुंछ, राजौरी, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा, कारगिल, लेह, मड़, विजयपुर, अखनूर, खूर, आरएस पुरा, सतवारी, साम्बा, बिश्नाह, पुंछ, बूनियार, लंगत	422
4	ef.kiqj	चंदेल, सी.सी.पुर, सेपुर चंदेल, उखरुल और चूड़ाचांदपुर	23
5	es?kky;	पश्चिम गारो पहाड़ी, दक्षिण गारो पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, पूर्व खासी पहाड़ी, पश्चिम खासी पहाड़ी	&
6	fetksje	चम्फई, लौगतलाई, मामित, सैहा, सेरचिप	&
7	ukxkySaM	किफिरे, मोन, फेक, त्यूनसांग	
8	iatkc	अमृतसर, तरन–तारन, फिरोजपुर, गुरदासपुर, अजनाला, चोगावान	111
9	flfDde	सिक्किम (पूर्व), सिक्किम (पश्चिम), सिक्किम (उत्तर)	&
10	f=iqjk	त्रिपुरा (द), ढलाई, त्रिपुरा (उ), सिद्धार्थनगर, पश्चिम त्रिपुरा, उत्तरी त्रिपुरा	05
11	mRrj çns'k	बहराइच, बलरामपुर, खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर	69
12	mRrjk[kaM	चमोली, चम्पावत, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, उत्तरकाशी	83
13	if'pe caxky	कूच बिहार, दार्जलिंग, दक्षिण दिनाजपुर, जलपाइगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद, नाडिया, उत्तर 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर	49
14	xqtjkr	बनासकांठा, कच्छ, पाटण	30
15	jktLFkku	जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर	46
		dqy	940

¼3½ vçSy 2017 eghus ds nkSjku pEikj.k lR;kxzg ds 100 lky

चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित शताब्दी समारोह के सिलसिले में बिहार में मोतीहारी में कार्यक्रम आयोजित किये गये। यहीं चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल माननीय रामनाथ कोविन्द (वर्तमान राष्ट्रपति) और केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने 'सत्य के सुर' कार्यक्रम का उद्घाटन किया। छह दिन तक चले इस कार्यक्रम में माननीय कौशल विकास मंत्री श्री राजीव प्रताप रूड़ी ने भी हिस्सा लिया।

¼4½ vkthfodk esyk

राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित आजीविका मेले में ग्रामीण भारत के सुंदर लोक नृत्यों और संगीत की झलक प्रस्तुत की गयी। मेले की सबसे बड़ी विशेषता दूर दराज के ग्रामीण अंचलों के हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी और देश के विभिन्न भागों की महिलाओं के स्व–सहायता समूहों के 500 से ज्यादा स्टॉल थे।

¼5½ jkT; lHkk fnol

राज्यसभा दिवस का आयोजन 1952 में इसकी पहली बैठक की याद में मनाया जाता है। इस सिलसिले में संसद भवन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

xhr ,oa ukVd çHkkx }kjk ebZ 2017 ds nkSjku fd;s x;s dk;Øeksa dh fo'ks"k ckrsa bl çdkj gSa

¼1½ fdlku esyk&cqansy[kaM l'tu

मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ में आयोजित किसान मेले में

भाग लेकर वित्तीय समावेशन और कृषि क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं को विशेष रूप से प्रचारित किया। दो दिन के कार्यक्रम का उद्घाटन केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किया। समापन समारोह में मध्य प्रदेश के मुखमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि थे। किसान मेले में किसानों समेत 10,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया।

¼2½ vkfM'kk e iqjh e ykd eyk

प्रभाग ने ओडिशा में पुरी में 5 दिन के उत्सव में हिस्सा लिया। इसका विषय था 'स्वच्छ भारत' और इसमें 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' को लोक संगीत और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।

¼3½ ued lR;kxg e vkfM'kk d ;kxnku ij dk;Øe

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह में ओडिशा के योगदान पर केन्द्रित कार्यक्रम 'लबना सत्याग्रह' आयोजित किया गया। इसमें नमक सत्याग्रह में आम लोगों, खास तौर पर महिलाओं की भागीदारी के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन में ओडिशा की भूमिका को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गीत एवं नाटक प्रभाग के कलाकार कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए

¼4½ vkrdokn fojk/k fnol

आतंकवाद विरोध दिवस (21 मई 2017) के अवसर पर अहिंसा, साम्प्रदायिक सद्भाव, भाई चारे, देशभक्ति, महिला सशक्तीकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे विषयों पर कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किये गये ताकि शांतिपूर्ण और स्वस्थ माहौल को बढ़ावा मिले।

(5) jchUæ t;rh ¼5 eb@25 o'kk[k½ %

गीत एवं नाटक प्रभाग के कोलकाता क्षेत्रीय केन्द्र ने कवि गुरु रबीन्द्र नाथ ठाकुर की जयंती पर पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में कई विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किये जिनमें राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव और भाईचारे पर जोर दिया गया।

¼6½ ut:y t;rh ¼24 eb 2017½ %

कोलकाता केन्द्र ने विद्रोही कवि काजी नजरूल इस्लाम की जयंती पर भी पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में अहिंसा, भाईचारे, देशभक्ति, महिला सशक्तीकरण, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, तथा साम्प्रदायिक और सामाजिक सद्भाव जैसे विषयों पर आधारित कई कार्यक्रम प्रस्तुत किये।

गीत एवं नाटक प्रभाग के जून 2017 के कार्यक्रमों की विशेष बातें इस प्रकार थीं :

¼1½ vrjk"Vh; ;kx fnol % युवाओं, स्कूली बच्चों, जेल के कैदियों, यातायात पुलिस आदि को ध्यान में रखकर देश भर में आयोजित 240 कार्यक्रमों से रोजमर्रा की जिंदगी में योग के महत्व को दर्शाया गया। इसमें जम्मू–कश्मीर, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में योग के माध्यम से अशांति दूर करने पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया।

¼2½ foRrh; lekos'ku

वित्तीय समावेशन विषय पर बिहार के गया जिले के दूर दराज के गांवों में कार्यक्रम आयोजित किये गये। 'मेरा खाता, भाग्य विधाता' के अंतर्गत जन धन योजना जैसे कई कार्यक्रमों को शामिल किया गया था। इनमें अन्य लोगों के अलावा सैकड़ों की संख्या में खेतिहर मजदूरों ने हिस्सा लिया।

¼3½ ,uMh, ljdkj d 3 lky

सरकार की सफलताओं के बारे में सभी राज्यों में नृत्य,

नाटक, कठपुतली शो आदि के कार्यक्रमों शुरू हुए। पहले चरण में जून 2017 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से करीब 230 कार्यक्रम आयोजित किये गये। इनमें बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और कम पानी से अधिक सिंचाई जैसी सरकार की कई प्रमुख योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया गया। इसके अलावा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, स्टार्ट अप इंडिया पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया।

¼4½ गीत एवं नाटक प्रभाग ने जून 2017 में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा और 13वें राजा महोत्सव 2017 के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये।

xhr ,oa ukVd çHkkx }kjk tqykbZ 2017 esa fd;s x;s dk;ZØeksa dh fo'ks"k ckrsa

¼1½ fo'o tula[;k fnol ij fo'ks"k dk;ZØe %

गीत एवं नाटक प्रभाग ने 11 जुलाई 2017 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर करीब 70 कार्यक्रम प्रस्तुत किये। इनमें से 20 पूर्वोत्तर राज्यों में आयोजित किये गये।

¼2½ Hkxoku txUukFk dh jFk ;k=k vkSj okilh jFk ;k=k ds volj ij fo'ks"k dk;ZØe %

ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा और वापसी रथ यात्रा के अवसर पर जुलाई 2017 में 30 कार्यक्रम आयोजित किये गये।

इस दौरान 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और 'स्वच्छ भारत मिशन' (एक कदम स्वच्छता की ओर) का विशेष प्रचार किया गया।

¼3½ u'khys inkFkksZa dh yr jksdus rFkk LokLF; dk lans'k nsus ds fy, fo'ks"k dk;ZØe

केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के तटवर्ती इलाकों में जुलाई 2017 में नेहरू युवा केन्द्र के साथ मिलकर 'वाक फॉर वैलनेस' नाम के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इनका उद्देश्य युवाओं और बच्चों में, नशीले पदार्थों की लत रोकने तथा स्वास्थ्य का संदेश देने के बारे में व्यापक रूप से चेतना जगाना था।

¼4½ ^Jh vejukFk ;k=k 2017* ds nkSjku fo'ks"k dk;ZØe%

गीत एवं नाटक एकांश ने जम्मू में जुलाई 2017 में पर्यटन विभाग के सहयोग से 25 कार्यक्रम प्रस्तुत किये। इन कार्यक्रमों के माध्यम से उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन इंद्रधनुष, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय एकीकरण और साम्प्रदायिक सद्भाव पर जोर दिया गया।

¼5½ Hkkjr&ikd lhekorhZ {ks=ksa esa fo'ks"k dk;ZØe

जम्मू केन्द्र के विभागीय कलाकारों ने भदरवाह जिले के सीमावर्ती इलाकों में 10 कार्यक्रम भारत–पाकिस्तान सीमा से लगे गांवों में प्रस्तुत किये।

कार्यक्रमों की प्रस्तुति के दौरान 'स्वच्छ भारत मिशन–(एक कदम स्वच्छता की ओर)', 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत,' 'राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव,' 'प्रधानमंत्री जन–धन योजना,' 'मिशन इंद्रधनुष,' 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना,' 'सबका साथ, सबका विकास,' 'कुपोषण के खिलाफ,' आदि पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया।

vxLr 2017 ds nkSjku dk;ZØeksa dh fo'ks"k ckrsa bl çdkj jgha%

1- lkaLd`frd io

(1) 9 अगस्त 2017 को राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में देशभक्ति के गीतों का

गीत एवं नाटक प्रभाग के कलाकार जम्मू–कश्मीर में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में प्रस्तुति देते हुए

गुलदस्ता प्रस्तुत करते हुए गीत एवं नाटक प्रभाग ने देश भर में 'संकल्प से सिद्धि – न्यू इंडिया अभियान 2017–22' विषय पर 400 कार्यक्रम प्रस्तुत किये।

(2) गीत एवं नाटक प्रभाग ने आम लोगों, खास तौर पर युवाओं में राष्ट्र के बारे में गौरव की भावना का संचार करना और उन्हें आजादी के बाद देश की प्रगति का एहसास कराने के लिए 400 से ज्यादा कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

पुदुच्चेरी और इम्फ़ाल में दो विशेष कार्यक्रम आयोजित किये गये। ले। गवर्नर डॉ. (श्रीमती) किरन बेदी पुदुच्चेरी में मुख्य अतिथि थीं। इस कार्यक्रम में कई कॉलेजों ने भाग लिया और न्यू इंडिया की शपथ दिलाई गयी। इम्फाल में आयोजित समारोह में मणिपुर की राज्यपाल श्रीमती नजमा हैपतुल्ला ने दर्शकों को न्यू इंडिया की शपथ दिलाई।

2- jk"Vªh; gFkdj?kk fnol

7 अगस्त, 2017 को आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस में देश के हथकरघा बुनकरों और भारत के हथकरघा उद्योग में उनके योगदान के सम्मान में देश भर में 125 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। नुक्कड़ नाटक (बुनकर का घर) में वस्त्र मंत्रालय द्वारा हथकरघा को बढ़ावा देने, बुनकरों की आमदनी बढ़ाने और उनमें अपने व्यवसाय के प्रति गौरव की भावना जगाने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना भी था।

3- fo'o f'k'kq Lruiku fnol

भारत में माताओं द्वारा शिशुओं को स्तनपान कराने के बारे में जागरूकता को व्यापक रूप से बढ़ावा देने के लिए 1 से 7 अगस्त 2017 तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया गया। इसमें पारम्परिक लोक निष्पादन कलाओं के माध्यम से यह बताने का भी प्रयास किया गया कि किस तरह माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार शिशु–जन्म संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान कर रही है और देश में स्तनपान को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है।

4- गीत एवं नाटक प्रभाग ने पश्चिम बंगाल में हावड़ा में विश्व शिशु स्तनपान सप्ताह के अवसर पर 1–7 अगस्त 2017 में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में स्वतंत्रता दिवस समारोह और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में भी अपनी प्रस्तुतियां दीं। इसके अलावा अगस्त 2017 में पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 21वीं राष्ट्रीय हैंडलूम प्रदर्शनी में भी कार्यक्रम प्रस्तुत किये।

flrcj 2017 d nkjku vk;kftr dk;Øek dh e[; ckr ;k jgh%

¼1½ ldYi io

न्यू इंडिया अभियान के तहत 'संकल्प से सिद्धि' जैसे कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के लिए गीत एवं नाटक प्रभाग ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में देशभक्ति के गीतों का गुलदस्ता प्रस्तुत किया। इसके लिए आयोजित विशेष कार्यक्रम में राज्यपाल ले. जनरल (रिटायर्ड) निर्भय शर्मा मुख्य अतिथि थे और मुख्यमंत्री श्री ललथनहौला सम्मानित अतिथि थे। इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर राज्यों के गीतों और नृत्यों के अलावा हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत भी प्रस्तुत किया गया।

¼2½ ^U;w bfM;k & fuekZ.k dk ldYi*½

संसदीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर केन्द्रित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और फोटो प्रदर्शनी 'न्यू इंडिया – निर्माण का संकल्प' असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में आयोजित किया गया। इसमें केन्द्रीय मंत्री श्री विजय गोयल, श्री एस.एस. अहलूवालिया और श्री महेश शर्मा मुख्य अतिथि थे। इन कार्यक्रमों के विषय न्यू इंडिया अभियान, संकल्प से सिद्धि और सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों पर केन्द्रित थे।

¼3½ LoPNrk lok½

स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के दौरान 600 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें 'स्वच्छता ही सेवा' को मुख्य विषय बनाया गया।

पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से कोलकाता में दक्षिणेश्वर मंदिर और बेलूरमठ, उत्तराखंड में ऋषिकेश के घाटों, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर और असम में

गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किये गये। इनमें पूजास्थलों में साफ–सफाई के महत्व पर जोर देने के लिए इन धार्मिक सम्प्रदायों के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया गया।

¼4½ jk"Vªh; ik"kkgkj lIrkg

स्वास्थ्य और समग्र खुशहाली के बारे में जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रमों के जरिए राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह का आयोजन किया गया। इनमें कुपोषण के दुष्परिणामों की जानकारी देने के साथ–साथ इसे दूर करने के उपायों के बारे में बताया गया।

vDrcj 2017 e vk;kftr dk;Øek dh e[; ckr%

¼1½ xke lef) ,o LoPNrk i[kokMk

ग्रामीण विकास मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वच्छ और हरित ग्राम, पं. दीन दयाल उपाध्याय अन्त्योदय योजना, ग्रामीण आवास योजना, पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और ग्रामीण स्व–रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि शामिल हैं, 26 राज्यों के 46 जिलों/पंचायतों में 770 ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किये गये। करीब 4 लाख लोगों ने इनमें हिस्सा लिया।

¼2½ gLrdyk lg;kx f'kfoj

वस्त्र मंत्रालय के हैंडलूम और हस्तशिल्प क्लस्टर्स के हस्तकला सहयोग शिविरों में करीब 200 कार्यक्रम स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आयोजित किये गये। नुक्कड़ नाटकों, कठपुतली, लोक कलाओं और संगीत पर आधारित इन कार्यक्रमों में बुनकरों और हस्तशिल्पियों को उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं के साथ–साथ मुद्रा योजना के तहत ऋण सुविधा, हथकरघा संवर्धन सहायता योजना के अंतर्गत तकनीकी उन्नयन और ई–धागा मोबाइल एप के प्रदर्शन जैसे प्रचार–प्रसार के कार्य किये गये।

¼3½ विभिन्न अवसरों जैसे पुरी (ओडिशा) में 87वें राज्य स्तरीय नमक सत्याग्रह स्मारक समारोह, कोलकाता में अलीपुर के एम्बारकेशन मुख्यालय में स्थापना दिवस समारोह, पुरी ओडिशा में 15वें लोक उत्सव 2017, पश्चिम बंगाल में पश्चिम मेदिनीपुर के हनुमानजी पूजा महोत्सव, ओडिशा के कोररापुट में श्रीश्रीश्री मां गंगेश्वरी वार्षिक समारोह, ओडिशा में बालेश्वर के वार्षिक चंदन यात्रा समारोह और ओडिशा के बरगढ़ में शीतल शष्ठि विवाह महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये।

QkVk çHkkx

I. Hkfedk

1959 में स्थापित फोटो प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है जो भारत सरकार की गतिविधियों की फोटो कवरेज करके दृश्य सहायता उपलब्ध कराता है। इसके पास 10 लाख से अधिक नेगेटिव/ट्रांसपेरेंसीज का संग्रह है जो डिजिटल फार्मेट में संरक्षित हैं। ये स्वतंत्रता से पूर्व से लेकर वर्तमान समय तक की हैं और इतिहास की दृष्टि से इनका बहुत अधिक महत्व है।

फोटो प्रभाग की स्थापना प्रकाशन विभाग के फोटो स्टूडियो और पत्र सूचना कार्यालय की फोटो यूनिट तथा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को मिलाकर की गयी थी ताकि इनके एक जैसे काम की दोहरावट न हो।

फोटो प्रभाग हर साल समाचार और फीचर से संबंधित 4500 से 5000 तक कार्यों को पूरा करता है और सरकारी कार्यक्रमों का फोटो के माध्यम से प्रचार करने के लिए इसकी अपनी वेबसाइट है। इसकी अपनी स्थायी फोटो गैलरी भी है जिसका निर्माण 2016–17 में किया गया था। इसमें सरकारी गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में फोटो प्रदर्शनियां लगायी जाती हैं।

प्रभाग के गठन के 50 साल पूरे होने के अवसर पर इसने राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कारों की शुरुआत की थी। बीते वर्षों में इन वार्षिक पुरस्कारों ने फोटोग्राफी की कला को बढ़ावा देने और शौकिया व पेशेवर फोटोग्राफरों द्वारा दृश्य प्रलेखन के जरिए देश की सांस्कृतिक विरासत जैसे कला, संस्कृति, धरोहरों, लोक जीवन, समाज, रीति–रिवाज को संरक्षित करना है।

II. QkVk çHkkx d dk;Z

फोटो प्रभाग का प्रमुख कार्य देश के सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक यात्रा के मील के पत्थरों को कैमरे की आंख के जरिए प्रलेखबद्ध करना, उनका प्रसार करना

तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रख्यात फिल्म निर्देशक श्री के. विश्वनाथ को दादा साहेब फाल्के सम्मान प्रदान करते हुए। इस अवसर पर तत्कालीन माननीय सूचना व प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू और तत्कालीन माननीय सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी उपस्थित थे।

और उन्हें भविष्य के लिए अभिलेख बनाकर सुरक्षित रखना है। इसके विशिष्ट कार्यों में शामिल हैं :

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों को विजुअल (यानी स्टिल फोटोग्राफ) उपलब्ध कराना ताकि उन्हें आगे विभिन्न जन संचार माध्यमों को भेजा जा सके।

क) पत्र सूचना कार्यालय की प्रेस फोटो सुविधा पूरी तरह फोटो प्रभाग समर्थित है।

ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) का प्रदर्शनी स्कंध बड़े आकार के प्रिंट तैयार करने और फोटो संबंधी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फोटो प्रभाग की मदद लेता है।

(2) प्रधानमंत्री के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की विशेष कवरेज के जरिए (सप्ताह में सातों दिन और चौबीसों घंटे) फोटो खींचने की व्यवस्था करता है। बाद में इनके आधार पर प्रधानमंत्री की यात्राओं के विशेष एलबम तैयार किये जाते हैं।

(3) महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, माननीय अध्यक्ष लोकसभा, कैबिनेट मंत्रियों और महत्वपूर्ण सार्वजनिक घटनाओं की फोटो कवरेज करना।

(4) भारत यात्रा पर आए राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों जैसे अति विशिष्ट व्यक्तियों की कवरेज के जरिए विदेश मंत्रालय के विदेशी प्रचार प्रभाग को मदद देना। विदेशी मेहमानों की यात्रा के अंत में उन्हें फोटो प्रभाग की ओर से उनके फोटोग्राफ्स का विशेष एलबम भेंट किया जाता है।

(5) पूर्वोत्तर राज्यों में विकास संबंधी गतिविधियों को फोटो के रूप में अभिलेखबद्ध करने के लिए विशेष अभियान चलाये जाते हैं।

(6) गैर–प्रचार संगठनों, निजी प्रकाशकों और आम जनता को निर्धारित मूल्य पर फोटोग्राफ उपलब्ध कराना।

III. lxBukRed <kpk

फोटो प्रभाग मुख्यालय नई दिल्ली के लोधी रोड इलाके में सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सूचना भवन में है। इसके प्रमुख निदेशक (फोटो प्रभाग) कहलाते हैं और उनकी सहायता के लिए उप निदेशक, वरिष्ठ फोटोग्राफिक अधिकारी, फोटोग्राफिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी तथा अन्य तकनीकी व अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं।

प्रभाग के कर्मचारी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य

मंत्रियों को विस्तृत फोटो कवरेज प्रदान करने और सचित्र प्रचार के लिए फोटो लेने उनके साथ देश–विदेश की यात्राओं पर जाते हैं। वे तस्वीरों को उचित तरीके से अभिलेखबद्ध करके भविष्य के लिए फोटो प्रभाग संग्रहालय को समृद्ध करने का कार्य भी करते हैं।

IV. QksVks çHkkx dk vk/kqfudhdj.k

फोटो प्रभाग की सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास किये गये हैं। इसके लिए बड़े और बेहतर उपकरण लगाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए प्रदर्शनियों में आदम कद फोटो उपलब्ध कराने के लिए बड़े फार्मेट वाले इंक जेट प्रिंटर लगाए जा रहे हैं और अति विशिष्ट लोगों के फोटो के एलबम तैयार करने के लिए विशेष डिजिटल प्रिंटर उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अलावा फोटोग्राफों को अभिलेखागार में संग्रहीत, उनके सूचीकरण और वर्गीकरण के लिए उच्च क्षमता का सर्वर लगाया गया है जिसमें 8–10 लाख डिजिटल तस्वीरों को रखा जा सकता है।

V. vU; ehfM;k bdkb;ksa ds lkFk rkyesy

फोटो प्रभाग अपनी सहयोगी मीडिया इकाइयों की डिजिटल फोटो की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित हुआ है। प्रभाग का समाचार फोटो नेटवर्क पूरी तरह डिजिटल मोड में काम कर रहा है ताकि पत्र सूचना कार्यालय और अन्य संबंधित संगठनों तक इनके पहुंचने मे किसी तरह का विलंब न हो। उप–राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत यात्रा पर आए अति विशिष्ट व्यक्तियों की कवरेज से संबंधित असाइनमेंट में आयोजन स्थल से सीधे फोटो भेजने के लिए डिजिटल कैमरा उपकरण को लैपटॉप और डेटाकार्ड/वी के साथ इस्तेमाल में लाया जाता है।

VI. 2017&18 ds nkSjku okf"kZd ;kstuk ij vey

'मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम' के अंतर्गत योजनागत कार्यक्रम के लिए फोटो प्रभाग ने एक उप–योजना लागू की है। 'राष्ट्रीय फोटोग्राफी केन्द्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष अभियान' नाम की इस उप योजना के तहत तस्वीरें अपलोड करने और वार्षिक फोटोग्राफिक पुरस्कार योजना का संचालन किया जाता है।

VII. o"kZ ds nkSjku lEiUu egRoiw.kZ QksVks dojst

अपनी गतिविधियों के हिस्से के रूप में फोटो प्रभाग ने निम्न आयोजनों का प्रलेखन किया:

mijk"Vªifr dh ;k=k,a	
Hkkjr	fons'k
सितंबर 2017 में आंध्र प्रदेश, झारखंड, पंजाब और कर्नाटक	अप्रैल 2017 में आरमीनिया और पोलैंड
अक्तूबर 2017 में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र	
नवंबर 2017 में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा	

ç/kkuea=h dh ;k=k,a	
Hkkjr	fons'k
अप्रैल 2017 में उत्तर प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, दादरा और नगर हवेली तथा हिमाचल प्रदेश	मई 2017 में श्रीलंका
मई 2017 में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और असम	जून 2017 में जर्मनी, स्पेन, रूस, फ्रांस, कजाखस्तान, पुर्तगाल, अमेरिका और हालैंड
जून 2017 में उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात	जुलाई 2017 में इजरायल और जर्मनी
जुलाई 2017 में गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश	सितंबर 2017 में चीन और म्यांमार
अगस्त 2017 में बिहार और राजस्थान	अक्तूबर 2017 में फिलिपीन्स
सितंबर 2017 में गुजरात और उत्तर प्रदेश	
अक्तूबर 2017 में गुजरात, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक	

दौरे पर आए राष्ट्राध्यक्ष/शासनाध्यक्ष

1. साइप्रस के राष्ट्रपति
2. तुर्की के राष्ट्रपति
3. बेलारुस के राष्ट्रपति
4. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री
5. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री
6. श्रीलंका के प्रधानमंत्री
7. मलेशिया के प्रधानमंत्री
8. मॉरीशस के प्रधानमंत्री
9. नेपाल के प्रधानमंत्री
10. जापान के प्रधानमंत्री
11. इटली के प्रधानमंत्री
12. भूटान नरेश
13. बेल्जियम नरेश

प्रत्येक दौरे के खत्म होने पर फोटो प्रभाग ने भारत सरकार की ओर से अति विशिष्ट व्यक्तियों को रंगीन फोटो वाला एलबम उनके विदा होते समय भेंट किया।

VIII- çkMD'ku lc/kh vkdM+s

वर्ष 2017–18 के दौरान (यानी 1.4.2017 से 30.01.2018 तक) कवर किये गये एसाइनमेंट, खींची गयी तस्वीरों, अपलोड किये गये प्रिंटों और तैयार किये गये एलबमों की संख्या इस प्रकार है:

1.	कवर किये गये समाचार और फीचर एसाइनमेंट	2727
2.	पीआईबी वेबसाइट में भेजी गयी/अपलोड की गयी इमेज	5589
3.	फोटो प्रभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गयी इमेज	6467
4.	प्रभाग में ही हासिल डिजिटल इमेज	282523
5.	अभिलेखागार में सूचीकरण और तालिकाकरण के लिए चयनित इमेज	50,933
6.	बनाए/भेजे गये डिजिटल प्रिंट	25445
7.	अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए बने फोटो एलबम	37

IX- jktHkk"kk vf/kfu;e ij vey

फोटो प्रभाग मुख्यालय के अपने छोटे से कार्यालय में राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल है। सितंबर 2017 में हिन्दी पखवाड़े के दौरान हिन्दी के सामान्य ज्ञान पर एक प्रतियोगिता आयोजित की गयी।

IV- o"kZ 2017 dk fy, lrdZrk lc/kh okf"kZd fjiksVZ

1.	संगठन के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता संबंधी ढांचे का ब्यौरा	सतर्कता संबंधी कार्य के लिए अलग से कोई स्टाफ स्वीकृत नहीं है। बहरहाल, वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थों की सहायता से आम तौर पर ऐसे मामले निपटाते हैं
2.	अवधि के दौरान संचालित एहतियाती सतर्कता गतिविधियां:	
	i) अवधि के दौरान नियमित निरीक्षणों की संख्या	4
	ii) इस दौरान औचक निरीक्षणों की संख्या	2
3.	अवधि के दौरान चौकसी और निवारक गतिविधियां:	वे सभी क्षेत्र जिनमें प्रोडक्शन का काम किया जाता है
	i) चौकसी के लिए चुने गये क्षेत्रों का ब्यौरा	शून्य
	ii) निगरानी के तहत रखने के लिए व्यक्ति की पहचान	शून्य
4.	जिन मामलों में नियुक्ति अधिकारी राष्ट्रपति से भिन्न हैं तो दंडात्मक कार्रवाई को संख्याओं में 4(i) से (ix) प्रदर्शित किया जाए	
	i. अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें/संदर्भ	शून्य
	ii. कितने मामलों में प्रारंभिक जांच की गयी	शून्य
	iii. कितने मामलों में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मिली	शून्य
	iv. कितने मामलों में किसी बड़ी सजा के लिए चार्जशीट दायर की गयी	शून्य
	v. कितने मामलों में किसी छोटी सजा के लिए चार्जशीट दायर की गयी	शून्य
	vi. कितने लोगों को बड़ी सजा दी गयी	शून्य

	vii. कितने लोगों को छोटी सजा दी गयी	शून्य
	viii. कितने लोगों को निलंबित किया गया	शून्य
	ix. कितने लोगों के खिलाफ चेतावनी देने जैसी प्रशासनिक कार्रवाई की गयी	शून्य
	x. कितने लोगों को नियमों के संगत प्रावधानों के अनुसार समय पूर्व सेवानिवृत्त किया गया।	शून्य

Hkkjrh; tu lapkj laLFkku

भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1880 (1860 के 21) के तहत एक पंजीकृत संस्था है, जो कि 17 अगस्त, 1965 को अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना पत्रकारिता, मीडिया और जन संचार क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण और उपक्रम अनुसंधान के उद्देश्य के लिए की गई थी।

आज के मीडिया उद्योग की तेजी से बढ़ती हुई और बदलती हुई के विविध प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए आईआईएमसी विशेष प्रकार पाठ्यक्रम आयोजित करती है। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के अलावा यह संस्थान प्रिंट पत्रकारिता (अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और उड़िया) रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता और विज्ञापन एवं जनसंपर्क में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। संस्थान विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित, 1969 से आईटीईसी,एससीएएपी और कोलंबो योजना स्कीम के टीसीएस के तहत एशियन, अफ्रीकन, लैटिन अमरीकन और ईस्ट यूरोपियन देशों के मध्यम स्तरीय श्रमजीवी पत्रकारों के लिए विकास पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का भी संचालन कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के विभिन्न मीडिया, प्रचार और परिचालन क्षेत्र में कार्यरत संचार पेशेवरों की हमेशा बढ़ती प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने के लिए संस्थान एक सप्ताह से लेकर चार सप्ताह अवधि वाले विभिन्न विशेष लघु अवधि पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है। संस्थान प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला आदि और संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है।

हाल के समय में, जन संचार बदलाव के दौर से गुजर रहा है और यह गतिविधियों के एक ऐसे प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा है जो निर्णय लेने की प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसने तेजी से महत्व और शोहरत हासिल कर ली है और विभिन्न शैक्षणिक विषय छात्रों के लिए प्रमुख आकर्षण बन गए हैं। दुनिया भर में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने जन संचार के विस्तार और स्वरूप को बदलने में व्यापक योगदान दिया है।

तदनुसार, बदलती हुई परिस्थितियों में संस्थान लगातार स्वतः मूल्यांकन करता है और अपने पाठ्यक्रम में बदलाव करता है ताकि तेजी से बदलते वातावरण में समकालीन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।

अस्तित्व में आने के आधी सदी बाद लगातार अपनी कड़ी मेहनत के जरिये और अपने उत्कृष्ट वितरण तंत्र के परिणामस्वरूप संस्थान लगातार संचार शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र की प्रतिष्ठा को बरकरार रखे हुए है। विभिन्न सर्वेक्षणों में संस्थान देश की शीर्ष मीडिया संस्थानों के बीच अपने रैंक को बनाए रखे हुए है।

vkbZvkbZ,elh dh {ks=h; igqap

आईआईएमसी की बढ़ती हुई प्रशिक्षण क्रिया–कलापों की प्रसिद्धि के कारण तथा क्षेत्रीय लोगों की आंकाक्षाओं को पूरा करने हेतु, 1993 में इसने ढेंकनाल (ओडिशा) में एक क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की। वर्तमान में यह केंद्र अंग्रेजी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा उड़िया पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चला रहा है।

आईआईएमसी के विस्तार का अगला चरण 2011 और 2012 में पूरा हुआ जब 2011 में आईजोल (मिजोरम) और अमरावती (महाराष्ट्र) में तथा 2012 में जम्मू (जम्मू और कश्मीर) तथा कोट्टायम (केरल) में क्षेत्रीय केंद्र खोले गए। इनकी स्थापना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराए गए अस्थाई परिसर में की गई। ये चारों क्षेत्रीय केंद्र अंग्रेजी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

दे रहे हैं। वर्ष 2017–18 से दो और क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक तो अमरावती में स्थित पश्चिमी क्षेत्रीय परिसर द्वारा चलाया जा रहा मराठी पत्रकारिता का पाठ्यक्रम है। दूसरा कोट्टायम स्थित दक्षिणी क्षेत्रीय परिसर द्वारा चलाया जा रहा मलयालम पत्रकारिता का पाठ्यक्रम है।

इस प्रकार आईआईएमसी ने अपना चरित्र काफी बदल लिया है। यह अब केवल दिल्ली आधारित संस्था न होकर राष्ट्रव्यापी संस्थान हो गया है और अब इसके क्षेत्रीय परिसर देश के पांच प्रमुख केंद्रों में स्थित हैं।

1 अप्रैल, 2017 से अक्तूबर 2017 तक की शैक्षणिक गतिविधियांः

vkbZvkbZ,elh }kjk lapkfyr ikBîØe

स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिप्लोमा पाठ्यक्रम

शैक्षणिक वर्ष 2017–18 के लिए निम्नलिखित स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया मार्च 2017 में शुरू हुईः

(1) पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (हिंदी), दिल्ली

(2) पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (अंग्रेजी), दिल्ली ढेंकनाल, आईजोल, अमरावती, जम्मू और कोट्टायम

(3) विज्ञापन और जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, दिल्ली

(4) रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, दिल्ली

(5) पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (उड़िया), ढेंकनाल

(6) उर्दू में पत्रकारिता स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, दिल्ली

(7) मराठी में पत्रकारिता स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, अमरावती

(8) मलयालम में पत्रकारिता स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, कोट्टायम

ऊपर उल्लेखित विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा के लिए पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 6624 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।

ऊपर बताए गए सभी पाठ्यक्रमों (उड़िया और उर्दू पत्रकारिता को छोड़कर) के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा 28 मई, 2017 को आयोजित की गई। ये प्रवेश परीक्षाएं पहली बार पूरे देश में 18 शहरों में आयोजित की गईं। ये परीक्षाएं नई दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, बंगलुरू, मुंबई, नागपुर, आईजोल, भोपाल, चेन्नई, जम्मू, कोच्ची, रायपुर, रांची और हैदराबाद में आयोजित की गई। हालांकि, केवल तीन उम्मीदवारों ने श्रीनगर का विकल्प चुना था। इसलिए बाद में उनसे परीक्षा के लिए जम्मू परिसर मे स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया। पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम (उड़िया, उर्दू, मराठी और मलयालम) के लिए प्रवेश परीक्षा 27 मई, 2017 को भुवनेश्वर, दिल्ली, नागपुर, मुंबई और कोच्चि में 21 जून, 2017 को परीक्षा के परिणामों की घोषणा की गई। इसके बाद साक्षात्कार / समूह चर्चा का आयोजन दिल्ली और क्षेत्रीय परिसर में 29 जून 2017 से किया गया। स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का अंतिम परिणाम 13 जुलाई 2017 को घोषित किया गया।

नए सत्र की शुरूआत 1 अगस्त, 2017 को हुई। अमरावती के माननीय सांसद श्री आनंदराव अडसूल ने मराठी पत्रकारिता स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की शुरूआत दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में की। इस कार्यक्रम को ऑनलाइन द्वारा अमरावती में आईएमसी के पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र से जोड़ा गया था। इस अवसर पर आईआईएमसी के छोटे ऑडिटोरियम में महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बालगंगाधर तिलक की मूर्ति का अनावरण भी किया गया।

नई दिल्ली स्थित आईआईएमसी केंद्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ओरिएन्टेशन सेशन का आयोजन 1 से 4 अगस्त 2017 तक किया गया था। इस सत्र में जनसंचार क्षेत्र के विख्यात विभिन्न विभूतियों ने भाग लिया। इनमें प्रमुख हैः डॉ. ए सूर्य प्रकाश – अध्यक्ष प्रसार भारती, श्री आलोक मेहता– वरिष्ठ पत्रकार, सुश्री सुवी चतुर्वेदी, इंटरनेट स्कॉलर और समीक्षक सुश्री अभिजीत दत्त, वरिष्ठ विज्ञापन तथा संचार परामर्शदाता। इन विभूतियों ने भी सत्र को संबोधित किया।

मलयालम पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरूआत 12 अगस्त, 2017 को आईआईएमसी के निदेशक श्री के.जी. सुरेश ने कोट्टायम, केरल स्थित आईआईएमसी के दक्षिण क्षेत्रीय परिसर में की।

Hkkjrh; lpuk lok ikBîØe

2016 बैच के भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' के 14

सूचना एवं प्रसारण सचिव एवं आईआईएमसी अध्यक्ष श्री एन. के. सिन्हा भारतीय सूचना सेवा, ग्रुप 'ए' के प्रशिक्षण के प्रथम चरण की समाप्ति पर प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ

अधिकारी प्रशिक्षुओं (ओटीएस) ने आईआईएमसी में अपना इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 अक्तूबर, 2017 को पूरा किया। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु अधिकारी को संचार, मीडिया–विशेषतः विभिन्न मीडिया ईकाइयों जैसे दूरदर्शन, डीएवीपी, डीएफपी, पीआईबी आदि के लिए तैयार किए गए कक्षा मॉड्यूलों के बारे में बताया गया। अन्य महत्वपूर्ण बातों में शामिल है दिल्ली से बाहर के कार्य जैसे कि असम राईफल्स के साथ डिफेन्स अटैचमेन्ट, झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के साथ वामपंथी प्रभावित क्षेत्रों में विशेष संचार की जरूरत को पूरा करने के लिए एलडबल्यूई अटैचमेन्ट, मानेसर में नेशनल सिक्यूरिटी गार्ड अटैचमेन्ट। जंगली जीवन और सामाजिक फोरेस्ट्री पर संरक्षण अध्ययनय इसके अलावा रेडियो, दूरदर्शन के फीचर तथा समाचार लेखन के बारे में तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना तथा एफटीआईआई, पुणे में डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म का निर्माण की जानकारी दिलवाना आदि। इन प्रशिक्षुओं को सोशल मीडिया का भी गहन परिचय कराया गया। इनमें फेसबुक, गूगल, मेल्टवाटर आदि से परिचय कराया गया। इनको क्राइसिस कम्यूनिकेशन के बारे में भी संक्षिप्त परिचय दिया गया। इस प्रशिक्षुओं को पर्यावरणीय ऑडिट, सामाजिक ऑडिट तथा जमीनी स्तर पर संचार की भी जानकारी दी गई। ये प्रशिक्षु अधिकारी तीन हफ्ते के लिए भारत दर्शन अध्ययन यात्रा पर भी गए। इस दौरान इन्होंने बुन्देलखंड के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को भी देखा।

इस वर्ष 2015 बैच के 9 प्रशिक्षु अधिकारियों ने दूसरे चरण के प्रशिक्षण को पूरा किया। इस दौरान इन्होंने दूसरी मीडिया इकाइयों में प्राप्त अपने अनुभवों को दूसरे साथियों से साझा किया। दूसरे चरण के प्रशिक्षण के दौरान सोशल मीडिया, रिसर्च और मीडिया प्लानिंग पर विशेष व्याख्यान आयोजित किए गए।

पहली बार भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के लिए मिड–करियर ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत तीसरे चरण का 4 हफ्तों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण एमडीआई, गुड़गांव और आईएसटीएम, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण सीनियर टाइम स्केल (एसटीएस) स्तर के उन अधिकारियों के लिए था जिनकी अगले ग्रेड में प्रोन्निति होने वाली थी।

fodkl i=dkfjrk e fMIykek ikBîØe

गुट निरपेक्ष और विकासशील देशों के लिए विकास

67वें विकास पत्रकारिता पाठ्यक्रम के छात्र आईआईएमसी में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हुए

पत्रकारिता में 67वें डिप्लोमा पाठ्यक्रम का दीक्षांत समारोह 27 अप्रैल 2017 को हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. वी.के. कुठियाला थे। उन्होंने 19 देशों के 23 मिड–केरियर पत्रकारों को डिप्लोमा प्रदान किए।

गुटनिरपेक्ष और विकासशील देशों के लिए विकास पत्रकारिता में 68 वें डिप्लोमा पाठ्यक्रम का 18 देशों के 25 प्रतिभागियों के साथ 1 अगस्त 2017 को आरंभ हुआ। चार महीने वाला यह पाठ्यक्रम 24 नवंबर 2017 को समाप्त हुआ।

आईआईएमसी के 50वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि श्री कैलाश सत्यार्थी और श्री के.जी. सुरेश, महानिदेशक तथा तत्कालीन अपर महानिदेशक श्री मयंक अग्रवाल दीप प्रज्वलित करते हुए

vkbZvkbZ,elh dk 50oka nh{kkar lekjksg

आईआईएमसी का 50वां दीक्षांत समारोह 20 नवंबर 2017 को उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी थे। उन्होंने समारोह को संबोधित भी किया। विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के कुल 339 छात्रों को उनके डिप्लोमा प्रदान किए गए। पहली बार संयुक्त दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय सूचना सेवा के 9 प्रशिक्षु अधिकारियों को उनकी 2 वर्ष के इंडक्शन प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने पर प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा 18 देशों के 25 विकास पत्रकारिता प्रतिभागियों ने भी 4 महीने से चल रहे विकास पत्रकारिता पाठ्यक्रम पूरा होने पर मुख्य अतिथि से डिप्लोमा प्राप्त किए।

1 vçSy 2017 ls 31 vä wcj 2017 dh nkSjku vk;ksftr fd, x, y?kq ikB~Øe

आईआईएमसी सूचना प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों के कर्मियों के लिए नियमित रूप से लघु–अवधि के शैक्षिक पाठ्यक्रम आयोजित करता है। इसके अलावा यह रक्षा अधिकारियों, विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों, केंद्र राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मीडिया और प्रचार संगठनों के कर्मियों की व्यावसायिक प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने के लिए भी लघु अवधि के पाठ्यक्रम आयोजित करता है। 1 अप्रैल से 31 अक्तूबर 2017 तक चलाए गए लघु अवधि के पाठ्यक्रमों

विकास पत्रकारिता पाठ्यक्रम के 68वें बैच के छात्र श्री के.जी. सुरेश, महानिदेशक तथा तत्कालीन अपर महानिदेशक श्री मयंक अग्रवाल, कोर्स निदेशक डॉ. आनन्द प्रधान के साथ

की सूची निम्न प्रकार से है:

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का नाम	दिनांक	पाठ्यक्रम निदेशक	प्रतिभागियों की संख्या
1.	एसएसबी के लिए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी	5 से 30 जून 2017	प्रो. विजय परमार	18
2.	जेसीओ/ एनसीओ के लिए वीडियोग्राफी पाठ्यक्रम	30 से 28 जुलाई 2017	प्रो. विजय परमार	15
3.	असम सरकार के डीआईपीआर अधिकारियों के लिए डिजीटल युग में जनसंपर्क पाठ्यक्रम	21 से 25 अगस्त 2017	प्रो. विजय परमार	07
4.	अधिकारी संचार और स्टाफ नियुक्ति/ पीआरओ/प्रशिक्षण के लिए मीडिया संचार पाठ्यक्रम	4 से 22 सितंबर 2017	प्रो. विजय परमार	17
5.	सामान्य अधिकारियों के लिए मीडिया संचार पर वर्कशॉप	9 से 13 अक्तूबर 2017	डॉ. अनुभूति यादव	12
6.	वरिष्ठ अधिकारी (ब्रिगेडयर/कर्नल/ समतुल्य) के लिए मीडिया संचार पाठ्यकक्रम	6 से 17 नवंबर 2017	डॉ. अनुभूति यादव	13
7.	टेलीविजन के लिए फिक्शन लेखन– एफटीआईआई लघु पाठ्यक्रम	7 से 29 नवंबर 2017	आईआईएमसी और एफटीआईआई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित	20
8.	एनडीआरएफ अधिकारियों के लिए जनसंपर्क पाठ्यक्रम	20 से 24 नवंबर 2017	डॉ. अनुभूति यादव	11

çe[k dk;Øe %

(i). आईआईएमसी का 53वां स्थापना दिवस 17 अगस्त 2017 को मनाया गया। इस अवसर पर छात्रों और कर्मचारियों ने खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के अध्यक्ष श्री बलदेव भाई शर्मा इस समारोह के मुख्य अतिथि थे।

(ii). रिपब्लिक टीवी के संस्थापक तथा एडिटर–इन–चीफ प्रो. अरनब गोस्वामी ने 18 अगस्त 2017 को स्थापना दिवस पर भाषण दिया।

vud lLFkkuk dk lkFk le>krk Kkiu

आईआईएमसी ने जनसंचार के क्षेत्र में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। इसके अनुसार दोनों संस्थाएं संयुक्त रूप से संस्कृत पत्रकारिता पर तीन महीने की अवधि का उन्नत पाठ्यक्रम आयोजित करेगी, एक समझौता ज्ञापन कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रामपुर के साथ किया गया। इसने भारतीय सूचना सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी विश्वविद्यालय में गए और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्लूई) प्रभावित क्षेत्रों में संचार जरूरतों पर संवादत्मक सत्र में भाग लिया। एक समझौता विज्ञान संचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान के साथ किया गया: और एक अन्य समझौता टेलीविजन आलेख लेखन के लिए भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के साथ किया गया।

vu|l/kku if=dk,i

आईआईएमसी दो त्रैमासिक अनुसंधान पत्रिकाएं प्रकाशित करती है। इनमें से एक का नाम 'संचार माध्यम' है जो हिंदी में निकलती है। दूसरी पत्रिका 'कम्यूनिकेटर' अंग्रेजी में निकलती है। इन पत्रिकाओं में मीडिया तथा संचार से संबंधित लेख प्रभावित किए जाते हैं।

^viuk jfM;k* dk ek/;e l lkenkf;d jfM;k dh igp

संस्थान का सामुदायिक रेडियो, 'अपना रेडियो' सप्ताह में 5 दिन सात घंटे का प्रसारण 96.9 एमएमजेड पर करता है। यह प्रसारण सुबह 10:30 बजे से सायं 5:30 तक संस्थान से 15 कि.मी. के दायरे के भीतर होता है। इस एफएम रेडियो स्टेशन में प्रसार–कक्ष, प्रस्तुति कक्ष, रिकॉर्डिंग कक्ष और तीन ध्वनि संपादन स्टेशन हैं।

lkenkf;d jfM;k l'kähdj.k ,oa llk/ku dæ

आईआईएमसी, नई दिल्ली में मार्च, 2017 में एक सामुदायिक रेडियो सशक्तीकरण एवं संसाधन केन्द्र की स्थापना की

गई। यह केन्द्र सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना, उनके संचालन तथा प्रबंधन का प्रशिक्षण देगा। यह एक ऐसा गतिशील केन्द्र होगा जिसमें सामुदायिक रेडियो पर विविध व्यावसायिक, व्यावहारिक और अनुसंधानात्मक गतिविधियां होंगी।

jk"Vªh; ehfM;k QSdYVh fodkl dsaæ

मीडिया शिक्षा, अनुसंधान, विस्तार और प्रशिक्षण के लिए वैश्विक मानकों को स्थापित करने के लिए आईआईएमसी के दृष्टिकोण के अनुरूप, संस्थान में एक राष्ट्रीय मीडिया फैकल्टी विकास केन्द्र की स्थापना की गई है।

,fues'ku] –';kRed çHkko] xsfeax vkSj d,feDl esa mR—"Vrk gsrq eqacbZ esa jk"Vªh; dsUæ dh LFkkiuk ¼,uhvkbZ&,ohthlh½

एनिमेशन, दृश्यात्मक प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) भारत में विकास के प्रारम्भिक चरण में हैं। इन क्षेत्रों में विस्तार और रोजगार देने की क्षमता को देखते हुए पूरे भारत में एवीजीसी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने आईआईएमसी के भाग के रूप में एनिमेशन, दृश्यात्मक प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक्स में उत्कृष्टता हेतु एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह केन्द्र सस्ती कीमत पर स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डॉक्टरल स्तर पर एवीजीसी के विभिन्न विषयों में विश्व स्तर की शिक्षा प्रदान करेगा।

यह केन्द्र मुम्बई में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने करीब 20 एकड़ जमीन फिल्म सिटी, मुम्बई में चिन्हित की है। इस केन्द्र की शुरूआत करीब 1480 छात्रों के साथ काम करने की है जिसमें 60 प्रतिशत छात्र स्नातक स्तर के कार्यक्रमों में होंगे। इस केन्द्र का अकादमिक उत्कृष्टता के लिए उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ तालमेल होगा।

आईआईएमसी ने प्रस्तावित केन्द्र की स्थापना के लिए प्रक्रिया पहले ही प्रारम्भ कर दी है।

Hkkjrh; tulapkj laLFkku dh dsUæh; {ks= dh ;kstuk,a

केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत आईआईएमसी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उन्नयन शामिल है। इससे संबंधित प्रस्तावों में आईआईएमसी, नई दिल्ली परिसर की मौजूदा मुख्य भवन और व्याख्यान ब्लॉक पर अतिरिक्त फर्श का निर्माण, उसी परिसर की खाली पड़ी जमीन पर नए भवन का निर्माण और ढेकनाल (उड़ीसा) परिसर में नए भवन का निर्माण शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र, मिजोरम, केरल तथा जम्मू और कश्मीर में चार नए क्षेत्रीय केन्द्रों की शुरूआत करना भी है जिसके लिए जमीन मुफ्त में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी जाएगी। इस प्रस्ताव में इन चारों केन्द्रों के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मुहैया कराई गई जमीन पर स्थायी परिसर का निर्माण भी शामिल है।

आईजोल परिसर की बिल्डिंग बनाने के लिए आईआईएमसी ने सीपीडब्ल्यूडी के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। संविदा सीपीडब्ल्यूडी को दिया गया और सितम्बर 2015 के आखिरी सप्ताह में कार्य प्रारम्भ किया गया। अक्टूबर 2017 तक 65 प्रतिशत कार्य हो चुका था।

जहां तक कोट्टायम परिसर बनाने की बात है, केरल सरकार ने कोट्टायम जिले के पैमपदी गांव में 10 एकड़ जमीन आईआईएमसी को मुफ्त में प्रदान की। आईआईएमसी ने कोट्टायम परिसर की बिल्डिंग बनाने के लिए सीपीडब्ल्यूडी से एक समझौता ज्ञापन किया। परिसर की बिल्डिंग बनाने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। सितम्बर 2017 के दूसरे क्वार्टर तक 40 प्रतिशत कार्य हो चुका था।

जम्मू परिसर की बिल्डिंग बनाने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने 24 मई, 2016 को आईआईएमसी को मुफ्त में जमीन प्रदान की। इस केन्द्र के बिल्डिंग निर्माण का कार्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सीपीडब्ल्यूडी (एआईआर) को सौंपा गया। इस समय परिसर की चारदीवारी बनाने का कार्य चल रहा है। स्थायी रूप से परिसर बनाने का कार्य बाद में प्रारम्भ किया जाएगा।

अमरावती परिसर के लिए आईआईएमसी को मुफ्त में 15 एकड़ जमीन 29 जून, 2016 को प्रदान की गई। अमरावती परियोजना का कार्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सीसीडब्ल्यू (एआईआर) को दिया गया। परियोजना रपट,

संरचनात्मक ड्रांइग आदि बनाने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। प्री–इन्वेस्टमेंट की गतिविधियों जैसे भूमि के स्थालाकृतिक सर्वेक्षण, मिट्टी की जांच आदि का कार्य शीघ्र ही शुरु होगा।

vU; igy

आईआईएमसी छात्रों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है और उसके पास एलौपैथिक डॉक्टर्स के अलावा होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हैं, जो नियमित रूप से परिसर में आते हैं।

दिल्ली और क्षेत्रीय दोनों परिसरों को स्वच्छ एवं हरित रखने के लिए आईआईएमसी ने अनेक कदम उठाए हैं। संस्थान ने अपने कर्मचारियों के जन्मदिन पर वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका नाम है 'प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा।'

आईआईएमसी के महानिदेशक श्री के.जी. सुरेश की अगुवाई में शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र स्वच्छ भारत अभियान को सफल करते हुए।

Hkkjrh; çsl ifj"kn

Hkwfedk

भारतीय प्रेस परिषद एक स्वायत्त प्राधिकरण है जिसे संसद से प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण के साथ–साथ प्रिंट मीडिया और प्रेस कर्मियों पर अपने अर्ध–न्यायिक कार्यों को पूरा करते हुए समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों में श्रेष्ठता के मानदंडों को बनाए रखने व इनमें सुधार की दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गयी है। परिषद में अध्यक्ष के अलावा 28 सदस्य भी होते हैं। प्रेस परिषद का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के किसी सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाने की परम्परा है। वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री चंद्रमौलि कुमार प्रसाद हैं। परिषद के 28 सदस्यों में से 20 प्रेस के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि आठ अन्य पाठकों के हितों की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं। इन आठ में से पांच संसद के दोनों सदनों (3 लोकसभा और 2 राज्यसभा) और देश की अग्रणी साहित्यिक और वैधानिक संगठनों, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और साहित्य अकादमी के प्रतिनिधि होते हैं। प्रेस परिषद के धन के स्रोतों में अखबारों से एकत्र शुल्क, अन्य प्राप्तियां और केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता शामिल है।

परिषद अपने कार्यों का निर्वहन प्रेस के खिलाफ पत्रकारिता के नैतिक मानदंडों के उल्लंघन या प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के खिलाफ शिकायतों से संबंधित मामलों पर अपने न्यायिक निर्णयों से करती है। अगर जांच के बाद परिषद् इस बात से संतुष्ट होती है कि किसी समाचार पत्र या समाचार एजेंसी ने पत्रकारिता के नैतिक मानदंडों या लोक–रुचि की सीमाओं का उल्लंघन किया है या किसी संपादक या श्रमजीवी पत्रकार ने कोई व्यावसायिक कदाचार किया है तो परिषद् उन्हें चेतावनी दे सकती है, फटकार लगा सकती है या फिर उनकी भर्त्सना कर सकती है या उनके आचरण को अनुचित ठहरा सकती है। प्रेस परिषद को प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किसी प्राधिकारी के बारे में, जिनमें सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं, ऐसी टिप्पणी करने का भी अधिकार है जो वह उचित समझता है। परिषद के निर्णय अंतिम होते हैं और उन्हें संविधान के संबद्ध अनुच्छेद के अंतर्गत रिट याचिका के अलावा अन्य तरीके से किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती

çsl ifj"kn dks feyh f'kdk;rsa

1 अप्रैल 2017 से 30 नवंबर 2017 तक भारतीय प्रेस परिषद को 506 शिकायतें मिलीं जिनमें से 142 मामले प्रेस ने दायर किये जबकि 364 प्रेस के खिलाफ थे। इसके अलावा पिछले 532 लंबित मामले भी परिषद के विचाराधीन थे। इनमें से 207 में परिषद ने न्यायिक निर्णय सुनाए और 687 मामले शुरू में ही मौखिक जांच के बिना बंद कर दिये गये। इस तरह परिषद ने 894 मामले निपटाये।

आलोच्य अवधि के दौरान परिषद ने निम्नलिखित रिपोर्टें प्रस्तुत कीं:

(1) जम्मू–कश्मीर में मीडिया और मीडिया परिदृश्य के

बारे में मध्यस्थ की रिपोर्ट की जांच कर रही उप समिति की रिपोर्ट (2) विज्ञापन और प्रत्यायन के मुद्दे पर उप समिति की रिपोर्ट (3) कर्नाटक विधानमंडल की महिला और बाल कल्याण समिति की सिफारिशें (4) अभद्र या छद्‌म विज्ञापन और रीमिक्स गीतों पर सदस्यों के निजी विधेयक के बारे में राय।

(5) भारतीय प्रेस परिषद अनैतिक तौर–तरीकों में लिप्त पाये गये और परिषद द्वारा फटकारे गये समाचार पत्रों की सूची विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को भेजता है ताकि प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति 2016 के प्रावधानों के अनुसार उनका नाम विज्ञापन प्राप्त करने वाले अखबारों की सूची से हटाया जा सके। यह कदम प्रेस को अपने नैतिक आचरण में सुधार को प्रेरित करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

ifj"kn us fuEufyf[kr ekeyksa dk Lor% laKku fy;k%

(1) पुलिस द्वारा फोटो पत्रकार श्रीयुत् श्रीकांत सिंह पर हमला, (2) आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम ग्रामीण जिले में नातवरम में साक्षी दैनिक के रिपोर्टर श्री ए.डी. बाबू पर हमला, (3) सोपोर (बारामूला) में पत्रकारों पर पुलिस का हमला, (4) 22.5.2017 को कोलकाता में पत्रकारों पर पुलिस का हमला, (5) दैनिक लोकमत (मराठी) के पत्रकार श्री गोविन्द इंगले के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला, (6) नई दुनिया के रिपोर्टर श्री कमलेश जैन की मंदसौर (मध्य प्रदेश) में हत्या, (7) अरुणाचल टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार/एसोसिएट संपादक श्री रंजीत मिश्रा पर अज्ञात लोगों द्वारा हमला, (8) ओडिशा में अंगुल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आयोजन की कवरेज के लिए पत्रकारों को धन देने का मामला, (9) ओडिशा में बालिपटना में प्रगतिवादी के रिपोर्टर श्री रमेश रथ पर नृशंस हमला, (10) बेंगलुरु में गौरी लंकेश पत्रिके की संपादक सुश्री गौरी लंकेश की अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या, (11) राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार श्री पंकज मिश्रा पर अरवल में जानलेवा हमला, (12) राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) द्वारा फ्रीलांस फोटो पत्रकार कामरान यूसुफ की गिरफ्तारी, (13) त्रिपुरा में दिनरात चैनल के रिपोर्टर शांतनु भौमिक की हत्या, (14) वरिष्ठ पत्रकार के.जे. सिंह की मोहाली (पंजाब) में हत्या, (15) छत्तीसगढ़ में माओवादियों द्वारा पत्रकारों को हत्या की धमकी, (16) अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश टाइम्स की प्रतियों को जला कर नष्ट करना, (17) छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा अमर उजाला के संपादक श्री विनोद वर्मा की गिफ्तारी, (18) तमिलनाडु पुलिस द्वारा फ्रीलांस कार्टूनिस्ट श्री जी. बाला की गिरफ्तारी, (19) बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पोनाफम दैनिक की प्रतियों को जलाया जाना, (20) त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के एक जवान द्वारा स्यंदन पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार सुदीप दत्ता भौमिक की हत्या।

çsl vkSj iqLrd iathdj.k vihyh; cksMZ

प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम, 1867 के अनुच्छेद

माननीय उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू तथा माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी 16 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भारतीय प्रेस परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हुए

8सी में अनुच्छेद 6 के अंतर्गत घोषणा का सत्यापन न करने और बाद में अनुच्छेद 8बी के तहत इसे रद्द करने के मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई का दायित्व भारतीय प्रेस परिषद को दिया गया है। इस बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा एक और सदस्य भी होता है जिसे भारतीय प्रेस परिषद अपने सदस्यों में से किसी एक को नामजद करती है। अवधि के दौरान बोर्ड ने अपनी चार बैठकों में 17 अपीलों की सुनवाई की और उनपर उपयुक्त आदेश सुनाए।

jk"Vªh; çsl fnol 2017

भारतीय प्रेस परिषद हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह का आयोजन करती है और यह साल परिषद की स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष होने के कारण इसके समापन समारोह में देशव्यापी चर्चा के लिए 'मीडिया के समक्ष चुनौतियां' विषय चुना गया था। मुख्य आयोजन का उद्घाटन माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने किया और माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी सम्मानित अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस अवसर पर पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए देश भर से प्राप्त प्रविष्टियों में से विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किये गये। विश्व प्रेस परिषद संघ (डब्ल्यूएपीसी) के प्रतिनिधियों ने भी, जो संघ की कार्यकरिणी की बैठक के सिलसिले में दिल्ली आए हुए थे, भारतीय प्रेस परिषद के इस आयोजन में हिस्सा लिया।

vrjk"Vªh; lokn@le>kSrk Kkiu

भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति चंद्रमौलि कुमार प्रसाद को विश्व प्रेस स्वाधीनता दिवस 2017 के अवसर पर यूनेस्को द्वारा इंडोनेशिया में जकार्ता में 'क्रिटिकल माइंड्स' फॉर क्रिटिकल टाइम्स : मीडियाज रोल इन एडवांसिंग पीसफुल, जस्ट एंड इनक्लूसिव सोसाइटीज' विषय पर 1–4 मई, 2017 तक आयोजित संगोष्ठी में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने श्रीलंका की प्रेस परिषद के आमंत्रण पर 1–3 अगस्त 2017 तक श्रीलंका का भी दौरा किया जहां उन्होंने मीडिया अध्ययन और पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के दीक्षांत समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में दीक्षांत भाषण दिया। उन्होंने पत्रकारिता को बढ़ावा देने की गतिविधियों के बारे में श्रीलंका की प्रेस परिषद के अध्यक्ष के साथ विचार–विमर्श किया। म्यांमार में 6 सितंबर 2017 को भारत के प्रधानमंत्री और म्यांमार की राजकीय सलाहकार की उपस्थिति में भारत और म्यांमार की प्रेस परिषदों के बीच एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये जिसमें सूचनाओं तक निर्बाध पहुंच के साथ नैतिकतापूर्ण, उत्तरदायी और कौशल संपन्न पत्रकारिता के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने की बात कही गयी है। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष, एक सदस्य और सचिव वाले शिष्टमंडल ने इस द्विपक्षीय समझौते को लागू करने के बारे में गहन चर्चा की जिसका उद्देश्य पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसी प्रशिक्षित श्रम शक्ति तैयार करना है जो सोशल मीडिया के दबाव से ऊपर

भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति चंद्रमौलि कुमार प्रसाद जकार्ता में विश्व प्रेस स्वाधीनता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए

उठकर कार्य कर सके और दोनों देशों द्वारा कड़ी मेहनत से कायम किये गये बहुमूल्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों में अपना योगदान कर सके।

ikjnf'krk dk fy, ç.kkyh

क. भारतीय प्रेस परिषद के सचिव कार्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी होते हैं। सचिवालय में किसी भी तरह के भ्रष्ट तौर–तरीकों को रोकने/इनसे निपटने के लिए नियमित और औचक जांच की गयी। शिकायत निवारण प्रणाली की अध्यक्षता प्रेस परिषद के सचिव करते हैं। आम जनता का कोई भी सदस्य अपनी शिकायतों के सिलसिले में हर बृहस्पतिवार को शाम 4 बजे से 5 बजे तक उनसे कार्यालय में मुलाकात कर सकता है।

ख. परिषद के नागरिक अधिकारपत्र (सिटीजन चार्टर) को अद्यतन किया जा रहा है।

ग. परिषद सचिवाल में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.जा./ दिव्यांगों आदि के बारे में भारत सरकार की आरक्षण नीति पर अमल किया जा रहा है।

jktHkk"kk dk c<kok

प्रेस परिषद ने सरकारी कामकाज में हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने पर खास ध्यान दिया। कर्मचारी राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित इसके अधिकांश कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने को प्रोत्साहित किया जाता है।

अलोच्य अवधि के दौरान हिन्दी अनुभाग ने अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए दो त्रैमासिक कार्यशालाओं का आयोजन किया। इसके अलावा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो त्रैमासिक बैठकें भी हुईं। प्रेस परिषद सचिवालय कर्मियों को हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भेजा गया।

हिन्दी के उपयोग पर जोर देने के लिए प्रेस परिषद सचिवालय में 14 से 28 सितंबर, 2017 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर प्रेस परिषद अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति चंद्रमौलि कुमार प्रसाद ने अपने भाषण में परिषद के कामकाज में हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के बारे में विचार व्यक्त किये। हिन्दी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकारी कामकाज में टिप्पण, प्रारूपण तथा टंकण जैसी गतिविधियों में हिन्दी भाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने में योगदान करने वाले प्रेस परिषद कर्मचारियों को नकद पुरस्कारों व प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया।

माननीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान–2017 के प्रसारण के अवसर पर सरदार वल्लभभाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए

डीडी न्यूज का समाचार कक्ष

5 ilkj.k {k= dh xfrfof/k;k

Hkkjr esa çlkj.k {k= dk voyksdu

1. 90 के दशक के शुरुआती वर्षों में केबल और सैटेलाइट टेलीविजन बाजार अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और स्वदेशी मीडिया कंपनियों के विकास से आरंभ हुआ। इस उद्योग में तेजी से विकास हुआ है। 1992 में इसके कुल सब्सक्राइबर की संख्या जहां 0.41 मिलियन थी, वहीं 2016 के अंत तक बढ़कर 181 मिलियन हो चुकी है। 31 अक्तूबर 2017 के अनुसार भारत में एक बड़ा प्रसारण और वितरण विभाग है, इसके अंतर्गत 877 टीवी चैनल, 1469 स्थाई और 2 प्रोविजनल मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) आते हैं जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पंजीकृत हैं। इसमें सात डीटीएच, सैटेलाइट टीवी ऑपरेटर्स और दो एचआईटीएस ऑपरेटर्स और कई आईपीटीवी सेवा प्रदाता भी हैं।

2. टेलीविजन उद्योग की मूल्य शृंखला में विषय–वस्तु निर्माण, प्रसारण और वितरण अनुभाग शामिल हैं। हालांकि विषयवस्तु निर्माण उद्योग अभी अनियमित है। प्रसारण और वितरण अनुभाग को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विनियमित किया है। नियमानुसार विदेश से अप. लिंक चैनलों की एक बड़ी संख्या के सैटेलाइट संकेत भारत में उपलब्ध हो सकते हैं, सिर्फ उन्हीं चैनलों को एमआईबी द्वारा प्रसारण और वितरण की मंजूरी दी गई है, जो अपलिंकिंग नीति और दिशा निर्देशों/डाउनलिंकिंग नीति–निर्देशों के अंतर्गत आते हैं। प्रसारणकर्ता द्वारा लिए गए राजस्व ढांचे पर निर्भर रहते हुए, एक टीवी चैनल या तो पे चैनल बन सकता है या फ्री टू एयर (एफटीए) चैनल। पे चैनल का राजस्व ढांचा सब्सक्रिप्शन के जरिए टीवी चैनलों के वितरकों से आने वाले राजस्व से आय प्राप्त करता है। इसमें आय का एक स्रोत उनके चैनलों पर आने वाले विज्ञापनों से भी मिलता है, जबकि एफटीए की आय सिर्फ विज्ञापनों से प्राप्त होने वाले राजस्व पर निर्भर करती है। वितरकों को सालाना सब्सक्रिप्शन मूल्य के भुगतान के साथ अपने नेटवर्क में सामग्री के वितरण के लिए टीवी प्रसारणकर्ताओं के साथ अनुबंध करने होते हैं। भारत में चार प्रकार के वितरण प्लेटफॉर्म्स को मंजूरी दी गई है। ये हैं केबल टेलीविजन सेवा, डायरेक्ट टू होम सेवा, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विसेज और स्काई सर्विसेज।

3. भारत में केबल टीवी सेवा को केबल टेलीविजन नेटवर्क्स एक्ट 1995 के तहत विनियमित किया गया है। प्रसारण सेवाओं के नियामक ट्राई द्वारा जारी किए गए आदेशों और निर्देशों के अनुसार इसके नियम तैयार किए गए हैं। हालांकि केबल एक्ट केबल ऑपरेटरों के डाक अधिकारियों के साथ पंजीकरण को जरूरी बताता है, फिर भी उनकी वास्तविक संख्या को लेकर कोई भी आधिकारिक आंकड़े मौजूद नहीं हैं। केबल टीवी सेवाओं की मूल्य शृंखला में चार मुख्य आपूर्ति पक्ष संस्थाएं हैं– प्रसारणकर्ता, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ), लोकल केबल ऑपरेटर (एलसीओ), और उपभोक्ता। प्रसारण ाकर्ता प्रसारण किए जाने वाली और दर्शकों को दिखाई जाने वाली सामग्री का स्वामी होता है। आपूर्ति शृंखला में प्रसारणकर्ता की भूमिका में सामग्री की अपलिंकिंग या प्रसारण सिग्नल को सैटेलाइट तक पहुंचाना शामिल होता है। एमएसओ का रोल प्रसारणकर्ता के सिग्नल को सैटेलाइट से डाउनलिंक करना, किसी एनक्रिप्टिड चैनल को डिक्रिप्ट करना और एलसीओ को कई सारे चैनलों की एक फीड उपलब्ध कराना होता है। भारतीय बाजार में इस समय लगभग 6000 एमएसओ मौजूद हैं, इनमें से 1471 सूचना व प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत हैं। एमएसओ का कार्य सामग्री के लिए प्रसारणकर्ताओं पर निर्भर करता है और कनेक्टीविटी व सबस्क्रीप्शन आय के लिए एलसीओ पर निर्भर करता है। एमएसओ की जरूरत होती है टीवी चैनलों की डाउनलिंकिंग के लिए। आपूर्ति शृंखला में एलसीओ की भूमिका एमएसओ से फीड प्राप्त करने और इसे अपने क्षेत्र में केबल के जरिये सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में होती है। एमएसओ सीधे भी उपभोक्ताओं को सिग्नल दे सकता है। औद्योगिक आंकड़ों के अनुसार देश में 60,000 से ज्यादा स्थानीय केबल ऑपरेटर हैं।

4. डीटीएच देश में डीटीएच सेवाओं को 15 मार्च, 2001 को भारत सरकार द्वारा जारी डीटीएच सेवाओं से संबंधित नीतिगत दिशा–निर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गई थी। प्रथम डीटीएच सेवा प्रदाता ने अपनी सेवाओं का संचालन 2 अक्तूबर, 2003 को शुरू कर दिया था। उस समय से अब तक निजी डीटीएच सेवा प्रदाताओं की संख्या छह तक पहुंच गई है। इसके अलावा दूरदर्शन भी फ्री.टू.एयर धारित डीटीएच सेवा प्रदान करता है। डीटीएच सेवा प्रदाता प्रसारकों द्वारा अपलिंक किए गए सैटेलाइट टीवी चैनलों को डाउनलिंक करने के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना करता है, उन चैनलों को यथा आवश्यकता डिक्रिप्ट करता है, सिग्नलों को एकत्र करके उन्हें पुनः इनक्रिप्ट करता है और अपने अर्थ स्टेशन के माध्यम से सैटेलाइट को भेजता है और उसे अधिकृत उपभोक्ता तक पहुंचाता है। क्योंकि सैटेलाइट फुटप्रिंट्स पैन इंडिया आधार पर उपलब्ध हैं, डीटीएच सेवाएं सुदूर क्षेत्रों में समाचार और मनोरंजन चैनलों के वितरण के लिए एक अहम जरिया हैं। डीटीएच के माध्यम से कंटेंट का प्रेषण डिजीटल तरीके से होता है इसलिए डीटीएच सेवाओं में अच्छी गुणवत्ता वाली पिक्चर मिलती है। इस माध्यम से अनेक प्रकार की मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। डीटीएच सेवा सीमित उपग्रह ट्रांस्पोंडर क्षमता, वर्षा या खराब मौसम के कारण प्रभावित होती है।

5. भारत में इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवाएं सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 सितंबर, 2008 को जारी आईपीटीवी सेवा के लिए दिशा.निर्देशों के अनुसार विनियमित की जाती हैं। इन दिशा–निर्देशों में इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए केबल आप. रेटरों के साथ.साथ योग्य टेलीकॉम या इंटरनेट प्रावधान किए गए हैं। आईपीटीवी सेवाएं डिजीटल कंटेंट और संवादात्मक सेवाएं प्रदान करती हैं इसलिए आईपीटीवी सेवाओं का विकास ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी की पहुंच और विकास से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है।

Hkkjr esa lSVykbV Vholh pSuyksa dh fLFkfr

(I) uhfr

वर्ष 2000 में पहले निजी सैटेलाइट टीवी चैनल को भारत की धरती से अपलिंक करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। इससे पहले निजी टीवी चैनलों को केवल विदेश से ही अपलिंकिंग करने की अनुमति थी। भारत में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के कई गुणा विकास और देश से ही टीवी चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग करने की बढ़ती मांग को देखते हुए 2002 में अपलिंकिंग और 2005 में डाउनलिंकिंग के लिए नीति और दिशा–निर्देश तय किये गये हैं। इन दिशा–निर्देशों को दिसंबर 2011 में संशोधित किया गया। दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध हैं।

l'kksf/kr fn'kk&funs'kksa dh izeq[k fo'ks"krk,¡

(i) सभी टीवी चैनलों को अनुमति की तिथि से एक साल की अवधि के भीतर अपने चैनलों को चालू करना होगा। गैर.समाचार एवं सम.सामयिकी चैनलों को एक करोड़ रुपये की निष्पादन बैंक गारंटी पर हस्ताक्षर करने होंगे वहीं समाचार एवं सम.सामयिकी चैनलों को दो करोड़ रुपये की निष्पादन बैंक गारंटी जमा करनी होगी। यदि चैनल एक वर्ष के भीतर चालू नहीं हुए तो प्रदर्शन बैंक गारंटी को जब्त कर लिया जाएगा और अनुमति रद्द कर दी जाएगी।

(ii) चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग की अनुमति समान रूप से 10 वर्ष के लिए होगी।

(iii) विलय, विघटन और एकीकरण के प्रस्ताव को कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रक्रिया के रूप में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद अनुमति दी जाएगी।

(iv) टीवी चैनल की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग की अनुमति 10 वर्ष की अवधि के लिए होगी। टीवी चैनलों के नवीनीकरण की अवधि 10 वर्ष की होगी लेकिन साथ ही यह शर्त होगी कि उसने किसी कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का पांच बार या उससे अधिक उल्लंघन नहीं किया हो। उल्लंघन का फैसला स्व–नियमन के तहत स्थापित मानदंडों के अनुसार विचार–विमर्श के बाद तय किया जाएगा।

(v) विदेशों और वहां के दर्शकों के लिए भारत से अपलिंक तथा संचालित चैनलों को लक्षित देश के नियम और दिशा–निर्देशों का पालन करना होगा।

(II) u, mixg Vhoh pSuyksa ds fy, vuqefr çkIr djus dh çfØ;k %

मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर दिए गए अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग नीति.निर्देशों में दिए गए पात्रता मापदंड के प्रकाश में नए टीवी चैनलों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा। कंपनी तथा उसके निदेशक मंडल के मामले में सुरक्षा अनुमति प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। आवेदनों को साथ ही साथ अंतरिक्ष विभाग/राजस्व विभाग को आवश्यक स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अन्य पात्रता मानदंडों के साथ–साथ कंपनी की शुद्ध संपत्ति की भी जांच की जाएगी। अंतर–मंत्रालयी अनुमति मिलने के बाद आवेदकों से पंजीकरण और अनुमति शुल्क लेने के बाद अनुमति पत्र जारी किये जाएंगे।

d- Vhoh pSuyksa dk fodkl %

1- वर्ष 2000 में पहले निजी उपग्रह टीवी चैनल 'आज तक' को अनुमति दी गई। तब से देश में बड़ी संख्या में निजी उपग्रह टीवी चैनलों का विस्तार हो रहा है। 30 नवंबर, 2017 तक मंत्रालय 877 चैनलों को अनुमति दे चुका है। अपलिंकिंग तथा डाउनलिंकिंग निर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त टीवी चैनलों की संख्या में वृद्धि का वर्षवार ब्योरा नीचे दिया गया है :

e=ky; }kjk vuqefnr Vsyhfotu pSuyksa dh la[;k ¼2001 ls½

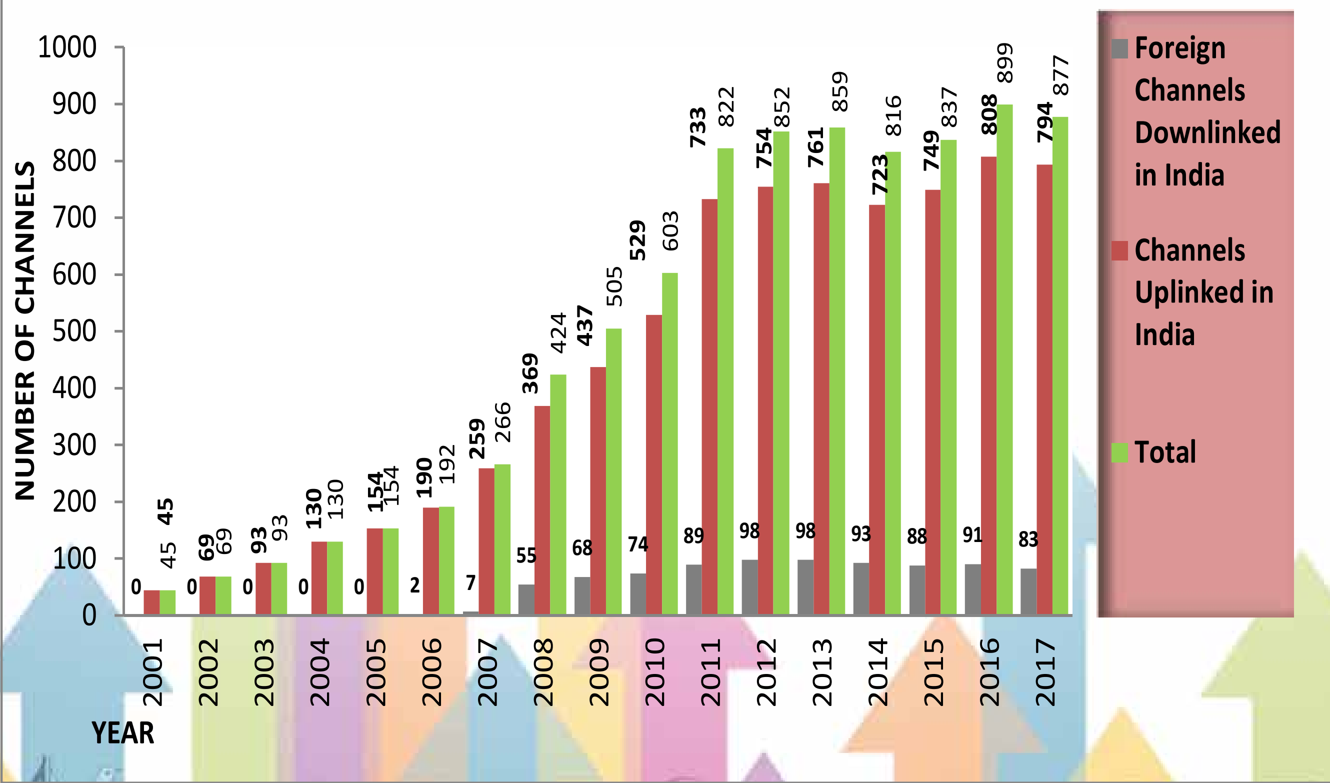

2- मंत्रालय द्वारा सिर्फ दो प्रकार के टीवी चैनलों का प्रसारण करने की अनुमति दी गई है. 'न्यूज और करंट अफेयर्स टीवी चैनल' और 'नॉन न्यूज और करंट अफेयर्स टीवी चैनल'। पूरी मंजूरी में समाचार और गैर–समाचार चैनलों के हिस्से का ब्योरा नीचे देखा जा सकता है–

J.khokj vuefr çkIr puy ¼lekpkj rFkk xj&lekpkj½

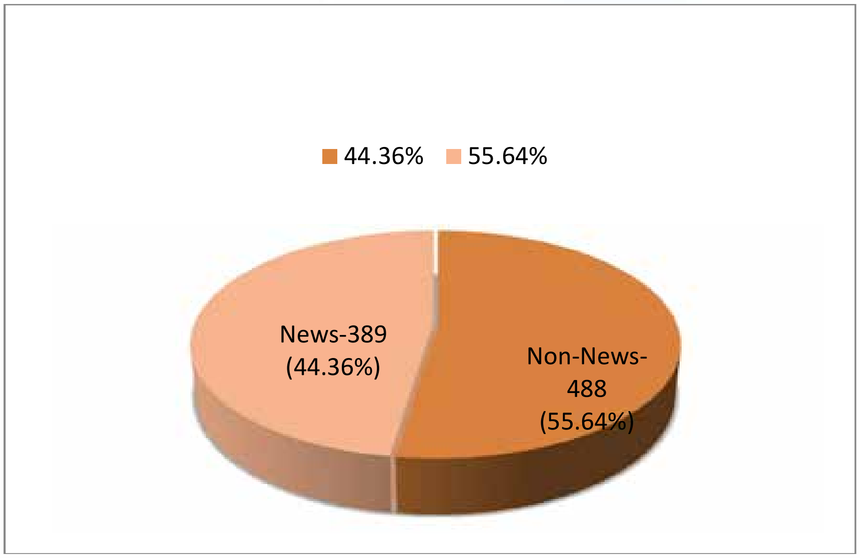

Vyhik Vl dk fodkl % 30 uocj] 2017 dh fLFkfr ¼ 68 VyhikVl½ 2001 l e=ky; }kjk etjh fn, x, VyhikVl dh l[;k

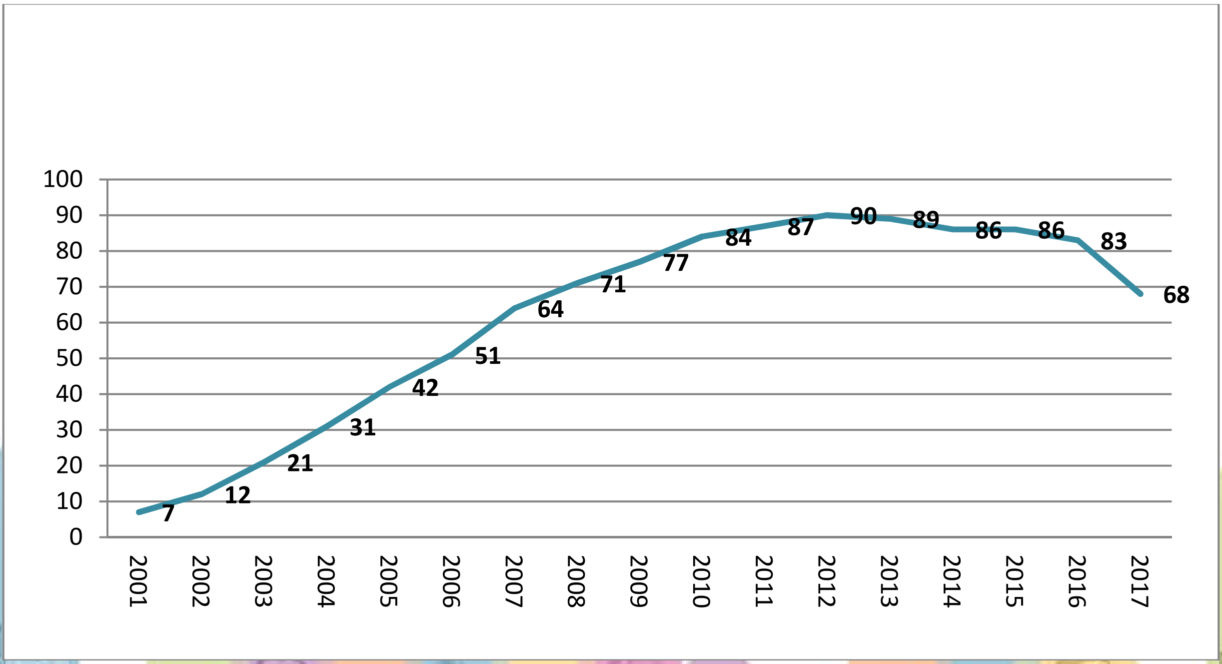

(III) ubl igy

d- 'kh"k çc/ku in %

5 दिसंबर 2011 के अपलिंकिंग दिशा निर्देशों के परिच्छेद 2.1.4 और 3.1.15 और 5 दिसंबर, 2011 के डाउनलिंकिंग दिशा निर्देशों के परिच्छेद 1.10 के अंतर्गत उच्च प्रबंधन स्तर पर नियुक्तियों के लिए समाचार या गैर समाचार और सम–सामयिक मुद्दों से जुड़े टीवी चैनलों संबंधी किसी भी मीडिया कंपनी में न्यूनतम तीन साल का अनुभव संबंधी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।

[k- okf"kd uohuhdj.k %

जिन प्रसारणकर्ताओं के पास अपलिंकिंग या डाउनलिंकिंग की वैद्य अनुमति है, उन्हें मंत्रालय से नवीनीकरण मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। वार्षिक मंजूरी राशि का भुगतान तय देय तारीख से 60 दिन पहले करने पर ही बिना किसी रुकावट के एक वर्ष चैनल को चलाने के लिए काफी होगा। सभी टीवी चैनलों और टेलीपोर्ट्स को इस फैसले से लाभ होगा, इसमें 10 साल की मंजूरी की वैधता उपलब्ध है।

(IV) ikjnf'krk vkj mRrjnkf;Ro ykuk

1- vkiu gkml cBd

हर महीने की 20 तारीख को प्रसारकों के साथ की गईं ओपन हाउस बैठकें काफी लाभदायक साबित हुईं। इन बैठकों में भाग लेने वाले प्रसारकों की संख्या पिछले एक साल में बढ़ी है। इन बैठकों से मिलने वाली प्रतिक्रिया से मंत्रालय को भुगतान का शीघ्र निपटान हेतु नई पहल से और भी पारदर्शिता लाने में मदद मिली है। इन बैठकों में प्रसारणकर्ताओं के साथ नए और अनुमति प्राप्त टीवी चैनलों, टेलीपोर्ट्स, एसएनजी/डीएसएनजी वैन, अस्थायी अपलिंकिंग मामले, सैटेलाइट का बदलाव, नाम और लोगो में बदलाव, शेयर प्राप्त करने के प्रारूप, नये निदेशकों का परिचय, एफआईपीबी मंजूरी इत्यादि जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है।

इन बैठकों के जरिये न सिर्फ आवेदकों को मंत्रालय के अधिकारियों के साथ सीधी बातचीत का अवसर मिलता है, बल्कि इससे आवेदकों को सीधे सूचना के प्रवाह में भी मदद मिलती है। इससे किसी को भी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं रही। सीधी बातचीत से प्रणाली में विश्वास का निर्माण हुआ है और अनावश्यक पत्राचार और फोन कॉल पर निर्भरता कम हो गई है।

Rofjr e t jh d fy, dne

मंत्रालय में मंजूरियों में तेजी लाने के लिए इनसेट विभाग की तरफ से दस दिन के अंतर्गत एमएचए, डॉस और सीए को प्रस्ताव एक साथ भेजे गए हैं। इस स्तर पर मंजूरियों के लिए इंतजार खत्म होने से देरी काफी रूप से कम हुई है।

¼1½ çlkj.k {k= e ç R;{k fon'kh fuo'k@,QMh-vkbl uhfr dh leh{kk

एफडीआई नीति की समीक्षा की गई और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के एफडीआई नीति 2017 और औद्योगिक नीति एवं प्रसार के अनुच्छेद 5.2.7.1 और अनुच्छेद 5.2.7.2 के अनुसार प्रसारण क्षेत्र के लिए और वह इस तरह है–

विभाग/गतिविधि	विदेशी निवेश की सीमा	प्रवेश मार्ग
5.2.7.1.1 (1) टेलीपोर्ट्स (अपलिंकिंग हब/टेलीपोर्ट्स की स्थापना) (2) डायरेक्ट टू होम (डीटीएच); (3) केबल नेटवर्क (मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) राष्ट्रीय या राज्य या जिला स्तर पर और डिजिटलीकरण और पता योग्यता की दिशा में नेटवर्क के उन्नयन के उपक्रम में सक्रिय हैं) (4) मोबाइल टीवी (5) हेडेंड इन द स्काई ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (एचआईटीएस)	100 प्रतिशत	स्वतः
5.2.7.1.2 केबल नेटवर्क (अन्य एमएसओ, जो डिजिटलीकरण के लिए नेटवर्क के उन्नयन का उपक्रम नहीं ले रहे और स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ)	100 प्रतिशत	स्वतः
5.2.7.2.1 स्थलीय प्रसारण एफएम (एफएम रेडियो) एफएम रेडियो स्टेशन की स्थापना हेतु मंजूरी देने के लिए सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले नियम व शर्तें।	49 प्रतिशत	सरकारी
5.2.7.2.2 'समाचार एवं करंट अफेयर्स' टीवी चैनलों की अपलिंकिंग	49 प्रतिशत	सरकारी

2- ekud Q,el vkj vkonu i=

कंपनी से सूचना एकत्र करने तथा कंपनी के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है। तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने की अवधि को घटा दिया गया है तथा इस प्रक्रिया की गति तेज हो गई है।

3- lSVykbV Vhoh ,Iyhds'ku Vfdx flLVe ¼,lVh,Vh,l½

कंपनियों के लंबित मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए सैटेलाइट टीवी एप्लीकेशन ट्रेकिंग सिस्टम (एसटीएटीएस) सॉफ्टवेयर 21 जनवरी, 2010 से चालू कर दिया गया है। इस खास सॉफ्टवेयर को एनआईसी ने विकसित किया है। इस सॉफ्टवेयर से आवेदक को निजी उपग्रह टीवी चैनल के आवेदन पत्र की स्थिति का पता लग जाता है। इस सॉफ्टवेयर पर नियमित रूप से डाटा अपलोड किए जाते हैं ताकि आवेदक को अपने आवेदन की ताजा स्थिति की जानकारी मिलती रहे।

(V) Vhoh] bulV foHkkx ds fy, lexz v,uykbu iksVy dk fodkl

वर्ष 2011 के निर्देश के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को देश में टीवी चैनलों को अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की अनुमति देने का अधिकार है। मंत्रालय ने आवेदकों के लिए जरूरी अनुमति लेने के लिए एकल खिड़की सुविधा उपलब्ध करायी है। इस प्रक्रिया में कागजी कार्रवाई ज्यादा होती है, कागज भी ज्यादा लगता है और मंत्रालय के ज्यादा कर्मचारी भी जुटे रहते हैं। इस कारण अक्सर जरूरी लाइसेंस जारी करने में विलंब हो जाता है और जमा किए गए कागजात खोने की आशंका रहती है। चैनलों के सामग्री की निरंतर और योजनाबद्ध निगरानी में दिक्कतें आती हैं। संबंधित एजेंसियों, विभागीय कर्मचारियों और वेंडरों के लिए आवेदन की ऑनलाइन स्थिति जानने के लिए प्रसारण सेवा नामक एक सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल विकसित की जाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद सभी हितधारकों के आवेदन करने, निगरानी प्रबंधन और जरूरी प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाएगा। इसमें मानवीय हस्तक्षेप कम से कम होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत एक समग्र ऑनलाइन समाधान ढूंढने की कोशिश है, जिसके माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमति देने/पंजीकरण/लाइसेंस देने का कार्य हो सके। इसे पूरा करने का कार्य बेसिल को सौंपा गया है और इसका निर्माण अंतिम स्तर पर है।

दो गतिविधियां यानी (i) वार्षिक अनुमति शुल्क का भुगतान तथा (ii) कार्यक्रमों के अस्थाई अपलिंकिंग अनुम. ति हेतु आवेदन का कार्य प्रसारण सेवा पोर्टल के माध्यम से की जाएंगी। पूरी तरह कार्यान्वित होने पर इन प्रस्तावों के निपटान में तेजी आएगी तथा व्यवस्था में तत्परता एवं पारदर्शिता लाने में सहायक होगा।

Vhoh pSuyksa dh lkexzh dk fu;eu

1. टेलीविजन पर प्रसारित सामग्री का विनियमन काफी चर्चा का विषय रहा है। उपग्रह चैनलों की सामग्री का भारतीय नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों पर नकारात्मक प्रभाव रहा है खासकर महिलाओं और बच्चों, जो कि सबसे ज्यादा जोखिम में हैं, को लेकर हो रही चिंता का समाधान संविधान में प्रदत्त बोलने और रचनात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए टीवी चैनलों की सामग्री को अनुकूल बनाना है। मंत्रालय ने पहले ही 877 निजी उपग्रह टीवी चैनलों को अनुमति दे दी है जिनमें से 488 गैर समाचार तथा सम–सामयिक चैनल तथा 389 समाचार एवं सम–सामयिकी चैनल हैं। डीटीएच सेवाओं में तेजी से विकास होने के बावजूद आज भी चैनलों का वितरण केबल आपरेटरों द्वारा किया जा रहा है जो एनालॉग तकनीक का प्रयोग करते हैं और जिनकी वहन क्षमता सीमित है। डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि केबल टीवी नेटवर्क की क्षमता बढ़ेगी।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 तथा इसके अंतर्गत नियमों के तहत प्रत्येक प्रसारणकर्ता को कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का अनिवार्य पालन करने का निर्देश दिया गया है। विभिन्न प्रसारण माध्यमों से दिखाये जाने वाली सभी वीडियो की सामग्री पर केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995 के अधीन कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता लागू होती है। यह संहिता सभी वीडियो विषयवस्तु विभिन्न प्रसारण माध्यम में लागू होता है।

3. मंत्रालय मुख्यतः अश्लीलता, महिलाओं की छवि को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करना, बच्चों पर बुरे प्रभाव, गुमराह करने के लिए बनाए गए विज्ञापन, गलत खबर और मानहानि वाली खबरें दिखाना जैसे विषयों पर कार्रवाई करता है। इन सभी मामलों में मंत्रालय द्वारा

भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार (2014–15) समारोह के अवसर पर

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है और जहां आवश्यक हो वहां परामर्श, चेतावनी या क्षमा–प्रार्थना प्रसारित करने के आदेश जारी किए जाते हैं।

4. वर्ष 2016–17 (21 दिसंबर, 2017 तक) के दौरान मंत्रालय ने विभिन्न चैनलों को विभिन्न परामर्श, चेतावनी, आदेश जारी किये। इसकी जानकारी नीचे दी जा रही है :

i) 5 सामान्य परामर्श– गणतंत्र दिवस परेड तथा स्वतंत्रता दिवस समारोह का प्रसारण संकेत भाषा कमेंटरी के साथ करने हेतु टीवी चैनलों को सलाह देते हुए, प्रसारण संहिता के नियम 7(10) का पालन करने विज्ञापनों के प्रसारण के वक्त ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 के प्रावधानों का पालन करने तथा कंडोम के विज्ञापनों के प्रसारण रात 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक करने के सलाह पत्र। कंडोम संबंधी विज्ञापनों पर, मंत्रालय ने दिनांक 20 दिसंबर, 2017 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को कार्यालय ज्ञापन जारी करते हुए यह स्पष्ट किया कि महिलाओं को यौन संबंधी विषय तथा अथवा यौन मुखरित सामग्री के रूप में चित्रित न करते हुए तथा कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का उल्लंघन न करते हुए सुरक्षित यौन संबंध आधारित विज्ञापनों को बढ़ावा देने संबंधी सलाह दी जाए।

ii) 10 विशेष परामर्श–टीवी चैनलों को कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए गए।

iii) 04 चेतावनी– कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का सख्ती से पालन करने के लिए चैनलों को निर्देश जारी किया गया।

iv) 05 आदेश– विभिन्न चैनलों को कुछ दिन प्रसारण रोकने के लिए निर्देश जारी किए गए।

vrj&e=kky;h lfefr ¼vkbl,e lh½

5. उपग्रह चैनलों की सामग्री की निगरानी के लिए एक अंतर–मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव इसके अध्यक्ष होते हैं, समिति में गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विदेश कार्य, रक्षा, उपभोक्ता मामले मंत्रालयों के प्रतिनिधि एवं एएससी आई उद्योग के एक प्रतिनिधि भी शामिल हैं। समिति तय करती है कि चैनलों ने किसी नियम का उल्लंघन किया है या नहीं। यह समिति सुझाव देती है। समिति के सुझाव के आधार पर दंड और दंड की सीमा मंत्रालय तय करता है।

byDV',fud ehfM;k e,fuVfjax lsVj ¼b,e,elh½

6. सरकार ने अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इलेक्ट्रानिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) अधिनियम, 1995 तथा इसके तहत गठित नियमों के अंतर्गत उपग्रह टीवी चैनलों के कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता के उल्लंघन करने वाली सामग्री को रिकॉर्ड करने एवं उस पर निगरानी रखने के लिए की है।

jkT; ,oa ftyk Lrj ij tkap lfefr;k

7. राज्य एवं जिला स्तर पर केबल कानून और नियमों को लागू करने के लिए मंत्रालय ने 6 सितंबर, 2005 को राज्य, जिला/स्थानीय स्तर पर केबल टेलीविजन चैनलों पर कार्यक्रम और विज्ञापनों के प्रसारण पर निगरानी के लिए 'निगरानी समिति' की व्यवस्था लागू की है। जिला और राज्य स्तर पर निगरानी समिति के लिए मंत्रालय ने 19 फरवरी, 2008 को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए। तथापि, बाद में, सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों, राज्य सूचना सचिवों तथा सभी जिला मजिस्ट्रेटों को दिनांक 26 अप्रैल, 2017 के का.ज्ञा. के जरिए राज्य जिला स्तरीय जांच समिति के गठन से संबंधित पूर्व में जारी सभी आदेशों को सम्मिलित करते हुए तैयार किए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए। इस संबंध में विस्तृत अनुदेश मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in में उपलब्ध है।

lekpkj pSuyksa ds ekeys esa vkRe&fu;eu

8. समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीए) ने अपने स्वनियमन तंत्र के भाग के रूप में स्वयं को विनियमित समाचार प्रसारण के लिए सिद्धांतों की एक विस्तृत रेंज को कवर करने के लिए एक नैतिकता और प्रसारण मानक संहिता तैयार की है। एसोसिएशन ने सामग्री से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए एक दो स्तरीय संरचना का गठन किया है। स्तर–1 में आने वाली शिकायतों को अपने स्तर पर अलग.अलग प्रसारकों द्वारा निपटाया जाता है, जबकि स्तर–2 से आने वाली शिकायतों का निपटारा एनबीए द्वारा 2008 में स्थापित समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

9. समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण का उद्देश्य मनोरंजन या समाचार से संबंधित किसी भी तरह की सामग्री के खिलाफ शिकायतों पर निर्णय करना है। प्राधिकरण में अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं और आठ अन्य सदस्य विशेषज्ञ क्षेत्र से होते हैं। इनमें चार प्रतिष्ठित संपादक जो ब्रॉडकास्टिंग प्रसारकों के साथ कार्यरत हैं, को लिया जाता है और चार कानून, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, साहित्य, लोक प्रशासन, उपभोक्ता मामले, पर्यावरण, मानव मनोविज्ञान और संस्कृति क्षेत्र में विशेषज्ञता वालों को शामिल किया जाता है। एनबीएसए के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवा. निवृत्त न्यायाधीश आर.वी. रवींद्रन हैं। विस्तृत जानकारी एनबीए की वेबसाइट http//:www.nbanewdelhi.com पर उपलब्ध है।

xSj&lekpkj ¼lkekU; euksjatu½ pSuyksa esa Lo&fu;eu

10. भारतीय ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ) ने गैर.समाचार चैनलों के मामले में स्व.नियमन के लिए एक तंत्र की स्थापना की है। इस ने टेलीविजन पर सामग्री प्रसारण के लिए सिद्धांत और मापदंड, सामग्री संहिता और प्रमाणन नियम 2011 तय किये हैं। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में शिकायतों के निवारण की द्विस्तरीय प्रणाली बनाई गई है। इसके पहले हिस्से में प्रत्येक प्रसारक को अपने चैनल पर प्रसारित विषय–वस्तु से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए विषय.वस्तु परीक्षक सहित मानक और कार्यप्रणाली विभाग स्थापित करना होता है।

11. प्रक्रिया के दूसरे एवं शीर्ष स्तर के रूप में जुला. ई 2011 में ब्रॉडकास्ट कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल (बीसीसीसी) की स्थापना एवं संचालन की व्यवस्था की गई। बीसीसीसी में उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विभिन्न विषयों के 13 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों में से चार गणमान्य सदस्य होते हैं। परिषद में राष्ट्रीय आयोगों का प्रतिनिधित्व भी किया जाता है, जिसमें चार प्रसारक सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त परिषद में दो विशेष आमंत्रित मेहमान होते हैं, जो भाषा शिकायतों का निपटारा करते हैं। बीसीसीसी के वर्तमान अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायधीश विक्रमजीत सेन हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आईबीएफ की वेबसाइट www.ibfindia.com देखें।

Vhoh pSuyksa ij foKkiu dk Lo&fofu;eu

12. टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों के नियमन के संबंध में स्व–नियमन निकाय एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) के कोड

को ग्रहण किया गया। इससे संबंधित नियम केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) एक्ट 1995 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम में सम्मिलित किए गए हैं। एएससीआई ने विज्ञापनों से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए उपभोक्ता शिकायत परिषद (सीसीसी) की स्थापना की है। सीसीसी के वर्तमान में 28 सदस्य हैं। इनमें 12 उद्योग के अंदर से हैं और 16 सिविल सोसाइटी से हैं जैसे प्रसिद्ध डॉक्टरों, वकीलों, पत्रकारों, शिक्षाविदों, उपभोक्ता कार्यकर्ताएं इत्यादि । विस्तृत जानकारी www.ascionline.org पर उपलब्ध है।

d,eu d,t vnkyrh fu.k;

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपी(सी) सं.387 ऑफ 2000–कॉमन कॉज बनाम भारत संघ एवं अन्य से संबंध में दिनांक 12.01.2017 को पारित अपने ऑर्डर में उपरोक्त मौजूदा व्यवस्था को स्वीकृति दी है।

MkbjsDV Vw gkse ¼MhVh,p½ lsok

DTH Transmission

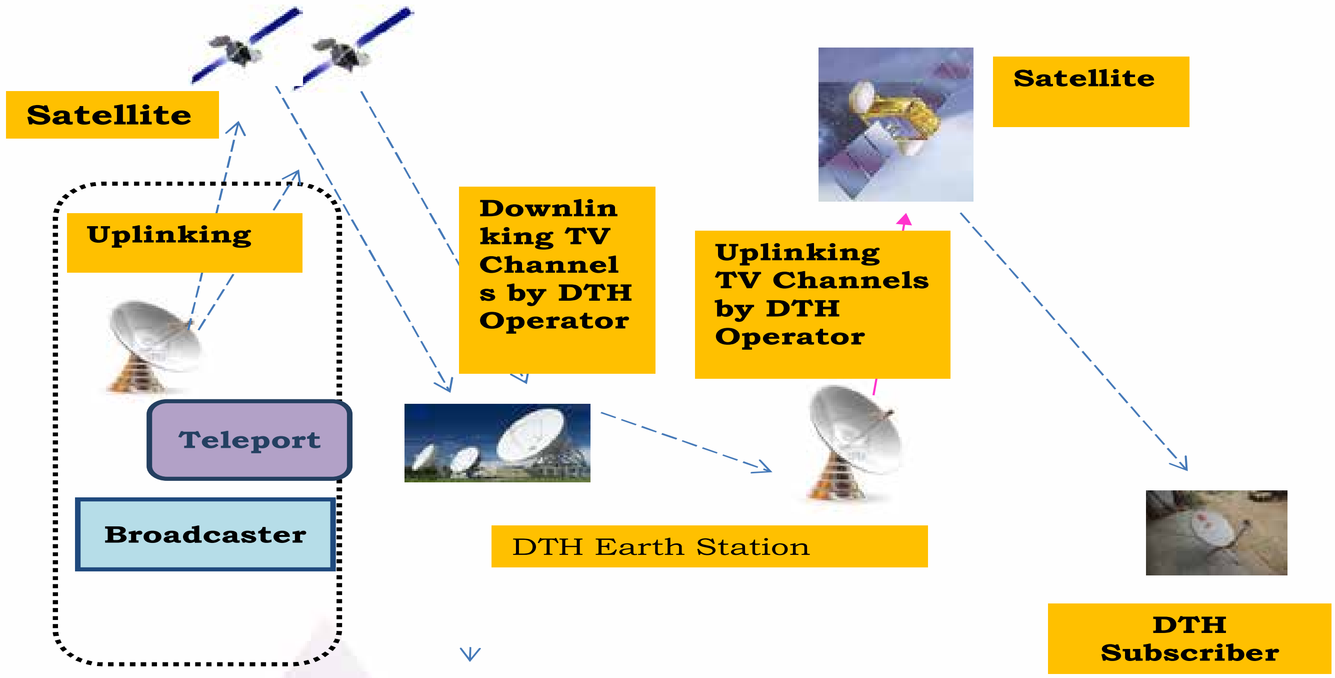

डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा

डीटीएच सेवाओं का विकास केबल प्रसारण के अपेक्षाकृत हाल ही में हुआ है। केबल तकनीक के मुकाबले डीटीएच सेवा तकनीकी रूप से अधिक लाभकारी है। डीटीएच समाधान योग्य व्यवस्था है जिसे अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जा रहा है। डीटीएच सेवा में उच्च क्षमता वाले उपग्रह के माध्यम से कहीं अधिक बड़ी संख्या में चैनलों को प्रसारित किया जा सकता है। डीटीएच के माध्यम से प्रसारित कार्यक्रम सीधे घरों में जा सकता है सुविधाजनक स्थान पर छोटे डिश एंटिना स्थापित करके सीधे प्रसारण प्राप्त किए जा सकते हैं। डीटीएच प्रसारण सेवाओं के लिए किसी व्यावसायिक मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। डीटीएच संचालक द्वारा प्रदत्त सेवाएं उपभोक्ता को सीधे प्राप्त हो सकती हैं। डीटीएच सेवाएं उपभोक्ताओं के स्थान पर सीधे टीवी सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए सेटेलाइट प्रणाली के उपयोग द्वारा क्यू बैंड में मल्टी चैनल कार्यक्रमों के वितरण के लिए दी जाती है। डीटीएच उपभोक्ता को भौगोलिक आवाजाही के अर्थों में इस प्रकार लाभ देता है कि ग्राहक एक बार डीटीएच हार्डवेयर खरीद कर उस एक इकाई का इस्तेमाल भारत में कहीं भी जारी रख सकता है।

सरकार ने 15 मार्च, 2001 को भारत में डीटीएच सेवाओं के परिचालन के लिए आवेदन पत्र और

लाइसेंसिंग समझौते के साथ विस्तृत दिशा–निर्देश भी जारी किए थे, जिन्हें 06 नवंबर 2007 को संशोधित किया गया है। दिशा–निर्देशों में योग्यता की शर्तें, अन्य वस्तु पूर्ण विदेशी इक्विटी स्वामित्व उपलब्ध कराना, जिसमें एफडीआई/एनआरआई/ओसीबी/एफआईआई शामिल है, आवेदक कंपनी 49 प्रतिशत से अधिक नहीं हो और विदेशी इक्विटी एफडीआई घटक 20 प्रतिशत से अधिक न हो। प्रसारण क्षेत्र के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रेस नोट संख्या 5 के तहत 24 जून, 2016 को (2016 श्रृंखला) डीटीएच सेक्टर में 100 प्रतिशत तक में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने को मंजूरी दी। कंपनी बोर्ड में प्रतिनिधित्व और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का निवासी भारतीय होने के रूप में यह आवेदक कंपनी पर भारतीय प्रबंधन नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

bVjuV çkWVksd,y Vsyhfotu ¼vkbZihVhoh½ lsok

आईपीटीवी सेवा संबंधी नीति सरकार ने 8 सितंबर, 2008 को आईपीटीवी के बारे में नीति निर्धारित की है और इस प्रकार दूरसंचार तथा केवल नेटवर्क के माध्यम से फिलहाल उपलब्ध अनुमति प्राप्त उपग्रह टीवी चैनलों के वितरण के लिए एक और मोड उपलब्ध कराया गया है। इससे भारतीय दर्शकों को डिजिटल तस्वीरों का एक नया अनुभव प्राप्त होगा, साथ ही ग्राहकों की विभिन्न मूल्य संवर्धित परस्पर जुड़ी नई सेवाओं की निरंतर बढ़ती मांग भी पूरी होगी। इससे प्रसारकों तथा प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाताओं को भी कारोबार के अलग–अलग मॉडल तैयार करने के नित नए अवसर मिलेंगे। आईपीटीवी संबंधी नीति में इन मुद्दों को और ज्यादा स्पष्ट किया गया है तथा दूरसंचार ऑपरेटर एवं केबल ऑपरेटर दोनों आईपीटीवी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे और इन्हें उनके लाइसेंसिंग शर्तों के अनुसार नियंत्रित किया जा सकेगा। केबल अधिनियम के तहत निर्धारित कार्यक्रम तथा विज्ञापन संहिता के अनुसार विषय–वस्तु को विनियमित किया जाएगा। यह अधिनियम अश्लील विषय–वस्तु पर प्रतिबंध लगाने के अलावा कई अन्य आशंकाओं को भी दूर करता है। इसमें विषय–वस्तु संबंधी संहिता के उल्लंघन का दायित्व तय किया गया है और यह भी बताया गया है कि उनसे किस प्रकार निपटा जाएगा। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को भी रखा गया है। इस नीति में व्यवस्था की गई है कि एमएसओ तथा केबल ऑपरेटर और प्रसारक प्रसारण की विषय–वस्तु, आईपीटीवी सेवाओं का लाइसेंस प्रदान करने वाले दूरसंचार प्राधिकरण को भी उपलब्ध कराएं। इसमें समाचार तथा सामयिक विषयों पर सामग्री तैयार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं को अपनी विषय–वस्तु तैयार करने की छूट दी गई है।

परिभाषित टेलीकॉम और केबल ऑपरेटरों के लिए आईपीटीवी सेवाएं प्रदान करने के लिए नीति को एक अलग अनुमति की आवश्यकता नहीं है। डाउनलिंकिंग दिशा–निर्देशों के उपबंध 5.6 में परिवर्तन करके प्रसारकों को अपने कार्यक्रम आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं को देना संभव बनाया गया है। इस नीति में, प्रसारकों से तत्संबंधी अधिकार प्राप्त केबल ऑपरेटरों और मल्टी–सिस्टम ऑपरेटरों को दूरसंचार आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं को समाहारित विषय–वस्तु उपलब्ध कराने की सुविधा भी दी गई है।

आईपीटीवी सेवाओं में एनिमेशन और गेमिंग उद्योग में बड़ी संभावनाएं देख रहा है। हालांकि इसमें ब्रॉडबैंड की पहुंच और उसकी कनेक्टिविटी गुणवत्ता इसकी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कारक होंगे।

वैश्विक स्तर पर आईपीटीवी केबल और डीटीएच सेवाओं के लिए एक प्रमुख पे–टीवी प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। उम्मीद है कि इससे कार्यक्रम और सेवा प्रदाताओं को अतिरिक्त आमदनी होगी और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए लागत में भी कमी आएगी। उम्मीद है कि आईपीटीवी विनियामक फ्रेमवर्क में स्पष्टता और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में वृद्धि से भारत आईपीटीवी बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले देश के रूप में उभरेगा।

fgV~l ¼gsM-,.M bu n LdkbZ½ lsok

प्रसारण के क्षेत्र में एक नई तकनीक का उदय हुआ है जिसे स्काई यानी हेड.एंड इन द स्काई (हिट्स) कहा जाता है, क्योंकि इसकी मदद से भारत में डिजिटलीकरण और समयबद्ध पहुंच स्थापित करने के फैलाव में तेज़ी आ सकती है। सरकार ने, केबल ऑपरेटरों को हिट्स के तौर पर सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ट्राई के साथ परामर्श कर नीतिगत रूपरेखा तैयार की है।

26 सितंबर, 2009 को सरकार ने देश में हिट्स सेवा प्रदाताओं के लिए नीतिगत दिशा.निर्देश जारी किए। उपभोक्ता और केबल ऑपरेटर किसी भी मौजूदा तंत्र का उपयोग कर सकते हैं या अगर केबल ऑपरेटर चाहें तो वह हिट्स प्रदाता नेटवर्क को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसका मतलब, यह आवश्यक.सीएएस (कंडीशनल एक्सेस

fgV l ¼gM&,M bu n Ldkb½ lsok

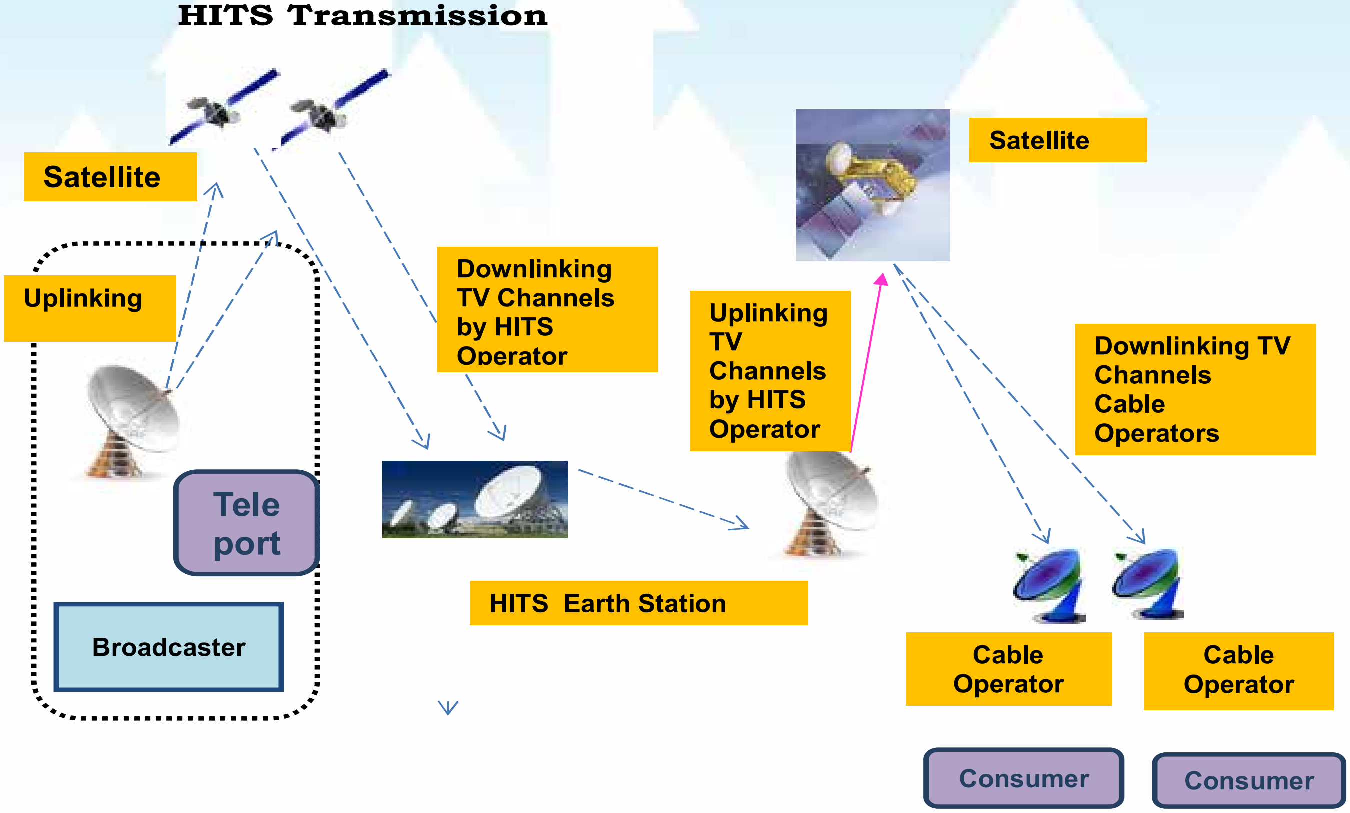

सिस्टम) के लिए अधिसूचित क्षेत्रों से अलग है।

हिट्स पूरे देश में सेटेलाइट के जरिये कई एमएसओ/केबल ऑपरेटरों को सिगनल प्रदान करता है, जो आगे अपने केबल नेटवर्क का प्रयोग कर उपभोक्ताओं को सिगनल देते हैं। हिट्स ऑपरेटर और बहु–तंत्र ऑपरेटर (एमएसओ) में यह अंतर है कि एमएसओ सेटेलाइट के जरिये चैनलों का पुलिंदा केबल ऑपरेटरों तक पहुंचाता है, जबकि हिट्स यही कार्य केबल के जरिये करता है। हिट्स टीवी चैनल के वितरण का एक डिजिटल तरीका है और इससे देश के गैर सीएएस क्षेत्रों में मौजूद केबल सेवाओं के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी। हिट्स से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में केबल का बाजार बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि सेटटॉप बॉक्स की कीमतों में कमी भी आएगी जहां अव्यवहारिकता के कारण यह कार्य संभव नहीं था।

इससे केबल बाजार और सुदृढ़ होगा। हिट्स के माध्यम से उपभोक्ता कई डिजिटल चैनलों की साफ तस्वीर और मुनासिब दामों पर बेहतर सेवाओं का लुत्फ़ उठा सकता है। मौजूदा प्राइम, नॉन–प्राइम बैंड में रखे गए चैनलों की सीमित क्षमता के स्थान पर हिट्स अधिक चैनल क्षमता प्रदान करेगा। हिट्स की नीति सही दिशा में एक कदम है और इससे ऑपरेटर के स्तर पर जरूरी निवेश को कम किया जा सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों के दूर–दराज़ के इलाकों में केबल सेवाएं पहुंच सकती हैं, जिसे कुछ मूल्य सूची और अंतर–संपर्क मुद्दों के समाधान के बिना यह शुरू नहीं किया जा सका था। उम्मीद है कि ट्राई अब डिजिटल तंत्रों के लिए मूल्य सूची ला रहा है और उद्योग जगत भी अब हिट्स सेवाओं के प्रावधानों के लिए मंच तैयार करने के लिए आगे आएगा। ट्रांसपोंडर क्षमताओं की उपलब्धता के बारे में कुछ बाधाएं हैं, लेकिन उम्मीद है कि मांग बढ़ने से आपूर्ति भी होगी। डीएएस के आने से हिट्स सेवाओं को बहाल करने में भी तेज़ी आएगी। एक उत्प्रेरक के रूप में डीएएस की शुरुआत भी हिट्स सेवाओं के एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में सेवाएं प्रदान करेगी।

केबल टीवी डिजिटलीकरण की वस्तुस्थिति

1- n'k e dcy Vhoh ç.kkyh

देश में केबल टीवी प्रणाली ने प्रसारण वितरण उद्योग की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य किया है। पिछले 20 वर्षों के दौरान केबल उद्योग ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र के विकास में एक प्रमुख भूमिका अदा की है। डीटीएच

सेवाओं के तेजी से होते विकास के बावजूद, केबल सेवाएं आज भी टीवी चैनलों के वितरण में सबसे आगे हैं।

2- çlkj.k m|kx dh :ij[kk

केबल टीवी सेवा मूल्यांकन श्रृंखला में चार मुख्य आपूर्तिकर्ता शामिल होते हैं, जो इस प्रकार हैं :

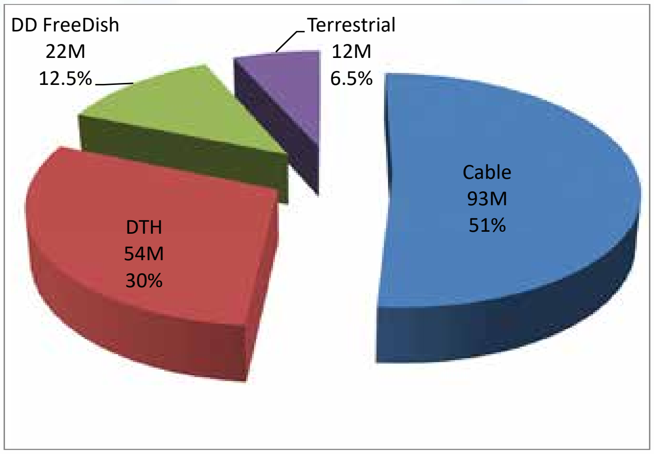

प्रसारक, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ), स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ) और अंतिम उपभोक्ता। प्रसारक टीवी पर प्रसारित होने वाली सामग्री का निर्माण करता है जिसे दर्शक देखते हैं। प्रसारक उपग्रह के लिए सामग्री के संकेत प्रेषण या अपलिंक करता है। एमएसओ उपग्रह से प्रसारकों के सिग्नल को डाउनलिंक करता है, किसी भी एन्क्रिप्टेड चैनल को डिक्रिप्ट करता है और कई चैनलों से मिलकर फीड का समूह प्रदान करता है। ट्राई के अनुसार, भारत में लगभग 6000 एमएसओ काम कर रहे हैं। एमएसओ का व्यापार, सामग्री (कंटेट) और एलसीओ पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी तथा सदस्यता राजस्व संग्रह के लिए प्रसारणकर्ता पर निर्भर रहता है। एमएसओ को टीवी सिग्नल को प्राप्त करने के लिए हेड. एंड्स की आवश्यकता है। एलसीओ एमएसओ से कई सिग्नल प्राप्त करता है और केबल के माध्यम से इसे अपने ग्राहकों तक पहुंचाता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 60,000 केबल ऑपरेटर हैं।

3- Vhyhfotu forj.k IyVQkek dk Lo:i

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टीवी बाजार है जिससे पहले केवल चीन का नंबर आता है। फिक्की केपीएमजी की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में निम्न प्लेटफॉर्म वितरण के हिसाब से 181 मिलियन घरों में टीवी हैं।

4- ,uky,x dcy Vhoh dh dfe;k %

एनालॉग केबल टेलीविजन में निम्नलिखित कमियां हैं :

- स्वीकृत सेटेलाइट टीवी चैनलों की संख्या जहां 700 के पार चली गई है, एनालॉग प्रणाली के पास केवल 70.80 चैनलों की क्षमता है। यह गंभीर रूप से ग्राहक के लिए उसकी पसंद पर पाबंदी लगाता है और प्रसारण क्षेत्र में बड़ी संख्या में उपलब्ध टीवी चैनल को ग्राहक तक पहुंचाने से इनकार करता है।
- सीमित संख्या में चैनल वहन करने की क्षमता से एनालॉग प्रणाली टीवी प्रसारकों के व्यापार में विकृति पैदा करती है, जैसे प्रसारणकर्ता को भारी फीस का भुगतान करके अपने चैनलों का वहन करने के लिए एमएसओ को प्रोत्साहित करने पर मजबूर होना पड़ता है।
- एनालॉग केबल के पास में ए–ला–कार्टे (व्यक्तिगत) चैनलों के चयन की सुविधा वाली तकनीकी सुविधा नहीं है। इस वजह से ग्राहक को मजबूरी में स्वयं के समझौते से बाहर जाकर एक केबल ऑपरेटर द्वारा तैयार चैनलों का चयन करना पड़ता है। इस प्रकार, एनालॉग प्रणाली ग्राहकों के अनुकूल नहीं है।
- एनालॉग सेवाओं की एक अन्य तकनीकी सीमा पारदर्शिता की कमी है जिसमें ग्राहक आधार सही नहीं बताया जाता है। यानी उनकी संख्या। इससे राजस्व की रिपोर्टिंग कम और कर राजस्व को छिपाया जाता है।
- सीमित वहनीय क्षमता और पारदर्शिता की कमी प्रसारकों के लिए व्यापार मॉडल को विकृत करती है और इससे उनकी निर्भरता केवल विज्ञापन राजस्व पर बढ़ जाती है और इससे सदस्यता का राजस्व सीमित रह जाता है (65:35)। तदनुसार, उच्च टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) के लिए चैनल अक्सर टीवी पर सनसनीखेज़ सामग्री का प्रयोग करते हैं।
- एनालॉग केबल में पिक्चर (तस्वीर) की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि एक चैनल प्राइम बैंड या ग़ैर–प्राइम बैंड में कितना देखा जा रहा है।
- केबल ऑपरेटरों को डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) और आईपीटीवी सेवाओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जो एक स्थिति में हैं कि वे ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता की सामग्री और मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और जब तक वे (केबल ऑपरेटर) अपनी सेवाओं को उन्नत नहीं कर लेते वे नए प्लेटफॉर्म के व्यापार से बाहर हो जाएंगे।

5- Vªkbl dh flQkfj'k

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 'भारत में डिजिटल एड्रेसेबल केबल प्रणाली (डीएएस)' को लागू करने संबंधी सिफारिशों में दिनांक 5 अगस्त 2010 को यह सिफारिश की थी कि केबल टीवी सेवाओं और केबल टीवी क्षेत्र में एक समयबद्धता के साथ एनालॉग प्रणाली को चार चरणों में डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली (डीएएस) के साथ डिजिटलीकरण को प्राथमिकता से कार्यान्वित किए जाए।

6- fMftVhdj.k ds ykHk

एड्रेसबिलिटी का अर्थ है केबल ऑपरेटर के सिग्नल एन्क्रिप्टेड (कूट रूप में) होंगे, सेवा प्रदायक से विधिवत कनेक्शन लेने के उपरांत सिग्नल केवल सेट टॉप बॉक्स के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार यह प्रत्येक ग्राहक की पहचान और डेटा बेस के रखरखाव, पारदर्शिता लाने और चोरी को रोकने के लिए सक्षम है। डीएएस के कार्यान्वयन से सभी हितधारकों को लाभ होगा। डिजिटलीकरण के अन्य महत्वपूर्ण लाभ निम्नानुसार हैं :

i. miHkksDrk

- उपभोक्ता को यह अधिकार मिलता है कि वह अपनी रुचि और अपनी आवश्यकताओं तथा बजट के अनुसार कहीं ज्यादा चैनलों के विकल्प में से अपनी इच्छा के कार्यक्रमों का चयन करें।
- उपभोक्ताओं को अधिकतम चैनल की पेशकश की जाती है जो मौजूदा 70–80 के बजाय सैकड़ों तक में होते हैं। यह उपभोक्ताओं को एक बेहतर तकनीक देखने का अनुभव देने के लिए उच्च गुणवत्ता/हाई डेफिनेशन डिजिटल टेलीविजन चैनलों की एक बड़ी संख्या को देखने के लिए सक्षम बनाएगा।
- डीटीएच और आईपीटीवी ग्राहकों की तरह, केबल टीवी ग्राहक भी सामग्री की गुणवत्ता में सुधार कर सकेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम गाइड, मूवी–ऑन डिमांड, वीडियो–ऑन–डिमांड, व्यक्तिगत वीडियो, गेमिंग आदि जैसे विभिन्न इंटरएक्टिव सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे।

ii. dscy vkWijsVlZ

- डिजीटलीकरण केबल ऑपरेटर ट्रिपल प्ले (तीन सेवाएं एक साथ) की सुविधा मुहैया कराता है जिसमें ध्वनि, वीडियो और डाटा मौजूद रहते हैं। केबल ऑपरेटर को इससे प्रति प्रयोक्ता औसत राजस्व मिलता है। प्रसारण और दूरसंचार सेवाओं के अभिसरण में सक्षम बनाता है। केबल टीवी सेवाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन में वृद्धि होगी।

iii. çlkj.kdrkZ

- बढ़ी हुई क्षमता प्रसारणकर्ताओं को आला चैनल और एचडीटीवी (हाई डेफिनिशन टेलीविजन) चैनलों की पेशकश करने के लिए सक्षम बनाएगी। बढ़ा हुआ सदस्यता राजस्व प्रसारकों को टीआरपी केंद्रित सामग्री से दूर रखने में मदद करेगा और प्रसारणकर्ता अंकेक्षण योग्य उपभोक्ता आधार पर अपना कारोबार चला पाने में समर्थ होंगे।

iv. ljdkj

- सरकार के कर संग्रह से वास्तविक बाजार का आकार मेल खाएगा।
- ग्राहक आधार में पारदर्शिता से घाटे में ज़बरदस्त कमी आई है जिस कारण सरकार के राजस्व चोरी में भी कमी आई है।
- उपभोक्ताओं की संख्या में पारदर्शिता के फलस्वरूप केंद्र तथा राज्य के करों की अपवंचना की घटनाओं में भारी कमी आएगी, जो मुख्यतः सेवा एवं मनोरंजन कर के रूप में रहती हैं और इस प्रकार सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
- डिजिटल केबल टीवी नेटवर्क ब्रॉडबैंड की पहुंच के लिए महत्वपूर्ण और वृहद बुनियादी ढांचा है जिसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों की ई.सरकारी सेवाओं तक पहुंचा जा सकता है।

7- Mh,,l dks ykxw djus ds fy, dscy vf/kfu;e esa la'kks/ku

ट्राई की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 13 अक्तूबर, 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आयोजित बैठक में, केबल टीवी में डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) को अनिवार्य रूप से लागू करने वाले मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें अन्य बातों के साथ, केबल टीवी सेवाओं में अखिल भारतीय स्तर पर डिजिटलीकरण के साथ कार्यान्वयन की समय सीमा और रोड मैप को शामिल किया गया। 31 दिसंबर, 2014 तक पूर्ण रूप से एनालॉग टीवी सेवाओं को बदलने को कहा गया। मंत्रिमंडल ने अध्यादेश के माध्यम से केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 को संशोधन कर

अध्यादेश जारी किया गया। जिसे केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2011 कहा जाता है। इस अध्यादेश को 25 अक्तूबर, 2011 को लागू किया गया था। इसके बाद 31 दिसंबर, 2011 को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2011 अस्तित्व में आया।

8- Mh,,l dk pj.kc) dk;kZUo;u dk fy, vf/klwpuk

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में दिनांक 11 नवंबर, 2011 को भारत में चार चरणों में केबल टीवी नेटवर्क के डिजिटलीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया था।

चरण 1	मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई	मूल रूप से 30 जून, 2012 तक रखा गया। इसे 31 अक्तूबर, 2012 तक संशोधित किया गया।
चरण 2	38 शहर (1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले)	31 मार्च, 2013
चरण 3	अन्य शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगर पालिकाएं)	मूल रूप से 30 सितंबर, 2014 को शुरू हुआ। 31 दिसंबर, 2015 को संशोधित न्यायालय के मुकदमों के निपटान के बाद डीएएस को पूरी तरह क्रियान्वित करने हेतु III चरण में मंत्रालय ने 31.01.2017 तक का समय दिया।
चरण 4	शेष भारत	मूल रूप से 31 दिसंबर, 2014 को शुरू हुआ। 31 दिसबंर, 2016 तक संशोधित। केस कोर्ट के निपटान के बाद 31.03.2017 तक पुनः संशोधित।

9- igy vkSj fØ;kUo;u

यह जानते हुए कि केबल टीवी नेटवर्क का डिजिटलीकरण एक बड़ी कवायद है इसलिए इसमें तमाम हिस्सेदारों, नामित व्यक्तियों, प्रसारणकर्ताओं, एमएसओ और एलसीओ का शामिल होना जरूरी हो जाता है। यह बात समझी जा सकती है कि एनालॉग व्यवस्था से डिजिटलीकरण का काम सहजता के साथ हो सके इसके लिए आवश्यक ढांचागत व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास डिजिटलीकरण की व्यवस्था लागू करने का अधिकार है इसीलिए मंत्रालय ने कुछ अहम कदम उठाए हैं ताकि समयबद्ध तरीके से यह काम संपन्न हो सके।

(i) टास्क फोर्स : मंत्रालय ने अपने विभाग के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स में इनका प्रतिनिधित्व भी है :

- प्रसारणकर्ता
- एमएसओ
- एलसीओ
- सीईएएमए (उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स एंड अप्लायंसेस मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन)
- उपभोक्ता फोरम
- दूरसंचार विभाग
- इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- ट्राई

o राज्य सरकारें

o प्रसार भारती

टास्क फोर्स की बैठक हर महीने हुई जिसमें उसने कामकाज की प्रगति की समीक्षा की। पहले चरण के लिए टास्क फोर्स की 20 बैठकें हुईं, दूसरे चरण के लिए 6 और तीसरे और चौथे चरण के लिए 21 बैठकें की गईं।

(ii) राष्ट्रीय स्तर के एमएसओ उपसमूहों और स्वाधीन एमएसओ तथा एसीओ के साथ बैठकें : इन उप समूहों के साथ अलग से बैठकें की गईं ताकि कामकाज की समीक्षा की जा सके और साथ ही उनकी परेशानियों को दूर किया जा सके।

(iii) प्रशिक्षण : इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए कि डिजिटलीकरण के काम में उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और साथ ही लोकल केबल ऑपरेटरों का प्रशिक्षण कार्य भी चलता रहे, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) से कहा गया कि वह छोटे–छोटे समूहों के रूप में लोकल केबल ऑपरेटरों के साथ प्रशिक्षण का काम करें लेकिन प्रशिक्षण के काम को लेकर केबल ऑपरेटरों की तरफ़ के कोई अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए बीईसीआईएल प्रशिक्षण के इस काम को जारी नहीं रख सका।

(iv) जन जागरूकता अभियान : डिजीटलीकरण का काम हो रहा है इसके बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में सूचना और जागरूकता अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य जागरूकता के साथ ही लोगों की चिंताओं का समाधान करना भी था।

(v) टोल फ्री हेल्पलाइन : जनता की ओर से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 31 मई, 2017 तक एक बहुभाषीय टोल फ्री नंबर 1800–180–4343 चालू किया गया।

(vi) वेबसाइट : इस काम के लिए एक पूर्णत समर्पित वेबसाइट www.digitalIndiamib.com बनाई गई।

(vii) राज्य सरकारों के साथ परस्पर बातचीत

यह जानते हुए कि स्थानीय स्तर पर इस काम को आगे बढ़ाने में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी इसलिए उनके साथ भी कई बैठकें की गईं ताकि उन्हें उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में बताया जा सके। दूसरे चरण के लिए प्रमुख सचिवों से आग्रह किया गया कि वे सभी 38 शहरों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें ताकि डीएएस के लिए समयबद्ध तैयारी की जा सके। तीसरे और चौथे चरण के लिए भी जिलावार नोडल अधिकारी नामित किए गए और उनके साथ बैठकों का आयोजन किया गया।

(viii) जनगणना डाटा

साल 2011 की जनगणना के मुताबिक डिजीटलीकरण के लिए शहर और चरणों के मुताबिक कितने टेलीविजन सेट्स की जरूरत होगी, इसकी जानकारी हासिल की गई। एक घर में अनेक टीवी होने की स्थिति एवं कार्यालयों/दुकानों में टीवी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त 20: का प्रावधान रखा गया। इसकी जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

(ix) सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) डाटा का एकत्रीकरण और आकलन

पहले और दूसरे चरण की समीक्षा के लिए मंत्रालय ने व्यापक आधार पर एक डाटा बेस तैयार किया। इसमें एमएसओ से यह जानकारी जुटाई गई कि शुरुआती समय में कितने एसटीबी की जरूरत पड़ेगी। डीटीएच ऑपरेटरों से भी डाटा मांगा गया।

शुरुआत में हर सप्ताह का डाटा ही जमा किया जाता रहा लेकिन जैसे ही पहले और दूसरे चरण में एक महीने का समय रह गया तो दैनिक आधार पर डाटा जमा करने का काम किया जाने लगा।

तीसरे और चौथे चरण के लिए एक सूचना प्रबंधन व्यवस्था (एमआईएस) तैयार की गई। इसमें सभी पंजीकृत ऑपरेटर (एमएसओ, डीटीएच और हिट्स ऑपरेटर) से कहा गया कि वे इलाके के अनुसार एसटीबी की आवश्यकताओं का विवरण दें। इस डाटा को देखने का अधिकार नोडल अधिकारियों को भी दिया गया ताकि वे राज्य और जिलों के हिसाब से काम की समीक्षा कर सकें।

(x) फील्ड टीमें

बीईसीआईएल और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से बड़े पैमाने पर इलाकों का दौरा किया गया।

यात्राओं के दौरान मंत्रालय की टीमें एमएसओ और एलसीओ प्रतिष्ठानों तथा एसबी निर्माताओं के पास भी पहुंचीं।

इन यात्राओं के दौरान खास तौर से दूर–दराज और झुग्गी–झोपड़ियों में बसने वाले उपभोक्ताओं से बातचीत

केबल टीवी डिजिटाइजेशन वेबसाईट www.digitalindiamib.com

की गई ताकि उनकी जरूरतों का पता चल सके और साथ ही उनकी प्रतिक्रिया भी हासिल हो पाए।

दूसरे चरण की बड़ी जरूरतों को देखते हुए आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से कहा गया कि वे सभी 38 शहरों के हिसाब से तकनीकी टीमों का गठन करें। ये टीमें एमएसओ प्रतिष्ठानों की लगातार यात्राएं करती रहीं और तमाम जानकारी और डाटा मंत्रालय को लगातार उपलब्ध कराती रहीं।

तीसरे चरण को लागू कराने के दौरान भी इसी तरह की व्यवस्थाएं की गईं और रेडियो तथा दूरदर्शन के अधिकारियों से कहा गया कि वे पंजीकृत एमएसओ की लगातार पड़ताल करते रहें।

(xi) नोडल अधिकारियों के साथ बैठकें

राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों के साथ लगातार बैठकों का दौर चलता रहा।

(xii) समय पर सही सूचना के लिए केबल नियम में संशोधन

6 जुलाई, 2012 को केबल नियमों में एक संशोधन किया गया। इसके मुताबिक हरेक एमएसओ और एलसीओ के लिए यह अपरिहार्य कर दिये गया कि केंद्र या राज्य सरकारों के जो भी अधिकृत अधिकारी कोई सूचना मांगते हैं तो वह निर्धारित स्वरूप और समय के भीतर देनी होगी। इसके साथ ही एमएसओ और एलसीओ को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जो भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है वह सत्य और सही है।

(xiii) एमएसओ का पंजीकरण

वे सभी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) जो डिजी. टल रूप में केबल टीवी सेवाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पंजीकरण प्राप्त करना था। 6 नवंबर, 2017 से, 1471 एमएसओ को डिजिटल केबल टीवी सेवाओं के लिए पंजीकरण जारी किए गए। गृह मंत्रालय से सुरक्षा निकासी निरस्त होने पर 10 एमएसओ का पंजीकरण रद्द किया गया तथा 6 आवेदकों को एमएसओ पंजीकरण नहीं दिए गए।

(xiv)एमओएस पंजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रणाली

ऑनलाइन में आवेदन हेतु 01 मई 2017 से एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित कर संचालित की गई है। इस के माध्यम से वे आवेदनों की स्थिति की जानकारी भी ऑनलाइन देख सकते हैं।

(xv) भारत कोष के जरिए ऑनलाइन भुगतान

मंत्रालय ने एमएसओ पंजीकरण हेतु प्रोसेसिंग शुल्क केवल ऑनलाइन में भारत कोष के माध्यम से स्वीकार

करना प्रारंभ कर लिया है। इस संबंध में वेबसाइट पर एक परिपत्र अपलोड किया गया है जिसके अनुसार एमएसओ पंजीकरण के लिए शुल्क भारत कोष से अदा करने से संबंधित सूचना दी गई है।

10 डिजीटलीकरण की स्थिति

10.1 पहला चरण

पहले चरण में डिजिटलीकरण का कार्य 31 अक्तूबर, 2012 को पूरा हो गया था। इनमें से चार मेट्रो शहरों में से 4 शहरों, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में डिजिटलीकरण का कार्य पूरे होने को है जबकि चेन्नई में कई लंबित कोर्ट मामलों के कारण यह कार्य अभी जारी है।

पहले चरण के शहरों में लगभग 85 लाख केबल सेट टॉप बॉक्स लगाए जा चुके थे। सबसे ज्यादा दिल्ली में 34 लाख, उसके बाद मुंबई में 26 लाख और कोलकाता में 22 लाख तथा चेन्नई में 3.5 लाख सेट टॉप बॉक्स लगाए जा चुके हैं।

10.2 दूसरा चरण

31 मार्च, 2013 तक 14 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैले 38 शहरों में द्वितीय चरण संपन्न हुआ।

38 शहरों में से 37 शहरों में कार्य पूरा हो गया है, जबकि कोयंबटूर में यह अदालती मामलों की वजह से जारी है। इस क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ एसटीबी की स्थापना की गई है।

10.3 तीसरा चरण

केबल टीवी नेटवर्क के डिजीटलीकरण के तीसरे चरण की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2015 को थी किंतु अदालत द्वारा दिए गए विस्तार/स्थगन आदेश के कारण मंत्रालय ने अदालती मामलों के निपटान के आधार पर तीसरे चरण में डिजीटलीकरण के क्रियान्वयन की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2017 कर दी थी।

10.4 चौथा चरण

भारत के शेष हिस्सों का डिजीटलीकरण चौथे चरण में 31 दिसंबर, 2016 तक पूरा करने का विचार था। अदालती मामलों की वजह से बाजार में आई अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए अंतिम तारीख 31 मार्च 2017 तक संशोधित किया गया।

11. केबल डिजिटलीकरण के तीसरे और चौथे चरण की राह में आई चुनौतियां

कार्य समापन की अंतिम तिथि यानी 31 दिसंबर, 2015 के ठीक पहले कुछ एमएसओ एसोसिएशन तथा कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से विभिन्न उच्च न्यायालयों में इस गुहार के साथ पहुंच गए कि तारीख बढ़ा दी जाए।

तीसरे चरण के क्रियान्वयन के लिए अलग–अलग अदालतों ने विस्तार का अलग–अलग समय प्रदान किया था। 1 अप्रैल 2016 को शिखर अदालत इस बात के लिए राज़ी हो गई कि तमाम केस उसके पास स्थानांतरित कर दिए जाएं और भविष्य में अगर कोई और इसी तरह का मामला आएगा तो उसकी सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय में की जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय में हस्तांतरित 45 मामलों में से तीन मामलों के अलावा सभी का निस्तारण किया गया। ये तीन मामले त्रुटिवश दिल्ली उच्च न्यायालय में हस्तांतरित किए गए थे इसलिए इन्हें संबंधित उच्च न्यायालयों में पुनः हस्तांतरित किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी मामलों का निस्तारण कर दिया है तथा अब इस मामले में कोई स्थगन विस्तार शेष नहीं है। तदनुसार, मंत्रालय ने दिनांक 23 दिसंबर, 2016 को सभी प्रसारणकर्ताओं, एमएसओ तथा एलसीओ को तीसरे चरण के डिजिटलीकरण के लिए चुने गए क्षेत्रों में एनालॉग सिग्नल बंद करने हेतु 31 जनवरी, 2017 तक का समय देते हुए निर्देश जारी किए। मंत्रालय ने चौथे चरण में आने वाले क्षेत्रों में केबल टीवी डिजिटलीकरण के चौथे चरण को लागू करने की अंतिम तारीख को दिनांक 23 दिसंबर 2016 के राजपत्रित अधिसूचना के जरिए 31 मार्च, 2017 तक बढ़ा दिया है।

12- orZeku fLFkfr ,o eqís

(i) 1 अप्रैल, 2017 से देश में केबल टीवी डिजिटलीकरण को अनिवार्य बना दिया गया है। मंत्रालय ने 30 मार्च, 2017 के परिपत्र के जरिए सभी प्रसारणकर्ताओं, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों तथा लोकल केबल ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च 2017 के बाद केबल नेटवर्क के माध्यम से कोई एनालॉग सिग्नल का प्रसारण नहीं होगा। ऐसा न करने पर चूककर्ता के खिलाफ केबल टीवी अधिनियम/नियम के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(ii) देश के कुछ हिस्सों से एनालॉग सिग्नलों के 31 मार्च, 2017 के बाद भी प्रसारित होने संबंधी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए राज्य संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों। सभी प्राधिकृत अधिकारियों तथा नोडल अधिकारियों को 21 अप्रैल 2017 को एक परामर्श पत्र मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है।

इसमें यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि कोई भी केबल ऑपरेटर एनालॉग सिग्नल प्रसारित कर रहा है तथा यदि कोई एमएसओ/केबल ऑपरेटर इन निर्देशों/आदेशों का पालन नहीं कर रहा हो तो इस मंत्रालय को सूचित करते हुए उनके खिलाफ केबल टीवी नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्यवाही की जाए।

(iii) मंत्रालय ने प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा एमएसओ के निरीक्षण हेतु एक जांच सूची तैयार कर 25 अप्रैल, 2017 को इसे सभी प्राधिकृत अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया है।

(iv) मंत्रालय ने 12 जून, 2017 को राज्य के सभी मुख्य सचिवों से यह अनुरोध किया है कि वे सभी जिला मजिस्ट्रेटों को यह निदेश दें कि चूककर्ताओं के खिलाफ धारा 11 के अंतर्गत निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही करें तथा इस मामले की निगरानी जिला कलक्टर, राजस्व सचिव या पुलिस महानिरीक्षक द्वारा करवाए।

(v) एमआईएस के अनुसार 84 प्रतिशत कार्य अब तक पूरा हो चुका है।

केबल नेटवर्क पर मूल्यवर्धन एवं ट्रिपल प्ले सर्विसेज हेतु मंच तैयार

केबल टीवी नेटवर्क के डिजिटलीकरण के कारण एमएसओ/एलसीओ के माध्यम से उनके व्यापार क्षेत्र को बढ़ाते हुए उपभोक्ताओं को मूल्यवर्धित एवं ट्रिपल प्ले सर्विसेज प्रदान करने के लिए इस नेटवर्क का इस्तेमाल करने पर विचार किया जा रहा है। केबल टीवी डिजिटलीकरण के प्रभाव का इतनी जल्दी औपचारिक रूप से आकलन नहीं किया जा सकता किंतु प्रारंभिक आंकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि डिजिटलीकरण का प्रमुख लाभ प्राप्त होना शुरू हो गया है।

स्पोर्ट्स ब्राडकास्टिंग सिग्नल्स (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 भारत और विदेश

13. केबल टीवी डिजिटीकरण के माध्यम से मनोरंजन कर संग्रहण का आकलन

क्रम सं.	*राज्य/संघ शासित प्रदेश*	*2012-13*	*2013-14*	*2014-15*	*2015-16*
		वित्तीय वर्ष			(लाख ₹ में)
01	बिहार	19.16	18.61	238.44	292.44
02	गुजरात	796.63	899.31	993.64	1091.12
03	झारखंड	100.41	1000.27	1500.38	1600.17
04	कर्नाटक (आंशिक)	281.48	569.44	1085.96	1261.92
05	महाराष्ट्र (आंशिक)	9145.72	9023.47	12733.89	13775.32
06	मिजोरम	43.82	48.17	97.83	77.13
07	राजस्थान	—	1389.00	5145.01	10107.07
08	त्रिपुरा	53.40	63.19	69.90	267.23
09	उत्तर प्रदेश	4775.08	5979.33	7869.06	8732.85
10	उत्तराखंड	2312.5	2341.87	2525.74	2895.82
11	पश्चिम बंगाल	901.41	1921.26	3830.10	4681.30
	कुल योग	**18429.61**	**23253.92**	**36090.63**	**44782.35**

माननीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डिजिटल प्रसारण के भविष्य के बारे में संबोधित करते हुए

में आयोजित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का प्रसारण निःशुल्क यानी फ्री टू एयर आधार पर अधिक से अधिक श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 पारित किया गया। यह कार्य प्रसार भारती के साथ खेल प्रसारण सिग्नलों की अनिवार्य हिस्सेदारी के जरिए किया जाता है। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 की धारा 3(1) के अनुसार इस अधिनियम के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न खेल कार्यक्रमों के प्रसारण संकेत प्रसार भारती के साथ साझा करना अनिवार्य है। सरकार ने जी.एस.आर. 687(ई) दिनांक 31 अक्तूबर, 2007 के जरिए खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) नियम 2007 अधिसूचित किए ताकि अधि. नियम का सुचारू और समुचित कार्यान्वयन किया जा सके। अधिनियम की धारा 2(1)(एस) में केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कवरेज के लिए राष्ट्रीय महत्व की खेल घटनाओं को अधिसूचित कर सकती है।

सरकार ने एस.ओ. 1489 (ई) दिनांक 04 जुलाई, 2012 और एस.ओ. 1957(ई) दिनांक 23 अगस्त, 2012 भी अधिसूचित किए हैं, जिनमें राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतियोगिताओं का ब्यौरा दिया गया है, जिनमें अन्य के अलावा क्रिकेट, टेनिस, हॉकी और फुटबॉल से संबंधित खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने क्रिकेट मैचों के संबंध में प्रसार भारती के साथ राष्ट्रीय महत्व के खेल प्रतियोगिताओं की अनिवार्य साझेदारी के लिए एस. ओ. 3264 (ई) दिनांक 22 अक्तूबर, 2016 को भी अधिसूचित किया है। सरकार ने अपने दिनांक 27.01.2017 के राजपत्रित अधिसूचना सं.एसओ.302(ई) के जरिए दिनांक 4 जुलाई 2012 की अधिसूचना सं.एसओ 1489 (ई) को पुनः वैध बना दिया। इसके बाद, सरकार ने फिफा यू–17 विश्व कप भारत 2017 को राष्ट्रीय महत्व के खेल प्रतियोगिता के रूप में शामिल करने संबंधी दिनांक 05.09.2017 से राजपत्रित अधिसूचना सं.एस.ओ 3060 (ई) के जरिए दिनांक 27.01.2017 की अधिसूचना एसओ 302 (ई) में संशोधन किया।

Hkkjr esa Vsyhfotu jsfVax ,tsafl;ksa ds fy, uhfr fn'kk&funsZ'k

भारत में टेलीविजन रेंटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) व्यापक बहस का मुद्दा रहा है, क्योंकि टीआरपी की वर्तमान प्रणाली में असंख्य विसंगतियां हैं, जैसे लघु नमूना आक. ार, जो प्रतिनिधिपूर्ण नहीं होता है, पारदर्शिता का अभाव, आंकड़ों का विश्वसनीयता और भरोसे का अभाव आदि। एमआईबी ने अगस्त 2012 में भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए व्यापक दिशा–निर्देशों व उनके प्रत्यायन की व्यवस्था के लिए ट्राई से सिफारिशें देने को कहा ताकि टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों द्वारा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, बेहतर मानक और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए दिशा–निर्देश के बारे में ट्राई की अनुशंसाएं 11.9.2013 को प्राप्त हुईं।

बीएआरसी की तरह के उद्योग आधारित निकाय के जरिए टेलीविजन रेटिंग के स्वःनियमन का समर्थन करते हुए ट्राई ने सिफारिश की कि टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों का नियमन एमआईबी द्वारा अधिसूचित दिशा–निर्देशों के एक फ्रेमवर्क के जरिए किया जाएगा। यह अनुशंसा की गई कि वर्तमान रेटिंग एजेंसियों सहित सभी रेटिंग एजेंसियों को उक्त दिशा–निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार एमआईबी के साथ पंजीकरण कराना होगा।

ट्राई की सिफारिशों के आधार पर भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए मंत्रालय द्वारा 16 जनवरी, 2014 को व्यापक नीति–निर्देश जारी किए गए।भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए दिशा–निर्देश इस बात को ध्यान में रख कर तैयार किए गए हैं कि वर्तमान टेलीविजन रेटिंग की खामियां दूर की जा सकें।

मैसर्स प्रसारण दर्शक अनुसंधान परिषद को 28 जुलाई, 2015 को टीआरपी एजेंसी के रूप में पंजीकरण प्रदान किया गया। मैसर्स टैम मीडिया रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ने 19 फरवरी, 2014 को टीआरपी एजेंसी के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। कई अनुस्मारकों के बावजूद कंपनी की तरफ से कोई जवाब न प्राप्त होने की स्थिति में, उनके आवेदन पर कार्रवाई हेतु अपेक्षित ब्योरों के अभाव में, इस मंत्रालय ने आवेदन पर कार्रवाई समाप्त कर दी है।

Lkkeqnkf;d jsfM;ks

voyksdu

सामुदायिक रेडियो, सार्वजनिक सेवा और वाणिज्यिक मीडिया से अलग, प्रसारण का महत्वपूर्ण तीसरा स्तर है। यह स्थानीय लोगों को, उनके जीवन से संबंधित मुद्दों को स्वर देने के लिए एक मंच मुहैया कराता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत में यह क्षेत्र धीरे–धीरे, लेकिन प्रभावी ढंग से वृद्धि कर रहा है। सामुदायिक रेडियो, वास्तव में, कम क्षमता के रेडियो स्टेशन हैं, जो स्थानीय समुदायों द्वारा स्थापित और संचालित किए जाते हैं। भारत में सीआरएस अनुमतियां केवल शैक्षणिक संस्थानों, कृषि संस्थानों और नागरिक संगठनों जैसे गैर–लाभकारी संगठनों को प्रदान की गई हैं। सीआरएस स्थानीय समुदायों में स्थित हैं और इनका स्वामित्व और प्रबंधन स्वयं समुदायों द्वारा किया जाता है। यह उन्हें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कृषि आदि स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की विशेष सुविधा देता है। इसके अलावा, सीआरएस क्षेत्र हाशिये पर स्थित समूहों को उनकी चिंताओं को आवाज देने के लिए सशक्त माध्यम उपलब्ध कराता है।

यही नहीं, चूंकि प्रसारण स्थानीय भाषाओं और बोलियों में होता है, लोग इससे आसानी से जुड़ने में समर्थ होते हैं। सामुदायिक रेडियो, विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को मजबूत करने की भी क्षमता रखता है। भारत जैसे देश में, जहां प्रत्येक राज्य की अपनी अलग भाषा और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, सीआरएस स्थानीय लोक संगीत और सांस्कृतिक विरासत का कोष भी है। कई सीआरएस, भावी पीढ़ी के लिए स्थानीय गीतों को रिकार्ड और संरक्षित भी करते हैं और स्थानीय कला. कारों को समुदाय के समक्ष उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए मंच मुहैया कराते हैं। सकारात्मक सामाजिक बदलाव के साधन के रूप में सीआरएस की अनूठी स्थिति, इसे समुदाय के सशक्तिकरण का एक आदर्श उपकरण बना देता है। सामुदायिक रेडियो के लिए नीतिगत दिशा–. निर्देश और वर्तमान में संचालित सीआरएस की सूची http://www.mib.nic.in/broadcasting/community.radio.station पर देखी जा सकती है।

दिसंबर 2002 में, भारत सरकार ने सुव्यवस्थित शिक्षण संस्थानों को सीआरएस की स्थापना के लिए अनुदान देने की एक नीति को मंजूरी दी। 2006 में, गैर–लाभकारी संस्थाओं को भी सीआरएस की अनुमति देने के लिए नीतिगत दिशा–निर्देशों में संशोधन किया गया, ताकि विकास और सामाजिक परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर नागरिक समाज की अधिक भागीदारी हो सके। वर्तमान समय में, 214 संचालित सीआरएस, 293 जीओपीए धारक और 562 एलओआई धारक हैं।

lkeqnkf;d jsfM;ks LVs'kuksa dh la[;k esa o"kZ&okj of)

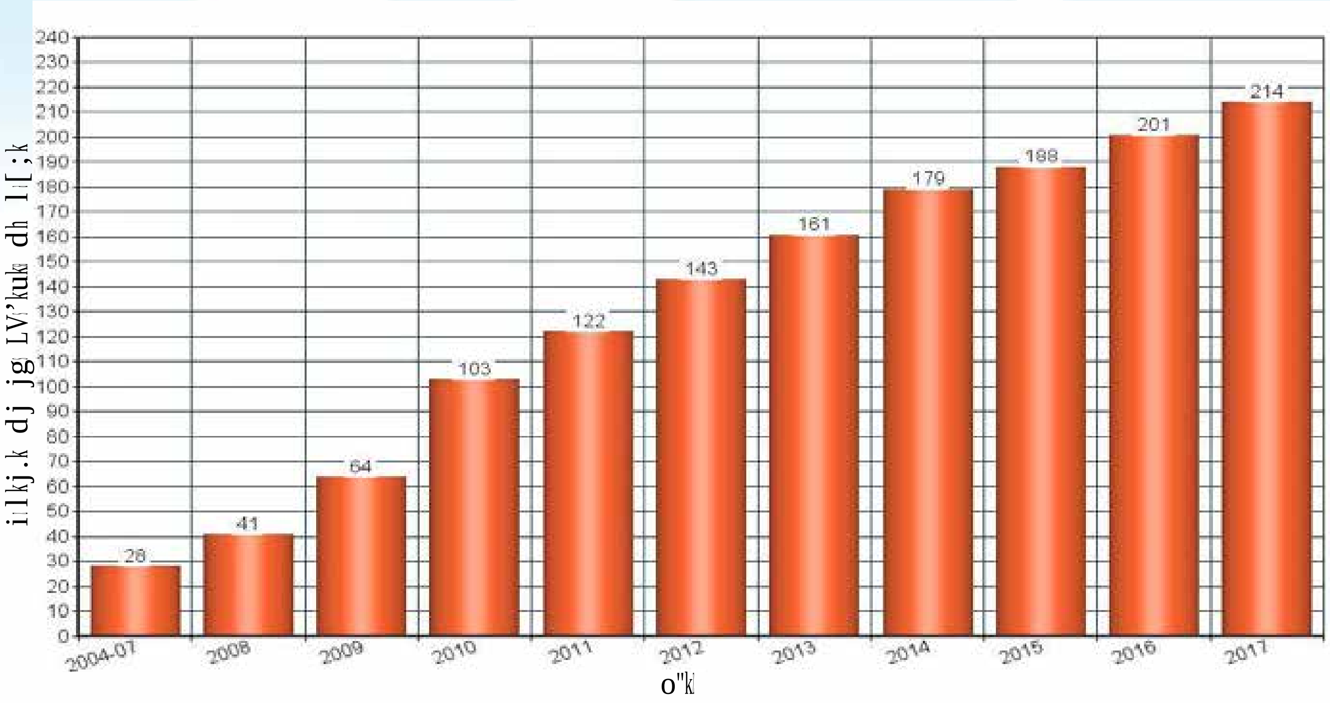

सीआर प्रसारण ने आवेदन कार्यप्रणाली के सरलीकरण, आवेदनों की प्रोसेसिंग की पारदर्शिता में सुधार, मंजूरी की गति में वृद्धि, बेहतर समन्वय, जागरूकता बढ़ाने, शेयर धारकों के मध्य बेहतर तालमेल और सीआर के प्रसारण में सरकारी मंत्रालयों की भागीदारी बढ़ाने जैसे कदम उठाकर भारत में सीआर के सार्थक विकास की ठोस नींव रखी है।

Hkkjr esa lhvkj,l dh fLFkfr

अब तक, 562 आवेदकों को आशय पत्र (एलओआई) जारी किए जा चुके हैं। इन 562 एलओआई धारकों में से 293 धारकों ने समझौते की स्वीकृति संबंधी अनुमति (जीओपीए) पर हस्ताक्षर किए। सीआरएस स्थापित करने की अनुमति देने के लिए करीब 340 आवेदनों पर इस समय विचार किए जा रहे हैं।

अब तक, देश में 214 सामुदायिक रेडियो स्टेशन कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 86 सीएसओ द्वारा, 113 शैक्षणिक संस्थानों और 15 एसएयू/केवीके द्वारा संचालित हैं। संचालित सी आर एस का रेखाचित्रीय प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है :

ea=ky; dh ubZ igy

midj.kksa ds fy, vuqnku % सामुदायिक रेडियो योजना को बढ़ावा देने तथा अधिक से अधिक संगठनों को सीआर स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास के तहत मंत्रालय ने उपकरणों की खरीद के लिए 7.50 लाख रूपए की अधिकतम अनुदान सीमा के साथ कुल अनुमानित खर्च के 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने का फैसला किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अधिकतम अनुमति अनुदान 7.5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ कुल अनुमानित खर्च का 90 प्रतिशत होगा।

dUVsaV l`tu ds fy, vuqnku % विभिन्न विषयों पर नए कार्यक्रम बनाने तथा प्रसारित करने के लिए 'भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को समर्थन प्रदान करने' की योजना के तहत संचालित हो रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को अनुदान प्रदान किए जाएंगे। सामग्रियों के सृजन के लिए अधिकतम अनुदान तीन साल की अवधि के लिए प्रति घंटे कार्यक्रम के लिए 2350 रुपये के हिसाब से 10 लाख रुपये तक सीमित होगा।

lhvkj,l dh {kerk fuekZ.k% सीआरएस की जरूरत के मुताबिक एक प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन किया गया है। इस मुद्दे पर हितधारकों के साथ कई दौर की चर्चा के बाद 5 विषयों की पहचान की गई है, जिन पर सीआरएस की क्षमता का निर्माण किया जाएगा। सीआरएस की क्षमता निर्माण के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए एफआरपी का मसौदा तैयार किया गया है।

हाल में भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) को सिद्धांत रूप से प्रसारण के विभिन्न मामलों, जैसे सामग्री सृजन, तकनीकी ज्ञान एवं देश के कुछ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में वाम उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के कर्मचारियों को प्रशिक्षण आदि में प्रशिक्षण देने की अनुमति दी गई है।

Hkkjr esa lh,lvkj dh iHkkfodrk ij v/;;u% सामुदायिक रेडिया की कारगरता तथा आसपास के समुदायों में इसकी पहुंच का मूल्यांकन करने के लिए मंत्रालय ने देश में संचालित हो रहे सामुदायिक रेडियो के संबंध में श्रोता संबंधी सर्वेक्षण करने का फैसला किया है। एएमएस, लखनऊ को मंत्रालय की ओर से यह सर्वेक्षण करने के लिए चुना गया। यह निर्णय किया गया कि इस सर्वे के लिए नमूना आकार 19 स्टेशनों (संचालित सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का 10 प्रतिशत) का होग.ा। सीआर स्टेशनों के भौगोलिक फैलाव तथा भाषाई आधार पर इन 19 सीआर स्टेशनों का चुनाव किया गया है। एएमएस, लखनऊ ने यह सर्वे किया है और मंत्रालय को अपनी मसौदा रिपोर्ट सौंप दी है। एएमएस द्वारा समर्पित मसौदा रिपोर्ट को संयुक्त सचिव (प्रसारण–।।) की अध्यक्षता में दिनांक 8 अगस्त, 2017 को आयोजित सीआर क्षेत्र के हितधारकों की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। रिपोर्ट में हितधारकों के सुझावों को सम्मिलित किया गया तथा एएमएस ने अपना अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तथा.पि अंतिम रिपोर्ट मंत्रालय की स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

पुद्दुचेरी में सामुदायिक रेडियो पर जागरूकता कार्यशाला (24–26 सितंबर 2017)

lkeqnkf;d jsfM;k ij tkx:drk dk;Z'kkyk% भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन की सफलता के लिए जागरूकता उत्पन्न करना महत्वपूर्ण है। इसलिए मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों के साथ जागरूकता कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से मंत्रालय सामुदायिक रेडियो योजना का व्यापक प्रचार किया। ये कार्यशालाएं दिशा.निर्देशों, अनुप्रयोग प्रक्रियाओं, सीआरएस के लिए सामग्रियां एवं निरंतरता संबंधी मामलों आदि से जुड़े मुद्दों का सफलतापूर्वक समाधान कर रही हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान पुदुच्चेरी और इंफाल में 2 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।

lhvkj,l dh fo"k; lkexh lk>k eap% एक दुनियाएकआवाज(ईडीएए)www.edaa.inसामुदायिकरेडियो प्रसारकों, सरकारी विभागों और अन्य आईइसी

इम्फाल में सामुदायिक रेडियो पर जागरूकता कार्यशाला (21–23 सितंबर 2017)

सामग्री उत्पादकों के लिए एक वेब आधारित सामग्री और जानकारी के आदान–प्रदान का एक स्वतंत्र और खुला मंच है। ईडीएए पोर्टल सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को आपस में उनके कार्यक्रमों की भागीदारी करने का अवसर उपलब्ध कराता है। मंत्रालय सामग्री प्रबंधन के लिए श्रमशक्ति हासिल करने में वित्तीय सहायता के जरिए इस मंच की मदद करता है।

इस पोर्टल के पास 29 विभिन्न भाषाओं/बोलियों में 11,000 ऑडियो क्लिप और रेडियो कार्यक्रमों का भंडार है। 110 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों ने इसमें, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, पंचायती राज, सफाई और पेयजल आदि विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम अपलोड किए हैं।

चरण I, II और III के अंतर्गत काम कर रहे और प्रस्तावित निजी एफएम स्टेशन

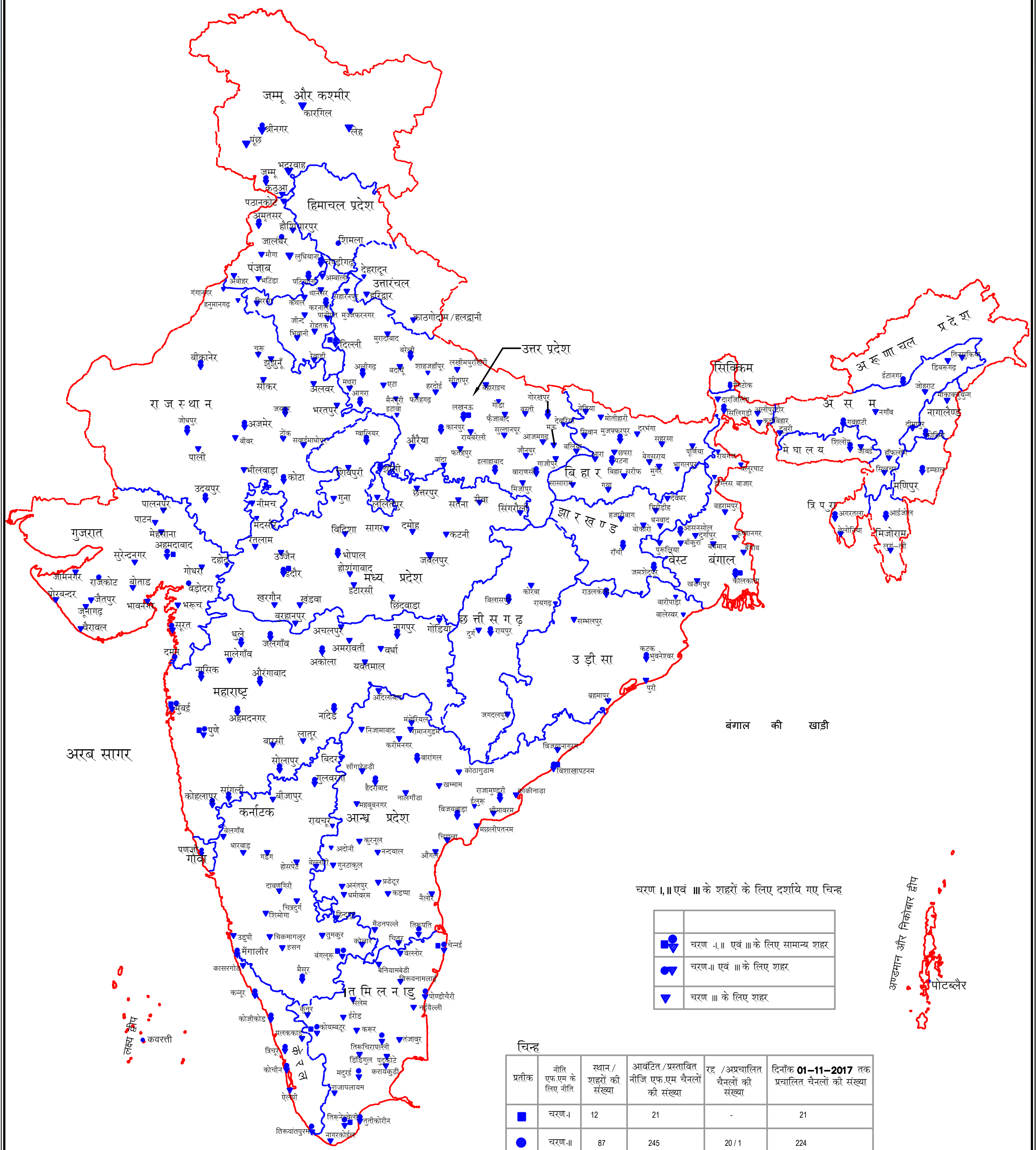

चिन्ह

प्रतीक	नीति एफ.एम के लिए नीति	स्थान / शहरों की संख्या	आवंटित / प्रस्तावित नीजि एफ.एम चैनलों की संख्या	रद्द /अप्रचालित चैनलों की संख्या	दिनांक 01-11-2017 तक प्रचालित चैनलों की संख्या
■	चरण-I	12	21	-	21
●	चरण-II	87	245	20 / 1	224
▼	चरण -III	313	839 (प्रस्तावित)	-	95

THIS DRAWING IS COPYRIGHT AND THE PROPERTY OF "B E C I L" AND IS NOT TO BE REPRODUCED, COPIED HANDED OVER TO A THIRD PARTY OR USEDFOR ANY PURPOSE OTHER THAN THAT FOR WHICH IT HAS BEEN ISSUED.

Map No. BECIL/FM/E&P/STATION/001/A

BECIL
BROADCAST ENGINEERING CONSULTANTS INDIA LIMITED
HEAD OFFICE:- 14-B, RING ROAD, I. P. ESTATE, NEW DELHI-110 002 (INDIA),
Tele:- 2337 8823, Fax No. 2337 9885

,Q,e çHkkx

देश के युवा और वयस्क के मध्य मनोरंजन का सबसे चहेता साधन एफएम रेडियो है। पिछले वर्षों में चैनलों की संख्या में हुई बढ़ोत्तरी से यह स्पष्ट है कि एफएम रेडिया स्टेशनों द्वारा स्थानीय भाषाओं में प्रसारित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों ने बहुतों का मन जीता है। ई.नीलामी में नए एफएम रेडियो चैनलों को प्राप्त करने हेतु निजी एफएम प्रसारणकर्ताओं की होड़ भी इस ओर सकारात्मक संकेत करते हैं। स्थानीय व्यापारों की जनसाधारण तक पहुंच को बढ़ाने में रेडियो विज्ञापन महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय निजी एफएम रेडियो का इस्तेमाल सरकार के विकासात्मक कार्यक्रमों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कर रहा है। उदाहरण के लिए महिलाओं से किए जा रहे भेदभाव के विरुद्ध लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए झंकार प्रस्तुत करना है। स्वच्छता अभियान जैसे सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों को जनसमूहों तक पहुंचाने का काम भी एफएम रेडियो करता है। मंत्रालय का एफएम रेडियो सेल 7 जुलाई 2011 को संघ मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं का निजी एजेंसियों के जरिए विस्तार के तीसरे चरण संबंधी नीतिगत दिशा–निर्देशों के अनुसार भारत के निजी एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधी सभी मामलों पर विचार करती है।

इस नीतिगत दिशा–निर्देश की अद्यतन प्रति मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। (http://mib.gov.in/sites/default/files/PolicyGuidelines_FMPhaseIII%20%281%29.pdf) सरकार ने एफएम रेडियो क्षेत्र को राज्य की राजधानियों में 21 निजी एफएम रेडियो चैनलों के साथ जुलाई 1999 में पहली बार निजी भागीदारी के लिए खोला। एफएम के दूसरे चरण के स्कीम में वर्ष 2005 में 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में विस्तार करने का कार्य प्रारंभ किया। दूसर चरण में 86 शहरों में 243 निजी एफएम चैनल संचालित किए गए। इसमें पहले चरण से स्थानांतरित 21 चैनल भी शामिल है।

एफएम रेडियो की पहुंच को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने 25 जुलाई 2011 को एफएम चरण प्प के नीतिगत दिशा.निर्देशों की घोषणा की जिसका लक्ष्य एक लाख या उससे अधिक की आबादी वाले शहरों के अलावा जम्मू व कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और प्रायः द्वीप क्षेत्रों के 11 सीमा शहरों, जिनकी आबादी एक लाख से कम है, में एफएम रेडियो का विस्तार करना था। एफएम रेडियो तीसरे चरण के तहत दो बैचों में की गई ई.नीलामी के बाद, मंत्रालय ने 162 चौनल देश को दिए हैं। संघ मंत्रिमंडल की 20.12.2017 को आयोजित बैठक में एफएम तीसरे चरण के अगले बैचों में 683 और चौनलों के लिए ई. नीलामी आयोजित करने की स्वीकृति भी दे दी है।

futh ,Q,e pSuyksa dk ekufp=

एक उप मानचित्र में एफएम की चरण.एक और चरण.दो योजनाओं के तहत आने वाले शहरों में संचालित निजी एफएम चैनलों को दिखाया गया है। इसमें एफएम चरण. तीन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित शहरों को भी दर्शाया गया है। दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 के अनुसार, देश के 26 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेश में कुल 320 एफएम चैनल संचालित हैं। एफएम तीसरे चरण के संपूर्ण क्रियान्वयन के बाद देश में (दादर और नागर हवेली को छोड़कर) 1200 निजी एफएम चैनल होंगे।

ikjnf'kZrk mik; ,oa i;Zos{k.k

आरोही ई.नीलामी के आधार पर कंपनियो को एफएम रेडियो चैनल आबंटित किए जाते हैं। निजी प्रसारणकर्ता. ओं से तिमाही लाइसेंस शुल्क ऑनलाइन भारतकोष पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होता है। मंत्रालय ने पब्लिक फिनैन्स मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के सहयोग से राजस्व संग्रहण तंत्र के सुगम शुरूआत हेतु प्रसारणकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया।

पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल ब्रॉडकास्ट सेवा के माध्यम से प्रसारण सेवाओं का चरणबद्ध डिजिटलीकरण भी कर रही है।

एफएम रेडियो तीसरे चरण के नीतिगत दिशा.निर्देशों तथा निजी प्रसारणकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट (जीओपीए) में दिए गए प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय के एफएम सेल के अधिकारी रेडियो स्टेशनों तथा कॉमन ट्रांस्मिशन इन्फ्रास्ट्रक्टर (सीटीआई) सुविधाओं का निरीक्षण करते हैं।

ljdkj dks jktLo L=ksr

सरकार को निजी प्रसारणकर्ताओं से एकमुश्त प्रवेश शुल्क, माइग्रेशन फी तथा वार्षिक लाइसेंस शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त होता है।

वित्तीय वर्ष 2017.18 के पहले तीन तिमाहियों में, 31 अक्टूबर, 2017 तक सरकार को ने लाइसेंस शुल्क के रूप में 136.73 करोड़ रुपए (लगभग) अर्जित किया है। पिछले साल इसी अवधि से लिए 128.96 करोड़ रुपए (लगभग)

लाइसेंस शुल्क के रूप में प्राप्त हुए थे।

गृह मंत्रालय से सुरक्षा निकासी प्राप्त होने पर, सरकार सन ग्रुप कंपनी से चार चैनलों के माइग्रेशन शुल्क और चेन्नई के एक चैनल के लिए गैर वापसी योग्य एकमुश्त प्रवेश शुल्क के रूप में लगभग 95.78 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।

गैर वापसी योग्य एकमुश्त प्रवेश शुल्क माइग्रेशन शुल्क तथा वार्षिक लाइसेंस शुल्क के रूप में देश के प्रसारित निजी एफएम रेडियो से वर्ष 2000 से लेकर लगभग 5565 करोड़ रूपये सरकार को कुल राजस्व के रूप में प्राप्त है।

वार्षिक लाइसेंस शुल्क	एकमुश्त प्रवेश शुल्क	माइग्रेशन शुल्क	कुल
1319.29 करोड़	1993.63 करोड़	2252.74 करोड़	5565.70 करोड़

çlkj Hkkjrh

प्रसार भारती, देश में लोक सेवा प्रसारक है। उसके दो संघटक.आकाशवाणी और दूरदर्शन हैं। प्रसार भारती 23 नवंबर, 1997 को अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य जनता को सूचना देने, शिक्षित करने और उसका मनोरंजन करने वाली लोक प्रसारण सेवाओं का आयोजन और संचालन करना तथा देश में प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।

míís';%

- देश की एकता, अखंडता और देश के संविधान द्वारा संस्थापित मूल्यों को बनाए रखना।
- राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।
- लोक हित के सभी मामलों की सूचना पाने के नाग. रिकों के अधिकार की रक्षा करना और निष्पक्ष और संतुलित सूचना प्रदान करना।
- शिक्षा और साक्षरता के प्रसार, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना, महिलाओं से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना और बच्चों, वृद्धों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाना।
- विभिन्न संस्कृतियों, खेलों और युवा मामलों पर पूरा ध्यान देना।
- सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और कामगारों व अल्पसंख्यकों तथा जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना।
- प्रसारण तकनीक का विकास, इसकी सुविधाओं का विस्तार और शोध को बढ़ावा देना।

प्रसार भारती निगम, प्रसार भारती बोर्ड द्वारा चलाया जाता है जिसमें एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी सदस्य (जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है), सदस्य (वित्त), सदस्य (कार्मिक), छह अंशकालिक सदस्य, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि और आ. काशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक पदेन सदस्यों के रूप में और निगम के कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्रसार भारती अध्यक्ष अंशकालिक सदस्य होता है, जिसका कार्यकाल तीन साल और सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष होती है। कार्यकारी सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होता है जिसका कार्यकाल पांच वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। सदस्य (वित्त) और सदस्य (का. र्मिक) भी पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल छह वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है।

प्रसार भारती बोर्ड की संरचना (दिनांक 18.12.2017 तक) निम्नलिखित है :

1)	डॉ. ए. सूर्य प्रकाश	अध्यक्ष
2)	श्री शशि शेखर वेम्पति	कार्यकारिणी सदस्य
3)	श्री राजीव सिंह	सदस्य (वित्त)
4)	श्री अली आर रिजवी, अति. सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि
5)	श्री सुनील अलघ	अंशकालिक सदस्य
6)	श्री अशोक कुमार टंडन	अंशकालिक सदस्य
7)	श्रीमती काजोल	अंशकालिक सदस्य
8)	श्री एफ. शहरयार, महानिदेशक : आकाशवाणी	पदेन सदस्य
9)	श्रीमती सुप्रिया साहू, महानिदेशक : दूरदर्शन	पदेन सदस्य

lixBukRed <kpk

निगम के मामलों का सामान्य संचालन, निर्देशन और प्रबंधन प्रसार भारती बोर्ड करता है। बोर्ड समय–समय पर बैठकें करता है और महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार–विमर्श करता है, महत्वपूर्ण नीतियां तय करता

है और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश देता है। कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में कार्य करते हैं और बोर्ड का नियंत्रण और निरीक्षण करते हैं और बोर्ड के ऐसे अधिकारों को प्रयोग तथा ऐसे कार्यों का संपादन करते हैं जो बोर्ड उन्हें सौंपता है।

दो महानिदेशक आकाशवाणी महानिदेशालय और दूरदर्शन महानिदेशालय के प्रमुख होते हैं। वे बोर्ड के नीति–निर्देशों और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की रोजमर्रा के मामला. के प्रबंधन के लिए सदस्य (वित्त), सदस्य (कार्मिक) और सीईओ के सहयोग से कार्य करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन में, विभिन्न गतिविधियों, जैसे प्रोग्राम, इंजी. नियरिंग, प्रशासन और वित्त के लिए मोटे तौर पर चार अलग–अलग विंग हैं।

njn'ku

प्रायोगिक सेवा के तौर पर 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। समय के साथ विकसित होते.होते आज यह दुनिया के प्रमुख टीवी संगठनों में से एक बन चुका है। दूरदर्शन ने सिर्फ देश के कोने.कोने तक अपने नेटवर्क का ही विस्तार नहीं किया, बल्कि टीवी प्रसारण के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकीय विकास के साथ ही कदम से कदम मिलाकर चला है।

laxBukRed lajpuk

दूरदर्शन का नेतृत्व महानिदेशक करते हैं जिनका दायित्व.नीति निर्माण, योजना एवं विकास, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास, बजटीय योजना और नियंत्रण, मानव संसाधन विकास, संचालन और रखरखाव संबंधी गतिविधियों आदि की निगरानी करना है। दिल्ली (उत्तरी क्षेत्र), मुंबई (पश्चिमी क्षेत्र), चेन्नई (दक्षिणी क्षेत्र), लखनऊ(मध्य क्षेत्र), कोलकाता (पूर्वी क्षेत्र), तथा गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र), में इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय हैं तथा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में परियोजनाओं और रखरखाव संबंधी गतिविधियों के लिए अपर महानिदेशक (इंजीनियरिंग) की देखरेख में चार इंजीनियरिंग क्षेत्रीय कार्यालय हैं। गुवाहाटी में स्थापित एक अन्य क्षेत्रीय कार्यालय वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्यों में रखरखाव संबंधी गतिविधियों पर ध्यान देता है। दूरदर्शन के अन्य कार्यालय हैं. दूरदर्शन केंद्र (स्टूडियो), उच्च क्षमता ट्रांसमीटर (एचपीटी), अनुरक्षण केंद्र, कम क्षमता वाले ट्रांसमी. टर (एलपीटी) तथा बहुत कम क्षमता वाले ट्रांसमीटर (वीएलपीटी)।

orleku rduhdh volajpuk

दूरदर्शन के पास इन हाउस प्रोडक्शन के लिए 67 स्टूडियो केंद्रों का नेटवर्क, 1409 स्थलीय ट्रांसमीटर्स हैं और यह शुल्करहित डीटीएच सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। स्टूडियो केंद्रों की राज्यवार सूची अनुलग्नक–I में दी गई है।

डीडी नेशनल चैनल की स्थल क्षेत्रीय व्याप्ति देश की अनुमानतः 92 प्रतिशत जनता तक है, जिसमें डीडी न्यूज चैनल की पहुंच लगभग 49 प्रतिशत आबादी तक है। डीडी नेशनल और डीडी न्यूज चैनल की क्षेत्रवार पहुंच क्रमशः 81 प्रतिशत और 26 प्रतिशत है।

राज्यवार ट्रांसमीटरों की संख्या अनुलग्नक–II में दी गई है।

उपग्रह संचार के लिए दूरदर्शन ने एमपीईजी–2 और एमपीईजी–4 कम्प्रेशन तकनीकों वाले डीवीबी–एस और डीवीबी–एस2 मानक अपनाए हैं। वर्तमान समय में दूरदर्शन 34 उपग्रह चैनलों का परिचालन कर रहा है। इनकी ब्योरा अनुलग्नक–III में दिया गया है।

पिछले वर्षों के दौरान डीडी नेटवर्क का विकास नीचे दर्शाया गया है :

njn'ku uVodl dk fodkl

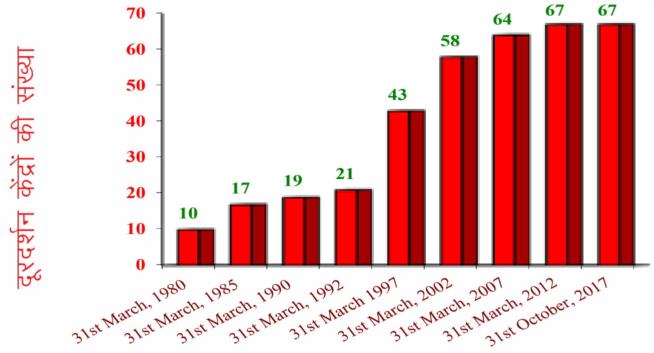

njn'ku VkalehVjksa dk fodkl

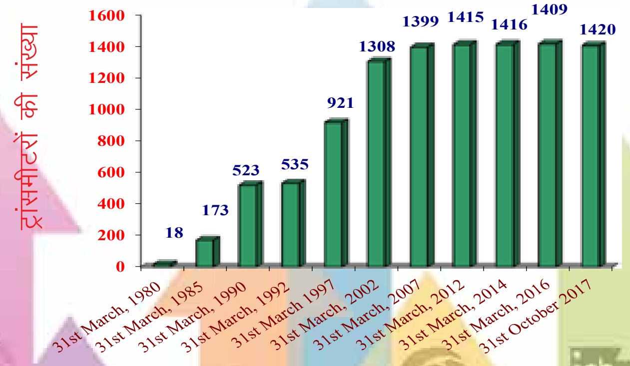

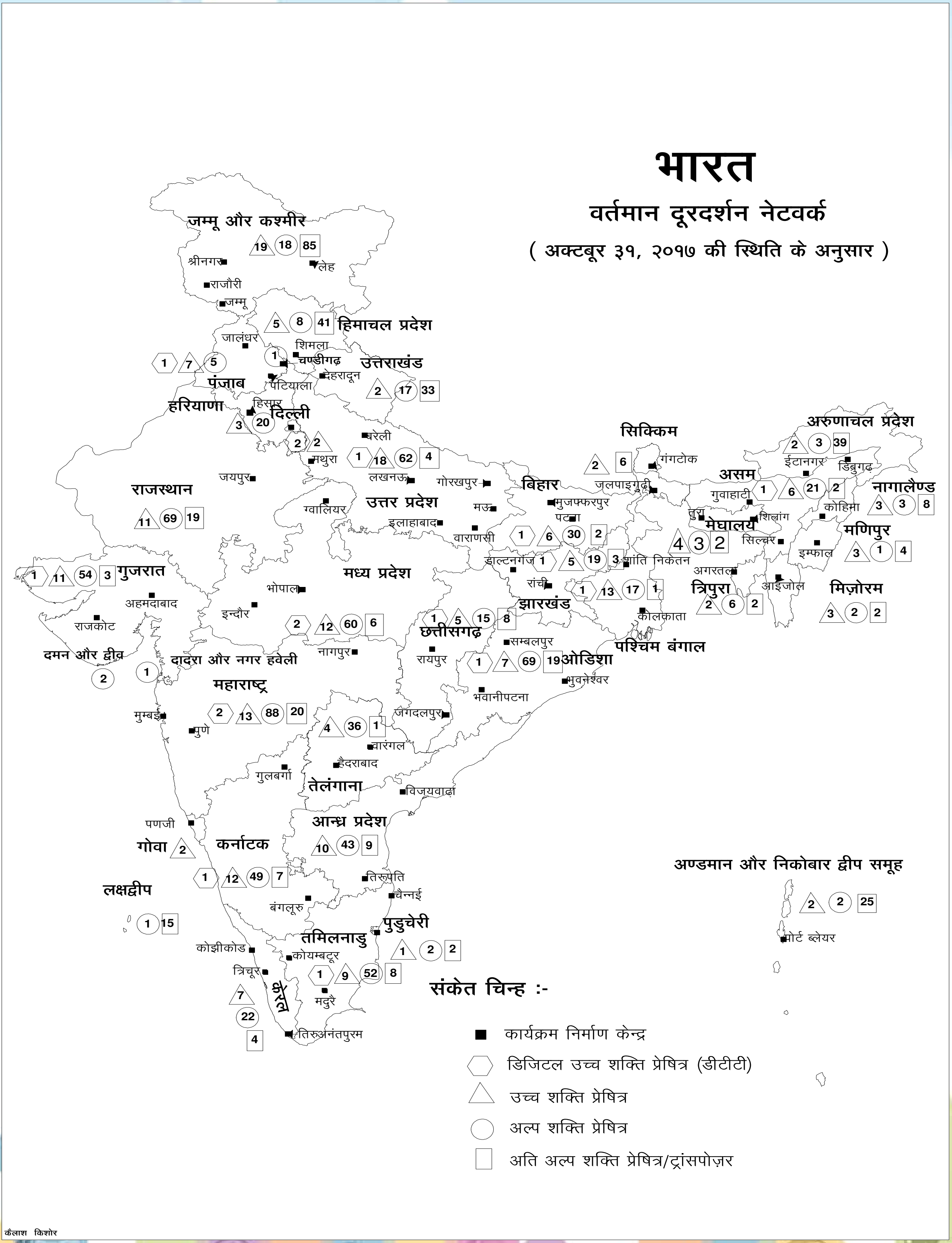
भारत
वर्तमान दूरदर्शन नेटवर्क
(अक्टूबर ३१, २०१७ की स्थिति के अनुसार)
जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर
लेह
राजौरी
जम्मू
हिमाचल प्रदेश
जालंधर
शिमला
चण्डीगढ़
उत्तराखंड
देहरादून
पंजाब
पटियाला
हरियाणा
हिसार
दिल्ली
बरेली
मथुरा
जयपुर
लखनऊ
गोरखपुर
राजस्थान
ग्वालियर
उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद
मऊ
वाराणसी
बिहार
मुजफ्फरपुर
पटना
सिक्किम
गंगटोक
जलपाइगुड़ी
अरुणाचल प्रदेश
ईटानगर
डिब्रूगढ़
असम
गुवाहाटी
नागालैण्ड
कोहिमा
तुरा
मेघालय
शिलांग
सिल्चर
मणिपुर
इम्फाल
डाल्टनगंज
शांति निकेतन
अगरतला
त्रिपुरा
आईजोल
मिज़ोरम
गुजरात
अहमदाबाद
राजकोट
भोपाल
मध्य प्रदेश
इन्दौर
रांची
झारखंड
कोलकाता
पश्चिम बंगाल
छत्तीसगढ़
सम्बलपुर
दमन और द्वीव
दादरा और नगर हवेली
नागपुर
रायपुर
ओडिशा
भुवनेश्वर
भवानीपटना
महाराष्ट्र
मुम्बई
पुणे
जगदलपुर
वारंगल
हैदराबाद
गुलबर्गा
तेलंगाना
विजयवाड़ा
पणजी
गोवा
कर्नाटक
आन्ध्र प्रदेश
लक्षद्वीप
तिरुपति
चैन्नई
बंगलूरु
पुडुचेरी
तमिलनाडु
कोझीकोड
कोयम्बटूर
त्रिचूर
केरल
मदुरै
तिरुअनंतपुरम
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह
पोर्ट ब्लेयर
संकेत चिन्ह :-
कार्यक्रम निर्माण केन्द्र
डिजिटल उच्च शक्ति प्रेषित्र (डीटीटी)
उच्च शक्ति प्रेषित्र
अल्प शक्ति प्रेषित्र
अति अल्प शक्ति प्रेषित्र/ट्रांसपोज़र
कैलाश किशोर

Ikeq[k rduhdh mUu;u

इस वर्ष की विशिष्ट विकास गतिविधियां रहीं :

1) 39 स्टूडियो केंद्रों का डिजिटलीकरण संपन्न।

2) सीपीसी, दिल्ली में मल्टीचैनल ऑटोमेटेड प्लेबैक सुविधा तैयार।

3) डीडीके, इटानगर के लिए ऑटोमेटेड प्लेबैक सुविधा डीडी–अरुण प्रभा का आरंभ।

4) सीपीसी, दिल्ली में एचडीटीवी फॉर्मेट संपन्न मल्टी कैमरा स्टूडियो प्रोडक्शन सुविधा की स्थापना।

प्रमुख परियोजनाएं जिनकी मौजूदा वित्तीय वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है :

1) श्रीनगर, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम में डिजिटल ट्रांसमीटरों की स्थापना।

2) डीडी न्यूज में नए एकीकृत न्यूज ऑटोमेशन सिस्टम का आधुनिकीकरण।

3) 9 स्थानों पर न्यू डिजिटल सेटेलाइट न्यूज संग्रहण (डीएसएनजी)।

4) दिल्ली में मल्टी कैमरा मोबाइल एचडी प्रोडक्शन।

fu%'kqYd MhVh,p ^MhMh Ýh fM'k*

दिसंबर 2004 में दूरदर्शन ने अपनी 33 टीवी चैनलों वाली निःशुल्क डीटीएच सेवा 'डीडी फ्री डिश' (पूर्व में डीडी डायरेक्ट प्लस) की शुरुआत की थी। डीटीएच के सिग्नल देश में छोटे आकार की डिश इकाइयों की मदद से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के अलावा अन्य सभी स्थानों पर प्राप्त किए जा सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सितंबर 2009 से 10 चैनलों वाली सी.बैंड डीटीएच सेवा की शुरुआत की गई थी। मौजूदा समय में डीटीएच मंच पर 80 टीवी चैनल उपलब्ध हैं जिनकी संख्या इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित इंडियन कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (आईस.ीएएस) के बाद 104 तक पहुंच जाएगी।

भारतीय एसटीबी ओईएम की सूची में शामिल करने के लिए, दूरदर्शन ने देशभर में निःशुल्क डीडी डिश डीटीएच सेवा प्राप्ति के लिए आईसीएएस युक्त एसटीबी के निर्माण और बिक्री के लिए एसटीबी ओईएम को मंजूरी दी है।

इसके बाद डीडी के डीटीएच प्लेटफॉर्म में और अधिक सुधार कर उसे 250 टीवी चैनलों तक बढ़ाने पर कार्य किया जा रहा है। 01/11/2017 तक डीडी निःशुल्क डिश चैनलों के संबंध में संक्षिप्त ब्योरा संलग्नक–IV में दिया है।

LFkyh; Vkaleh Vjksa dk fMftVhdj.k

दूरदर्शन के स्थलीय ट्रांसमीटर नेटवर्क अधिकांशतः एनालॉग ट्रांसमीटरों से युक्त हैं जिनमें से प्रत्येक 7 मेगाहर्ट्ज पर वीएचएफ बैंड के लिए या यूएचएफ बैंड के लिए 8 मेगाहर्ट्ज पर पीएएल–बी और पीएएल–जी स्तर पर एक कार्यक्रम का प्रसारण करता है।

नई तकनीकों के आगमन के साथ, डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन (डीटीटी) का इस्तेमाल करने वाले एक ट्रांसमीटर के साथ कई टीवी चैनलों का प्रसारण संभव हो सकेगा। डीटीटी उच्च स्तरीय चैनलों के प्रसारण में सहायक होता है जिन्हें टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, टेब्लेट्स आदि विभिन्न उपकरणों पर प्राप्त किया जा सकता है।

डीडी ने अपने स्थलीय नेटवर्क के डिजिटलीकरण के लिए डीवीबी.टी2 मानक को अपनाने का फैसला किया है जिसके जरिये सेवाओं में कुशलता, मजबूती और लचीलापन आ सकेगा। दुनियाभर में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न डिजिटल टीवी मानकों का ब्योरा चित्र 1 और चित्र 2 में दिया गया है।

fp= 1% MhVhVh ekud vkj n'kk dh l[;k

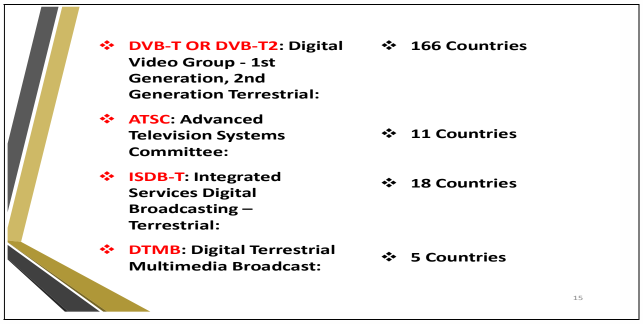

fp= 2% MhVhVh

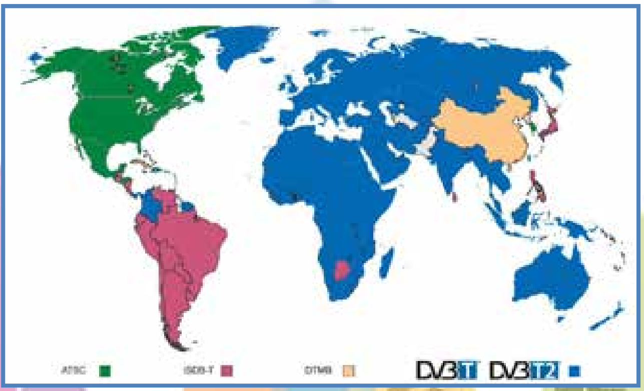

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से संबोधन का दूरदर्शन द्वारा प्रसारण

दूरदर्शन विभिन्न शहरों और कस्बों में चरणबद्ध तरीके से 63 डीटीटी ट्रांसमीटरों की स्थापना कर रहा है। पहले चरण में 16 डीटीटी ट्रांसमीटर्स दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पटना, अहमदाबाद, रायपुर, लखनऊ, भोपाल, गुवाहाटी, इंदौर, बंगलुरु, जालंधर, रांची, कटक और औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में फरवरी 2016 को स्थापित किए गए जिनके जरिये 5 डीडी चैनल, डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, डीडी भारती, डीडी स्पोर्ट्स और डीडी किसान/प्रादेशिक चैनल प्रसारित किए गए। हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम और श्रीनगर में कुछ समय में 3 और डीटी.टी ट्रांसमीटरों की शुरुआत की जाएगी। चार महानगरों में दूसरा मल्टीप्लेक्स स्थापना के लिए तैयार है। अगले चरण में 44 डीटीटी ट्रांसमीटर्स स्थापित किए जा रहे हैं। 63 शहरों में चालू किए जाने के बाद देश की 44 प्रतिशत आबादी और 31 प्रतिशत क्षेत्र को डिजिटल प्रसारण मिलने की संभावना है। 63 डीटीटी ट्रांसमीटरों का स्थान अनुलग्नक–ट में दर्शाया गया है।

मौजूदा समय में एनालॉग ट्रांसमीटरों द्वारा टीवी कवरेज क्षेत्र की बराबरी करने के लिए दूरदर्शन देश में 630 स्थानों पर डीटीटी ट्रांसमीटरों की स्थापना करने की योजना बना रहा है।

हाई डेफिनिशन टीवी (एचडीटीवी)

वर्ष 2007 में एचडीटीवी से संबंधित एक प्रायोगिक परियोजना के साथ दूरदर्शन ने एचडीटीवी की ओर यात्रा शुरू की थी। इसके साथ ही दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक फील्ड प्रोडक्शन (ईएफपी) वैन और एचडीटीवी इंग कैम्कॉर्ड्स और एडिट सुईट उपलब्ध हुई थी। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान एचडी ईएफपी वैन का व्यापक इस्तेमाल हुआ था।

योजना से जुड़ी नीतियों के अनुसार, सीपीसी, दिल्ली में एचडीटीवी फॉर्मेट की मल्टी कैमरा स्टूडियो प्रोड.क्शन सुविधाओं को स्थापित किया गया है। चेन्नई और कोलकाता में एचडीटीवी स्टूडियो सुविधाएं और दिल्ली में एचडीटीवी फॉर्मेट में मल्टी कैमरा मोबाइल प्रोडक्शन सुविधा अमल में लाई जा रही है। डीडीके, दिल्ली में एचडीटीवी अपलिंकिंग सुविधा मौजूद है।

मानव संसाधन विकास

दिल्ली और भुवनेश्वर में दो कैम्पस वाला नेशनल एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीमीडिया, एनएबीएम (पूर्ववत स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एसटीआई (टी) के बतौर जाना जाने वाला) प्रसार भारती का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है जो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण कर्मियों

को प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। शिलांग में भी इसकी एक स्थानीय अकादमी है और आरएबीएम, मलाड में भी यह सीमित प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराता है।

अकादमी एशिया प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न देशों के रे. डियो और टेलिविजन अभियांत्रिकी कर्मियों के लिए, एशिया पेसेफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (एआईबीडी) और एशिया पेसेफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (एबीयू) के साथ मिलकर प्रशिक्षण/वर्कशॉप आयोजित करता है।

दूरदर्शन के कर्मियों के लिए निम्न विशेष कोर्स/सेमिनारों का आयोजन किया जाता है।

1. सोलर फोटो वोल्टेक पावर जेनरेशन : एनपीसी चेन्नई में डिजाइन, इंस्टॉलेशन एंड चेलेंजेस।

2. यूएए नैनीताल में वरिष्ठ अफसरों के लिए कार्यकारी विकास कार्यक्रम।

3. एमसीएफ हासन में उपग्रह संचार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

od'kki %

1. एनएबीएम दिल्ली में जियो–स्पेशियल मैनेजमेंट।

2. एनएबीएम दिल्ली में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और जीएसटी।

3. एनएबीएम भुवनेश्वर में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और जीएसटी।

अप्रैल 2017 से अक्तूबर 2017 तक दूरदर्शन के करीब 446 इंजीनियरिंग अफसरों को 35 प्रशिक्षण कोर्सेज में ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान 'ईजीनियरिंग छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण' और एमटीएस की परीक्षा–पूर्व प्रशिक्षण के लिए 37 प्रत्याशियों ने भाग लिया।

नेटवर्क में नवीन उपकरणों को शामिल किए जाने के लिए उपकरण निर्माताओं द्वारा विभिन्न ए/टी के विपरीत मौजूदा वित्तीय वर्ष में लगभग 37 इंजीनियरिंग अफसरों को प्रशिक्षित किया गया है।

vrjk"Vh; lEeyu@,ch; dk;'kkyk,

2017–18 (अक्तूबर, 2017 तक) के दौरान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/एबीयू वर्कशॉप्स में दूरदर्शन अधिकारी शामिल हुए :

1) कोलम्बो, श्रीलंका में 4 अप्रैल, 2017 से 5 अप्रैल, 2017 तक एबीयू टेक्निकल ब्यूरो मिड–ईयर मीटिंग।

2) लास वेगास में 22 अप्रैल, 2017 से 27 अप्रैल, 2017 तक एनएबी शो 2017 कॉन्फ्रेंस/प्रदर्शनी।

3) सिंगापुर में 23 मई, 2017 से 25 मई, 2017 तक ब्रॉडकास्ट एशिया 2017।

4) आरएआई एमस्टर्डम में 14 सितंबर, 2017 से 19 सितंबर, 2017 तक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग कन्वेंशन (आईबीसी)–2017।

5) चेंग्दू, चीन में 31 अक्तूबर, 2017 से 04 नवंबर, 2017 तक एबीयू जनरल असेंबली एंड एसोसिएटेड मीटिंग्स।

6) क्वालालम्पुर, मलेशिया में 04 दिसंबर, 2017 से 08 दिसंबर, 2017 तक चौथी एबीयू रीजनल वर्कशॉप ऑन इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स फॉर ब्रॉडकास्टर्स।

31.03.2018 तक विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा निम्न अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस/एबीयू वर्कशॉप्स आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

1. क्वालालम्पुर, मलेशिया में 05 मार्च, 2018 से 08 मार्च, 2018 तक एबीयू डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग सिम्पोजियम।

fof'k"V vk;kstuk dh doj t

ओबी/ईएफपी वैनों द्वारा 2017–18 (31 अक्तूबर, 2017 तक) के दौरान दूरदर्शन ने लगभग 150 आयोजनों को कवर किया। इसके अलावा, 31 मार्च, 2018 तक 15 बड़े आयोजनों को कवर करने का प्रस्ताव है। दूरदर्शन द्वारा विशिष्ट आयोजनों की कवरेज/प्रस्तावित कवरेज का ब्योरा संलग्नक–VI में दिया गया है।

MhMh u'kuy & ie[k puy

देश के प्रथम और प्रमुख सार्वजनिक सेवा प्रसारक के तौर पर डीडी नेशनल मनोरंजन, सूचना और शिक्षा का समुचित संतुलन प्रस्तुत करता है और इसकी सेवाएं प्रातः 05:30 से मध्यरात्रि तक स्थलीय मोड पर उपलब्ध रहती हैं। सेटेलाइट मोड पर इसका प्रसारण चौबीस घंटे उपलब्ध रहता है।

प्रमुख आयोजनों का सीधा प्रसारण डीडी नेशनल की प्रमुख विशेषताओं में से है। वर्ष 2017 के दौरान, डीडी नेशनल पर देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया गया। ये कार्यक्रम सरकार की प्रमुख योजनाओं से जुड़े थे। इसके अलावा, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय महत्व के आयोजन, महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों (जैसे स्वामी विवेकानंद, बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल, पं. दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख) की जयंतियां/पुण्यतिथियां, सतर्कता

अभियान और राष्ट्रीय एकता दिवस आदि का प्रसारण भी समुचित महत्व के साथ इस दौरान डीडी नेशनल पर किया गया।

डीडी नेशनल सामाजिक महत्व कार्यक्रम और संचारी रोगों की रोकथाम एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य जागरूकता संदेशों का निरंतर प्रसारण पर किया गया।

डीडी नेशनल पर महत्वपूर्ण खेल आयोजनाओं का भी प्रसारण किया गया जिनमें एकदिवसीय क्रिकेट मैच, अंडर–17 फीफा वर्ल्ड कप (फुटबॉल), विम्बलडन के महिला एवं पुरुष मैच आदि शामिल हैं।

प्रधानमंत्री का संबोधन मन की बात का प्रसारण भी डीडी नेशनल पर किया गया और उसके प्रादेशिक भाषा में अनुवाद भी स्थानीय केंद्रों से प्रसारित किए गए।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, स्टूडियो में मौजूद पैनलिस्टों और देश भर के विभिन्न केंद्रों के सहयोग से दिन भर चलने वाले 'टॉकाथन' कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। सेवा दिवस (17 सितंबर, 2017) और काला धन विरोधी दिवस (08.11.2017) के दौरान देश भर से प्राप्त ताजा रिपोर्टों के आधार पर पैनलिस्टों द्वारा टॉका. थन कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया गया था।

दूरदर्शन ने जीएसएलवी एमके III–डी1/जीसेट–19, पीएसएलवी–सी38/कार्टोसेट–2 सीरीज सेटेलाइट और जीसेट–17 सेटेलाइट के छोड़े जाने के सीधे प्रसारण के लिए आईएसआरओ के साथ व्यापक प्रबंध किए थे।

डीडी नेशनल ने आईएफएफआई–2017 (गोवा) की भी विस्तृत कवरेज की। आईएफएफआई पर आधारित 42 कड़ियों का विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किया गया था।

13 नवंबर, 2017 से 28 नवंबर, 2017 तक 16 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के एक विशेष पैकेज का भी आयोजन किया गया था।

बीबीसी के सहयोग से यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित किशो. रों के लिए एक शो 'आधा फुल', भारत की बाल चित्र समिति द्वारा बच्चों के लिए एक जासूसी धारावाहिक 'वी–3', ड्यूश वैले (जर्मन टीवी) के सहयोग से निर्मित 'मंथन' और सीसेम वर्कशॉप ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित बच्चों का शो 'गली गली सिम सिम' भी इस दौरान डीडी नेशनल पर प्रसारित किए गए।

वर्ष का समापन 31 दिसंबर, 2017 को डीडीके मुंबई द्वारा नववर्ष कार्यक्रम के प्रसारण के साथ हुआ। प्रादेशिक केंद्रों ने अपनी भाषाओं में नववर्ष कार्यक्रमों का प्रसारण किया।

किशोरों के लिए 'आधा फुल' शो का दूरदर्शन प्रसारण

2018 d fy, ;kstuk,

- डीडी नेशनल ने अपने दर्शकों के लिए नवाचारी इन–हाउस प्रोडक्शन, ब्लॉकबस्टर प्रदर्शित में शामिल करने और सामाजिक तौर पर प्रासंगिक संदेशों के उचित सम्मिश्रण का प्रस्ताव रखा है।
- दर्शनीय और अनुभूतिजन्य, ग्राफिक्स, सेट डिजाइन, प्रोमो और लोगो टेम्प्लेट्स के विकास पर कार्य किया जाएगा।
- प्रसारित सामग्री के दर्शकों में पैठ बनाने के प्रयास और उसके उचित मुद्रीकरण के लिए समर्पित प्रचार अभियान और सोची–समझी बिक्री नीति का प्रस्ताव रखा गया है।
- गणतंत्र दिवस, बीटिंग द रिट्रीट समारोह आदि जैसे प्रमुख आयोजनों का प्रसारण किया जाएगा।

fQYe

2017–18 के दौरान दूरदर्शन महानिदेशालय के फिल्म संभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियां:

डीडी नेशनल पर प्रति सप्ताह शुक्रवार, शनिवार और रविवार को 4 हिन्दी फीचर फिल्में प्रसारित की जाती थीं। रविवार को 2 फिल्में दोपहर 12 बजे और रात्रि 9 बजे प्रसारित होती थीं। अब सप्ताह में प्रत्येक दिन प्राइम टाइम बैंड पर हिन्दी फिल्में प्रसारित की जाएंगी। अब प्रति सप्ताह 8 हिन्दी फिल्मों का प्रसारण होता है। नतीजतन, दर्शकों की संख्या और जीवीएल (दर्शकों की सकल संख्या लाख में) रेटिंग और दूरदर्शन के नेशनल नेटवर्क प्राइम टाइम पर अन्य कार्यक्रमों की अपेक्षा दर्शक अधिक समय बिताते हैं।

विशिष्ट दिवसों पर निम्न विशेष फिल्मों का प्रसारण किया गया :

1) 15 अगस्त, 2017 (स्वतंत्रता दिवस विशेष) – 'पिंक', 'एयरलिफ्ट' और 'बजरंगी भाईजान'।

2) 17 सितंबर, 2017 को सभी निजी चैनलों से पहले, पहली बार टेलिविजन पर स्वच्छ भारत विषय पर 'टॉयलेट एक प्रेम कथा' का प्रसारण किया गया।

3) 2 अक्तूबर 2017 (गांधी जयंती) – 'गांधी से महात्मा तक'।

4) 31 अक्तूबर 2017 (सरदार पटेल जन्मतिथि) – 'सरदार'।

5) 13 से 28 नवंबर, 2017 के दौरान आयोजित भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के संबंध में 16 फिल्मों का प्रसारण में किया गया। ये फिल्में आईएफएफआई ब्लॉकबस्टर्स के तौर पर प्रोत्साहित की जा रही हैं।

6) 06/12/2017 को बाबासाहेब बी. आर. अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर एक फीचर फिल्म का प्रसारण किया गया।

विभिन्न प्रायोजकों/निर्माताओं ने अपनी सर्वश्रेष्ठ फिल्में दूरदर्शन को देने का प्रस्ताव रखा। रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, सांस्कृतिक समारोहों, राष्ट्रीय समारोहों जैसे विविध विषयों पर फिल्मों को प्रसारण किया गया। सार्वजनिक सेवा प्रसारक के तौर पर सामाजिक, देशभक्ति और प्रेरणाप्रद विषयों पर भी फिल्में प्राप्त की गई और दिखाई गईं। दूरदर्शन के फिल्म विंग ने निर्माताओं/प्रायोजकों को सुनने के लिए मुक्त द्वार नीति अपनाई। टीआरपी बढ़ाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं परिणामस्वरूप जीवीएल में लगातार निम्नानुसार सुधार हुए हैं:

1 flrcj] 2017 rd fQYek dh th oh ,y dk vkl r

Ok"kZ	2015	2016	2017
शुक्रवार हाउसफुल स्लॉट	5.9	7.4	9.4
शनिवार जुबली स्लॉट	5.9	7.9	9.2
रविवार ब्लॉकबस्टर्स स्लॉट		8.5	9.1

(स्रोत: बीएआरसी)

सप्ताह के अन्य दिनों में फिल्मों की जीवीएल 8 से 17 के बीच है।

भावी योजनाओं के मद्देनजर, डीडी फिल्म विंग न्यूनतम

सद्गुरु के साथ आज सवेरे कार्यक्रम

शुल्क के आधार पर (अन्य निजी चैनलों की तुलना में) अपने दर्शकों को सर्वश्रेष्ठ फिल्में दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है।

MhMh U;wt

दूरदर्शन न्यूज (डीडी न्यूज) देश का एकमात्र स्थलीय सह–सेटेलाइट तथा बहुभाषायी न्यूज चैनल है। इसकी सेवाएं नॉन–केबल, नॉन–सेटेलाइट घरों में भी स्थलीय प्रसारण प्रणाली से पहुंचती हैं।

दूरदर्शन की नियमित समाचार सेवा 15 अगस्त, 1965 से शुरू हुई थी। यह सेवा हिन्दी समाचार बुलेटिन के रूप में शुरू हुई थी। पहला अंग्रेजी बुलेटिन 3 जुलाई, 1971 को शुरू हुआ। पृथक चैनल के तौर पर डीडी न्यूज की शुरुआत 3 नवंबर, 2003 को हुई थी। डीडी मेट्रो चैनल को बदलकर 24 घंटे के समाचार चैनल के तौर पर इसे शुरू किया गया था।

डीडी न्यूज का मुख्यालय दिल्ली में है जहां से हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू तथा संस्कृत भाषाओं में समाचार प्रसा. रित होते हैं। इसके अलावा, मूक.बधिरों के लिए भी दो विशिष्ट बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं। इन भाषाओं में प्रतिदिन 40 समाचार बुलेटिनों का प्रसारण होता है जि. सकी सेवाओं का सीधा प्रसारण प्रतिदिन 18.5 घंटे होता है।

डीडी न्यूज प्रतिदिन तीन मेट्रो आरएनयू (रीजनल न्यूज यूनिट्स) भी प्रायोजित करता है जिनका प्रसारण मेट्रो स्कैन शीर्षक के अंतर्गत होता है। चैनल प्रतिदिन तीन खेल बुलेटिन, दो बिजनेस शो और कई समसामयिक विषयों के कार्यक्रम भी प्रसारित करता है।

Lkekpkj laxg.k

डीडी न्यूज में देशभर के दूर.दराज क्षेत्रों से उपग्रह आधारित तकनीक के आधार पर समाचार प्राप्त होते हैं। समाचार संग्रहण में डिजिटल न्यूज संग्रहण (डीएसएनजी) वाहन/ओबी वैन्स और फाइल इंटरनेट/सेल्युलर मोबाइल आधारित तकनीकें जैसे कि टीयूवी बैकपैक्स और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स (एफटीपी) का भी सहयोग रहता है। डीडी न्यूज अपने अधिकांश समाचार निम्न स्रोतों से प्राप्त करता है :

–मुख्यालय और आरएनयूज़ के अपने संवाददाताओं द्वारा

–स्ट्रिंगर्स और अंशकालिक संवाददाताओं द्वारा

–एजेंसियां (पीटीआई, यूएनआई, रॉयटर्स, एएनआई)

–अंतरराष्ट्रीय सहभागियों (उदाहरणार्थ अन्य नेशनल ब्रॉडकास्टर्स, एशिया विजन) द्वारा।

Ikeq[k gkfy;k 'kq#vkr@dojst@xfrfof/k;ka %

डीडी न्यूज ने 1 अप्रैल 2017 से 30 अक्तूबर 2017 की अवधि के बीच माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित/भाग लिए गए सभी राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय आयोजनों को कवर किया। दूरदर्शन अपनी टीमों को ऐसे सभी स्थानों पर भेजता है जहां कोई प्राकृतिक आपदा अथवा संघर्ष की स्थिति बनी हो, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में रेल दुर्घटना को कवर किया गया था और जनता लाभार्थ हेल्पलाइन नंबर प्रसारित करने जैसी सेवाएं दी गई थीं। एनडीआरएफ तथा अन्य राहत एजेंसियों, सरकारों और आमजन द्वारा किए जाने वाले कार्यों की खबरें भी प्रसारित की गई।

Mk;ykWx@MhMh U;wt

एनडीए सरकार के तीन वर्ष पूरे होने अवसर पर डीडी न्यूज ने पांच घंटे के कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसका शीर्षक था 'डायलॉग/डीडी न्यूज'। इन कार्यक्रमों में उपस्थित केंद्रीय मंत्रियों ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए।

सरकार के तीन साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम

Tkh,lVh ls tqMh dojst

सरकार ने 1 जुलाई, 2017 से देशभर में जीएसटी लागू करने का निर्णय लिया गया था जिसे डीडी न्यूज ने व्यापक कवरेज दी।

ladYi fnol %

9 अगस्त 2017 को डीडी न्यूज ने देश के विभिन्न अंचलों में मनाए जा रहे संकल्प दिवस और भारत छोड़ो अभियान पर दिन भर का विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया।

Uk, Hkkjr dh ladYiuk %& ladYi ls flf)

डीडी न्यूज ने डीडी नेशनल द्वारा 15 अगस्त, 2017 पर निर्मित विशेष कार्यक्रम 'संकल्प से सिद्धि' का प्रसारण किया था जिसमें लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री का

भाषण और नया भारत विषय पर देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित विमर्श शामिल थे। इसके अलावा, देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष की उत्सव किए गए पर भी कार्यक्रम प्रसारित।

,d Hkkjr & J"sB Hkkjr

डीडी न्यूज ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया।

प्रधानमंत्री का 'मन की बात' कार्यक्रम संस्कृत और संकेत भाषा में :

डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम 'मन की बात' की शुरुआत संस्कृत और संकेत भाषा में की जिसे डीडी भारती से प्रसारित किया जाता है।

gFkdj?kk fnol

डीडी न्यूज ने 7 अगस्त, 2017 को हथकरघा दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण किया।

प्रतिदिन, साप्ताहिक और पाक्षिक तौर पर प्रसारित होने वाले अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम :

- चर्चा में – ज्वलंत मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम।
- आमने–सामने – बृहस्पतिवार सायं 10 बजे परिचर्चा आधारित हिन्दी कार्यक्रम।
- जेन नेक्स्ट – युवाओं और किशोर दर्शकों के लिए हिन्दी कार्यक्रम।
- रंग–तरंग – हिन्दी में प्रसारित मनोरंजक कार्यक्रम।
- जानने का हक – सूचना के अधिकार पर आधारित हिन्दी कार्यक्रम।
- सिनेमा इस हफ्ते में हालिया फिल्मों की समीक्षा और उन पर लोगों की प्रतिक्रिया दिखाई जाती है।
- तेजस्विनी में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों पर रोशनी डाली जाती है।
- सीधा संवाद में विभिन्न क्षेत्रों की जानी–मानी हस्तियों का साक्षात्कार लिया जाता है।
- जनादेश : डीडी न्यूज में 5 राज्यों के चुनावों का व्यापक कवरेज किया गया।
- डीडी न्यूज में साप्ताहिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय खबरों पर अंग्रेजी में वर्ल्ड कनेक्ट प्रोग्राम का प्रसारण किया जाता है।
- डीडी न्यूज में साप्ताहिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय खबरों पर हिन्दी में खबर दुनिया की कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है।
- संस्कृत में साप्ताहिक तौर पर 30 मिनट अवधि का कार्यक्रम वार्तावली का प्रसारण होता है।

rduhdh volajpuk

दिल्ली में चौबीस घंटे समाचार चैनल का राष्ट्रीय समाचार कक्ष और दो स्टूडियो हैं। इन्हें अत्याधुनिक क्वांटेल ऑटोमेशन सिस्टम और सर्वरों से सुसज्जित किया गया है जिनमें एडिटरों के डेस्क तक नॉन–लीनियर वीडियो एडिट फीचर्स होते हैं। उपग्रह आधारित समाचार संग्रहण के लिए, विभिन्न राज्यों में 16 डीएसएनजी वैन तैनात किए गए हैं। उन स्थानों पर मोबाइल–कनेक्टिविटी आधारित बैकपेक उपकरण भी तैनात किए गए हैं जहां डीएसएनजी वैन मौजूद या तैनात नहीं हैं।

डीडी न्यूज हिन्दी/अंग्रेजी में डीडी नेशनल चैनल पर 15 मिनट अवधि के पांच बुलेटिन प्रसारित करता है। डीडी न्यूज डीडी उर्दू के लिए 10 लाइव बुलेटिन और न्यूज स्क्रॉल्स भी तैयार करता है। किसान चैनल की शुरुआत के साथ ही, डीडी न्यूज ने किसानों के हितों के बारे में समाचार देने वाले दो बुलेटिनों की शुरुआत की है।

Lkekpkj vkSj lks'ky ehfM;k ls lacaf/kr MhMh U;wt

सोशल मीडिया पर न्यूज चैनल का एक फेसबुक पेज है, साथ ही, हिन्दी और अंग्रेजी में ट्विटर हैंडल और एक यूट्यूब चैनल भी है। डीडी न्यूज की वेबसाइट http://ddnews.gov.in है, जिसमें सितंबर, 2013 को वीडियो देखने की सुविधा शुरू की गई थी। मौजूदा दौर में, नया रूप और आभास देने वाली वेबसाइट को जुलाई, 2017 में पुनः शुरू किया गया था।

डीडी न्यूज का अंग्रेजी ट्विटर हैंडल '/डीडीन्यूज लाइव' जनवरी, 2013 को शुरू किया गया था और 31.10.2017 तक इसके फॉलो करने वालों की संख्या 20 लाख तक पहुंच गई थी जिसमें अभी भी वृद्धि हो रही है। हिन्दी में एक नया ट्विटर हैंडल /डीडीन्यूजहिन्दी की शुरुआत जनवरी 2014 में की गई थी जिसके 3 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। डीडी न्यूज का फेसबुक पेज https://www.facebook.com/DDNews के 15 लाख से अधिक फा. ॅलोअर्स हैं। यूट्यूब पर एक चैनल https://www.youtube.com/user/DDNewsofficial की शुरुआत फरवरी, 2013 को की गई थी जिसके 3.10 लाख से अधिक ग्राहक हैं।

डीडी न्यूज की मोबाइल एप लोगों को उनकी उंगलियों के इशारे पर खबरें और समसामयिक सूचनाएं उपलब्ध कराती है। इस एप का नया स्वरूप मार्च, 2017 को लांच किया गया था।

Ikzknsf'kd lekpkj bdkb;ka

देश भर में डीडी न्यूज की 31 प्रादेशिक समाचार

इकाइयां/ब्यूरो हैं जो प्रादेशिक दूरदर्शन केंद्रों से संचालित होते हैं। यह अधिकांशतः राज्यों के मुख्यालयों में स्थित होते हैं। यह आरएनयू एक दिन में 23 भाषाओं/बोलियों में 174 बुलेटिन और 8 समसामयिक मुद्दों के कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इनका प्रतिदिन का संयुक्त प्रसारण समय 33 घंटे और 10 मिनट का है।

ngjknu MhMhd dk vkj,u; e lekpkj dh 'k#vkr

देहरादून डीडीके के आरएनयू की स्थापना और उसका औपचारिक उद्घाटन 29 जून, 2017 को तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री वैंकेया नायडू ने किया था। यहां से प्रतिदिन स्थलीय मोड में सायं 6.30 से 6.45 तक एक बुलेटिन प्रसारित किया जाता है। इसे 15 जुलाई, 2017 को डीडी उत्तर प्रदेश के सहयोग से प्रतिदिन सायं 20.00 से 20.15 सेटेलाइट मोड से जोड़ा गया।

इटानगर (अरुणाचल प्रदेश) से प्रतिदिन बुलेटिन एकत्र किए जाने की प्रक्रिया भी संपन्न हुई और अब यहां से डीडी अरुण प्रभा चैनल की औपचारिक शुरुआत का इंतजार है।

MhMh&Hkkjrh

डीडी भारती की शुरुआत 26 जनवरी, 2002 को हुई थी और नवंबर 2010 में इसे संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं जीवनशैली के विशिष्ट चैनल के तौर पर पुनः आरंभ किया गया। इसकी पहुंच और दर्शक संख्या बढ़ाने के लिए देश भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के आधार पर इसकी अंग्रेजी कवरेज (लगभग 115 कार्यक्रमों का टेलीकास्ट) को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस अरसे के दौरान डीडी भारती ने 75 से अधिक कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया है।

इस दौरान डीडी भारती पर प्रसारित किए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम :– मौसिकी एक खोज, उत्तर कथा, गोरा, बूंद और समुद्र, टैगोर की कविता (त्रयोदशी), भारत की चित्रकला और स्थापत्य, शिवानी लिखित कृष्ण कली (निर्देशनःश्री अमोल पालेकर), ये है इंडिया मेरी जान – ट्रैवल शो, रचित उत्तररामचरितम :–एक संस्कृत धारावाहिक, भारत के किले, एक प्रेम कथा :– बासु चटर्जी की लघु प्रेम कथाओं पर निर्मित धारावाहिक, तहरीर – मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यासों गोदान और निर्मला पर आधारित धारावाहिक, नाच्यो बहुत गोपाल :– पद्म. भूषण अमृतलाल नागर के उपन्यास पर धारावाहिक, मेरा स्टूडियो मेरा मेहमान :– प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट स्व. श्री सुधीर तैलंग की अंतिम श्रंखला, नाद भेद – भारतीय शास्त्रीय संगीत पर पहला रियलिटी शो, लौह पुरुष – व्यक्तित्व और कृतित्व :– सरदार वल्लभभाई पटेल पर एक विशेष कार्यक्रम (इन–हाउस प्रोग्राम), जरा याद करो कुर्बानी :– देशभक्ति पर विशेष कवि सम्मेलन (इन–हाउस प्रोग्राम), होली के सुरीले रंग, मां दुर्गा :– नवरात्र पर डॉ. चंदना राऊल द्वारा उड़िया नृत्य नाटिका, 15 अगस्त, 2017 को प्रसारित, अंतरराष्ट्रीय श्याम–बैंड की राष्ट्रभक्ति की धुनों पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम संकल्प से सिद्धि तक।

Hkfo"; dh dk;uhfr

डीडी भारती कला, संस्कृति, साहित्य और जीवनशैली के क्षेत्रों में शीर्ष कार्यक्रमों का निर्माण और प्राप्ति करने की योजना बना रहा है। इसके लिए वह देश भर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक/सामाजिक/साहित्यिक आयोजनों को कवर करेगा। इसके लिए वह क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के साथ सहभागिता में वहां मौजूद अभिलेखागारों की अकूत संपदा के इस्तेमाल का भी प्रयास कर रहा है। इसके माध्यम से वह प्रमुख कार्यक्रमों को निशुल्क प्राप्त कर सकेगा। चैनल सोशल मीडिया और डिजिटल मंच पर अपनी पहचान बनाने के भी प्रयास कर रहा है।

MhMh&mn

डीडी उर्दू चैनल की शुरुआत 15 अगस्त, 2006 को हुई थी। इसके बाद, 14 नवंबर, 2007 को चैनल की सेवाएं चौबीस घंटे की कर दी गई थीं।

मौजूदा समय में डीडी उर्दू 8 से 9 कार्यक्रमों का निर्माण इन–हाउस कर रहा है। इनके नाम हैं: पते की बात, यादों के दरीचे से, आईना–ए–माज़ी, तालीम और रोजगार, यादें, मुबाहिसा, भुलाये न बने, टीवी रिपोर्ट्स, मुशायरा और पर्व तथा जयंतियों की कवरेज करने वाले ईएनजी के अन्य कार्यक्रम।

इन आयोजनों में प्रमुख हैं : स्वतंत्रता दिवस की

पूर्वसंध्या पर 'हिन्दुस्तान हमारा' नाम से विशेष रिकॉर्डिंग्स, अंतरराष्ट्रीय 'श्याम बैंड' द्वारा 'देशभक्ति संगीत धुनें' नामक वैरायटी शो, 'संकल्प सिद्धि संस्कृति मंथन' नामक साहित्य और कला कार्यक्रम जिसमें विशिष्ट हस्तियां शामिल होती हैं।

अन्य कार्यक्रमों में हैं–1) 'अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्लान ऑफ एनडीए' जिसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं और 2) 'लॉ एंड ऑर्डर – चैलेंजेस एंड कनसर्न्स' जिसमें डॉ. नजमा हेपतुल्ला, श्री फारूख खान आदि कई राज्यपालों का साक्षात्कार प्रसारित होता है।

Hkkoh ;kstuk,

डीडी उर्दू चैनल ड्राइवर के तौर पर 'नए इन–हा. उस कार्यक्रम' प्रस्तुत करने की योजना बना रहा है जिनमें महिला, स्वास्थ्य, कानूनी मुद्दों, पाक कला, संगीत और जानी–मानी हस्तियों के साक्षात्कार आधारित साप्ता. हिक कार्यक्रम होंगे। इन साप्ताहिक कार्यक्रमों के नाम अवामी अदालत, बज्म–ए–ख्वातीन, सेहत हजार नेमत, कानूनी सलाह, नैमत–ए–आलम, ग़ज़ल के सफर, खास मुलाकात, गुफ्तगू आदि होंगे।

इस अवधि के दौरान प्रसारित कार्यक्रमों की सूची :

जीएसटी पर आधारित धारावाहिक 'एक मुल्क एक टैक्स', राम नवमी पर कई विशेष कार्यक्रम, डॉ. बी. आर. आम्बेडकर, सादत हसन मंटो, ऑन रमज़ान, ईद, हज, ईद–उल–जुहा, मुहर्रम, पॉल्यूशन डे, नवरात्र, दशहरा आदि और इसके अलावा, विनोद खन्ना, रीमा लागू, ओम पुरी, मीना कुमारी, शकील बदायूनी, किशोर कुमार, आशा भोंसले आदि पर विशेष कार्यक्रम।

MhMh&bafM;k

डीडी ने 14 मार्च, 1995 को अपने अंतरराष्ट्रीय चैनल की शुरुआत कर दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले थे। 2002 में डीडी–वर्ल्ड का नाम बदलकर डीडी–इंडिया कर दिया गया था। इसमें 16 समाचार बुलेटिन, महत्वपूर्ण घटनाओं पर फीचर्स, मनोरंजक कार्यक्रम, संगीत और नृत्य, धारावाहिक, वृत्तचित्र, समाचार और समसामयिक मुद्दे, घटनाएं और पर्यटन आदि पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं।

भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी व्यापक पहचान बनाने के लिए डीडी–इंडिया ने जीसैट–10 से इनसेट 4–बी के जरिये अपना प्रसारण करना शुरू किया। डीडी इंडिया के कार्यक्रम सबमैरीन केबल, सेटेलाइट और डीटीएच प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से देश भर में केबल के जरिए अधिकांश एमएसओ और टाटा स्काई के डीटीएच प्लेटफॉर्म्स से भी प्रसारित होते हैं। इसके अलावा, फ्री डिश, इन–डिजिटल, हैथवे, एयरटेल डिजिटल टीवी, डिश टीवी, वीडियोकॉन रिलायंस डिजिटल टीवी, डेन केबल आदि से भी डीडी–इंडिया का प्रसारण किया जाता है। चैनल की वैश्विक पहुंच और वितरण को बढ़ाने के लिए नई नीति पर भी कार्य जारी है। 6 कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित अनुबंध किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उप–राष्ट्रपति, संसद आदि से जुड़े सीधे प्रसारण और कार्यक्रमों को भी डीडी–इंडिया पर प्रसारित किया जाता है।

01 अप्रैल, 2017 से आज तक डीडी–इंडिया पर प्रसारित होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार रहे :

काव्य सौरभ, लांच ऑफ इनेबल ट्रेवल, गुड हेल्थ इज़ गुड वेल्थ (विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कार्यक्रम), चेती चांद मेला–2017, जश्न–ए–अदब (कविता उत्सव), 70 ईयर्स ऑफ इंडिया–रशिया डेलिगेशन, स्वागत पर्व, गाते रहो, रशिया इन इंडिया (रूसी संस्कृति पर विशेष), कर्वी भटनागर द्वारा भरतनाट्यम आदि ; द मैन विद ए मिशन – फूलचंद शास्त्री, विज़न दिव्यांग (दिव्यांग जन का होली उत्सव), गांधी विजन ऑफ इंडिया, स्वदेशी मेला – 2017 (टीवी रिपोर्ट), 13वें हॉस्पिटेलिटी इंडिया एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड एनुअल इंटरनेशनल ट्रैवल अवा. ड्र्स–2017, वेलोसिटी ऑफ डार्कनेस, नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ एससी/एसटी ओन्ड एंटरप्राइजेस (एनएसआईसी), ईपीएफओ फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन आदि।

18 निर्माताओं के साथ प्रायोजित श्रेणी के अंतर्गत कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए किए गए समझौते का प्रसारण शुल्क रु. 1,75,54,360/– रहा।

संयुक्त राज्य अमेरिका, लातिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे नए क्षेत्रों में एमएसओ के आपसी समझौतों के जरिए सबमैरीन/केबल लिंक्स के साथ प्रसारण किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

MhMh&LiksV~Zl

2017 डीडी स्पोर्ट्स के लिए प्रभावशाली परिवर्तनों वाला वर्ष रहा। इस वर्ष कई नई शुरुआतों के साथ इसे इंडस्ट्री के बराबर लाने का प्रयत्न किया गया। 2005–06

स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शन प्रसारण

में क्रिकेट अधिकारों और 2012 में ओलम्पिक स्पोर्ट्स अधिकारों के वापस लिए जाने के बाद चैनल अपने अस्तित्व की रक्षा से जूझ रहा था। इस वर्ष उठाए गए अनेक कदमों और अगले वर्ष की योजनाओं के साथ चैनल के कलेवर का पुनः निर्धारण हो सकेगा। नई पहलें हैं :

MhMh LikVZ~l ij vrjjk"Vªh; [ksyksa dk izlkj.k%

प्रसार भारती के खेल अधिकार संपन्न समिति ने खेल अधिनियम – 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत सभी खेल आयोजनों को डीडी नेशनल की बजाय डीडी–स्पोर्ट्स पर प्रसारण करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। नतीजतन, भारत में फीफा अंडर–17 वर्ल्ड का प्रसारण डीडी–स्पोर्ट्स पर किया गया। इस वर्ष प्रसारण किए जाने वाले महत्वपूर्ण खेल आयोजन हैं क्रिकेट सिरीज (भारत–दक्षिण अफ्रीका, भारत–इंग्लैंड श्रृंखला), राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल आदि।

vR;k/kqfud izLrqfrdj.k 'kSyh%

इस वर्ष खेल आयोजनों में शो से पहले, शो के दौ. रान और बाद में प्रस्तुतिकरण की अत्याधुनिक शैली को व्यापक परिवर्तन के तौर पर देखा जा रहा है। इनमें भुवनेश्वर में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता की 'स्टूडियो फ्रॉम द ग्राउंड जीरो', फीफा अंडर–17 वर्ल्ड कप के लिए इन–हाउस स्रोत वाले अनोखे आउटडोर स्टूडियो और फोर्थ अंपायर के लिए अत्याधुनिक आर्ट स्टूडियो शामिल हैं।

loZJs"B mn~?kks"kd@ fo'ks"kK@ekuuh; vfrfFk%

चैनल के कार्यक्रमों के लिए उद्घोषकों/विशेषज्ञों/समीक्षकों और खेल हस्तियों की संख्या में व्यापक वृद्धि की गई है। डीडी स्पोर्ट्स पर इस वर्ष उपस्थित रही खेल हस्तियों में रहे – श्री के. श्रीकांत, श्री मोहिंदर अमरनाथ, श्री दिलीप वेंगसरकर, श्री मनोज प्रभाकर, श्री एस.एम. एच. किरमानी और श्री अतुल वासन क्रिकेट के लिए, श्री बाईचुंग भूटिया और श्री रेनेडी सिंह फुटबॉल के लिए, श्री पुलेला गोपीचंद, सुश्री पी.वी. सिंधु और सुश्री अश्विनी पोनप्पा बेडमिंटन के लिए, सुश्री साक्षी मलिक कुश्ती के लिए, सुश्री दीपा कर्माकर जिमनास्टिक्स के लिए।

MhMh LikVZ~l ds fo'ks"k 'kks%

इस वर्ष डीडी स्पोर्ट्स ने विशेष अवसरों के लिए अनेक कार्यक्रमों की अवधारणा तैयार कर उन्हें प्रसारित किया था। इनमें भारत–चीन सीमारेखा पर आईटीबीपी के एक कैम्प में 'एक शाम जवानों के नाम' और गाजियाबाद के सीआईएसएफ कैम्प में 'वतन है तो हम हैं' प्रमुख रहे। चैनल एक अनोखा शो 'हौसलों की उड़ान' लेकर आ रहा है। क्रिकेट पर एक शो क्रिकेट टेल्स में कोचिंग और क्रिकेट से जुड़ी अनोखी कथाओं का समावेश होगा।

MhMh LikVl lHkk%

चैनल ने अपने औपचारिक डीडी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2017 के साथ 'ब्रांडिंग विद द पर्पज' के जरिए नई शुरूआत की है। देश में प्रसारित इस पहली खेल सभा में गुवाहाटी, मुंबई, नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और सीपीसी स्टूडियो से खेल हस्तियां, खेल प्रशासक और बॉलीवुड की हस्तियां जुड़ी। वर्तमान सरकार के शासनकाल के 3 वर्ष पूरे होने साथ पड़ने वाले इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री वैंकेया नायडू ने किया और इसके समापन सत्र में ओलंपिक मैडल विजेता और युवा मामलों एवं खेल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ शामिल हुए।

चैनल प्रधानमंत्री की शुरुआत 'मिशन 11 मिलियन' को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और ऊर्जा अभियान और युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय के 'खेलो इंडिया' अभियान इसकी अगुवाई कर रहे हैं।

MhMh&fdlku

26 मई, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को पूरी तरह समर्पित टीवी चैनल (डीडी किसान) की शुरुआत की थी। इसके जरिए किसान वर्ग को विकास धारा में शामिल किए जाने का लक्ष्य है। 15 अगस्त, 2017 को चैनल की समूची रूपरेखा को बदला गया।

चैनल का लक्ष्य कृषक और ग्रामीण समुदाय तक पहुंच बनाना है और देश के दूर–दराज के इलाकों में पहुंच बनाकर ग्रामीण जन को सूचना देना और शिक्षित कर उनके सतत और सम्मिलित विकास की दिशा में वातावरण तैयार करना।

चैनल ग्रामीण और कृषि समुदाय के लिए कार्यक्रम प्रसारित करता है। इनमें मूल कृषि के अलावा, नॉन–फिक्शन, फिक्शन और रियलिटी शो आदि कार्यक्रम भी शामिल होते हैं। इसके अधिकांश कार्यक्रम इन–हाउस निर्मित होते हैं।

इस अवधि में प्रसारित विशेष कार्यक्रम :

- स्वतंत्रता दिवस – 'फिर छिड़ी आज देश की बात'।
- 'किसान मंथन – संकल्प से सिद्धि'।
- सरकार की विभिन्न शुरुआतों पर कार्यक्रम 'वाद संवाद'।

नई पहल:

- जागो किसान – कृषि और संबंधित क्षेत्र की उपभोक्ता शिकायतों और विशेषज्ञों द्वारा उनके निवारण के लिए एक नया विमर्श कार्यक्रम।
- मौसम खबर – प्रातः, दोपहर और सायं का बुलेटिन।
- 'सृजन' नामक शोधपूर्ण निर्माणाधीन कार्यक्रम जिसमें फसल/सब्जी/फल को उसके बोए जाने, भौगोलिक विशेषता, पोषकता, विविधता आदि के बारे में बताया जाएगा।
- मूल कृषि से जुड़े विमर्शपूर्ण कार्यक्रमों में डीएसएनजी के जरिए राज्यों से लाइव इनपुट।
- गुणवत्ता सुधार के लिए निम्न निरंतर और स्थायी प्रयास किए जा रहे हैं:
- कार्यक्रम को भिन्न खंडों में बांट दिया गया ताकि विभिन्न पक्षों को अधिकाधिक रोचक बनाया जा सके।
- अखिल भारतीय परिदृश्य के मद्देनजर प्रत्येक कार्यक्रम के लिए देश भर से इनपुट मंगाए जाएंगे।

Ikknf'kd Hkk"kvk d lVykbV puy

MhMh≶knh

डीडी सह्याद्री 24 घंटे प्रसारण वाला प्रादेशिक मराठी चैनल है जिसमें प्रातः 6 से 9 (रविवार के अलावा) और सांय 3 से 7 बजे (सभी दिन) स्थालीय सहयोग होता है। बिना रुकावट प्रसारण के लिए, मार्च 2017 को मीडिया एसेट मैनेजमेंट (एमएएम) और कार्यक्रम तैयारी के लिए फाइल आधारित वर्कफ्लो, प्रोडक्शन और रीपर्पजिंग की शुरुआत की गई। डीडी सह्याद्री अपने कार्यक्रमों, दर्शकों तक जुड़ने और प्रोमोशन के लिए सोशल मीडिया का भी

इस्तेमाल कर रहा है।

महत्वपूर्ण प्रसारण :

- 25 जून, 2017 को गोदरेज नं.1 के 16वें सह्याद्री नवरत्न पुरस्कार समारोह का प्रसारण।
- 13 मई, 2017 को नया कार्यक्रम गुड मॉर्निंग सह्याद्री की शुरुआत।
- 20 मई, 2017 से प्रत्येक शनिवार चैनल पर मराठी फीचर फिल्मों का प्रसारण शुरू।
- 9 सितंबर, 2017 को नए पाककला शो 'अन्वत स्वाद' का प्रारंभ।
- 1 अक्तूबर, 2017 से इन–हाउस कार्यक्रम 'गीत स्वप्नातले गीत मनातले' की शुरुआत।
- 14 अक्तूबर, 2017 से मनोरंजन प्रधान इन–हाउस कार्यक्रम 'ए... फस्सा...' का प्रारंभ।
- 15 अक्तूबर, 2017 से इन–हाउस पारिवारिक हास्य धारावाहिक 'अहो कौन अले बाघ' की शुरुआत।

MhMh&fxjukj

01.10.1993 से गुजराती में सेटेलाइट प्रादेशिक भाषा चैनल डीडी–11 की शुरुआत की गई थी जिसे दिल्ली से अपलिंक किया गया और 15.08.1994 से इस सेवा की अपलिंकिंग स्थानीय स्तर से की जाने लगी थी। प्रादेशिक सेटेलाइट भाषा सेवा का चौबीस घंटे का प्रसारण 01.05.2000 से शुरू किया गया और 02.10.2007 से डीडी–गिरनार की पहचान ब्रांड के तौर पर बन गई।

अप्रैल, 2017 से आज तक प्रसारित महत्वपूर्ण कार्यक्रम :

- साबरमती आश्रम से गुजरात शताब्दी समारोह के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री की यात्रा का सीधा प्रसारण।
- गुजरात के आजी बांध से सीधा प्रसारण।
- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 'सुजलाम सुफलाम नर्मदा' नहर आधारित जल सेवा का उद्घाटन।
- महात्मा मंदिर से टेक्सटाइल इंडिया 2017 का उद्घाटन।
- भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम।
- स्वतंत्रता दिवस की 70वीं वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम 'स्वतंत्रता न संगे कविता न उमंगे' का प्रसारण।
- द्वारका माधवपुर (घेद) और सारंगपुर (अहमदाबाद) से जन्माष्टमी महोत्सव पर विशेष कार्यक्रम – वहलो मारो अवशे आथम नी अधारथे का सीधा प्रसारण।
- माननीय प्रधानमंत्री की जापान के माननीय प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात का सीधा प्रसारण।
- साबरमती रेलवे स्टेशन पर भारत और जापान के माननीय प्रधानमंत्रियों द्वारा भारत की पहली बुलेट ट्रेन की नींव रखा जाना।
- ओखा और बेटद्वारका के बीच सेतु की नींव रखा जाना।
- गांधीनगर में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नए आईआइ.'टी कैम्पस की इमारत का लोकार्पण और ई–टेब्लेट वितरण।
- घोघा से दहेज तक रो रो फैरी सेवा का उद्घाटन।
- सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर विशेष कार्यक्रम।
- गांधी नगर में अक्षरधाम मंदिर का रजत जयंती समारोह।

MhMh&ikf/kxbl

प्रादेशिक तमिल सेटेलाइट चैनल – पोधीगई की चौबीस घंटे सेवा की शुरुआत 15.01.2001 को की गई थी।

इस अवधि के दौरान प्रसारित महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहे :

- पिल्लईयरपत्ती के अरुलमिगु करपगा विनयगर मंदिर का महाभिषेकम।
- थिरुवरूर स्थित संगीत मुम्मोर्थिगल इसई विझ में पंचरत्न कृथि का प्रस्तुतिकरण।
- मदुरई के अरुलमिगु मीनाक्षी–सुंदरेश्वर थिरुकल्याणम।
- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रामेश्वरम में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन।
- 25.08.2017 को पिल्लईयरपत्ती के अरुलमिगु करपगा विनयगर मंदिर से विनयगर चतुर्थी उत्सव का सीधा प्रसारण।

- कुलक्षेत्रपत्तिनम के अरुलथरुम मुत्थरम्मन थिरुक्कोयिल से दशहरा समारोह का सीधा प्रसारण।

डीडी–यादगिरी

संयुक्त आंध्र प्रदेश के दो राज्यों में विभाजन के बाद दूरदर्शन के सप्तगिरी चैनल का नाम बदलकर हैदराबाद में डीडी–यदगिरी कर दिया गया था और इसने 27.09. 2014 से काम करना शुरू कर दिया था। डीडी–यदगिरी का प्रचार वाक्य सुमधुरम–सुमनोहरम है।

इस अवधि के दौरान प्रसारित महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहे :

- टॉक शो – मन माता मन पाता का प्रसारण।
- तेलंगाना की संस्कृति पर मन बोनालु का प्रसारण।
- स्वतंत्रता दिवस पर विशेष प्रसारण।
- डीडी स्टूडियो में रिकॉर्डेड बटुक्कम्मा का प्रसारण।

डीडी–सप्तगिरि

आंध्र प्रदेश की जनता को समर्पित डीडी–सप्तगिरि चैनल की शुरुआत 27.09.2014 को की गई थी।

इस अवधि के दौरान केंद्र द्वारा प्रसारित महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहे :

- डॉ. आम्बेडकर के जीवन इतिहास पर एक धारावाहिक (100 कड़ियां)
- 'सबका साथ सबका विकास' पर तत्कालीन माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वैंकेया नायडु का साक्षात्कार।
- भारत के उप–राष्ट्रपति श्री एम. वैंकेया नायडु की आंध्र प्रदेश यात्रा (अमरावती) के दौरान नागरिक अभिनंदन।
- महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का तिरुपति यात्रा के दौरान नागरिक अभिनंदन।
- विजयवाडा के इंद्र कीलाद्रि में आयोजित दशरा उत्सवलु।

डीडी–बांग्ला

20 अगस्त, 1992 को शुरू किया गया डीडी बांग्ला चैनल का प्रसारण 1 जनवरी, 2000 को बढ़ाकर 24 घंटे कर दिया गया। बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और उसे आगे बढ़ाने के लिए डीडी बांग्ला महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और देश के बंगाली दर्शकों के बीच यह चैनल बहुत लोकप्रिय रहा है।

इस अवधि के दौरान प्रसारित महत्वपूर्ण कार्यक्रम :

- 15.04.2017 को प्रसारित नबाबरशेर बोइठक–1424।
- 09.05.2017 को विश्व–भारती शांतिनिकेतन और जोरासांको ठाकुरबाड़ी से प्रसारित 'कवि प्रणाम'।
- 21.06.2017 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रसारित 'योगासने महाध्यानी'।
- 09.08.2017 को डीडी बांग्ला की 43वीं वर्षगांठ पर प्रसारित 'आजो नवीन'।
- 15.08.2017 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी पर प्रसारित विशेष कार्यक्रम 'मेघे ढाका सूर्या'।
- 19.09.2017 महालया के अवसर पर प्रसारित 'महिषासुरमर्दिनी'।
- 26.09.2017 से 30.09.2017 तक विभिन्न समयावधियों पर 'बेलूर मठ दुर्गा पूजा' का प्रसारण।
- 26.09.2017 से 30.09.2017 तक विभिन्न समयावधियों पर 'इबार पुजॉय भारत दर्शन' का प्रसारण।

डीडी–पंजाबी

डीडी पंजाबी 24 घंटे प्रसारित होने वाला पंजाबी चैनल है जिसे भारत और उन अन्य देशों में व्यापक तौर पर देखा जाता है जहां सेटेलाइट जीसैट–17 की पहुंच है। डीडी पंजाबी जीसैट–15 उपग्रह से डीटीएच प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है और इसे दुनिया भर में इंटरनेट के माध्यम से भी देखा जा सकता है।

इस अवधि के दौरान प्रसारित महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहे :

- 13.04.2017 को बैसाखी के अवसर पर 'जट्टा आई

दूरदर्शन के पैनल कक्ष की एक झलक

बैसाखी' का प्रसारण।

- 27.05.2017 को गायकों खुदाबख्श और सुश्री अफसाना के साथ 'सांझ सुरन दी' का सीधा प्रसारण।
- 19.06.2017 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 'संवाद–चैट शो' का सीधा प्रसारण।
- 05.08.2017 को डीडी पंजाबी की 17वीं वर्षगांठ पर 'जन्मदिन मुबारक' का प्रसारण।
- 20.09.2017 से 30.09.2017 तक 'रामलीला' पर विशेष कड़ियों का प्रसारण।
- 15.09.2017 को दूरदर्शन दिवस पर विशेष कार्यक्रम 'सुनहरा सफर' का प्रसारण।

KASHIR

MhMh&d'khj

डीडी कशीर चैनल की शुरुआत 26 जनवरी, 2000 को की गई थी। उस समय इसकी प्रसारण अवधि प्रतिदिन 14 घंटे की होती थी। 15 मार्च, 2003 को चैनल की प्रसारण अवधि बढ़ाकर 24 घंटे की कर दी गई।

यह मूलतः सेटेलाइट चैनल है जिसे 30 ट्रांसमीटरों का स्थलीय सहयोग है जिसके जरिये यह कश्मीर क्षेत्र की 77 प्रतिशत जनता तक पहुंचता है। श्रीनगर के दूरदर्शन केंद्र से अपलिंक्ड किए जाने वाले डीडी कशीर के कार्यक्रमों को देश भर में केबल नेटवर्क के जरिए देखा जा सकता है। चैनल 'डीडी डायरेक्ट प्लस' सेवा का भी हिस्सा है जिसकी शुरुआत 16 दिसंबर, 2004 को दूरदर्शन द्वारा की गई थी। इस पर बल्टी, डोगरी, गूजरी, कश्मीरी, लद्दाखी, पहाड़ी, पंजाबी, शीना और उर्दू भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित होते हैं।

सीमा पर से किए जाने वाले झूठे प्रचार को नकारने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखलाभी प्रसारित की जाती है। प्रति सप्ताह आठ ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण किया जाता है जिनके कथ्य और विषय–वस्तु को गृह मंत्रालय और सेना के सैन्य खुफिया निदेशालय की मंजूरी होती है।

कशीर चैनल पर प्रसारित कार्यक्रमों में इन–हाउस प्रोडक्शन और कमीशंड प्रोग्राम का समावेश होता है।

2017–2018 के दौरान प्रसारित महत्वपूर्ण कार्यक्रम :

- 2017 को रमजान के पवित्र महीने में 30 दिनों तक प्रातः सहरी और इफ्तार के समय 'पयाम–ए–रमजान' सीरीज का प्रसारण किया गया।
- 2017 को मुहर्रम के पहले दस दिनों तक अशूरा–ए–मुहर्रम के संबंध में सीरीज 'याद–ए–कर्बला' का प्रसारण किया गया।
- नियंत्रण रेखा पर सबसे आगे तैनात सेना के अफसरों के साथ 'वी द सोल्जर्स' नामक विशेष श्रृंखला का 8 अगस्त, 2017 से 14 अगस्त, 2017 तक प्रसारण।
- केंद्र सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के संबंध में 'पेशरफ्त' नामक विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला का प्रसारण।
- प्रतिदिन ब्रेकफास्ट शो 'गुड मॉर्निंग जेएंडके' और सीपीजी कार्यक्रमों का प्रसारण।
- प्रसिद्ध कश्मीरी कवि श्री जी. एन. फिराक़ पर आधारित कार्यक्रम 'सदा ते समुंदर'।

निम्न फोन–इन शो भी इन कार्यक्रमों के जरिए चैनल की मुख्य गतिविधियों का हिस्सा हैं :

1) हैलो डीडी, 2) टेलिक्लास रूम, 3) डॉक्टर–ऑन–ला. इन और 4) खेल और खिलाड़ी।

DD ODIA

MhMh&mfM;k

डीडी उड़िया का प्रारंभ 2 अक्तूबर, 1993 को डीडी–5 के तौर पर हुआ था। 1 अप्रैल, 2001 को (ओडिशा राज्य निर्माण 'उत्कल दिवस') इसकी प्रसारण अवधि बढ़ाकर 24 घंटे की कर दी गई थी।

2017–18 की अवधि के दौरान डीडी उड़िया की महत्वपूर्ण गतिविधियां रहीं :

- 31 मई, 2017 को सम्बलपुर से सीतल सस्थी का सीधा प्रसारण।
- राज्य में ओडिशा दिवस के आयोजन पर टीवी रिपोर्ट और राज्य निर्माण दिवस पर विशेष कार्यक्रमों 'बंदे उत्कल ज्ञानी' और 'उत्कल्य अस्मितारा संधान' का प्रसारण।
- राजा उत्सव (14–16 जून, 2017) पर विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण।
- 25 जून, 2017 को विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यात्रा का पुरी से सीधा प्रसारण।
- 03 जुलाई, 2017 को पुरी में भगवान जगन्नाथ धाम से बहुधा यात्रा (रिटर्न कार फेस्टिवल) का सीधा प्रसारण।
- 14 सितंबर–30 सितंबर, 2017 को दशहरा पर विशेष शृंखला का प्रसारण।
- प्रत्येक सोमवार को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम ओडिशा दर्शन का प्रसारण किया जाता है।

iLrkfor lh/kk ilkj.k@vU; egRoi.k ilkj.k % ¼uocj] 2017&ekp] 2018½

- कोणार्क उत्सव 2017 : 1–5 दिसंबर, 2017
- मुक्तेश्वर नृत्य उत्सव : 14–16 जनवरी, 2018
- राजरानी संगीत उत्सव : 18–20 जनवरी, 2018
- धौली–कलिंग महोत्सव : 06–08 फरवरी, 2018

MhMh&ey;kye

वर्ष 1985 में अपनी स्थापना के बाद से डीडी मलयालम ने पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है। केंद्र की प्रोडक्शन सुविधाएं थिरुवनंतपुरम, थ्रिसूर और कालिकट में हैं और राज्य में उनके स्थलीय ट्रांसमीटरों का नेटवर्क भी है। इस अवधि के दौरान बीट द फ्लोर, नो योर मिनिस्टर, वी द सोल्जर्स, 'सुदिनम' नामक प्रतिदिन प्रसारित होने वाला मॉर्निंग शो की शुरुआत हुई। केंद्र के कुछ आने वाले कार्यक्रमों में हैं : इंटरेक्टिव टीवी शो रंगोली – ओल्ड हिट्स, ट्रेवलॉग, म्यूजिक शो, कॉमेडी सीरियल, ईवनिंग लाइव शो और इंटरेक्टिव प्रोग्राम।

इस अवधि के दौरान प्रसारित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहे :

- 'थ्रिसूर पूरम' उत्सव का सीधा प्रसारण।
- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कोझिकोड के किनावूर में उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स के सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन।
- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पलरीवत्तोम मैट्रो स्टेशन में कोच्चि मैट्रो का उद्घाटन।
- अलप्पुझा के पुन्नमडा झील में नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन।
- अरनमुला में आयोजित अरनमुला नौका दौड़ का सीधा प्रसारण।
- कोल्लम में माता अमृतानंदमयी की 64वीं सालगिरह पर राष्ट्रपति द्वारा सहायतार्थ कार्यक्रमों के उद्घाटन का सीधा प्रसारण।
- पल्लिपुरम में राष्ट्रपति द्वारा टेक्नोसिटी के उद्घाटन का सीधा प्रसारण।

MhMh&pnuk

15 अगस्त, 1994 को प्रारंभ डीडी चंदना कन्नड़ भाषा का उपग्रह चैनल है जिसे बंगलुरु एवं गुलबर्गा के दूरदर्शन स्टूडियो का सहयोग मिलता है। वर्ष 2000 में यह चौबीस घंटे प्रसारण वाला चैनल हो गया तथा 24 मार्च, 2003 से इसकी कवरेज 30 से अधिक देशों में होने लगी है।

इस अवधि के दौरान प्रसारित महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहे :

- बंग्लुरु में डेविस कप ओशियानिया में भारत बनाम उज्बेकिस्तान के टेनिस मैच का सीधा प्रसारण।
- बंग्लुरु के डॉ. बी. आर. आम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के शिलान्यास का सीधा प्रसारण।
- बंग्लुरु में माननीय राष्ट्रपति द्वारा मेट्रो के फेज–1 के लोकार्पण का सीधा प्रसारण।
- इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा जीएसटी पर आयोजित विशेष कार्यक्रम।
- मैसुरु के बन्निमंतप से दशहरा जुलूस मैसुरु पैलेस एंड टॉर्च लाइट परेड का प्रसारण।

MhMh ukFkZ&bLV

डीडी नॉर्थ–ईस्ट 1 नवंबर, 1990 में कमीशंड किया गया और अंततः 15 अगस्त, 1994 को इसका शुभारंभ किया गया। 27 दिसंबर, 2000 से यह 24 घंटे प्रसारण वाला चैनल हो गया।

इस अवधि के दौरान प्रसारित महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहे :

- नमामि ब्रह्मपुत्र पर टीवी रिपोर्ट।
- विश्व रत्न डॉ. भूपेन हजारिका सौहार्द पुरस्कार, 2017 पर टीवी रिपोर्ट।
- रंगोली बिहु पर टीवी रिपोर्ट।
- प्रधानमंत्री की असम यात्रा पर टीवी रिपोर्ट।
- गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के अंबु बाछी मेला पर कार्यक्रम – अंबुबाछी – इति आलोकपट।
- दूरदर्शन के 58वें स्थापना दिवस पर चैट शो/म्यूजिकल प्रोग्राम का सीधा प्रसारण।
- महालया के अवसर पर विशेष संगीत कार्यक्रम का प्रसारण।

MhMh&jktLFkku

डीडी राजस्थान, चौबीस घंटे प्रसारण वाले हिंदी क्षेत्रीय चैनल के रूप में 1 अगस्त, 2013 को अस्तित्व में आया और 15 अगस्त 2013 से इसने औपचारिक रूप से कार्यक्रमों का प्रसारण प्रारंभ किया। 24 घंटे प्रसारण वाला यह केंद्र राज्य के दर्शकों की रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शैलियों के कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। केंद्र 'सांसद आपके द्वार' कार्यक्रम के माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्री माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की राजस्थान यात्राओं के बारे में लगातार टीवी रिपोर्ट प्रसारित कर रहा है।

इस अवधि के दौरान प्रमुख गतिविधियां, पहल और उपलब्धियां :

- तीसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का एसएमएस स्टेडियम, जयपुर से सीधा प्रसारण।
- स्वतंत्रता दिवस उत्सव – जैसलमेर के सैम सैंड ड्यून्स से 'संकल्प से सिद्धि'।
- उदयपुर से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के उद्घाटन का सीधा प्रसारण।
- इस दौरान डीडी राजस्थान में आयोजित क्रिकेट मैचों/अन्य खेल गतिविधियों का सीधा प्रसारण किया।

MhMh&fcgkj

चौबीस घंटे प्रसारण वाला प्रादेशिक उपग्रह चैनल, डीडी बिहार की शुरुआत 01.05.2013 को हुई थी। तब से इसने देश भर में अपना विस्तार किया है।

इस अवधि के दौरान डीडीके, पटना की मुख्य गतिविधियां:

- देवघर, झारखंड के आयोजित कौशल महोत्सव का 02.04.2017 को प्रसारण।
- साहेबगंज, झारखंड में 06.04.2017 को गंगा नदी पर चार लेन मार्ग सेतु के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन का सीधा प्रसारण।
- 'चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह' पर विशेष कार्यक्रम का 19.04.2017 को प्रसारण।
- टीवी रिपोर्ट 'सफर तीन साल' का 22.06.2017 को प्रसारण।
- जन्माष्टमी पर विशेष कार्यक्रम का 15.08.2017 को प्रसारण।
- मां दुर्गा पर विशेष कार्यक्रम का 27.09.2017 को प्रसारण।
- पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह का पटना कॉलेज से 14.10.2017 को सीधा प्रसारण।
- 'छठ पर्व' का 26/27.10.2017 को सीधा प्रसारण।

MhMh&mRrj izns'k

चौबीसों घंटे उपलब्ध होने वाला 'डीडी उत्तर प्रदेश' 16 अगस्त, 2013 को अस्तित्व में आया। पहले डीडी उत्तर प्रदेश केवल स्थलीय नेटवर्क पर उपलब्ध था। 24 घंटे का यह चैनल लोक संगीत, सुगम संगीत, नाटक, टॉक शो, क्विज और कुछ अभिलेखीय कार्यक्रमों आदि जैसी शैलियों को कवर करता है।

इस अवधि के दौरान प्रसारित महत्वपूर्ण कार्यक्रम :

- 5 अप्रैल, 2017 को नवरात्र का सीधा प्रसारण।
- 18 अगस्त, 2017 – मथुरा से 'श्रीकृष्ण जन्माष्टमी' का सीधा प्रसारण।
- गोरखपुर और लखनऊ में क्रमशः 14 एवं 23 सितंबर, 2017 को फिल्म संगीत रियलिटी शो का ऑडिशन आयोजित किया गया।
- 17 सितंबर, 2017 – कविता शो 'वन्स मोर' का उद्घाटन।
- 30 अक्तूबर, 2017 – बाराबंकी जिले में फसल संगोष्ठी का आयोजन।

MhMh&e/; in'k

डीडीके, भोपाल ने उपग्रह के माध्यम से 24 घंटे का प्रसारण प्रारंभ किया है और इसे 25 जून, 2013 से डीडीः मध्य प्रदेश नाम दिया गया है। पीजीएफ : ग्वालियर और पीजीएफ : इंदौर डीडी : मध्य प्रदेश पर प्रसारण के लिए कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं। हिन्दी के अलावा, मालवी, बुंदेली, बघेली और निमाड़ी जैसी स्थानीय बोलियों में भी कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। इस अवधि के दौरान प्रसारित महत्वपूर्ण कार्यक्रम :

- यह है नारी शक्ति
- संकल्प से सिद्धि
- झिलमिल सितारे, खेल समय
- कौशल विकास पर कार्यक्रम 'हैलो डीडी' आदि
- कार्यक्रम 'सबका साथ सबका विकास' के अंतर्गत दर्शकों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में सूचित किया जाता है।
- 'नव प्रभात' और 'इंद्रधनुष' अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विभिन्न परियोजनाओं के बारे में बताते हैं।
- दर्शकों के लाभ के लिए 'मेक अप इंडिया', 'स्टार्ट. अप इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' विषयों पर कार्यक्रम प्रसारण।

njn'ku 0;kolkf;d lok

दूरदर्शन व्यावसायिक सेवा (डीसीएस) एक स्वतंत्र प्रकोष्ठ है, जो मुख्यालय, दूरदर्शन केंद्रों, विपणन प्रभागों और डीसीडी द्वारा एजेंसियों/ग्राहकों/निर्माताओं से राजस्व एकत्र करने के साथ–साथ एयर टाइम की बिक्री जैसे सभी व्यावसायिक क्रियाकलापों में समन्वय करती है। डीसीएस प्रसार भारती बोर्ड के अनुमोदन से विपणन प्रभागों और क्षेत्रीय केंद्रों से प्राप्ति सूचना के अनुसार व्यावसायिक नीतियों का गठन करने और दर कार्ड को अद्यतन करने का दायित्व निभाता है।

यह प्रकोष्ठ विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों को पंजीयन और प्रत्यायन स्टेट्स प्रदान करता है और इनसे एयर टाइम की बिक्री के लिए संपर्क करता है। बाजार के बदलते परिप्रेक्ष्य में संबंधित नियमावलियों और नीतियों का गठन एवं उनकी समीक्षा समय–समय पर की जाती है। दूरदर्शन द्वारा वर्षवार हासिल किए कुल राजस्व का विवरण इस प्रकार है:

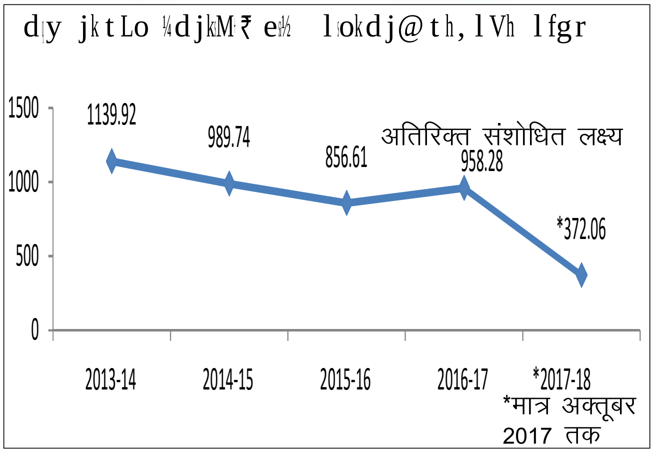

ubl 'k#vkr%

- व्यवसाय करने को सुलभ बनाने के लिए, एक नई पंजीकरण एवं प्रमाणन नीति की शुरुआत की गई।
- देश भर में ग्राहकों को भुगतान की सरल विधि उपलब्ध कराते हुए, ब्रॉडकास्टिंग ऑटोमेटेड शेड्यूलर (बीएटीएस) को शुरू किया गया जिसके माध्यम से हाथ से बनाए हुए बिलों की बजाय ऑनलाइन बिलिंग की शुरुआत हुई।

fodkl lapkj foHkkx ¼Mh lh Mh½ ,oa 0;kolkf;d jktLo foHkkx ¼lhvkjMh½] fnYyh

सरकारी विभागों/मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संचार संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सिंगल विंडो विपणन प्रभाग और नवीनतम विकास संचार मॉडल सहित प्रोडक्शन हाउस के रूप में कार्य करने के लिए मार्च 2001 में विकास संचार प्रभाग (डीसीडी) की स्थापना की गयी थी। यह मीडिया प्लानिंग, सॉफ्टवेयर उत्पाद, शेड्यूलिंग और पड़ने वाले असर के आकलन के संबंध में सुगठित समाधान उपलब्ध कराती है। विकास संचार प्रभाग निम्नलिखित के लिए सिंगल विंडो सुविधा प्रदान करता है :

- दूरदर्शन के एयर टाइम का विपणन और उत्पादन क्षमता।
- परामर्शी और अनुकूलित मीडिया प्लानिंग।
- क्षेत्रीय भाषाओं में देशभर के स्टेशनों में कार्यक्रमों का

निर्माण करना तथा प्रतिक्रिया और ग्राहकों के लिए अनुसंधान सर्वेक्षण।

- डीसीडी ने सक्रियता के साथ राजस्व की दर में वृद्धि की है जो दूरदर्शन के समूचे राजस्व का 35 प्रतिशत से अधिक रहा।
- दुनिया के सबसे बड़े सफाई अभियान 'स्वच्छ भारत' का प्रसारण।
- ग्रामीण विकास पर आधारित 'गांव विकास की ओर' की एक सीरीज को नेशनल और 34 क्षेत्रीय चैनलों पर भी किया जा रहा है। 2017–18 के वित्तीय वर्ष के दौरान इसे 52 कड़ियों के लिए बढ़ाया गया।
- वर्ष 2016–17 के दौरान कई तरह अभियान प्रसारित किए गए जिन्हें मौजूदा वर्ष 2017–18 में भी प्रसारित किया जा रहा है। इनमें सामाजिक न्याय मंत्रालय का सुलभ भारत अभियान, बुजुर्ग स्वास्थ्य अभियान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का तंबाकू विरोधी, चिकनगुनिया, डेंगू, टीकाकरण और स्तनपान कराना अभियान, पर्यटन मंत्रालय का अतुल्य भारत और वित्त मंत्रालय का आय घोषणा योजना और जीएसटी शामिल है।
- बच्चों के टीकाकरण और जागो ग्राहक जागो जैसी नई योजनाओं के लिए नई योजना मिशन 'इंद्रधनुष' के स्पॉर्ट्स को दूरदर्शन पर प्रसारित किया जा रहा है। डीसीडी ने विकलांगजनों के लाभ से संबंधित कार्यकलापों के स्पॉट्स भी प्रसारित किए हैं।
- सुगम्य भारत–एक्सेसिबल इंडिया अभियान।
- सबका साथ सबका विकास।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना–पीएमएफबीवाई और मृदा स्वास्थ्य कार्ड।
- सेवा दिवस के अवसर पर दूरदर्शन पर एक विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया गया जिसे गेल इंडिया लि. ने प्रायोजित किया और स्पॉट्स के प्रसारण से राजस्व प्राप्त किया गया।
- मई 2017 महीने के दौरान दूरदर्शन पर स्टूडियो आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम 'डॉक्टर ऑन लाइन' की शुरुआत की गई। इसके अलावा, 2017–18 के दौरान डेंगू, स्वाइन फ्लू, ट्यूबरक्युलोसिस, परिवार नियोजन आदि विभिन्न मुद्दों पर स्पॉट्स/अभियान प्रसारित किए गए।
- 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान की भी शुरुआत हुई।
- राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2017 विशेष कार्यक्रम का निर्माण और सितंबर, 2017 पर दूरदर्शन के चैनलों पर इसका प्रसारण हुआ।

सेवा दिवस पर विशेष कार्यक्रम

वर्ष 2017–18 के दौरान 31 अक्तूबर, 2017 तक डीसीडी सीआरडी–दिल्ली द्वारा प्राप्त राजस्व ₹ 143.12 करोड़ रहा (डीसीडी=119.42 + सीआरडी=23.70)। इस दौरान व्यावसायिक उत्पाद ₹ 250 करोड़ का रहा।

MhMh vkdkb0l

डिजिटलीकरण किए जाने की दिशा में भारी तेजी आई है। इसके अलावा, यहां मौजूद ऑडियो–विजुअल साम्रगी की दुर्लभ धरोहर को सहेजने की दिशा में अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं। मौजूदा अवसंरचात्मक ढांचे को सुचारू करने के लिए नई नीतियां तैयार की जा रही हैं।

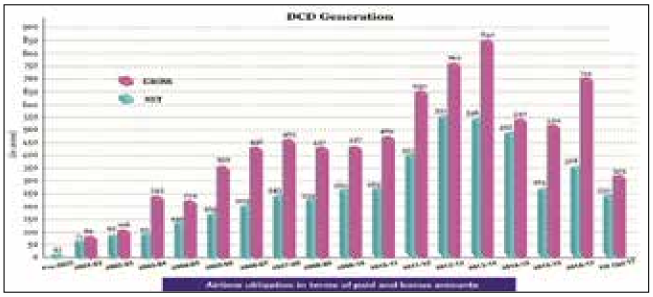

दूरदर्शन अभिलेखागार (आर्काइव्स) में उत्पादकता को केंद्र में रखकर काम किया जा रहा है।

आम और विशिष्ट दर्शकवर्ग तक पहुंचने के लिए दूरदर्शन आर्काइव्स ने अपने यूट्यूब चैनल की भी शुरुआत की हैं। सर्कस, दूसरा केवल, फ्लॉप शो आदि जैसे लोकप्रिय धारावाहिक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं और अन्य कई धारावाहिकों को भी शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा।

दूरदर्शन अभिलेखागार का प्रमुख केंद्रीय और उत्तर–क्षेत्रीय केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में इसके तीन क्षेत्रीय आर्काइविंग केंद्र भी हैं। दूरदर्शन के सभी 67 केंद्र अपने निर्माणाधीन कार्यक्रमों की नियमित आर्काइविंग के लिए केंद्रीय और उत्तर–क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क में रहते हैं। दूरदर्शन अभिलेखागार के जिम्मे विविध कार्य आते हैं,

दूरदर्शन आर्काइव का पैम्फलेट

जिनके बारे में नीचे बताया गया है –

d½ fMftVhdj.k

रिकॉर्डिंग मीडिया फॉर्मेट्स को एमपेक्स से बीसीएन से बीटाकैम से डीवीसी से एचडी में बदला गया है। डिजिटीकरण की प्रक्रिया सभी पांचों केंद्रों में चल रही है। अभी तक 18500 घंटे अवधि का कंटेंट डिजिटाइज्ड किया जा चुका है। डीडी अभिलेखागार यूमेटिक टेप्स, बीसीएन, एम्पेक्स, बीटाकैम को डीवीसी प्रो50 फॉर्मेट और उसके बाद एलटीओ (लीनियर टेप ओपन) फॉर्मेट में बदलने की प्रक्रिया में है जो कि डिजिटीकरण कार्य के लिए अंतरराष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत फॉर्मेट है। अभी तक 24,225 घंटे की सामग्री को लेगेसी टेप्स से डिजिटल टेप्स में बदला जा चुका है। डीडीके, कोलकाता में डिजिटीकरण के विकसित स्तर की शुरुआत करने जा रहा है। दूरदर्शन अभिलेखागार अपने मोबाइल डिस्प्ले/सेल काउंटरों की मदद से बहुत कम दरों पर रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध कराता है। अभी तक डीडी अभिलेखागार लगभग 89 डीवीडी रिलीज कर चुका है। पांच अन्य डीवीडी पर काम जारी है जो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। यह डीवीडी दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी केंद्रों पर, दिल्ली हाट में स्थायी कियोस्क और www.prasarbharatiarchives.co.in पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। दूरदर्शन अभिलेखागार ने खरीदारों तक पहुंचने के लिए दो रंग–बिरंगे ब्रॉशर भी प्रकाशित किए हैं जिनमें पुराने लोकप्रिय कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी है। दूरदर्शन अभिलेखागार में मौजूद फुटेज व्यावसायिक लक्ष्य, निजी संग्रहण और अध्येताओं के लिए निश्चित शुल्क पर उपलब्ध हैं।

अभिलेखागार विभाग विभिन्न चैनलों को पुराने कार्यक्रमों की फुटेज की रीपैकेजिंग करके उपलब्ध करा रहा है। मौजूदा समय में डीडी नेशनल प्रति सप्ताह छह कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। अन्य डीडी चैनल और केंद्र भी अपनी जरूरत के अनुसार विभिन्न कार्यक्रम डीडी आर्काइव्स से प्राप्त करते हैं।

jk"Vªh; fofue; lalk/ku iwy ¼,uvkjbZih½

अभी तक लगभग 30132 घंटे अवधि के कार्यक्रमों को डिजिटल माध्यम में स्थानांतरित किया जा चुका है।

आकाशवाणी संगीत सीडी और ऑल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन के अभिलेखीय संबंधी सामग्री के प्रति जागरूकता के लिए निम्न अवसरों पर स्टॉल लगाए गए :

- 05 अप्रैल, 2017 को चाणक्यपुरी, नई दिल्ली के विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेटिंग इंडिया।
- 17 से 20 अप्रैल, 2017 को ग्रेटर नोएडा में ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेज, इंडियन एक्सपोजिशन मार्ट।
- 26 अगस्त से 3 सितंबर, 2017 तक प्रगति मैदान में दिल्ली पुस्तक मेला 2017।
- 7 अक्तूबर, 2017 को सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन।

25 से 26 मई, 2017 को फीजी में संधारणीय विकास के लिए बैठक में 14 प्रशांत द्वीपीय देशों (पीआईसी) को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन अभिलेखागार से कार्यक्रम प्रसारण के लिए उपहार स्वरूप दिए गए।

व्यावसायिक गतिविधियां

अप्रैल 2017 से अक्तूबर 2017 तक अभिलेखागार रिलीज और फुटेज की कुल बिक्री की लगभग ₹ 18 लाख रही। इसमें से ऑनलाइन सेल लगभग 4.5 लाख ₹ की रही जो http://www.prasarbharatiarchives.co.in & www.amazon.in पर हुई।

ehfM;k izpkj foHkkx ¼,eihMh½

मीडिया और प्रचार गतिविधियों के प्रमुख अतिरिक्त महानिदेशक के आगमन के बाद मीडिया प्रचार विभाग का विस्तार हुआ है। इसके जरिए, दूरदर्शन के कार्यक्रमों और गतिविधियों के प्रचार आदि के लिए सभी तरह के संचार, विज्ञापन, आउटडोर कार्य, प्रेस विज्ञप्तियां, बुकलेट्स, प्रेस बैठकों आदि कार्य किए जाते हैं।

एमपीडी विभाग ने प्रसार भारती के सभी कार्यस्थलों, दूरदर्शन, एआईआर, टोडापुर, एचपीटी पीतमपुरा और सीपीसी खेल गांव में बिलबोर्ड्स और यूनिपोल्स को बदलने की दिशा में सहयोग किया है।

17–20 अप्रैल, 2017 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट की तीसरी प्रदर्शनी में दूरदर्शन ने 'गोल्ड स्पॉन्सर' के तौर पर हिस्सा लिया

था। प्रदर्शन स्थल पर दूरदर्शन को 36 वर्ग मीटर का स्थल प्रदान किया गया था। स्टाल की पृष्ठभूमि में 'द चैनल ऑफ इंडिया' का कलात्मक डिजाइन नुमायां था। डीडी नेशनल, डीडी किसान, डीडी न्यूज और डीडी भारती के रचनात्मक कर्मियों की मदद से टेबल ब्रांडिंग की गई थी। इस अवसर पर बारह पृष्ठों वाली एक दूरदर्शन बुकलेट भी डिजाइन और प्रकाशित की गई थी ; जिसमें संगठन के सभी पक्षों की जानकारी शामिल थी।

21 जून, 2017 को एजेंसी द्वारा 'योग दिवस' के अवसर पर 'योगोत्सव' नामक एक विशेष तौर पर डिजाइन पुस्तिका का प्रकाशन किया गया। इसमें विभिन्न केंद्रों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी थी जिसे सभी मंत्रालयों में वितरित किया गया।

1 fnlcj] 2016 l 15 uocj] 2017 d nkjku dV d fu.k;@vkn'kk ij vey

क्र. सं.	मीडियायूनिट /अनुभाग डीजीःदूरदर्शन	वर्ष 2017 में कैट से निर्णय/आदेश	वर्ष 2017 के दौरान अमल में लाए गए निर्णय/आदेश	अमल में लाए जाने वाले/चुनौती दिए जाने वाले आदेश
1.	एस-1	09	06	01/02
2.	एस-II(ए)	12	04	–
4.	एस-III	02	01 (श्री के. डी. कल्पित द्वारा दायर मामले 819/2013 (सीसीपीए 0050/0035/2015) के फैसले (दिनांक 20/07/17) पर अमल)।	01(श्रीमती एन.वी. विजयालक्ष्मी सेवानिवृत एएसडी द्वारा माननीय कैट बंगलूरु में ग्रेच्युटी तथा अन्य पैंशन लाभों के देर से भुगतान पर 15% दंडात्मक ब्याज दिए जाने की याचिका की गई। मूल आवेदन 170/0/032/2016 पर संशोधित आवेदन 170/00030/2017 को माननीय कैट, बंगलूरु ने रद्द कर दिया। फैसले को मंत्रालय के अनुमोदन से अमल में लाया जाना है।)
5.	एस-IV	05	05	स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया गया।
6.	एससीओआर	01	Nil	माननीय कैट के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय, दिल्ली में रिट याचिका (W.P. (c) No. 9207/2017) दायर की गई। उच्च न्यायालय ने निर्णय के अमल पर प्रभाव के संबंध में स्थगन आदेश दिया।
7.	सतर्कता	04	04	–

Mhth % njn'ku e fgUnh dk vuiz;kx

निदेशालय और उसके अधीन कार्यालयों में हिंदी में कार्य सुनिश्चित कराने के लिए अलग से एक हिंदी अनुभाग कार्य कर रहा है।

वर्ष 2017–18 के दौरान अनुभाग द्वारा किए गए मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :

- वर्ष के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा–3(3) के तहत सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी किए गए और हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया गया। ऐसे 5320 दस्तावेज जारी किए गए।
- निदेशालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए, वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं।
- समय–समय पर हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गईं जिनमें 53 अधिकारियों/कर्मियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा, आधिकारिक भाषा निरीक्षण पर भी एक वर्कशाप आयोजित हुई जिसमें विभिन्न दफ्तरों

से अधिकारी आमंत्रित किए गए।

- 1 सितंबर से 29 सितंबर, 2017 तक हिंदी माह मनाया गया और इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
- संसद पर राजभाषा समिति ने वर्ष के दौरान 6 दूरदर्शन केंद्रों/कार्यालयों का निरीक्षण किया। और उसके द्वारा निरीक्षण किए गए संबंधित कार्यालयों को यथासंभव मदद और सहयोग के साथ प्रश्नावली संबंधित कार्यालयों को सौंपी।
- विशाखापट्टनम में 17–18 अगस्त, 2017 को 'सी' मंडल में स्थित डीडीके/डीएमसी/एचपीटी के हिन्दी अधिकारियों और स्थानीय आधिकारिक भाषा कार्यालय प्रमुखों की सम्मेलन आयोजित किया गया।
- अवधि के दौरान 16 डीडीके/डीएमसी/एचपीटी का निरीक्षण किया गया और समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी।

n'kd vu|l/kku

देशभर में दूरदर्शन केंद्रों के साथ संलग्न 19 फील्ड इकाइयों सहित दूरदर्शन की दर्शक अनुसंधान इकाई, 1976 से प्रसारण के विभिन्न पहलुओं के बारे में शोध अध्ययन में जुटी हैं। अप्रैल 2016 से मार्च 2016 के दौरान दर्शक अनुसंधान इकाई का योगदान निम्नलिखित रहा :

- बीएआरसी टीवीआर का साप्ताहिक आधार पर विश्लेषण और रिपोर्टिंग।
- दर्शक अनुसंधान एवं कार्यक्रम कर्मियों के लिए बीएआरसी, बीएमडब्ल्यू सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- डीडी एलपीटी हिंदूपुर (आंध्र प्रदेश) के क्षेत्रीय अध्ययन की रिपोर्ट जून, 2017 को प्रेषित की गई।
- भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता में सितंबर, 2017 को दर्शक अनुसंधान कर्मियों द्वारा शोध कार्यप्रणाली पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

njn'ku dsn ¼LVfM;k dsn½ **vuyXud&I**

jkT;@dsUn'kkflr {ks=	LFkku	jkT;@dsUn'kkflr {ks=	LFkku
आंध्र प्रदेश	विजयवाडा, तिरुपति	ओडिशा	भुवनेश्वर, भवानीपटना, सम्बलपुर
अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	पंजाब	जालंधर, पटियाला
असम	डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, (पीपीसी) सिल्चर	राजस्थान	जयपुर
बिहार	पटना, मुजफ्फरपुर	सिक्किम	गंगटौक
छत्तीसगढ़	जगदलपुर, रायपुर	तमिलनाडु	चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई
गोवा	पणजी	तेलंगाना हैदराबाद,	वारंगल
गुजरात	अहमदाबाद, राजकोट	त्रिपुरा	अगरतला
हरियाणा	हिसार	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, मऊ, वाराणसी, मथुरा
हिमाचल प्रदेश	शिमला	उत्तराखंड	देहरादून
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर, जम्मू, लेह, राजौरी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता, शांतिनिकेतन, जलपईगुड़ी
झारखंड	रांची, डाल्टनगंज	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर
कर्नाटक	बंग्लुरू, गुलबर्गा	चंडीगढ़	चंडीगढ़
केरल	कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम, त्रिचूर	दिल्ली	दिल्ली, दिल्ली (सीपीसी)
मध्य प्रदेश	भोपाल, इंदौर, ग्वालियर	पुडुचेरी	पुडुचेरी
महाराष्ट्र	मुंबई, नागपुर, पुणे		
मणिपुर	इम्फाल		
मेघालय	शिलांग, तूरा		
मिजोरम	आइजोल		
नगालैंड	कोहिमा		

दूरदर्शन नेटवर्क **(01.11.2016** तक**)**															
क्रमांक	राज्य/यूटी	ट्रांसमीटरों की संख्या													
		मुख्य चैनल (डीडी–1)					समाचार चैनल (डीडी न्यूज)				प्रसारण की समूची अवधि के दौरान प्रादेशिक कार्यक्रम प्रसारित करने वाले डीडी–1 ट्रांसमीटर्स				डीटीटी
		HP Ts	**LP Ts**	**VLP Ts**	**Tr p**	**TOT AL**	**HP TS**	**LP Ts**	**VLP Ts**	**TOT AL**	**HP TS**	**LP Ts**	**VLP Ts**	**TOT AL**	**HP Ts**
1	आंध्र प्रदेश	7	37		1	**45**	3	6		**9**			8	**8**	
2	अरुणाचल प्रदेश	1	3	39		**43**	1			**1**				**0**	
3	असम	4	20	1	1	**26**	2	1		**3**				**0**	**1**
4	बिहार	4	28	2		**34**	2	2		**4**				**0**	**1**
5	छत्तीसगढ़	4	15	8		**27**	1			**1**				**0**	**1**
6	गोवा	1				**1**	1			**1**				**0**	
7	गुजरात	7	51			**58**	4	3		**7**			3	**3**	**1**
8	हरियाणा	2	13			**15**	1	7		**8**				**0**	
9	हिमाचल प्रदेश	3	7	39	2	**51**	2	1		**3**				**0**	
10	जम्मू और कश्मीर	10	7	67	1	**85**	5	3		**8**	4	8	17	**29**	
11	झारखंड	3	17	2		**22**	2	2	1	**5**				**0**	**1**
12	कर्नाटक	8	47			**55**	4	2		**6**			7	**7**	**1**
13	केरल	4	20			**24**	3	2		**5**			4	**4**	
14	मध्य प्रदेश	8	60	6		**74**	4			**4**				**0**	**2**
16	महाराष्ट्र	8	78			**86**	5	10		**15**			20	**20**	**2**
17	मणिपुर	2	1	4		**7**	1			**1**				**0**	
15	मेघालय	2	3	2		**7**	2			**2**				**0**	
18	मिजोरम	2	1	2		**5**	1	1		**2**				**0**	
19	नगालैंड	2	2	6	2	**12**	1	1		**2**				**0**	
20	ओडिशा	5	62		1	**68**	2	7	2	**11**			16	**16**	**1**
21	पंजाब	4	4			**8**	3	1		**4**				**0**	**1**
22	राजस्थान	7	65	17	2	**91**	4	4		**8**				**0**	
23	सिक्किम	1		6		**7**	1			**1**				**0**	
24	तमिलनाडू	6	42		1	**49**	2	10		**12**	1		7	**8**	**1**
25	तेलंगाना	3	36			**39**	1			**1**			1	**1**	
26	त्रिपुरा	1	5	1	1	**8**	1	1		**2**				**0**	
27	उत्तर प्रदेश	11	53	3		**67**	7	9	1	**17**				**0**	**1**
28	उत्तराखंड	1	15	31	2	**49**	1	2		**3**				**0**	
29	पश्चिम बंगाल	8	15			**23**	4	2		**6**	1		1	**2**	**1**

30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	19		**21**	1	1	6	**8**				**0**	
31	चंडीगढ़		1			**1**				**0**				**0**	
32	दादर और नगर हवेली		1			**1**				**0**				**0**	
33	दमन और दीव		2			**2**				**0**				**0**	
34	दिल्ली	1				**1**	1			**1**				**0**	**2**
35	लक्षद्वीप समूह		1	1		**2**			7	**7**			7	**7**	
36	पुडुचेरी	1	1	1		**3**		1		**1**			1	**1**	
	कुल	**132**	**714**	**257**	**14**	**1117**	**73**	**79**	**17**	**169**	**6**	**8**	**92**	**106**	**17**
	ट्रांसमीटरों की कुल संख्या					**1409**									

अनुलग्नक – III

njn’ku dk puy

अखिल भारतीय चैनल (6)	डीडी नेशनल	डीडी न्यूज	डीडी स्पोर्ट्स
	डीडी भारती	डीडी उर्दू	डीडी किसान
प्रादेशिक चैनल (16)	डीडी मलयालम	डीडी चंदना	डीडी यदगिरी
	डीडी पोधीगई	डीडी सह्याद्री	डीडी गिरनार
	डीडी उड़िया	डीडी कशीर	डीडी पूर्वोत्तर
	डीडी बांग्ला	डीडी पंजाबी	डीडी राजस्थान
	डीडी बिहार	डीडी उत्तर प्रदेश	डीडी मध्य प्रदेश
	डीडी सप्तगिरी		
राज्य नेटवर्क (11)	हिमाचल प्रदेश	झारखंड	छत्तीसगढ़
	हरियाणा	उत्तराखंड	त्रिपुरा
	मिजोरम	मेघालय	मणिपुर
	अरुणाचल प्रदेश	नगालैंड	
अंतरराष्ट्रीय चैनल (1)	डीडी इंडिया		

अनुलग्नक-IV

01.11.2017 तक डीडी फ्री डिश चैनलों का संक्षिप्त विवरण

टीएस-1	टीएस -2	टीएस -3	टीएस -4	टीएस -5
Freq (MHz) U/L-14140 D/L-11090 S.R. 29.5 MSPS FEC 3/4 GSAT -15	Freq (MHz) U/L-14220 D/L-11170 S.R. 29.5 MSPS FEC 3/4 GSAT -15	Freq (MHz) U/L-14270 D/L-11470 S.R. 29.5 MSPS FEC 3/4 GSAT -15	Freq (MHz) U/L-14310 D/L-11510 S.R. 29.5 MSPS FEC 3/4 GSAT -15	Freq (MHz) U/L-14350 D/L-11550 S.R. 29.5 MSPS FEC 3/4 GSAT -15
टीवी चैनल				
1. डीडी–नेशनल	17. डीडी राजस्थान	33. नापतोल ब्ल्यू	49. बिग मैजिक	65. मनोरंजन मूवीज़
2. डीडी न्यूज	18. डीडी उड़िया	34. डीडी उर्दू	*50.* टेस्ट 402	66. मूवीज हाउस
3. डीडी स्पोर्ट्स	19. डीडी पोधीगई	35. सिनेमा टीवी	51. 9एक्सएम	67. हाउसफुल मूवीज
4. डीडी किसान	20. डीडी पंजाबी	36. डीडी सप्तगिरी	*52.* टेस्ट 404	68. स्टार उत्सव मूवीज़
5. डीडी भारती	21. डीडी सह्याद्री	37. इंडिया टीवी	53. ज़ी हिन्दुस्तान	69. रशिया टुडे
6. डीडी बांग्ला	22. डीडी यदगिरी	*38.* टेस्ट 306	54. स्टार उत्सव	70. ज़ी अनमोल सिनेमा
7. डीडी चंदना	23. डीडी मलयालम	39. मनोरंजन टीवी	55. जी अनमोल	71. 9एक्स बजाओ
8. डीडी गिरनार	24. लोक सभा	40. न्यूज नेशन	56. मस्ती	*72.* टैस्ट 508
9. डीडी कशीर	25. राज्य सभा	41. सोनी पल	57. बी–4यू म्यूजिक	73. चड़दीकला टाइम टीवी
10. महा मूवी	*26.* टैस्ट 210	42. दबंग	*58.* टेस्ट 410	74. डीडी इंडिया
11. टेस्ट 111	27. दंगल	43. रिश्ते	59. न्यूज स्टेट यूपी/यूके	75. 9एक्स जलवा
12. बी–4यू मूवीज	28. भोजपुरी चैनल	44. सोनी मिक्स	60. न्यूज 24	76. रिश्ते सिनेप्लेक्स
13. वॉव सिनेमा	29. डीडी बिहार	45. होम शॉप 18	61. सोनी वाह	77. स्टार स्पोर्ट फर्स्ट
14. इंडिया न्यूज	30. डीडी पूर्वोत्तर	46. डीडी एमपी	62. आजतक	78. एमटीवी बीट्स
15. न्यूज 18 इंडिया	31. डीडी यूपी	47. एंटर 10	63. एबीपी न्यूज	79. ईटीवी राजस्थान
16. बिग मैजिक गंगा	32. साधना नेशनल	48. स्टार भारत	64. जी न्यूज	80. ईटीवी यूपी/उत्तराखंड

रेडियो चैनल				
1. एआईआर वीबीएस	9. एआईआर गुजराती	17. एआईआर कन्नड़	25. एआईआर रागम	33. एआईआर कोहिमा
2. एआईआर तेलुगू	10. एफएम रेनबो	18. एआईआर बांग्ला	26. रेनबो बंगलौर	34. एआईआर आइजोल
3. एआईआर मराठी	11. एआईआर पंजाबी	19. एआईआर हिन्दी	27. एआईआर उर्दू	35. एआईआर इटानगर
4. एआईआर तमिल	12. एफएम गोल्ड	20. एआईआर पूर्वोत्तर	28. एआईआर उड़िया	36. एआईआर अगरतला
5. एआईआर नेशनल	13. रेडियो कश्मीर	21. एआईआर चेन्नई	29. एआईआर मलयालम	37. एआईआर रोहतक
6. रेनबो कोलकाता	14. एआईआर लखनऊ	22. एफएम गोल्ड मुंबई	30. एआईआर असमी	38. एआईआर शिमला
7. एआईआर विजयवाड़ा	15. एआईआर पटना	23. एआईआर जयपुर	31. एफएम गोल्ड चेन्नई	39. एआईआर वाराणसी
8. एआईआर इम्फाल	16. एआईआर भोपाल	24. रेनबो मुंबई	32. एफएम गोल्ड कोलकाता	*40. रेडियो टैस्ट 508*
कुल टीवी चैनल्स – 80/73, कुल रेडियो चैनल्स – 39				

अनुलग्नक – V

डिजिटल हाई पावर टीवी ट्रांसमीटर प्रोजेक्ट्स

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	11वीं योजना के अंश के तौर पर अनुमोदित		12वीं योजना के अंश के तौर पर अनुमोदित
		पहला चरण – 19	दूसरा चरण – 21	23
1	आंध्र प्रदेश		विजयवाड़ा	तिरुपति
2	अरुणाचल प्रदेश			इटानगर
3	असम	गुवाहाटी		
4	बिहार	पटना		मुजफ्फरपुर
5	छत्तीसगढ़	रायपुर		जगदलपुर
6	गुजरात	अहमदाबाद	सूरत	
			वडोदरा	
			राजकोट	
7	हरियाणा			हिसार
8	हिमाचल प्रदेश		कसौली	शिमला
9	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर		जम्मू
10	झारखंड	रांची		जमशेदपुर
11	कर्नाटक	बंगलुरू	मैसूर	शिमोगा
				धारवाड़
12	केरल	तिरुवनंतपुरम	कोच्चि	कोझिकोड
13	मध्य प्रदेश	भोपाल	ग्वालियर	
		इंदौर		
14	महाराष्ट्र	मुंबई	नागपुर	अम्बाजोगई
		औरंगाबाद	पुणे	

15	मणिपुर			चूड़चंदपुर
16	मेघालय			शिलांग
17	मिजोरम			लुंगलेई
18	नगालैंड			मोकोकचुंग
19	ओडिशा	कटक		बालासोर (बालेश्वर)
20	पंजाब	जालंधर	अमृतसर	
21	राजस्थान		जयपुर	बूंदी
				बाड़मेर
22	सिक्किम			गंगटौक
23	तमिलनाडु	चेन्नई	कोडइकनाल	रामेश्वरम
24	तेलंगाना	हैदराबाद		
25	त्रिपुरा			अगरतला
26	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	कानपुर	
			वाराणसी	
			इलाहाबाद	
			आगरा	
			बरेली	
27	उत्तराखंड		मसूरी	
28	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कुर्सियांग	आसनसोल
			कृष्णा नगर	
29	दिल्ली	दिल्ली		

अनुलग्नक - VI

महत्वपूर्ण कवरेज (अप्रैल 2017 से अक्तूबर 2017)			
क्रम संख्या	कार्यक्रम	स्थान	दिनांक
1.	XVII राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक एवं XVI राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता	जयपुर	01-04 अप्रैल,17
2.	माननीय प्रधानमंत्री का इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भव्य समापन समारोह के दौरान उपस्थिति का सीधा प्रसारण	इलाहाबाद	02 अप्रैल, 17
3.	पूर्व उप–प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के श्रद्धांजली समारोह के दौरान माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति का सीधा प्रसारण	दिल्ली	05 अप्रैल,17
4.	झारखंड के साहिबगंज में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रेलवे पुल के उद्घाटन का सीधा प्रसारण	साहिबगंज	06 अप्रैल,17
5.	रक्षा एवं नागरिक अधिष्ठापन समारोह में माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिति का सीधा प्रसारण	राष्ट्रपति भवन	06 अप्रैल,17

6.	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राधिकापुर रेलवे स्टेशन से बांग्लादेश के लिए रवाना गाड़ी को और कोलकाता–कुल्ना–ढाका के बीच बस सेवा को रवाना किए जाने का सीधा प्रसारण।	दिल्ली, राधिकापुर रेलवे स्टेशन और कोलकाता बस स्टेशन	08 अप्रैल,17
7.	भारतीय सांसदों और मुंबई हीरोज के बीच क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण।	धर्मशाला	08 अप्रैल,17
8.	जनपथ, नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छाग्रह का सीधा प्रसारण।	दिल्ली	10 अप्रैल,17
9.	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की जन्मतिथि के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री के सानिध्य में आयोजित समारोह का सीधा प्रसारण।	दिल्ली	14 अप्रैल,17
10.	महाराष्ट्र के कोराडी थर्मल पावर प्लांट में प्रधानमंत्री की यात्रा का सीधा प्रसारण।	कोराडी	14 अप्रैल,17
11.	दीक्षा भूमि, नागपुर में माननीय प्रधानमंत्री की यात्रा का सीधा प्रसारण।	नागपुर	14 अप्रैल,17
12.	विभिन्न मुख्यालयों द्वारा टेलिकॉन्फ्रेंसिंग/हॉट स्विचिंग के जरिए माननीय प्रधानमंत्री की लोक सेवाओं से संबंधित समारोह में उपस्थिति।	दिल्ली	21 अप्रैल,17
13.	हैदराबाद हाउस में श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ माननीय प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बातचीत का सीधा प्रसारण।	दिल्ली	26 अप्रैल,17
14.	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शिमला, कोडापा और नांदेद से उड़ान फ्लाइट्स के फ्लैग ऑफ का सीधा प्रसारण।	शिमला, कोडपा और नांदेड़	27 अप्रैल,17
15.	माननीय प्रधानमंत्री और साइप्रस के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बातचीत का हैदराबाद हाउस से सीधा प्रसारण।	दिल्ली	28 अप्रैल,17
16.	नई दिल्ली के विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अंतरराष्ट्रीय बसावा सम्मेलन के उद्घाटन का सीधा प्रसारण।	दिल्ली	29 अप्रैल,17
17.	माननीय प्रधानमंत्री की केदारनाथ धाम यात्रा का सीधा प्रसारण।	केदारनाथ	03 मई,17
18.	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हरिद्वार स्थित पतंजलि शोध संस्थान के उद्घाटन और जनसभा को संबोधित किए जाने का सीधा प्रसारण।	हरिद्वार	03 मई,17
19.	नई दिल्ली में आयोजित सीनियर एशियन फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन स्टाइल और महिला कुश्ती प्रतियोगिता–2017 का सीधा प्रसारण।	नई दिल्ली	10-14 मई,17
20.	माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा न्यूमोकोकल कॉन्ज्युगेट वैक्सीन (पीसीवी) के लोकार्पण का सीधा प्रसारण।	मंडी (हिमाचल प्रदेश)	13 मई,17
21.	माननीय प्रधानमंत्री की अमरकंटक (मध्य प्रदेश) की यात्रा का सीधा प्रसारण – दो कवरेज	अमरकंटक	15 मई,17
22.	बिहार के बक्सर स्थित गेरुआबंद गांव से हॉट स्विचिंग/टेलिकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र सरकार के कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम का सीधा प्रसारण।	बक्सर	17 मई,17

23.	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कांदला बंदरगाह पुरस्कार समारोह का उद्घाटन और जनसभा संबोधन का सीधा प्रसारण।	कांदला (गुजरात)	22 मई,17
24.	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नर्मदा नहर के उद्घाटन का सीधा प्रसारण।	भचाऊ (गुजरात)	22 मई,17
25.	माननीय प्रधानमंत्री के सानिध्य में गुजरात के गांधी नगर स्थित महात्मा मंदिर में अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत का सीधा प्रसारण।	गांधीनगर (गुजरात)	23 मई,17
26.	असम के तिनसुखिया में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सदिया ढोला सेतु के उद्घाटन का सीधा प्रसारण।	तिनसुखिया	26 मई,17
27.	असम के धेमाजी स्थित गोगामुख में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आईएआरआई के शिलान्यास का सीधा प्रसारण।	धेमाजी, (असम)	26 मई,17
28.	हैदराबाद हाउस में माननीय प्रधानमंत्री की मॉरीशस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता का सीधा प्रसारण।	दिल्ली	27 मई,17
29.	नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से डीडी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का सीधा प्रसारण।	सीपीसी	28 मई,17
30.	पुरी से स्नान पूर्णिमा का सीधा प्रसारण।	पुरी	09 जून,17
31.	16वें नॉर्थ–ईस्ट रीजन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण।	इम्फाल	15 जून,17
32.	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कोझिकोड के किनालूर स्थित उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स के सिंथेटिक ट्रेक के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उद्घाटन का सीधा प्रसारण।	किनालूर, कोझिकोड	15 जून,17
33.	नई दिल्ली के विज्ञान भवन से आकाशवाणी पुरस्कार समारोह का सीधा प्रसारण।	विज्ञान भवन, नई दिल्ली	16 जून,17
34.	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कोच्चि मैट्रो लाइन के उद्घाटन के लिए एर्नाकुलम कोच्चि की यात्रा का सीधा प्रसारण।	कोच्चि, केरल	17 जून,17
35.	माननीय राष्ट्रपति द्वारा बंग्लुरु विधान सभा से मैट्रो प्रथम चरण के लोकार्पण का सीधा प्रसारण।	बेंग्लुरु	17 जून,17
36.	माननीय प्रधानमंत्री की एर्नाकुलम के सेंट टेरेसा कॉलेज की यात्रा का सीधा प्रसारण।	एर्नाकुलम	17 जून,17
37.	मुंगेर, वाराणसी के अस्सी घाट और गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से योग दिवस के अवसर पर 'योगोत्सव' का सीधा प्रसारण जिसे दूरदर्शन के हॉट स्विचिंग/टेलिकॉन्फ्रेंसिंग से योग सप्ताह के तौर पर प्रसारित किया गया।	मुंगेर, वाराणसी और गोरखपुर	19-20 जून,2017
38.	अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 2017 का सीधा प्रसारण।	लखनऊ	19-22 जून,2017
39.	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लखनऊ के एपीटीयू कैम्पस के उद्घाटन का सीधा प्रसारण।	लखनऊ	20 जून,17
40.	तीसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री की लखनऊ यात्रा का सीधा प्रसारण।	लखनऊ	21 जून,17

41.	पुरी की रथ यात्रा का सीधा प्रसारण।	पुरी	25 जून,17
42.	जीएसटी पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण।	दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरू, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर और दिल्ली	01 जुलाई,17
43.	22वें एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण। दूरदर्शन ने इसे मेजबान प्रसारक के तौर पर कवर किया।	भुवनेश्वर	05-09 जुलाई,17
44.	जीएसटी मास्टर क्लासेस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण।	दिल्ली	06-12 जुलाई,17
45.	स्किल इंडिया की वर्षगांठ का सीधा प्रसारण।	विज्ञान भवन	15 जुलाई,17
46.	माननीय राष्ट्रपति द्वारा 20.07.2017 को पैका विद्रोह की 200वीं वर्षगांठ के स्मारक आयोजन के उद्घाटन का सीधा प्रसारण।	विज्ञान भवन	20 जुलाई,17
47.	25.07.2017 (मंगलवार) को भारत के माननीय राष्ट्रपति के शपथ समारोह का सीधा प्रसारण।	दिल्ली	25 जुलाई,17
48.	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रामेश्वरम में एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक की यात्रा का सीधा प्रसारण।	रामेश्वरम	27 जुलाई,17
49.	भारत के नव–निर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण।	दिल्ली	4 अगस्त,17
50.	भारत के नव–निर्वाचित उप–राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का राष्ट्रपति भवन से सीधा प्रसारण।	दिल्ली	11 अगस्त,17
51.	जन्माष्टमी पर्व का सीधा प्रसारण।	मथुरा	15 अगस्त,17
52.	स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण।	दिल्ली	15 अगस्त,17
53.	डीडीके दिल्ली से ग्रेंड स्टैंड के साथ वर्ली–मुंबई, वाघा बॉर्डर, वाराणसी, जैसलमेर, कोच्चि, हैदराबाद, शिमला, विजय चौक–दिल्ली, कन्याकुमारी, औली और पोर्ट ब्लेयर से संकल्प से सिद्धि शो का सीधा प्रसारण।	वर्ली, वाघा बॉर्डर, कोच्चि, वाराणसी, जैसलमेर, हैदराबाद, शिमला, दिल्ली, कन्याकुमारी, औली, पोर्ट ब्लेयर	15 अगस्त,17
54.	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हैदराबाद हाउस से कटैय्या–कुशाहा प्रसारण रेखा के उद्घाटन का सीधा प्रसारण जिसे नेपाल में रिमोट ऑपरेशन से शुरू किया गया।	दिल्ली, कटैय्या, कुशाहा	24 अगस्त,17
55.	राष्ट्रपति भवन से भारत के नव–निर्वाचित मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण।	दिल्ली	28 अगस्त,17

56.	सतीश धवन स्पेस सेंटर (एसएचएआर) से पीएसएलवी–सी39 / आईआरएनएसएस–1एच के प्रक्षेपण का सीधा प्रसारण।	श्रीहरिकोटा	31 अगस्त,17
57.	माननीय राष्ट्रपति की तिरुपति यात्रा का सीधा प्रसारण।	तिरुपति	01 सितंबर,17
58.	माननीय राष्ट्रपति की अहमदाबाद के साबरमती आश्रम की यात्रा का सीधा प्रसारण।	अहमदाबाद	03 सितंबर,17
59.	माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2016 के वितरण समारोह का सीधा प्रसारण।	विज्ञान भवन	05 सितंबर,17
60.	माननीय राष्ट्रपति के सानिध्य में 2017 के अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस का सीधा प्रसारण।	विज्ञान भवन	8- सितंबर-17
61.	माननीय प्रधानमंत्री के सानिध्य में नई दिल्ली के इंडिया गेट से नार्थ ईस्ट कॉलिंग (फैशन शो) का सीधा प्रसारण।	नई दिल्ली	10 सितंबर,17
62.	माननीय प्रधानमंत्री के सानिध्य में आयोजित स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो धर्म संसद के संभाषण की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण।	विज्ञान भवन	11 सितंबर,17
63.	माननीय प्रधानमंत्री और जापानी प्रधानमंत्री की साबरमती आश्रम और नदी आमुख यात्रा का सीधा प्रसारण।	अहमदाबाद	13 सितंबर,17
64.	माननीय प्रधानमंत्री और जापानी प्रधानमंत्री की हवाई अड्डे से साबरमती आश्रम तक की यात्रा के रोड शो का सीधा प्रसारण।	अहमदाबाद	13 सितंबर,17
65.	माननीय प्रधानमंत्री की सिद्धि सैयद जली की यात्रा का सीधा प्रसारण।	अहमदाबाद	13 सितंबर,17
66.	माननीय प्रधानमंत्री और जापानी प्रधानमंत्री द्वारा साबरमती मैदान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुलेट ट्रेन के शिलान्यास और रेल विश्वविद्यालय बड़ोदा के उद्घाटन और जन संबोधन का सीधा प्रसारण।	अहमदाबाद	14 सितंबर,17
67.	माननीय प्रधानमंत्री और जापानी प्रधानमंत्री द्वारा दांडी कुटीर, महात्मा मंदिर की यात्रा का सीधा प्रसारण।	अहमदाबाद	14 सितंबर,17
68.	माननीय राष्ट्रपति द्वारा लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के नागरिक अभिनंदन में शामिल होने का सीधा प्रसारण।	लखनऊ	14 सितंबर,17
69.	माननीय राष्ट्रपति के सानिध्य में हिन्दी दिवस समारोह 2017 का सीधा प्रसारण।	विज्ञान भवन	14 सितंबर,17
70.	कानपुर के ईश्वरीगंज गांव में स्वच्छता ही सेवा के उद्घाटन के लिए माननीय राष्ट्रपति की यात्रा का सीधा प्रसारण।	कानपुर	15 सितंबर,17
71.	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मार्केट यार्ड और एक जन सभा के उद्घाटन का सीधा प्रसारण।	अहमदाबाद	17 सितंबर,17
72.	नए इंटेलिजेंस सेटअप, इंटरेक्टिव मोबाइल एप और एसएसबी द्वारा छात्रवृत्ति वितरण के उद्घाटन का सीधा प्रसारण।	विज्ञान भवन	18 सितंबर,17

73.	माननीय प्रधानमंत्री के सानिध्य में राष्ट्रीय निर्वाचिका का सीधा प्रसारण।	विज्ञान भवन	21 सितंबर,17
74.	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी के बड़ा लालपुर से रिमोट द्वारा वडोदरा और सूरत रेलवे स्टेशन से गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने और जनसभा संबोधित करने का सीधा प्रसारण।	वाराणसी	22 सितंबर,17
75.	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी के अराजी लाइन में पशुधन आरोग्य मेला और जनसभा संबोधन का सीधा प्रसारण।	वाराणसी	23 सितंबर,17
76.	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा डीआरडीओ भवन में भारत सरकार के सहायक सचिवों को संबोधन का सीधा प्रसारण।	दिल्ली	26 सितंबर,17
77.	माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार वितरण का सीधा प्रसारण।	विज्ञान भवन	27 सितंबर,17
78.	जीरो संगीत समारोह का सीधा प्रसारण।	इटानगर	28-30 सितंबर,17
79.	दशहरा उत्सव समारोह का सीधा प्रसारण जिसमें माननीय राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे।	दिल्ली	30 सितंबर,17
80.	महात्मा गांधी के 148वें जयंती समारोह का सीधा प्रसारण।	दिल्ली	02 अक्तूबर,17
81.	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बिलासपुर में एम्स के शिलान्यास और जनसभा संबोधन का सीधा प्रसारण।	बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)	03 अक्तूबर,17
82.	फीफा अंडर–17 फुटबॉल वर्ल्ड कप संबंधित कवरेज का सीधा प्रसारण।	दिल्ली	04-28 अक्तूबर,17
83.	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ओखा और बेट द्वारा के बीच पुल के शिलान्यास और उसके बाद जनसभा संबोधन का सीधा प्रसारण।	द्वारका	07 अक्तूबर,17
84.	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चोटिला के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के शिलान्यास और उसके बाद जनसभा संबोधन का सीधा प्रसारण।	राजकोट	07 अक्तूबर,17
85.	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गांधी नगर में नई आईआईटी बिल्डिंग के लोकार्पण और उसके बाद जनसभा संबोधन का सीधा प्रसारण।	गांधीनगर	07 अक्तूबर,17
86.	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वाडनगर में मिशन इंद्रधनुष के उद्घाटन, मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण और हटकेश्वर मंदिर की यात्रा का सीधा प्रसारण।	वाडनगर	08 अक्तूबर,17
87.	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भरूच गांव में बांध के शिलान्यास और रिमोट द्वारा उधाना (सूरत) रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना करने का सीधा प्रसारण।	भरूच और उधाना	08 अक्तूबर,17
88.	भारतीय वायुसेना की 85वीं वर्षगांठ पर सीधा प्रसारण।	गाजियाबाद	08 अक्तूबर,17
89.	माननीय प्रधानमंत्री के सानिध्य में विज्ञान कॉलेज मैदान में पटना विश्वविद्यालय शताब्दी वर्ष कार्यक्रम आयोजन का सीधा प्रसारण।	पटना	14 अक्तूबर,17
90.	माननीय प्रधानमंत्री के सानिध्य में मोकमा में स्वच्छता कार्यक्रम और जनसभा का सीधा प्रसारण।	मोकमा	14 अक्तूबर,17

91.	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दूसरे आयुर्वेद दिवस के उद्घाटन का सीधा प्रसारण।	दिल्ली	17 अक्तूबर,17
92.	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भावनगर के निकट घोघा में फेरी सेवा और आरओ–पैक्स के उद्घाटन का सीधा प्रसारण।	घोघा	17 अक्तूबर,17
93.	पुलिस स्मृति दिवस का सीधा प्रसारण।	दिल्ली	21 अक्तूबर,17
94.	सीमा सुरक्षा बल हाफ मैराथन का सीधा प्रसारण।	दिल्ली	22 अक्तूबर,17
95.	भारत–तिब्बत सीमा पुलिस के 56वें स्थापना दिवस का सीधा प्रसारण।	ग्रेटर नोएडा	24 अक्तूबर,17
96.	माननीय प्रधानमंत्री के सानिध्य में नए बाजारों में उपभोक्ता सशक्तिकरण संबंधित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण।	दिल्ली	26 अक्तूबर,17
97.	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कर्नाटक के धर्मस्थल में दर्शन एवं पूजा का सीधा प्रसारण।	कर्नाटक	29 अक्तूबर,17
98.	माननीय उप–राष्ट्रपति द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम के उद्घाटन का सीधा प्रसारण।	दिल्ली	30 अक्तूबर,17
99.	पुलिस अकादमी की पासिंग आउट परेड का सीधा प्रसारण।	हैदराबाद	30 अक्तूबर,17
100.	पटेल चौक, ध्यानचंद स्टेडियम और इंडिया गेट से राष्ट्रीय एकता दिवस का सीधा प्रसारण।	दिल्ली	31 अक्तूबर,17

प्रस्तावित महत्वपूर्ण कवरेज (नवंबर 2017 से मार्च 2018)

क्रम संख्या	कार्यक्रम	स्थान	दिनांक
1.	वर्ल्ड फूड इंडिया–2017 के उद्घाटन का सीधा प्रसारण जिसमें चार से पांच देशों के माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होंगे।	विज्ञान भवन एवं इंडिया गेट	03 नवंबर,17
2.	प्रवासी भारतीय केंद्र, नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में व्यवसाय करने में सुलभता पर माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण।	दिल्ली	04 नवंबर,17
3.	33वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण।	हैदराबाद	10-14 नवंबर,17
4.	दूसरे हॉकी इंडिया 5–ए साइड सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप 2017 (महिला एवं पुरुष) का सीधा प्रसारण।	विशाखापट्टनम	11-12 नवंबर,17
5.	20वें एशियन मैन्स क्लब लीग हैंडबॉल प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण।	हैदराबाद	20-30 नवंबर,17
6.	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट के उद्घाटन का सीधा प्रसारण।	हैदराबाद	28 नवंबर,17
7.	राजपथ, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन पर गणतंत्र दिवस समारोह–2018	दिल्ली	26 जनवरी,18
8.	गैरीसन परेड ग्राउंड पर प्रधानमंत्री की एनसीसी रैली	दिल्ली	28 जनवरी,18
9.	विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट	दिल्ली	29 जनवरी,18
10.	बजट संबंधित कवरेज	दिल्ली	1 फरवरी , 18

vkdk'kok.kh ekufp=

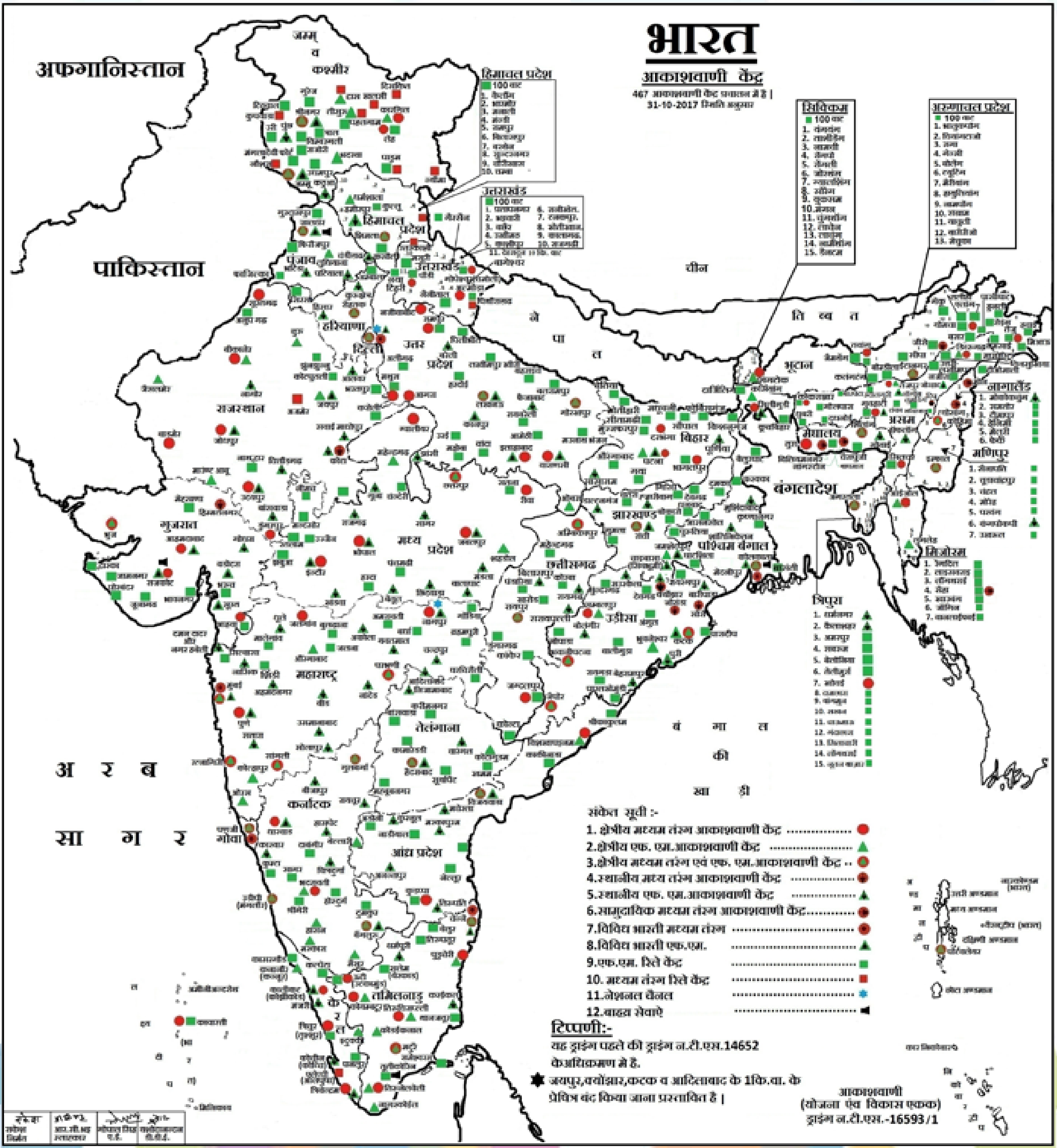

vkdk'kok.kh

rF; ,d utj esa		
1 çlkj.k dsaæ		467
¼,½ ik.kh LVwfM;ks ds lkFk dsaæ		220
i) स्थानीय रेडियो केंद्र		86
ii) एलआरएस के अलावा स्टूडियो के साथ केंद्र		129
iii) सामुदायिक रेडियो केंद्र		5
¼ch½ fjys dsaæ		247
(209 100 डब्ल्यू एफएम रिले केंद्रों सहित)		
(सी) एफएम ट्रांसमीटर वाले आकाशवाणी के स्टेशन		439
(डी) विविध भारती केंद्र		41
(ई) विदेश सेवाओं के लिए प्रेषण केंद्र		11
(एफ) रिकॉर्डिंग स्टूडियो		1 (भुवनेश्वर)
2 VªkalehVjksa dh la[;k		662
(ए) मीडियम वेव		140
(बी) शार्ट वेव		48
(सी) एफएम		474
¼3½ çlkj.k dojst	{ks= (%)	tula[;k (%)
प्राथमिक ग्रेड सिग्नल द्वारा		
(मीडियम वेव+एफएम	92.00%	99.20%
केवल एफएम सिग्नल द्वारा	39.00%	52.00%
केवल मीडियम वेव सिग्नल द्वारा	90.65%	98.40%
¼4½ dfIVo vFkZ dsaæ		32
¼5½ LVwfM;ks		228
¼6½ vkj,u;w		47
¼7½ vkdk'kok.kh ds MhVh,p pSuy		39
¼8½ lh/kk LVªhfeax pSuy		17

vfHk;kaf=dh

¼,½ usVodZ foLrkj vkSj dojst

आकाशवाणी विश्व के सबसे बड़े प्रसारण नेटवर्कों में एक है। देश की स्वतंत्रता के समय 6 रेडियो केंद्र और 18 ट्रांसमीटर (6 मीडियम वेव और 12 शार्टवेव) थे जो 11 प्रतिशत जनसंख्या को और देश के 2.5 प्रतिशत क्षेत्र को कवर करते थे।

31 अक्टूबर, 2017 तक आकाशवाणी के नेटवर्क का विस्तार 467 स्टेशनों और 662 ट्रांसमीटरों तक हुआ है, जो देश के 92.00 प्रतिशत क्षेत्र में फैले 99.20 प्रतिशत आबादी को कवर करता है। इसमें लगभग 8–10 किमी क्षेत्रों के स्थानीय कवरेज के लिए 238 100 डब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर शामिल हैं।

¼ch½ o"kZ ds nkSjku çeq[k xfrfof/k;ka

1. 1 अप्रैल, 2017 से 31 अक्टूबर, 2017 तक, स्टेशनों की संख्या 419 से बढ़कर 467 और ट्रांसमीटरों की संख्या 608 से बढ़कर 662 हो गई है।

¼,½ o"kZ ds nkSjku vkjaHk fd, x, u, dsaæ@VªkalehVj	
1 देहरादून (उत्तराखंड)	स्टूडियो सुविधाओं के साथ 10 किलोवाट एफएम रेडियो केंद्र
2 कोटपुतली (राजस्थान)	एलपीटीपी कोटपुतली में 100 डब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर स्थापित
3 लोंगथेराई (त्रिपुरा)	स्टूडियो सुविधा के साथ 5 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर
4 गोवालपाड़ा (असम)	1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर (रिले)
5 नूतन बाजार (त्रिपुरा)	1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर (रिले)
6 लुमडिंग (असम)	1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर (रिले)
7 फेक (नगालैंड)	1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर (रिले)
8 उखरुल (मणिपुर)	1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर (रिले)
¼ch½ o"kZ ds nkSjku orZeku dsaæ ij VªkalehVj vkjaHk	
1 धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश)	पुरानी 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर के स्थान पर 10 किलोवाट का नया एफएम ट्रांसमीटर लगाया गया।
2 कोटा (राजस्थान)	1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर
3 तुरा (मेघालय)	दूरदर्शन स्थल पर पर 5 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर,
4 चेरापूंजी (मेघालय)	1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर

¼lh½ vU; xfrfof/k;ka

1 {ks=h; lekpkj bdkbZ ¼vkj,u;w½ u dk;Z çkjaHk fd;k

2 vkdk'kok.kh ds 4 pSuyksa ds lh/kk LVªhfeax dh eatwjh

3 MhMh Ýh 7 fMft'k ¼MhVh,p½ ij jsfM;ks pSuyksa dh eatwjh

- रतलाम, नेल्लोर और सुलतानपुर में 10 किलोवाट का एफएम ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है, जबकि इटावा और उधमपुर में भूमि अधिग्रहण के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
- भारत– नेपाल सीमा के साथ 10 किलोवाट का एफएम ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए 5 स्थानों को चिन्हित किया गया है।
- लुधियाना में 10 किलोवाट का एफएम ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय परिसर में स्थान को अंतिम रूप दिया गया है।

¼2½ dsaæ@VªkalehVj rduhdh :i ls rS;kj

निम्नलिखित केंद्र कार्य करने के लिए तकनीकी रूप से तैयार हैं:

1 जलगांव (महाराष्ट्र)	5 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर
2 अमृतसर (पंजाब)	20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर

3 चौटन हिल (राजस्थान)	20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर
4 दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)	स्टूडियो सुविधा के साथ 10 किलोवाट का एफएम ट्रांसमीटर
5 सिलचर (असम)	स्टूडियो सुविधा के साथ 5 किलोवाट का एफएम ट्रांसमीटर
6 नौशेरा (जम्मू–कश्मीर)	10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर

¼3½ fMftVhdj.k ;kstuk

ijh dh xbZ vkj fØ;kfUor dh tk jgh ifj;kstuk,¡

i. वर्तमान स्टेशनों पर नए मीडियम वेव डिजिटल रेडियो मॉन्डियल (डीआरएम) ट्रांसमीटर द्वारा 33 पुराने मीडियम वेव ट्रांसमीटर बदले गए:

20 किलोवाट	संख्या 6	सभी ट्रांसमीटर स्थापित और चालू कर दिए गए हैं।
100 किलोवाट	संख्या 11	
200 किलोवाट	संख्या 10	
300 किलोवाट	संख्या 6	

ii. शार्ट वेव डिजिटल रेडियो मॉन्डियल (डीआरएम) ट्रांसमीटर द्वारा 3 शार्ट वेव ट्रांसमीटर बदले गए:

- 500 किलोवाट का एक शार्ट वेव डीआरएम ट्रांसमीटर बंगलुरु में स्थापित किया गया है और सेवा में है।
- किंग्सवे (दिल्ली) के लिए खरीदे गए 100 किलोवाट के 2 शार्ट वेव डीआरएम ट्रांसमीटर अब स्थापित किए जा रहे हैं।

iii. जिन ग्रामीण क्षेत्रों में तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों (वर्तमान आकाशवाणी/दूरदर्शन के एलपीटी स्थानों पर) में एफएम कवरेज का विस्तार करने के लिए 100 स्थानों पर 100 डब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर।

- सभी स्थानों पर ट्रांसमीटर स्थापित।

iv. दूरस्थ और सीमावर्ती इलाकों में 34 स्थानों पर (6 किलोवाट के 27 और 10 किलोवाट के 7) उसी शक्ति और 1 किलोवाट के 6 मीडियम वेव ट्रांसमीटर 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर द्वारा बदले गए:

- 10 किलोवाट के सभी 13 ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं।
- 6 किलोवाट के 27 एफएम ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं और सेवा में ली गई हैं।

v. 24 स्थानों पर 1 किलोवाट/5 किलोवाट के नए एफएम ट्रांसमीटर :

- 1 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर (12) और 5 किलोवाट के (12) स्थापित किए गए हैं और इनमें से अनेक सेवारत हैं।

vi. 98 स्टूडियो का डिजिटीकरण:

- सभी 98 स्टूडियो पर डिजिटल कंसोल उपलब्ध कराए गए।
- 48 स्टेशनों पर बैक–अप के ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर प्रदान किए गए हैं, शेष 50 स्टेशनों के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

vii. अभिलेखीय सुविधा का डिजिटीकरण

दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में अभिलेखीय सुविधा की स्थापना पूरी हो चुकी है जिसमें डाटाबेस सर्वर और भंडारण के साथ डिजिटाइजेशन और बहाली कार्य केंद्र शामिल हैं।

viii. मौजूदा 44 क्षेत्रीय समाचार इकाइयों (आरएनयू) का सुदृढ़ीकरण और 7 नए आरएनयू का निर्माण।

- सभी स्थानों पर सुदृढ़ीकरण कार्य पूरा किया गया।
- बनाई जाने वाली 7 क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में से 3 पुंछ, संबलपुर और विशाखापत्तनम में प्रारंभ की गई हैं और शेष 4 स्थानों – जोधपुर, राजकोट, दरभंगा और पासीघाट पर कार्य पूरा कर लिया गया है।

ix. 127 डिजिटल स्टूडियो ट्रांसमीटर लिंक

- 127 एसटीएल (स्टूडियो ट्रांसमीटर लिंक) की स्थापना कार्य प्रगति पर।

x. 5 नए कैप्टिव अर्थ केंद्र।

- देहरादून, सिलचर, तिरुचिरापल्ली, विजयवाड़ा और धारवाड़ में 5 नए कैप्टिव अर्थ स्टेशनों की स्थापना कार्य प्रगति पर है।

¼4½ tEew&d'ehj dk fy, fo'ks"k iSdst ¼pj.k&3½

- इस योजना में ग्रीन रिज (उरी सेक्टर), हिंबोतिंगला (लद्दाख क्षेत्र), पटनीटॉप (जम्मू क्षेत्र) और नौशेरा में मौजूदा टीवी साइट पर 10 किलोवाट के 4 ट्रांसमीटरों की स्थापना शामिल है।

- नौशेरा में 10 किलोवाट का एफएम ट्रांसमीटर तकनीकी तौर पर कार्य करने के लिए तैयार है और उरी, हिंबोतिंगला और पटनीटॉप में तीन अन्य पूरा होने वाले हैं।
- इसके अतिरिक्त, एफएम कवरेज प्रदान करने के लिए करगिल, द्रास, तीसुरु तथा पदम में 100 डब्ल्यू के 4 एफएम ट्रांसमीटर पहले से ही चालू हैं।

5½ iokÙkj {k= fo'k"k i dt ¼pj.k&2½

कार्यान्वयन के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र और द्वीप क्षेत्रों में हवाई सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए विशेष पैकेज में शामिल हैं:

i. ,d fdyksokV dk ,Q,e dæ&19

1. अरुणाचल प्रदेश	: रोइंग (अन्नी से मोड़ के तहत), चांगलंग, दापोरजियो, बमडलिया, खोनसा
2. असम	: करीमगंज, लुमडिंग, गोवा लपारा
3. मणिपुर	: उखरुल, तामेंगलोंग
4. मेघालय	: चेरापूंजी
5. मिजोरम	: तुइपांग, चेम्फाल, कोलासिब
6. नागालैंड	: वोखा, जुन्हेबोतो, फेक
7. त्रिपुरा	: उदयपुर, नूतन बाजार

19 नए एफएम केंद्र स्थापित करने के लिए नए स्थानों की आवश्यकता थी। संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से साइटों (स्थलों) के अधिग्रहण की कठिन प्रक्रिया ने इस योजना में विलंब की।

- 19 में से 17 स्थानों का अधिग्रहण कर लिया गया है।
- 6 स्थानों– गोवालपाड़ा, नूतन बाजार, चेरापूंजी, लुमडिंग, फेक और उखरुल में ट्रांसमीटर चालू किए गए। 10 स्थानों पर ट्रांसमीटर स्थापित किया गया और 1 स्थान पर कार्य प्रगति पर है।

  तमेंगलोंग में उचित स्थान नहीं पाया गया और अब सेनापति (मणिपुर) में केंद्र स्थानांतरित करने पर विचार किया जा रहा है।
- तामेंगलोंग में उचित स्थान नहीं पाया गया और अब सेनापति (मणिपुर) में केंद्र स्थानांतरित करने पर विचार किया जा रहा है।

  अनीनी (अरुणाचल प्रदेश) में उपयुक्त जगह नहीं मिली और अब केंद्र को नमसई (अरुणाचल प्रदेश) के स्थानांतरित करने पर विचार किया जा रहा है।

ii. 100 स्थानों पर 100 डब्ल्यू का एफएम रिले ट्रांसमीटर : 96 स्थानों पर ट्रांसमीटर लगाए गए और 2 स्थानों पर ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं। दो ट्रांसमीटर दूसरे काम में लगाए गए।

iii. चिनसुराह : 1000 किलोवाट का मीडियम वेव ट्रांसमीटर (वर्तमान 1000 किलोवाट के मीडियम वेव ट्रासमीटर का बदलना) स्थापित और चालू।

iv. गुवाहाटी में क्षेत्रीय कार्यालय को सुदृढ़ बनाना

- गुवाहाटी में स्थायी कार्यालय का निर्माण पूरा
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 38 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है।

¼6½ 12oha ;kstuk dh rgr ubZ igy%

¼,½ lhfer mRiknu lqfo/kk okys u, ,Q,e VªkalehVj % 11 LFkku

¼i½ 10 fdyksokV ds 8 ,Q,e VªkalehVj dk- dhukMk ¼vk/kz çns'k½] egt¶Qjiqj ¼fcgkj½] Vhoh LFky jryke ¼e/; çns'k½] Vhoh LFky —".kuxj ¼MCY;wch½] yqf/k;kuk ¼iatkc½] cnh ¼jktLFkku½] bVkok ¼mÙkj çns'k½] ejB ¼mÙkj çns'k½A

मेरठ (उत्तर प्रदेश) और रतलाम (मध्य प्रदेश) में नए स्टेशनों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इटावा (उत्तर प्रदेश) स्थान का अधिग्रहण बाकी है। 10 किलोवाट के 4 एफएम ट्रांसमीटरों की खरीद के लिए खरीद आदेश दिया गया है।

लुधियाना में, बीएसएनएल परिसर में एफएम ट्रांसमीटर की अंतरिम व्यवस्था पहले ही आरंभ हो चुकी है।

¼ii½ 5 fdyksokV ds 3 ,Q,e VªkalehVj vyi>k ¼dsjy½] veBh ¼mÙkj çns'k½ vkSj jhok ¼e/; çns'k½%

5 किलोवाट के 2 एफएम ट्रांसमीटर खरीदने के लिए खरीद आदेश दिया गया है।

अमेठी में दूरदर्शन स्थान पर 5 किलोवाट का अंतरिम एफएम ट्रांसमीटर पहले ही कार्यरत।

(बी) एफएम ट्रांसमीटर के साथ अतिरिक्त चैनल : 7 स्थान

(प) 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर : 4
(दिल्ली, कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई)

(पप)10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर : 3
कानपुर (उत्तर प्रदेश), विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), पणजी (गोवा),

¼lh½ ,yMCY;bZ ;kstuk d rgr eh-o- VkalehVjk dk cnyuk

100 किलोवाट के 4 और 200 किलोवाट मीडियम वेव के 2 मेगावाट ट्रांसमीटरों को समान शक्ति के मीडियम वेव डीआरएम तैयार ट्रांसमीटरों से बदला जा रहा है।

¼Mh½ orZeku ,yihVh@,pihVh MhMh LFkkuk ¼100 LFkkuk½ ij 100 MCY;w ,Q,e VkalehVj LFkkfir djuk

एनआईटी प्रकाशित किया गया है

¼b½ 77 LFkkuk ij ijkus ,Q,e VkalehVj dk cnyuk@mUu;u

20 किलोवाट के 3 एफएम ट्रांसमीटर खरीदे गए

¼,Q½ 6 LFkkuk ij ijkus ehfM;e oso VkalehVjk dk ,Q,e VkalehVjk e cnyuk

- किन्नौर (हिमाचल प्रदेश)
- जोरंदा (ओडिशा), सोरो (ओडिशा)
- अल्मोड़ा (उत्तराखंड), उडगमंडलम (उट्टाकमपुंड) (तमिलनाडु)
- मथुरा (उत्तर प्रदेश) – 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर से बदला गया।

10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर (2) और 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर (4) की खरीद के लिए आदेश दिया गया है।

¼th½ Hkkjr&usiky lhek d lkFk ,Q,e çlkj.k 0;oLFkk% 6 LFkku%

- सीमावर्ती क्षेत्रों से लगे मौजूदा एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) केंद्रों पर 6 स्थानों पर 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर स्थापित किए जाएंगे।
- एसएसबी के साथ संयुक्त रूप से 10 स्थान पहचाने गए हैं जिनमें से 5 स्थानों को अंतिम रूप दिया गया हैं।

¼,p½ oSdfYid IyVQkek ij çlkj.k%

आकाशवाणी को 17 लोकप्रिय कार्यक्रमों की सीधा स्ट्रीमिंग शुरू हुई है और मोबाइल एप्लिकेशन के लिए आईओएस, विंडो और एंड्रॉइड प्लेटफार्मों पर भी उपलब्ध है।

¼7½ vkbZVh çHkkx dh xfrfof/k;k%

वर्ष के दौरान इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल प्रसारण की घटनाओं और उपलब्धियों के क्षेत्र में आईटी प्रभाग द्वारा की गईं प्रमुख नई पहल इस प्रकार हैं :

(i) आईटी डिवीजन द्वारा विकसित पेरोल 'पैकेज' का इस्तेमाल वेतन और वेतन स्लीप की तैयारी के लिए सभी कार्यालयों/स्टेशनों द्वारा किया जा रहा है। सातवें वेतन आयोग के ^HkÙk* की अधिसूचना को शामिल किया गया और इसे कार्यालयों के लिए समय पर उपलब्ध कराया गया था और वर्तमान में इसका संचालन हो रहा है।

(ii) आकाशवाणी के निम्नलिखित तेरह लोकप्रिय चैनलों की सीधा स्ट्रीमिंग राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के बदले सामग्री वितरण नेटवर्क (सीडीएन) आधारित स्ट्रीमिंग से की जा रही है।

(i) एफएम इंद्रधनुष,
(ii) एफएम गोल्ड,
(iii) उर्दू,
(iv) विविध भारती,
(v) गुजराती,
(vi) मलयालम,
(vii) पंजाबी,
(viii) मराठी,
(ix) बांग्ला,
(x) तमिल,
(xi) तेलुगू,
(xii) कन्नड़ तथा
(xiii) रागम

आकाशवाणी के निम्नलिखित 4 लोकप्रिय चैनलों को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग बुके में जोड़ा गया है,

(i) रेडियो कश्मीर,
(ii) आकाशवाणी ओड़िया
(iii) आकाशवाणी असमिया तथा
(iv) पूर्वोत्तर सेवा

(iii) आकाशवाणी की वेबसाइट और मोबाइल एप के माध्यम से स्ट्रीमिंग के बारे में श्रोताओं के अनुभव को बढ़ाने के लिए सीडीएन ने एनआईसी को नियुक्त कर सेवाएं ली।

(iv) एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफार्मों के लिए सीधा स्ट्रीम किए गए चैनलों (सीडीएन के माध्यम से) को सुनने

के लिए अधिक संख्या में चैनलों के साथ अपग्रेड किया गया मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किए गए हैं।

(v) ऑनलाइन पंजीकरण सॉफ्टवेयर 'ऑनलाइन संगीत ऑडिशन सिस्टम', एकीकृत भुगतान पोर्टल के साथ शुरू किया गया है।

¼8½ vkdk'kok.kh lalk/kuksa dh xfrfof/k;k

आकाशवाणी संसाधन की स्थापना मई 2001 में प्रसार भारती संसाधनों/बुनियादी ढांचे के साझाकरण माध्यम से राजस्व अर्जित करने के लिए की गई थी। आकाशवाणी संसाधनों ने 229 चैनलों के दूसरे चरण से तीसरे चरण में जाने के लिए निजी एफएम ब्रॉडकास्टर के साथ 221 नए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 8 निजी एफएम ऑपरेटरों ने दूसरे चरण से तीसरे चरण में जाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ जीओपीए पर हस्ताक्षर किए हैं। आकाशवाणी संसाधनों ने चरण 3 की बैच 1 के तहत 94 नए एलओआई धारकों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं जबकि एमआईबी द्वारा बैच 2 के तहत 43 एलओआई जारी किए गए हैं और 42 एलओआई धारकों ने आकाशवाणी संसाधन के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

आकाशवाणी संसाधन राजस्व साझाकरण आधार पर आकाशवाणी कार्यक्रमों पर एसएमएस आधारित सेवा का संचालन कर रहा है और पूरे भारत में विभिन्न आकाशवाणी कार्यक्रमों पर विभिन्न मोबाइल ऑपरेटर से एसएमएस हिट की कुल संख्या का रिकार्ड रखता है।

आकाशवाणी संसाधन साप्ताहिक शुल्क के आधार पर इंजीनियरिंग/डिप्लोमा छात्रों (आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र) को प्रशिक्षण प्रदान करके राजस्व सृजन कर रहा है।

आकाशवाणी संसाधन ने पूरे भारत में 37 स्थानों पर ज्ञानवाणी एफएम ट्रांसमीटर के संचालन और रखरखाव के लिए इग्नू के साथ एक संयुक्त उद्यम करार किया है। इग्नू की ज्ञानवाणी सेवाएं 3 स्थानों पर शुरू की गई हैं और चरणबद्ध तरीके से आकाशवाणी नेटवर्क के माध्यम से अन्य ट्रांसमीटरों से पुनः आरंभ हो रही हैं। ये सेवाएं जल्द ही सभी ज्ञानवाणी ट्रांसमीटरों से फिर से शुरू हो सकती हैं।

आकाशवाणी संसाधनों द्वारा 2001–2002 से 2017–18 तक (सितंबर 2017 तक) अर्जित राजस्व निम्न तालिका/ग्राफ में दिया गया है :

Øe la[;k-	vof/k	jkf'k¼₹ esa½
1	2001–2002 (आकाशवाणी संसाधन प्रारंभ मई 2001)	13,38,25,000
2	2002–03	8,38,59,900
3	2003–04	11,50,20,500
4	2004–05	19,70,19.300
5	2005–06	45,04,49,781
6	2006–07	35,50,67,009
7	2007–08	46,14,36,834
8	2008–09	47,97,29,427
9	2009–10	45,89,81,599
10	2010–11	53,22,84,545
11	2011–12	57,39,84,778
12	2012–13	56,72,03,504
13	2013–14	49,08,72,113
14	2014–15	65,01,43,374
15	2015–16	68,67,74,419
16	2016–17	51,49,20,717
17	2017–18 (सितंबर 2017 तक)	26,81,53,397
	dqy	7]01]97]26]197

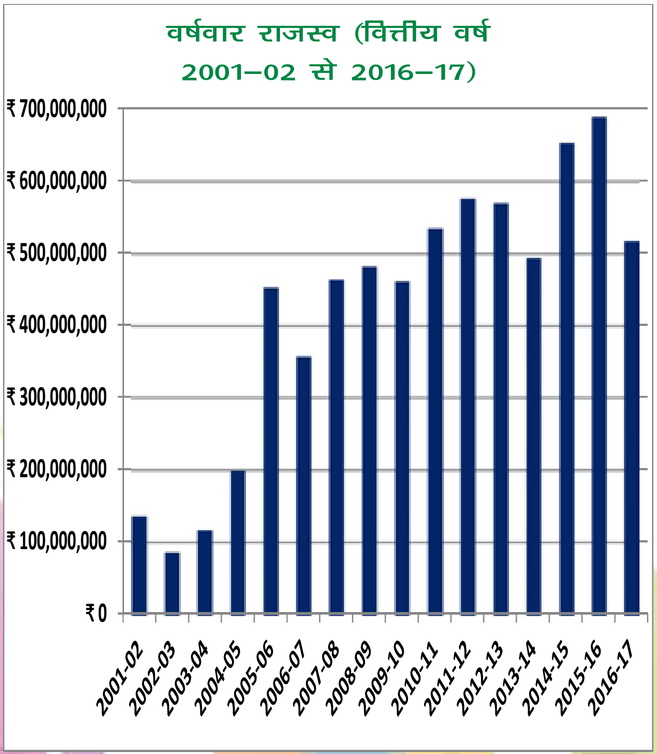

jktLo vtZu foÙk o"kZ 2017&18 ¼30-09-2017 rd½

चालू वित्त वर्ष के दौरान सितंबर 2017 तक अर्जित राजस्व 26,81,53,397 है, जो वित्तीय वर्ष 2017–18 के लक्ष्य के मुकाबले 75 करोड़ है। अप्रैल 2017 से चालू वित्त वर्ष (महीना के अनुसार) के दौरान अर्जित आय का ब्योरा नीचे तालिका में दिया गया है:

th,lVh iwoZ				
Ø-	vof/k	vkdk'kok.kh lalk/ku fdjk;k	lsok dj	dqy jkf'k ¼₹ esa½
1	अप्रैल 2017	₹ 3,54,01,430	₹ 52,83,717	₹ 4,06,85,147
2	मई 2017	₹ 4,93,26,860	₹73,46,736	₹ 5,66,73,596
3	जून 2017	₹ 10,54,54,443	₹ 1,41,35,588	₹ 11,95,90,031
4	जुलाई 2017	₹ 60,94,345	₹ 9,14,153	₹ 70,08,498
	dqy	**₹ 19,62,77,078**	**₹ 2,76,80,194**	**₹ 22,39,57,272**
th,lVh i'pkr				
Ø-	vof/k	vkdk'kok.kh lalk/ku fdjk;k	lsok dj	dqy jkf'k ¼₹ esa½
5	अगस्त 2017	₹ 1,06,92,387	₹ 17,86,773	₹ 1,24,79,160
6	सितम्बर 2017	₹ 2,58,23,467	₹ 45,85,134	₹ 3,04,08,601/ ₹ 13,08,364*
		* व्यावसायिक / औद्योगिक प्रशिक्षण		
	dqy	**₹ 3,65,15,854**	**₹ 63,71,907**	**₹ 4,41,96,125**
	dqy ;ksx			**₹ 26, 81,53,397**

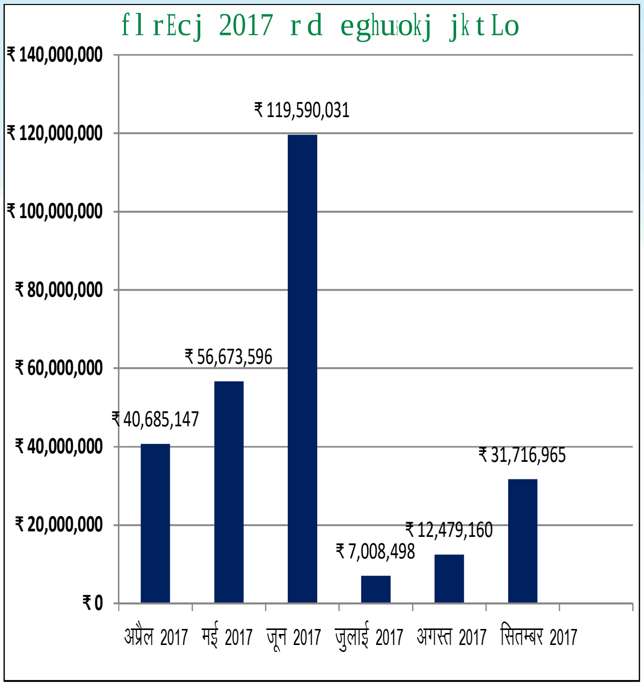

(9½ us'kuy ,dsMeh v,Q czkWMdkfLVax vkSj eYVhehfM;k ¼rduhdh½ dh xfrfof/k;ka ij fjiksVZ

नेशनल एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीमीडिया (एनएबीएम) का उद्देश्य दिल्ली और भुवनेश्वर में दो परिसरों के साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसारण पेशेवरों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए चुनौतीपूर्ण प्रसारण वातावरण में विकसित करना है और यह एक अग्रणी संगठन के रूप में उभरा है जो रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन, पोस्ट–प्रोडक्शन और प्रसारण के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह एशिया–प्रशांत क्षेत्र में प्रसारणकर्ता प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी उभरा है।

अकादमी में रेडियो और टीवी स्टूडियो के साथ नवीनतम प्रोडक्शन और पोस्ट–प्रोडक्शन उपकरण, मापन प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, नेटवर्किंग प्रयोगशाला, रेडियो और टीवी ट्रांसमीटर और पुस्तकालय हैं, जिसमें 7,000 से अधिक तकनीकी पुस्तकें हैं। अकादमी में 120 कमरों के साथ छात्रावास की बहुत अच्छी सुविधा है। शिलॉग में क्षेत्रीय अकादमी है और आरएबीएम मलाड में सीमित प्रशिक्षण सुविधा है।

अकादमी एशिया प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न देशों के रेडियो और टेलीविजन इंजीनियरिंग कर्मियों के लिए प्रशिक्षण/कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिए एशिया प्रशांत

प्रसारण विकास संस्थान (एआईबीडी) और एशिया प्रशांत प्रसारण यूनियन (एबीयू) के साथ सहयोग करती है।

xfrfof/k;k¡ %&

1- jk"Vªh; xfrfof/k;k¡

(ए) आकाशवाणी और दूरदर्शन इंजीनियरिंग स्टाफ के लिए प्रशिक्षण गतिविधियां :

विवरण vuqyXud&1 में दिए गए हैं।

2- varjkZ"Vªh; xfrfof/k;k¡

वर्ष 2017–18 के दौरान अकादमी द्वारा आगे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया।

- एनएबीएम दिल्ली में 19 उम्मीदवारों के लिए 15 से 19 मई, 2017 तक एचडी और यूएचडी टीवी प्रौद्योगिकी पर एआईबीडी क्षेत्रीय कार्यशाला।

¼10½ vuqla/kku fodkl vkdk'kok.kh vkSj nwjn'kZu

¼01&04&2017 ls 31&10&2017 dh vof/k dh nkSjku miyfC/k;k¡½

¼d½ ,Mokal fjeksV e,fuVfjax ,aM dUVªksy ¼çlkj.k VkWlehVjksa ds fy, VsyhehVªh flLVe½

एडवांस टेलीमेट्री सिस्टम आकाशवाणी के 11 मीडियम वेव ट्रांसमीटरों पर लागू किया गया है, ये हैं कोटा, रोहतक, तिरुनेलवेली, तिरुअनंतपुरम, ब्रह्मवार, छतरपुर, अंबिकापुर, आयजोल, तुरा, सिलचर, और जलगांव। जालंधर (एफएम), छतरपुर (मीडियम वेव), रोहतक (मी. डियम वेव), कसौली (एफएम) और नागौर (एफएम) में वेब आधारित टेलीमेट्री सिस्टम भी स्थापित किया गया है और इसे निम्नलिखित एयर स्टेशनों पर स्थैतिक आईपी पता ट्रांसमीटर साइटों पर संबंधित स्टेशनों द्वारा उपलब्ध कराने पर लागू किया जाएगा :

1. दरभंगा (मीडियम वेव)
2. रीवा (मीडियम वेव)
3. रत्नागिरी (मीडियम वेव)
4. भुज (मीडियम वेव)
5. लेह (मीडियम वेव)
6. गंगटोक (मीडियम वेव)
7. हजारीबाग (एफएम)
8. कटक (एफएम)
9. कैलाशहर (एफएम)
10. विजयवाड़ा (एफएम))

¼[k½ mPp 'kfä ,Q,e ,UVhuk dk fodkl½

एकल बे उच्च शक्ति वीएचएफ एफएम एंटीना गढ़ी और जांच की गई है। 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर के लिए अंतिम 5 बे उच्च शक्ति वीएचएफ एफएम एंटीना सिस्टम के निर्माण और परीक्षण का कार्य रायबरेली में प्रगति पर है।

¼x½ /ofud ysc dk vk/kqfudhdj.k vkSj mUu;u½

वाणिज्यिक आधार पर ध्वनिक सामग्री के एनआरसी और एसटीसी परीक्षण (16 नमूनों के लिए) विभिन्न निजी कंपनियों/ओइएम के लिए किए गए थे और इनसे 2,27,722 रु. का राजस्व अर्जित किया गया।

¼?k½ varjkZ"Vªh; e,fuVfjax dsUnz] rkMkiqj] ubZ fnYyh esa rduhdh fuxjkuh lqfo/kkvksa dk mUu;u vkSj vk/kqfudhdj.k½

एचएफ संचार मॉनिटरिंग रिसीवर (मेकः आर एंड एस, मॉडल ईबी–510) स्थापित किया गया है और अन्य कार्य प्रगति पर हैं।

dk;ZØe dh xfrfof/k;k¡

¼,½ egRoiw.kZ lh/kk dojst

i. 6 अप्रैल, 2017 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली के दरबार हॉल से दूसरे रक्षा निवेश समारोह का सीधा प्रसारण।

ii. भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा 12 अप्रैल, 2017 को राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रीय भू–विज्ञान पुरस्कार 2016 की प्रस्तुति का सीधा प्रसारण।

iii. 17 अप्रैल, 2017 को राष्ट्रपति भवन, सांस्कृतिक केंद्र ऑडिटोरियम, नई दिल्ली से भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा 'ग्लोबल एक्जीबिशन ऑन सर्विसेज 2017' के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण

iv. 21 अप्रैल, 2017 को सिविल सेवा दिवस 2017 पर समापन पुरस्कार प्रस्तुति समारोह का सीधा प्रसारण।

v. 27 अप्रैल, 2017 को भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की कृपापूर्ण उपस्थिति में आयोजित 52वें ज्ञानपीठ पुरस्कार समारोह का जीएमसी बालयोगी सभागार, संसद पुस्तकालय भवन, नई दिल्ली से सीधा प्रसारण।

vi. 29 अप्रैल, 2017 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में विज्ञान भवन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बीएएसएवीए सम्मेलन का सीधा प्रसारण।

vii. 3 मई, 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित 64 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का सीधा प्रसारण।

viii. अंतरराष्ट्रीय डॉन कोरस दिवस के अवसर पर 7 मई, 2017 को तेरह देशों (आयरलैंड की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, यूरोपीय प्रसारण संघ और आकाशवाणी–आरटीई) में छह समान मानक समय में बीस अलग–अलग स्थानों से सुबह के समय पक्षियों के कलरव की शानदार आवाजों का सीधा प्रसारण।

ix. भारत के उच्चतम न्यायालय के कार्यक्रम 'पेपर कोर्ट से डिजिटल कोर्ट से सुरक्षा और पारदर्शिता की ओर बढ़ते हुए' के उद्घाटन का 10 मई, 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली से सीधा प्रसारण।

x. 23 मई, 2017 को अहमदाबाद में आयोजित अफ्रीकी गुजरात विकास बैंक की वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र का सीधा प्रसारण।

xi. 21 जून, 2017 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योग प्रदर्शन समारोह का सीधा प्रसारण।

xii. 23 जुलाई, 2017 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की विदाई समारोह का सीधा प्रसारण।

xiii. 24 जुलाई, 2017 को माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा राष्ट्र के नाम विदाई संबोधन।

xiv. 25 जुलाई, 2017 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली से माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण।

xv. 11 अगस्त, 2017 को राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल से उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण।

xvi. स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त, 2017 को भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द का राष्ट्र के नाम संबोधन का प्रसारण।

xvii. स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 2017 को लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सीधा प्रसारण।

xviii. 15 अगस्त, 2017 को मथुरा से श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का सीधा प्रसारण।

xix. भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की उपस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) वितरण समारोह का 24 अगस्त, 2017 को विज्ञान भवन से सीधा प्रसारण।

xx. 24 अगस्त, 2017 को हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली से दूरवर्ती संचालन के माध्यम से भारत और नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 132 केवी के कटैया–कुसाहा और रक्सौल–परवानीपुर ट्रांसमिशन लाइन के उद्घाटन का सीधा प्रसारण।

xxi. 24 अगस्त, 2017 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली से भारत के प्रधान न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण।

xxii. 5 सितंबर, 2017 को भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू द्वारा शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार, 2016 देने के अवसर पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित समारोह का सीधा प्रसारण।

xxiii. शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर, 2017 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित पुरस्कृत शिक्षकों की भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात बैठक का सीधा प्रसारण।

xxiv. भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की मौजूदगी में 21 नवंबर, 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी दिवस समारोह का सीधा प्रसारण।

xxv. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 2 अक्टूबर, 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा आयोजित 'स्वच्छ भारत दिवस' समारोह का सीधा प्रसारण।

xxvi. 4 अक्टूबर, 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित भारत के कंपनी सचिव संस्थान की स्वर्ण जयंती समारोह का सीधा प्रसारण।

xxvii. 9 अक्टूबर, 2017 को भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की उपस्थिति में वरिष्ठ नागरिकों (व्योश्रेष्ठ सम्मान 2017) के लिए आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का सीधा प्रसारण।

xxviii. उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन में नए बाजार में उपभोक्ताओं का सशक्तीकरण विषय पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली से सीधा प्रसारण। 26 अक्तूबर, 2017 को आयोजित इस सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी उपस्थित थे।

xxix. 27 अक्टूबर, 2017 को भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की उपस्थिति में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार वितरण समारोह का सीधा प्रसारण।

xxx. 31 जनवरी, 2017 को सरदार पटेल जयंती के अवसर पर पटेल चौक पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह का प्रसारण और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से एकता के लिए दौड़ 2017 का सीधा प्रसारण।

¼ch½ vU; egRoiw.kZ dojst@çlkj.k

i. 'मन की बात' का प्रसारण – विभिन्न मुद्दों/विषयों (हर महीने के प्रसारण) पर भारत के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन।

ii. 31 मई, 2017 को जर्मनी की अपनी यात्रा के दौ. रान विभिन्न कार्यक्रमों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए भाषणों के रिकॉर्डिंग का प्रसारण।

iii. 4 जून, 2017 को फ्रांस की अपनी यात्रा के दौरान कार्यक्रमों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए भाषणों के रिकॉर्डिंग का प्रसारण।

iv. 10 जून, 2017 को कजाकिस्तान दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए भाषणों के रिकॉर्डिंग का प्रसारण।

v. 20 जून, 2017 को रामकृष्ण मिशन के प्रमुख श्री आत्मस्थानंद के दुखद निधन पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा का सीधा प्रसारण।

vi. भारत के प्रधानमंत्री की हाल की यात्रा के दौरान 27 जून, 2017 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्य के रिकॉर्डिंग का प्रसारण।

vii. 7 सितंबर, 2017 को यांगून म्यांमार में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय समुदाय को संबोधन का प्रसारण।

viii. पंडित दीन दयाल उपाध्याय शताब्दी और 11 अगस्त, 2017 को स्वामी विवेकानंद के शिकागो सम्मेलन में संबोधन के 125वें वर्ष पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन, नई दिल्ली में छात्र नेताओं के सम्मेलन में दिए गए भाषण की रिकार्डिंग।

¼lh½ jfM;ks fjiksVZl

i. 2 अप्रैल, 2017 को चेनानी–नेसरी सुरंग का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जम्मू–कश्मीर की यात्रा के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों पर रेडियो रिपोर्ट।

ii. 20 अप्रैल, 2017 को सिविल सेवा दिवस 2017 के उद्घाटन सत्र पर रेडियो रिपोर्ट।

iii. 3 मई, 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित 64 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण

समारोह की रेडियो रिपोर्ट।

iv 16 जून, 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह की रेडियो रिपोर्ट।

v. 21 जून, 2017 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों पर समेकित रेडियो रिपोर्ट।

vi. पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के उद्घाटन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और 14 अक्टूबर, 2017 को मोकामा में प्रधानमंत्री द्वारा अवसंरचना योजनाओं की आधारशिला रखने के लिए आयोजित समारोह पर रेडियो रिपोर्ट।

vii. 27 अक्टूबर, 2017 को पर्यटन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित पर्यटन पर्व पर समेकित रेडियो रिपोर्ट।

viii. माननीय कपड़ा तथा सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा 31 अक्टूबर, 2017 को लोकतंत्र के लिए प्रसारण 'लैंडस्केप का मॉडल' विषय पर दिए गए सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान 2017 पर रेडियो रिपोर्ट।

ix. 9 से 13 नवंबर, 2017 को हैदराबाद में आयोजित भारत के 20वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2017 पर दैनिक रेडियो रिपोर्ट।

¼Mh½ pky foÙkh; o"kZ 2017&18 dh 'k"k vof/k d fy, çLrkfor dk;Øe

i. पणजी (गोवा) में 20 से 28 नवंबर, 2017 तक आयोजित 48वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कवरेज।

माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 26 अक्तूबर 2017 को सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान आयोजन के दौरान

ii. 13 दिसंबर, 2017 को संसद भवन, नई दिल्ली के गीत नंबर 11 और 12 के बीच बनी पट्टिका पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह का सीधा प्रसारण।

iii. गणतंत्र दिवस समारोह 2018 के सिलसिले में निम्नलिखित कार्यक्रमों का प्रसारण प्रस्तावित किया गया है:

(ए) गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी, 2018 को आकाशवाणी के संबंधित स्टेशनों द्वारा क्षेत्रीय भाषा के संस्करण के साथ माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन।

(बी) 25 जनवरी, 2018 को राष्ट्रीय कवि संगोष्ठी की रिकॉर्डिंग का प्रसारण।

(सी) गणतंत्र दिवस परेड का सीधा प्रसारण और 26 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली में राजपथ से सांस्कृतिक झांकी का प्रसारण।

(डी) 29 जनवरी, 2018 को बीटिंग रिट्रीट समारोह के बारे में रेडियो रिपोर्ट।

(ई) गणतंत्र दिवस 2018 के अन्य समारोह/घटनाओं के लिए कवरेज

iv. जनवरी, 2018 में प्रधानमंत्री की एनसीसी रैली का सीधा प्रसारण

v. भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2018 का कवरेज।

vi. 2018–19 के बजट सत्र पर संसद के दोनों सदनों के लिए माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण का सीधा प्रसारण।

vii. केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा लोक सभा में आम बजट 2017–18 की प्रस्तुति का सीधा प्रसारण।

ckyw x, 'kCn

आकाशवाणी ने 2017–18 के दौरान 467 स्टेशनों के नेटवर्क पर सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को समर्थन दिया। स्पोकन वर्ड डिवीजन, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के महत्वपूर्ण विषय/योजनाओं/नीतियों के प्रचार का काम करता है। अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2017 की अवधि में आकाशवाणी के सभी स्टेशनों द्वारा निम्नलिखित सरकारी योजनाओं का प्रचार किया गया :

1. सरकार की उपलब्धि बताने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए।

- वस्तु और सेवा कर
- राष्ट्रीय डिजिटीकरण अभियान
- मुद्रा संर्वद्धन अभियान
- स्वच्छ भारत अभियान
- बेटी पढाओ बेटी बचाओ
- मेक इन इंडिया
- कौशल भारत कार्यक्रम
- दीनदयाल उपाध्याय स्वर्ण जयंती
- पर्यटन प्रोत्साहन
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास
- शहरी विकास पर फोकस
- जन धन योजना
- एक भारत श्रेष्ठ भारत

2. अहमदाबाद को विश्व धरोहर शहर का दर्जा दिए जाने पर होने वाले एक पखवाड़े के लंबे उत्सवों के लिए प्रचार कार्य बढ़ाया गया।

3. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आकाशवाणी के सभी स्टेशनों को व्यापक प्रचार करने और जोखिमपूर्ण 'ब्लू व्हेल' खेल के बारे में शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में जागरुकता पैदा करने की सलाह दी गई थी।

4. संस्कृति मंत्रालय द्वारा 5 से 25 अक्टूबर, 2017 तक आयोजित 'पर्यटन पर्व' को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रचार दिया गया।

5. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित 'दिव्यांगजन सशक्तीकरण शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता 2017' के लिए उचित प्रचार कार्य किया गया।

6. 8 से 14 नवंबर, 2017 को हैदराबाद में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह 'गोल्डन एलीफैंट' के लिए प्रचार किया गया।

7. पंडित दीन दयाल उपाध्याय गरीब कल्याण कोष की भावना को समर्थन देने के लिए कपड़ा मंत्रालय द्वारा 7 से 17 अक्टूबर, 2017 तक आयोजित 'हस्तकला सहयोग शिविर' का व्यापक प्रचार किया गया।

8. निम्नलिखित पुरस्कारों का प्रचार किया गया :–

i. राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार,

ii. शराब और पदार्थ (औषध) रोकथाम के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की योजना

iii. मानवाधिकार का वास्तविक अर्थ–जागरुकता अभियान

iv. स्वच्छता ही सेवा अभियान

9. साक्षरता दिवस, विश्व योग दिवस ,पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नागरिक सेवा दिवस, रक्षा लेखा दिवस, महिला दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस आदि पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों/घटनाओं/गतिविधियों के लिए प्रचार।

10. विभिन्न विषयों/बिलों पर लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों से प्राप्त अधिसूचना/घोषणाओं के लिए प्रचार समर्थन बढ़ाया गया।

11. प्रसार भारती की 20वीं वर्षगांठ समारोह मनाने के लिए प्रचार अभियान शुरू किया गया।

12 कैलाश मानसरोवर यात्रा और अमरनाथ यात्रा 2017 के प्रचार को बढ़ाया गया।

13. सरदार पटेल, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और अन्य नेताओं के शताब्दी समारोह के अवसरों पर आयोजित कार्यक्रमों/कार्यक्रमों का प्रचार किया गया।

M,- jktsæ çlkn Lefr 0;k[;ku

आकाशवाणी ने 1969 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में एक वार्षिक स्मृति व्याख्यानमाला की शुरुआत की। साहित्य, संस्कृति, अर्थशास्त्र, राजनीति, विज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञान क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों और विद्वानों द्वारा हिंदी में व्याख्यान हर साल देश के विभिन्न हिस्सों में बारी–बारी से आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, प्रसिद्ध सामाजिक वैज्ञानिक डॉ. पी.सी. जोशी, डॉ. हरिवंश राय बच्चन जैसे कई दिग्गजों ने इस व्याख्यानमाला में व्याख्यान दिए हैं। 2017 के लिए स्मृति स्मारक व्याख्यान नवंबर, 2017 में दिया गया था। व्याख्यान की रिकॉर्डिंग 3 दिसंबर, 2016 को 9.30 बजे डॉ. राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर

आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित की गई।

ljnkj iVy Lefr 0;k[;ku

यह व्याख्यानमाला 1956 से स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में आयोजित की जाती है। प्रसिद्ध विद्वानों, प्रशासकों, न्यायविदों, इतिहासकारों, समाज विज्ञानियों, अर्थशास्त्रियों द्वारा अंग्रेजी में यह व्याख्यान दिया जाता है। पहला व्याख्यान प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल डॉ. सी. राजगोपालाचारी ने दिया था। व्याख्यान देने वाली प्रमुख हस्तियों में भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्री पी. एन. भगवती, प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर बिपिन चंद्रा, प्रो. रोमिला थापर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन शामिल हैं।

वर्ष 2017 का सरदार पटेल स्मृति माननीय वस्त्र तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा 26 अक्टूबर, 2017 को दिया गया। ^ykdra= esa vkn'kZ çlkj.k e,My* विषय पर इस व्याख्यान की रिकॉर्डिंग 31 अक्टूबर, 2017 को आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर 9.30 बजे प्रसारित की गई ।

vkdk'kok.kh ykd lEink lj{k.k egkifj;kstuk ¼lLdkj xhr½

आकाशवाणी की इस परियोजना में (i) विभिन्न अनुष्ठानों (संस्कार)– चरण/जीवन काल के मील के पत्थर से जुड़े गीत (ii) ऋतु गीत, पर्व गीत, शर्म गीत, नाडी गीत, वृक्ष गीत, स्थल गीत, पर्वत गीत और आंदोलन गीत जैसे विभिन्न प्रकार के लोक गीत और (iii) लोक गाथाओं की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था है जिससे भावी पीढ़ी के लिए भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में मदद मिलेगी।

गीतों की रिकॉर्डिंग कार्य आकाशवाणी के 114 स्टेशनों द्वारा किए गए हैं और यह 150 जिलों और 140 भाषाओं और बोलियों में पूरा किया गया है। यहूदी धर्म को छोड़ कर सभी जातियों, उप–जातियों और जनजातियों के अनुष्ठानों से जुड़े गीत रिकार्ड किए गए हैं। इस मेगा परियोजना में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आकाशवाणी पटना में दो दिन की कार्यशाला 5 से 6 अक्टूबर, 2017 को आयोजित की गई।

अब तक 87 भाषाओं/बोलियों में 20,000 संस्कार गीत और पारंपरिक लोक गीत रिकार्ड किए गए हैं और आकाशवाणी अभिलेखागार में संरक्षित हैं। संस्कृति मंत्रालय के अधीन नेशनल बुक ट्रस्ट ने इनके प्रकाशन के लिए आकाशवाणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी नई दिल्ली में 26 अक्टूबर, 2017 को 'मॉडल ऑफ ब्रॉडकास्ट लैंडस्केप' विषय पर सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान देते हुए।

jk"Vªh; dfo lEesyu ¼lo Hkk"kk dfo lEesyu½

1956 में प्रस्तुत सर्व भाषा कवि सम्मेलन (कवियों की राष्ट्रीय संगोष्ठी) पारस्परिक बातचीत के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण और भाषाई सद्भाव के लिए एक रचनात्मक मंच प्रदान करने और सभी भारतीय भाषाओं की समकालीन कविता में सर्वश्रेष्ठ समन्वित प्रस्तुति का प्रयास है। यह एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां 22 भारतीय भाषाओं, जिनमें चार नई भाषाओं, डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो शामिल हैं, के जीने–माने कवि मंच पर एक साथ मिलकर अपनी सर्वश्रेष्ठ रचनात्मकता प्रस्तुत करते हैं। पहले इन सभी भाषाओं के कवि स्वयं कविताएं प्रस्तुत करते हैं और बाद में उनके हिंदी संस्करण प्रस्तुत किए जाते हैं। 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रात्रि 10 बजे आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर दो घंटे की रिकॉर्डिंग प्रसारित की गई। इस कार्यक्रम के क्षेत्रीय भाषा संस्करण राष्ट्र की लंबाई– चौड़ाई तक पहुंचने वाले आकाशवाणी के संबंधित स्टेशनों से प्रसारित किए जाते गए।

2018 के दौरान 25 जनवरी, 2018 के प्रसारण में 'सर्व भाषा कवि सम्मेलन' का आयोजन गया।

vkdk'kok.kh okf"kd iqjLdkj

वर्ष 2014 और 2015 के लिए आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार समारोह 16 जून,2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तत्कालीन माननीय केंद्रीय सूचना और प्रसारण , शहरी विकास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू और माननीय राज्य सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने एक शानदार समारोह में विभिन्न श्रेणियों के कार्यक्रम, इंजीनियरिंग, समाचार, दर्शक अनुसंधान, प्रशिक्षण आदि में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया।

—f"k vkSj ?kjsyw çlkj.k

आकाशवाणी अपने ग्रामीण दर्शकों के लिए पांच दशकों से अधिक समय से समर्पित है। ग्रामीणों, बच्चों और युवाओं के लिए प्रतिदिन सुबह, दोपहर और शाम को 60 से 100 मिनट की औसत अवधि के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

आकाशवाणी ने स्थानीय किसानों को दैनिक बाजार की दर, मौसम की रिपोर्ट और सूक्ष्म स्तर पर उनके

तत्कालीन माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार समारोह– 2014–15 के दौरान

अपने–अपने क्षेत्रों से जुड़ी सूचनाएं प्रतिदिन देने के लिए कृषि विस्तार के लिए मास मीडिया सहायता पर कृषि और सहकारिता विभाग के सहयोग से फरवरी 2004 से 'किसानवाणी' नामक एक विशेष परियोजना लांच की। वर्तमान में 'किसानवाणी' को पूरे देश में आकाशवाणी के चिन्हित 96 स्टेशनों से प्रसारित और रिले किया जा रहा है। एक संकीर्ण कास्टिंग मोड पर प्रसारित यह कार्यक्रम खेतों में किसानों की संवाद रिकार्डिंग पर आधारित है, इसमें फोन पर विशेषज्ञों से प्रश्न पूछे जाते हैं और विशेषज्ञ फोन पर ही जवाब देते हैं, जो श्रोताओं में काफी लोकप्रिय हैं।

'किसानवाणी' के कृषि कार्यक्रमों में खाद के रूप में जैविक ठोस अपशिष्ट के उपयोग के बारे में किसान समुदाय में जागरूकता पैदा करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं। आकाशवाणी स्टेशनों को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों पर ऑडियो स्पॉट प्रसारित करने के निर्देश दिए गए हैं।

dhVuk'kdksa ds lqjf{kr vkSj mfpr mi;ksx ij vfHk;ku

विशेष रूप से जनसाधारण और कृषि समुदाय के बीच जागरुकता फैलाने वाले कार्यक्रम, कीटनाशकों के सुरक्षित और समझदार उपयोग तथा उपभोग से पहले फलों और सब्जियों में कीटनाशक के अवशेषों को कम करने के तौर–तरीकों पर कार्यक्रम प्रसारित किए गए हैं।

स्टेशनों को कीटनाशकों की खरीद, भंडारण, संचालन और छिड़काव के दौरान किसानों के लिए क्या करें और क्या नहीं करने के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। स्टेशनों द्वारा कार्यक्रमों में खाद्यान्न, फलों और सब्जियों में कीटनाशकों के अवशेषों को कम करने के लिए उपभोक्ताओं और नागरिकों के लिए क्या करें और न करें विषय पर भी प्रकाश डाला गया।

fd lkuk dk fy, 0;kid ekSle iwokZuqeku

आकाशवाणी के सभी स्टेशनों और किसानवाणी प्रसारित करने वाले 96 केंद्र अपने दैनिक खेत और घर कार्यक्रमों में किसानों के लिए पांच मिनट की अवधि का व्यापक मौसम पूर्वानुमान कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। दैनिक मौसम के पूर्वानुमान कवरेज में अति विपरित स्थिति जैसे सूखा, बाढ़, आंधी तूफान, चक्रवात, ओला, ठंड इत्यादि सहित कृषि के महत्वपूर्ण मापदंडों जैसे– वर्षा, तापमान, मिट्टी और वायु नमी, विकिरण, गर्म, सूखा, ठंडी और आद्रता शामिल किए जाते हैं ताकि किसानों को जागरूक बनाया जा सके और फसल बर्बाद होने से रोकने में मदद की जा सके।

okfudj.k

आकाशवाणी वानिकी, वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन में सरकार द्वारा की गई पहलों की सफलता को बताता है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। कार्यक्रमों में सामाजिक वानिकी, भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण, ओजोन छिद्र में कमी, जलवायु परिवर्तन, जल संचयन और ध्वनि प्रदूषण विषय को भी उचित स्थान दिया जाता है।

आकाशवाणी के सभी केंद्र पर्यावरण और वन से संबंधित कानूनी पक्षों का व्यापक प्रचार कर रहे हैं।

आकाशवाणी के स्टेशनों द्वारा स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता पर बल देते हुए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लांच किए गए 'स्वच्छ भारत अभियान' को काफी प्रचारित किया है।

fdlkuksa dk Qly fo'k"k lykg dk çpkj

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा व्यक्त मौसमी आलू फसलों में फफूंद बीमारियों के पूर्वानुमान के बारे में आलू उपज वाले क्षेत्रों में कार्यरत स्टेशनों द्वारा किसानों के लिए जागरुकता कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं।

हरियाणा और पंजाब स्थित स्टेशनों को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सलाह के अनुसार खरीफ कपास फसलों को सफेद मक्खी के शिकार होने से बचाने के लिए किसानों में जागरुकता अभियान शुरू करने की सलाह दी गई थी।

fdlkuok.kh çHkko eY;kadu vkj {kerk l`tu dk;Z'kkyk

किसानवाणी कार्यक्रम प्रोड्यूसर्स के लिए देशभर में पांच 'प्रभाव आकलन और क्षमता सृजन' कार्यशालाएं हितधारकों के लिए आयोजित की जा रही हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, सोनभद्र , उत्तर प्रदेश में 29 से 30 मार्च, 2017 और शेरे कश्मीर विश्वविद्यालय, जम्मू और कश्मीर में 29 से 30 जून, 2017 तक दो कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

vkdk'kok.kh uVodZ ij çeq[k@fo'k"k dk;Øe

कुछ कार्यक्रमों के प्रसारण का विवरण नीचे दिया गया हैः

flVh dkiklV ¼[kkn½

आकाशवाणी के सभी केंद्र कृषि खादों के लाभ और कृषि प्रथाओं में कीट नाशक खाद के बारे में कृषि समुदाय को शिक्षित करने के लिए अभियान चलाते हैं। इस विषय पर

शिमला में किसानवाणी कार्यशाला

जिंगल भी प्रसारित किए जा रहे हैं।

e'nk LokLF; dkM

मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ और कृषि में नीमलेपित यूरिया के उपयोग पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना और जैविक मूल्य श्रृंखला विकास के लिए मिशन का भी प्रचार किया गया।

ç/kkue=h Qly chek ;kstuk

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं।

fdlku lqfo/kk ,Ii

हाल ही में लांच किया गया 'किसान सुविधा ऐप्प', किसानों को मौसम संबंधी सूचनाएं, डीलरों की जानकारी, कृषि वस्तु के लिए लाभकारी बाजार मूल्य, कृषि सलाह, पौधा संरक्षण आदि जैसी उपयोगी जानकारी प्रदान करता है।

Hkkjr NkMk vknksyu dh 75oh o"kxkB ij fo'k"k dk;Øe Ük[kYkk

भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ और स्वतंत्रता दिवस, 2017 मनाने के लिए स्टेशनों को सलाह दी गई थी कि 'इस मिट्टी को तिलक करो' नामक एक सप्ताह के सोशल मीडिया कार्यक्रम श्रृंखला के माध्यम से कृषि उत्पादन में मिट्टी के महत्व और सामाजिक–आर्थिक विकास को उजागर करने वाले कार्यक्रम चलाए और प्रचारित किए जाएं।

fo'o e/keD[kh fnol

19 अगस्त, 2017 को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के सतत विकास में मधुमक्खियों के महत्व और मधुमक्खी पालन के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए विश्व मधुमक्खी दिवस का प्रचार भी किया गया।

LokLF; vkj ifjokj dY;k.k dk;Øe

efgykvk d dk;Øe

आकाशवाणी लड़कियों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम और कन्या भ्रूण हत्या,लैंगिक भेदभाव, महिला साक्षरता के प्रसार के माध्यम से महिला भेदभाव तथा कानूनी साक्षरता प्रसार के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और विशेषाधिकारों के बारे में जागरूकता के कार्यक्रम प्रसारित करता है। ग्रामीण श्रोताओं के साथ संवाद करने के लिए विभिन्न परंपरागत लोक रूपों का भी उपयोग किया गया। 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम शुरु किया गया, जो 2017 में जारी है।

आकाशवाणी के केंद्र मीडिया में महिलाओं के अश्लील चित्रण से संबंधित कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का उचित प्रचार करते हैं और महिलाओं के अश्लील चित्रण पर मौजूदा कानूनों और विनियमों के तहत उपलब्ध कानूनी प्रावधानों और उपचारों के साथ महिलाओं के सकारात्मक चित्रण के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाते हैं।

आकाशवाणी के केंद्र दिल्ली उच्च न्यायालय की अपील संख्या 786/2010 के फैसले के संबंध में महिलाओं से संबंधित यौन अपराधों पर कानूनों, नियमों, विनियमों को प्रचारित करते हैं और महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित कानूनी दिशा–निर्देशों और कानूनी प्रावधानों के बारे में जन जागरूकता पैदा करने और इस तरह के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड से संबंधित जानकारी का प्रसारण करते हैं।

LokLF; dk;Øe

स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत रोगों के बारे में जाग. रूकता, उनके कारणों और रोकथाम, उपलब्ध उपचार के बारे में जानकारी, प्रतिरक्षण संबंधी जानकारी के बारे में जागरूकता, विभिन्न रोगों के इलाज के लिए सरकारी सुविधाओं, स्वास्थ्य से संबंधित सरकारी योजना जैसे स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला जाता है।

स्वास्थ्य कार्यक्रमों के नियमित प्रसारण में शामिल अन्य विषयों में विवाह की सही उम्र, पहले बच्चे के जन्म में विलंब, दो बच्चों के बीच का समय अंतराल, अंतक पद्धति, मातृ देखभाल, बाल अस्तित्व, अंतर जीवन साथी संचार प्रोत्साहन/पुरुष जिम्मेदारी प्रोत्साहन, पुरुष वरीयता भाव को निष्क्रिय करने, गर्भावस्था की चिकित्सकीय समाप्ति, संस्थागत कानूनी प्रावधान प्रोत्साहन, प्रजनन कार्य प्रणाली संक्रमण (आरटीआई) और यौन संचारित संक्रमण (एसटी. आई) का प्रबंधन, जन्म पूर्व निदान तकनीक (नियमों और दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम–1994, स्तनपान,

विकलांगता, तपेदिक, कुष्ठ रोग और प्रजनन बाल स्वास्थ्य आदि हैं।

भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3.40 करोड़ बच्चों को कवर करने के लिए अगस्त, 2017 में खसरा–रुबेला टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू किया। इस विषय पर आकाशवाणी के नेटवर्क पर विभिन्न रूपों में कार्यक्रम प्रसारित किए गए ताकि आम जनता में जागरूकता पैदा हो सके।

कुछ भागों में डेंगू और चिकनगुनिया के फैलने पर आकाशवाणी के नेटवर्क पर डेंगू की रोकथाम विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित किया गया।

इसी तरह जब देश के कुछ हिस्सों में जिका वायरस फैला तो डेंगू की रोकथाम पर आकाशवाणी के नेटवर्क से जागरूकता कार्यक्रम को प्रसारित किया गया।

आकाशवाणी से प्रतिकूल बाल लिंग अनुपात के बारे में जागरूकता पैदा करने और बालिका भ्रूण गर्भपात की नकारात्मक मनोदशा को बदलने के लिए पूरे देश में प्रसारण किया जाता है।

देश के कई हिस्सों में स्वाइन फ्लू फैलने के दौरान रोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आकाशवाणी के स्टेशनों ने उपयुक्त कार्यक्रमों को चलाया।

आकाशवाणी ने 2017 के दौरान इस अभियान के माध्यम से टीकाकरण के तीसरे चरण को व्यापक कवरेज और प्रचार किया। पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज में सुधार के लिए मिशन इंद्रधनुष का चौथा चरण 7 अप्रैल, 2017 से शुरू हुआ, नियमित टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रमों को प्रसारित किया गया और मिशन इंद्रधनुष को व्यापक कवरेज प्रदान किया गया।

अक्टूबर में स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता महीने में सभी आयु वर्ग के महिलाओं में जागरूकता, शीघ्र पहचान और उपचार के साथ–साथ इस रोग के उपशामक देखभाल में वृद्धि करने के लिए सभी रोग के कारकों, लक्षणों, रोकथाम और इलाज के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार किया गया।

cPpk dk dk;Øe

आकाशवाणी तीन श्रेणियों के बच्चों के लिए यानी 5 से 7 वर्ष की उम्र, 8 और 14 वर्ष की आयु और ग्रामीण बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।

आकाशवाणी स्टेशनों द्वारा बच्चों के लिए प्रसारित नियमित कार्यक्रमों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

1. बच्चों के अधिकारों का संरक्षण और विशेष रूप से कानून के शिकंजे में आए किशोरों की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की सुरक्षा।
2. दिव्यांग बच्चों की देखभाल और समर्थन।
3. कठिन परिस्थितियों में बच्चों की देखभाल और सहायता।
4. लड़कियों की समान स्थिति।
5. बुनियादी शिक्षा के लिए बच्चों की सार्वभौमिक पहुंच और लड़की की शिक्षा पर अधिक ध्यान।
6. बच्चों को सुरक्षित और सहायक वातावरण प्रदान करना।
7. सुरक्षित पेयजल सुविधा और मलमूत्र निपटान के लिए स्वच्छता साधन
8. इंटरनेट और ऑनलाइन दुनिया के खतरों से संरक्षण।

बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए दिल्ली आयोग के अनुरोध पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी बच्चों के मीडिया रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देशों को प्रचारित किया गया। आकाशवाणी ने यूनिसेफ के कार्यक्रमों की जानकारी पूरे भारत में प्रसारित करके योगदान दिया।

lxhr

आकाशवाणी अपनी स्थापना के बाद से भारतीय संगीत के प्रसार और संरक्षण में सेवारत है।

¼1½ leh{kk o"k ¼vçy 2017 l fnlcj 2017½ d nkjku çlkfjr fofHkUu lxhr dk;Øe d fooj.k bl çdkj g %

dukfVd 'kkL=h; lxhr

i) वर्ष 'ट्रिनिटी और अन्य वाग्गीकार संगीत कंसर्टों' के प्रसारण के साथ प्रारंभ हुआ जिसमें प्रमुख कलाकार चेन्नई

की श्रीमती सुगुना वरदचारी ¼R;kxjkt jpuk½] त्रिशूर के श्री एम के शंकरन नंबूतिरी ¼eFkLokeh nhf{krj l¡dyu½] हैदराबाद की श्रीमती श्वेता प्रसाद ¼';kek 'kkL=h l¡dyu½ और मैसूर के श्री एम राघवेंद्र ¼cYykjh 'k"kkfxfj vkpkj dh jpuk,¡½।

ii) संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम और रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में भाग लेने वाले कुछ प्रमुख कलाकारों में शामिल थे श्री प्रपंचम एस बालचंदर (बांसुरी), श्रीमती नागवल्ली नागराज (गायन), श्री द्वारम दुर्गा प्रसाद राव और श्री द्वारम सत्यनारायण (वायलिन युगल), श्री महाराजापुरम एस श्रीनिवासन (गायन), श्रीमती एस श्रीवाणी (वीणा), कोठाकोटा श्री एन रामा राव (डोलु एकल), श्री अलंगुडी ए वी पक्कीरीस्वामी एंड पार्टी (नागस्वरम), श्रीमती भूषण कल्याण रमन (गायन), श्री के सत्यनारायण (कुंजीपटल), श्रीमती शेरथलाई आर अनंतकृष्णन (मृदंगम), श्री सुरेश के नायर (गायन), लालगुड़ी जीजेआर कृष्णन और विजयलक्ष्मी (वायलिन युगल), कलाकला कलाविद वेट्टीकवाला के एन शशिकुमार (नागस्वरम), आर गीता (दीक्षितर संकलन), डॉ. एम नर्मदा (वायलिन), कलाकला कलाविद भाग्यलक्ष्मी चंद्रशेखरन (वीणा)।

¼ch½ fgnqLrkuh 'kkL=h; laxhr

राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम और रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में भाग लेने वाले कुछ प्रमुख कलाकार थे पं. रंजीत सेन गुप्ता (सरोद), केन्द्रीय अभिलेखागार की ओर से किशोरी अमोनकर (गायन) को विशेष श्रद्धांजलि, जयतीरथ मेवुंडी (गायन), रविकिरण नाकोद (तबला), संजीव अभयंकर (गायन), ऐबे रुस्तम सोपोरी (संतूर), पं. कार्तिक कुमार (सितार), कैलाश पात्रो (वायलिन), डी कुमार दास (गायन), पं. प्रतीक चौधरी (सितार), सुरंजना बोस (लेफ्टिनेंट कर्नल गायन), पं. सुजीत साहा (तबला), प्रदीप कुमार बारोत (सरोद), एस एल वेणुगोपाल (गायन), सत्येंद्र सिंह सोलंकी (संतूर), मिलिंद शोरे (बांसुरी), पं सोमनाथ मर्दुर (गायन), नरसिंहुलु वदावती (क्लैरियोनेट), पं रवींद्र यवागल (तबला एकल), अनंजना नाथ (गायन), पं साहित्य कुमार नाहर (सितार), सुरेश बापट (गायन), सुधीर पोटे (गायन), अखिलेश गुंडेचा (पखावज), पं राम कृष्ण (क्लैरियोनेट), पं प्रकाश संगीत (गायन), संदीप चटर्जी (संतूर), और राजा काले (गायन)।

¼lh½ fgnqLrkuh lqxe vkSj yksd laxhr

क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में, संगीत शैलियों की एक विस्तृत और विविध श्रेणी प्रसारित की गई, जैसे संजीव घोष द्वारा आधुनिक बांग्ला गीत, देवयानी मुखर्जी द्वारा पुरातनी गीत, जितेंद्र सिंह द्वारा मेघालय के गीत, गजल, गुजराती लोक संगीत हेमंत चौहान, नीलम लैंगे (डोगरी लोक संगीत), बुंदु खान और पार्टी (राजस्थानी लोक संगीत) और वैशाली बाकोरे (गीत/भजन)।

¼Mh½ dukZVd lqxe vkSj yksd laxhr

इसी तरह दक्षिणी भारत से श्रीमती संगीता बालचंद्र (भक्ति संगीत), श्री एम महादेव स्वामी (तंबूरी पद/देवरपद), श्री पी पूर्णचंदर (सुगम संगीत–तेलुगु), श्री एम वी सिंहाचल शास्त्री (हरिकथा) प्रसारित किए गए। 70oa Lora=rk fnol lekjksg dk flyflyk esa ,d fo'k"k dk;Øe vxLr eghus esa çlkfjr fd;k x;kA blesa çfl) ik'oZ xk;d Jh ,l ih ckylqczge.;e }kjk ns'kHkfä xhr xk, x,A

vkdk'kok.kh laxhr lEesyu 2017

कलाकार और संगीत के पारखी लोगों का पसंदीदा आकाशवाणी संगीत सम्मेलन एक वार्षिक संगीत कार्यक्रम है जो 1954 में शुरू हुआ। यह आकाशवाणी के लिए एक मजबूत ब्रांड के रूप में विकसित हुआ है। यह पूरे देश में आयोजित किया जाता है, जिसमें हिंदुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के नामी और उभरते कलाकार भाग लेते हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का कोई कलाकार कभी भी इस प्रतिष्ठित संगीत सम्मेलन में शामिल होने से नहीं चूकता।

आकाशवाणी संगीत सम्मेलन 7 अक्टूबर, 2017 को इस साल 24 स्थानों पर आयोजित किया गया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, ग्वालियर, धर्मशाला, पणजी, पुणे, भुवनेश्वर, कुरुक्षेत्र, वाराणसी, तिरुवनंतपुरम, गुंटूर, मंगल्लुरु, तिरुचिरापल्ली 17 जगहों पर हिंदुस्तानी और कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत कंसर्ट हुए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कंसर्ट सुबह में गुवाहाटी और जम्मू में किए गए। 5 स्थानों – मथुरा, जोधपुर, राजकोट, वारंगल और पुड्डुचेरी में शाम को सुगम और लोक संगीत

आकाशवाणी संगीत सम्मेलन– 2017

कंसर्ट आयोजित किए गए।

इन संगीत समारोहों का प्रसारण डीटीएच पर रागम चैनल, वेब स्ट्रीमिंग और एआईआर सीधा मोबाइल ऐप के अलावा आकाशवाणी के सभी राजधानी और क्षेत्रीय स्टेशनों से राष्ट्रीय हुक–अप पर 4 नवंबर, 2017 से 15 दिसंबर, 2017 तक निर्धारित है।

इस वर्ष के संगीत सम्मेलन कार्यक्रम के प्रमुख और उभरते कलाकार हैं:

fgnLrkuh lxhr

भीमना जाधव (सुंदरी), कलाकला कलाविद अनुराधा पाल (तबला), सुब्रा गुहा (गायन), देबाशीश चक्रवर्ती (गिटार), पं. दिनकर पनशिकर (गायन), उस्ताद कमाल साबरी (सारंगी), सुभेंद्र राव (सितार), पं. मंडन मोहन उपाध्याय, पृथ्वी राजकुमार (तबला–पखावज) (युगल बंदी), पं. निर्मला डे (ध्रुपद/धमार), अब्दुल सलाम नौशाद (क्लैरियनेट), डॉ श्रीमती मृत्युंजय एच आगाडी (गायन), पं. उल्हास कशालकर (गायन), निषाद बाक्रे (गायन), जयदीप घोष (सरोद), अश्विन श्रीनिवासन (वाद्य), पं. संदीपन समाजपति (गायन), मुकेश शर्मा (सरोद), पं. मनोजीत मलिक (गायन), पं. भजन सोपोरी (संतूर), अरुण मोरोन (सितार), पं. दामोदर होता (गायन), पं. सौमित्र लाहिरी (सितार), पं. सांतनु भट्टाचार्य (गायन), अनुराधा कुबेर (गायन), सुभाष वनागे (गिटार), मोहम्मद याकूब शेख (सूफी संगीत), उस्ताद अब्दुल रशीद हाफिज और पार्टी (कलाम–ए–मेयाम), उस्ताद मुस्तफा रजा (विचित्र वीणा), कुहू गांगुली मुखर्जी (गायन) और सुगम तथा लोक संगीत के तीन कार्यक्रम मथुरा, जोधपुर और राजकोट में आयोजित किए गए। नंदिता चक्रवर्ती (गीत/भजन), धर्मेश नरगोत्रा (गजल), शारदा सिन्हा (भोजपुरी लोकगीत), शदाब साबरी और पार्टी (कव्वाली), प्रवीण मकवाना (गुजराती लोक संगीत), शांती बाई चेलक (पंडवानी गायन)।

dukVd lxhr

कलाविद एस आर महादेव शर्मा और कलाविद एस आर राजश्री (वायलिन युगलबंदी), वी. एल तुलसी विश्वनाथ (गायन), कलाविद सुधा रघुनाथन (गायन), सुधा रघुरामन (गायन), कलाविद डी शेषाचारी और कलाविद डी राघव. चरी (गायन युगलवंदी), वसुधा रवि (गायन), कुदालमुर

जनार्दनन (बांसुरी), एम अशोक (सुगम संगीत तमिल), कलानीलयम राजीवम और कोत्ताकली मधु (पदंगल), कलाविद डी श्रीनिवास (वीणा), कलाविद वी नागराजू वेणू (वाद्य),कलाविद सूर्यदेप्पा (वायलिन), कलाविद पेटी सतीश (मृदंगम), कलाविद एम मुनीरातनाम (डोलू), पी सुध ा राणी (भक्ति गायन), एम.एस. शीला (गायन), मैसूर एस राजलक्ष्मी (वीणा), जे ए जयंथ (बांसुरी)।

vkdk'kok.kh laxhr çfr;ksfxrk,& 2016

आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता युवाओं के बीच नई प्रतिभाओं की तलाश करने के लिए नियमित रूप से आयोजित होती है जिसमें 67 विजेताओं को मान्यता के रूप में बी ग्रेड देने के अलावा संगीत की विभिन्न शैलियों में पुरस्कार प्रदान किए गए।

¼2½ tuojh 2018 ls ekpZ 2018 dk nkSjku dqN fu;fer dk;Øe

संत त्यागराज आराधना संगीत समारोह के अवसर पर 6 जनवरी, 2018 को संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में तिरुवइयरू से प्रत्यक्ष रिले और उसी दिन पंचतंत्र कीर्ति गोष्ठी गानम (पंचतंत्र की रचनाओं का समूह गायन) का सीधा प्रसारण।

राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम और रवि वासारिया संगीत सभा में भाग लेने वाले हिन्दुस्तानी और कर्नाटक संगीत के कलाकार निम्न हैं :

देबप्रियो अधिकारी (गायन), राजेंद्र कुलकर्णी (बांसुरी), विदुषी श्रुति सादोलीकर (गायन), एस बालेश (शहनाई), विश्वनाथ नाकोद (तबला), रामचंदर भागवत (स्टाफ) (वायलिन), विजय राम दास (पखावज), मीनल मटगोणकर (गायन), राजरूप चौधरी (सरोद), डॉ. जयश्री रानाडे (सुगम शास्त्रीय गायन), पं. सदानंद नैयम्पल्ली (तबला एकल), दीपक क्षीरसागर (गिटार), फैयाज वसिफुद्दीन डागर (ध्रुपद–धमार), सुनील अवचत (बांसुरी), विदुषी अश्विनी भिडे देशपांडे (गायन), डॉ आर गणेश (गायन), मंजुल सुरेंद्र (वीणा), राम कृष्ण मूर्ति (गायन), पी वरमूर्ति (नागस्वरम) और डीवी मोहन कृष्ण (गायन)।

क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल कुछ कलाकारों में उत्तम प्रधान (नेपाली लोक), शशि कुमार पांडे (रीवा), रंजना बरुआ (अगरतला) और सानिया पटनायक (पुणे) हैं।

[ksy

आकाशवाणी ने 1 अप्रैल, 2017 से 31 अक्टूबर, 2017 की अवधि के दौरान अपने राष्ट्रीय हुक–अप और साथ ही साथ क्षेत्रीय स्टेशनों पर विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को उचित कवरेज प्रदान किया। कुछ प्रमुख आयोजनों के राष्ट्रीय हुक–अप कवरेज का विवरण नीचे दिया गया है:

fØdsV

1. आकाशवाणी द्वारा इंग्लैंड और वेल्स में 4 जून, 2017 से 18 जून, 2017 तक हुए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सभी 15 मैचों, सेमी फाइनल और फाइनल मैच की सीधी कमेंट्री प्रसारित।
2. आकाशवाणी–बीबीसी–एबीसी का सह–निर्माण 'स्टम्प्ड' – सीरीज IV एक अप्रैल, 2017 से 31 अक्टूबर, 2017 (हर शनिवार एफएम रेनबो नेटवर्क पर) तक प्रसारित किया गया।
3. वेस्ट इंडीज में आयोजित भारत–वेस्टइंडीज ओडीआई / टी –20 क्रिकेट सीरीज की गेंद–दर–गेंद कमेंट्री 23 जून, 2017 से 9 जुलाई, 2017 तक प्रसारित की गई।
4. 23 जुलाई, 2017 को इंग्लैंड में आयोजित आईसीसी महिला विश्व कप –2017 के फाइनल मैच की गेंद–दर–गेंद कमेंट्री।
5. 26 जुलाई, 2017 से 6 सितंबर, 2017 तक श्रीलंका में आयोजित भारत–श्रीलंका क्रिकेट सीरीज–2017 की गेंद–दर–गेंद कमेंट्री।

g,dh

1. 30 अप्रैल, 2017 को रोहतक में आयोजित 7वें हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय–2017 के फाइनल मैच का सीधा कवरेज।
2. 25 जून, 2017 को लखनऊ में 7वें हॉकी वरिष्ठ पुरुष राष्ट्रीय–2017 के फाइनल मैच का सीधा कवरेज।
3. 31 अक्टूबर, 2017 को नागपुर में खेले गए 34वें

सुरजीत हॉकी चैम्पियनशिप –2017 के फाइनल मैच का सीधा कवरेज ।

QVc,y

1. 23 अप्रैल, 2017 को गोवा में ऊर्जा–2017 सीएपीएफ यू–17 फुटबॉल प्रतिभा खोज मैच–2017 खेला गया।
2. 21 मई 2017 को कटक में खेले गए 38वें फेडरेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट–2017 के फाइनल मैच का सीधा कवरेज।
3. भारत में 06 अक्टूबर, 2017 से 28 अक्टूबर, 2017 तक फीफा अंडर –17 विश्व कप फुटबॉल–2017 पहले मैच, भारत के सभी मैचों और 16 चक्र से फाइनल मुकाबले तक का सीधा कवरेज।
4. 58वीं सुब्रोतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच का सीधा कवरेज। यह मैच 26 जुलाई, 2017 को दिल्ली में खेला गया।

Vfu l

1. 4 जुलाई, 2017 से 17 जुलाई, 2017 तक विंबलडन टेनिस चौम्पियनशिप, 2017 की दैनिक रिपोर्ट।
2. 7 से 9 अप्रैल, 2017 को बेंगलुरु में खेला गया डेविस कप एशिया/ओशेनिया दूसरे दौर के टेनिस मैच का सीधा कवरेज।

ckLdVc,y

30 जुलाई, 2017 को बेंगलुरु में खेले गए एफआईबीए महिला एशिया कप–2017 मैच पर रेडियो रिपोर्ट

,FkyfVDl

1. 6 से 9 जुलाई, 2017 तक भुवनेश्वर में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप–2017 की दैनिक रिपोर्ट और सीधा एफएम अपडेट।
2. 4 जून, 2017 को पटियाला में आयोजित 21वें फेडरेशन कप नेशनल सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप पर रेडियो रिपोर्ट।
3. चेन्नई में 25 से 28 सितंबर, 2017 में आयोजित 57वें राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप –2017 की रेडियो रिपोर्ट।

cMfeVu

1 अप्रैल 2017 को दिल्ली में खेले गए इंडिया ओपन बैडमिंटन–2017 के फाइनल मैच का सीधा कवरेज।

d'rh

15 मई, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित वरिष्ठ एशियाई फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन स्टाइल और महिला कुश्ती चैम्पियनशिप–2017 पर रेडियो रिपोर्ट।

fofo/k [ky vk;ktu

17 से 27 सितंबर, 2017 तक अशगबत , तुर्कमिस्तान में हुए 5वें एशियाई इंडोर एंड मार्शल आर्ट्स गेम्स –2017 का सीधा एफएम अपडेट।

lkbfDyx

10 अक्तूबर से 12 अक्टूबर, 2017 तक दिल्ली में आयोजित ट्रैक एशिया कप साइक्लिंग स्पर्धा –2017 पर रेडियो रिपोर्ट ।

2017&2018 dk çLrkfor vk;ktu

आकाशवाणी द्वारा प्रसारण की अनुमति/अधिकारों की प्राप्ति पर निम्न कार्यक्रमों के सीधा कवरेज प्रदान करने का प्रस्तावः

1. क्रिकेटः दक्षिण अफ्रीका में भारत–दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट सीरीज (जनवरी–फरवरी)
2. स्टम्प्ड – आकाशवाणी–बीबीसी–एबीसी की सह–प्रस्तुति 1 नवंबर, 2017 से 31 मार्च, 2018 (एफएम रेनबो नेटवर्क पर हर शनिवार)
3. बैडमिंटनः

ए. सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप–2018 (जनवरी, 2018)

बी. बीडब्ल्यूएफ इंडिया ओपन बैडमिंटन–2018 (मार्च, 2018)

4. टेनिसः

चेन्नई ओपन टेनिस चैंपियनशिप (जनवरी 2018)

lekpkj lok çHkkx

आकाशवाणी (एआईआर) को दुनिया के प्रमुख प्रसारण

संगठनों में से एक होने का गर्व है। समाचार सेवा प्रभाग (एनएसडी) भारत और विदेशों में श्रोताओं के लिए समाचार और समाचार आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।

fotu oä0;

समाचार सेवा प्रभाग (एनएसडी) का प्रयास 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' के अपने आदर्शों के अनुरूप रेडियो प्रसारण में उच्चतम पेशेवर नैतिकता और मानकों का पालन करते हुए प्रयास प्रमुख भाषाओं और बोलियों में 24x7 विशाल देश के सभी इलाकों में समाचार और विचार प्रदान करना है। प्रभाग लोगों की आवाजों के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

lekpkj lok çHkkx dk dk;l

- आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग (एनएसडी) देश/विदेश में श्रोताओं के लिए विभिन्न चैनलों पर प्रसारित समाचार बुलेटिनों और समाचार–आधारित कार्यक्रमों को तैयार करता है। यह नई दिल्ली में अपने मुख्यालय से 61 घंटे की अवधि और पूरे देश में 47 क्षेत्रीय समाचार इकाइयों (आरएनयू) के लिए प्रतिदिन 92 भाषाओं/बोलियों (भारतीय और विदेशी) में 609 समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है। समाचार बुलेटिन मूल रूप से प्राइमरी चैनल (क्षेत्रीय सेवाएं सहित) और विविध भारती सेवा, राष्ट्रीय चैनल, एफएम चैनल, डीटीएच चैनल और ऑल इंडिया रेडियो के विदेश सेवा प्रभाग से प्रसारित होते हैं।
- आकाशवाणी समाचार को राष्ट्रीय मुद्दों पर विश्वसनीय, उद्देश्यपूर्ण, निष्पक्ष, समावेशी और संतुलित कवरेज के रूप में देखा जाता है। समाचार सेवा प्रभाग क्षेत्रीय समाचार इकाइयों (आरएनयू) के अपने व्यापक नेटवर्क तथा संवाददाताओं और अंशकालिक संवाददाताओं के साथ समकालीन रुचि और प्रासंगिकता के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और स्थानीय विषयों पर सूचना का प्रसार करने में सफल होता है। समाचार सभी मान्यता प्राप्त भाषाओं और बड़ी संख्या में स्थानीय और जनजातीय बोलियों में उपलब्ध हैं।
- आकाशवाणी समाचार हमारे बहुलवादी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचते हैं और समाचार संकलन तथा प्रसार में संवेदनशीलता, न्याय और संतुलन की जरूरत पर प्रकाश डालने का कार्य करते हैं।
- भारत का एकमात्र सार्वजनिक सेवा प्रसारक
- जनता के बीच प्रामाणिकता और विश्वसनीयता
- देशव्यापी पहुंच–99 प्रतिशत आबादी और 92 प्रतिशत क्षेत्र का कवरेज
- विकास की कहानियों को साझा करना
- भारत की विकास गाथा का प्रसार करना
- लोगों को सरकार की पहल, नीतियों, कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना
- वंचित विशाल ग्रामीण, उप–शहरी श्रोताओं तक पहुंचना
- बड़ी युवा, मोबाइल आबादी तक पहुंचना
- गुणवत्ता आधारित समाचार कार्यक्रम

lxBukRed <kpk

समाचार सेवा प्रभाग का नेतृत्व भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, महानिदेशक (समाचार) करते हैं और उनकी सहायता अतिरिक्त महानिदेशकों (समाचार), निदेशकों (समाचार) और संयुक्त निदेशक (समाचार) की टीम करती है। दिल्ली में समाचार सेवा प्रभाग के विभिन्न परिचालन विंग में शामिल हैं : जनरल न्यूज रूम, हिंदी न्यूज रूम, रिपोर्टिंग यूनिट, टॉक यूनिट, न्यूजरील यूनिट, न्यू फॉर्मेट सेल, भारतीय भाषा इकाइयां, संदर्भ, नीति, योजना और विकास (पीपी एंड डी) यूनिट, आईटी यूनिट एवं प्रशासनिक विंग। विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय समाचार इकाइयों की अध्यक्षता एक निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/आईआईएस ग्रुप 'बी' अधिकारी करते हैं और समाचार संपादक, संवाददाता और समाचार वाचकों–सह–अनुवादकों द्वारा उन्हें सहायता प्रदान की जाती है।

lekpkj lkr

आकाशवाणी (एआईआर) का समाचार सेवा प्रभाग (एनएसडी) समाचार इकट्ठा करने के लिए निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग करता है:

(क) विदेशी संवाददाताओं सहित मुख्यालयों के संवाददाता/रिपोर्टर

(ख) आरएनयू में पदस्थापित संवाददाता

(ग) संबधित आरएनयू के माध्यम देश के 520 जिलों में अंशकालिक संवाददाता (पीटीसी)

(घ) तार एजेंसियां–पीटीआई/यूएनआई

(ड़) सोशल मीडिया यथा – सत्यापित ट्विटर हैंडल, प्रसिद्ध व्यक्तियों के फेसबुक अकाउंट्स

oclkbV vkj lk'ky ehfM;k ly

आईटी यूनिट एनएसडी की आधिकारिक समाचार वेबसाइट newsonair.nic.in का संचालन करती है और वेबसाइट को अद्यतन करती है। वेबसाइट पर विभिन्न राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, खेल, व्यापार समाचार, समाचार आधारित कार्यक्रम, फीचर और विशेष कार्यक्रम अपलोड किए जाते हैं। एनएसडी और क्षेत्रीय समाचार इकाइयों के समाचार बुलेटिनों के ऑडियो और पाठ भी वेबसा. इट पर दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री के 'स्वतंत्रता दिवस संबोधन' तथा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संदेश तथा केंद्रीय बजट आदि के ऑडियो और मूलपाठ वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाते हैं। 'मन की बात' कार्यक्रम का सीधा वेबकास्टिंग एनएसडी की वेबसाइट पर विशेष विंडो के माध्यम से किया जाता है। वेबसाइट पर पोस्ट किए जाने वाले जागरूकता कार्यक्रमों में न्यू इंडिया मंथन, भारत छोड़ो आंदोलन, जनता का सकारात्मक प्रभाव, स्वच्छ भारत अभियान, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, मतदाताओं के लिए ऑनलाइन सेवाएं, राष्ट्रीय एकता दिवस और सतर्कता जागरूकता सप्ताह जैसे अभियानों का कवरेज शामिल है।

foLrkj vkj vfHkuo ç;kl

एनएसडी अपनी मौजूदगी का विस्तार कर रहा है, नई प्रौद्योगिकियों और व्यवहारों को अपना रहा है, जो इसके पारंपरिक प्लेटफॉर्म और न्यू मीडिया और न्यू मीडिया एप्लिकेशन यथा सोशल मीडिया को जोड़ते हैं।

समाचार सेवा प्रभाग ने समाचार/सामाजिक मीडिया जैसे वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, साउंडक्लाउड और इंस्टाग्राम पर अपनी उपस्थिति में काफी वृद्धि दर्ज की है।

lkmMDykmM & एनएसडी 2014 में एक बहुत ही लोकप्रिय ऑडियो प्लेटफॉर्म में शामिल हो गया। प्रमुख राष्ट्रीय बुलेटिन और समकालीन विषयों के कार्यक्रमों को उनके प्रसारण के तुरंत बाद साउंडक्लाउड पर लगाया जाता है और ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से लिंक उपलब्ध कराए जाते हैं। आज एनएसडी के पास 16 हजार फॉलोअर हैं।

युवा पीढ़ी के लिए जून 2013 में फेसबुक अकाउंट शुरू हुआ। इसके 3.2 मिलियन से अधिक फॉलोवर हैं।

एनएसडी का ट्वीटर अकाउंट & airnewsalerts की शुरुआत जनवरी 2013 में हुई ताकि समाचार को मिनट दर मिनट अद्यतन किया जा सके। इसके 1.75 मिलियन से अधिक फॉलोअर हैं, जिनमें सरकार और मीडिया के प्रमुख नाम शामिल हैं।

एनएसडी मुख्यालयों के साथ तालमेल रखते हुए एनएसडी की क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने भी अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज शुरू किए हैं और अपने संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री पोस्ट कर रहे हैं।

एनएसडी की वेबसाइट– www.newsonair.com/ www.newsonair.nic.in पर विभिन्न राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, खेल, व्यापार समाचार, समाचार आधारित कार्यक्रम, फीचर और विशेष कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाता है। इसे औसतन पर प्रति माह 1-67 fefy;u से अधिक लोग विजिट करते हैं।

fjikfVax ;fuV

अवधि के दौरान रिपोर्टिंग यूनिट द्वारा विविध समाचार और घटनाओं को कवर किया गया है जिसमें जीएसटी के कार्यान्वयन और इसकी अनुवर्ती कार्रवाई, डिजिटल भुगतान के लिए भीम ऐप का शुभारंभ, विमुद्रीकरण, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल पूरा होना और विश्व खाद्य भारत सम्मेलन और एक्सपो, स्वच्छता ही सेवा, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा, ग्राम समृद्धि एवम स्वच्छता अभियान, डाक जीवन बीमा के विस्तार के लिए संपूर्ण बीमा ग्राम योजना भी शामिल थीं। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के सभी संस्करण व्यापक रूप से कवर किए गए थे।

jk"Vifr dh bfFk;kfi;k] thcrh vkj uiky ;k=k] mi jk"Vifr की पोलैंड, अर्मेनिया, जकार्ता यात्रा और ç/kkuea=h की म्यांमार, चीन, जर्मनी, स्पेन और श्रीलंका यात्रा के कवरेज के लिए विशेष संवाददाता विदेश गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री के संबोधन को एनएसडी बुलेटिनों में व्यापक कवरेज भी दिया गया।

उपरोक्त समाचार घटनाओं के अलावा संसद और दिल्ली

समाचार सेवा प्रभाग (आकाशवाणी) में इन–हाउस पत्रिका का विमोचन

विधानसभा सत्रों को आकाशवाणी के बुलेटिनों में भी शामिल किया गया।

एनएसडी ने नवंबर 2017 में 31वीं आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री की मनीला यात्रा को कवरेज प्रदान किया।

okrk vkj lkef;dh bdkb

वार्ता और सामयिकी इकाई स्पॉटलाइट/समाचार विश्लेषण, समायिकी, मनी टॉक, वाद– संवाद, कंट्रीवाइड, सुर्खियों से परे, पब्लिक स्पीक और चर्चा का विषय है जैसे अपने दैनिक और साप्ताहिक कार्यक्रमों में समक. ालीन विषयों पर समाचार आधारित विश्लेषण प्रसारित करती है।

'नया भारत मंथन' और भारत छोड़ो आंदोलन के 75वें वर्ष पर विशेष चर्चा कार्यक्रम किया गया। जीएसटी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, कई चर्चा कार्यक्रम और साक्षात्कार प्रसारित किए गए थे। 'नोटबंदी' के एक वर्ष पूरा होने पर, विशेष चर्चा कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रसारित की गई जिसमें डिजिटल इंडिया आंदोलन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर विमुद्रीकरण का प्रभाव, काला धन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, रियल एस्टेट विनियमन शामिल हैं। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली का साक्षात्कार 8 नवम्बर को स्पॉटलाइट/समाचार विश्लेषण कार्यक्रम में प्रसारित किया गया था।

U;t jhy ;fuV

न्यूज रील यूनिट 10 मिनट का दैनिक न्यूजरील/समाचार दर्शन कार्यक्रम को प्रसारित करती है। 30 मिनट का न्यूजरील/समाचार दर्शन विशेष अवसरों जैसे कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर प्रसारित किया गया। इस साल 10 मिनट का विशेष न्यूजरील कार्यक्रम को 'राष्ट्रीय एकता दिवस', अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर और सरकार के 3 साल पूरा करने, 75 वीं वर्षगांठ भारत छोड़ो आंदोलन और स्वच्छता ही सेवा अभियान पर माउंट किया गया था।

fo'k"k çkxkfe.x

ljnkj oYyHkHkkb iVy t;rh

एनएसडी, आकाशवाणी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर, 2017 को राष्ट्रीय एकता दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों का कवरेज किया। इन कार्यक्रमों में नई दिल्ली में संसद भवन के निकट पटेल चौक पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह हुआ जिसमें माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से एकता के लिए दौड़ –2017 को झंडी दिखा कर रवाना किया।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म ने कम से कम 257 ट्वीट्स

किए और 'राष्ट्रीय एकता दिवस' पर एनएसडी की वेबसाइट पर एक विशेष विंडो newsonair.nic.in बनाया गया जिसमें प्रमुख हस्तियों के वीडियो क्लिप, कवरेज की तस्वीरें आदि शामिल हैं।

सरदार पटेल के योगदान को उजागर करते हुए राष्ट्रीय एकता के विषय पर pkj चर्चा कार्यक्रम एनएसडी, मुख्यालय द्वारा प्रसारित किए गए।

47 क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने संबंधित कार्यक्रमों को कवर किया और सरदार पटेल के योगदान पर कार्यक्रम माउंट किए।

e|æk çkRlkgu vfHk;ku

एनएसडी, एआईआर ने 27 सितंबर से 17 अक्टूबर 2017 तक ^e|æk lo/ku vfHk;ku* से संबंधित 17 आयोजनों को कवर किया। एनएसडी ने एफएम गोल्ड कार्यक्रम 'परिक्रमा' में क्षेत्रीय समाचार इकाइयों से प्राप्त 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' पर ऑडियो कैप्सूल भी प्रसारित किया। सोशल मीडिया सेल ने अपने ट्विटर हैंडल, फेसबुक, साउंडक्लाउड और इंस्टाग्राम के माध्यम से ^e|æk lo/ku vfHk;ku* से संबंधित कम से कम 23 कार्यक्रमों का प्रचार किया।

एनएसडी और आरएनयू द्वारा *e|æk lo/ku vfHk;ku* से संबंधित विशेष चर्चा कार्यक्रम भी प्रसारित किए गए थे।

i;Vu io

एनएसडी, आकाशवाणी ने 05 अक्टूबर, 2017 से 25 अक्टूबर, 2017 तक सरकार द्वारा शुरू किए गए 'पर्य. टन पर्व' से संबंधित आयोजनों को व्यापक रूप से कवर किया। सोशल मीडिया सेल ने 'पर्यटन पर्व' से संबंधित कम से कम 39 आयोजनों को कवर किया और अपने ट्विटर हैंडल, फेसबुक, साउंडक्लाउड और इंस्टाग्राम के जरिए प्रचारित किया।

u;k Hkkjr eFku & ldYi ls flf)

समाचार सेवा प्रभाग ने 'नया भारत मंथन–संकल्प से सिद्धि' के संबंध में विशेष कार्यक्रम चलाया और 9 अगस्त 2017 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जिला कलेक्टरों के साथ हुई बातचीत से संबंधित आयोजन को कवर किया। समाचार सेवा प्रभाग ने जिला कलेक्टरों द्वारा एक दृष्टि दस्तावेज तैयार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के फोन काल पर जिला कलेक्टरों की आवाजों के साथ साउंड कास्ट/कैप्सूल की एक श्रृंखला भी प्रसारित की।

LoPNrk xfrfof/k;k

समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की स्वच्छता पखवाड़ा की उपलब्धियों से संबंधित आयोजनों को कवर किया। एनएसडी ने क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार बुलेटिनों, समाचार आधारित कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर 15 सितंबर, 2017 को माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर में लांच 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान से संबंधित आयोजनों के लिए विशेष कवरेज किया ।

vrjk"Vh; ;kx fnol

एनएसडी, आकाशवाणी ने तीसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के योग से संबंधित विभिन्न आयोजनों को व्यापक रूप से कवर किया। इन आयोजनों में लखनऊ का मुख्य आयोजन शामिल था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया। 05 जून, 2017 को योग गुरु बाबा राम देव के साथ साक्षात्कार सहित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में 05 चर्चा कार्यक्रम प्रसारित किए गए। इसके अतिरिक्त मई, 2017 के महीने में 'योग' पर दो कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं।

ifMr nhun;ky mik/;k; tUe 'krkCnh o"k

एनएसडी, आकाशवाणी ने पं. दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी समारोह से संबंधित आयोजनों के लिए चर्चा कार्यक्रमों सहित विशेष कवरेज प्रदान किए।

lnHk vkj ihih ,M Mh ;fuV

एनएसडी, आकाशवाणी की संदर्भ और पीपी एंड डी यूनिट विभिन्न इकाइयों के लिए दैनिक/सरकारी/राजनैतिक दलों के कार्यक्रमों/कार्यक्रमों के बारे में पूर्व जानकारी प्रदान करती है और इसमें मासिक कैबिनेट सारांश, सरकारी कार्यक्रमों की उपलब्धियों, योजनाओं के साथ–साथ स्वच्छता कैलेंडर के अनुसार की गई कार्रवाई पर प्रगति रिपोर्ट का प्रसारण भी शामिल है। यह इकाई आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार के लिए आवेदनों की जांच भी काम करती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार (समाचार) के लिए दिशानिर्देश की समीक्षा की गई और ताजा दिशानिर्देश जारी किए गए। यूनिट ने पुस्तकालय का रखरखाव भी किया है, जिसमें 20998 शीर्षक हैं। कुल संग्रह में से इसमें मास मीडिया और प्रसारण पर लगभग 281 पुस्तकें हैं। पुस्तकालय में लगभग 26 अखबार और 78 पत्रिकाएं मंगाई जाती हैं।

{k=h; lekpkj bdkb;k

पहली क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन को अप्रैल, 1953 में लखनऊ और नागपुर स्टेशनों से प्रसारित किया गया था और बाद में क्षेत्रीय समाचार इकाइयां (आरएनयू) मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में स्थापित की गईं। वर्तमान में देश के विभिन्न हिस्सों में काम कर रही 47 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां हैं। क्षेत्रीय समाचार इकाइयां 77 क्षेत्रीय भाषाओं/बोलियों में बुलेटिन और प्रोग्राम तैयार करती हैं ताकि समाचार क्षेत्र विशिष्ट और लोगों के अनुकूल हो सकें। आरएनयू लगभग 38 घंटे की कुल अवधि के लिए हर दिन 475 बुलेटिन तैयार करती है जिसमें क्षेत्रीय, विदेश, डीटीएच सेवाओं और एफएम सुर्खियां शामिल हैं। आरएनयू द्वारा राज्य विधानसभाओं के सत्र में होने पर विशेष कार्यक्रमों के प्रसारण के अतिरिक्त 140 घंटे की कुल अवधि के लिए एक महीने में 1060 समाचार आधारित कार्यक्रम माउंट करती हैं ।

एफएम मुख्य समाचार शहरों और कस्बों में अपने दैनिक व्यस्त कार्यक्रम के दौरान सूचना प्रेमी श्रोताओं की तत्काल जरूरतों को पूरा करते हैं। वर्तमान में आरएनयू द्वारा 17 भाषाओं में 252 हेडलाइन बुलेटिन तैयार किया जा रहा है।

आरएनयू के पास लगभग 81 पूर्णकालिक संवाददाता/संपादकों, जिला स्तर पर 520 अंशकालिक संवाददाता (पीटीसी) हैं। पीटीसी के पेशेवर कौशल को मजबूत करने के लिए 16 eb] 2017 dk tEe में एक कार्यशाला का आयोजन गया ताकि पीटीसी को नई उभरती मीडिया जैसे ट्वीटर/फेसबुक के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके। अब 45 आरएनयू के पास ट्वीटर हैंडल हैं और 8 नवंबर, 2017 तक 45 आरएनयू के अपने फेसबुक अकाउंट हैं।

एनएसडी ने चुनाव वाले राज्य fgekpy çns'k और xqtjkr में पीटीसी कार्यशालाओं का आयोजन किया ताकि उन्हें चुनाव कवरेज और मॉडल आचार संहिता के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके।

ubl vkj,u;w@cqysfVu ¼2017&18½ dh 'kq#vkr

7 अप्रैल, 2017 को विशाखापत्तनम में 10 मिनट की शाम की बुलेटिन के साथ एक नई क्षेत्रीय समाचार इकाई प्रारंभ की गई।

jktHkk"kk dk dk;kZUo;u

राजभाषा इकाई ने राजभाषा नीतियों पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेश का कार्यान्वयन किया। स्वच्छता पर स्लोगन और पोस्टर प्रतियोगिता तथा हिन्दी में क्वीज कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। न्यूज रीडर–सह–अनुवादकों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था। हिंदी पखवाड़ा के दौरान 13 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और पुरस्कारों का वितरण किया गया। अंतरविभागीय पत्रिका समाचार भारती 2017 का छठा अंक प्रकाशित किया गया और इसे 29 अगस्त, 2017 को महानिदेशक (समाचार), आकाशवाणी द्वारा जारी किया गया था।

okf.kfT;d foax

आकाशवाणी का वाणिज्यिक विंग मुंबई में अपने केंद्रीय बिक्री इकाई के माध्यम से काम करती है और देश के विभिन्न भागों में 15 मुख्य वाणिज्यिक प्रसारण सेवा केंद्र हैं।

वाणिज्यिक विंग ने पहली बार राजस्व साझा करने की व्यवस्था में पहुंचने के लिए 'महाभारत' के ऑडियो संस्करण और भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग 'चांदी के पर्दे से' पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया। शुल्क संशोधन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और नई दरें 01 जून, 2017 से लागू की गई हैं। संशोधनों में इकाइयों को विवेकाधीन शक्तियां देकर अधिक विज्ञापनदाताओं को आकर्षित करना और क्षेत्र में, सभी प्राथमिक चैनलों, स्थानीय रेडियो स्टेशनों, एफएम और विविध भारती स्टेशनों में बुकिंग के लिए स्पॉट–बुकिंग पर 1:1 बोनस योजना जारी रखने की सुविधाएं शामिल हैं।

नीचे दी गई तालिका में आकाशवाणी के सभी स्रोतों से सकल राजस्व आय का विवरण है, जिसमें पिछले पांच सालों के दौरान विज्ञापनों से आय भी शामिल हैं :

वर्ष	सकल राजस्व आय
2012–13	₹ 349.84 करोड़
2013–14	₹ 409.77 करोड़
2014–15	₹ 468.39 करोड़
2015–16	₹ 489.30 करोड़
2016–17	₹ 501.15 करोड़

इस वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए राजस्व आंकड़े शुद्ध मूल्यों में हैं यानी सभी करों और छूटों को घटाकर मूल्य निर्धारण किया गया है। 2017–18 (अक्टूबर 2017 तक) में शुद्ध राजस्व 273.39 करोड़ रुपए है।

okf.kfT;d vkj jktLo foHkkx ¼lhvkjMh½

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 270 करोड़ (सकल) के लक्ष्य के मुकाबले 272 करोड़ हासिल किया गया।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए राजस्व लक्ष्य 325 करोड़ शुद्ध है। egRoi.k jktLo vftr djus okys dk;Øe ^eu dh ckr* ¼3-15 djkM #i;½] ^LikVl c,MdkLV l* ¼5-23 djkM #i;½] ^lfudk dk lns'k* ¼38 yk[k½] ^vuxt* ¼28 yk[k½ vkfn gA

सीआरडी ने 2016–17 में दिसंबर 2016 से जून 2017 तक रेडियो श्रोताओं के लिए धारावाहिक महाभारत के 140 एपिसोड का विपणन किया, जिसमें 11.67 करोड़ रुपये (निर्माताओं के साथ राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर) की कमाई हुई। सितंबर, 2017 के बाद से एक नई प्रस्तुति 'चांदी के पर्दे से' आकाशवाणी पर है और अब तक 10 करोड़ रु. (राजस्व साझेदारी आधार पर) का राजस्व अर्जित किया है जो महाभारत की राजस्व आय से अधिक है।

राष्ट्रीय समाचार और क्षेत्रीय समाचार भी राजस्व अर्जित करने में बहुत योगदान करते हैं (लगभग 50 करोड़ रुपए)।

Vkalf ØI'ku vkj çkxke ,Dlpt lok

ट्रांसक्रिप्शन सेवा 3 vçy 1954 को शुरू की गई थी और इसे भारत के राष्ट्रपतियों और प्रधान–मंत्रियों के विशेष संदर्भ के साथ सभी गणमान्य व्यक्तियों के भाषणों का प्रतिलेखन तैयार करने का मुख्य कार्य सौंपा गया। यह यूनिट भविष्य के प्रसारण के उद्देश्य से रिकॉर्डिंग के संरक्षण के लिए वाइनिल डिस्क लेबल के 'एआईआर–टीएस रिकॉर्ड' के प्रसंस्करण का काम भी कर रही थी। इस सेवा का नामकरण 1 अप्रैल, 1959 से *Vkalf ØI'ku ,M çkxke ,Dlpt lfol* में बदल दिया गया और कार्यालय को 'निदेशक' के स्वतंत्र प्रभार के तहत रखा गया। एनालॉग चुंबकीय टेप आदि जैसे संरक्षण के नए तरीकों का इस्तेमाल किया गया।

lxBukRed ljpuk

इस कार्यालय में निम्नलिखित कार्यकारी इकाइयां हैं–

(ए) केंद्रीय अभिलेखागार (डिजिटल ध्वनि अभिलेखागार)

(बी) कार्यक्रम एक्सचेंज यूनिट (आंतरिक और विदेशी)

(सी) राष्ट्रपतियों/प्रधानमंत्रियों के भाषणों का प्रतिलेखन

(डी) रिबफर्बिशिंग यूनिट

(ई) वाणिज्यिक विज्ञप्ति और विपणन

fo’k"k dk;Øek dk ek/;e l vftr jktLo ¼ldy½] foÙk o"k 2017&18

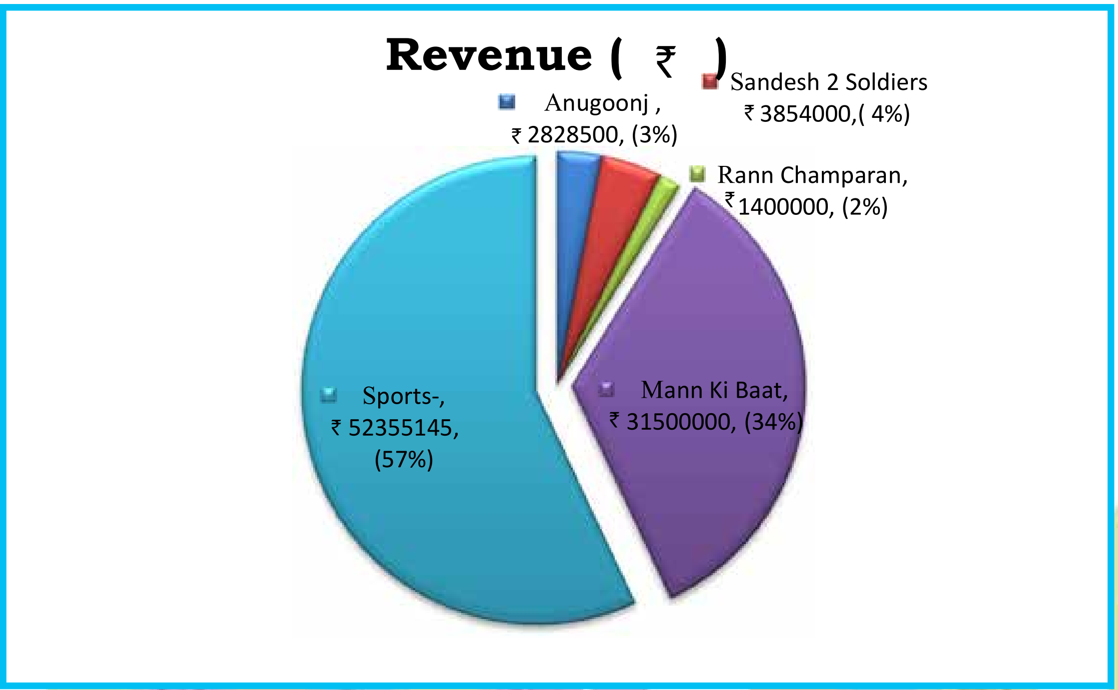

vkdk'kok.kh vfHkys[kkxkj ls fjyht

पिछले कुछ समय से आकाशवाणी सभी प्रमुख संगीतकारों की प्रस्तुतियों को प्रसारित और संरक्षित करता है। आज आकाशवाणी के पास भारतीय शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों का शानदार भंडार है। एआईआर अभिलेखागार ने अप्रैल 2003 से 'आकाशवाणी संगीत' बैनर के तहत अपने अनमोल संगीत अभिलेखागार से संकलनों को जारी करना शुरू कर दिया है। अब तक 105 संगीत एलबम केंद्रीय अभिलेखागार से जारी किए गए हैं। उनकी बिक्री के लिए बिक्री काउंटर आकाशवाणी के 100 स्टेशनों, दूरदर्शन केंद्रों और नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में खोले गए थे।

fjyht dh fy, rS;kj ,lhMh

1. निम्नलिखित ऑडियो सीडी स्क्रीनिंग, चयन, ऑडियो गुणवत्ता सुधार और अंतिम रूप देने के बाद रिलीज के लिए तैयार हैं :

   (ए) गुरुबाणी,

   (बी) गिरिजा घर समूह गायन

   (सी) हम्द–नात–सलाम–मंकबत

   (डी) उस्ताद मुश्ताक अली खान (सितार)

ubZ foi.ku j.kuhfr;k

आकाशवाणी 'आकाशवाणी संगीत' के बैनर के अंतर्गत प्रामाणिक और मूल अभिलेखीय संगीत को जारी कर रही है। बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल www.prasarbharatiarchives.co.in फरवरी 2016 में शुरू किया गया था, जहां आकाशवाणी और दूरदर्शन के अभिलेखागारों के दुर्लभ संग्रह उपलब्ध हैं। दुर्लभ संग्रह अब www.amazon.in पर भी उपलब्ध हैं।

/ofu vfHkys[kkxkj

भारतीय संगीत रिकॉर्डिंग की सबसे बड़ी ऑडियो लाइब्रेरी ध्वनि अभिलेखागार है, जो प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों, स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नेताओं, पुरस्कार विजेता रेडियो नाटक, फीचर, वृत्तचित्रों और स्मारक व्याख्यान तथा भारत के सभी राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्री की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखता है।

fMftVy /ofu vfHkys[kkxkj

ट्रांसक्रिप्शन और प्रोग्राम एक्सचेंज सेवा (टी एंड पीईएस) प्रसारण नेटवर्क में प्रमुख डिजिटल पुस्तकालयों में से एक है।

jsfM;ks vkRedFkk

रेडियो आत्मकथा की श्रेणी में जीवन के सभी क्षेत्रों के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की 228 रिकॉर्डिंग को संरक्षित किया गया है। आकाशवाणी का केंद्रीय अभिलेखागार प्रसिद्ध श्री जे आर डी टाटा, उस्ताद अली अकबर खान, श्री हरिवंश राय बच्चन और डॉ. वर्गीस कुरियन जैसे संगीतकारों, सार्वजनिक व्यक्तित्वों , साहित्यिकारों आदि की आत्मकथाओं की रिकॉर्डिंग का एक अनमोल समृद्ध भंडार है। हाल ही में हमने निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों की आत्मकथाएं रिकार्ड की हैं :

(ए) पद्मश्री विदुषी प्रो. रीता गांगुली, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक

(बी) पद्मश्री डॉ. ज्ञान चतुर्वेदी, राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ कार्टूनिस्ट और

(सी) डॉ. कपिल तिवारी, वरिष्ठ लेखक, दार्शनिक, भाषा विशेषज्ञ तथा शोध विद्वान

çksxzke ,Dlpsat ykbczsjh

पीईयू लाइब्रेरी में स्टेशनों के बीच विनिमय के लिए 8000 टेप हैं जिसमें रेडियो धारावाहिक, भाषाओं पर पाठ, सामुदायिक रूप से गाए जाने वाले गीतों के साथ–साथ संगीत तथा बोले जाने वाले कार्यक्रमों की रिकार्डिंग है।

ट्रांसक्रिप्शन और प्रोग्राम एक्सचेंज सेवा को आरएन चैनल पर 11.10 बजे से 12.15 बजे के बीच एक निश्चित हिस्सा आवंटित किया गया है ताकि ध्वनि अभिलेखागार, और कार्यक्रम एक्सचेंज लाइब्रेरी के कार्यक्रमों सहित आकाशवाणी के सभी स्टेशनों पर कार्यक्रमों को प्रेषित किया जा सके।

कार्यक्रम एक्सचेंज लाइब्रेरी डीजी की पीपी एंड डी यूनिट की सॉफ्टवेयर विकास परियोजनाओं के तहत निर्मित रेडियो धारावाहिकों को आकाशवाणी के चिन्हित रेडियो स्टेशनों में प्रसारित करती है। आकाशवाणी डीजी के केन्द्रीय नाटक इकाई द्वारा तैयार मासिक श्रृंखला नाटक आकाशवाणी के रेडियो स्टेशनों को भी प्रसारित किया जाता है।

Vkl fØI'ku ;fuV

सार्वजनिक कार्यक्रमों के सिससिले में राष्ट्रपति और

प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सभी भाषणों को रिकॉर्ड करना आकाशवाणी स्टेशनों के लिए अनिवार्य है। सभी प्रतिलेखनों के बाउंड वॉल्यूम तैयार किए जाते हैं और अभिलेखागार में रखे जाते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सभी भाषण सीडी फॉर्म में विस्तृत डेटा प्रविष्टि के साथ संरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑडियो के साथ ध्वनि प्रतिलेखन केंद्रीय अभिलेखागार में संरक्षित है।

vkdk'kok.kh dh iqjkuh if=dkvksa dk fMftVhdj.k

भारतीय श्रोताओं, आकाशवाणी पत्रिका, सारंग, आवाज, बेतार जगत, वाणी और आकाशी जैसे आकाशवाणी के करीब 5000 पुराने प्रकाशनों को डिजिटल बनाया गया है और उनके मेटा डेटा वेब आधारित पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर पर अपलोड किए जा रहे हैं।

1 vçSy ls 31 vDVwcj] 2017 dh nkSjku vkdk'kok.kh vfHkys[kkxkj ekdsZfVax fMfotu esa xfrfof/k;ksa dh fo'ks"krk,a

(1) आकाशवाणी संगीत सीडी और आकाशवाणी और दूरदर्शन के अभिलेखीय सामग्री के प्रचार और जागरूकता के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों के दौरान स्टालों को लगाया गया है :—

(ए) 5 अप्रैल, 2017 से संवाद भारत पर सम्मेलन, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।

(बी) ग्रेटर नोएडा में 17 से 20 अप्रैल, 2017 तक सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी, भारतीय प्रदर्शनी मार्ट ।

(सी) प्रगति मैदान में 26 अगस्त से 3 सितंबर, 2017 तक दिल्ली पुस्तक मेला 2017

(डी) 7 अक्टूबर, 2017 को सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन।

(2) 25 से 26 मई, 2017 तक फिजी में सतत विकास पर सम्मेलन में आकाशवाणी और दूरदर्शन के चयनित कार्यक्रमों को 14 प्रशांत द्वीप देशों (पीआईसी) को प्रसारण के लिए उपहार में दिया गया है।

foÙkh; xfrfof/k;ka

(क) अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2017 के दौरान अभिलेखीय रिलीज और फुटेज से बिक्री लगभग 18 लाख थी।

(ख) इस ऑनलाइन बिक्री में से लगभग 4.5 लाख की बिक्री पीबी वेबसाइट यानी http://www.prasarbharatiarchives.co.in और www.amazon.in के माध्यम से की गई थी।

fons'k lsok çHkkx

¼d½ lf{kIr ifjp;

ऑल इंडिया रेडियो ने 1 अक्टूबर 1939 को विदेशी प्रसारण प्रारंभ किया। यह प्रसारण विशुद्ध रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के प्रचार के लिए किया गया ताकि क्षेत्र में जर्मन रेडियो प्रचार का मुकाबला किया जा सके। इस भाग में बीबीसी के प्रयासों को पूरा करने के लिए पश्तो भाषा में सेवा के साथ विदेश प्रसारण शुरू किया गया था। आकाशवाणी का विदेश प्रसारण सेवा प्रभाग (ईएसडी) भारत और बाकी दुनिया के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है, खासकर उन देशों के साथ जहां भारत की रुचि भारतीय आबादी के कारण उन देशों में रहती है।

आकाशवाणी का fons'k çlkj.k lsok çHkkx विश्व के रेडियो नेटवर्कों में पहुंच और आकार में की दृष्टि से उच्च स्थान पर है और 27 भाषाओं में करीब 150 देशों को कवर करता है। जिन भाषाओं में एआईआर अपने विदेशी दर्शकों तक पहुंचता है, उनमें अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्वाहिली, अरबी, फारसी, तिब्बती, चीनी, थाई, बर्मी और इंडोनेशियाई भाषा हैं। हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ और गुजराती सेवा विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सारायकी, सिंहली, बांग्ला और नेपाली सेवा भारतीय उपमहाद्वीप के श्रोताओं और तात्कालिक पड़ोस के लिए हैं। विदेश सेवा प्रभाग एक समग्र पैटर्न का अनुसरण करता है जो आम तौर पर न्यूज बुलेटिन, कमेंट्री, सम–सामयिक घटनाओं और भारतीय प्रेस की समीक्षा के होते हैं।

विदेश सेवा प्रभाग के कार्यक्रमों का प्रमुख विषय भारत की वास्तविकता को एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य के रूप में प्रस्तुत करना है जो जीवंत आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी प्रगति का कार्य कर रहा है। इसी तरह अहिंसा में भारत का विश्वास, सार्वभौमिक मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और एक नई विश्व आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में भारत के योगदान की चर्चा अक्सर की जाती है। विदेश प्रसारण सेवा वर्तमान सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों

के तहत लगभग 25 विदेशी प्रसारण संगठनों को संगीत, बोलने वाले शब्द और समग्र कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग की सप्लाई जारी रखे हुए है।

¼[k½ ubl igy vkj vk/kfudhdj.k ç;kl

(1) विदेश प्रसारण सेवा (ईएसडी) ने हाल ही में इन क्षेत्रों के लिए लक्षित विभिन्न सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण का काम प्रारंभ किया है। वर्ष के दौरान अपनी नेपाली, तिब्बती, चीनी, दारी, बलूची, उर्दू, सिंधी, बांग्ला, पश्तो और फारसी सेवाओं की सामग्री पुनर्रचना पर विशिष्ट जोर दिया गया।

इस प्रयास के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की हाल की ईरान यात्रा के दौरान विदेश सेवा प्रभाग ने अपनी फारसी सेवा के लिए एक समर्पित मल्टी मीडिया वेबसाइट और मोबाइल ऐप लांच किया । माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले साल ईरान की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान इस सेवा का विशेष जिक्र किया था। भारत की विदेश नीति और विदेशी संबंधों में बांग्लादेश के महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 23 अगस्त 2016 को बांग्लादेश के लिए एक समर्पित सेवा और बांग्ला भाषी डायसपोरा 'आकाशवाणी मैत्री' लॉन्च की थी। यह चैनल पश्चिम बंगाल के चिनसुराह में स्थापित अत्याधुनिक उच्च शक्ति के 1000 किलोवाट डीआरएम ट्रांसमीटर से कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। इसमें बांग्लादेश की पूरी लंबाई और चौड़ाई को कवर करने की क्षमता है। चैनल प्रति दिन 16 घंटे के लिए प्रसारण करता है और कार्यक्रम सीधा स्ट्रीमिंग के माध्यम से मल्टी मीडिया वेबसाइट airworldservice.org और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

(2) ईएसडी की 27 सेवाओं के लिए मांग आधार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसारक मानकों के समरूप सीधा इंटरनेट रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन और रेडियो के साथ एक मल्टी–मीडिया वेबसाइट लॉन्च की गई है। इससे विश्व स्तर पर और विशेषकर उन क्षेत्रों में सभी ईएसडी सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी जहां पहले सेवा नहीं पहुंच रही थी। ईएसडी का मल्टी–मीडिया वेब पोर्टल www.airworldservice.org पर उपलब्ध है।

(3) अभिलेखीय मूल्य के सभी रिकॉर्डिंग के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटीकरण कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में 25,000 से अधिक टेप समयबद्ध तरीके से डिजिटल किए गए हैं।

(4) ईएसडी ने सभी विदेशी भाषा इकाइयों को कंप्यूटरीकृत करने की दिशा में कदम शुरू किया है ताकि धीरे–धीरे कागज रहित प्रणाली की तरफ बढ़ा जा सके। सभी इकाइयों को सहज और प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए इंटरनेट सुविधा प्रदान की गई है।

(5) ईएसडी ने अपने कार्यक्रमों के प्रसार के लिए फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप्प, मोबाइल ऐप आदि जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करना शुरू कर दिया है ताकि कार्यक्रमों को अधिक इंटरएक्टिव बनाया जा सके। उर्दू सेवा में व्हाट्सएप्प आधारित अनुरोध कार्यक्रम और फोन–इन कार्यक्रमों को दुनियाभर में बहुत सराहा गया है, जबकि मोबाइल एप्लिकेशन के साथ ईएसडी सेवाएं अब विश्व में आसानी से सुलभ हो गई हैं।

¼x½ fon'k e=ky; d lkFk lg;kx vkj leUo;u

विदेश मंत्रालय (विदेश मंत्रालय और ईएसडी, आकाशवाणी के एक्सपी डिवीजन के प्रयोजनों की समानता के साथ समन्वय और सहयोग को पुनर्जीवित करने के लिए पहल की गई है। 34 वर्षों के बाद विदेशी प्रसारण पर समन्वय–सह–सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है जिसमें विदेश सहित सभी हितधारक शामिल किए गए हैं। इसकी पहली बैठक 25 सितंबर, 2017 को हुई।

ईएसडी के 15 विदेशी और 12 भारतीय भाषा सेवाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए विदेशों में सभी भारतीय मिशनों द्वारा एक विदेश प्रसारण दिवस मनाने का बड़ा निर्णय लिया गया है। एनडीए सरकार की नई पड़ोस नीति को देखते हुए भूटान के लिए एक झोंगखा भाषा सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है जो अंतिम चरण में है।

jk"Vªh; pSuy

1. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम 'मन की बात' सीधा रिले किया जाता है।
2. राष्ट्रीय चैनल 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना', 'अटल पेंशन योजना', 'प्रधानमंत्री जनधन योजना' जैसी योजनाओं पर कार्यक्रम प्रसारित करता है ।
3. 'उज्ज्वला योजना', 'स्वच्छ भारत अभियान', 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना', 'स्मार्ट सिटी मिशन', 'अल्पसंख्यकों के लिए उस्ताद योजनाएं' और 'दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए योजनाएं'

जैसी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को उजागर करने वाले कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

4. 'राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन', स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया इत्यादि योजनाओं पर कार्यक्रम माउंट किए गए।

5. देश के ग्रामीण इलाकों के किसानों और लोगों के उत्थान के लिए 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड', 'प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना', 'दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना', 'फसल बीमा योजना' बनाई गई।

6. *e|ykdkr* कार्यक्रम में कुछ प्रसिद्ध लेखक और पदमश्री श्याम सिंह 'शशि', डॉ. रामदरस मिश्र, डॉ. राजकुमार सुमित्रा जैसे लेखक और कवि तथा प्रसिद्ध व्यंग्यकार डॉ. प्रेम जनमेजय का साक्षात्कार किया गया।

7. मई–जून 2017 के दौरान *jetku* में कार्यक्रम *lgjxgh* राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से प्रसारित किया गया था जिसमें हम्द, नात, कव्वाली और कुरान के पाठ शामिल थे।

8. *n'k çn'k* शीर्षक से नया पर्यटन आधारित कार्यक्रम श्रोताओं के लिए शुरू किया गया।

vrjk"Vh; lc/k ;fuV

1. यूनिट ने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आकाशवाणी की भागीदारी में समन्वय का काम किया। इन प्रतियोगिताओं में एबीयू पुरस्कार–2017, एआईबीडी पुरस्कार–2017, 29वां यूआरटीआई इंटरनेशनल रेडियो ग्रां प्री 2017, 5वां ग्रां प्री नोवा, इंटरनेशनल रेडियो ड्रामा फेस्टिवल और एबीयू सोनिक रेडियो ड्रामा फेस्टिवल हैं। आकाशवाणी की दो प्रविष्टियों को चीन के चेंगदू में आयोजित पुरस्कार समारोह में एबीयू पुरस्कार–2017 के 'प्रशस्ति पत्र' से सम्मानित किया गया।

2. आकाशवाणी ने एबीयू पुरस्कार 2017 के प्रारंभिक निर्णय में श्रीमती उज्वला श्रीनिवास, सहायक कार्यक्रम निदेशक, मुंबई को नामित करके योगदान दिया। उन्होंने क्वालालंपुर, मलेशिया में एबीयू पुरस्कार 2017 के निर्णायक मंडल के अंतिम सदस्य के रूप में अपनी सेवा दी।

3. अंतर्राष्ट्रीय संबंध यूनिट ने आकाशवाणी और बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया।

4. अंतर्राष्ट्रीय संबंध यूनिट ने तजाकिस्तान, उजबेकिस्तान में आयोजित 23वीं बौद्धिक संपदा और कानूनी समिति

रेडियो एशिया– 2017

की बैठक में अपनी भागीदारी के बारे में महानिदेशक, आकाशवाणी और आठ अन्य अधिकारियों की विदेशी प्रतिनियुक्तियां सफलतापूर्वक निष्पादित कीं। रेडियो एशिया सम्मेलन–2017 बैंकाक, थाईलैंड में आयोजित एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन–2017 चिन्दो, चीन में आयोजितय माले, मालदीव में आयोजित एआईबीडी महासभा मीडिया 2020 और पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स इंटरनेशनल सम्मेलन सिनाया, रोमानिया में आयोजित किया गया और कुआलालंपुर, मलेशिया में एबीयू पुरस्कार 2017 की अंतिम स्क्रीनिंग आयोजित की गई।

5. आकाशवाणी को दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रसार भारती की ओर से एशिया मीडिया सम्मेलन 2018 के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह सम्मेलन 8 से 11 मई, 2018 तक होगा और इसमें 300 से 400 विदेशी प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है।

jk"Vh; çlkj.k vkj eYVhehfM;k ¼dk;Øe½ vdkneh ¼,u,ch,e½

1948 में यूनिफाइड नेशनल एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीमीडिया को डीजी, आकाशवाणी, नई दिल्ली के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था और इसे डीजी आकाशवाणी अधीनस्थ कार्यालय के रूप में वर्तमान स्थान रेडियो कॉलोनी, किंग्सवे कैंप में स्थानांतरित कर दिया गया। छह क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान अर्थात एनएबीएम भुवनेश्वर और अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, शिलांग और तिरुवनंतपुरम में आरएबीएम कार्यालय अस्तित्व में आए।

एनएबीएम दिल्ली, भुवनेश्वर और उनके अधीन आरएबीएम

को प्रसार भारती को हस्तांतरित कर दिया गया।

1- vkdk'kok.kh vkj njn'ku LVkQ d fy, bu&gkml çf'k{k.k ikBîØe

नेशनल एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीमीडिया, दिल्ली और भुवनेश्वर ने टेलीविजन प्रॉडक्शन तकनीकों, नॉन लाइनर संपादन और थ्रीडी ग्राफिक्स, टेलीफिल्म प्रोडक्शन एंड तकनीक पर अपने दूरदर्शन कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया।

प्रशासनिक पाठ्यक्रम प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ–साथ आकाशवाणी के कार्यक्रम और इंजीनियरिंग शाखाओं में तैनात कर्मचारियों तथा दूरदर्शन çf'k{k.k dk;Øe में तैनात कर्मियों के लिए आयोजित किए जाते हैं – lg;kx e :

1- yfxd lonu'khyrk vkj çkxkfex ij dk;l'kkyk

(ए) 11 से 13 अक्टूबर, 2017 तक यूनिसेफ के भारत कार्यालय के सहयोग से आकाशवाणी के प्रोग्रामर के लिए लिंग संवेदनशीलता और प्रोग्रामिंग पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

(बी) दूरदर्शन के प्रोग्रामर के लिए विशेष रूप से एक समान कार्यशाला 22 से 24 नवंबर, 2017 तक आयोजित की गई।

(सी) अन्य आरएबीएम में इस सहयोग के विस्तार के लिए बातचीत चल रही है।

2- oLr vkj lok dj] ih,Q,e,l ij dk;l'kkyk

डीजी, आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा एनएबीएम दिल्ली और अन्य आरएबीएम के साथ मिलकर वस्तु और सेवा कर तथा पीएफएमएस के सफल कार्यान्वयन के लिए कार्यशाला की श्रृंखला आयोजित की गई।

Jkrk vuql/kku fox

वर्ष 2017–18 के दौरान, निम्नलिखित दर्शकों के अनुसंधान गतिविधियों/अध्ययन योजना चलाई गईं/योजना बनाई गई :

1. अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2017 तक प्रसारित 'मन की बात' के सभी सात एपिसोड के लिए टेलीफोनिक त्वरित प्रतिक्रिया पर अध्ययन।
2. अप्रैल–मई, 2017 में 7 स्टेशनों पर चरम पंथ प्रभावित क्षेत्र (चरण –3) में प्रचार अभियान पर प्रभाव आकलन अध्ययन।

यूनीसेफ द्वारा लैंगिक संवेदनशीलता पर 11–13 अक्तूबर, 2017 को आयोजित कार्यशाला

3. 50 स्टेशनों पर अगस्त, 2017 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के प्रचार अभियान पर प्रभाव आकलन अध्ययन।
4. स्थानीय रेडियो स्टेशनों (एलआरएस) पर जुलाई–अगस्त, 2017 में 25 स्टेशनों पर रेडियो श्रोता सर्वेक्षण।
5. प्रसार भारती–2016–17 की वार्षिक रिपोर्ट का संकलन

1 uocj] 2017 l 31 ekp] 2018 dh vof/k d nkjku v/;;u ;ktuk

1. नवंबर–दिसंबर, 2017 के दौरान 28 स्टेशनों पर प्राथमिक चैनल पर रेडियो श्रोता सर्वेक्षण
2. जनवरी–फरवरी, 2017 के दौरान 26 स्टेशनों पर एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड चैनलों पर रेडियो श्रोता सर्वेक्षण
3. फरवरी–मार्च, 2017 के दौरान 7 स्टेशनों पर चरम पंथ प्रभावित क्षेत्र (चरण –4) में प्रचार अभियान पर प्रभाव आकलन अध्ययन।

vtk@tt k@fiNM oxk d fy, vkj{k.k

आकाशवाणी ने अजा/जजा/पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति लागू करने के लिए एक समर्पित अजा/जजा प्रकोष्ठ स्थापित करने के सभी आवश्यक उपाय किए हैं। सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों को लाभ देने के लिए नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी सभी प्रासंगिक

नीति निर्देश क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय इकाइयों को अनुपालन के लिए भेजा गया है।

lkoltfud f'kdk;r vkj lek/kku 0;oLFkk

शिकायत निवारण और पहुंच व्यवस्था प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही है और केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से निगरानी की जाती है।

1 अप्रैल, 2017 से 15 नवंबर, 2017 की अवधि में डीएआरपीजी पोर्टल पर शिकायतों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

(1) बकाया शेष –	114
(1 अप्रैल, 2017 तक)	
(2) शिकायत प्राप्त –	607
(1 अप्रैल, 2017 से 15 नवंबर, 2017)	
dqy %	721
(3) निष्पादित –	547
(4) समापन शेष –	174
(15 नवंबर, 2017 तक)	

lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2005 dk dk;kUo;u

1. सभी आकाशवाणी केंद्रों ने विभिन्न स्वरूपों में कई कार्यक्रमों को प्रसारित किया है ताकि लोगों को सशक्त बनाने और प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में योगदान देने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में लोगों को सूचित किया जा सके। सभी स्टेशनों के कार्यक्रम प्रमुखों से कार्यक्रम में इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता को उजागर करने के लिए कहा गया है।

2. आकाशवाणी में 42 सीपीआईओ और निदेशालय में 18 अपीलीय प्राधिकारी को आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नामित किया गया है। वर्ष 2017–18 (1 जनवरी, 2017 से 31 अक्टूबर, 2017 तक) में निदेशालय में 855 आवेदन प्राप्त हुए और निर्धारित समय के भीतर उत्तर दिए गए। अवधि के दौरान (1 जनवरी, 2017 से 31 अक्टूबर, 2017) निदेशालय में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 79 अपील प्राप्त हुई थीं और सभी का निपटान किया गया था। सीपीआईओ और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की सूची को हमारी वेबसाइट पर नियमित रूप से अद्यतन किया गया है।

Loh—r in l[;k vkj u, Loh—r in

आकाशवाणी में विंग के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या नीचे दी गई है:

foax	vkdk'kok.kh
प्रोग्राम	6896
इंजीनियरिंग	5,974
आकाशवाणी मुख्यालय	725
प्रशासन(आकाशवाणी के केंद्र)	10,833
समाचार विंग	209
सीसीडब्ल्यू	1,492
dqy	26]129

dY;k.k foHkkx

1. आकाशवाणी का एक विशाल नेटवर्क है जिसमें पूरे देश में 467 केंद्र/कार्यालय हैं। तीन धाराओं– कार्यक्रम, इंजीनियरिंग और आकाशवाणी प्रशासन में काम कर रहे लगभग 16000 कर्मचारी हैं।

2. आकाशवाणी में समूह 'ए', 'बी' और 'सी' में काम कर रही महिलाओं का प्रतिशत मानव संसाधनों की कुल शक्ति का लगभग 25 प्रतिशत है। सभी आकाशवाणी स्टेशनों/कार्यालयों को यौन उत्पीड़न की शिकायतों/शिकायतों की जांच के लिए एक शिकायत समिति स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी आकाशवाणी स्टेशनों/कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की गई है। यह भी निर्देश दिया गया है कि आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्षता वरिष्ठ स्तर की महिला अधिकारी द्वारा की जाएगी और इसके आधे सदस्यों में महिला होनी चाहिए।

vkdk'kok.kh egkfun'kky;] ubl fnYyh e fnol euk, x, ¼01 vçy] 2017 l 31 vDVcj] 2017 rd½

1- 14 vçy] 2017 % ckck lkgc M,- Hkhe jko vEcMdj dh t;rh% 13 नवंबर, 2017 को इस निदेशालय में महानिदेशक, आकाशवाणी द्वारा 11 बजे सम्मेलन हॉल, आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली में

श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।

2- 21 eb] 2017 ¼ vkradokn fojks/kh fnol½ प्रत्येक वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 मई, 2017 को सम्मेलन हॉल, आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली में शपथ समारोह आयोजित किया गया था।

3- 20 vxLr] 2017¼ lnHkkouk fnol½ सद्भावना दिवस मनाने का उद्देश्य हिंसा से बचने और लोगों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देना है। 18 अगस्त, 2017 को फील्डन हॉल, पहली मंजिल, आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली में 11.00 बजे महानिदेशक द्वारा क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में शपथ दिलाने का समारोह का आयोजित किया गया।

4- 31 vDVwcj] 2017¼ jk"Vªh; ,drk fnol½ 31 अक्टूबर, 2017 को सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। आकाशवाणी के महानिदेशक और इंजीनियर इन चीफ (आकाशवाणी) द्वारा फील्डन हॉल, पहली मंजिल, आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली में 11.00 बजे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में शपथ दिलाने का समारोह आयोजित किया गया।

fnO;kax tuksa ds fy, vkj{k.k

- 'दिव्यांग जनों व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1955' दिव्यांग जनों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी भागीदारी सुनिश्चित करने का एक प्रयास है।
- नवंबर 1977 में दिव्यांग जनों (पीडब्लूडी) के लिए आरक्षण समूह 'सी' और 'डीश' पदों में प्रत्यक्ष भर्ती के मामले में शुरू किया गया था और वर्ष 1989 में समूह 'सी' और 'डी' पद तक बढ़ा दिया गया था। पीडब्ल्यूडी अधिनियम लागू होने के साथ सीधी भर्ती के मामले में दिव्यांग जनों लिए आरक्षण चिन्हित समूह ए और बी पदों पर भी लागू किया गया था।
- प्रसार भारती ने दिव्यांग जनों के लिए आरक्षण के सभी आवश्यक उपाय किए हैं, समय–समय पर डीओपी एंड टी द्वारा जारी किए गए सभी प्रासंगिक नीतिगत निर्णय और निर्देशों का पालन किया जा रहा है।
- आकाशवाणी देशभर में अपने प्रसारण केंद्रों के माध्यम से दिव्यांग जनों के लिए कार्यक्रम प्रसारित करती है। इन कार्यक्रमों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिव्यांग जनों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के अलावा, कार्यक्रमों इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि ये न केवल सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के लाभ पाने में मदद करते हैं बल्कि दिव्यांग जनों को सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए भी प्रोत्साहित करते है। कार्यक्रम सामाजिक जागरुकता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और दिव्यांग जनों के प्रति समाज के कठोर रवैये को बदलने में भी उपयोगी हैं।
- रैंप बनाने, विशेष शौचालय, प्राथमिक रूप से भूमि तल पर बनाने की गतिविधियां आकाशवाणी के सीसीडब्लू 'छोटे–मोटे कार्यों के लिए बजट' से शुरू की जाती हैं।

dSV ds fu.kZ;@vkns'kksa dk dk;kZUo;u

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार वर्ष 2017–18 (1 अप्रैल, 2017 से 31 अक्टूबर, 2017) के लिए आकाशवाणी में कैट मामलों के निर्णय/आदेशों के कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी यहां दी गई है:

क्रम संख्या	अनुभाग/केंद्र/कार्यालय	1 अप्रैल, 2017 से 31 अक्टूबर, 2017 की अवधि के लिए कैट से प्राप्त आदेशों की संख्या	1 अप्रैल, 2017 से 31 अक्टूबर, 2017 की अवधि के लिए लागू किए गए कैट के निर्णयों/आदेशों की संख्या
1	Mh t h % vkdk'kok.kh ¼vuqHkkx@dsæ @dk;kZy;½	40	2

jktHkk"kk ¼fganh ;wfuV½

egkfuns'kd % vkdk'kok.kh ¼eq[;ky;½

महानिदेशक : आकाशवाणी (मुख्यालय) की हिंदी यूनिट राजभाषा नीति लागू करती है और विभिन्न आकाशवाणी स्टेशनों/कार्यालयों में वार्षिक कार्यक्रम में उल्लिखित लक्ष्य को लागू किया जाता है। अधिकारियों/

अधिकारियों को राजभाषा हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए :

1 vçy] 2017 l 31 vDVcj] 2017 rd vk;kftr fgnh fnol@fgnh i[kokM dh fjikV vkj vU; fof'k"V dk;l %

2017&18 e vk;kftr fgnh fnol@fgnh i[kokMk

14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मन. ाया जाता है। इस परंपरापरा का पालन करते हुए 'हिंदी दिवस' 14 सितंबर, 2017 को मनाया गया था और 15 सितंबर, 2017 से 26 सितंबर, 2017 तक महानिदेशक श्री एफ शहरयार के मार्गदर्शन/निर्देशों के तहत 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर भारत सरकार के गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और प्रसार भारती के संदेशों को पढ़ा गया।

हिंदी पखवाड़े के दौरान गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के अधिकारी/अधिकारियों के लिए अलग से हिंदी प्रतियोगिताओं सहित हिंदी में बारह प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

fgnh dk;'kkyk

इस साल दो हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं जिसमें हिंदी में आधिकारिक काम करते समय आने वाली समस्याओं के लिए समाधान प्रदान किए गए थे। 12 जुलाई, 2017 को 'ई–शासन' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें अधिकारियों को उनके आधिकारिक काम के लिए हिंदी का उपयोग करने के बारे में निर्देशित किया गया। 3 नवंबर, 2017 को 'मेरा लक्ष्य–भ्रष्टाचार मुक्त भारत' पर एक दूसरी कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें भ्रष्टाचार को खत्म करने के सुझावों और तरीकों के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिया गया।

vuyXud &1

vkdk'kok.kh vkj njn'ku d bthfu;fjx LVkQ d fy, çf'k{k.k xfrfof/k;k

अकादमी निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती हैः –

¼d½ Vhoh ikBîØe %

- स्टूडियो और न्यूजरूम ऑटोमेशन
- प्रोडक्शन और पोस्टप्रोडक्शन ख्स्टैंडर्ड डेफिनेशन टेलीविजन (एसडीटीवी) और हाई डेफिनिशन टेली. विजन (एचडीटीवी),
- ट्रांसमीटर (एनालॉग एंड डिजिटल)
- उपग्रह पृथ्वी केंद्र, डाइरेक्ट–टू–होम और डिजिटल सेटेलाइट न्यूज गैदरिंग (डीएसएनजी)

¼[k½ jfM;k ikBîØe %

- रेडियो स्टूडियो और न्यूजरूम ऑटोमेशन प्रणाली
- रेडियो प्रोडक्शन और पोस्टप्रोडक्शन
- रेडियो ट्रांसमीटर (एमई, एसडब्ल्यू, एफएम)
- डिजिटल रेडियो ट्रांसमीटर और प्रौद्योगिकी
- कैप्टिव अर्थ केंद्र और डीएसएनजी

¼x½ dI;Vj rduhd %

- कंप्यूटर नेटवर्किंग और सर्वर प्रशासन
- कंप्यूटर हार्डवेयर रखरखाव

¼?k½ çc/ku vkj ç'kklfud dk'ky fodkl ikBîØe

¼M½ ijh{kk iol çf'k{k.k

¼p½ Mhty tujVj

fu;fer ikBîØek d vfrfjä fo'k"k ikBîØe Hkh vk;kftr fd, tkr g %

- सोलर फोटोवोल्टिक पावर जनरेशनः डीआईडी/एडीई/एई की डिजाइन, स्थापना और चुनौतियां विषय पर पाठ्यक्रम चेन्नई में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) द्वारा 1 से 5 मई, 2017 तक 23 प्रतिभागियों के लिए आयोजित किया गया।
- 19 से 23 जून, 2017 को उत्तराखंड एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (यूएए), नैनीताल में आकाशवाणी/दूरदर्शन के वरिष्ठ अधिकारी के लिए 18 प्रतिभागियों के लिए कार्यकारी विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- मास्टर कंट्रोल सुविधा (एमसीएफ), हासन में 23 से 27 अक्टूबर, 2017 तक आकाशवाणी/दूरदर्शन के अधिकारियों के लिए सेटेलाइट कम्युनिकेशन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- 25 सितंबर, 2017 को नेशनल एकेडमी ऑफ

ब्रॉडकास्टिंग और मल्टीमीडिया (एनएबीएम), दिल्ली में आकाशवाणी और दूरदर्शन के डीडीजी/डीई/डीडीई के लिए 38 प्रतिभागियों के लिए भू–आकाशीय प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित की गई।

- लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और वस्तु और सेवा कर पर कार्यशाला एनएबीएम दिल्ली में 86 उम्मीदवारों के लिए 5 से 7 जून 2017 तक और 27 से 28 जुलाई, 2017 तक एनएबीएम भुवनेश्वर में 58 उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई थी।

ijh{kk lcaf/kh çf'k{k.k %

- एमटीएस के लिए पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण 5 से 7 जून, 2017 से एनएबीएम दिल्ली में 35 उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया गया था।

¼,½ bathfu;fjx Nk=k d fy, xh"edkyhu çf'k{k.k

- 'इंजीनियरिंग छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण' पर एक पाठ्यक्रम का आयोजन 12 जून से 21 जुलाई 2017 तक 37 उम्मीदवारों के लिए किया गया था।

U;w ehfM;k fox

1945 में स्थापित किए गए अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग का नाम बदलकर अब 'न्यू मीडिया विंग' कर दिया गया है। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए सूचना प्रदान करने वाली इकाई के तौर पर कार्य करता है। यह मंत्रालय के उपयोग के लिए इसकी मीडिया इकाइयों और जनसंचार से जुड़े अन्य लोगों को पृष्ठभूमि, संदर्भ और अनुसंधान सामग्री प्रदान करता है।

lxBukRed <kpk

न्यू मीडिया विंग का मुख्यालय नई दिल्ली में लोधी रोड स्थित सीजीओ कॉम्पलेक्स के सूचना भवन में है। महानिदेशक इसके प्रमुख हैं जिनकी सहायता के लिए एक निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक तथा अन्य सहयोगी स्टाफ है।

eq[; xfrfof/k;k

lks'ky ehfM;k

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का न्यू मीडिया विंग सरकार और आम जनता के बीच वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर सेतु का काम करता है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ब्लाग और गूगल प्लस जैसे वैश्विक पहुंच और सीधे संपर्क की क्षमताओं वाले प्लेटफार्मों के जरिए यह विंग आम लोगों तक पहुंचता है। न्यू मीडिया विंग ने पिछले 5 वर्षों में लोगों के साथ अपना संपर्क निरंतर मजबूत किया है।

टॉकाथोन और फेसबुक लाइव जैसी नई पहलों के जरिए सरकार और आम जनता के बीच वर्चुअल दुनिया में संपर्क एक नए स्तर तक जा पहुंचा है। इन कार्यक्रमों के जरिए मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आम जनता के साथ सीधे संपर्क का प्लेटफॉर्म विकसित हुआ है, इसके अलावा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने अनेक ऑनलाइन प्रतियोगिताएं शुरू की हैं जिनसे सरकार के कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी को बढ़ावा मिला है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ट्विटर हैंडिल @MIB_India के 9 लाख 31 हजार फॉलोअर है और इसकी पोस्टों से प्रतिमाह 60 लाख इंप्रेसन बनते हैं। पिछले दिनों, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हिंदी भाषी समुदाय के लिए हिंदी ट्विटर हैंडल @MIB_HINDI शुरू किया है। मंत्रालय के आधिकारिक फेसबुक पेज @inbministry के 13 लाख फॉलोअर हैं और प्रतिमाह इसकी औसत पहुंच 18 लाख लोगों तक है।

vçy 2017 ls U;w ehfM;k fox dh xfrfof/k;k

1- lkexh r;kj djuk

न्यू मीडिया विंग द्वारा की गई मुख्य पहल इस प्रकार है :

LoPN Hkkjr fe'ku

न्यू मीडिया विंग ने स्वच्छाथोन पुरस्कार समारोह के तुरंत प्रस्तुति की और ग्राफिक प्लेट पोस्ट करके और महत्वपूर्ण हैंडल रिट्विट करके इसका व्यापक प्रचार किया। स्वच्छाथोन से जुड़ी सभी सामग्री पोस्ट करने के लिए #SwachhtaHiSeva का इस्तेमाल किया गया।

इसके साथ ही, न्यू मीडिया विंग ने स्वच्छ भारत मिशन और इससे जुड़ी विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों, जैसे स्वच्छ भारत हैकाथोन, स्वच्छ सर्वेक्षण (ग्रामीण) के प्रारंभ, स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि प्रतियोगिताओं तथा स्वच्छ भारत मिशन की तीसरी वर्षगांठ पर आयोजित स्वच्छता ही सेवा अभियान को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित चित्र, प्रेस विज्ञप्तियां और वीडियो शेयर किए

गए। स्वच्छ भारत से जुड़ी सफलता की कहानियां ब्लाग पर अपलोड की गईं और मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर वीडियो चलाए गए।

fuokZpu vk;ksx ds fy, fo'ks"k dk;Z

पेयजल और स्वच्छता राज्यमंत्री श्री एस.एस अहलूवालिया और श्री रमेश चंडप्पा जिगाजिनागी नई दिल्ली में एक समारोह में स्वच्छाथोन पुरस्कार विजेताओं के साथ

निर्वाचन आयोग के स्वच्छाथोन अभियान के व्यापक प्रचार के लिए बनाया गया विशेष जीआईएफ

न्यू मीडिया विंग ने #EVM Challenge सहित विभिन्न अवसरों पर निर्वाचन आयोग के लिए प्रचार–प्रसार करने में अग्रणी भूमिका निभाई। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव ईवीएम चैलेंज तथा राज्यों के चुनावों से जुड़ी चुनाव आयोग की प्रेस वार्ताओं का सीधा प्रसारण किया गया और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर लाइव अपडेट जारी किए गए।

नई दिल्ली में 3 जून, 2017 को #इलेक्शन कमीशन #ईवीएम चैलेंज पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. नसीम जैदी की प्रेस वार्ता

th,lVh dh 0;kid dojst

न्यू मीडिया विंग ने जीएसटी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पर्याप्त प्रचार किया जिसमें मास्टर क्लासेज का फेसबुक और यूट्यूब पर सीधा प्रसारण शामिल है। सभी प्लेटफार्मों पर इंफोग्राफिक्स सहित 100 से ज्यादा पोस्ट जारी किए गए।

lks'ky ehfM;k laokn ¼Qslcqd ykbo@V,dFkkWu½& न्यू मीडिया विंग की सक्रिय और अनोखी पहल से सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जुड़ने का अवसर मिलता है। यह लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का एक संपूर्ण समन्वय है जिसमें ट्विटर और फेसबुक के जरिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं और विशेषज्ञ और अतिथियों के पैनल द्वारा तुरंत उत्तर दिए जा सकते हैं। यह गतिविधि यूट्यूब और फेसबुक पर भी उसी समय प्रस्तुत की जा सकती है। इस तरह यह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक विशेष अवसर है जिसमें लोग किसी मुद्दे/घटना अथवा प्रक्रिया से जुड़े मंत्रियों, नीति–निर्माताओं, लोकप्रिय हस्तियों, कलाकारों से सीधे प्रश्न कर सकते हैं और उनके विचार जान सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री श्री कलराज मिश्र और श्री राधामोहन सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने सोशल मीडिया विंग द्वारा आयोजित ऐसे संवादों में हिस्सेदारी की।

Hkkjr dk varjkZ"Vªh; fQYe lekjksg 2017

न्यू मीडिया विंग ने गोवा में भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय

फिल्म समारोह का सोशल मीडिया क्षेत्र में व्यापक प्रचार किया। न्यू मीडिया विंग ने समारोह के उद्घाटन तथा समापन कार्यक्रमों की लाइव ट्विटिंग और फोटो ट्विटिंग की तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किए। फेसबुक पर स्पेशल एलबम लोड किए गए तथा @IFFIGoa/ @pib_panjim,@pib_india और @HMIB जैसे हैंडलों पर रिट्विट भी किए गए। फिल्म समारोह के प्रमुख चित्र इंस्टाग्राम पर डाले गए, विशेष इंफोग्राफिक्स बनाए गए तथा ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर इन्हें शेयर किया गया। समारोह से जुड़ी प्रेस विज्ञप्तियां ब्लॉग पर अपलोड की गई और इसके साथ–साथ इन्हें ट्वीट भी किया गया।

,drk dk fy, nkSM+ ¼ju Q,j ;wfuVh½

31 अक्तूबर, 2017 को आयोजित रन फॉर यूनिटी के अवसर पर न्यू मीडिया विंग ने अनेक गतिविधियों में हिस्सा लिया। रन फॉर यूनिटी से जुड़ी सभी गतिविधियों के ट्विटर पर लाने के लिए विशेष हैशटैग, जैसे #RunForUnity, #RashtriyaEktaDiwas,#SardarVallabhbhaiPatel इस्तेमाल किए गए। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, ब्लॉग, गूगल प्लस और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रेस विज्ञप्तियां चित्र और वीडियो डाले गए। मंत्रालय के ट्विटर पेज पर भी रन फॉर यूनिटी से जुड़ी गतिविधियां डाली गईं। इस दौड़ को लोकप्रिय बनाने के लिए दूसरे ट्विटर हैंडलों जैसे @pmoindia, @narendramodi, @pib_india से रिट्वीट भी किए गए।

gLrf'kYi

न्यू मीडिया विंग ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिए व्यापक प्रचार किया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस से जुड़ी सभी ट्विटर गतिविधियों के लिए #NationalHandloomDay नाम से विशेष हैशटैग इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस से जुड़े विशेष वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए गए और ट्वीट

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर इंफोग्राफिक

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्तूबर, 2017) को नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पर झंडी दिखाकर एकता के लिए दौड़ का शुभारंभ करते हुए। केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह, युवा मामले और खेल मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

किए गए। गीत और नाटक प्रभाग द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में की गई गतिविधियों को ट्विटर और फेसबुक पर डाला गया। दूसरे एकाउंट से रिट्वीटिंग भी की गई। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस से जुड़े विशेष इंफोग्राफिक साझा किए गए।

l dYi l flf)

संकल्प से सिद्धि से जुड़ी सभी सामग्री ट्वीट करने के लिए विशेष हैशटैग #SankalpSeSiddhi इस्तेमाल किया गया। फोटो ट्वीटिंग, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने @pmoindia, @narendramodi, @smritiirani, @pib_india जैसे प्रमुख हैंडलों के जरिए रिट्वीट करने की गतिविधियां संपन्न की गई। गीत और नाटक प्रभाग के कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों के चित्रों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर साझा किया गया।

dæ ljdkj d rhu o"k

केंद्र सरकार के कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे होने पर अनेक पत्रकार सम्मेलन आयोजित किए गए और सभी प्लेटफॉर्मों पर चित्र, इंफोग्राफिक और अन्य संबंधित जानकारी पोस्ट की गई।

bQkxkfQDl@thvkb,Q

भारत सरकार के प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रमों के बारे में विशेष इंफोग्राफिक्स तैयार किए गए। इन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी मीडिया प्लेटफॉर्मों पर जारी किए गए। भारत सरकार की प्रमुख पहलों और संबंधित कार्यक्रमों के बारे में सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर स्पेशल जीआईएफ पोस्ट किए जाते हैं।

eknh QLV ¼efdx v,Q MoyIM bfM;k QLVhoy½

इस कार्यक्रम से संबंधित सामग्री को पोस्ट करने के लिए #ModiFest का इस्तेमाल किया गया। फेसबुक और यूट्यूब जैसे अन्य प्लेटफार्मों पर भी फोटो साझा किए गए।

lkekftd ehfM;k fo'yi"k.k

न्यू मीडिया विंग सरकार से जुड़े मुद्दों तथा घटनाक्रम पर विश्लेषण और विभिन्न रिपोर्टें प्रस्तुत करता है।

1. सोशल मीडिया विश्लेषण

   सभी प्रासंगिक और ट्रेंडिंग विषयों पर जनभावना विश्लेषण रिपोर्ट (सेंटिमेंट एनालाइसिस रिपोर्ट) तैयार की जाती है। इसके लिए मैल्टवाटर जैसे सोशल मीडिया टूल्स का इस्तेमाल होता है।

2. प्रमुख आयोजनों पर विशेष रिपोर्ट

   सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जुड़े प्रमुख आयोजनों के बारे में विशेष सोशल मीडिया रिपोर्ट तैयार की जाती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों की प्रतिक्रिया के आधार पर इन आयोजनों की पहुंच और प्रतिक्रिया का आकलन किया जाता है।

bfM;k&okf"kd lnHk xFk

न्यू मीडिया विंग 'इंडिया वार्षिक संदर्भ ग्रंथ' की सामग्री जुटाता है जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासन तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संस्थानों के घटनाक्रम और प्रगति के बारे में जानकारी समाहित होती है। इस ग्रंथ का भारत नाम से हिंदी में भी साथ–साथ प्रकाशन होता है। इंडिया रेफरेंस एनुअल–2018 की सामग्री संकलित कर दी गई है। इस ग्रंथ का डिजिटल संस्करण भी तैयार किया गया है।

ljdkjh dkedkt dh Hkk"kk d rkj ij jktHkk"kk fgnh dk bLreky

राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए तमाम दिशा–. निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए 'न्यू मीडिया विंग' में हिंदी के प्रगतिशील इस्तेमाल के लिए सभी जरूरी प्रयास किए गए। निदेशक की अध्यक्षता के अंतर्गत विंग में हिंदी समिति की तिमाही सभा आयोजित की गई। आधिकारिक कार्यों में हिंदी के इस्तेमाल का प्रसार करने के लिए हर तिमाही में हिंदी कार्यशाला भी आयोजीत की गई। सितंबर 14 से 28 तक हिंदी पखवाड़ा भी आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ।

lpuk dk vf/kdkj

डीओपीटी के निर्देशों के अनुसार आरटीआई एक्ट के अंतर्गत सूचना मांगने वाले लोगों के लिए एक सीपीआईओ और एक नोडल अधिकारी तथा एक अपीलीय प्राधिकरण की नियुक्ति की गई।

lnHk iLrdky;

प्रभाग के पुस्तकालय में विविध विषयों पर दस्तावेजों, चुनी हुई पत्रिकाओं तथा विभिन्न मंत्रालयों, समितियों और आयोगों की सजिल्द रिपोर्टों का विशाल संकलन

है। इस पुस्तकालय में पत्रकारिता, जनसंपर्क, विज्ञापन तथा दृश्य–श्रव्य मीडिया की पुस्तकें प्रमुख विश्वकोष तथा समकालीन लेखों के संग्रह रखे हुए हैं।

tulpkj ij jk"Vh; çy[ku dæ ¼,uMhlh,elh½

विभाग के एक हिस्से के रूप में मंत्रालय द्वारा गठित विशेष समिति की सिफारिश पर सन् 1976 में जन. संचार पर राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र का गठन किया गया। इसका कार्य इसकी पोरियोडिकल सर्विसेज के जरिए जनसंचार से जुड़े चलन और घटनाओं के बारे में सूचना का संकलन, विश्लेषण और प्रसार करना है।

lrdrk xfrfof/k;k

1- e[;ky; vkj {k=h; dk;ky;k e lxBu d fy, dh xbl lrdrk xfrfof/k;k dh tkudkjh

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं।

2- bl nkjku fuokjd lrdrk xfrfof/k;k

i. इस दौरान नियमित निरीक्षण किए गए।

ii. इस दौरान औचक निरीक्षण किए गए।

3- bl nkjku fuxjkuh vkj tkp xfrfof/k;k

i. fuxjkuh d fy, pu x, {k=k dk C;kjk & न्यू मीडिया विंग एक छोटा अधीनस्थ कार्यालय है और इनमें निगरानी के लिए सीमित गुंजाइश है।

ii. fuxjkuh e j[ku d fy, ik, x, 0;fä;k dh l[;k & कोई नहीं (3(i) को देखते हुए)

4- nMkRed xfrfof/k;k ¼4 ¼i½ l ¼x½ d vkx l[;k nh tk,] tgk fu;fä çkf/kdkjh jk"Vªifr d vykok dkbl vU; g½

i) इस दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या : शून्य

ii) मामलों की संख्या जिनमें प्रारंभिक जांच की गई : शून्य

iii) मामलों की संख्या जिनमें प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई : शून्य

iv) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें दंड के लिए आरोप पत्र जारी किए गए : शून्य

v) ऐसे मामले जिनमें मामूली दंड के लिए आरोप पत्र जारी किए गए थे : शून्य

vi) ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन पर भारी जुर्माना लगाया गया था : शून्य

vii) जिन पर मामूली जुर्माना लगाया गया था उन व्यक्तियों की संख्या : शून्य

viii) उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें निलंबन के अंतर्गत रखा गया : शून्य

ix) ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के तौर पर चेतावनी जारी करने जैसे कदम उठाए गए : शून्य

x) व्यक्तियों की संख्या जो नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत समय से पहले सेवानिवृत्त हुए : शून्य

çlkj.k bthfu;fjx dlYVVl bfM;k fyfeVM ¼chblhvkb,y½

1- cfly ¼chblhvkb,y½ dk lf{kIr bfrgkl

प्रसारण इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का ISO 9001:2008] ISO/IEC 20000: 2012] ISO 27001:2013] ISO 9001:2015 मान्यता प्राप्त मिनी रत्न, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। संप्रेषण और उत्पादन प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में प्रसारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए 24 मार्च, 1995 को इसकी स्थापना की गई। इसमें स्थलीय और उपग्रह प्रसारण के विशेष क्षेत्र, केबल और विभिन्न आईटी संबंधी क्षेत्र जिसमें ऑडियो–वीडियो सिस्टम भी शामिल हैं, में विशेषज्ञ समाधान देना भी शामिल है।

बेसिल भारत तथा अन्य देशों में सामग्री उत्पादन सुविधाओं, स्थलीय प्रसारण, ट्रांसमिशन और सैटेलाइट तथा केबल प्रसारण सहित रेडियो और टेलीविजन, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग के सभी क्षेत्रों में परामर्श सेवाओं तथा परियोजना के प्रारंभ से लेकर इसे संपन्न करने तक की सेवाएं प्रदान करता है। साथ ही, प्रशिक्षण तथा कामगर सुलभ कराने जैसी मानव संसाधन गतिविधियां भी संपन्न करता है। बेसिल ने अपने कार्यों का विस्तार किया है और रक्षा, पुलिस और विभिन्न अर्ध–सैनिक बलों के लिए विशिष्ट संचार, निगरानी और जांच कार्यों के लिए प्रणालियां उपलब्ध कराता है। बेसिल का मुख्यालय दिल्ली में, कॉर्पोरेट कार्यालय नोएडा तथा क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु में है।

बेसिल ने दक्ष और कुशल इंजीनियरों की एक टीम भी

तैयार की है और साथ ही प्रसारण उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से पेशेवरों का एक बड़ा समूह तैयार किया है, इसमें सार्वजनिक और निजी प्रसारक और प्रतिरक्षा व केबल उद्योग शामिल हैं। तकनीकी रूप से दक्ष इस नेटवर्क के जरिए, बेसिल ने उद्योग की जरूरतें पूरी करने के लिए अपनी अखिल भारतीय उपस्थिति दर्ज कराई है।

बेसिल के पास विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह है, यह आकाशवाणी और दूरदर्शन एकीकृत करता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है, जो एक अरब लोगों तक पहुंचता है और दुनिया का सबसे बड़ा उपग्रह टेलीविजन नेटवर्क है, जिसे भारत और विदेशों में लाखों टीवी सेट्स तक पहुंचने के लिए एनालॉग और डिजिटल सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस दी जाती है।

2- y{;

स्थलीय, केबल और उपग्रह प्रसारण के माध्यम से भारत तथा विदेशों में रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के विकास तथा आधुनिकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाना और उत्कृष्टता हासिल करना।

3- fotu

भारत और संबद्ध एशियाई क्षेत्र में प्रसारण सेवाओं का विकास। प्रसारण इंजीनियरी और सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में विश्व–स्तरीय परामर्श सेवाएं तथा परियोजनाओं के प्रारंभ से लेकर संपन्न होने तक की सेवाएं प्रदान करना।

4- mís';

1) ग्राहकों की एक व्यापक श्रेणी को विशेष और अनुकूलित समाधान प्रदान करके बाजार में मौजूद हिस्सेदारी बढ़ाना।
2) प्रसारण से जुड़ी नीति के निर्माण और नियमन के लिए विभिन्न दस्तावेज तैयार करने में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को तकनीकी सेवा उपलब्ध कराना।
3) विदेशी बाजार में मौकों की तलाश।
4) उत्पाद विकास के लिए बाजार शोध करना।
5) टीवी चैनलों और दूरस्थ शिक्षा केंद्रों के लिए सैटेलाइट अपलिंक और डाउनलिंक प्रणाली तैयार करना।
6) प्रसारण केंद्रों की स्थापना और रखरखाव।
7) प्रसारण पेशेवरों को प्रशिक्षण देना।
8) विशेष प्रसारण उपकरणों का विकास, निर्माण और डिजाइन करना।

5- bl o"kZ iwjh dh xbZ çeq[k ifj;kstuk,a

- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र (ईएमएमसी)
- भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)
- प्रकाशन विभाग (डीपीडी)
- भारतीय विमानपत्त प्राधिकरण (एएआई)
- छत्तीसगढ़ स्टेट बीवरजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएसबीसीएल)
- प्रसारण स्कंध का स्वचलितीकरण (सूचना और प्रसारण मंत्रालय)
- सीडीएसी (मोरक्को, पापुआ न्यू गिनी और वानूआतू के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेंडर)
- सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय (एमओआ. रटीएच) – सोशल मीडिया
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय–सोशल मीडिया
- पत्र सूचना कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- ईस्टर्न रेलवेज
- सोशल मीडिया–कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), ईएसआईसी, श्रम तथा रोजगार मत्रालय, भारत निर्वाचन आयोग
- ऑडियो वीडियो एएमसी – राष्ट्रीय मीडिया केंद्र (एनएमसी)
- राजस्थान इंफोकॉम सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल)
- डब्ल्यूडीआरए (सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लाबिंग, आईटी)
- सामुदायिक रेडियो केंद्र–15 स्थानों पर संपूर्ण स्थापना
- विश्वभारती, शांतिनिकेतन (पश्चिम बंगाल) में स्टूडियो का निर्माण
- लोकसभा टीवी तथा उत्कर्ष सोसाइटी, पंजाब की अपलिंक प्रणालियों का रख–रखाव
- सत्यजित राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान,

कोलकाता में स्टूडियो निर्माण

- डीपीआर, रायपुर (छत्तीसगढ़) के लिए टेलीविजन चैनल मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार करना
- दूरदर्शन डीटीएच के लिए सेट टॉप बॉक्स बनाना

6- cfly & çc/ku o lxBu

निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामांकित एक अध्यक्ष और एक प्रबंध निदेशक, एक पूर्णकालिक निदेशक (कार्य प्रणाली व विपणन), दो निदेशक और एक स्वतंत्र गैर–सरकारी निदेशक शामिल होता है। निदेशक स्तर से नीचे महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, प्रबंधक, उप प्रबंधक और सहायक प्रबंधक और कनिष्ठ प्रबंधक शामिल हैं। परियोजना का काम कंपनी द्वारा अनुबंध के आधार पर काम पर रखे गए सलाहकारों और परियोजना प्रबंधकों को सौंपा जाता है।

इस समय निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य हैं :

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक –श्री जॉर्ज कुरुविला

पूर्णकालिक निदेशक –श्री डी.आर. गोगोई

सरकार द्वारा नामित निदेशक –सुश्री अंजू निगम, संयुक्त सचिव और श्री रोहित कुमार परमार, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

गैर–सरकारी निदेशक –सुश्री रंजना उपाध्याय

7- 0;olkf;d xfrfof/k;k

- रेडियो प्रसारण
- टीवी चैनल, स्टूडियो, मीडिया सेंटर आदि स्थापित करना
- टेलीपोर्ट्स, डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) प्रणाली और केबल हेड एंड्स प्रणालियों का संस्थापन
- सैटेलाइट के जरिये दूरस्थ शिक्षा प्रणाली
- सामुदायिक रेडियो स्टेशन की एसआईटीसी प्रणाली
- ध्वनि, स्टेज प्रकाश, ध्वनि सुदृढ़ीकरण प्रणाली में विशेषज्ञता
- सोशल मीडिया, ई–गवर्नेंस, सूचना टैक्नोलॉजी (आईटी) तथा सूचना संचार टैक्नोलॉजी (आईसीटी) परियोजनाएं
- ऑनलाइन परीक्षाएं और प्रशिक्षण
- लॉगर, सेट टॉप बॉक्स जैसे प्रसारण संबंधित उपकरणों का निर्माण
- मैन पॉवर आउटसोर्सिंग

8- foÙkh; foo.k

साल 2015–16 के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन आगे दिया गया है:

(लाख ₹ में)

	विवरण	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
		2016-17	2015-16
(क)	**कार्य–कलापों के परिणाम**		
	कार्य–कलापों से आय	18449.85	3142.26
	जमा कार्य का मूल्य	4349.13	2717.20
	वर्ष के दौरान कुल व्यवसाय	22798.98	5859.46
	व्यय (जमा काम सहित)	22153.68	6199.64
	परिचालन (लाभ/घाटा)	645.30	(340.18)
	वित्तीय लागत	64.86	440.89
	अवमूल्यन और परिशोधन	239.39	191.23
	संदिग्ध प्राप्तियों और अग्रिम अनुमान	-	-
	पूर्व अवधि समायोजन और असाधारण आइटम	4.95	(7.17)
	लाभ/(हानि)–कर खर्च से पहले	336.09	(965.13)
	स्थगित कर	131.85	(342.99)
	लाभ/(हानि)–कर खर्च के बाद	204.25	(622.14)
	निगमित सामाजिक दायित्व के लिए स्थानांतरण	4.08	-
	आय/(हानि)–प्रति शेयर (₹ में)	150.00	(456.00)

(ख)	**कोष के स्रोत**		
	इशूड, सब्सक्राइब्ड और चुकता पूंजी रिजर्व तथा अधिवेशन	136.50	136.50
	रिजर्व और अधिशेष	1532.10	1401.37
	गैर–वर्तमान देनदारियां	643.81	554.98
	वर्तमान देनदारियां	21412.89	14063.73
	कुल	23725.29	16156.58
	कोष का इस्तेमाल		
	अचल सम्पत्ति	1257.07	1288.19
	वर्तमान संपत्ति	21785.95	14066.68
	स्थगित कर परिसंपत्ति (नेट)	667.18	799.03
	दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम	-	2.68
	अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	15.09	-
	कुल	**23725.29**	**16156.58**
(ग)	**अन्य जानकारी**		
	अधिकृत पूंजी	**250.00**	**250.00**
	नियोजित पूंजी	1668.59	1537.87
	कुल मूल्य	**1001.42**	**738.84**

'kq;j iwath

बीईसीआईएल को रु. 250 लाख की आधिकारिक पूंजी दी गई थी। 1995–96 के लिए प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 25 लाख रुपये से बढ़कर रु. 136.5 लाख हो गई है। केंद्र सरकार के पास 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी है। बीईसीआईएल को सरकार से बजट सहयोग नहीं मिलता है।

çeq[k miyfC/k;ka

- विभिन्न कार्यकलापों (डिपोजिट कार्यों सहित) से रा. जस्व रु. 228 करोड़ हो गया जबकि पिछले वर्ष यह रु. 59 करोड़ था। इस तरह राजस्व में 286 प्रतिशत वृद्धि दर रही।
- पिछले वर्ष की रु. 9.65 करोड़ की हानि की तुलना में कर–पूर्व लाभ रु. 3.36 करोड़ रहा। पिछले वर्ष की रु. 6.22 करोड़ शुद्ध हानि की तुलना में रु. 2.04 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ।
- स्थापना के बाद से अब तक, इस वर्ष सबसे ज्यादा राशि का कारोबार हुआ।
- इस वर्ष मैनपॉवर गतिविधियों में सर्वाधिक कारोबार हुआ।
- पिछले पांच वर्षों की तुलना में सबसे ज्यादा लाभ हुआ

9- o"kZ ds nkSjku çeq[k igy rFkk 0;kikj xfrfof/k;ka

समीक्षाधीन वर्ष में, बेसिल ने निम्न प्रमुख परियोजनाओं पर कार्य किया:

एफएम के तीसरे चरण के दूसरे बैच की नीलामी में 48 शहरों में 66 चौनल आबंटित हुए।

उन शहरों में जहां दूसरे चरण अथवा तीसरे चरण के पहले बैच का कोई खाली चौनल है और कोई अतिरिक्त चौनल प्रस्तावित है और सीआईटी (कॉमन ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रकचर) बेसिल ने तैयार किया हो, वहां सीआईटी का उन्नयन बेसिल द्वारा ही किया जाएगा। साथ ही, स्थल पर एफएम चौनल की को–लोकेशन अनिवार्य कर दिया गया है।

एफएम तीसरे चरण के अंतर्गत लेह (जम्मू–कश्मीर की नीलामी के बाद सफल एलओआई–धारकों ने बेसिल से सिस्टम इंटेग्रेटर बनने तथा सीआईटी तैयार करने के लिए संपर्क किया। इसके अंतर्गत सीटीआई बनाना, स्थापित करना और प्रसारण शुरू करवाना शामिल है। लेकिन इन एलओआई–धारकों ने अब तक परियोजना प्रबंध समझौता (पीएमए) सभी कार्य–स्थलों पर कार्य संपन्न किया जा रहा है।

एफएम तृतीय चरण (बैच II) के अंतर्गत प्रसारकों की सूची इस प्रकार है :

1) साउथ एशिया एफएम लिमिटेड
2) पूर्वी ब्रॉडकास्ट (पी) लिमिटेड

3) इंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड

4) संभव मीडिया लिमिटेड

5) कल रेडियो लिमिटेड

6) जेसीएल इंफ्रा लिमिटेड

7) उषोदय इंटरप्राइजेज (पी) लिमिटेड

fuxjkuh vfHkxe fue=.k çc/ku ç.kkyh ¼lo'ykl ,Dlsl eusteaV flLVe ¼,l,lh,e,l½

यह परियोजना पूर्ण रूप से कार्यरत परिचालन निगरानी एवं प्रवेश नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली के डिजाइन, खरीद, स्थापना, एकीकरण, परीक्षण एवं शुरूआत और संबद्ध सेवाओं के बारे में हैं जो कि ग्राहकों की जरूरतों और उन कोड्स पर आधारित है, जो दो मुख्य इमारतों और उससे जुड़े क्षेत्रों को केंद्रीय सुरक्षा प्रबंधन, एकीकृत नियंत्रण और दूरस्थ निगरानी उपलब्ध कराते हैं। इसमें भारत सरकार की सभी मौजूदा सुविधाएं भी शामिल हैं। एसएसीएमएस सख्त नियमन और राज्य के अत्याधुनिक सुरक्षा प्रौद्योगिकी के अनुकूल ढालने, विश्वसनीयता के उच्चतम स्तर पर पालन करने और इस तरह के इंटरनेट, इंटरनेट, लैन/वैन के रूप में नेटवर्किंग ढांचे को एकीकृत करेगा। एसएसीएमएस के अंतर्गत सभी इंटरफेस कॉरपोरेट इंट्रानेट/इंटरनेट/लैन/वैन टीसीपी से आईपी नेटवर्क प्रोटोकॉल कनेक्टिविटी पर आधारित होंगे। बेसिल इन परियोजनाओं को चिरकालीन सहयोग देती है और इसके उपभोक्ता को लगातार इसके इस्तेमाल और रखरखाव में मदद करती है।

lqjf{kr MkVk VkslQj usVodZ ifj;kstuk ¼,lMhVh,u½

देश के एक प्रमुख सरकारी संगठन ने बेसिल को कंप्यूटर डेटा नेटवर्क बनाने की एक परियोजना सौंपी। यह एक जटिल परियोजना थी, जिसमें बीस आउटस्टेशनों को जोड़कर सुरक्षित डाटा नेटवर्क प्रणाली कायम करनी थी। इसके बाद यह परियोजना पूरी की गई और अब इसने काम करना शुरू कर दिया है।

Hkkjr ljdkj ds lwpuk ,oa çlkj.k ea=ky; dh çlkj.k foax ds vkWVkses'ku ds fy, oscikWVZy dk fMtkbu] fodkl vkSj j[kj[kko

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रसारण विंग के ऑटोमेशन के लिए वेबपोर्टल का डिजाइन, विकास और रखरखाव का कार्य किया जा रहा है।

bZ,e,elh & Qsl& nks ifj;kstuk

i. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) के लिए सिविल, इंटीरियर, आईटी नेटवर्किंग और एमईपी कार्य नई दिल्ली के सूचना भवन की 11वीं मंजिल पर किया जाना।

ii. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर में आपूर्ति, स्थ. ापना, वीडियो वॉल सिस्टम लगाने का कार्य नई दिल्ली के सूचना भवन की दसवीं मंजिल पर किया जाना।

iii. नई दिल्ली के सूचना भवन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर में 600 टीवी चैनलों की आरएफ डाउनलिंक प्रणाली व्यवस्था के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध।

Hkkjr ljdkj ds lwpuk ,oa çlkj.k ea=ky; ds çdk'ku foHkkx funs'kky; esa lwph çca/ku vkSj vU; O;kikj çfØ;kvksa dk dEI;wVjhdj.k

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग निदेशालय में सूची प्रबंधन और अन्य व्यापार प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है।

Vªkb ds fu;e o ekudksa ds vk/kkj ij fMftVy ,Mªsl cy flLVe ¼lh,,l] ,l,e,l ,oa ,lVhch½ dk vkWfMV

ट्राइ के नियम व मानकों की अनुसूची–1 के अनुसार डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (सीएएस, एसएमएस एवं एसटीबी) का ऑडिट करना। ऑडिट में ट्राइ के नियम व मानकों की अनुसूची–1 के अनुसार ग्राहक को डीएएस व्यवस्था प्राप्त करने के लिए सलाह और परामर्श देना भी शामिल है। जरूरत के अनुसार सभी ऑडिट कर लिए गए हैं।

ekuuh; VhMhlsV ds funs'kkuqlkj vkWfMV

माननीय टीडीसैट के निर्देशानुसार ऑडिट का दायरा क्या हो, यह विभिन्न मामलों पर दिए गए निर्देशों पर निर्भर करता है। यह व्यवसायिक और तकनीकी दोनों तरह का ऑडिट भी हो सकता है।

fe'ku fMftVhdj.k ifj;kstuk

केबल टीवी डिजिटाइजेशन के फेस–3 और फेस–4 का

क्रियान्वयन। कार्य का विस्तार देश भर में 12 क्षेत्रीय इकाइयां स्थापित करना, इन क्षेत्रीय इकाइयों पर सं. विदात्मक कर्मचारियों (पीडी, एपीडी, ओए और डीईओ) की भर्ती, बहुभाषीय कॉल सेंटरों की स्थापना, एसटीबी की निगरानी के लिए एमआईएस एप्लीकेशन का विकास, केबल टीवी डिजिटाइजेशन के सभी हितधारकों को सभी जरूरी सूचनाएं और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक वेबसाइट का विकास। फेस–3 का कार्य पूरा कर लिया गया और सभी गतिविधियां भी पूरी की गईं। फेस–4 का कार्य प्रगति पर है।

çf'k{k.k rFkk vU; xfrfof/k;k

बेसिल ने देशभर में एवी इंस्टालेशन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए इंफोकॉम इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है।

lkeqnkf;d jsfM;ks LVs'ku ds fy, VkalehVj ,aVhuk ¼lhvkj,l 50½ vkSj Vw cs oh,p,Q ,aVhuk dk fuekZ.k

बेसिल के पास बंगलुरु में एफएम ट्रांसमीटर एंटीना (सीआरएस 50) और टू बे वीएचएफ एंटीना का निर्माण करने के लिए पर्याप्त सेटअप है। इसे बेसिल द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। बेसिल ने समीक्षाधीन वित्त वर्ष के लिए लगभग 25 ट्रांसमीटर और 18 एंटीना तैयार किए हैं।

9- Hkkoh 0;kikj xfrfof/k;k

बेसिल की व्यापार संभावनाएं निम्नलिखित हैं:

1. समग्र टेलीविजन बाजार में प्रगति संभावित है:

- पे–टीवी का दायरा बढ़ने से टेलीविजन उद्योग में प्रगति होगी।
- केबल डिजिटाइजेशन के क्रियान्वयन के साथ पे–टीवी एआरपीयू में भी बढ़ोतरी होगी।
- फेस–3 के जरिये निजी एफएम प्रसारण का विस्तार रेडियो क्षेत्र में भी गतिविधियों को बढ़ाएगा।
- टीवी कवरेज और कर्नाटक विधानमंडलों की कार्यवाही का प्रसार।
- वार्ता भवन, बंगलुरु में मीडिया केंद्र की स्थापना।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, चेन्नई में बोर्ड रूम की स्थापना के लिए ध्वनिकी, ए वी और वीडियो सम्मेलन सिस्टम उपलब्ध कराना।
- पॉडिचेरी के 'जिपमेर' चिकित्सा संस्थान के लिए मल्टीमीडिया सेटअप लगाने और टेलीमेडिसिन सुविधा देना।
- अहिल्या आई फाउंडेशन, पलक्कड़ में सभागार के लिए ध्वनिक व्यवस्था, पेशेवर ध्वनि सुदृढीकरण और संबद्ध सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- आधुनिक कला, बंगलुरु की नेशनल गैलरी ऑफ मॉर्डन आर्ट में ऑडियो–वीडियो, चरण ड्रेपरी और प्रकाश व्यवस्था का उन्नयन।
- बंगलुरु में निमहांस संग्रहालय के लिए ऑडियो और वीडियो सुविधाओं का उन्नयन।
- इरोड के आईआईएम के कोंगु इंजीनियरिंग कॉलेज इरोड में कन्वेंशन सेंटर का नवीनीकरण।
- बंगलुरु के आर.एल. जलप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेंटर।
- औरंगाबाद के डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के लिए टीवी स्टूडियो एवं मल्टीमीडिया सेटअप।

2. बेसिल के प्रबंधन ने विभिन्न व्यापार के अवसरों में वृद्धि और विस्तार के लिए कार्यक्षेत्रों में बदलाव किया है और निम्न क्षेत्रों में काम करने की योजना बनाई है:

dk;Z u, {ks=

- नए व्यापारिक क्षेत्रों को अपनाना
- सेवाओं, उत्पादों और क्षेत्रों में विविधता लाना
- सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के लिए साइबर सुरक्षा
- ब्रॉडकास्ट टावर निर्माण
- प्रसारण क्षेत्र में डिजिटाइजेशन
- ई–एजुकेशन क्लासरूम्स की मांग
- सेट टॉप बॉक्सों का उत्पादन

[kqys ljdkj dh ubZ uhfr;ksa ds lkFk ubZ 'kq:vkr

- डिजिटल इंडिया पहल: केंद्रीय और राज्य सरकारों की ई–गवर्नेंस योजना, पेमेंट गेटवे के साथ

ऑनलाइन वेब पोर्टल।

- मेक इन इंडिया पहलः नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (एनवीआर) और सीसीटीवी व सर्वेलांस प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए तकनीकी कंपनियों से साझेदारी।
- स्किल इंडिया पहलः केबल डिजिटाइजेशन, सीसीटीवी सर्विलांस, स्मार्ट सिटी, एफएम रेडियो परियोजनाओं इत्यादि क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्युनिकेशन के आईआईटी तथा डिप्लोमा विद्यार्थियों का प्रशिक्षण। बेसिल कौशल क्षेत्र परिषद, आईएएससी के संचालक सदस्यों में है।

3. रचनात्मक मीडिया एवं फिल्म निर्माण

बेसिल ने रेडियो, टेलीविजन, कम्यूनिकेशन, सैटेलाइट और केबल प्रसारण के क्षेत्र में सफलतापूर्वक विभिन्न योजनाओं को पूरा किया है और खुद को श्रेष्ठ सेवा प्रदाता साबित किया है। अब बेसिल अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए नए रास्ते तलाश रही है ताकि नए अवसरों का अधिकतम लाभ लिया जा सके।

बेसिल ने रचनात्मक मीडिया एवं फिल्म निर्माण को एक अहम कदम के तौर पर आगे बढ़ाया है। इसका उद्देश्य ब्रांड और पहचान बनाने के लिए संस्थाओं और संगठनों की रचनात्मक मांगों को पूरा करना है।

इस व्यवसाय क्षेत्र में निम्नलिखित गतिविधियां की जाएंगीः

- समाचार एवं जीईसी श्रेणी में विभिन्न टीवी चैनलों के लिए ऑन एयर प्रमोशन और प्रसारणकर्ताओं के लिए उच्च श्रेणी के विज्ञापन तैयार करना।
- कंपनियों के लोगो तैयार करना और ब्रांडिंग करना।
- कॉरपोरेट एवी, वीएफएक्स और विभिन्न विज्ञापन समाधान।
- दूरदर्शन के लिए टेंडर निकालना (रचनात्मक संस्था के लिए)।
- शिक्षाप्रद फिल्में बनाने के लिए एनआईओएस के साथ मिलकर काम करना।
- व्यावसायिक फिल्मों और आयोजनों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संपर्क करना।
- अवधारणा के साथ–साथ प्रचार सामग्री प्रदान करने के लिए राज्य पर्यटन विभागों से संपर्क करना।

10- lpuk ,o çlkj.k e=ky; d lkFk ,evk;

बेसिल ने वित्त वर्ष 2017–18 के लिए सूचना व प्रसारण मंत्रालय के साथ बेसिल से जुड़े लक्ष्य तय करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

11- vuqlwfpr tkfr@vuqlwfpr tutkfr@vU; fiNMk oxZ@vYila[;d dk vH;fFk;ksa dh fu;qfä

कंपनी आरक्षण की नीतियों पर सरकार के दिशा–निर्देश/निर्देशों का पालन करती है। इसी के आधार पर कंपनी में अल्पसंख्यकों की भर्ती और पदोन्नति करने के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में आरक्षण के संदर्भ में सरकार के नीति–. निर्देशों का ध्यान रखा जाता है।

इन श्रेणियों के लिए तय किए गए आरक्षण कोटे के समुचित प्रक्षेपण के लिए नियम और निर्देशों के अनुसार कार्यसूची बनाई जाती है। आरक्षण नीतियों के क्रियान्वयन के बारे में आवधिक रिपोर्ट/रिटर्न भी भेजी जाती है।

12- lpuk dk vf/kdkj

पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और इनका प्रसार करने के लिए किसी भी तरह से प्राप्त सवालों और शंकाओं का समाधान समय रहते किया गया और उचित कदम भी उठाए गए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए सेंट्रल पब्लिक इंफोर्मेशन ऑफिसर (सीपीआईओ) नियुक्त किया गया और सूचना के समय पर अनुपालन और प्रसार के लिए अत्यंत सावधानी बरती जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान कंपनी ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 74 आवेदन प्राप्त किए और सभी पर तय समय–सीमा के अंतर्गत प्रतिक्रिया भी दी गई।

13- fgnh dk fujrj mi;kx

राजभाषा रिपोर्ट के विभिन्न हिस्सों में की गई सिफारिशों पर बेसिल द्वारा किए गए अनुपालन की जरूरी कार्रवाई/अद्यतन स्थिति सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रस्तुत की गई। 21 सितंबर, 2017 से 29 सितंबर, 2017 तक बेसिल में हिंदी पखवाड़े का आयोजन भी किया गया था। इस पखवाड़े के दौरान राजभाषा नीति ज्ञान, हिंदी निबंध और वादविवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शब्दकोष और तकनीकी शब्दावलियों जैसी जरूरी

मदद सामग्री भी अधिकारियों व कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई ताकि उन्हें दफ्तर के कामकाज में हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

14- lrdZrk xfrfof/k;k

बेसिल में सतर्कता विभाग निवारक सतर्कता के सभी पहलुओं को मजबूत करने और बेसिल में अनुपालन के लिए नियमित रूप से केंद्रीय सतर्कता आयोग, सार्वजनिक उद्यम विभाग और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिशा–. निर्देशों के आधार पर नीति–निर्देश और मानदंड जारी कर रहा है। आवधिक रिपोर्ट नियमित रूप से केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रस्तुत की जा रही हैं और समय–समय पर औचक निरीक्षण और नियमित निगरानी के अलावा उचित जांच भी की जा रही है।

15- lkekU;

कंपनी को सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई बजटीय सहायता नहीं मिली है। खुले बाजार में प्रतियोगी टेंडर प्रणाली के जरिये सुरक्षित किए गए रोजगार और परामर्श कार्य संबंधी खर्च और प्राप्तियों के आंतरिक प्रक्षेपण से बेसिल ने अपना बजट तैयार किया है। कंपनी को महिलाओं, उत्तर–पूर्व, रोजगार देने वाली, ग्रामीण अंग, जनजातीय उपयोजना, विशेष योजना, स्वयंसेवा समूह, सूचना एवं प्रसार, अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित किसी भी केंद्र प्रायोजित योजना से नहीं जोड़ा गया है।

byDVª,fud ehfM;k fuxjkuh dsæ

टेलीविजन चैनल संचार क्षेत्र में एक अहम भूमिका अदा करते हैं और उनकी पहुंच बहुत विस्तृत और अद्भुत है। टेलीविजन कार्यक्रम विभिन्न उम्र, संस्कृति और पृष्ठभूमि के लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और इसलिए इसमें विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ी सामग्री शामिल होती हैं। उपभोक्ताओं को टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित की जाने वाली अवांछनीय सामग्री से बचाने के लिए एक आदर्श संहिता पालन दुनिया के प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में किया जाता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) को टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित की जाने वाली सामग्री की निगरानी का कार्य सौंपा गया है। इसमें यह देखना भी शामिल है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेगुलेशन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का उल्लंघन न हो। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत सबसे नई मीडिया ईकाई ईएमएमसी के पास निगरानी, रिकॉर्ड और प्रसारण सामग्री के विश्लेषण के लिए उन्नत तकनीकों का अग्रणी तंत्र है।

टेलीविजन पर अश्लील भद्दे रियलिटी शो, समाचार कार्यक्रमों, वृत्तचित्रों तथा धारावाहिक कथा–चित्रों के प्रसारण की शिकायतों को देखते हुए ऐसे प्रसारणों की निगरानी की जरूरत महसूस की गई। साथ ही, घर पर टेलीविजन प्रसारणों से बच्चों के संवेदनशील मनों पर हिंसा, भद्देपन और अश्लीलता का असर पड़ता है। सीसीटीवी और मोबाइल पर रिकॉर्ड वास्तविक हिंसा की ऐसी घटनाएं भी समाचार चौनलों पर दिखा दी जाती है जो बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी विचलित कर सकती है। कभी–कभी तो ऐसे दुर्व्यवहार से प्रभावित महिलाओं–बच्चों की पहचान भी प्रसारण के दौरान उजागर कर दी जाती है और ऐसे प्रसारणों पर पड़ने वाला सदमा चिंता की बात है।

इसी तरह, विज्ञापन भी भारतीय टेलीविजन उद्योग की प्रमुख विषय–वस्तु हैं। ये विज्ञापन झूठी, गुमराह करने वाली जानकारी देकर तथा तंबाकू, शराब आदि स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद वस्तुओं को प्रचारित कर ऐसी चीजों की खरीद के लिए उकसाते हैं। भारत सरकार ने समुचित कानून, आदेश और निर्देशों के जरिए ऐसे विज्ञापनों पर नियंत्रण रखने के लगातार प्रयास किए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय हमेशा इस बात के प्रति आगाह करता रहा है कि ऐसे विज्ञापन विभिन्न उत्पादों के ऐसे करिश्माई दावों से गुमराह न करें जो पुष्ट नहीं किए जा सकते हों। केबल टेलीविजन नेटर्वक अधिनियम, 1995 के नियम 7(5) के अंतर्गत ऐसे मामलों में जरूरी रोक लगाई जाती है।

- ईएमएमसी के पास भारत में चल रहे 900 चैनलों की सामग्री को रिकॉर्ड करने और उस पर निगरानी रखने की तकनीकी क्षमता है, ताकि केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेगुलेशन) एक्ट 1995 के अंतर्गत किसी भी तरह के मानकों के उल्लंघन की जांच की जा सके। फिलहाल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मंजूरी से चल रहे सभी चौनलों की निगरानी ईएमएमसी द्वारा की जाती है। केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेगुलेशन) अधिनियम, 1995 में विभिन्न मानक शामिल हैं, जिनका प्रत्येक प्रसारण इकाई द्वारा पालन किया जाना जरूरी है। ईएमएमसी

उल्लंघन किए गए मानकों की रिपोर्ट रिकॉर्ड की गई क्लिप्स के साथ जांच समिति के सामने रखता है, जो कि उल्लंघन का विश्लेषण करती हैं और आगे की कार्यवाही के लिए अंतर–मंत्रालय समितियों और अन्य निकायों को भेजती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर लोक महत्व के प्रमुख मामलों की जांच भी करता है और उन्हें आकलन और उचित कार्रवाई के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजता है।

- ईएमएमसी सरकार के निर्देश पर विशेष रिपोर्ट भी तैयार करता है और मंत्रालय को भेजता है, मंत्रालय के निर्देश मिलने पर, ईएमएमसी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के प्रसारणों पर भी निगरानी रखता है।

lkekftd&lkaL—frd xfrfof/k;k¡

ईएमएमसी ने अप्रैल से नवंबर 2017 के दौरान विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। इसमें हिंदी पखवाड़े के दौरान रचनात्मक लेखन, क्विज, भाषण प्रतियोगिता आयोजित करना इत्यादि शामिल हैं। गैर–हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए भी प्रतियोगिता आयोजित की गई। ईएमएमसी के सभी स्टाफ सदस्यों ने सभी आयोजनों में उत्साह से भाग लिया।

माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, श्री मनोहर पर्रिकर आईएफएफआई–2017 के समापन समारोह में प्रख्यात अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन एवं अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ

6 fQYe {k= dh xfrfof/k;k

fQYe iHkkx

फिल्म प्रभाग पिछले 67 वर्षों से भारतीय जनता को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में हिस्सेदारी के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रभाग के लक्ष्यों और उद्देश्यों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लोगों को शिक्षित और प्रेरित करना तथा भारतीय एवं विदेशी दर्शकों के समक्ष देश की छवि और धरोहर को प्रस्तुत करना शामिल है। फिल्म प्रभाग सिनेमा थिएटरों और गैर–थिएटर सर्किटों जैसे क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की इकाइयों, दूरदर्शन, शैक्षिक संस्थानों, फिल्म समितियों और स्वयंसेवी संगठनों की जरूरतें पूरी करने के लिए वृत्त चित्र, लघु और एनिमेशन फिल्मों का निर्माण करता है। प्रभाग परिसर में भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय (एनएमआईसी) एक नए अनुभाग के रूप में शामिल किया गया है। इस संग्रहालय में प्रदर्शन दीर्घाओं का निर्माण और स्थापना का कार्य क्रमशः एनबीसीसी और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम) द्वारा लगभग पूरा किया जा चुका है।

पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वैंकेया नायडू एनएमआईसी, फिल्म प्रभाग के दौरे पर

fQYe iHkkx d fofHkUu Ld/k

प्रभाग को चार समूहों में विभाजित किया गया है :–

(1) निर्माण, (2) वितरण, (3) अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्र, लघु एवं एनिमेशन फिल्म समारोह और (4) प्रशासन।

¼1½ fuekZ.k Ld/k ½

निर्माण स्कंध फिल्मों (वृत्त चित्र, ग्रामीण दर्शकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई लघु फीचर फिल्में, एनिमेशन और वीडियो फिल्में) के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। इसका मुख्यालय मुम्बई में है और तीन अन्य निर्माण केंद्र बेंगलुरू, कोलकाता और नई दिल्ली में हैं।

¼2½ forj.k Ld/k ½

वितरण स्कंध के 7 शाखा कार्यालय बेंगलुरू, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुम्बई, तिरूवनंतपुरम और विजयवाड़ा में स्थित हैं। यह स्कंध सिनेमा थिएटरों को अनुमोदित फिल्मों की आपूर्ति करता है, जन–सूचना अभियानों में हिस्सा लेता है, डीवीडीज़ की बिक्री करता है और फिल्म प्रभाग की चुनी हुई फिल्मों के प्रिंटों/वीडियो का वितरण विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार प्रभाग के जरिए विदेश स्थित भारतीय मिशनों को करता है।

(3½ vUrjkZ"Vªh; oÙkfp=] y?kq ,oa ,fues'ku fQYe QfLVoy ½

फिल्म प्रभाग 1990 से द्विवार्षिक "डाक्युमेंटरी, लघु एवं एनिमेशन फिल्मों के लिए मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव" (एमआईएफएफ) का आयोजन करता है। यह फिल्मोत्सव फिल्म निर्माताओं, प्रोड्यूसरों, वितरकों, प्रदर्शकों और फिल्म समीक्षकों को एक विशेष अवसर प्रदान करता है, जहां वे मिलकर विचारों और धारणाओं का आदान प्रदान करते हैं। 15वां एमआईएफएफ–2018 28 जनवरी, से 03 फरवरी 2018 के बीच आयोजित किया गया।

¼4½ iz'kklu Ld/k ½

प्रशासन स्कंध के अंतर्गत वित, कार्मिक, भंडार, लेखा, फैक्टरी प्रबंधन और सामान्य प्रशासन शामिल है। फिल्म प्रभाग के संदर्भ में कर्मचारियों की संख्या/स्थिति का ब्यौरा 30.11.2017 के अनुसार इस प्रकार हैः

क्र सं	श्रेणी	स्वीकृत संख्या	वर्तमान संख्या	रिक्त पदों की संख्या
क	ख	ग	घ	ङ
1	समूह 'क'	31	17	14
2	समूह 'ख'	193	171	22
3	समूह 'ग'	385	354	31
	कुल	609	542	67

o"kZ dh miyfC/k;k¡

- 39 डाक्युमेंटरी फिल्मों का निर्माण, जिसमें से 28 फिल्में विभाग द्वारा और 11 फिल्में बाहरी निर्माताओं के जरिए बनाई गई।
- विभिन्न संगठनों/संस्थानों/स्कूलों और कॉलेजों द्वारा आयोजित 19 विशेष स्क्रीनिंग कार्यक्रमों में 142 फिल्में प्रदर्शित की गईं।
- फिल्म प्रभाग ने जून, 2017 में गुवाहाटी में काहिलीपाड़ा स्थित ज्योति चित्रबन परिसर में गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय डाक्युमेंटरी फिल्मोत्सव आयोजित किया।
- फिल्म प्रभाग ने 18 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सवों में 48 डाक्युमेंटरी फिल्में भेजीं और अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय फिल्मोत्सवों के 10 पुरस्कार जीते।
- शाखा कार्यालयों/निर्माण केंद्रों द्वारा आयोजित 9 कार्यक्रमों/फिल्मोत्सवों में 46 फिल्में दिखाईं।
- 4 स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों से कुल 85 विद्यार्थियों ने अध्ययन के प्रयोजन और फिल्म निर्माण तकनीक को समझने के लिए फिल्म प्रभाग, मुम्बई का दौरा किया।

,QMh tksu%

एफडी ज़ोन फिल्म प्रभाग और स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं का संयुक्त अनुभाग है, जो डाक्युमेंटरी, लघु फिल्मों और एनिमेशन फिल्मों तथा कला के क्षेत्र में अग्रगामी और सार्थक सिनेमा के नियमित दिक्‌दर्शन प्रदर्शन (क्युरेटिड स्क्रीनिंग) का आयोजन करता है। प्रत्येक स्क्रीनिंग के लिए एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता स्वैच्छिक आधार पर फिल्म प्रभाग और स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं की फिल्मों को स्क्रीनिंग के लिए प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में प्रदर्शित की जाने वाली स्वतंत्र फिल्मों के निर्देशक, सिनेमेटोग्राफर या संपादक, ध्वनि रिकार्डिस्ट और निर्माण दल के प्रमुख सदस्यों को दर्शकों के साथ वार्तालाप के लिए स्क्रीनिंग के समय आमंत्रित किया जाता है। फिल्मों की स्क्रीनिंग निःशुल्क और सबके लिए खुली होती है।

,QMh tksu का विकास देश के विभिन्न शहरों/कस्बों में संगठनों और व्यक्तियों के फिल्म क्लबों के अखिल भारतीय नेटवर्क के रूप में किया जा रहा है, ताकि डाक्युमेंटरी, लघु, एनिमेशन और कला के क्षेत्र में अग्रगामी फिल्मों को बढ़ावा दिया जा सके। एफडी ज़ोन की शाखाएं त्रिशूर (केरल), चेन्नई, कोयम्बटूर, कोलकाता,

तुर्की के प्रतिनिधिमंडल फिल्म प्रभाग, मुम्बई का दौरा करते हुए

दिल्ली, चंडीगढ़, मुम्बई और वर्धा में संचालित हैं।

izeq[k dk;Øe

¼1½ xfr'khy osc iksVZy vkSj bZ&dkWelZ

वेब पोर्टल का लक्ष्य निम्नांकित उपायों के जरिए परस्पर संवादात्मक और इस्तेमालकर्ता–अनुकूल बनना हैः

- समसामयिक घटनाक्रम, फिल्म प्रदर्शनों, डीवीडी और फिल्म रिलीज़ होने संबंधी जानकारी को अद्यतन बनाना।
- बाहरी फिल्म प्रस्तावों के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था करना।
- फिल्म प्रभाग में निर्मित और भंडारित वीडियो समग्री के बारे में जानकारी से युक्त फिल्म प्रभाग कैटलॉग को अपलोड करना।

¼2½ vfHkys[kh; vuqla/kku dsUnz ¼,vkj,lh½%

एआरसी एक मल्टी स्टेशन अनुसंधान सुविधा है, जिसका उद्‌घाटन 26 अक्तूबर, 2013 को किया गया था। इसका लक्ष्य दृश्य इतिहास और दृश्य प्रलेखन की विपुल संपदा को साझा करना है। यह सुविधा वर्तमान में इस केंद्र के साथ जुड़े 15 अनुसंधान केंद्रों पर उपलब्ध है।

¼3½ Hkkjrh; flusek dk jk"Vªh; laxzgky;%

भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय (एनएमआईसी) सामान्य जन को फिल्म संबंधी जानकारी का भंडार उपलब्ध कराएगा और फिल्म निर्माताओं, फिल्म विद्यार्थियों, जिज्ञासुओं और समीक्षकों को न केवल देश में बल्कि विश्व के सभी भागों के बारे में कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सिनेमा के विकास की जानकारी हासिल करने में मदद करेगा। भारत में कोई फिल्म संग्रहालय न होने को देखते हुए इस संग्रहालय

का विशेष महत्व है।

संग्रहालय को 156.90 करोड़ रुपये की कुल संशोधित लागत के साथ दो अलग–अलग चरणों में तैयार किया जाना है। संग्रहालय के निर्माण कार्य का दायित्व राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) और कला वस्तुओं के प्रदर्शन के लिए दीर्घाओं की स्थापना का कार्य राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को सौंपा गया है।

lokvk e vtk] vtk vkj vfio dk ifrfuf/kRo

फिल्म प्रभाग द्वारा सेवाओं में अजा, अजजा और अपिव समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व के बारे में समय–समय पर जारी सरकारी आदेशों/अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए आरक्षण रोस्टर निर्धारित नियमों के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

30-11-2017 dk vtk] vtk] vfio] efgyk depkfj;k vkj 'kkjhfjd fodykx 0;fDr;k dk lok e ifrfuf/kRo bl idkj Fkk%

पदों का वर्गीकरण	वर्तमान में सेवारत कर्मचारियों की कुल संख्या	अजा	अजा का प्रतिशत	अजजा	अजजा का प्रतिशत	अपिव	अपिव का प्रतिशत	महिला	शावि
		कर्मचारी							
समूह क	17	4	23.53	..	..	5	29.41	3	..
समूह–ख	171	38	22.09	13	7.60	32	18.60	26	03
समूह–ग	354	103	29.09	24	6.76	86	24.23	58	11
कुल	**542**	**145**	..	**37**	..	**123**	..	**87**	**14**

31-10-2017 dk fQYe iHkkx e vtk] vtk] vfio d fy, fiNy u Hkj x, ink dk C;kjk bl idkj g%

क्र सं	श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	वर्तमान कर्मचारियों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	न भरे गए पद	अजजा के न भरे गए पद	अपिव के न भरे गए पद
1	समूह क	31	17	14	0	1	0
2	समूह–ख	192	171	22	0	2	0
3	समूह–ग	386	354	31	0	0	0
	कुल	**609**	**542**	**67**	**0**	**0**	**0**

fn0;kx tu%

मंत्रालय ने फिल्म प्रभाग में निम्नांकित श्रेणियों के पदों का चयन दिव्यांग जनो से भरने के लिए किया है।

समूह 'ग'	समूह 'घ' (वर्तमान में समूह 'ग' के रूप में प्रोन्नत)
सहायक लेआउट कलाकार कलाकार ग्रेड–1 कलाकार ग्रेड–2 सहायक संपादक ग्रेड–1 संहायक संपादक ग्रेड–2 सहयक रिकॉडिस्ट सहायक अवर श्रेणी लिपिक	चपरासी पैकर

फिल्म प्रभाग में समूह 'क' की रिक्तियों में कोई पद ऐसा नहीं है, जिसकी पहचान दिव्यांग जनो से भरे जाने के लिए की गई हो। सीधे भर्ती के अंतर्गत दिव्यांग जनो से भरे जाने के लिए चुने गए पदों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

समूह	कर्मचारियों की संख्या				
	कुल	चुने हुए पदों में से	दृवि दृष्टि विकलांग	श्रवि श्रवण विकलांग	अवि अस्थि विकलांग
1	2	3	4	5	6
समूह क	17	.	.	.	.
समूह–ख	171	53	.	.	4
समूह–ग	354	117	.	.	10
कुल	542	170	.	.	14

दिव्यांग जनो से भरे जाने वाले पदों में कोई बैक लॉग रिक्तियां नहीं हैं, परंतु 3 पदों (अवर श्रेणी लिपिक के 2 पद और चपरासी का 1 पद) की पहचान सीधे भर्ती के अंतर्गत शारीरिक विकलांग व्यक्तियों से भरे जाने के लिए की गई है।

ukxfjd pkVj%

फिल्म प्रभाग ने "फिल्म प्रभाग की सूचना विवरणिका" (इन्फार्मेशन ब्रोशर ऑफ फिल्म्स डिविजन) शीर्षक से नागरिक चार्टर तैयार किया है, जो वेबसाइट http://www.filmsdivision.org पर उपलब्ध है। प्रभाग ने नागरिक चार्टर के समुचित कार्यान्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है और फिल्म प्रभाग के कार्यक्रमों से सीधे संबद्ध अधिकारियों के सम्मेलन/सेमिनार आयोजित किए जाते हैं।

tu f'kdk;r fuokj.k 0;oLFkk%

सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार जन–शिकायतों के निवारण के लिए व्यवस्था की गई है। फिल्म प्रभाग से संबंधित जन–शिकायतों के निवारण के लिए महानिदेशक को निर्दिष्ट किया गया है। जन–शिकायतों और कर्मचारियों की शिकायतों के लिए रजिस्टर रखे गए हैं और जन–शिकायतों के निपटान के बारे में अपेक्षित रिपोर्ट नियमित रूप से मंत्रालय को भेजी जाती है।

fgnh vuHkkx%

हिंदी अनुभाग कार्यालय पत्राचार में हिंदी (राजभाषा) के इस्तेमाल की देखरेख करता है। फिल्म प्रभाग में केंद्र सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के संशोधित मानदंडों के अनुसार प्रभाग में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद सृजित किए गए हैं।

lrdrk xfrfof/k;k%

प्रभाग के कर्मचारियों के खिलाफ सतर्कता/अनुशासनात्मक मामलों की देखरेख के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ बनाया गया है, जिसमें एक अधीक्षक, दो सहायक और एक अवर श्रेणी लिपिक रखे गए हैं, जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी की

फिल्म प्रभाग कैम्पस में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

देखरेख में काम करते हैं।

lpuk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 dk dk;kUo;u%

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी तत्संबंधी अनुदेशों/दिशा–निर्देशों के अनुपालन में फिल्म प्रभाग ने प्रशासन के निदेशक को अपील प्राधिकारी और एक उप–महानिदेशक (प्रभारी) को केंद्रीय जन–सूचना अधिकारी के रूप में नामित/नियुक्त किया है।

सूचना अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामले मुख्यालय में नोडल सेक्शन अर्थात् स्थापना–1 अनुभाग में निपटाए जाते हैं।

Hkkjrh; cky fQYe lfefr ¼lh,Q,lvkbZ½

Hkwfedk

भारतीय बाल फिल्म समिति (सीएफएसआई) की स्थापना मई, 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो बच्चों के प्रति विशेष सरोकार रखते थे, की पहल और फिल्म जांच समिति (1949) की सिफारिश के आधार पर की गई थी। यह संस्था समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं को फिल्मों के माध्यम से 'मूल्य आधारित' मनोरंजन उपलब्ध कराना है।

समिति का प्रमुख इसका अध्यक्ष होता है, जो सिनेमा क्षेत्र के किसी जानेमाने व्यक्ति को बनाया जाता है। वह कार्यकारी परिषद और सामान्य निकाय का भी प्रमुख होता है। समिति के सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी समिति के अध्यक्ष के तहत काम करता है, जिसके अंतर्गत सभी विभागाध्यक्ष आते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोजमर्रा के प्रशासन, निर्माण, विपणन और लेखा कार्यों का प्रबंधन करता है।

सीएफएसआई का मुख्यालय मुम्बई में है और इसके शाखा कार्यालय नई दिल्ली और चेन्नई में हैं।

fuekZ.k xfrfof/k;k%

iwjh dh xbZ fQYesa%

अप्रैल से अक्तूबर, 2017 के दौरान वी–3 (हिंदी) नामक एक वैब सीरीज़, इशु (असमिया फीचर फिल्म), द केक स्टोरी (हिंदी लघु फिल्म), स्कूल चलेगा (हिंदी फीचर फिल्म), बनारसी जासूस (हिंदी फीचर फिल्म) आदि फिल्में पूरी की गईं।

fuekZ.kk/khu fQYesa%

कुल मिला कर 2 फिल्में अर्थात् 'नानी तेरी मोरनी' (नगा भाषा आंशिक हिंदी) और चिड़ियाखाना (हिंदी फीचर), निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

fQYeksa dh MfCkx%

एनएफडीसी के माध्यम से सीएफएसआई की 10 फिल्मों की डबिंग पूर्वोत्तर की 6 भाषाओं और पूर्वोत्तर से संबंधित 3 फिल्मों की डबिंग 13 क्षेत्रीय भाषाओं में की जा रही है। सीएफएसआई को गुणवत्ता नियंत्रण के लिए 6 भाषाओं में गट्टू, गारू, पिंटी का साबुन, हैपी मदर्स डे नामक फिल्में प्राप्त हुई हैं।

fizaV rS;kj djuk%

सीएफएसआई के 36 डिजिटल सिनेमा पैकेज (डीसीपीज़), 11 ब्लू रेज़ और 1222 डीवीडीज़ वितरण के लिए तैयार की गईं।

foi.ku vkSj forj.k xfrfof/k;k%

forj.k%

''स्कूलों में सीएफएसआई फिल्मों का प्रदर्शन'' के अंतर्गत 300 थिएटरिकल शो (फिल्म बोनांजा) और गैर–थिएटरिकल शो (एलसीडी शो) आयोजित किए गए, जिनमें 1,49,382 बाल दर्शकों ने हिस्सा लिया। पूर्वोत्तर विभाग मंत्रालय के अंतर्गत फिल्म बोनांजा के रूप में 93 शो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ, केरल, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में आयोजित किए गए, जिनमें 30,030 दर्शकों ने हिस्सा लिया। स्वयंसेवी संगठनों के जरिए मुम्बई, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में पृथक शो और मिनी उत्सवों के रूप में 53 अन्य फिल्म शो आयोजित किए गए, जिनमें 19,496 दर्शकों ने भाग लिया।

मेघालय में आयोजित फिल्म बोनांजा थिएटरिकल शो

foi.ku%

1. 'चुलबुली फिल्में चटपटी गपशप' के राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम पर 7 फिल्में टेलीकास्ट की गईं, जिनसे रु. 3.37 लाख राजस्व प्राप्त हुआ।
2. 5 फिल्में डीडीके चेन्नई पर टेलिकास्ट की गई, जिनसे रु. 2.80 लाख राजस्व अर्जित हुआ।
3. वर्ष 2017 के दौरान विभिन्न सीएफएसआई फिल्मों की 944 डीवीडी बेची गईं, जिनसे रु 97,350 की राशि प्राप्त हुई।

अप्रैल से अक्तूबर, 2017 के दौरान कुल 34.46 लाख रुपये राजस्व के रूप में प्राप्त किए गए।

vrjk"Vªh; fQYeksRlokas esa Hkkxhnkjh %

सीएफएसआई की 14 फिल्मों ने 42 देशों में हुए 72 अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सवों में हिस्सा लिया।

xfrfof/k;k¡%

- तमिलनाडु के कांचीपुरम, झारखंड के रांची, ओड़िसा के भुवनेश्वर, उत्तराखंड के देहरादून, मध्य प्रदेश में भोपाल, छत्तीसगढ़ में रायपुर, केरल में पलक्कड़ और पंजाब के मुक्तसर शहर में फिल्म बोनांजा आयोजित किए गए।
- पूर्वोत्तर में असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में भी फिल्म बोनांजा आयोजित किए गए।

20oka vrjk"Vªh; cky fQYeksRlo] gSnjkckn] rsyaxkuk%

भारत का 20वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव 8 से 14 नवंबर, 2017 के बीच हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित किया गया। इसका विषय था – 'न्यू इंडिया'। इसमें 55 देशों से 317 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं, जो एक नया कीर्तिमान था। ये फिल्में तेलंगाना राज्य में फैले 40 थिएटरों में 43 स्क्रीनिंग के अंतर्गत दिखाई गईं। विभिन्न वर्गों के 22 जूरियों में बच्चों सहित देश विदेश की प्रमुख फिल्मी हस्तियां शामिल थीं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खंड में कुल 41 फिल्मों, एशियाई पैनोरमा में 20 फिल्मों और बाल–निर्देशक (लिटिल डायरेक्टर) खंड में 23 फिल्मों को देखकर पुरस्कारों के लिए चयन करना था। इसके अतिरिक्त समारोह के दौरान बाल जगत खंड के अंतर्गत 233 फिल्में दिखाई गईं। एनिमेशन फिल्म निर्माण और कथा कहने के बारे में 3 कार्यशालाओंकाआयोजनकियागया।बालफिल्मोंऔरविशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों के बारे में व्यवसायी वक्ताओं के साथ विभिन्न विषयों पर 5 मुक्त मंचों और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने तथा विचार विमर्श के लिए मीडिया एवं संचार मंचों का आयोजन किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव, तेलंगाना में भाग लेते कलाकार

b&dkWelZ xfrfof/k;k¡%

भुगतान गेट–वे के एकीकरण के साथ फिल्म निर्माण प्रस्ताव जमा कराने और प्रतिनिधियों के पंजीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। सीएसएफआई द्वारा आयोजित किए जाने वाले फिल्मोत्सवों के लिए प्रविष्टियां जमा कराने का काम ऑनलाइन किया जाता है। सीएफएसआई गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की सुविधा के साथ एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। सभी प्राप्तियां और भुगतान ऑनलाइन किए जा रहे हैं। सेवाएं खरीदने के लिए ई–निविदा प्रक्रिया का अनुपालन किया जा रहा है।

Hkkjrh; fQYe vkSj Vsyhfotu laLFkku ¼,QVhvkbZvkbZ½

भारतीय फिल्म संस्थान, पुणे की स्थापना भारत सरकार ने 1960 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत की थी। 1974 में टेलीविजन स्कंध को इसमें मिला देने के बाद संस्थान का नया नामकरण भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कर दिया गया। अक्तूबर, 1974 में संस्थान का पंजीकरण समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में किया गया। एफटीआईआई सोसायटी के सदस्यों में फिल्म, टेलीविजन, संचार, संस्कृति से सम्बद्ध जानीमानी हस्तियां और संस्थान के पुराने विद्यार्थी तथा सरकार के पदेन

अधिकारी शामिल हैं। संस्थान का संचालन अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है। संस्थान की शैक्षिक नीतियां, शैक्षिक परिषद द्वारा तैयार की जाती हैं और वित्त संबंधी मामले स्थायी वित्त समिति द्वारा नियंत्रित होते हैं।

संस्थान के दो स्कंध हैं –फिल्म और टेलीविजन स्कंध। फिल्म स्कंध निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी, साउंड रिकार्डिंग और साउंड डिजाइन, संपादन और कला निर्देशन तथा प्रोडक्शन डिजाइन में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, अभिनय में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम और फीचर फिल्म पटकथा लेखन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित करता है। टेलीविजन संबंधी पाठ्यक्रमों में निर्देशन, इलेक्ट्रोनिक सिनेमेटोग्राफी, वीडियो संपादक, साउंड रिकार्डिंग और टीवी इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ टेलीविजन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शामिल है।

एफटीआईआई दूरदर्शन के सभी ग्रेडों के अधिकारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। दूरदर्शन स्टाफ, आईआईएस प्रोबेशनरों आदि के लिए अल्पावधि पाठ्यक्रम

एफटीआईआई पुणे स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान

भी संचालित किए जाते हैं। एफटीआईआई एनएफएआई, पुणे के सहयोग से हर वर्ष गहन फिल्म बोध पाठ्यक्रम भी संचालित करता है।

o"k dk nkjku ieq[k xfrfof/k;k

- कम लागत पर और सुगम गुणवत्तापूर्ण सिनेमा साक्षरता प्रदान करने के लिए अल्पावधि पाठ्यक्रमों के संचालन में ब्रैंड एफटीआईआई के विकास के लिए एक नया कार्यक्रम, एसकेआईएफटी (स्किलिंग इंडिया इन फिल्म एंड टेलीविजन) (अर्थात् भारत को फिल्म और टेलीविजन में कुशल बनाना), तैयार किया गया। एसकेआईएफटी के अंतर्गत राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/शैक्षिक संस्थानों के सहयोग से देशभर में वर्षभर विभिन्न अल्पावधि पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं।
- फिल्म बोध, अभिनय, पटकथा लेखन, डिजिटल सिनेमेटोग्राफी, टेलीविजन के लिए कथा लेखन आदि में अक्तूबर 2017 तक 36 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। 1800 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनसे लगभग 1.50 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। प्रशिक्षण पाने वाले प्रतिभागियों में से अधिकतर को विभिन्न पदों पर पहले ही रोजगार प्राप्त हो चुका है।
- भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआई. आई) पुणे को जुलाई 2017 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) की विशेष परियोजना श्रेणी के अंतर्गत अल्पावधि कौशल उन्मुखी पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति प्राप्त हुई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल वीडियो संपादन में 21 दिन की अवधि के पाठ्यक्रम के दो बैचों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गयाः–

i. प्रथम बैच (10 प्रतिभागी) : 09.10.2017 से 02.11.2017

ii. दूसरा बैच (10 प्रतिभागी) : 08.11.2017 से 01.12. 2017 तक।

- सुश्री पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित एफटीआईआई की संवाद फिल्म ऑफ्टर नून क्लाउड्स को 2017 के कान फिल्म समारोह में स्क्रीनिंग के लिए चुना गया। इस वर्ष कान फिल्म समारोह के लिए यह भारत की एकमात्र प्रविष्टि थी।
- श्री अभिजीत खुमान द्वारा निर्देर्शित, टेलीविजन स्कंध में फाइनल की गई कथा फिल्म कल्पवृक्ष, को गैर–फीचर फिल्म श्रेणी के अंतर्गत सर्वोत्कृष्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए इलेक्ट्रोनिक सिनेमेटोग्राफी के विद्यार्थी अल्पेश कुमार के साथ (संयुक्त रूप से) प्रतिष्ठित रजत कमल मिला।
- टेलीविजन और फिल्मों के लिए उद्योग की वीएफएक्स (विजुअल इफेक्ट्स) संबंधी मूलभूत जरूरतें पूरी करने के लिए तैयार किया गया तीन महीने का वीएफएक्स

और फिनिशिंग कोर्स (18.09.2017 से 08.12.2017) संचालित किया गया।

- एफटीआईआई ने अपने कैम्पस में 10 से 16 अक्तूबर, 2017 और 23–29 अक्तूबर, 2017 के बीच 7 दिन की बुनियादी फिल्म निर्माण कार्यशाला आयोजित की। इसमें दोनों बैचों में 10 से 16 वर्ष की आयु समूह के कुल 26 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।
- एफटीआईआई ने अपने कैम्पस में 13 से 28 अक्तूबर, 2017 के दौरान 15 दिन की बुनियादी अभिनय कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में दो आयु समूहों, 7 से 10 वर्ष और 11 से 15 वर्ष के लिए आयोजित की गई। दोनों आयु समूहों के कुल 20 प्रतिभागियों ने कार्यशाला में हिस्सा लिया।
- एफटीआईआई का भारत में प्रथम डिजिटल सिनेमेटोग्राफी अल्पावधि पाठ्यक्रम 12.07.2017 से 03.08.2017 के बीच पोर्टब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) में आयोजित किया गया। स्किफ्ट (स्किलिंग इंडिया इन फिल्म एंड टेलीविजन) कार्यक्रम के अंतर्गत 3 सप्ताह के इस फाउंडेशन कोर्स में 24 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
- जुलाई 2017 में संस्थान के कैम्पस में 5 महीने की अवधि का टेलीविजन फिक्सन राइटिंग (कहानी लेखन) कोर्स प्रारंभ किया गया, जो भारत में अपनी तरह का पहला पाठ्यक्रम है। इसका प्रयोजन टेलीविजन उद्योग की लंबी कथाओं के फॉरमेट की जरूरत पूरी करना है।
- श्रीनगर में फिल्म बोध पाठ्यक्रम संचालित किया गया, जो कश्मीर घाटी में अपनी तरह का पहला पाठ्यक्रम था। 5 दिन का यह कोर्स कश्मीर विश्वविद्यालय के मीडिया शिक्षा अनुसंधान केन्द्र (एमईआरसी) के सहयोग से आयोजित किया गया। फिल्म बोध पाठ्यक्रम में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रवेश लिया।
- 12 मई, 2017 को माननीय सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एफटीआईआई का दौरा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गुणवत्तापूर्ण और वहन करने योग्य सिनेमा शिक्षा तक उन सबकी पहुंच होनी चाहिए जो इस माध्यम के बारे में अधिक जानने के इच्छुक हों। एफटीआईआई द्वारा आयोजित किए जा रहे अल्पावधि पाठ्यक्रम गुणवत्तापूर्ण सिनेमा साक्षरता को कैम्पस से बाहर सामान्य जन तक पहुंचाने की दिशा में एक अग्रणी कदम है।
- एफटीआईआई ने ''स्मरणांजली'' कार्यक्रम के आयोजन के साथ जाने–माने फिल्मकार स्वर्गीय ऋषिकेश मुखर्जी को उनके 95वें जन्मदिवस पर याद किया। कार्यक्रम का उद्घाटन 30 सितम्बर, 2017 को प्रतिष्ठित फिल्मनिर्माता और एफटीआईआई के पूर्व विद्यार्थी कुंदन शाह ने एफटीआईआई के मुख्य थिएटर में किया, जिसमें उनकी फिल्में दिखायीं गई और उनके कार्यों पर विचार–विमर्श किया गया। इस अवसर पर एफटीआईआई के पूर्व डीन श्री महबूब खान, एफटीआईआई के संपादन विभाग के पूर्व अध्यक्ष योगेश माथुर भी उपस्थित थे, जिन्होंने प्रतिष्ठित फिल्म संपादक और फिल्मनिर्माता के बारे में अपने विचार साझा किए।
- संस्थान के स्टाफ, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया, जिसका आयोजन हर महीने के प्रथम शुक्रवार को किया गया। इस अवसर पर एफटीआईआई आवासीय कालोनी में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

एफटीआईआई पुणे में आगन्तुक

- एफटीआईआई और महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिहार (एमजीसीयूबी) ने शैक्षिक और व्यावसायिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए; इसके तहत एफटीआईआई फिल्म, टीवी और जनसंचार संस्थान की स्थापना में एमजीसीयूबी की सहायता करेगा।
- एफटीआईआई ने महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड (एमएमबी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार एफटीआईआई के विद्यार्थी महाराष्ट्र मैरिटाइम क्षेत्र में अपनी परियोजनाओं की शूटिंग कर

सकेंगे और एमएमबी के साथ आउटरीच परियोजनाएं संचालित कर सकेंगे।

- वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान अनेक अतिथि लेकचरर्स ने एफटीआईआई में विभिन्न विषयों पर कार्यशालाओं / सेमिनारों / मास्टर कक्षाओं का आयोजन किया।

fQYekRlok e ,QVhvkbvkb fQYek dh Hkkxhnkjh

- 2017 बाफ्टा अमरीकी स्टूडेंट्स फिल्म अवाड्र्स किंग्सटन, लंदन (22 जून, 2017)।
- सातवां पोस्टारिया सीसाइड फिल्म फेस्टिवल (26 से 30 जुलाई, 2017)।
- व्लादिवोस्टोक, रूस में एशिया प्रशांत देशों का 15वां अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव ''पैसिफिक मेरिडियन'' (9 से 15 सितम्बर, 2017)।
- अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा आयोजित स्टूडेंट्स अकेडमी अवाड्र्स, कैलिफोर्निया, अमरीका (12 अक्टूबर, 2017)।
- 22वां बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव, बुसान, कोरिया (12 से 21 अक्टूबर, 2017)।
- 26वां फिलाडेल्फिया फिल्मोत्सव, अमरीका (19 से 29 अक्टूबर, 2017)।
- 15वां टोफिफेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव, पोलैंड (21 से 29 अक्टूबर, 2017)।
- पेइचिंग फिल्म अकादमी का 16वां अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स फिल्म एवं वीडियो समारोह (आईएसएफवीएफ), चीन (22 से 29 अक्टूबर, 2017)।
- दूसरा कश्मीर विश्व फिल्म समारोह (01 से 05 नवम्बर, 2017)
- 15वां आसियान अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव, कोरिया (02 से 07 नवम्बर, 2017)
- 20वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव 'द गोल्डन एलिफेंट', तेलंगाना (08 से 14 नवम्बर, 2017)।
- सिनेमैटोग्राफी कला का 25वां कैमरिमेज अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव बिड्गोस्ज़क्ज़, पोलैंड (01 से 08 नवम्बर, 2017)।
- 48वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव, गोवा (20 से 28 नवम्बर, 2017)।
- क्योटो अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स फिल्म और फिल्मोत्सव–2017 जापान (नवम्बर, 2017)।
- 17वां रीवर टू रीवर फ्लोरेंस इंडियन फिल्म फेस्टिवल, इटैलिया (7 से 12 दिसम्बर, 2017)

फिल्मोत्सवों में फिल्माए जाने के लिए चुनी गई एफटीआईआई फिल्में

क्र. स.	फिल्म / डाक्युमेंटरी का नाम	फिल्मोत्सव में चयन	निर्देशक
1	'आफ्टर नून क्लाउड्स'	कान फिल्म समारोह 2017; 16वां अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स फिल्म एवं वीडियो समारोह (आईएसएफवीएफ), पेइचिंग चीन और 5वां एकादेशमा अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव, नेपाल।	पायल कपाडिया
2	श्याम रात शहर	16वां अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स फिल्म एवं वीडियो समारोह (आईएसएफवीएफ), पेइचिंग चीन	अरुणिमा शर्मा
3	सदाबहार ब्रास बैंड	16वां अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स फिल्म एवं वीडियो समारोह (आईएसएफवीएफ), पेइचिंग चीन	तुषार मोरे
4.	सखीसोना	16वां अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स फिल्म एवं वीडियो समारोह (आईएसएफवीएफ), पेइचिंग चीन	प्रांतिक बसु

एफटीआईआई फिल्मों को प्राप्त हुए पुरस्कार

क्र.स	दिनांक	फिल्म का नाम	पुरस्कार
1.	अप्रैल 2017	कल्पवृक्ष	64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वोत्कृष्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए इलेक्ट्रोनिक सिनेमेटोग्राफी के विद्यार्थी अल्पेश नागर गैर फीचर फिल्म श्रेणी में रजत कमल प्रदान किया गया। पुरस्कार के रूप में रजत कमल और 50 हजार रुपये नक़द दिए जाते हैं।
2.	जून 2017	'आफ्टर नून क्लाउड्स	तीसरे फेस्टिवल इंटरनेशनल द सिने फिल्माड्रिड, स्पेन में आधिकारिक प्रतिस्पर्धा में विशेष उल्लेख
3.	जुलाई 2017	सिक एंड हाइड	उत्कृष्ता के लिए मुम्बई में 12वें आईडीपीए पुरस्कारों में स्टूडेंट्स फिक्सन, गोल्ड
4.	जुलाई 2017	सदाबहार ब्रास बैंड	उत्कृष्ता के लिए मुम्बई में 12वें आईडीपीए पुरस्कारों में स्टूडेंट्स फिक्सन, रजत
5.	जुलाई 2017	कामाक्षी	उत्कृष्टता के लिए 12वें आईडीपीए पुरस्कार–2017 के दौरान जूरी के विशेष उल्लेख से सम्मानित।
6.	सितम्बर	आफ्टर नून क्लाउड्स	21वां अंतर्राष्ट्रीय वीडियो उत्सव वीडियोमेडेजा, सर्बिया– सर्वोत्कृष्ट ग्रैज्युएट फिल्म के लिए लुनार्टिस पुरस्कार 'आफ्टर नून क्लाउड्स' को दिया गया। यह फिल्म, तकनीक और गुणवत्ता दोनों दृष्टियों से श्रेष्ठ निर्माण कला और विशुद्ध सिनेमैटिक गति और लय के साथ एक उत्कृष्ट वातावरण का सृजन करती है।
7.	अक्टूबर 2017	अंधेरे में	लघु फिल्म के लिए विशेष उल्लेख : 16वां इमेजिनइंडिया अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव, 2017 मैड्रिड, स्पेन।

ubl igy

एफटीआईआई ने स्वर्गीय श्री मंगेश देसाई (ध्वनि विभाग के प्रथम और पूर्व विभागाध्यक्ष) को ''स्मरणांजलि'' के आयोजन के साथ याद किया। 25 दिसम्बर 2017 को एफटीआईआई के मुख्य थिएटर में आयोजित कार्यक्रम में उनकी फिल्में दिखायी गईं और उनके जीवन एवं कार्यों पर विचार–विमर्श किया गया।

एफटीआईआई ने 23 और 24 सितम्बर, 2017 को आम लोगों को संस्थान का दौरा करने की छूट दी ताकि वे फिल्म निर्माण प्रक्रिया, तत्संबंधी सुविधाओं और संस्थान की समृद्ध विरासत की जानकारी प्राप्त कर सकें। एफटीआईआई स्टाफ और शिक्षकों की सहायता से पुणे में करीब 12000 से अधिक लोगों को यह जानकारी प्रदान की जा सकी।

एफटीआईआई देश के विभिन्न भागों में fLd¶V अल्पावधि पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है।

lR;thr jk; fQYe ,oa Vsyhfotu laLFkku ¼,lvkj,QVhvkbZ½

सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई) की स्थापना 1995 में एक स्वायत्त शैक्षिक संस्थान के रूप में की गई और इसे पश्चिम बंगाल समिति पंजीकरण अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। संस्थान का नाम प्रसिद्ध फिल्म विशेषज्ञ सत्यजीत राय के नाम पर रखा गया। यह संस्थान छह विशेषज्ञता क्षेत्रों में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है –(1) निर्देशन और पटकथा लेखन (2) सिनेमैटोग्राफी (3) सम्पादन (4) ध्वनि रिकॉर्डिंग और डिजाइन, (5) फिल्म और टेलीविजन के लिए कार्यक्रम निर्माण और (6) ऐनिमेशन सिनेमा। एसआरएफटीआई में वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान उपरोक्त तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में कुल 72 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया। इसके अतिरिक्त एसआरएफटीआई में वर्तमान में 12 विदेशी विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं।

एसआरएफटीआई ने 14.08.2017 से इलेक्ट्रोनिक्स और डिजिटल मीडिया (ई एंड डीएम) में दो–वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया है। प्रथम बैच में विद्यार्थियों की कुल संख्या 30 है। पाठ्यक्रमों का विवरण इस प्रकार हैः (1) डिजिटल मीडिया के लिए लेखन (2) इलेक्ट्रोनिक और डिजिटल मीडिया प्रबंधन (3) इलेक्ट्रोनिक्स और डिजिटल मीडिया के लिए वीडियोग्राफी (4) इलेक्ट्रोनिक्स और डिजिटल मीडिया के लिए कार्यक्रम निर्माण (5) इलेक्ट्रिोनिक और डिजिटल मीडिया के लिए संपादन और (6) इलेक्ट्रोनिक और डिजिटल मीडिया के लिए ध्वन्यांकन।

lxBukRed Ýeodl

संस्थान का संचालन भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाता है। समिति अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कार्यकारी परिषद के माध्यम से संस्थान का संचालन करती है। कार्यकारी परिषद में सिनेमा क्षेत्र के विशेषज्ञों के अलावा मंत्रालय और अन्य मीडिया यूनिटों के अधिकारी पदेन सदस्य होते हैं। इसमें पूर्व विद्यार्थियों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाते हैं। कार्यकारी परिषद संस्थान के समग्र पर्यवेक्षण और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। समिति, कार्यकारी परिषद और स्थायी वित्त समिति में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए पदेन सदस्य के रूप में शामिल हैं। कार्यकारी परिषद द्वारा गठित शैक्षिक परिषद में डीन के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के 6 विशेषज्ञ और संस्थान के 6 विभागाध्यक्ष तथा विद्यार्थियों और पूर्व विद्यार्थियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। शैक्षिक परिषद सभी शैक्षिक और शिक्षा संबंधी मुद्दों की देखरेख करती है। निदेशक संस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जो कार्यकारी परिषद के निर्देशों और मार्गदर्शन के अंतर्गत काम करता है और शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्यों में उसकी सहायता के लिए क्रमशः डीन और रजिस्ट्रार होते हैं।

o"kZ dh miyfC/k;k¡

- फिल्म संपादन में डिप्लोमा विद्यार्थी के. जिशु सेन द्वारा संपादित 'गुडु' (घोंसला) ने 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में गैर–फीचर श्रेणी में सर्वोत्कृष्ट संपादक का पुरस्कार हासिल किया और लॉस एंजेलस में भारतीय फिल्मोत्सव–2017 के दौरान जुरी के विशेष उल्लेख का सम्मान प्राप्त किया।
- 21 अप्रैल, 2017 को संस्थान के परिसर में चुने हुए स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया।
- इस संस्थान के 9वें और 10वें बैच के विद्यार्थियों के लिए 7वां दीक्षांत समारोह प्रसिद्ध फिल्मी हस्ती स्वर्गीय सत्यजित रे की जयंती, 2 मई, 2017 को आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल महामहिम केशरीनाथ त्रिपाठी, लोक सेवा प्रसारण ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री राजीव मेहरोत्रा और प्रसाद फिल्म लेबोरेटरी के प्रबंध निदेशक श्री रमेश प्रसाद उपस्थित थे। दीक्षांत भाषण महामहिम श्री केशरीनाथ त्रिपाठी ने दिया।
- एसआरएफटीआई के प्रोफेसर देबाशीष घोषाल (एसआरडी) के मार्गदर्शन के अंतर्गत 'सिनेमा की यात्रा' के बारे में 10 सप्ताह का पाठ्यक्रम 15.05.2017 से 23.07.2017 के बीच अरुणाचल प्रदेश में स्थित फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अस्थायी कैम्पस (एसआरएफटीआई का विस्तारित कैम्पस), में सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
- नोबेल पुरस्कार विजेता रबीन्द्रनाथ ठाकुर की 156वीं जयंती संस्थान में 9 मई, 2017 को मनाई गई, जिसमें आयोजित समारोह में कर्मचारियों ने भाग लिया।
- बांग्लादेश सरकार के तहत बांग्लादेश सिनेमा एवं टेलीविजन संस्थान के विद्यार्थियों के लिए 'सिनेमा में ध्वनि' अर्थात् साउंड इन सिनेमा के बारे में 4 दिन की कार्यशाला आयोजित की गई और बांग्लादेश सिनेमा और टेलीविजन संस्थान तथा सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के बीच विद्यार्थियों और शिक्षकों के आदान प्रदान के बारे में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- फिल्म समारोह निदेशालय और सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के सहयोग से 9 दिन का ''यूरोपीय संघ फिल्मोत्सव–2017'' 14 से 22 जुलाई, 2017 के बीच आयोजित किया गया, जिसका विषय था – ''सिनेमा के प्रति प्रेम दर्शाने वाली अद्यतन यूरोपीय फिल्में''।
- एनएसडीएल के साथ 14 अगस्त, 2017 को नेशनल डिपोजिटरी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए और तत्संबंधी टेस्ट डेटा अपलोड किया गया।
- सिद्धांत, व्यवहार और शिक्षण में शैक्षिक बोझ का पता लगाने के लिए शैक्षिक प्रबंधन सॉफ्टवेयर का विकास संस्थान के भीतर किया गया और उसे विद्यार्थियों की परियोजनाओं पर निगरानी के लिए 16 अगस्त, 2017 से प्रचालित किया गया।

- निर्देशन विभाग के विद्यार्थी श्री वैभव हिवासे द्वारा निर्देशित फिल्म 'पलाश' को पेइचिंग में होने वाले पेइचिंग फिल्म अकेडमी फिल्मोत्सव में प्रदर्शन के लिए चुना गया।
- एसआरएफटीआई ने 15 सितंबर से 2 अक्तूबर 2017 के बीच ''स्वच्छता ही सेवा'' अभियान सफलतापुर्वक आयोजित किया, जिसके लिए स्वच्छता जागरूकता के बारे में एसआरएफटीआई द्वारा निर्मित फिल्म ''ये देश है मेरा'' (अवधि 4 मिनट) संस्थान के मुख्य थिएटर में पूर्वाह्न 11 बजे दिखाई गई।
- संस्थान ने डिजिटल और ऑडियो विजुअल मीडिया पर बल देने के लिए 13 से 19 नवंबर, 2017 के बीच सात दिन की अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका विषय था ''लायब्रेरी ऑटोमेशन' (आईडब्ल्यूपीटीएलए) इस कार्यक्रम से करीब 2,47,000 रुपये (दो लाख सैंतालिस हजार रुपये) अर्जित किए गए।
- 20 नवंबर, 2017 को 07 विद्यार्थियों के साथ 'स्क्रीन एक्टिंग' के बारे में एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया, जो 20 अप्रैल, 2018 तक जारी रहेगा। इसके लिए प्रति विद्यार्थी 60,000 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। इस कार्यक्रम से कुल 3 लाख रुपये का राजस्व अर्जित होने की संभावना है।

एसआरएफटीआई, कोलकाता में टेलीविजन स्कंध के लिए नवनिर्मित फिल्म स्टुडियो के निकट कार्यरत विद्यार्थी

- 21 जून, 2017 को संस्थान ने 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' विधिवत रूप से आयोजित किया, जिसमें संस्थान के शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने बाहर से आमंत्रित योग विशेषज्ञ के नेतृत्व में योगाभ्यास किया।
- श्रीमती गीता सेन, जिनका इस वर्ष के प्रारंभ में कोलकाता में देहांत हो गया था, की स्मृति में, और अभिनय में उनके बेजोड़ स्थायी योगदान को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे के सहयोग से एक पश्चदर्शन कार्यक्रम 12 से 14 मई, 2017 के बीच आयोजित किया गया, जिसमें श्रीमती गीता सेन की सात फिल्में प्रदर्शित की गईं।

विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई फिल्मों का फिल्मोत्सवों और पुरस्कारों के लिए चयन

क्रम सं	फिल्म/डाक्युमेंटरी का नाम	निर्देशक	फिल्मोत्सव/पुरस्कार के लिए चयन
1.	"पलाश"	श्री वैभव हिवासे	अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, भारत गोवा 2017
2.	जीआई	अकिला हेनरी	
3.	एपिल	आर के सोरेन	
4.	'गध'	निर्देशन : सौरव राय संपादक : जिश्नु सेन	64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2016 में सर्वोत्कृष्ट संपादन पुरस्कार से सम्मानित और भारतीय फिल्म समारोह, लॉस एंजिल्स, अमरीका, 2017 में विशेष जुरी उल्लेख के लिए चुनी गई।
5.	पलाश	निर्देशन : वैभव हिवासे	पेइचिंग में पेइचिंग फिल्म अकादमी में स्क्रीनिंग के लिए चुनी गई
6.	'रंदु कुरिप्पुकल'	निर्देशन : गिरीश कुमार के	संकेत फिल्म समारोह, 2016 में सर्वोत्कृष्ट लघु फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित। आईएफएफआई–2016 में प्रदर्शन के लिए चुनी गई।
7.	'तोउ–ताई'	निर्देशन : निरंजन कुजुर	22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, कोलकाता में सर्वोत्कृष्ट लघु फिल्म के पुरस्कार के लिए चुनी गई।

v#.kkpy in'k e fQYe vkj Vyhfotu lLFkku ¼iokRrj {k=½

देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के प्रति सरकार के उपायों के हिस्से के रूप में तथा फिल्म एवं टेलीविजन के क्षेत्र में पूर्वोत्तर के युवाओं में प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे (एफटीटीआई) और सत्यजित रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई) की तर्ज पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी राज्य में फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना की जाए।

इस दिशा में एक अस्थायी कैम्पस ईटानगर में शुरू किया गया, जहां पूर्वोत्तर क्षेत्र से सम्बद्ध विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। प्रोफेसर देबाशीष घोषाल के मार्गदर्शन के अंतर्गत 10 सप्ताह का प्रथम पाठ्यक्रम ''जर्नी टू सिनेमा'' यानी ''सिनेमा की यात्रा'', 15.05.2017 से 23.07.2017 के बीच फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई का विस्तारित कैम्पस), अरुणाचल प्रदेश के अस्थायी परिसर में सफलतापूर्वक संचालित किया गया।

fo|kfFk;k dk vknku inku dk;Øe

शैक्षिक प्रयोजनों के लिए विद्यार्थियों और शिक्षकों के आदान प्रदान के लिए बांग्लादेश सिनेमा और टेलीविजन संस्थान तथा सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

Hkkjr dk jk"Vh; fQYe vfHkys[kkxkj ¼,u,Q,vkb½

,d >yd

भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार–(एनएफएआई) की स्थापना फरवरी 1964 में निम्नांकित लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए की गई थी:

1. आने वाली पीढियों के लिए राष्ट्रीय सिनेमा की धरोहर की खोज करना, उसे हासिल और संरक्षित करना तथा विश्व सिनेमा की चुनी हुई फिल्मों का संग्रह तैयार करना;
2. फिल्म से संबंधित आंकड़ों का वर्गीकरण और प्रलेखन, सिनेमा के बारे में अनुसंधान संचालित और प्रोत्साहित

माननीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एनएफएआई अधिकारियों से बातचीत करते हुए

करना तथा उसे प्रकाशित और वितरित करना;

3. देश में फिल्म संस्कृति के सम्प्रेषण के लिए एक केंद्र के रूप में काम करना और विदेश में भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक मौजूदगी सुनिश्चित करना।

इसके अतिरिक्त एनएफएआई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि विश्वभर में भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक मौजूदगी दिखाई दे। एनएफएआई एकमात्र ऐसा संगठन है, जिसे भारत की समृद्ध और विविध फिल्म धरोहर के संग्रहण और संरक्षण का कार्य सौंपा गया है।

,u,Q,vkbZ dh fQYe laxg.k uhfr

- भारत में फिल्मों के लिए राज्य पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में पुरस्कार एवं गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाली फिल्में।
- अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के भारतीय पैनोरमा खंड में दिखाई जाने वाली फिल्में।
- बॉक्स आफिस पर लोकप्रियता हासिल करने वाली फिल्में और भारत और विदेश में बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित करने वाली फिल्में।
- भारतीय और विदेशी, दोनों तरह की जानी–मानी साहित्यिक कृतियों के फिल्म रूपांतरण।
- भारतीय और विदेशी स्थानीय परिवेश में शूट की गई तथा भारतीय अथवा विदेशी निर्माताओं द्वारा बनाई गई फिल्में।
- एनएफडीसी और अन्य सरकारी संगठनों द्वारा वित्त पोषित/निर्मित सभी फिल्में।
- बेहतरीन बाल फिल्मों के विशिष्ट नमूने।
- भारतीय और विदेशी फिल्म निर्माताओं द्वारा की गई समाचार कवरेज में दर्ज यथार्थ सामग्री वाली फिल्में।
- सरकारी और प्राइवेट एजेंसियों द्वारा निर्मित ऐतिहासिक महत्व के वृत्त चित्र।

t;dj caxyk%

पुणे में लॉ कॉलेज रोड पर एनएफएआई के मुख्य परिसर में स्थित, बैरिस्टर मुकुल आर. जयकर के निवास ''जयकर बंगला'' को धरोहर इमारत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैरिस्टर मुकुल जयकर जाने माने शिक्षाविद् और विधि विशेषज्ञ थे, जो पुणे विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति बने और उन्होंने पुणे की समृद्ध विरासत में व्यापक योगदान दिया।

1964 में भारतीय फिल्म संस्थान, पुणे के परिसर में अस्थायी कमरों के लघु शेडों में हुई सामान्य शुरुआत के बाद मई 1974 में एनएफएआई का कार्यालय जयकर बंगले में स्थानांतरित किया गया। एनएफएआई ने मार्च 1981 में दो एकड़ भूमि के साथ इंडियन लॉ सोसायटी से जयकर बंगला अधिग्रहीत किया था। जयकर बंगले में, एनएफएआई ने अपना कार्यालय जनवरी 1994 तक रखा। उसके बाद एनएफएआई को उसी परिसर में एक नया भवन मिला, जहां फिल्म कक्षों का डिजाइन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण मानकों के साथ तैयार किया गया है, उपयुक्त रूप में सुसज्जित संरक्षण विभाग है, काफी मात्रा में किताबें हैं और पत्र–पत्रिकाओं का पुस्तकालय है और एक कैटलॉग, अनुसंधान और प्रलेखन केंद्र है, जिसमें सिनेमा पोस्टरों, अचल चित्रों और अन्य अनुषंगी सामग्री का बहुमूल्य संग्रहालय है। अभिलेखागार में 3 सिनेमा ऑडिटोरियम हैं, जहां वह अपने संग्रह से जनता के लिए फिल्मों का प्रदर्शन करता है।

धरोहर होने के कारण जयकर बंगले का ऐतिहासिक महत्व है और इसे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर स्थिति में संरक्षित रखने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने जयकर बंगले के संरक्षण कार्य और डिजि. टल पुस्तकालय के लिए अपेक्षित ढांचे की स्थापना हेतु 9 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

fiNys n'kdks esa egRoiw.kZ ikfIr;k%

12 वीएचएस टेप्स – जाने माने फिल्म अभिनेता और निर्माता अमोल पालेकर से दान स्वरूप प्राप्त इन फिल्मों में निर्देशक के रूप में किए गए उनके प्रयासों से संबंधित फिल्में भी शामिल हैं, जैसे कच्ची धूप (1987), मृगनयनी (1991) और पऊल खुना (1993)।

–क्लासिक फिल्म बड़ी बहन (1949), जो सुश्री राधिका पई से प्राप्त हुई है।

vu"kxh lkexh – 9 अप्रैल, 2017– एनएफएआई को विधु विनोद चोपड़ा का योगदान। इस संग्रह के अंतर्गत पोस्टर, गीत पुस्तिकाएं, लॉबी कार्ड्स और ifjnk] 1942% yo LVksjh] fe'ku d'ehj vkSj ,dyO; जैसी उनकी फिल्मों से संबंधित प्रचार सामग्री शामिल है। इस संग्रह की खास बात यह है कि इसमें ,dyO; % n jk;y xkMZ (2007) के लिए श्री चोपड़ा द्वारा अपनी कलम से लिखी टिप्पणियां और ऑडियो–वीडियो कंटीन्यूटी शीट्स और चमड़े के जिल्द वाली एक अलंकृत पुस्तक, जो एकलव्य के लिए सारांश और प्रचार सामग्री से युक्त

है, भी इस संग्रह का हिस्सा है।

iVdFkk,¡ ¼fLØIV l½ & 30 मई 2017– प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता सईं प्रांजपे ने अपनी फिल्मों – स्पर्श (1980) और दिशा (1990) की पटकथाएं और दिशा के दो सेलूलॉयड प्रिंट अभिलेखागार को दान किए, जिससे एनएफएआई का संग्रह समृद्ध हुआ है। इंडियन न्यू वेव के रूप में डब की गई दो महत्वपूर्ण फिल्मों, स्पर्श और दिशा ने आधुनिक भारतीय सिनेमा को आकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

vpy fp= & 3 जुलाई, 2017 – जाने माने फोटोग्राफर एस एम अजरेकर ने मराठी सिनेमा से संबंधित एक हजार अचल चित्रों का एक अद्भुत खजाना एनएफएआई को

श्री प्रकाश मगदम, निदेशक, एनएफएआई जाने–माने फोटोग्राफर श्रीमती एसएम अजरेकर के साथ।

दान में दिया है। गार्जस मैट फिनिश के साथ ये उत्कृष्ट फोटोग्राफ हैं।

fQYe iksLVj& 4 अगस्त, 2017– एनएफएआई ने 2500 फिल्म पोस्टरों का एक समृद्ध भंडार हासिल किया। इसमें मुगल–ए–आजम का भव्य हस्तचित्रित 6 शीट वाला पोस्टर शामिल है। संग्रहालय में फीयरलेस नाडिया की कई फिल्में और अमिताभ बच्चन अभिनीत 90 फिल्में भी शामिल हैं।

fQYesa&13 सितंबर, 2017– एनएफएआई ने 162 फिल्मों का बड़ा लॉट हासिल किया। इनमें से अनेक फिल्में नेगेटिव प्रिंट में हैं, जो संग्रह की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इन फिल्मों में सात हिंदुस्तानी, उसकी रोटी और अम्बर जैसी महत्वपूर्ण फिल्में शामिल हैं। इसमें कई गुजराती और मराठी फिल्में भी समाहित हैं। प्रमुख उपलब्धि के रूप में विट्ठल भाई झावेरी द्वारा महात्मा गांधी पर बनाई गई छह घंटे की डाकूमेंटरी शामिल है।

fQYe HkaMkj.k@lqj{k.k& एनएफएआई के पास करीब 27 अत्याधुनिक फिल्म संग्रह सुविधाएं/कक्ष हैं जो अभिलेखागार विषयक मानकों और विशिष्टताओं से युक्त हैं। इन कक्षों की क्षमता करीब दो लाख फिल्म रीलों को स्थान प्रदान करने की है। फिल्म कक्ष श्वेत–श्याम

एनएफएआई, पुणे में फिल्म परिरक्षण कक्ष

फिल्मों, कलर फिल्मों और नाइट्रेट आधारित फिल्मों के लिए निम्नांकित अनुसार तापमान बनाए रखते हैं:

fQYe dk izdkj	rkieku	lkisf{kd vknzrk
नाइट्रेट फिल्में	10–12 डिग्री से.	40 प्रतिशत
श्वेत–श्याम फिल्में	10–12 डिग्री से.	40प्रतिशत +/– 5
रंगीन फिल्में	2–4 डिग्री से.	30 प्रतिशत +/– 5

fQYe lekjksgksa esa Hkkxhnkjh

iwokZsRrj fQYeksRlo 2017

एनएफएआई ने फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ), भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और नॉर्थ ईस्ट कम्युनिटी आग्रेनाइजेशन, पुणे (एनईसीओपी) के सहयोग से 28 से 30 जनवरी, 2017 के दौरान लॉ कॉलेज रोड स्थित अपने परिसरों में पूर्वोत्तर फिल्म समारोह एनईएफएफ–2017 आयोजित किया।

समारोह का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अजय मित्तल ने 28 जनवरी, 2017 को किया। इस अवसर पर अन्वेषा महंत और नागाजेनस समूह ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें दर्शकों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के नृत्य और संगीत के सफर का आनंद लिया। इसके बाद भास्कर हजारिका की फिल्म dkBkukMh (2015) फिल्माई गई। dkBkukMh ने पिछले

श्री अजय मित्तल, पूर्व सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पूर्वोत्तर फिल्मोत्सव के प्रतिभागियों के साथ।

वर्ष सर्वोत्कृष्ट असमिया फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था और इसे बुसान फिल्म समारोह और अन्य फिल्म उत्सवों में भी दिखाया जा चुका है।

इस वर्ष के पूर्वोत्तर फिल्म समारोह की चुनिंदा फिल्में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से पुणे पहुंचीं। पिछले वर्ष की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्में और भारतीय पैनोरमा फिल्में जैसे ykdrd ykbjEch ¼ef.kijh½] vkukrkg ¼[kklh½ vkj lfcu vyu ¼dkch½ सहित 14 फिल्में एनएफएआई ऑडिटोरियम में प्रदर्शित की गईं। फिल्म प्रदर्शन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों, हस्तशिल्प प्रदर्शनी, फूड स्टाल आदि के आयोजन ने सांस्कृतिक अनुभव को समृद्ध बना दिया।

एनएफएआई ने राष्ट्रव्यापी नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन (एनएफएचएम) की स्थापना की तैयारी शुरू कर दी है। एनएफएआई में यह अभियान श्री अजय मित्तल ने एनएफएचएम के प्रथम चरण अर्थात् फिल्म स्थिति आकलन और गैर–फिल्मी सामग्री के डिजिटीकरण के साथ शुरू किया।

iujf{kr Dykfld fQYek dk lekjkg% एनएफएआई द्वारा पुनर्रक्षित क्लासिक फिल्मों का समारोह में दर्शकों को नए प्रिंटों के साथ कागज़ के फूल, दो बीघा ज़मीन और मेघा ढाका तारा फिल्में बहुत पसन्द आई।

ÝdkQku fQYe lekjkg & फ्रेंच भाषा की विविधता दर्शाने के लिए एनएफएआई ने एक फिल्म समारोह की मेजबानी की। एनएफएआई द्वारा अलाइन्स फ्रेंकाइसे के सहयोग से आयोजित फिल्म समारोह में फ्रांस, लग्जमबर्ग, बुर्कीनाफासो, कनाडा और स्विटजरलैंड की फिल्में दिखाई गईं।

एनएफएआई में यूरोपीय फिल्मोत्सव

;jkih; l?k fQYe lekjkg%

एनएफएआई ने यूरोपीय संघ फिल्म समारोह की 22वीं कड़ी के अंतर्गत 11 से 17 जून, 2017 की अवधि में यूरोप से 22 प्रतिष्ठित फिल्में प्रदर्शित कीं। एस्टोनिया के फिल्म निर्माता आंद्रेज माइमिक और कैट्रिन माइमिक ने एक व्याख्यान सत्र में अपने विचार भी रखे।

ejkBh dkeMh fQYe lekjkg%

अशे फिल्म क्लब के सहयोग से एनएफएआई ने मरा. ठी कॉमेडी फिल्म समारोह (22 से 26 जून, 2017) की

मेजबानी की। समारोह में प्रदर्शित की गई फिल्मों में पेडगावचे शहाणे, सोगदया, गुलाचा गणपति और वरहाडी वजंतरी जैसी कुछ क्लासिक फिल्में शामिल थीं।

fgeky; dh xkn es % uikyh fQYe lekjksg

भारतीय दर्शकों के नेपाली फिल्में दिखने के लिए एनएफएआई ने 4 दिन का फिल्म समारोह (28–31 जुलाई, 2017) आयोजित किया। इसमें द ब्लैक हेल, द मास्क ऑफ डिजायर और पशुपति प्रसाद सहित कुल दस नेपाली फिल्में प्रदर्शित की गईं।

Fkkbl fQYe lekjksg

थाईलैंड के शाही महावाणिज्य दूतावास के सहयोग से एनएफएआई ने 4 और 5 अगस्त, 2017 को पुरस्कार विजेता थाई फिल्में प्रदर्शित कीं। समारोह का अन्य आकर्षण एक सांस्कृतिक नृत्य कार्यक्रम था, जो थाईलैंड की ओर से प्रस्तुत किया गया। दर्शकों को थाई व्यंजन भी परोसे गए। फिल्मों का प्रदर्शन डीसीपी फार्मेट में किया गया जो डीवीडी स्क्रीनिंग की तुलना में एक प्रमुख सुधार है।

teu fQYe lekjksg

एनएफएआई ने 19 से 21 सितंबर, 2017 के दौरान मैक्समूलर भवन के सहयोग से जर्मन फिल्म समारोह जेन नेक्स्ट 9.0 पाश्च आयोजित किया।

fo'k"k dk;Øe %

ifl) vfHkusrk fouksn [kUuk dks J)katfy%

जाने माने फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना की अप्रैल, 2017 में मृत्यु हो जाने पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 28 अप्रैल, 2017 को ‘‘अचानक’ फिल्म का विशेष प्रदर्शन किया गया।

एनएफएआई ओडिटोरियम, पुणे में लघु फिल्म देखते हुए बच्चे

एनएफएआई और अर्भात चिल्ड्रन्स फिल्म क्लब– एनएफएआई ने प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक उमेश कुलकर्णी के संगठन अर्भात फिल्म्स के सहयोग से बच्चों के लिए एक विशेष फिल्म क्लब प्रारंभ किया। 29 अप्रैल, 2017 को नंदन कुधियाड़ी द्वारा निर्देशित तीन लघु फिल्में दिखाईं। इनके नाम इस प्रकार हैं : रामानुजम, सीवी रामन और बीरबल साहनी।

एनएफएआई और मास्टर कट पिक्चर्स ने राहुल चित्तेला द्वारा निर्देशित फिल्म ^vktkn^ का प्रदर्शन किया। 7 मई, 2017 को दर्शकों से खचाखच भरे एनएफएआई ऑडिटोरियम में प्रश्नोत्तर के लिए फिल्म के कलाकार और निर्माता, निर्देशक आदि उपस्थित थे।

,u,Q,vkbl }kjk vkLdj ,dMeh dk idk'ku ^fMftVy fMyek* dk fgnh vuqokn % फिल्म संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एनएफएआई ने एकेडमी आफ मोशन पिक्चर्स आट्र्स एंड साइंस (ऑस्कर के रूप में लोकप्रिय) के प्रकाशन ‘डिजिटल डिलेमा’ के हिंदी अनुवाद की एक परियोजना शुरू की।

बदलते समय के साथ बड़ी संख्या में फिल्मों को डिजिटल रूप में सृजित, प्रदर्शित और संगृहीत किया जा रहा है, जिससे फिल्म संरक्षण की प्रक्रिया बदल रही है। इस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए कि यह बदलाव प्रचार माध्यम पर क्या असर डालेगा, मोशन पिक्चर्स आट्र्स और साइंस ने ‘डिजिटल डिलेमा’ नामक एक पुस्तक प्रकाशित की। मिल्ट शेफटर द्वारा लिखित इस पुस्तक में डिजिटल माध्यम की चुनौतियों से निपटने के उपायों पर विचार किया गया है।

uo vf/kxgr lkexh dk in'ku %

एनएफएआई ने अपने फिल्म अधिग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 4 जुलाई, 2017 को एनएफएआई द्वारा संगृहीत नए पोस्टरों, लॉबी कार्डों और पुस्तिकाओं की प्रदर्शनी लगाई।

'k#vkrh ewd fQYeksa vkSj vR;Ur nqyHk fQYeksa dh LØhfuax %

7 जुलाई 1896 को भारत में पहली बार मुम्बई में लुमियर बंधुओं ने मूक फिल्में प्रदर्शित की थीं। इस घटना की वर्षगांठ मनाने के लिए एनएफएआई ने 8 जुलाई, 2017

को odlll yhfoxx n QDVjh vkj Vu vjkbUt ,V n LVs'ku सहित 35 एमएम फार्मेट में फिल्मों का प्रदर्शन किया, जो सिनेमा के इतिहास की प्रारंभिक फिल्में थीं। इस कर्यक्रम का मुख्य आकर्षण 1911 में किनेमाकलर में बनी दिल्ली दरबार की अत्यंत दुर्लभ फुटेज का प्रदर्शन था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शकों ने हिस्सा लिया।

flusek ds vkbus ls Hkkjrh; Lora=rk vkanksyu

स्वतंत्रता दिवस मनाने के अवसर पर एनएफएआई ने रविवार, 13 अगस्त, 2017 को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। आंदोलन (1951) और झांसी की रानी (1953) जैसी फीचर फिल्मों के अतिरिक्त भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित दुर्लभ चलचित्र प्रदर्शित किए गए। इनमें नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पर बना एक दुर्लभ वृत्त चित्र भी शामिल था। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बनी फिल्मों से संबंधित पोस्टरों की एक प्रदर्शनी लगाई गई। इस कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण वरिष्ठ कलाकार सुबोध गुरुजी द्वारा अपने हाथ से फिल्म पोस्टर बनाकर दिखाना था।

ukxunk dh fo'ks"k LØhfuax%

एनएफएआई ने 9 सितंबर, 2017 को एक दुर्लभ फेंटेसी फिल्म ukxunk प्रदर्शित की, जिसमें जाने माने संगीतकार सी. रामचन्द्र ने अभिनय किया है। संगीत निर्देशक के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पहले, अभिनेता बनने के संक्षिप्त प्रयास में उन्होंने इस फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाई। फिल्म इतिहासकार श्री सुरेश चन्दवांकर कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया था।

J0;&n`'; /kjksgj fnol ds fy, fo'ks"k izn'kZuh%

यूनेस्को का श्रव्य–दृश्य धरोहर दिवस मनाने के लिए एनएफएआई ने 27 अक्तूबर, 2017 को अपने संग्रह से दुर्लभ वस्तुओं की एक प्रदर्शनी आयोजित की। इसमें मुगले आजम फिल्म के पोस्टर, लॉबी कार्ड, गीत पुस्तिकाएं, ग्लास स्लाइड्स और 6–शीट पोस्टर प्रदर्शित किए गए। दर्शकों ने क्लासिक फिल्मों से क्लिपिंग्स का भी आनंद लिया।

एनएफएआई ने एफटीआईआई के साथ संयुक्त रूप से श्रीनगर और जयपुर में 27 से 30 जुलाई, 2017 के दौरान फिल्म बोर्ड पाठ्यक्रम संचालित किया।

,u,Q,vkbZ }kjk Lo;a vk;ksftr dk;ZØe vkSj vU; laLFkkvksa }kjk vk;ksftr dk;ZØeksa ds fy,

fQYeksa dh vkiwfrZ%

भारत में फिल्म संस्कृति के प्रसार से संबंधित एनएफएआई की गतिविधियों में 25 सक्रिय फिल्म क्लब/सदस्यों के साथ वितरण लायब्रेरी; भारत में होने वाले विभिन्न स्क्रीनिंग कार्यक्रमों और फिल्मोत्सवों के लिए फिल्मों की आपूर्ति करना शामिल है। वर्ष के दौरान एनएफएआई ने फिल्मों की आपूर्ति की और अन्य संगठनों के सहयोग से विभिन्न फिल्म समारोहों का आयोजन किया।

राजा परांजपे प्रतिष्ठान ने 15 से 19 अप्रैल, 2017 के दौरान पांच दिवसीय फिल्मोत्सव का आयोजन किया। इसमें एक फिल्म एनएफएआई के संग्रह से जारी की गई।

स्वर्गीय वैंकटेश मदगुलकर की 90वीं जयंती मनाने के लिए दो दिन का पुनरावलोकन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 8 और 9 अप्रैल, 2017 को उनकी फिल्में दिखाई गईं। कुल मिला कर उनकी 4 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।

महाराष्ट्र साहित्य कला प्रसारिणी सभा पुणे ने 13 अप्रैल, 2017 को एक फिल्म शो आयोजित किया, इसके लिए फिल्म 'सामना' एनएफएआई के संग्रह से जारी की गई ।

कोच्चि फिल्म सोसायटी ने 8 और 9 अप्रैल, 2017 को जी. अरविंदन के बारे में एक पूर्वावलोकन कार्यक्रम एनएफएआई और केरल सरकार के जनसंपर्क विभाग के साथ मिल कर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के लिए एनएफएआई ने 9 फिल्में प्रदान कीं।

एनएफएआई और एनसीपीए, मुम्बई – ने संयुक्त रूप से 20 अप्रैल, 2017 को फिल्म ^ek>s cy* और 29 जून, 2017 को ^v/;kfidk* की स्क्रीनिंग की। ये दोनों फिल्में एनएफएआई के संग्रह से जुटाई गई थीं।

एनएफएआई और अक्षय फिल्म क्लब ने मिल कर आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ मनाने के सिलसिले में 13 मई, 2017 को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में डाक्यूमेंटरी प्रदर्शित की। इस अवसर पर महानायक (अंग्रेजी संस्करण) नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। समारोह के दौरान एक वेबसाइट www.azadhindyatra 2017.in का शुभारंभ भी किया गया। एनएफएआई ने अक्षय फिल्म क्लब और प्रोटेक्टटेरा इकोलॉजिकल फाउंडेशन के सहयोग से 4 जून, 2017 को पर्यावरण दिवस मनाने के सिलसिले में फिल्म ^^g;seu** की स्क्रीनिंग की व्यवस्था की। अन्य फिल्म प्रदर्शनों के अंतर्गत 1 अगस्त, 2017

को एनएफएआई के मुख्य थिएटर में मराठी फिल्म ^ukMh ogkr`*] अक्षय रोटरी क्लब द्वारा 14 सितंबर, 2017 को ^^cnu gqj**] एनएफएआई के मुख्य थिएटर में 9 अक्तूबर 2017 को ^cki tuek* का प्रदर्शन शामिल है।

पुणे स्थित डाक्यूमेंटरी फिल्म निर्माता समूह vodk'k fufeZrh ने 14 मई, 2017 को अपनी फिल्म ^^ifY'kdkjkP;k fufeRrk.k** की स्क्रीनिंग का आयोजन किया।

,lvkj,QVhvkbZ dkydkrk us ,u,Q,vkbZ ds lg;ksx ls 12 से 14 मई, 2017 के दौरान गीता सेन की फिल्मों का पूर्वावलोकन कार्यक्रम आयोजित किय. ा। एनएफएआई के संग्रह से 4 फिल्में इस समारोह के लिए भेजी गईं, जिनमें ^^dydRrk 71**, ^^dq/kkj**, ^^vdkyj lU/kku;** और ^^,d fnu izfrfnu** शामिल थीं।

हैबिटेट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल–2017 का आयोजन 20 से 28 मई, 2017 के दौरान किया गया। फिल्म समारोह के दौरान ''सिटी इन सिनेमा'' श्रृंखला के अंतर्गत फिल्म ^^uhpk uxj** प्रदर्शित की गई।

जानीमानी फिल्म अदाकारा रीमा लागू को श्रद्धांजलि स्वरूप फिल्म ^^okLro** प्रदर्शित की गई। रीमा लागू का मई, 2017 में देहांत हो गया था।

सातवें पुणे लघु फिल्म समारोह–2017 का आयोजन 9 से 13 जून, 2017 के दौरान मराठी चित्रपट परिवार की ओर से एनएफएआई के मुख्य थिएटर में किया गया।

iqLrd foekpu–10 जुलाई, 2017 को मेहता पब्लिशिंग हाउस ने प्रसिद्ध अभिनेत्री दीप्ति नवल की उपस्थिति में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया। बाद में दीप्ति नवल द्वारा निर्देशित लेकिन जारी न की गई फिल्म ^^nks iSls dh /kwi pkj vkus dh ckfj'k** की स्क्रीनिंग भी की गई।

vk;HkV 'kkWV fQYe Dyc ने 13 से 16 जुलाई, 2017 के दौरान ''शूट ए शॉट'' नामक कार्यशाला और 29 जुलाई को एनएफएआई कोथर्ड में एक फिल्म शो तथा 27 अक्तूबर को जाने माने निर्देशकों द्वारा बनाई गई अनेक लघु फिल्में और 28 अक्तूबर, 2017 को एक बाल फिल्म की स्क्रीनिंग की।

vkj-Mh- cewu की जयंती मनाने के लिए एनएफएआई ने फिल्म पंचम रीमिक्स्ड का शो आयोजित किया। फिल्म को इसके निर्देशक श्री ब्रह्मानंद ने दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया।

महाराष्ट्र सांस्कृतिक केंद्र ने 3 अगस्त, 2017 को एनएफएआई के मुख्य थिएटर में डॉ. मोहन अगाशे की फिल्म ^^dklo** की स्क्रीनिंग का आयोजन किया।

हिंदी फिल्म संगीत के प्रेमी, बी नॉस्टेल्जिक ग्रुप पुणे ने 6 अक्तूबर, 2017 को एनएफएआई के मुख्य थिएटर में श्रेष्ठ फिल्मी गीतों का प्रदर्शन और जानीमानी फिल्म समीक्षक सुलभा टर्नीकर के साथ विचार विमर्श का आयोजन किया।

निर्मिति पुणे ने 14 और 15 अक्तूबर, 2017 को एनएफएआई के मुख्य थिएटर में लघु फिल्म उत्सव आयोजित किया।

^menj bfM;k*^ की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर के एंड क्यू (किंग एंड क्वीन) क्लब पुणे ने श्री सत्येंद्र राठी की अध्यक्षता में 24 अक्तूबर, 2017 को एनएफएआई के मुख्य थिएटर में ''महबूब खान की फिल्म 'मदर इंडिया' के बारे में कही और अनकही कहानियां'' शीर्षक से एक विशाल ऑडियो–विजुअल कार्यक्रम आयोजित किया।

अक्षय फिल्म क्लब पुणे और चित्रांगण कोल्हाटकर प्रतिष्ठान, पुणे ने संयुक्त रूप से 26 अक्तूबर, 2017 को एनएफएआई के मुख्य थिएटर में ''चित्रांगण कोल्हाटकर पुरस्कार'' कार्यक्रम आयोजित किया। इसके लिए एनएफएआई पुणे द्वारा 35 एमएम फिल्म प्रिंट उपलब्ध कराया गया।

vUrjk"Vªh; fQYeksRloksa ds fy, Hkkjrh; fQYes%

अप्रैल, 2017 में स्कॉटलैंड में डुंडी कंटेम्परेरी आर्ट्स द्वारा आयोजित _fRod ?kVd iqujkoyksdu fQYeksRlo के लिए एनएफएआई के संग्रह से 5 फिल्में जारी की गईं।

एनएफएआई संग्रह में उपलब्ध 1917 में बनी एक मूक भारतीय फिल्म ^yadk ngu* की एक विशेष स्क्रीनिंग 30 जून, 2017 को बोलोग्ना, इटली में 31वें सिनेमा रिट्रोवाटो में आयोजित की गई। इसे एनएफएआई के निर्देशक ने प्रस्तुत किया।

^Hkkfedk* फिल्म (डीसीपी फार्मेट में) 14 मई 2017 को डैनिश फिल्म इंस्टिट्यूट, कोपेनहेगन में आयोजित भारतीय फिल्मोत्सव में स्क्रीनिंग के लिए भेजी गई।

10 भारतीय शास्त्रीय फिल्मों का एक पैकेज 3 से 8 जुलाई, 2017 के बीच नाडर, मोरक्को में आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा उत्सव और साझा स्मृति समारोह के लिए नई दिल्ली शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल – नई

दिल्ली डीएसएफएफ (इंटरनेशनल) को भेजा गया।

fQYe ck/k ikB;Øe

एनएफएआई और एफटीटीआई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 42वां फिल्म बोध पाठ्यक्रम 8 मई, 2017 को प्रारंभ हुआ और 3 जून, 2017 को संपन्न हुआ। समापन समारोह में जानीमानी फिल्म निर्देशिका और संपादक श्रीमती अरुणा राजे मुख्य अतिथि थीं। ,u,Q,vkbZ us 'kh r dkyhu fQYe ck/k ikB;Øe dk lapkyu esa Hkkh ,QVhVhvkbZ dk lkFk lg;kx fd;kA

ejkBh esa fQYe ck/k ikB;Øe

एनएफएआई ने एफएफएसआई (महाराष्ट्र शाखा) के सहयोग से दूसरे चरण में 10 से 16 सितम्बर 2017 के बीच 12वें फिल्म बोध पाठ्यक्रम का आयोजन किया। पाठ्यक्रम का उद्घाटन प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता श्री सचिन खेडेकर ने किया और समापन समारोह के अवसर पर वरिष्ठ फिल्म निर्देशक तथा सिनेमेटोग्राफर श्री गोविंद निहलानी उपस्थित रहे।

ikLVj in'kfu;k

fo'o iqLrd esyk

एनएफएआई ने 7 से 15 जनवरी 2017 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में हिस्सा लिया। एनएफएआई ने प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली के साथ समन्वय करते हुए प्रकाशन और अन्य अनुषंगी सामग्री मेले में प्रदर्शित की।

jktLFkku vrjk"Vh; fQYe lekjkg%

राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के हिस्से के रूप में 14 से 18 जनवरी, 2017 के बीच 53 प्रदर्शनीय वस्तुओं की एक प्रदर्शनी जयपुर में लगाई गई। इसका विषय था – आजादी के 70 साल : याद करो कुर्बानी। फिल्म जगत और फिल्म प्रेमी लोगों ने प्रदर्शनी की सराहना की।

ihvkbZ,Q,Q in'kuh

13 से 19 जनवरी, 2017 के दौरान पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह अयोजित किया गया। इसका विषय था – आजादी के 70 साल : याद करो कुर्बानी। इसका उद्घाटन प्रसिद्ध फिल्म दंपति श्री रमेश देव और श्रीमती सीमा देव ने किया। इसके अलावा एनएफएआई द्वारा प्रदान किए गए आधुनिक वर्चुअल रिएलिटी डिवाइस में एनएफएआई के वर्चुअल टूर और वर्चुअल प्रदर्शनी की सभी ने सराहना की। प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोगों ने रुचि प्रदर्शित की। फिल्म जगत के सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने प्रदर्शनी में भाग लिया।

okbZvkbZ,Q,Q in'kuh

इसी प्रदर्शनी को 20 से 26 जनवरी, 2017 के दौरान यशवंत अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोतसव, मुम्बई ले जाया गया। इसका उद्घाटन फिल्म अभिनेता श्री पंकज कपूर और राजनीतिक नेता श्री शरद पवार ने किया। यह प्रदर्शनी फिल्म जगत से जुड़े लोगों और फिल्म प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बनी।

vktknh dk 70 lky fo"k; ij in'kuh

आजादी के 70 साल विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन जयपुर में 26 जुलाई से 20 अगस्त 2017 के दौरान किया गया, जिसमें भारतीय सिनेमा में देश के स्वतंत्रता आंदोलन को दर्शाया गया। यह आयोजन फिल्म बोध पाठ्यक्रम के साथ किया गया। जयपुर कला केंद्र में 32 वस्तुएं प्रदर्शित की गईं, जो हिंदी सहित सभी भाषाओं से भारतीय सिनेमा को कवर करती थीं।

fnYyh iqLrd esyk

एनएफएआई ने प्रगति मैदान नई दिल्ली में 26 अगस्त से 3 सितंबर, 2017 के दौरान आयोजित दिल्ली पुस्तक मेले में हिस्सा लिया। अपर सचिव सुश्री जयश्री मुखर्जी ने प्रदर्शनी का दौरा किया, जिसमें प्रकाशन पोस्टर, पोस्टकाड्‌र्स, डीवीडी और काफी मग प्रदर्शित किए गए थे।

xqokgkVh vrjk"Vh; fQYekRlo

एनएफएआई ने 28 अक्तूबर से 2 नवंबर, 2017 के दौरान आयोजित गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में हिस्सा लिया और 60 भारतीय फिल्म पोस्टरों की एक प्रदर्शनी लगाई जिसमें भारतीय सिनेमा का इतिहास दर्शाया गया था। इस दौरान एनएफएआई प्रकाशनों और अनुषंगी/प्रचार सामग्री की बिक्री भी की गई।

48oka Hkkjrh; vrjk"Vh; fQYe lekjkg ¼vkbZ,Q,QvkbZ½

एनएफएआई ने 20–28 नवंबर, 2017 के दौरान गोवा में हुए 48वें आईएफएफआई में हिस्सा लिया। संगठन ने इसके लिए फिल्में प्रदान कीं और श्रेष्ठ भारतीय फिल्म पोस्टरों की एक प्रदर्शनी भी लगाई जिनमें महिलाओं से संबंधित मुद्दों को दर्शाया गया था।

lxBukRed <kpk

एनएफएआई का मुख्यालय पुणे में स्थित और इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर, कोलकाता तथा तिरूवनंतपुरम में हैं। एक निदेशक की निगरानी के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय फिल्म समितियों, शैक्षिक संस्थानों और सांस्कृतिक संगठनों के माध्यम से मुख्य रूप से अपने अपने क्षेत्र में फिल्म संस्कृति के प्रसार में लगे हैं। 3 क्षेत्रीय कार्यालयों सहित एनएफएआई के कर्मचारियों की संख्या प्रशासनिक स्कंध में 22 और तकनीकी स्कंध में 27 है।

vrjk"Vh; fQYe vfHkys[kkxkj ifjl?k

एनएफएआई मई 1969 से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार परिसंघ (एफआईएएफ) का सदस्य है। एफआईएएफ की सदस्यता एनएफएआई को विशेषज्ञ सलाह, जानकारी और परिरक्षण तकनीक संबंधी सामग्री, प्रलेखन, और ग्रंथ सूचियां आदि प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इससे एनएफएआई को अभिलेखीय आदान प्रदान कार्यक्रमों के अंतर्गत अन्य अभिलेखागारों से दुर्लभ फिल्मों के आदान प्रदान की सुविधा भी मिलती है।

ifrfu;fDr@f'k"VeMy

एनएफएआई के निदेशक ने निम्नांकित कार्यक्रमों में भाग लिया :–

1) बोलोग्ना, इटली में 28 से 29 जून, 2017 की अवधि में दूसरे सिनेमा रिट्रोवाटो फिल्मोत्सव के 31वें संस्करण।
2) अप्रैल 28–मई 3, 2017 की अवधि में 73वीं एफआईएएफ कांग्रेस और परिचर्चा एवं आम सभा।
3) सिनेमाथीक फ्रेंकाइसे पेरिस, फ्रांस और आई फिल्म इंस्टीट्यूट एम्सटर्डम का अध्ययन दौरा 6 से 10 मार्च, 2017, ताकि एनएफएआई में राष्ट्रीय फिल्म धरोहर मिशन के सफल कार्यान्वयन को देखते हुए डिजिटलीकरण और फिल्मों की बहाली के बारे में नवीनतम टेक्नोलोजी की जानकारी प्राप्त की जा सके। ये दौरे अत्यंत ज्ञानप्रद और लाभदायक सिद्ध हुए।

vk/kfudhdj.k] dEI;Vjhdj.k vkj b&xoul@b&dke l

एनएफएआई देश में फिल्म संस्कृति के प्रसार के लिए एक केंद्र के रूप में काम करते हुए भारतीय सिनेमा की विरासत हासिल करने और उसे संरक्षित करने के कार्य में भी संलग्न है। अभिलेखागार की वेबसाइट के जरिए देश के विभिन्न भागों और समूचे विश्व से सामान्य जन, सिनेमा के गंभीर अध्येता और अनुसंधानकर्ता अभिलेखागार में संगृहीत वस्तुओं और अभिलेखागार की सेवाओं तक पहुंच कायम कर सकते हैं। फिल्म बोध पाठ्यक्रमों और अनुसंधान फेलोशिप कार्यक्रमों के लिए आवेदन प्रपत्र वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। लोगों के प्रश्नों के उत्तर आमतौर पर ईमेल nfaipune@gmail.com के जरिए दिए जाते हैं। एनएफएआई के फेसबुक और ट्वीटर अकाउंट्स का भी सक्रियता से इस्तेमाल किया जा रहा है।

jk"Vh; fQYe /kjkgj fe'ku%

भारत की फिल्म धरोहर को बहाल करने और उसके संरक्षण के लिए रु. 597.41 करोड़ रुपये की ''राष्ट्रीय फिल्म धरोहर मिशन'' परियोजना मंजूर की गई है। राष्ट्रीय फिल्म धरोहर मिशन (एनएफएचएम) के अंतर्गत बनायी गई उच्च स्तरीय समिति की 4 बैठकें सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गईं, जिनमें मिशन के कार्यान्वयन के बारे में विचार किया गया। एएस एंड एफए, जेएस (फिल्म्स), डीजी (एफडी), श्री जाहनू बरुआ और एसआरएफटीआई कोलकाता के निदेशक श्री राजीव मेहरोत्रा बैठक में उपस्थित थे, जिन्होंने एनएफएआई के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व किया।

कार्मिकों की पहचान और भर्ती तथा राष्ट्रीय फिल्म धरोहर मिशन की विभिन्न गतिविधियों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी/एजेंसियां सूचीबद्ध करने के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति कर दी गई है।

jk"Vh; fQYe /kjkgj fe'ku ¼,u,Q,p,e½ d y{;

i) फिल्म संग्रह में फिल्म की स्थिति का मूल्यांकन करना और किसी फिल्म के शेष बचे जीवन का पता लगाना।

ii) 1,32,000 फिल्म रीलों का निवारक संरक्षण।

iii) भारतीय सिनेमा की 1086 ऐतिहासिक फीचर फिल्मों और 1152 लघु फिल्मों की 2के/4के पिक्चर एवं ध्वनि बहाल करना तथा प्रत्येक फिल्म की नई पिक्चर और साउंड इंटर नेगेटिव्स की रिकार्डिंग।

iv) 1160 फीचर फिल्मों और लघु फिल्मों का डिजिटीकरण।

v) एनएफएआई कैम्पस, पुणे में एनएफएचएम के अंतर्गत बहाल की गई सामग्री को धूल मुक्त, न्यूनतम आर्द्रता और कम तापमान स्थितियों में संरक्षित करने के लिए अभिलेखीय और संरक्षण सुविधाओं का निर्माण।

vi) संरक्षण, परिरक्षण और संग्रहण के लिए इन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ एजेंसियों के साथ समन्वय करते हुए प्रशिक्षण कार्यशालाओं और पाठ्यक्रमों का आयोजन।

fFk,Vj lfo/kk,¡%

एनएफएआई के पास तीन बहु–प्रयोजनीय थिएटर हैं। इनमें मुख्य परिसर में 35 सीटों का एक प्री–यू थिएटर और 300 सीटों का मुख्य थिएटर तथा कोथर्ड में 200 सीटों का एक कला थिएटर शामिल है। इसके अलावा अन्य थिएटरों में पुणे में मैक्स मूलर भवन, एलाइंस फ्रेंकाइसे और ब्रिटिश काउंसिल परिसर में स्वयं के लिए और एनएफएआई फिल्म सर्कल सदस्यों के लिए नियमित आधार पर स्क्रीनिंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्ष के दौरान मुख्य ऑडिटोरियम और प्री–व्यू थिएटर को 311 कार्यक्रमों के लिए किराए पर दिया गया।

fuekrkvk@dkihjkbV ekfydk d fy, lfo/kk,

एनएफएआई निर्माताओं/कॉपीराइट धारकों को उनके मूल नेगेटिव्स की मरम्मत करने, डुप्लीकेट प्रतियां तैयार करने और टेलीकास्ट प्रयोजनों के लिए वीडियो कॉपी करने जैसे कार्यों में सेवाएं प्रदान करता है। एनएफएआई के संग्रह से राष्ट्रीय और उपग्रह नेटवर्कों पर अनेक सेल्युलॉयड क्लैसिक्स टेलीकास्ट किए जाते हैं।

vuyXud&d

वर्ष के दौरान अभिलेखागार में जोड़े गए कुछ महत्वपूर्ण नए टाइटल इस प्रकार हैं :–

ukbfdfupk lt k & 35 एमएम/पिक्चर और साउंड नेगेटिव/मराठी

xr inyh Vdk Vd & 35 एमएम/पिक्चर और साउंड नेगेटिव/मराठी

gkfre rkb dh cVh & 16 एमएम/हिंदी

,d fnu dk ckn'kkg & 16 एमएम/हिंदी

xy&,&cdkoyh& 16 एमएम/हिंदी

yfEex&35 एमएम/विदेशी फिल्म

bUo'kUl ckjcjl & 35 एमएम/विदेशी फिल्म

n chV nV ekb gkV fLdIM & 35 एमएम/विदेशी फिल्म

dku g dcV &(किंग्स नेम) – 35 एमएम/विदेशी फिल्म

xjk or & 35 एमएम/विदेशी फिल्म

,y&,UQV & 35 एमएम/विदेशी फिल्म

jke jke xxkjke & 35 एमएम/मराठी

rep vkepk teyk & 35 एमएम/मराठी

1000 Fkkykb oxl ;k viol fprke.kh & 35 एमएम/तमिल

dykFkj dUuek& 35 एमएम/तमिल/पिक्चर और साउंड नेगेटिव

o/kkykykxk& 35 एमएम/तमिल/पिक्चर और साउंड नेगेटिव

vfHkeku &35 एमएम/कन्नड

efFkuk gkjk & 70 एमएम/कन्नड

vkxrd& 35 एमएम/कन्नड

uEek Hkfe & 35 एमएम/कन्नड

peRdkj & 35 एमएम/कन्नड

ed el t; gejh tku & भोजपुरी/2002 35 एमएम

ohj fogky & गुजराती /1980 35 एमएम

vokuk vk/kk nh vk/kkfj;k & भोजपुरी/2013 35 एमएम

eUuk ctjxh & भोजपुरी/2009 35 एमएम

ykxhyxu Hkkyukfk dh & भोजपुरी/2009/35 एमएम

viuh ckyh viukn'k&भोजपुरी/2009 35 एमएम

'kMk & हिंदी/2009/35 एमएम आरपी

fcYoexy&मूक/1919/श्वेत श्याम/35 एमएम

vkVe bu U;;kdl&अंग्रेजी/2000/35 एमएम

lidh gkml & अंग्रेजी/2000/35 एमएम

foMhxk & अंग्रेजी/1978/35 एमएम

e;kyk jkEeUuk & गुजराती/2010/35 एमएम

ckefjYy & तेलुगू/2006/35 एमएम

nojkuh tBkuh&गुजराती/1985/16 एमएम

jfl;k ckye&गुजराती/1993/16 एमएम

le;kuh lkrkddkMh&गुजराती/1989/16 एमएम

'kh'k egy ¼mQ enhuk t;k½ &गुजराती/16 एमएम

ekufouh Hkobl& गुजराती/16 एमएम

cxjkMk eu"; & कन्नड

HkDr decjk & कन्नड

eFkknkuk & कन्नड/2001/35 एमएम

अनुलग्नक–ख

31 दिसंबर, 2017 को अभिलेखीय प्राप्ति दिखाने वाला वर्णन

मद	31.03.2017 को	1.4.2016 से 31.10.2017 तक	31.12.2017 को
फिल्में	19098	196	21224
वीडियो कैसेट्स	2,798	222	3348
डीवीडी	2,654	189	3140
पुस्तकें	29329	412	5949
पटकथाएं	38575	150	42625
पहले से रिकार्डिड ऑडियो कैसेट्स	1,098	--	1098
अचल चित्र (स्टिल्स)	156316	7926	1658844
वाल पोस्टर्स	28206	1464	32637
गाना पुस्तिकाएं	2742	1360	4512
ऑडियो टेप्स (वाचिक परंपरा)	191	--	191
प्रेस क्लिपिंग्स	2,05,619	1312	227624
पंफलेट्स/फोल्डर्स	8915	91	9906
स्लाइड्स	8,576	--	8576
डिस्क रिकॉर्ड्स	3,214	--	3214
ऑडियो कम्पैक्ट डिस्क	155	--	155
अनुशंगी फिल्म सामग्री का डिजिटीकरण	3,70,220	--	370220

एनएफएआई की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में आंकड़े

रीलों/फिल्मों की संख्या	16 एमएम	35 एमएम
1. फिल्मों की व्यापक जांच	–	150
2. फिल्मों की नियमित जांच	–	3287
3. रीलों की नियमित जांच	–	5319
फिल्म संस्कृति का सम्प्रेषण		
1. वितरक पुस्तकालय सदस्य	35	
2. वितरक पुस्तकालय सदस्यों को आपूर्ति की गई फिल्मों की संख्या	30	
3. विशेष अवसरों पर आपूर्ति की गई फिल्में	45	
4. संयुक्त स्क्रीनिंग	20	
5. फिल्म बोध पाठ्यक्रमों के लिए आपूर्ति की गई फिल्में	50	
6. अनुसंधान कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराई गई फिल्म देखने की सुविधाएं	30	
7. शैक्षिक स्क्रीनिंग के लिए एफटीआईआई को आपूर्ति की गई फिल्में	144	
8. एनएफएआई में फिल्म शो की संख्या	350	
9. पुस्तक लायब्रेरी सेवा प्राप्त करने वाले पाठकों की संख्या	1500	
10. अनुसंधानकर्ताओं की संख्या, जिन्होंने डाक्युमेंटेशन अनुभाग की सेवाएं प्राप्त कीं	500	
11. एनएफएआई में आने वाले दर्शकों की संख्या	40,000	

fQYe lekjkg funs'kky; ¼Mh,Q,Q½

फिल्म समारोह निदेशालय ने वर्ष भर कई फिल्म उत्सवों और बाजारों का आयोजन किया/में हिस्सा लिया। इनमें से कुछ प्रमुख का विवरण नीचे दिया गया है :–

1. महात्मा गांधी फिल्मोत्सव का आयोजन मोतीहारी, बिहार में 14–16 अप्रैल, 2017 की अवधि में किया गया। यह फिल्मोत्सव महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चलाए गए चम्पारण सत्याग्रह की शताब्दी के उपलब्ध में आयोजित किया गया। इसका आयोजन महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी के सहयोग से किया गया।
2. तीन दिन के भारतीय फिल्मोत्सव का आयोजन भारतीय उच्चायोग के सहयोग से 10 से 12 अप्रैल, 2017 के दौरान सिंगापुर में नेशनल यूनिवर्सिटी आफ सिंगापुर (एनयूएस) कैम्पस में आयोजित किया गया। फिल्मोत्सव का उद्घाटन सिंग.ापुर में भारत के उच्चायुक्त जावेद अशरफ ने किया। इस अवसर पर संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी विभिन्न भाषाओं में दिखाई गई। फिल्मोत्सव के दौरान विभिन्न भाषाओं में प्रदर्शित फिल्मों में मंत्र (अंग्रेजी), चित्रोकर (बांग्ला) और इरुधीसुत्रु (तमिल) शामिल थीं।
3. तीन दिवसीय 'राष्ट्रभक्ति' और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' फिल्म समारोह का आयोजन 26 से 28 अप्रैल 2017 के दौरान जोधपुर में जिला प्रशासन जोधपुर और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से किया गया। इसमें प्रदर्शित की गई फिल्मों में शहीद (उद्घाटन फिल्म), आई एम कलाम, लोकमान्य–एक युगपुरुष, छोटा सिपाही, इकबाल (समापन फिल्म) शामिल थीं। समारोह में ''एक भारत श्रेष्ठ भारत'' के तत्वावधान में पश्चिम बंगाल से दो फिल्में – सहज पाथेर गप्पो और कादम्बरी प्रदर्शित की गई।

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (एनयूएस) में भारतीय फिल्मोत्सव

4. 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 3 मई, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान वर्ष 2016 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जाने माने फिल्म निदेशक और पटकथा लेखक श्री के विश्वनाथ को प्रदान किया।

भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 3 मई, 2016 को विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में 113 पुरस्कार विजेताओं को 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार –2016 प्रदान किए। इनमें 20 स्वर्ण पदक, 101 रजत पदक और 13 विशेष उल्लेख शामिल थे। प्रमुख पुरस्कार विजेताओं में श्री अक्षय कुमार, श्री मोहन लाल, श्री हाओबम पबन कुमार, सुश्री संतवना बारदोलोई, श्री आदिल हुसैन, सुश्री सोनम कपूर आदि शामिल थे।

4 से 17 मई, 2017 के दौरान राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मों का सार्वजनिक प्रदर्शन सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में किया गया। इस दौरान 39 फीचर और 26 गैर–फीचर फिल्मे दिखाई गई। उद्घाटन फिल्मों के रूप में 'फायर फ्लाईज़ इन द एबिस' (गैर–फीचर फिल्म) और फीचर फिल्म 'कासव' (मराठी) का प्रदर्शन किया गया। उद्घाटन समारोह में उद्घाटन फिल्मो के निर्देशक श्री चन्द्रशेखर रेड्डी, सुश्री सुमित्रा भावे और श्री सुनील सुखथांकर उपस्थित थे।

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मों की सार्वजनिक स्क्रीनिंग 18 मई से 14 जून, 2017 के दौरान मक्विनेज पैलेस, पंजिम, गोआ में भी की गई। इस दौरान 39 फीचर फिल्में और एक गैर–फीचर फिल्म दिखाई गई।

5. सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 6 मई, 2017 को यूनेस्को, नई दिल्ली और सक्षम ट्रस्ट के सहयोग से एक्सेसिबल सिनेमा यानी सुगम सिनेमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 6 मई, 2017 को सिरी फोर्ट आडिटोरियम में दिव्यांग जनों के लिए 'फिल्म निर्माण अनुभव' की एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य श्रव्य वर्णन विशेषताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना था, जिन्हें उप–शीर्षकों के साथ

श्री अक्षय कुमार ने 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार–2016 के दौरान फिल्म रुस्तम के लिए सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी, माननीय पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू और माननीय सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

सुश्री सुरभि 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार–2016 में माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से मलयालम फिल्म 'मिन्नामिनन्गु' (जुगनू) के लिए सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

जोडकर कोई भी दृष्टि और/या श्रवण बाधित व्यक्ति फिल्म का आनंद सामान्य व्यक्ति की तरह ले सकता है। कार्यशाला के बाद लोकप्रिय हिंदी फिल्म 'दंगल' दिखाई गई।

6. बाल फिल्मोत्सव (कांकेर छत्तीसगढ़) का आयोजन 5 से 20 मई 2017 के दौरान फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा कांकेर जिला प्रशासन के सहयोग से ग्रीष्म शिविर–उमंग 2017 ''चाहतों की उड़ान'' के हिस्से के रूप में कांकेर, छत्तीसगढ़ में किया गया। कांकेर में ग्रीष्म शिविर–उमंग 2017 ''चाहतों की उड़ान'' के दौरान राष्ट्रभक्ति की कुल 5 फीचर फिल्में दिखाई गईं। इनमें 'आई एम कलाम', 'छोटा सिपाही', 'नेताजी सुभाष चन्द्र बोस–द फोरगटन हीरो', 'दुरंतो एंड सरदार' शामिल थीं। स्क्रीनिंग के लिए कोई टिकट नहीं रखा गया था और दर्शकों को पहले आओ पहले पाओ आधार पर हाल में प्रवेश की अनुमति दी गई थी।

7. यूरोपीय संघ फिल्मोत्सव का आयोजन 9 से 16 जून 2017 के दौरान सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम–2 में किया गया। इसमें एस्टोनिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, बुलगारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, लात्विया, लक्जम्बर्ग, हालैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और स्पेन की कुल 22 फीचर फिल्में प्रदर्शित की गईं।

8. डीएफएफ ने दक्षिण–पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के चेगडू में 23 जून से 27 जून 2017 के दौरान आयोजित दूसरे ब्रिक्स फिल्म समारोह में हिस्सा लिया। समारोह के दौरान गैर–प्रतियोगी वर्ग में 5 फीचर फिल्में प्रदर्शित की गईं। ये हैं – कसाव, लोकतक लाइरेम्बी, बाहुबली : द बिगनिंग एंड कंक्लुजन, कारवां और आवारा। प्रतियोगी वर्ग में एक फिल्म अर्थात् 'लेडी आफ द लेक' दिखाई गई। भारतीय फिल्म दिवस का शुभारंभ मराठी फीचर फिल्म कसाव के साथ हुआ, जिसे समारोह के दौरान सर्वोत्कृष्ट अभिनेता पुरस्कार से नवाजा गया।

9. एफटीटीआई पुणे ने डीएफएफ के सहयोग से तीन पाठ्यक्रमों – 11 से 30 जून, 2017 के दौरान अभिनय में फाउंडेशन कोर्स तथा लेखन में फाउंडेशन कोर्स और 23–26 जून, 2017 के दौरान फिल्म बोध पाठ्यक्रम का आयोजन सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में किया। इन पाठ्यक्रमो में कुल 137 प्रतिभागियों ने फिल्म बोध पाठ्यक्रम, 30 ने अभिनय पाठ्यक्रम और 25 प्रतिभागियों ने लेखन पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किए।

10. प्रतिष्ठित फिल्म कार्यक्रम, तेल अवीव अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का आयोजन जुलाई 18–22, 2017 के दौरान इस्राइल में किया गया, जिसमें 2 भारतीय फिल्में – 'आई एम कलाम' और 'बुधिया सिंह बोर्न टू रन' – दिखाई गईं। डीएफएफ ने इस्राइल में भारतीय दूतावास

को अंग्रेजी उप–शीर्षकों के साथ वांछित फार्मेट में फिल्में उपलब्ध कराईं।

11. देशभक्ति और एक भारत–श्रेष्ठ भारत विषय पर देश के विभिन्न शहरों में कई फिल्म समारोह आयोजित किए गए, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

i. गुरदासपुर, पंजाब में 22 से 23 जुलाई, 2017 के दौरान फिल्म गांधी, सुभाष चन्द्र बोस, छोटा सिपाही, आई एम कलाम, शहीद, लगान का प्रदर्शन गुरदासपुर फिल्म समारोह के अंतर्गत किया गया। 'लोकमान्य एक युगपुरुष', 'एलिजाबेथ एकादशी' का प्रदर्शन एक भारत–श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया।

ii. उत्तरी गोआ में 14 से 16 अगस्त, 2017 के दौरान पणजी के आसपास विभिन्न स्कूलों को आमंत्रित किया गया और समारोह के दौरान लोकमान्य तिलक, सुभाष चन्द्र बोस–द फोरगटन हीरो और सरदार फिल्मे प्रदर्शित की गईं। सभी तीनों दिन स्कूलों में मार्निंग शो के दौरान ये फिल्में दिखाई गईं।

iii. डिब्रूगढ़, असम में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए 15 अगस्त, 2017 को कुहखल और गांधी नामक दो फिल्में प्रदर्शित की गईं। समारोह के दौरान विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के भारत सरकार के प्रयास के हिस्से के रूप में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के तत्वावधान में हिंदी फिल्म 'ओए लक्की लक्की ओए' प्रदर्शित की गई।

विद्यार्थी ''एक भारत श्रेष्ठ भारत'' फिल्मोत्सव में भाग लेते हुए।

iv. रायगढ़, महाराष्ट्र, जहां जिला प्रशासन के सहयोग से डीएफएफ द्वारा प्रदान की गई 3 फिल्में – गांधी, लोकमान्य–मैन आफ द ऐज और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित की गईं। समारोह में ओडिसा से संबंधित फिल्म 'आदिम विचार' भी दिखाई गई।

v. तवांग, अरुणाचल प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में 15 अगस्त, 2017 को 3 फिल्मों का एक पैकेज दिखाया गया, जिसमें गांधी, शहीद, कुहखल शामिल थीं। समारोह के दौरान विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान–प्रदान को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित फिल्म 'मसान' भी प्रदर्शित की गई।

vi. दीव में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए 15 अगस्त, 2017 को तीन फिल्में – सरदार, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और वीर सावरकर प्रदर्शित की गईं। समारोह में एक तमिल फिल्म इरूधी सुत्तरू भी दिखाई गई।

vii. लुंगलेई, मिजोरम में 15 अगस्त, 2017 में तीन फिल्में –चिटगोंग, शहीद और कुहखल दिखाई गईं। विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान–प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए समारोह में 'यार्वंग रूट्स' (त्रिपुरा) और मिथिला मखान (बिहार) भी प्रदर्शित की गईं।

viii. बीकानेर, राजस्थान में 15 अगस्त, 2017 को तीन फिल्में – आई एम कलाम, सरदार और चक दे इंडिया का प्रदर्शन किया गया। शंकचिल, नटोकर मोटो नामक फिल्म भी स्क्रीन की गई।

ix. जम्मू कश्मीर में लेह–लद्दाख में राष्ट्रभक्ति की 6 फिल्में दिखाई गईं।

x. बिहार में राजगीर में देशभक्तिपूर्ण 6 फिल्में प्रदर्शित की गई।

xi. जबलपुर, मध्य प्रदेश में देशभक्तिपूर्ण 6 फिल्में प्रदर्शित की गई।

xii. शिमला, हिमाचल प्रदेश में देशभक्तिपूर्ण 6 फिल्में स्क्रीन की गईं।

xiii. चंडीगढ़ में देशभक्तिपूर्ण 5 फिल्में दिखाई गईं।

12. भारत समारोह– 2017 का आयोजन भारतीय उच्चायोग के सहयोग से थाईलैंड में किया गया,

जिसमें भारत–आसियान संबंधों की 25वीं वर्षगांठ मनाने के सिलसिले में 2 से 5 अगस्त, 2017 के दौरान 'धूम–3' (थाई भाषा में डब की गई) की कई बार गैर–व्यावसायिक स्क्रीनिंग आयोजित की गई। भारत और थाईलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत फिल्मोत्सव–2017 के हिस्से के रूप में 12–13 अगस्त, 2017 को भी इस फिल्म को स्क्रीन किया गया।

13. ''लात्विया में भारत के दिन और स्टॉकहोम सांस्कृतिक उत्सव में फिल्म सप्ताह'' नाम का फिल्मोत्सव अगस्त महीने में स्टॉकहोम स्थित भारतीय दूतावास के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें निम्नांकित फिल्में प्रदर्शित की गईं :–

क. ओटटल

ख. नचोमिया–कुम्पासर

ग. जाने भी दो यारो

घ. जिंदगी न मिलेगी दोबारा

ङ द मेकिंग आफ महात्मा

14. सिंगापुर उच्चायोग के सहयोग से तीन दिन का सिंगापुर फिल्मोत्सव 1 से 3 सितंबर, 2017 के दौरान नई दिल्ली के सिरी फोर्ट आडिटोरियम में आयोजित किया गया। फिल्मोत्सव के दौरान के दौरान दिखाई गई 5 फिल्मों के पैकेज में कान में चुनी गई दो फिल्मे – ए येलो बर्ड और अप्रेंटिस–शामिल थीं। प्रत्येक फिल्म के प्रदर्शन के बाद उसके निर्माताओं और विशेषज्ञों के साथ वार्तालाप का भी आयोजन किया गया। फिल्मोत्सव के अंतिम दिन 'शिन याओ' (अर्थात् मंडारियन में सिंगापुर के गीत) को समर्पित संगीत उत्सव भी आयोजित किया गया। शिन याओ सिंगापुर की एक विशिष्ट संगीत शैली है, जो फिल्मोत्सव का अतिरिक्त आकर्षण बनी।

15. मैसूर में भारतीय पैनोरमा फिल्मोत्सव, जिसके अंतर्गत 19 भारतीय पैनोरमा फिल्मों का एक पैकेज कर्नाटक चलनचित्र अकादमी को भेजा गया, ताकि वह उन्हें 21 से 28 सितंबर, 2017 के दौरान दशहरे के अवसर पर प्रदर्शित कर सके।

16. छठा भारतीय फिल्मोत्सव कोरिया गणराज्य और सोल स्थित भारतीय दूतावास के सहयोग से सोल में बुसान सिनेमा सेंटर में 28–29 अक्तूबर, 2017 को आयोजित किया गया। समारोह के दौरान 4 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्में प्रदर्शित की गईं, जिनमें नीरजा, पिंक, 24 और महेशिंते प्रतिकरम शामिल थीं। विभिन्न प्रकार की अन्य गतिविधियों ने भी समारोह में भीड़ का ध्यान आकर्षित किया, जिनमें कैरम अनुभव, भारतीय चाय का अनुभव, मेकिंग इंडियन पेपर फीगर्स, मेक इन इंडिया शोरूम, भारतीय भोजन का अनुभव, भारतीय परिधान का अनुभव आदि शामिल थीं।

17. दिव्यांगजन सशक्तिकरण लघु फिल्म प्रतियोगिता, 2017 – निदेशालय ने माननीय मंत्री श्री थावर चंद गहलोत की उपस्थिति में विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से दिव्यांग सशक्तिकरण लघु फिल्म प्रतियोगिता समारोह आयोजित किया। इसमें डाक्युमेंटरी, लघु फिल्में और टीवी स्पॉट्स की तीन श्रेणियों के अंतर्गत दस फिल्मों ने पुरस्कार जीते।

कार्यक्रम के दौरान भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) के विद्यार्थियों ने संकेत भाषा में राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया। इसके बाद एएलपीएएनए से विकलांगजन विद्यार्थियों द्वारा फ्यूजन डांस (मिश्रित नृत्य) प्रस्तुत किया। इसके बाद अमर ज्योति चेरिटेबल ट्रस्ट से विशेष रूप में सक्षम बच्चों ने घूमर नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम के अंत में पुरस्कार विजेताओं की पूर्ण फिल्में प्रदर्शित की गईं।

18. सोल स्थित भारतीय दूतावास और कोरिया गणराज्य के सहयोग से निदेशालय ने दक्षिण कोरिया में सोल में 14 से 18 नवंबर, जेजू में 21 से 26 नवंबर और संचन में 24 से 26 नवंबर, 2017 के दौरान भारतीय फिल्मोत्सव का आयोजन किया। समारोह के दौरान 5 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्में दिखाई गईं जिनमें नीरजा (हिंदी) पिंक (हिंदी), 24 (तमिल), महेशिंते प्रतिकरम (मलयालम) और वेंटिलेटर (मराठी) शामिल थीं।

19. कोलम्बो में 21 से 25 नवंबर, 2017 के दौरान सार्क फिल्मोत्सव आयोजित किया गया। डीएफएफ ने भारतीय पैनोरमा से चुनी गई पांच फिल्में निर्दिष्ट कीं ताकि उन्हें सार्क फिल्मोत्सव के विभिन्न खंडों में दिखाया जा सके। पिंकी ब्यूटी पार्लर (हिंदी) और ओनाताह (खासी) को फीचर श्रेणी में और तांडव (हिंदी) और आर्मीउडे अंतिवारामबूकल (मलयालम) को गैर–फीचर फिल्म में प्रतियोगिता खंड के लिए नामित किया गया। जानेमाने फिल्मकार जयराज वीरम मेक्बेथ (मलयालम) की अद्यतन फिल्म मास्टर सेक्शन भी स्क्रीन की गई।

20. अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव और साझा स्मृति का छठा संस्करण –नाडोर, मोरक्को में 7 से 12 नवंबर, 2017 के दौरान आयोजित किया गया। प्रतियोगिता खंड और पुरानी भारतीय क्लासिक फिल्मों के खंड के लिए डीएफएफ द्वारा दो अलग अलग फिल्म पैकेज भेजे गए। 8 नवंबर, 2017 को ''भारतीय सबक – कला की एकता और विविधता'' शीर्षक से एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया। सम्मेलन में 200 से अधिक आमंत्रित व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, जिनमें मोरक्को और विदेशों के प्रमुख बुद्धि जीवी तथा मीडिया से जुड़े लोग शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान भारत और भारतीय संस्कृति पर ध्यान केंद्रित रहा, जिसमें भारतीय सिनेमा, संगीत और नृत्य के प्रति भारी आकर्षण दिखाई दिया और मोरक्को समुदाय में भारतीय फिल्मी हस्तियों के प्रशंसकों की बड़ी संख्या देखी गई।

21. भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव

भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव (आईएफएफआई) भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 20 से 28 नवंबर, 2017 के दौरान गोआ में आयोजित किया गया। पहली बार फिल्मोत्सव का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) द्वारा किया गया। इस आयोजन में पहले की तरह गोआ सरकार की ओर से एंटरटेनमेंट सोसायटी आफ गोआ ने भागीदार की भूमिका निभाई। समारोह का विषय था – ''सिनेमा के भविष्य का उत्सव''।

- फिल्मोत्सव 9 दिन तक चला, जिसमें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की स्क्रीनिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया। इनमें अनेक वैश्विक, अंतर्राष्ट्रीय, एशियाई और भारतीय प्रीमियर फिल्मों की स्क्रीनिंग, विशेष प्रस्तुतिकरण, कलाकारों की उपस्थिति के साथ बड़े रेड कार्पेट समारोह, मास्टर क्लासिज़, परिचर्चाएं, मिक्स्ड रियलिटी साइडबार, सह–निर्माण सेमिनार, मुक्ताकाश स्क्रीनिंग, संवाददाता सम्मेलन और 4 दिवसीय फिल्म बाजार जैसे कार्यक्रम शामिल थे। फिल्म बाजार का आयोजन पहली बार आईएफएफआई के बैनर तले किया गया था।

- इस वर्ष की संचालन समिति के सदस्य जाहनू बरुआ, सिद्धार्थ राय कपूर, भारत बाला, आनंद गांधी, प्रसून जोशी, वानी त्रिपाठी, पीयूष पांडेय, शाजी एन करुण, मेरेनइम्चेन, अश्विनी अय्यर तिवारी, नागेश कुकुनूर, शूजीत सरकार और एनएफडीसी के निदेशक तथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्मो की प्रीव्यू समिति में खालिद मोहम्मद, आरती बजाज, रमेश पांगे, नरेश चन्द्र लाल, नरेंद्र कोहली, विवेक अग्निहोत्री, साइबल चटर्जी, अभिमन्यु सिंह, भावना सोमाया, जीवित राजशेखर, गौतमी ताडिमल्ला, नितेश तिवारी, जीएस भास्कर, पल्लवी जोशी, अनिरुद्ध राय चौधरी, राजा कृष्ण मेनन, सिद्धार्थ काक, तरुण कैटियल, अभिषेक बासु, हर्षिता भट्ट, अभिषेक जैन, संतवान बार्दोलोई, भास्कर हजारिका, प्रदीप कुरबाह, डोमिनिक मेगम, मैपाक्सना हाओरोंगबम, जुआला छांग्टे, सचिदानंद जोशी, भारत गुप्त, निर्मला शर्मा, राठी विनय झा, राजेश कुमार सिंह, संगी दोरजी, अनिल रस्तोगी, पुनीत अस्थाना, भुमेंजॉय कोंसम, अजय कुमार मल्कानी और लवलीन थाडानी सदस्य के रूप में शामिल थे।

गोवा में भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई) के उद्घाटन के अवसर पर कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए कलाकार।

- समारोह का भव्य उद्घाटन कार्यक्रम 20 नवंबर को श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम तलईगांव गोवा में आयोजित किया गया। इस अवसर पर माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी और गोआ के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर के साथ अनेक कलाकार उपस्थित थे। शाहरुख खान ने समारोह के उद्घाटन की घोषणा की। संयोजकों में राजकुमार राव और राधिका आप्टे जैसे कलाकार शामिल थे। अन्य प्रमुख

भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई) की अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के सदस्य।

फिल्मी हस्तियों में श्रीदेवी और बोनी कपूर, सुभाष घई, अनुपम खेर, नाना पाटेकर, शाहिद कपूर, एआर रहमान और कई अन्य कलाकार शामिल थे।

- समारोह की उद्घाटन फिल्म के रूप में ईरान के प्रमुख फिल्मकार माजिद मजिदी की बियोंड द क्लाउड्स दिखाई गई। इस फिल्म में भारतीय कलाकारों और कर्मियों ने काम किया है, जिसका भारतीय प्रीमियर कला अकादमी में किया गया था। फिल्म का परिचय इसके कलाकारों और निर्माताओं के साथ माजिद मजिदी द्वारा दिया गया। इनमें संगीत निर्देशक एआर रहमान, लेखक विशाल भारद्वाज पहली बार फिल्म अभिनय करने वाले ईशान खट्टर और अभिनेत्री मलाविका मोहनम उपस्थित थे।

- समारोह के फिल्म कार्यक्रम के अंतर्गत 82 देशों से 195 फिल्में प्रदर्शित की गईं। यह इस बात का प्रमाण था कि कार्यक्रम का सिनेमाई विस्तार अंतर्राष्ट्रीय विविधता लिए हुए है। इन फिल्मों में वैश्विक फिल्मोत्सवों में शामिल की जाने वाली कई जानी मानी फिल्में, अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्में, भारत और विदेश से पहुंची गई असाधारण फिल्में शामिल थीं। इनमें 10 विश्व प्रीमियर, 10 एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर और 64 भारतीय प्रीमियर फिल्में शामिल थीं, जो आधिकारिक कार्यक्रम का हिस्सा बनीं।

- समारोह में विशेष रूप से बनाए गए बांड रिटरोस्पेक्टिव खंड के अंतर्गत 1962 से 2012 के बीच बनी 12 बांड फिल्में प्रदर्शित की गईं।

- रीस्टोर्ड क्लासिक सेक्शन के अंतर्गत गोडार्ड, ओज़ू, हिचकोक, बुनुएल, फ्रित्ज़लोंग और अन्यों द्वारा निर्मित सिनेमेटिक इतिहास की 8 हॉलमार्क फिल्में प्रदर्शित की गईं। समारोह का विशेष आकर्षण हाल ही में पुनर्जीवित की गई तार्कोवस्की की अंतिम लिजेंडरी फिल्म सेक्रीफाइस का भारतीय प्रीमियर था।

- जानीमानी अभिनेत्री श्रीदेवी भारतीय पैनोरमा के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य सम्मानित अतिथि थीं। उद्घाटन कार्यक्रम इनोक्स–2 में 21 नवंबर, 2017 को किया गया। भारतीय पैनोरमा की उद्घाटन फिल्म के रूप में विनोद काकरी की पिहु (फीचर फिल्म) और कमाल स्वरूप की पुष्कर पुराण (गैर–फीचर फिल्म) दिखाई गई। भारतीय पैनोरमा खंड के अंतर्गत 42 फिल्में दिखाई गई जिनमें 26 फीचर फिल्में शामिल थीं, जिनका चयन 154 पात्र प्रविष्टियों में से किया गया था। इसी तरह 21 गैर–फीचर फिल्में शामिल की गई जिनका चयन 154 पात्र प्रविष्टियों में से किया गया था।

अभिनेता श्री शाहरूख खान भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई) के अवसर पर माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के साथ वार्तालाप करते हुए।

● 48वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2017 के दौरान 2017 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता निर्देशक के. विश्वनाथ की तीन फिल्में दिखाई गई थीं, जो इस पश्चदर्शन के उद्घाटन के अवसर पर मौजूद थे।

● लगातार दूसरे वर्ष, एक्सेसिबल इंडिया फिल्म्स के अंतर्गत विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों के लिए सीक्रेट सुपर स्टार और हिंदी मीडियम फिल्म प्रदर्शित की गई। एक्सेसिबल इंडिया आईएफएफआई, सक्षम भारत और यूनेस्को के बीच एक सहयोगी संगठन है, जिसका लक्ष्य दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी फिल्मों को प्रोत्साहित करना है।

● आईएफएफआई 2017 के दौरान पिछले वर्ष दिवंगत हुई फिल्म उद्योग की जानीमानी हस्तियों को श्रद्धांजलि के रूप में उनकी प्रभावशाली और स्थायी सिनेमेटिक विरासत से चुनी हुई फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।

● इस वर्ष ओम पुरी, अब्दुल माजिद, विनोद खन्ना, टॉम आल्टर, रीमा लागू, जे जयललिता, कुंदन शाह, दसारी नारायण राव और रामानंद सेनगुप्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जोगर्स पार्क में 'जाने भी दो यारों' की विशेष मुक्ताकाश स्क्रीनिंग की गई, जिसमें फिल्म के कलाकारों और निर्माताओं में से सतीश कौशिक, नीना गुप्ता, रंजीत कपूर और सुधीर मिश्रा उपस्थित थे।

● आईएफएफआई 2017 में कंट्री फोकस के अंतर्गत कनाडा पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके लिए टेलीफिल्म्स कनाडा के सहयोग से टोरंटो इंट. रनेशनल फिल्म फेस्टिवल द्वारा उपलब्ध कराई गई फिल्में दिखाई गईं। कनाडा फिल्म उद्योग से निर्देशकों, अभिनेताओं और फिल्म व्यवसायियों के 19 सदस्यों के शिष्टमंडल की उपस्थिति में फोकस के अंतर्गत कुल 8 फिल्में प्रदर्शित की गईं। इस वर्ष के फोकस की सफलता में कनाडा उच्चायोग द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलनों, एक सह–फिल्म निर्माण सेमिनार और भव्य रिसेप्शन का विशेष योगदान रहा। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त महामहिम श्री नादिर पटेल ने फिल्मोत्सव और समापन समारोह में हिस्सा लिया।

जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई) के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए

● संगठन में एक नई पहल मिक्स्ड रियलिटी साइडबार के अंतर्गत सिनेमा का भविष्य कार्यक्रम को मंजूरी दी गई जिसके अंतर्गत एआर/वीआर प्रदर्शनी तथा परिचर्चाएं और डिजिटल युग में वर्चुअल रियलिटी के उदय और उभरती हुई सिनेमा प्रवृत्तियों पर उसके परिवर्तनकारी प्रभाव के बारे में मास्टर क्लासेज का आयोजन किया गया। इसका संचालन इंग्लैंड के क्रासओवर लैब्स के श्री मार्क अटकिन और श्री टॉम मिलेन ने किया। इस खंड को बेसिल द्वारा प्रायोजित किया गया था।

● समारोह में एक अन्य नई पहल आईएफएफआई और वेनिस इंटरनेशनल फेस्टिवल के बीच आधिकारिक सहयोग के रूप में सामने आई, जिसके अंतर्गत बाइनेल कॉलेज, वेनिस से 4 फिल्में आईएफएफआई 2017 में प्रदर्शित की गईं।

● फिल्म समारोह के दौरान इस उद्योग की कई हस्तियों द्वारा मास्टर क्लासिज आयोजित की गई, जिनमें शेखर कपूर, मुकेश छाबड़ा, एटम इगोयन, सुभाष घई, आस्कर विजेता साउंड डिजाइनर ग्रेग मान, आनंद गांधी नंद, भूमि पेडनेकर प्रमुख थे। फिल्मोत्सव के दौरान फिल्म निर्माण, प्रोडक्शन और वित्त पोषण, बाल फिल्में, समकालीन साहित्य और सिनेमा तथा अनेक समसामयिक विषयों पर कई परिचर्चाएं आयोजित की गईं, जिनमें फिल्म जगत के जाने माने व्यवसायियों ने हिस्सा लिया जिनमें प्रसून जोशी, करण जौहर, एकता कपूर, साजिद नाडियाडवाला, सिद्धार्थ राय कपूर, नीतीश तिवारी, अमीष त्रिपाठी, पाब्लो आस्कर, मुनमुन सेन और अन्य शामिल थे। आलिया भट्ट के साथ 'इन कन्वर्सेशन' यानी वार्तालाप कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सुश्री वाणी त्रिपाठी टिक्कू द्वारा मास्टर क्लासिज और परिचर्चाओं का संचालन किया गया।

● फेडरेशन आफ फिल्म सोसायटीज़ आफ इंडिया (एफएफएसआई) और इंडियन डाक्युमेंट्री प्रोड्यूसर्स

असोसिएशन (आईडीपीए) ने क्रमशः 22 से 24 नवंबर और 25 से 27 नवंबर के बीच फिर से ओपन फोरम का आयोजन किया।

- भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ने पुराने पोस्टरों और फिल्मो के अचल चित्रों की एक प्रदर्शनी कला अकादमी में आयोजित की।

- फिल्मोत्सव की अंतर्राष्ट्रीय जूरी में फिल्म उद्योग के जाने माने व्यवसायी शामिल थे – फिल्म निर्माता मुजफ्फर अली (अध्यक्ष), अभिनेता – निर्देशक तज़ाही ग्राड (इस्राइल), सिनेमेटोग्राफर व्लादीस्लोव ओपेलियांट्स (रूस), ब्रिस्बेन फिल्म समारोह के निर्देशक मेक्सिन विलियमसन (आस्ट्रेलिया) और आस्कर विजेता प्रोडक्शन डिजाइनर रोजर क्रिश्चियन (इंग्लैंड)।

- आईएफएफआई 2017 के दौरान निम्नांकित पुरस्कार प्रदान किए गए :
- सर्वोत्कृष्ट फिल्म (गोल्डन पीकॉक) : 120 बीट्स पर मिनट, जिसका निर्देशन रॉबिन कैम्पिलो ने किया है।
- सर्वोत्कृष्ट निर्देशक (सिल्वर पीकॉक) : विवियन क्यू को फिल्म एंजल्स वीयर व्हाइट के लिए।
- सर्वोत्कृष्ट अभिनेता (सिल्वर पीकॉक) : नाहूऐल पेरेज़ बिस्कायार्ट को 120 बीट्स पर मिनट के लिए।
- सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री (सिल्वर पीकॉक) : पार्वती को टेक ऑफ के लिए।
- विशेष जुरी अवार्ड (सिल्वर पीकॉक) : महेश नारायण को टेक ऑफ के लिए।
- सर्वोत्कृष्ट नव–निर्देशक की फीचर फिल्म (सिल्वर पीकॉक) : किरो रूसो को डार्क स्कॅल के लिए।
- आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक : मनौज कदाम्ह द्वारा निर्देशित क्षितिज (ए होरिजन) आईएफएफआई 2017 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कनाडा के जाने माने फिल्म निर्माता एटम इगोयन को दिया गया।
- वर्ष के लिए भारतीय फिल्म–विभूति पुरस्कार (सिल्वर पीकॉक) श्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया।
- फिल्मोत्सव का भव्य समापन और पुरस्कार वितरण समारोह 28 नवम्बर को श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंदौर स्टेडियम, तालेइगांव, गोवा में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कलाकारों में अमिताभ बच्चन, सलमान खान, कैटरिना कैफ, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सुशान्त सिंह राजपूत, अक्षय कुमार और अन्य शामिल थे।

फिल्मोत्सव के समापन पर प्रदर्शित फिल्प 'थिंकिंग ऑफ हिम' थी, जिसका निर्माण भारत–अर्जेन्टिना ने संयुक्त रूप से किया है। इसका निर्देशन पाब्लो केसर ने किया है और जिसका अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर कला अकादमी में किया गया था। फिल्म को इसके निर्देशक और अभिनेत्री एलेओनोरा वेक्सलर ने दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया।

dsUnzh; fQYe izek.ku cksMZ ¼lhch,Q lh½

Hkwfedk

1. फिल्म निर्माण और फिल्मों के प्रदर्शन का संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये कला के सर्वाधिक व्यापक और लोकतांत्रिक माध्यम समझे गए हैं। जनमत तैयार करने, ज्ञान प्रदान करने और विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति एवं लोक परंपराओं को समझने में फिल्मों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में फीचर फिल्मों का निर्माण अधिकतर निजी क्षेत्र में किया जा रहा है।

2. हमारा संविधान भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है; परंतु यह स्वतंत्रता ''भारत की सार्वभौमिकता और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार और नैतिकता तथा अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने जैसे मामलों को ध्यान में रख कर तर्कसंगत प्रतिबंधों'' के अधीन है। संविधान के इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्म प्रमाणन में बोर्ड का मार्गदर्शन करने वाले बुनियादी सिद्धांत सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए अधिनियम की धारा 5बी(2) के अंतर्गत केंद्र सरकार ने व्यापक दिशा–निर्देश जारी किए हैं।

3. सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों की मंजूरी देने के प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 की धारा 3 के अंतर्गत फिल्म सेंसर

बोर्ड का गठन किया, जिसे 1 जून, 1983 से नया नाम, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड दिया गया। वर्तमान बोर्ड में एक अध्यक्ष और 12 सदस्य हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

4. बोर्ड का मुख्यालय मुम्बई में है और यह अपने 9 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ काम करता है, जो मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरू, हैदराबाद, तिरूवनंतपुरम, दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में स्थित हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख क्षेत्रीय अधिकारी/अपर क्षेत्रीय अधिकारी होते हैं और फिल्मों की जांच में परामर्शी पैनल उनकी सहायता करते हैं। बोर्ड और परामर्शी पैनलों के सदस्यों में समाज के विभिन्न वर्गों के सदस्य और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे शिक्षा, सामाजिक कार्य से सम्बद्ध व्यक्ति, गृहणियां, फिल्मी हस्तियां, डाक्टर, पत्रकार आदि शामिल किए जाते हैं।

5. बे–रोकटोक सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त फिल्मों को ''यू'' प्रमाणपत्र दिया जाता है; ऐसी फिल्में जो बे–रोकटोक सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त समझी गई, लेकिन 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए माता–पिता से कुछ मार्गदर्शन की अपेक्षा रखती हैं, उन्हें ''यूए'' प्रमाणपत्र दिया जाता है, साथ ही माता–.पिता के लिए इस आशय की चेतावनी दे दी जाती है। गैर–वयस्कों के लिए अनुपयुक्त फिल्मों को ''ए'' प्रमाणपत्र; और सामान्य जन के लिए अनुपयुक्त, परंतु डॉक्टरों आदि विशेषज्ञतापूर्ण दर्शकों के समक्ष प्रदर्शन के लिए उपयुक्त फिल्मों को ''एस'' प्रमाणपत्र दिया जाता है। सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अनुपयुक्त समझी गई फिल्मों को प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाता है।

fQYe iek.ku

6. भारत विश्व के प्रमुख फिल्म निर्माता देशों में से एक है। वर्ष के दौरान प्रमाणित की गई भारतीय फीचर फिल्मों की संख्या में संतुलित वृद्धि हुई। अप्रैल, 2017 से अक्तूबर 2017 के दौरान बोर्ड ने कुल 9,316 प्रमाणपत्र जारी किए, जिनमें से एक प्रमाणपत्र सेलुलॉयड फिल्म, 3525 प्रमाणपत्र वीडियो फिल्मों और 5790 प्रमाणपत्र डिजिटल फिल्मों को जारी किए गए।

fMftVy

डिजिटल फिल्मों को जारी किए गए 5790 प्रमाणपत्रों में से, 767 प्रमाणपत्र भारतीय फीचर फिल्मों, 144 विदेशी फीचर फिल्मों, 4590 भारतीय लघु फिल्मों और 289 विदेशी लघु फिल्मों को प्रदान किए गए।

ohfM;k

इसी प्रकार वीडियो फिल्मों को जारी किए गए 3525 प्रमाणपत्रों में से, 157 प्रमाणपत्र भारतीय फीचर फिल्मों, 273 विदेशी फीचर फिल्मों, 2754 भारतीय लघु फिल्मों और 341 विदेशी लघु फिल्मों को प्रदान किए गए।

lsyyk;M

सैलूलॉयड फार्मेट में केवल एक प्रमाणपत्र भारतीय फीचर फिल्म को जारी किया गया।

अप्रैल 2017 से अक्तूबर 2017 की अवधि में प्रमाणित फिल्मों का प्रमाणपत्रवार और श्रेणीवार ब्यौरा अनुलग्नक–1 में दिया गया है।

7. अनुलग्नक–2 और 3 में भारतीय सैलूलॉयड फिल्मों का क्षेत्रवार और विषयवार वर्गीकरण दिया गया है। अनुलग्नक–4 में भारतीय डिजिटल फिल्मों का क्षेत्रवार और भाषावार ब्यौरा है। सबसे अधिक फिल्में हिंदी भाषा में बनीं और उसके बाद तेलुगू, कन्नड और तमिल का स्थान है। अनुलग्नक–5 में भारतीय डिजिटल फिल्मों का विषयवार वर्गीकरण है। अनुलग्नक–6 में विदेशी डिजिटल फिल्मों की क्षेत्रवार और राष्ट्रवार जानकारी दी गई है और अनुलग्नक–7 में डिजिटल विदेशी फिल्मों का विषयवार वर्गीकरण किया गया है।

ckMZ cSBd@{k=h; vf/kdkfj;k dh cSBd

8. वर्ष के दौरान 2 बोर्ड बैठकें एवं कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

i) 142वीं बोर्ड बैठक एवं कार्यशाला 28 जुलाई, 2017 को तिरूवनंतपुरम के होटल मस्कट में आयोजित की गई। बोर्ड बैठक की अध्यक्षता सीबीएफसी के अध्यक्ष श्री पहलाज निहलानी की अनुपस्थिति में कार्यकारी अधिकारी श्री अनुराग श्रीवास्तव ने की।

ii) 143वीं बोर्ड बैठक एवं कार्यशाला 11 सितंबर, 2017 को मुम्बई के होटल ट्राइडेंट, बीकेसी में आयोजित की गई। बोर्ड बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के नव–.नियुक्त अध्यक्ष श्री प्रसून जोशी ने की।

श्री एम. वेंकैया नायडू, माननीय पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री तथा कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, माननीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री ई–सिने प्रमाणन का शुभारंभ करते हुए।

9. क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक 24 अक्तूबर, 2017 को फिल्म प्रभाग परिसर, मुम्बई में आयोजित की गई।

egRoiw.kZ xfrfof/k;k¡

10. सीबीएफसी की ऑनलाइन फिल्म प्रमाणन प्रणाली 'ई–सिने प्रमाण' 01.04.2017 को अस्तित्व में आई। ऑनलाइन प्रणाली का शुभारंभ 27 मार्च 2017 को माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली मे किया। सीबीएफसी की नई प्रणाली का लक्ष्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में पारदर्शिता और व्यापार सुगमता लाना है। सीबीएफसी कार्यालय को कागज रहित बनाने और सीबीएफसी अधिकारियों तथा निर्माताओं, दोनों को कारगर निगरानी रखने और वास्तविक समय आधारित प्रगति की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

11. सीबीएफसी ने अप्रैल, 2017 में पेड्डर रोड स्थित नए परिसर, फिल्म्स डिविजन कॉम्प्लैक्स में अपना कार्यालय स्थानांतरित किया। नए कार्यालय का उद्घाटन 04 अप्रैल, 2017 को जानेमाने अभिनेता अमिताभ बच्चन ने किया।

f'kdk;rsa

12. सीबीएफसी को फिल्मों के प्रमाणन को लेकर जनता से निरंतर शिकायतें मिलती रहीं। ये शिकायतें लिंग, धर्म, पर्दे पर हिंसा आदि से संबंधित थीं। अधिकतर शिकायतें सामान्य किस्म की थीं।

lsalj'kki mYya?ku

13. अप्रैल, 2017 से अक्तूबर 2017 के दौरान फिल्मों के प्रदर्शन के समय सेंसरशिप उल्लंघन का कोई मामला सामने नहीं आया। परंतु, उल्लंघन के ज्यादातर मामले फिल्मों में अंतर्वेशन से संबंधित थे। कुछ फिल्मों में सेंसरशिप संबंधी उल्लंघन मुख्य रूप से 5 प्रकार के देखे गए। अर्थात् : क) सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान ऐसे हिस्से शामिल करना, जो सीबीएफसी द्वारा हटा दिए गए थे; ख) किसी प्रमाणित फिल्म में बोर्ड को न दिखाए गए हिस्से समाविष्ट करना; ग) किसी प्रमाणित फिल्म में कुछ उद्धरण शामिल करना; घ) जाली प्रमाणपत्रों के साथ गैर–सेंसर्ड फिल्में प्रदर्शित करना और ङ) बिना सेंसर प्रमाणपत्र के फिल्म प्रदर्शित करना।

विभिन्न स्थानों पर पता लगाए गए अंतर्वेशन के मामलों में जांच रिपोर्टें आवश्यक कार्रवाई के लिए सम्बद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेटों को भेजी गई हैं।

flus Jfed dY;k.k fuf/k vf/kfu;e

14. वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ नं. 15(106)–बी(आर)/2016 दिनांक 27 जुलाई, 2016 को देखते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की ओर से भारतीय फीचर फिल्मों पर सिने श्रमिक

श्री अमिताभ बच्चन मुम्बई में सीबीएफसी के नए परिसर का उद्घाटन करते हुए, साथ में हैं – सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री अजय मित्तल और सीबीएफसी के पूर्व अध्यक्ष श्री पहलाज निहलानी।

कल्याण उपकर वसूल करना बंद कर दिया। यह उपकर 01 अप्रैल, 2016 से समाप्त किया गया।

iæek.ku 'kqYd

15. प्रमाणन शुल्क के रूप में रु 5,09,63,516 वसूल किए गए।

16. मंत्रालय के आदेश संख्या 807/3/2007 दिनांक 24 सितंबर, 2007 के तहत कुछ श्रेणियों की फिल्मों के प्रमाणन संबंधी प्रावधान से छूट दी गई है।

egRoiw.kZ ifji=

17. 19 अप्रैल, 2017 को सीबीएफसी मुम्बई में फिल्मों को हिंदी में डब किए जाने के अनुप्रयोग के बारे में एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया गया।

01.04.2017 से 31.10.2017 तक बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्मों का समेकित विवरण

सैलूलॉयड								
	यू	यू *	यूए	यूए *	ए	ए *	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्म	1	0	0	0	0	0	0	1
विदेशी फीचर फिल्म	0	0	0	0	0	0	0	0
भारतीय लघु फिल्म	0	0	0	0	0	0	0	0
विदेशी लघु फिल्म	0	0	0	0	0	0	0	0
फीचर फिल्मों से इतर भारतीय फीचर फिल्में	0	0	0	0	0	0	0	0
फीचर फिल्मों से इतर विदेशी फीचर फिल्में	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल (क)	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
वीडियो								
	यू	यू *	यूए	यू ए*	ए	ए *	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्म	28	13	40	73	1	2	0	157
विदेशी फीचर फिल्म	43	9	97	115	8	1	0	273
भारतीय लघु फिल्म	1842	42	768	44	57	1	0	2754
विदेशी लघु फिल्म	77	2	220	14	27	1	0	341
फीचर फिल्मों से इतर भारतीय फीचर फिल्में	0	0	0	0	0	0	0	0
फीचर फिल्मों से इतर विदेशी फीचर फिल्में	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल (ख)	**1990**	**66**	**1125**	**246**	**93**	**5**	**0**	**3525**
डिजिटल								
	यू	यू *	यूए	यू ए*	ए	ए *	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्म	146	96	102	291	34	98	0	767
विदेशी फीचर फिल्म	7	5	39	35	28	30	0	144
भारतीय लघु फिल्म	3879	69	475	77	84	6	0	4590
विदेशी लघु फिल्म	35	2	218	3	31	0	0	289
फीचर फिल्मों से इतर भारतीय फीचर फिल्में	0	0	0	0	0	0	0	0
फीचर फिल्मों से इतर विदेशी फीचर फिल्में	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल (ग)	**4067**	**172**	**834**	**406**	**177**	**134**	**0**	**5790**
कुल योग (क+ख+ग)	**6058**	**238**	**1959**	**652**	**270**	**139**	**0**	**9316**

अनुलग्नक–2

01.04.2017 से 31.10.2017 तक बोर्ड द्वारा प्रमाणित की गई भारतीय फिल्मों का समेकित विवरण

क्षेत्रवार–भाषावार

(सैलूलॉयड)

क्र सं	भाषा	मुम्बई	चेन्नई	कोलकाता	बेंगलूरू	हैदराबाद	तिरूवनतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
1	मलयालम	-	-	-	-	-	1	-	-	-	**1**
	कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**

अनुलग्नक–3

01.04.2017 से 31.10.2017 तक बोर्ड द्वारा प्रमाणित की गई भारतीय फिल्मों का समेकित विवरण

विषयवार वर्गीकरण (सैलूलॉयड)

क्र सं	भाषा	मुम्बई	चेन्नई	कोलकाता	बेंगलूरू	हैदराबाद	तिरूवनतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
1	अन्य	-	-	-	-	-	1	-	-	-	**1**
	कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**

01.04.2017 से 31.10.2017 तक बोर्ड द्वारा प्रमाणित की गई भारतीय फिल्मों का समेकित विवरण

क्षेत्रवार–भाषावार वर्गीकरण (डिजिटल)

क्र सं	भाषा	मुम्बई	चेन्नई	कोलकाता	बेंगलूरू	हैदराबाद	तिरूवनतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
1	हिंदी	129		1				8		2	**140**
2	तेलुगु	4	5		2	104					**115**
3	कन्नड		1		97						**98**
4	तमिल	2	62		3	5					**72**
5	मलयालम		2			3	60				**65**
6	मराठी	52				1					**53**
7	बांग्ला			48							**48**
8	भोजपुरी	45		1				1			**47**
9	गुजराती	42						1			**43**
10	पंजाबी	12						10			**22**
11	ओड़िया								17		**17**
12	अंग्रेजी	3	2	1							**6**
13	असमिया									6	**6**
14	टुलु				6						**6**
15	खासी									4	**4**
16	छत्तीगढ़ी	3									**3**
17	राजस्थानी	2									**2**
18	कोंकणी	1			1						**2**
19	अवधी							1			**1**
20	बंजारा					1					**1**
21	गढ़वाली							1			**1**
22	हिंदी आंशिक अंग्रेजी	1									**1**
23	जैंतिया									1	**1**
24	कोडावा				1						**1**
25	लंबनी				1						**1**
26	मलयालम डब की गई	1									**1**
27	नागपुरी								1		**1**
28	नेपाली	1									**1**
29	पनार									1	**1**
30	पंजाबी पोधी							1			**1**
31	संथाली								1		**1**
32	सिंधी	1									**1**
33	सुरजापुरी									1	**1**
34	तमिल डब की गई	1									**1**
35	तेलुगु डब की गई	1									**1**
36	उर्दू					1					**1**
	कुल	**301**	**72**	**51**	**111**	**115**	**60**	**23**	**19**	**15**	**767**

अनुलग्नक–5

01.04.2017 से 31.10.2017 तक बोर्ड द्वारा प्रमाणित की गई भारतीय फिल्मों का समेकित विवरण

विषयवार वर्गीकरण (डिजिटल)

क्र सं	भाषा	मुम्बई	चेन्नई	कोलकाता	बेंगलूरू	हैदराबाद	तिरूवनतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
1	फीचर/सामाजिक	300	71	50	108	113	59	23	19	15	758
2	बाल फिल्में	-	-	-	3	1	1	-	-	-	5
3	शैक्षिक	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
4	डाक्यूमेंटरी	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
5	अन्य	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	कुल	**301**	**72**	**51**	**111**	**115**	**60**	**23**	**19**	**15**	**767**

अनुलग्नक–6

01.04.2017 से 31.10.2017 तक बोर्ड द्वारा प्रमाणित की गई विदेशी फिल्मों का समेकित विवरण

क्षेत्रवार–राष्ट्रवार वर्गीकरण (डिजिटल)

क्र सं	भाषा	मुम्बई	चेन्नई	कोलकाता	बेंगलूरू	हैदरा बाद	तिरूवनतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
1	अमरीका	109	-	-	-	-	-	-	-	-	109
2	कोसोवो	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8
3	ब्रिटेन	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7
4	फ्रांस	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
5	आस्ट्रेलिया	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
6	हांगकांग	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
7	हंगरी	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
8	अन्य	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
9	संयुक्त अरब अमीरात	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	दक्षिण अफ्रीका	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	नेपाल	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

अनुलग्नक–7

01.04.2017 से 31.10.2017 तक बोर्ड द्वारा प्रमाणित की गई विदेशी फिल्मों का समेकित विवरण

विषयवार वर्गीकरण (डिजिटल)

क्र सं	भाषा	मुम्बई	चेन्नई	कोलकाता	बेंगलूरू	हैदराबाद	तिरूवनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
1	फीचर	140	-	-	-	-	-	-	-	-	140
2	डाक्यूमेंटरी	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	बाल फिल्म	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	विज्ञान कल्पित कथा	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	कुल	**144**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**144**

ckM dh foRr 0;oLFkk

सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के प्रावधान के अंतर्गत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड एक सांविधिक निकाय है, जो फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन का नियमन करता है। परंतु, प्रशासनिक प्रयोजन के लिए बोर्ड को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय समझा जाता है।

बोर्ड को राजस्व सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 में निर्दिष्ट अनुसार प्रमाणन शुल्क की वसूली से प्राप्त होता है। बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय में फिल्मों की स्क्रीनिंग के संदर्भ में प्रोजेक्शन प्रभार भी लगाता है। 1 अप्रैल, 2017 से 31 अक्तूबर, 2017 तक बोर्ड की कुल आय ₹ 557.43 लाख थी। वसूल किया गया राजस्व भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है। बोर्ड इस बारे में कोई बैंक खाता ऑपरेट नहीं करता है।

आय एवं व्यय का हिसाब रखने के प्रयोजन से बोर्ड भारत सरकार द्वारा अनुपालन की जा रही वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) प्रणाली अपनाता है। बोर्ड को मंत्रालय से विभिन्न मदों के लिए गैर–योजना व्यय के अंतर्गत अनुदान प्राप्त होता है। 01.04.2017 से 31.10.2017 तक इन मदों के अंतर्गत खर्च की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

ctV vkoVu vkj 0;;

(लाख ₹ में)

	गैर–योजना ब.अ. (2017–18)	31 अक्तूबर, 2017 तक व्यय
वेतन	700.00	336.19
चिकित्सा	6.80	3.59
टीई	20.65	7.93
ओई	95.00	52.69
पीपीएसएस	150.00	114.56
किराया दरें और कर	08.00	4.52
अन्य प्रशासनिक व्यय	07.00	1.94
सूचना प्रौद्योगिकी	2.55	1.81
कुल	**990.00**	**523.23**

1- ;kstuk 0;; % lhch,Qlh vkj iek.ku ifØ;k dk mUu;u] vk/kfudhdj.k vkj foLrkj

2017 से 2020 के दौरान 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत प्रस्तावित कार्यक्रम ''सीबीएफसी और प्रमाणन प्रक्रिया का उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार'' के अंतर्गत सीबीएफसी निम्नांकित गतिविधियां संचालित करेगा, जिनके लिए ₹ 7.50 करोड निर्धारित किए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ₹ 3.50 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

(क) फिल्म अनुप्रयोग और प्रमाणन, वेबसाइट की ऑनला. इन प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर विकास।

(ख) सीबीएफसी के सभी कार्यालयों के लिए डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम और डिजिटल थिएटर।

(ग) सीबीएफसी के क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालयों के लिए अतिरिक्त कार्यालय स्थान की आवश्यकता –

एसएफसी ने अनुमोदन नहीं किया है, अतः कोई व्यय नहीं किया गया।

2- ;kstuk dk;Øe % ekuo lalk/ku fodkl ds fy, izf'k{k.k

सीबीएफसी ''मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण'' कार्यक्रम के अंतर्गत 2017–18 के दौरान निम्नांकित गतिविधियां संचालित कर रहा है।

(क) क्षेत्रीय कार्यालयों और मुम्बई में बोर्ड के सदस्यों और क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए कार्यशाला/सेमिनार/संवाद।

(ख) प्रत्येक क्षेत्र में परामर्शी पैनल सदस्यों के लिए प्रशिक्षण/कार्यशाला।

(ग) समूह 'क', 'ख' और 'ग' कर्मचारियों को प्रशासन लेखा और बजट प्रक्रिया, रिकॉर्ड रख–रखाव, ई–गवर्नेंस, आईटी कौशल, सतर्कता और आरटीआई मामलों का प्रशिक्षण।

,lchth 2017&18 % ₹ 25 yk[k

31-10-2017 rd 0;; % ₹ 5-27 yk[k

jk"Vªh; fQYe fodkl fuxe ¼,u,QMhlh½

भारत का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है, जिसकी स्थापना देश में बेहतर सिनेमा आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। एनएफडीसी का प्रमुख लक्ष्य सिनेमा में उत्कृष्टता की योजना बनाना, उसे प्रोत्साहित करना और मजबूती प्रदान करना है। एनएफडीसी (और इसका पूर्ववर्ती फिल्म वित्त निगम) अभी तक 21 भारतीय भाषाओं में 300 से अधिक फिल्मों का वित्त पोषण/निर्माण कर चुका है। इन फिल्मों की व्यापक सराहना हुई है और उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। एनएफडीसी द्वारा निर्मित/संयुक्त रूप से निर्मित कुछ महत्वपूर्ण फिल्में नीचे दी गई हैं।

सर रिचर्ड एटनब्रो की गांधी (8 अकादमी पुरस्कार जीतने वाली), सत्यजित रे की गणशत्रु और घरे बायरे, श्याम बेनेगल की द मेकिंग आफ महात्मा, मीरा नायर की सलाम बाम्बे, रितेश बत्रा की लंच बॉक्स, केतन मेहता की मिर्च मसाला, कुंदन शाह की जाने भी दो यारो, के एस सेतुमाधवन की द गुड रोड (2013 के ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि) और मारूपक्कम, कल्पना लाज़मी की रुदाली, पामेला रूक्स की मिस बेटीज़ चिल्ड्रन, राजन खोसा की डांस ऑफ द विंड, डा. जब्बार पटेल की डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर आदि। फिल्मों के निर्माण के अतिरिक्त एनएफडीसी सरकारी एजेंसियों के लिए समेकित विपणन समाधान भी उपलब्ध कराता है और विज्ञापन, डाक्युमेंटरी, लघु फिल्में, टीवी धारावाहिक, वेब विज्ञापन, रेडियो धारावाहिक और विषयपरक संगीत धुनें भी बनाता है।

फिल्म विकास एजेंसी के रूप में, एनएफडीसी फिल्म उद्योग के ऐसे क्षेत्रों/खंडों के विकास में मदद करने के लिए भी जिम्मेदार है, जो सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हों और ऐसे क्षेत्र जो वाणिज्यिक कारणों से निजी उद्यमियों द्वारा शुरू न किए जा सकते हों। एनएफडीसी के जीर्णोद्धार के एक वर्ष के भीतर इस निगम ने लगातार तीन वित्तीय वर्षों – 2010–11, 2011–12 और 2012–13 में लाभ अर्जित किया। इसे देखते हुए एनएफडीसी को 1 नवंबर, 2013 को सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा 2013 के टर्न अराउंड पुरस्कार प्रदान किया गया।

एनएफडीसी ने ''बेयोंड द नोन वर्ल्ड'' फिल्म के सह–निर्माण के लिए 08.11.2017 को समझौते पर हस्ताक्षर किए। पेन नलिन द्वारा निर्देशित यह फिल्म भारत–न्यूजीलैंड द्वारा संयुक्त रूप से बनाई जाएगी।

fQYekRlok e Hkkxhnkjh

रुचिका ओबराय द्वारा निर्देशित हिंदी फीचर फिल्म ''आइलैंड सिटी'' को फिल्मफेयर पुरस्कार 2017, बोधिसत्व अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2017, पटना, केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2017, भारत के नज़रिया अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्मोत्सव–2017 के लिए नामित किया गया।

fQYe forj.k

समूहन (सिंडिकेशन)

टेलीविजन

- वितरण विभाग 'जी नेटवर्क्स' के साथ निरंतर कार्यनीतिक भागीदारी बनाए हुए है, जिसके अंतर्गत एनएफडीसी फिल्में भारत की शानदार स्वतंत्र फिल्मों के रूप में 'जी क्लैसिक चैनल' पर प्रदर्शित की जाती हैं। दर्शकों और फिल्म उद्योग के विशिष्ट व्यक्तियों ने इसकी सराहना की है। टाटा स्काई ने अपने डीटीएच प्लेटफार्म पर फिल्म 'किस्सा' का 'जीयो मामी' के लिए वर्ष 2017–18 हेतु नवीनीकरण किया।

डिजिटल

- वर्ष 2017 के दौरान विश्व के प्रमुख वीओडी प्लेटफार्मों में से एक अमेजोन प्राइम के साथ एनएफडीसी की कार्यनीतिक भागीदारी जारी रही, जिसके अंतर्गत वैश्विक दर्शकों को एनएफडीसी की श्रेष्ठ फिल्में उपलब्ध कराई गईं। एक ऑनलाइन वीडियो–स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म हॉटस्टार, जो स्टार इंडिया की अनुशंगी कंपनी है, के साथ भी कार्यनीतिक भागीदारी की गई और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ द्वारा संचालित एक वीओडी प्लेटफार्म, जियो सिनेमा के साथ भी इसी तरह की भागीदारी की गई।
- युप्प टीवी (भारत और अमरीका) के साथ भी कार्यनीतिक भागीदारी, 2017–18 के दौरान जारी रही।

इन–फ्लाइट

- विश्वभर में एयरलाइन्स पर एनएफडीसी की फिल्में प्रदर्शित करने के लिए एंटरटेनमेंट कंपनी कंटेंटिनो मीडिया एलएलपी के साथ कार्यनीतिक साझेदारी की गई, जो उड़ानों में फिल्म सामग्री की आपूर्ति करने के मामले में भारत की सबसे सुदृढ़ कंटेंट कंसोलिडेटर है।

होम वीडियो

- होम वीडियो एंटरटेनमेंट में विशेषज्ञता रखने वाली भारत की प्रमुख कंपनियों में से एक, शेमरू एंटरटेनमेंट के साथ कार्यनीतिक भागीदारी कायम की गई। उनके सहयोग से जारी करीब 98 टाइटलों की एक लायब्रेरी का इस्तेमाल वर्ष 2017–18 के दौरान किया गया।

मांग पर वीडियो : www.cinemasofindia.com

- एनएफडीसी के वीओडी प्लेटफार्म पर कुल 130 से अधिक फिल्में वैश्विक दर्शकों को दिखाए जाने के लिए उपलब्ध हैं और एनएफडीसी ने वीओडी प्लेटफार्म के लिए एक सुचारू इस्तेमालकर्ता अनुभव सृजित करने के वास्ते एक अंतर्राष्ट्रीय ओटीटी वेंडर प्रोटोजेटा तथा पेमेंट गेटवे पार्टनर, पे–यू के साथ साझेदारी की है।

अंतर्राष्ट्रीय बिक्री

- एनएफडीसी की फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रस्तुत करने और उनके समूहन के लिए अमरीका की प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटर एंडरसन मीडिया ग्रुप के साथ कार्यनीतिक भागीदारी प्रारंभ की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजार

- एनएफडीसी फिल्मों के अंतर्राष्ट्रीय समूहन के लिए नई साझेदारी तलाश करने के प्रयोजन से एएफएम (सांता मोनिका, अमरीका) और फिल्म बाजार–2017 में प्रतिनिधित्व किया। इससे ए–सूची के उत्सव कार्यक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय बिक्री एजेंटों/वितरकों और प्रतिष्ठित पत्रकारों के साथ सुदृढ़ संबंध कायम करने में मदद मिली।

प्री–व्यू थिएटर

- एनएफडीसी मुम्बई स्थित अपने 81 सीटों के प्रीव्यू थिएटर और चेन्नई स्थित 100 सीटों के प्रीव्यू थिएटर को फिल्मों की प्रदर्शनी के लिए विभिन्न सरकारी/गैर–सरकारी ग्राहकों को किराए पर देता है। ये थिएटर अद्यतन प्रौद्योगिकी से सुसज्जित हैं, जिनमें 3 डी प्रोजेक्शन सुविधाओं सहित एनालॉग और डिजिटल प्लेटफार्मों पर फिल्में दिखाई जा सकती हैं।

mRlo vkj fQYe in'ku

1 अप्रैल, 2017 से निम्नांकित फिल्मोत्सवों के लिए सुविधाएं प्रदान की गईं।

1½ fQYekRlo vkj dkyt dk;Øe

- पंजाब आउटरीच प्रोग्राम – फगवाड़ा स्थित जीएनए विश्वविद्यालय और ललित कला अकादमी, चंडीगढ़ द्वारा आयोजित पंजाब फिल्मोत्सव के सहयोग से आउटरीच कार्यक्रम संचालित किए गए। फिल्मोत्सव के दौरान अन्ने घोड़े दा दान, किस्सा और मढ़ी दा दीवा फिल्में दिखाई गईं। पटकथा लेखन और सिनेमा शिक्षा की धारणा और उसके क्षेत्र के विस्तार में सहायक अन्य अवसरों और विद्यार्थियों के लिए सम्बद्ध रोजगार विकल्पों के बारे में विश्वविद्यालय और इसके विभागों के निकटवर्ती कॉलेजों में विद्यार्थियों के समक्ष प्रेजेंटेशन दिए गए।
- मेंगलुरू आउटरीच प्रोग्राम – यह कार्यक्रम एनआईटीटीई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के सहयोग से मेंगलुरू में सेंट अलायसिस कॉलेज परिसर में आयोजित किया गया। समारोह में 'किस्सा' 'जाने भी दो यारो' 'कलियाचन', 'द गुड रोड एंड आईलैंड सिटी' फिल्में प्रदर्शित की गईं। आउटरीच से संबंधित कार्यक्रम 7 कॉलेजों में आयोजित किए गए, जिनका लक्ष्य सिनेमा शिक्षा की धारणा और क्षेत्र के विस्तार तथा विद्यार्थियों के लिए सम्बद्ध रोजगार विकल्पों के बारे में जागरूकता पैदा करना था।
- धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह – धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह–2017 के लिए सम्पर्क और प्रायोजन में सहायता की गई। उनके साथ विभिन्न को–ब्रैंडिंग और आउटरीच के अवसर सृजित किए गए। कुंदन शाह के प्रति श्रद्धांजलि और समारोह की आउटरीच के रूप में 'जाने भी दो यारो' की दो स्क्रीनिंग की गईं (धर्मशाला स्थित राज्य कारागार के कैदियों के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग सहित)।
- बिहार में आउटरीच और स्क्रीनिंग के लिए गांधी पैनोरमा के सहयोग से 5 स्थलों पर फिल्में दिखाई गईं। इनमें गांधी और मेकिंग आफ ए महात्मा की भी स्क्रीनिंग की गई।
- एनएफडीसी ने उभरती हुई ऑनलाइन फिल्म स्क्रीनिंग कंपनी 1018एमबी डॉटकॉम के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत दर्शकों के समक्ष एनएफडीसी की फिल्में ऑनलाइन स्क्रीन की जाएंगी।

2½ J)katfy

- ओमपुरी और कुंदन शाह को श्रद्धांजलि देने के लिए 'जाने भी दो यारो' फिल्म का प्रदर्शन दिसंबर में केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव और अक्तूबर में जियो मामी मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में किया गया।
- सितंबर 2017 में ग्रैफटी और जागरण फिल्म समारोहों के दौरान ओम पुरी को श्रद्धांजलि देने के लिए फिल्म 'धारावी' दिखाई गई। इस समारोह में फिल्म 'आदि शंकराचार्य' भी प्रदर्शित की गई।

3½ fluek vkmVjhp vkj ikRlkgu

- एनएफडीसी–बिग एफएम रेडियो आउटरीच कार्यक्रम –92.7 बिग एफएम के साथ सहयोग का सत्र–1। 12 सत्रों के लिए जमीनी स्तर पर समन्वय और रिकार्डिंग की गई, जिसमें मिलन लुथरिया, मुजफ्फर अली, सुधीर मिश्रा, मीरा नायर, सौरभ शुक्ला, अलीक पदम्सी, कमल हासन, रजत कपूर, सुभाष कपूर, मधुर भंडारकर, रोहिणी हतंगड़ी, संजय सूरी, श्याम बेनेगल, सईद अख्तर मिर्जा, केतन मेहता, नागेश कुकूनूर, एमएस सथ्यू, शमा ज़ैदी, कुंदन शाह, सतीश शाह, सतीश कौशिक, विजया मेहता, होमी अदजानिया, पवन मल्होत्रा, दिबाकर बैनर्जी आदि वक्ता शामिल थे।
- fQYe vktdy&LØhfuax vkj okrkykyki& रेडियो आउटरीच प्रोग्राम के हिस्से के रूप में एनएफडीसी फिल्मो के 12 स्क्रीनिंग कार्यक्रमों का जमीनी स्तर पर कार्य निष्पादन ओवरएक्ट स्टूडियोज़, हरकत स्टूडियोज़ और जीएसए फाउंडेशन फॉर कंटम्परेरी कल्चर परिसर में किया गया। इसके अंतर्गत फिल्म स्क्रीनिंग, मेहमाननवाज़ी और स्क्रीनिंग के बाद वार्तालाप की रिकॉर्डिंग जैसे कार्य शामिल थे। वक्ताओं में कमल स्वरूप, सुधीर मिश्र, केतन मेहता, रजत कपूर, सतीश कौशिक, सौरव शुक्ल, शरत कटारिया, सईद मिर्जा, किरन नागरकर, पवन मल्होत्रा और आशुतोष गोवारिकर शामिल थे। इन सत्रों का संचालन जानेमाने सिनेकार और रेडियो जॉकी आर के सिद्धार्थ ने किया।

fons'k ea lo/kZu vkj foi.ku

एनएफडीसी की नई फिल्मों और वर्तमान सूची में शामिल फिल्मो के विपणन और भारतीय फिल्मों को वैश्विक बाजार में बढ़ावा देने के लिए निगम विभिन्न उपाय करता है। स्वयं की सूची में शामिल फिल्मों की बिक्री के अलावा एनएफडीसी भारतीय सिनेमा और भारतीय फिल्मकारों को विदेश में प्रोत्साहित करने की गतिविधियां भी संचालित करता है।

निगम का विदेश प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह और बाजारों में भारतीय सिनेमा की उपस्थिति दर्ज करने की दिशा में काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समुदाय की भारतीय सिनेमा में बढ़ती रुचि को देखते हुए, एनएफडीसी मुख्य रूप से भारत के सिनेमा तथा भारतीय प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सवों और बाजारों में प्रोत्साहित और प्रदर्शित करने, विश्वभर के निजी और सरकारी फिल्म संस्थानों के साथ साझेदारी सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 2017 में एनएफडीसी ने कान फिल्म समारोह और अमरीकी फिल्म बाजार में हिस्सा लिया।

फिल्म बाजार

- एनएफडीसी ने 20 नवंबर, 2017 से 24 नवंबर, 2017 के दौरान गोआ में फिल्म बाजार–2017 आयोजित किया। फिल्म बाजार एक ऐसा मंच है, जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय और दक्षिण एशियाई फिल्म समुदाय के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसमें फिल्म–सृजन, निर्माण और वितरण के क्षेत्र में दक्षिण एशियाई विषयवस्तु और प्रतिभा की खोज करने, उसे बढ़ावा देने और प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह बाजार विश्वभर के फिल्म क्रेताओं और विक्रेताओं के लिए एक मंच का काम करता है। फिल्म बाजार का लक्ष्य विश्व सिनेमा की दक्षिण एशियाई क्षेत्र में बिक्री में सहायता करना भी है।
- फिल्म बाजार–2017 में 39 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जबकि 2007 में आयोजित पहले फिल्म बाजार में 18 देशों ने भाग लिया था।
- वर्ष 2017 के दौरान अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और कनाडा में सह–निर्माण बाजार, फिल्म बाजार पटकथा लेखक प्रयोगशाला, पटकथा लेखक स्टूडियो और फिल्म निर्माताओं की वर्क–इन प्रोग्रेस प्रयोगशालाओं के लिए आकर्षक परियोजनाएं लाइन–अप की गईं।
- सह–निर्माण बाजार, फिल्म बाजार पटकथा लेखक प्रयोगशाला, पटकथा लेखक स्टूडियो और वर्क–इन प्रोग्रेस प्रयोगशालाओं ने कुल 39 परियोजनाएं प्रस्तुत कीं, जो विकास और निर्माण के विभिन्न चरणों में थीं।

if'k{k.k vkSj fodkl

एनएफडीसी ने फिल्म क्षेत्र में लगे व्यवसायियों के लिए प्रशिक्षण में अंतराल दूर करने के लिए 2012 में एनएफडीसी लैब्स ब्रैंड के अंतर्गत प्रशिक्षण और विकास विभाग की स्थापना की थी। इसका लक्ष्य भारतीय फिल्म समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण निर्माण बिंदु के रूप में काम करना, व्यावसायिक फिल्म निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, फिल्मों से संबंधित मूलभूत विषयों–निर्देशन, लेखन, संपादन, सिनेमेटोग्राफी और निर्माण में कार्यशालाओं और प्रमुख कक्षाओं का प्रबंध करना है।

1. एनएफडीसी लैब्स 3 भाग वाले एक पाठ्यक्रम–''स्क्रीन राइटर्स लैब'' का संचालन करता है। इसके अंतर्गत 11वें संस्करण का आयोजन किया गया। जिसके लिए कुल 176 आवेदनों में से 8 लेखकों को भागीदारी के लिए चुना गया। प्रयोगशाला के सभी तीनों सत्रों का आयोजन एल एंड टी एलडीए, लोनावला में किया गया। चुने हुए प्रतिभागियों ने अपने गुरुओं के साथ 5 महीने के गहन कार्यक्रम के अंतर्गत काम किया ताकि अपनी पटकथाओं को एक–एक करके और साथ ही समूह सत्रों के दौरान जांचा परखा जा सके।

2. एनएफडीसी लैब्स ने 3 भाग वाले एक अन्य पाठ्यक्रम–'द स्क्रीन राइटर्स स्टूडियो' का भी संचालन किया। इसका संचालन भारत से मौलिक आवाज और पटकथाएं विकसित करने के सतत प्रयास के हिस्से के रूप में किया गया। चुने हुए 8 लेखकों के साथ स्टूडियो का प्रथम संस्करण फिल्म बाजार स्क्रीन राइटर्स लैब के समानांतर कार्यक्रम के रूप में संचालित किया गया।

3. फिल्म बाजार के दौरान दोनों स्क्रीन राइटिंग प्रयोगशालाओं के प्रतिभागियों ने विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्क्रीन राइटर्स पिच सेशन में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म व्यवसायियों के समक्ष प्रस्तुत किया। लेखकों ने निर्माताओं, स्टूडियो संचालकों और निवेशकों के समक्ष अपने पीस–टू–कैमरा वीडियो प्रस्तुत किए। फिल्म सृजकों, निर्माताओं, स्टूडियो प्रमुखों और टेलेंट एजेंटों के साथ प्रतिभागियों की बैठकें आयोजित की गईं, ताकि उन्हें फिल्म निर्माण के वास्तविक सरोकारों की जानकारी प्रदान की जा सके।

4. एनएफडीसी लैब्स ने फिल्म बाजार–2017 के दौरान आयोजित सह–निर्माण बाजार (सीपीएम) के लिए 18 परियोजनाएं संचालित और प्रस्तुत कीं। ये परियोजनाएं भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल और कनाडा से सम्बद्ध थीं। बाजार की शुरुआत ओपन पिच के साथ हुई। कुल 492 एक के बाद एक बैठकें

आयोजित की गईं। सह–निर्माण बाजार परियोजना प्रतिनिधियों के लिए एक प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म बाजार का परिचय, सह–निर्माण बाजार कार्य प्रणाली, फिल्म सुविधा कार्यालय की भूमिका, सह–निर्माण की रूपरेखा, सार्वजनिक वित्त पोषण के बारे में ओएलएफएफआई सत्र, फेसबुक (प्रोत्साहन के लिए सोशल मीडिया का उपयोग) और हाउ टू पिच एंड हैव इफेक्टिव सत्र क्रमबद्ध रूप से शामिल थे।

rduhdh dk'ky fodkl

- कुशल भारत अभियान (स्किल इंडिया मिशन) के अंतर्गत चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय में प्रशिक्षण डिविजन तमिलनाडु में युवाओं के लिए विभिन्न मीडिया संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। इस डिविजन ने एनिमेशन, कैमरा, संपादन, मल्टीमीडिया फोटोग्राफी और ऑडियो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 7000 से अधिक युवाओं के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण और व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए हैं। अनुमान है कि यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने वाले करीब 70 प्रतिशत युवाओं को रोजगार प्राप्त हो चुका है। एनएफडीसी अन्य राज्यों में भी कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का विस्तार करने की प्रक्रिया में है।
- राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड का चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय तमिलनाडु सरकार की विभिन्न एजेंसियों जैसे तमिलनाडु स्किल डिवेल्पमेंट कॉर्पोरेशन, टीएएचडीसीओ, बीसी/एमबीसी/डीएनसी, टीएएमसीओ, जनजातीय कल्याण और दिव्यांगजन कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित बेरोजगार युवाओं के लिए मीडिया के बारे में कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के हरसंभव उपाय भी किए जाते हैं।
- अप्रैल, 2017 से अभी तक 4500 उम्मीदवारों को मीडिया संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जा चुका है और अभी तक 70 प्रतिशत उम्मीदवारों को रोजगार प्राप्त हो चुका है। तकनीकी पाठ्यक्रमों में – एबीआईडी–डिजिटल नोन लाइनियर एडिटिंग, एफसीपी–डिजिटल नोन लाइनियर एडिटिंग, डिजिटल वीडियोग्राफी, डिजिटल स्टिल फोटोग्राफी, मल्टीमीडिया (डिजाइनिंग), थ्रीडी एनिमेशन, ऑडियो इंजीनियरिंग शामिल थे।
- *भारतीय सिने कलाकार कल्याण निधि*

भारतीय सिने कलाकार कल्याण निधि (सीएडब्ल्यूएफआई) एक न्यास है, जो 1991 से एनएफडीसी द्वारा प्रबंधित है। गांधी फिल्म के निर्माता लॉर्ड रिचर्ड एटनबरो ने इस फिल्म से अर्जित लाभ राशि के 5 प्रतिशत हिस्से का उपयोग करते हुए इस निधि की स्थापना की थी, जिसका लक्ष्य बीते जमाने के जरूरतमंद सिने कलाकारों को वित्तीय मदद पहुंचाना है।

foKkiu fQYe fuekZ.k vkSj lapkj

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान एनएफडीसी ने विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों/विभागों, के साथ सहयोग किया और ऑडियो वीजुअल्स तथा क्रास–प्लेटफार्म कैम्पेन निर्मित और वितरित किए। ऐसा करते हुए एनएफडीसी ने आद्योपांत संचार समाधान उपलब्ध कराए और अपने को विभिन्न मंचों के लिए विज्ञापन संचार सृजन और सम्प्रेषण के लिए एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में स्थापित किया।

एनएफडीसी ने कई क्षेत्रीय भाषाओं में प्रायोजित रेडियो और वीडियो कार्यक्रमों की 108 कड़ियों, और विभिन्न फार्मेटों के 300 ऑडियो–वीडियो विज्ञापन तथा रेडियो स्पॉट्स तैयार किए। एनएफडीसी ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश से एबी कंटेंट विषयवस्तु परियोजनाएं सफलतापूर्वक हासिल कीं और कुछ पथ प्रवर्तक आधारभूत कार्यशीलन गतिविधियों को अंजाम दिया, जैसे राजघाट समाधि समिति, मोदी फेस्ट, संकल्प से सिद्धि, रॉक कंसर्ट्स, न्यू इंडिया मैराथन और स्वच्छ भारत मिशन के तीन वर्ष पूरे होने पर डीडब्ल्यूएस प्रदर्शनी, जिनसे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रमुख अभियानों को पूरा करने की एनएफडीसी की क्षमता सिद्ध हुई।

मीडिया प्रोडक्शन

- राजघाट समाधि समिति ने 2 अक्तूबर, 2017 को प्रदर्शित करने के लिए गांधीजी के जीवन से सम्बद्ध विभिन्न विषयों को कवर करते हुए इंटरेक्टिव डिजिटल डिस्प्ले की विषयवस्तु तैयार करने और उसे श्रव्य–दृश्य रूप में प्रस्तुत करने का कार्य एनएफडीसी को सौंपा।
- स्वच्छता ही सेवा – एनएफडीसी ने स्वच्छ भारत मिशन की वर्षगांठ मनाने के लिए 2 अक्तूबर को विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिए गए पुरस्कारों के लिए प्रशस्ति फिल्म तैयार करने और स्वच्छ भारत अभियान की यात्रा के डिजिटल डिस्प्ले का काम किया।

- वयो श्रेष्ठ सम्मान–2017 – एनएफडीसी ने विभिन्न श्रेणियों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिए गए पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों की 22 प्रशस्ति फिल्में और एक डाक्युमेंटरी तैयार की। ये पुरस्कार वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने के लिए विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए।
- भारत के व्यापार सुधार – एनएफडीसी ने व्यापार करने में सुगमता की दृष्टि से शीर्ष 100 स्थानों में भारत की रैंकिंग में सुधार के उपलक्ष्य में 5 मिनट की एक फिल्म बनाई। यह फिल्म भारत के माननीय प्रधानमंत्री और विश्व बैंक के सीईओ की उपस्थिति में दिखाई गई।

fQYe lqfo/kk dk;kZy; ¼,Q,Qvks½

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2015 में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) में फिल्म सुविधा कार्यालय की स्थापना की थी। इसका लक्ष्य भारत में विदेशी फिल्म निर्माताओं को फिल्म शूटिंग के लिए प्रोत्साहित करना और तत्संबंधी सुविधाएं प्रदान करना है। फिल्म सुविधा कार्यालय द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार अब भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए भी किया गया है।

यह कार्यालय एक ही स्थान पर सुविधाएं और मंजूरी प्रदान करने की व्यवस्था के रूप में काम कर रहा है। इससे भारत में फिल्म निर्माण में सुगमता आती है और साथ ही एक फिल्म–अनुकूल वातावरण का निर्माण होता है, जिससे देश को फिल्म निर्माण के आकर्षक लक्ष्य के रूप में बढावा देने में मदद मिलती है।

इसकी स्थापना देश में फिल्म अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए की गई है। इसके लिए निम्नांकित मंत्रालयों/विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए – गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण आदि। इसके अलावा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों में भी नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए ताकि फिल्मों की शूटिंग में सुविधा प्रदान की जा सके।

फिल्म सुविधा कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान किए गए उपाय

1. *मंजूरी प्रदान करने में सहायता*

जनवरी से दिसंबर, 2017 की अवधि में टेलीविजन धारावाहिकों सहित अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के लिए भारत में शूटिंग के 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें से 17 प्रस्ताव फीचर फिल्मों अैर 6 टेलीविजन धारावाहिकों से संबंधित थे। भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माण के जो प्रस्ताव इस अवधि में प्राप्त हुए, वे मुख्य रूप से रूस, अमरीका, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, फ्रांस, बांग्लादेश, तुर्की, डेनमार्क, स्पेन, जर्मनी और आस्ट्रेलिया से संबद्ध थे। दो फीचर फिल्मों और एक टेलीविजन धारावाहिक के लिए भारत में फिल्म निर्माण की अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया जारी है।

2. *फिल्म निर्माण के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य पुरस्कार–2016*

राज्यों को अपने–अपने क्षेत्र में फिल्म निर्माण के अनुकूल माहौल बनाने में सक्रिय करने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पुरस्कार प्रदान करने का उपाय किया है। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तत्वावधान में 3 मई, 2017 को 16 राज्यों ने फिल्म निर्माण के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य पुरस्कार–2016 में हिस्सा लिया। जाने माने फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर के नेतृत्व में जूरी के सदस्यों में कौशिक गांगुली, कृश जगरलामुंडी जैसे वरिष्ठ फिल्म निर्माता और विशिष्ट आईएएस अधिकारी डॉ मोहन कांडा शामिल थे।

16 राज्यों से प्राप्त प्रविष्टियों में से जूरी ने यह अनुशंसा की कि फिल्म निर्माण के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य पुरस्कार–2016 उत्तर प्रदेश को दिया जाना चाहिए, जिसने प्रदेश को फिल्म निर्माण के एक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए ध्यान केंद्रित करने वाली 'सिंगल विंडो एजेंसी ''फिल्म बंधु, उत्तर प्रदेश'' की व्यवस्था करने सहित बेजोड़ फिल्म नीति लागू की है। जूरी ने यह भी महसूस किया कि स्थानीय फिल्म निर्माण प्रतिभा को बढ़ावा देने और समूचे भारत से फिल्म निर्माताओं को सब्सिडी प्रदान करने सहित फिल्म उद्योग के विकास के प्रयासों के लिए झारखंड राज्य को विशेष उल्लेख प्रमाणपत्र दिया जाए।

3. *भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 29 सर्कलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति में सहायताः*

गोवा में फिल्म बाजार के साथ विचार विमर्श के लिए 22 नवंबर, 2015 को आयोजित की गई फिल्म पर्यटन विचार गोष्ठी के निष्कर्षों का अनुपालन करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 29 सर्कलों ने नोडल

अधिकारी नियुक्त किए ताकि विभिन्न एएसआई स्थलों में फिल्म शूटिंग की अनुमति देने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके। इससे फिल्म निर्माताओं को एएसआई स्थलों पर पहुंचने और शूटिंग के लिए आकर्षित किया जा सकेगा, जिससे इन स्थलों को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहन मिलेगा।

4. *महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रालयों के साथ सिलसिलेवार बैठकें*

फिल्म सुविधा कार्यालय ने निम्नांकित प्रतिभागी मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित कीं ताकि उनके अधिकार क्षेत्र में फिल्म निर्माताओं को आने वाली कठिनाइयों और फिल्म बनाने की प्रक्रिया में सुगमता लाने के बारे में विचार विमर्श किया जा सके।

- विदेश मंत्रालय – विदेश मंत्रालय द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी के साथ बैठक के दौरान यह तय किया गया कि प्रमुख भारतीय मिशनों में एक नोडल अधिकारी होगा, जो भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं, उनके कलाकारों और कामगारों को वीज़ा प्राप्त करने में सहायता करेगा।
- रेलवे मंत्रालय – रेलवे मंत्रालय द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी के साथ बैठक में यह निर्णय किया गया कि रेलवे से सम्बद्ध फिल्म निर्माताओं के साथ रेलवे के विभिन्न अंचलों के प्रमुख अधिकारियों की एक कार्यशाला आयोजित की जाए, ताकि विभिन्न रेलवे स्टेशनों/परिसरों और डिब्बों को शूटिंग में शामिल करते समय फिल्म निर्माताओं को आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों के बारे में चर्चा की जा सके।

5. *एएफसीआई की सिनेमा विचार गोष्ठी (सिनेपोज़ियम)–2017 में फिल्म सुविधा कार्यालयः*

असोसिएशन ऑफ फिल्म कमिश्नर्स इंटरनेशनल (एएफसीआई) का सदस्य बनने के बाद फिल्म सुविधा कार्यालय ने 20 से 22 अक्तूबर, 2017 के बीच आयोजित एएफसीआई के 41वें प्रमुख वार्षिक उद्योग शिक्षा कार्यक्रम, 'सिनेपोज़ियम इन एलए' में हिस्सा लिया।

इस कार्यक्रम से फिल्म सुविधा कार्यालय को लोकेशन मैनेजरों और/या निर्माताओं/निर्देशकों के लिए एक सफल अध्ययन दौरे की योजना बनाने की प्रेरणा मिली, ताकि फिल्म कमिश्नरों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों के अलावा किसी स्थान के चयन के लिए अंतिम निर्णय करने के बारे में रचनात्मक प्रक्रिया पर उसके प्रभाव, फिल्म निर्माण के आर्थिक प्रभाव को देखते हुए आंकड़ा सग्रहण के महत्व की जानकारी उन्हें प्रदान की जा सके।

फिल्म सुविधा कार्यालय ने इस अवसर का लाभ विभिन्न प्रमुख कंपनियों और हॉलीवुड के बड़े स्टूडियोज़ जैसे एचबीओ, वार्नर ब्रदर्स, नेटफ्लिक्स, अमेजोन आदि से मिलने के लिए उठाया, ताकि भारत को फिल्म निर्माण के लक्ष्य के रूप में प्रोत्साहित किया जा सके।

6. फिल्म बाजार–2017 में भागीदारी

फिल्म सुविधा कार्यालय ने फिल्म बाजार 2017 में भाग लिया, जिसका आयोजन भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के बैनर तले 21 से 24 नवंबर 2017 के दौरान गोवा में किया गया था। इस अवसर पर फिल्म सुविधा कार्यालय ने एक काउंटर की स्थापना की थी।

फिल्म सुविधा कार्यालय ने 14 राज्यों के फिल्म निर्माताओं के लिए वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहनों की एक व्यापक सूची संकलित की और उसे फिल्म निर्माताओं के साथ साझा किया। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, गोआ, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। फिल्म सुविधा कार्यालय ने जानकारी प्रदान करने के लिए ''फिल्म निर्माण में सुविधा'' के बारे में एक सत्र आयोजित किया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में देशभर में फिल्म निर्माण में सुगमता के लिए किए गए विभिन्न उपायों की जानकारी प्रदान की गई। दस राज्य सरकारों अर्थात् दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, लक्षद्वीप,

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, और उत्तर प्रदेश फिल्म बाजार में उपस्थित थे, जिन्होंने भारत और विदेश से आए फिल्म निर्माताओं को अपने अपने स्थलों की जानकारी प्रदान की।

ये कार्यालय विभिन्न स्थानों पर फिल्म निर्माण से संबंधित संवेदनशील मुद्दों के बारे में जानकारी भी प्रदान करते हैं ताकि फिल्म निर्माताओं को विशेष अनुरोध प्राप्त करने और तदनुरूप वांछित फिल्में

पणजी, गोवा में 25 नवम्बर, 2017 को भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएआई–2017) के अवसर पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुज़फ्फर अली, रोज़र क्रिश्चिन, त्ज़ाही ग्राड, मैक्सिन विलियमसन और व्लादिस्लाव ओपेलियांट्स।

बनाने में सहायता की जा सके। लक्षद्वीप (जिसने पहली बार हिस्सा लिया), तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ने भी जानकारी सत्र आयोजित किए, जिनमें उन्होंने अपने राज्य की फिल्म नीतियों और फिल्म निर्माण को सुचारू बनाने के लिए किए गए उपायों की जानकारी प्रदान करते हुए फिल्म बाजार में उपस्थित फिल्म निर्माताओं को अपने यहां उपयुक्त स्थलों पर आने के लिए आमंत्रित किया।

भावी कार्यक्रम

फिल्म सुविधा कार्यालय आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए एक प्रतिबद्ध वेब पोर्टल स्थापित करने की प्रक्रिया में है। कार्यालय एक स्थल निर्देशिका और सेवा डायरेक्टरी भी तैयार कर रहा है ताकि वह भारत में फिल्म शूटिंग के इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समुदाय के लिए एक ही स्थान पर सुविधाएं और मंजूरी प्रदान करने की व्यवस्था के रूप में काम कर सके।

Hkkjr dk varjk"Vh; fQYe lekjksg

भारत का 48वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई) 20 से 28 नवंबर, 2017 के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा गोवा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। यह प्रथम अवसर था जब सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने फिल्मोत्सव का आयोजन किया, जबकि इसके आयोजन में एंटरटेनमेंट सोसायटी आफ गोवा (ईएसजी) ने गोवा सरकार की ओर से हिस्सा लिया। फिल्मोत्सव का विषय था –''सिनेमा के भविष्य का उत्सव''

- 9 दिन तक चले फिल्मोत्सव में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की स्क्रीनिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया, कई वैश्विक, अंतर्राष्ट्रीय, एशियाई और भारतीय प्रीमियर आयोजित किए गए, विशेष प्रस्तुतिकरण, सिने कलाकारों की उपस्थिति के साथ भव्य कार्यक्रम, मास्टर क्लासेज़, परिचर्चाएं, मिक्स्ड रियल्टी साइडबार, सह–फिल्म निर्माण सेमीनार, मुक्ताकाश स्क्रीनिंग, संवाददाता सम्मेलन और पहली बार आइएफएआई के बैनर तले 4 दिन के फिल्म बाजार का आयोजन किया गया।
- पहली बार फिल्मोत्सव की संचालन समिति में देशभर से जाने माने फिल्म निर्माताओं और फिल्मी हस्तियों को शामिल किया गया, जिनमें जाहनू बरुआ, सिद्धार्थ राय कपूर, भरत बाला, आनंद गांधी, प्रसून जोशी, वाणी त्रिपाठी, पीयूष पांडेय, शाजी, एन करुण, मेरेन इमचेन, अश्विनी अय्यर तिवारी, नागेश कुकूनूर, शुजीत सरकार और एनएफडीसी के निदेशक शामिल थे।
- इस वर्ष पहली बार फिल्मोत्सव की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म प्रीव्यू कमेटी में देशभर से विशिष्ट फिल्मकारों और फिल्मी हस्तियों को शामिल किया गया, जिनमें खालिद मोहम्मद, आरती बजाज, रमेश पतंगे, नरेश चन्द्र लाल, नरेंद्र कोहली, विवेक अग्निहोत्री, साइबल चटर्जी, अभिमन्यु सिंह, भावना सोमाया, जीविता राजशेखर, गौतमी ताडीमाला, नितेश तिवारी, जीएस भास्कर, पल्लवी जोशी, अनिरुद्ध राय चौधरी, राजा कृष्णा मेनन, सिद्धार्थ काक, तरुण कत्याल, अभिषेक बासु, इशिता भट्ट, अभिषेक जैन, सांत्वना बारदोलोई, भास्कर हजारिका, प्रदीप कुर्बाह, डोमिनिक मेगम, मैपक्षना होरोंग्बम, जुआला छांगटे, सचिदानंद जोशी, भरत गुप्त, निर्मला शर्मा, राठी विनय झा, राजेश कुमार सिंह, सांगी दोर्जी, अनिल रस्तोगी, पुनीत अस्थाना, भुमेंजॉय कोंसम, अजय

कुमार मलकानी और लवीन थाडानी शामिल थे।

- फिल्म समारोह का भव्य उद्घाटन समारोह 20 नवंबर, 2017 को तालेगांव, गोवा स्थित श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में किया गया। अपने आकार और क्षेत्र की दृष्टि से यह कार्यक्रम अभूतपूर्व था। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री माननीय श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी और गोवा के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर पर्रिकर के साथ अनेक फिल्म कलाकार मौजूद थे। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने फिल्मोत्सव के उद्घाटन की घोषणा की। कार्यक्रम का संचालन राजकुमार राव और राधिका आप्टे ने किया। अन्य प्रमुख फिल्मी हस्तियों में श्रीदेवी और बोनी कपूर, सुभाष घई, अनुपम खेर, नाना पाटेकर, शाहिद कपूर, एआर रहमान और कई अन्य कलाकार शामिल थे।
- समारोह की उद्घाटन फिल्म के रूप में ईरान के प्रमुख फिल्म निर्माता माजिद मजिदी की बियोंड द क्लाउड्स दिखाई गई। इस फिल्म के कलाकारों और निर्माताओं में सभी भारतीय हैं। इसका इंडिया प्रीमियर कला अकादमी में आयोजित किया गया था। फिल्म का परिचय निर्माता और कलाकारों के दल के साथ माजिद मजीदी द्वारा दिया गया, जिनमें संगीत निर्देशक एआर रहमान, पटकथा लेखक विशाल भारद्वाज,पहली बार फिल्म में अभिनय करने वाले ईशान खट्टर और अभिनेत्री मलाविका मोहनन शामिल थीं।
- फिल्म समारोह के फिल्म कार्यक्रम में 82 देशों की 195 फिल्में दिखाई गईं, जो सिनेमा कार्यक्रम के विस्तार में अंतर्राष्ट्रीय विविधता का प्रमाण था। इनमें कई प्रतिष्ठित फिल्में शामिल थीं, जो विश्वभर के फिल्मोत्सवों में दिखाई जा चुकी हैं। इसके अलावा भारत और विदेश से अकादमी पुरस्कार प्रविष्टियां एवं असाधारण फिल्में, आदि भी दिखाई गईं।
- आधिकारिक कार्यक्रम के अंतर्गत 10 विश्व प्रीमियर, 10 एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर और 64 भारतीय प्रीमियर फिल्में शामिल थीं।
- समारोह में विशेष रूप से बनाए गए बांड रिटरोस्पेक्टिव खंड के अंतर्गत 1962 से 2012 के बीच बनी 12 बांड फिल्में प्रदर्शित की गईं। ये फिल्में फिल्मोत्सव के प्रतिनिधियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनीं। इस बेजोड़ पश्चदर्शन के उद्घाटन के अवसर पर श्री विजय अमृतराज और श्री कबीर बेदी मौजूद थे।
- रीस्टोर्ड क्लासिक सेक्शन के अंतर्गत गोडार्ड, ओज़ू, हिचकोक, बुनुएल, फ्रित्ज़लोंग और अन्यों द्वारा निर्मित सिनेमेटिक इतिहास की 8 हॉलमार्क फिल्में प्रदर्शित की गईं। समारोह का विशेष आकर्षण हाल ही में पुनर्जीवित की गई तार्कोवस्की की अंतिम लिजेंडरी फिल्म सक्रीफाइस का भारतीय प्रीमियर था।
- भारतीय पैनोरमा खंड के अंतर्गत 42 फिल्में दिखाई गई जिनमें 26 फीचर फिल्में शामिल थीं, जिनका चयन 154 पात्र प्रविष्टियों में से किया गया था। इसी तरह 21 गैर–फीचर फिल्में शामिल की गई जिनका चयन 154 पात्र प्रविष्टियों में से किया गया था।
- जानीमानी अभिनेत्री श्रीदेवी भारतीय पैनोरमा के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य सम्मानित अतिथि थीं। उद्घाटन कार्यक्रम इनोक्स–2 में 21 नवंबर, 2017 को किया गया। भारतीय पैनोरमा की उद्घाटन फिल्म के रूप में विनोद कापरी की पिहु (फीचर फिल्म) और कमाल स्वरूप की पुष्कर पुराण (गैर–फीचर फिल्म) दिखाई गई।
- भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च सम्मान, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, भारतीय सिनेमा के जनक की विरासत को दर्शाता है, जो फिल्म उद्योग की वरिष्ठ हस्तियों को उनके आजीवन योगदान की सराहना के लिए दिया जाता है। 48वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2017 के दौरान 2017 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता निर्देशक के. विश्वनाथ की तीन फिल्में दिखाई गई थीं, जो इस पश्चदर्शन के उद्घाटन के अवसर पर मौजूद थे।
- लगातार दूसरे वर्ष, एक्सेसिबल इंडिया फिल्म्स के अंतर्गत विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों के लिए सीक्रेट सुपर स्टार और हिंदी मीडियम फिल्म प्रदर्शित की गई। एक्सेसिबल इंडिया आईएफएफआई, सक्षम भारत और यूनेस्को के बीच एक सहयोगी संगठन है, जिसका लक्ष्य दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी फिल्मों को प्रोत्साहित करना है।
- आईएफएफआई 2017 के दौरान पिछले वर्ष दिवंगत हुई फिल्म उद्योग की जानीमानी हस्तियों को श्रद्धाजंलि के रूप में उनकी प्रभावशाली और स्थायी सिनेमेटिक विरासत से चुनी हुई फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इस वर्ष ओम पुरी, अब्दुल माजिद, विनोद खन्ना, टॉम आल्टर, रीमा लागू,

जे जयललिता, कुंदन शाह, दसारी नारायण राव और रामानंद सेनगुप्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जोगर्स पार्क में जाने भी दो यारों की विशेष मुक्ताकाश स्क्रीनिंग की गई, जिसमें फिल्म के कला. कारों और निर्माताओं में से सतीश कौशिक, नीना गुप्ता, रंजीत कपूर और सुधीर मिश्रा उपस्थित थे।

- आईएफएफआई 2017 में कंट्री फोकस के अंतर्गत कनाडा पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके लिए टेलीफिल्म्स कनाडा के सहयोग से टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल द्वारा उपलब्ध कराई गई फिल्में दिखाई गईं। कनाडा फिल्म उद्योग से निर्देशकों, अभिनेताओ और फिल्म व्यवसायियों के 19 सदस्यों के शिष्टमंडल की उपस्थिति में फोकस के अंतर्गत कुल 8 फिल्में प्रदर्शित की गईं। इस वर्ष के फोकस की सफलता में कनाडा उच्चायोग द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलनों, एक सह–फिल्म निर्माण सेमिनार और भव्य रिसेप्शन का विशेष योगदान रहा। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त महामहिम श्री नादिर पटेल ने फिल्मोत्सव और समापन समारोह में हिस्सा लिया।
- संगठन में एक नई पहल मिक्स्ड रियलिटी साइडबार के अंतर्गत सिनेमा का भविष्य कार्यक्रम को मंजूरी दी गई जिसके अंतर्गत एआर/वीआर प्रदर्शनी तथा परिचर्चाएं और डिजिटल युग में वर्चुअल रियलिटी के उदय और उभरती हुई सिनेमा प्रवृत्तियों पर उसके परिवर्तनकारी प्रभाव के बारे में मास्टर क्लासेज का आयोजन किया गया। इसका संचालन इंग्लैंड के क्रासओवर लैब्स के श्री मार्क अटकिन और श्री टॉम मिलेन ने किया। इस खंड को बेसिल द्वारा प्रायोजित किया गया था।
- समारोह में एक अन्य नई पहल आईएफएफआई और वेनिस इंटरनेशनल फेस्टिवल के बीच आधिकारिक सहयोग के रूप में सामने आई, जिसके अंतर्गत बाइनेल कॉलेज, वेनिस से 4 फिल्में आईएफएफआई 2017 में प्रदर्शित की गईं।
- फिल्म समारोह के दौरान इस उद्योग की कई हस्तियों द्वारा मास्टर क्लासिज आयोजित की गई, जिनमें शेखर कपूर, मुकेश छाबड़ा, एटम इगोयन, सुभाष घई, आस्कर विजेता साउंड डिजाइनर ग्रेग मान, आनंद गांधी नंद, भूमि पेडनेकर प्रमुख थे। फिल्मोत्सव के दौरान फिल्म निर्माण, प्रोडक्शन और वित्त पोषण, बाल फिल्में, समकालीन साहित्य और सिनेमा तथा अनेक समसामयिक विषयों पर कई परिचर्चाएं आयोजित की गईं, जिनमें फिल्म जगत के जाने माने व्यवसायियों ने हिस्सा लिया जिनमें प्रसून जोशी, करण जौहर, एकता कपूर,

गोवा की राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा, माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, फिल्म अभिनेता शाहरूख खान और अन्य गणमान्य व्यक्ति 20 नवम्बर, 2017 को पणजी, गोवा में भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई–2017) के उद्घाटन के अवसर पर।

साजिद नाडियाडवाला, सिद्धार्थ राय कपूर, नीतीश तिवारी, अमीष त्रिपाठी, पाब्लो आस्कर, मुनमुन सेन और अन्य शामिल थे। आलिया भट्ट के साथ 'इन कन्वर्सेशन' यानी वार्तालाप कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सुश्री वाणी त्रिपाठी टिक्कू द्वारा मास्टर क्लासिज और परिचर्चाओं का संचालन किया गया।

- फेडरेशन आफ फिल्म सोसायटीज़ आफ इंडिया (एफएफएसआई) और इंडियन डाक्युमेंट्री प्रोड्यूसर्स असोसिएशन (आईडीपीए) ने क्रमशः 22 से 24 नवंबर और 25 से 27 नवंबर के बीच फिर से ओपन फोरम का आयोजन किया।
- भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ने पुराने पोस्टरों और फिल्मो के अचल चित्रों की एक प्रदर्शनी कला अकादमी में आयोजित की।
- फिल्मोत्सव की अंतर्राष्ट्रीय जूरी में फिल्म उद्योग के जाने माने व्यवसायी शामिल थे – फिल्म निर्माता मुजफ्फर अली (अध्यक्ष), अभिनेता – निर्देशक तज़ाही ग्राड (इस्राइल), सिनेमेटोग्राफर व्लादीस्लोव ओपेलियांट्स (रूस), ब्रिस्बेन फिल्म समारोह के निर्देशक मेक्सिन विलियमसन (आस्ट्रेलिया) और आस्कर विजेता प्रोडक्शन डिजाइनर रोजर क्रिश्चियन (इंग्लैंड)।
- आईएफएफआई 2017 के दौरान निम्नांकित पुरस्कार प्रदान किए गए :
- सर्वोत्कृष्ट फिल्म (गोल्डन पीकॉक) : 120 बीट्स पर मिनट, जिसका निर्देशन रॉबिन कैम्पिलो ने किया है।
- सर्वोत्कृष्ट निर्देशक (सिल्वर पीकॉक) : विवियन क्यू को फिल्म एंजल्स वीयर व्हाइट के लिए।
- सर्वोत्कृष्ट अभिनेता (सिल्वर पीकॉक) : नाहूऐल पेरेज़ बिस्कायार्ट को 120 बीट्स पर मिनट के लिए।
- सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री (सिल्वर पीकॉक) : पार्वती को टेक ऑफ के लिए।
- विशेष जुरी अवार्ड (सिल्वर पीकॉक) : महेश नारायण को टेक ऑफ के लिए।
- सर्वोत्कृष्ट नव–निर्देशक की फीचर फिल्म (सिल्वर पीकॉक) : किरो रूसो को डार्क स्कॅल के लिए।
- आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक : मनोज कदाम्ह द्वारा निर्देशित क्षितिज (ए होरिजन) आईएफएफआई 2017 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कनाडा के जाने माने फिल्म निर्माता एटम इगोयन को दिया गया।
- वर्ष के लिए भारतीय फिल्म–विभूति पुरस्कार (सिल्वर पीकॉक) श्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया।
- फिल्मोत्सव का भव्य समापन और पुरस्कार वितरण समारोह इसके उद्घाटन समारोह की ही भांति अभूतपूर्व भव्यता के साथ आयोजित किया गया। समापन समारोह माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी और गोआ के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर पर्रिकर की मौजूदगी में 28 नवम्बर को श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंदौर स्टेडियम, तालेगांव, गोवा में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री माननीय श्री किरेन रिजिजू, पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) माननीय श्री केजी अल्फोंस शामिल थे। इस अवसर पर उपस्थित कलाकारों ने इसमें अमिताभ बच्चन, सलमान खान, कैटरिना कैफ, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सुशान्त सिंह राजपूत, अक्षय कुमार और अन्य शामिल थे।
- फिल्मोत्सव के समापन पर प्रदर्शित फिल्प 'थिंकिंग ऑफ हिम' थी, जिसका निर्माण भारत–अर्जेन्टिना ने संयुक्त रूप से किया है। इसका निर्देशन पाब्लो केसर ने किया है और जिसका अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर कला अकादमी में किया गया था। फिल्म को इसके निर्देशक और अभिनेत्री एलेओनोरा वेक्सलर ने दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया।
- समारोह में उपस्थित प्रसिद्ध व्यक्तियों में सर्वश्री अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, शाहिद कपूर, सुभाष घई, मुकेश छाबड़ा, भूमि पेडनेकर, श्रीदेवी, बोनी कपूर, जाह्नवी कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सुशांत सिंह राजपूत, कैटरीना कैफ, सोनाली बेंद्रे, राजकुमार राव, अक्षय कुमार, राधिका आप्टे, करण जौहर, एकता कपूर, हुमा कुरैशी, अदिति राव हैदरी, डायना पेंटी, पूजा हेगड़े, आतिया शैट्टी, आलिया भट्ट, एआर रहमान, अनुपम खेर, सतीश कौशिक, सुधीर मिश्र, कबीर बेदी, एटम इगोइन, रोजर क्रिश्चियन, क्रैग मान, विशाल भारद्वाज, ईशान खट्टर, राइमा सेन, एलेयोनोरा वेक्सलर, मालविका मोहनन और अन्य शामिल थे।

चेक गणराज्य के राजदूत श्री मिलान होवोरका नई दिल्ली में माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी से मुलाकात करते हुए।

7

vrjk"Vh; lg;kx

Hkkjr ,o ;uLdk

भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्थाओं में से एक, यूनेस्को के संस्थापक सदस्यों में है। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और जनसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। विकासोन्मुख देशों की संचार क्षमताएं विकसित करने के उद्देश्य से यूनेस्को के 21वें महाधिवेशन ने 1981 में संचार के विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए अपनी स्वीकृति दी थी। इसकी स्थापना में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत आईपीडीसी का सदस्य होने के साथ ही इसकी अंतर–सरकारी समिति (आईजीसी) का भी सदस्य है।

यूनेस्को की सामान्य सभा का 39 वां सत्र 30 अक्तूबर से 14 नवम्बर, 2017 की अवधि में पेरिस में संपन्न हुआ जिसका लक्ष्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता एवं पत्रकारों की सुरक्षा, मीडिया में विविधता लाने को सुगम बनाने तथा सहभागिता बढ़ाने के साथ ही स्वतंत्र एवं दीर्घकालीन अवधि तक चलने वाले मीडिया संस्थानों को बढ़ावा देने हेतु उपयुक्त परिवेश उपलब्ध कराना था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुश्री अंजू निगम ने इस सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 06 –07 नवंबर, 2017 को संचार पर गठित उप–आयोग की बैठक में भाग लिया।

vrjk"Vh; ehfM;k dk;Øe

यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही नई योजना 'मानव संसाधन विकास' का एक घटक है। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- विभिन्न देशों के बीच बेहतर आपसी समझ के संवर्धन में मीडिया द्वारा निभाई जा सकने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना तथा इस दिशा में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए मीडिया से जुड़े व्यक्तियों के बीच और अधिक परस्पर संपर्क के साथ ही एक–दूसरे के बारे में अधिक जानकारी का प्रसार करना।
- लोकतान्त्रिक मूल्यों और विभिन्न समाजों के बीच सहिष्णुता बढ़ाने में मीडिया द्वारा निभाई जा सकने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना।
- इस योजना का व्यापक उदेश्य सूचना एवं समाचार पत्र (प्रिंट) माध्यमों के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देकर विभिन्न देशों के बीच आपसी संबंधों में मजबूती लाना है, यह इस बात से भी प्रेरित है कि सभी देशों के साथ सूचना एवं मीडिया के क्षेत्र में निकट सम्बन्ध विकसित होने ही चाहिए।
- भारत एवं अन्य देशों के मध्य संबंधों में सुदृढ़ता।
- समाचार माध्यमों, प्रसारण और फिल्मों के क्षेत्र में भारत तथा अन्य देशों के बीच विचारों के आदान –प्रदान का संवर्द्धन ।
- अद्यतन मीडिया प्रशिक्षण।
- संकटकालीन संचार।
- सामाजिक एवं मल्टीमीडिया प्रशिक्षण।

fofHkUu n'kk dk lkFk lkL—frd vknku& çnku dk;Øe ¼lhbih½

सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों/समझौतों का उद्देश्य भारत के अन्य देशों से संबंधों में सुदृढ़ता के साथ ही जन संचार, सूचना और फिल्मों के क्षेत्र में भारत व अन्य देशों के मध्य आदान–प्रदान को बढ़ावा देना है।

वर्ष 2017–18 के दौरान भारत और अन्य देशों जैसे फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील, माली और बेलारूस के मध्य क्रियान्वित किए जाने वाले 21 मसौदा सीईपी प्रस्ताव संस्कृति मंत्रालय से प्राप्त हुए हैं तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी केंद्री गांव, जिला रायपुर में 146 करोड़ रुपए की विविध योजनाएं लोगों को समर्पित करती हुई।

8 vu|lfpr tkfr;k@vu|lfpr tutkfr;k vkj vU; fiNMk oxl d fy, vkj{k.k

यह मंत्रालय सरकार द्वारा जारी आदेश/निर्देशों/दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए पदों और सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अधिकारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए गए हैं। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों/पीएसयू/अधिकारिक निकायों द्वारा पद आधारित सूची बनाई जाती है।

सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग और नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अन्य लाभों के लिए दिशानिर्देश और अनुदेश सख्त अनुपालन के लिए सभी मीडिया इकाइयों को भेजे जाते हैं।

डीओपीटी के निर्देश के अनुसार, 01.01.2017 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व से संबंधित सूचना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संदर्भ में डीओपी एंड टी के यूआरएल 'rrcps.nic.in' पर अपलोड करने के लिए संकलित की गई है।

01/01/2017 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत, मंत्रालय में कर्मचारियों की कुल संख्या के साथ–साथ सभी संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों में शामिल कर्मचारियों की संख्या:

J.kh	dy deZpkjh	,l lh	,lVh	vkchlh	vU;
,	503	73(14.51)	30(5.96)	25(4.97)	375
ch	1001	187(18.68)	64(6.39)	147(14.68)	603
lh (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	1393	452(10.28)	259(18.59)	340(24.40)	342
lh (सफाई कर्मचारी)	14	14(100)	0(0)	0(0)	0
dy	2911	726¼24-93½	353¼12-12½	512¼17-58½	1320

माननीय सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर नई दिल्ली में 5 मई, 2017 को भारत में डिजिटल प्रसारण के बारे में दो दिन के सेमिनार के समापन के अवसर पर भारतीय दूरसंचार नियमन प्राधिकरण (ट्राई) पर डाक टिकट जारी करते हुए।

9

e=ky; dh lsokvksa esa fn0;kax tuksa dk ifrfuf/kRo

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नोडल मंत्रालय विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियमों एवं दिशानिर्देशों को सभी मीडिया एककों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के प्रशासनिक अनुभागों में कड़ाई से पालन हेतु प्रसारित/वितरित किया जाता है। दिव्यांग जनों के हितों की देखरेख के लिए ही सचिवालय में एक सम्पर्क अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में डीओपीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार दिव्यांग जनों हेतु ऐसे आरक्षित पदों, जो पिछले काफी समय से खाली पड़े हैं, पर भर्ती के लिए विशेष अभियान चल रहा है। दिव्यांग जनों हेतु ऐसे आरक्षित पदों की जानकारी का प्रतिवर्ष संकलन करके डीओपीटी को प्रेषित किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में 01 जनवरी, 2018 को सीधी भर्ती वाले और प्रोन्नति वाले पदों पर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है :

'kkjhfjd fn0;kax 0;fä çfronu& 1

lsokvksa esa fn0;kax tuksa dk çfrfuf/kRo n'kkZus okyk okf"kZd fooj.k

¼01 tuojh] 2018 dks o"kZ 2017 grq½

मंत्रालय/विभाग : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय :

ç'kklu&2 vuqHkkx

समूह	निर्धारित पद				
	कुल	निर्धारित पद	वीएच	एचएच	ओएच
1	2	3	4	5	6
समूह क	1679	812	02	02	06
समूह ख	5834	4266	14	11	45
समूह ग	10941	7668	43	23	141
समूह घ	2510	1943	07	08	44
कुल	20964	14689	66	44	236

नोटः

(i) वीएच दृष्टि बाधित अर्थात ऐसे व्यक्ति जो दृष्टिहीन हों अथवा जिन्हें कम दिखाई देता हो (विजुअली हैंडीकैप्ड)।

(ii) एचएच श्रवण बाधित अर्थात जिन व्यक्तियों को कम सुनाई दे अथवा बधिर (हीयरिंग इम्पेयरमेंट) ।

(iii) ओएच अर्थात प्रमस्तिष्क पक्षाघात (सेलेब्रल पाल्सी) या चलने–फिरने में अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति (ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड) ।

i|i=&II

dyMj o"kZ 2017 esa fn0;kax tuksa dh fu;qfDr;ksa dk fooj.k

समूह	सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत दिव्यांग जनों हेतु आरक्षित पद			सीधी भर्ती कोटा में की गई कुल नियुक्तियां					प्रोन्नति कोटा के अंतर्गत दिव्यांग जनों हेतु आरक्षित पद			कोटा में की गई कुल नियुक्तियां				
	वीएच	एचएच	ओएच	कुल की गई नियुक्तियां	दिव्यांग जनों हेतु निर्धारित पदों पर की गई कुल नियुक्तियां	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल की गई नियुक्तियां	निर्धारित पदों पर की गई कुल नियुक्तियां	वीएच	एचएच	ओएच
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
समूह क	01	02	04	13	13	00	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00
समूह ख	03	13	08	01	01	00	01	00	00	00	00	04	04	00	00	00
समूह ग व घ	21	20	37	78	76	18	07	21	00	00	00	00	00	00	00	00
कुल	25	35	49	92	90	18	09	21	00	00	00	04	04	00	00	00

नोटः (i) वीएच दृष्टि बाधित अर्थात ऐसे व्यक्ति जो नेत्रहीन हों अथवा जिन्हें कम दिखाई देता हो (विजुअली हैंडीकैप्ड) ।

(ii) एचएच श्रवण बाधित अर्थात जिन व्यक्तियों को कम सुनाई दे अथवा बधिर (हीयरिंग इम्पेयरमेंट) ।

(iii) ओएच अर्थात प्रमस्तिष्क पक्षाघात (सेलेब्रल पाल्सी) या चलने–फिरने में अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति (ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड)।

(iv) शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों (दिव्यांगों) के लिए समूह क और ख पदों पर प्रोन्नति के लिए कोई आरक्षण नहीं है। तथापि, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों (दिव्यांगों) को ऐसे पदों पर प्रोन्नति दी जा सकती है बशर्ते ऐसा पद निर्धारित हो एवं शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों (दिव्यांगों) के लिए उपयुक्त हो।

पुणे स्थित भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार में संरक्षित एक फिल्म पोस्टर।

भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह– 2017 के दौरान महिला कलाकारों का रंगारंग प्रदर्शन।

10

jkt Hkk"kk d : i e
fganh dk ç;kx

हिंदी भारत संघ की आधिकारिक भाषा है। आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रगतिशील इस्तेमाल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के पास एक सुविचारित नीति है। भारत सरकार की राजभाषा नीति के तहत यह मंत्रालय हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देता रहा है। मुख्य सचिवालय में मंत्रालय की राजभाषा क्रियान्वयन समिति (ओएलआईसी) मुख्य सचिवालय और इससे जुड़े तमाम कार्यालयों में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग की निगरानी करती है। राजभाषा विभाग द्वारा तय किए गए वार्षिक कार्यक्रम के तहत राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का स्तर और कार्यालय संबंधी कार्यों में हिंदी को बढ़ावा देने वाले तरीकों और साधनों का स्तर जांचने के लिए मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें भी नियमित रूप से होती हैं।

अनुवाद, कार्यान्वयन और भारत सरकार की राजभाषा नीति की निगरानी में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए, मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में एक निदेशक, एक उपनिदेशक, दो सहायक निदेशक, दो वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और दो कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों की आवश्यकता को मंजूरी दी है।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत सभी कागजों/दस्तावेजों का प्रकाशन द्विभाषी रूप में सुनिश्चित करने और हिंदी में प्राप्त होने वाले पत्रों और हिंदी में ही हस्ताक्षर किए गए पत्रों का हिंदी में ही जवाब दिया जाना सुनिश्चित करने हेतु जांच बिंदुओं को सुदृढ़ बनाया गया था। इसके अलावा विभिन्न वर्गों और मीडिया इकाइयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई और राजभाषा नीति का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की गई।

कामकाज में हिंदी के उपयोग का प्रसार करने के लिए, 14–28 सितंबर 2017 तक मंत्रालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान निबंध लेखन, कविता लेखन, अनुवाद, टिप्पण–आलेखन, वाद–विवाद और प्रश्नोत्तर प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिनमें 70 अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार मूल टिप्पण और मसौदा तैयार करने के लिए दो प्रोत्साहन योजनाएं भी चालू हैं। इस वर्ष मंत्रालय के अनुभागों और मीडिया इकाइयों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना में, कार्यालयों में हिंदी के उपयोग पर वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर मंत्रालय तथा मीडिया प्रमुखों को इनाम/ट्रॉफी प्रदान की जाएंगी। कामकाज में हिंदी का इस्तेमाल सुचारू बनाने के लिए, मंत्रालय में हिंदी कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। इससे संबंधित कार्यालयों को अपने–अपने संस्थानों में हिंदी कार्यशालाएं आयोजित करने का निवेदन किया गया ।

साल के दौरान इस मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा पर बनाई गई संसद की दूसरी सह–समिति ने 14 कार्यालयों का निरीक्षण किया। समिति द्वारा दिए गए सुझावों का संज्ञान लेते हुए राजभाषा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए उन पर उपचारात्मक कदम उठाए गए।

भूतपूर्व माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस– 2017 के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की महिला कर्मचारियों को संबोधित करते हुए।

11 efgyk dY;k.k lac/kh xfrfof/k;k

राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशा–निर्देशों के आधार पर महिलाओं के लिए विकास कार्यक्रम और उनके कार्यान्वयन की योजनाओं की समीक्षा के लिए साल 1992 में मंत्रालय में एक महिला ईकाई का गठन किया गया था। इसके बाद विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा–निर्देशों के आधार पर 16 मई 2002 को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दों से संबंधित शिकायत समिति के तौर पर इस ईकाई का पुर्नगठन किया गया। 13 जनवरी 2006 को वाईडब्ल्यूसीए से एक बाहरी विशेषज्ञ को अनौपचारिक सदस्य के तौर पर इस महिला ईकाई में शामिल किया गया। महिला ईकाई को 25 अक्टूबर 2013 को 'आंतरिक शिकायत समिति' (आईसीसी) का नाम दिया गया। 3 जुलाई, 2017 को इस समिति का पुनर्गठन किया गया जिसमें संयुक्त सचिव सुश्री अंजू निगम अध्यक्ष के तौर पर, राष्ट्रीय प्रशासनिक सचिव सुश्री कल्पना डेविड भारत के वाईडब्ल्यूसीए से बाहरी विशेषज्ञ एवं मंत्रालय से तीन अन्य महिलाएं और एक पुरुष सदस्य शामिल हैं।

आंतरिक शिकायत समिति मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में भी कार्यरत हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय–समय पर जारी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के बारे में दिशानिर्देश भी इस मंत्रालय के सभी मीडिया इकाइयों को अनुपालन के लिए भेजा जाता है।

माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी नई दिल्ली में 29 अगस्त, 2017 को नीति आयोग द्वारा आयोजित 'वुमन ट्रांसफोर्मिंग इंडिया अवार्ड– 2017' वितरण समारोह को संबोधित करते हुए।

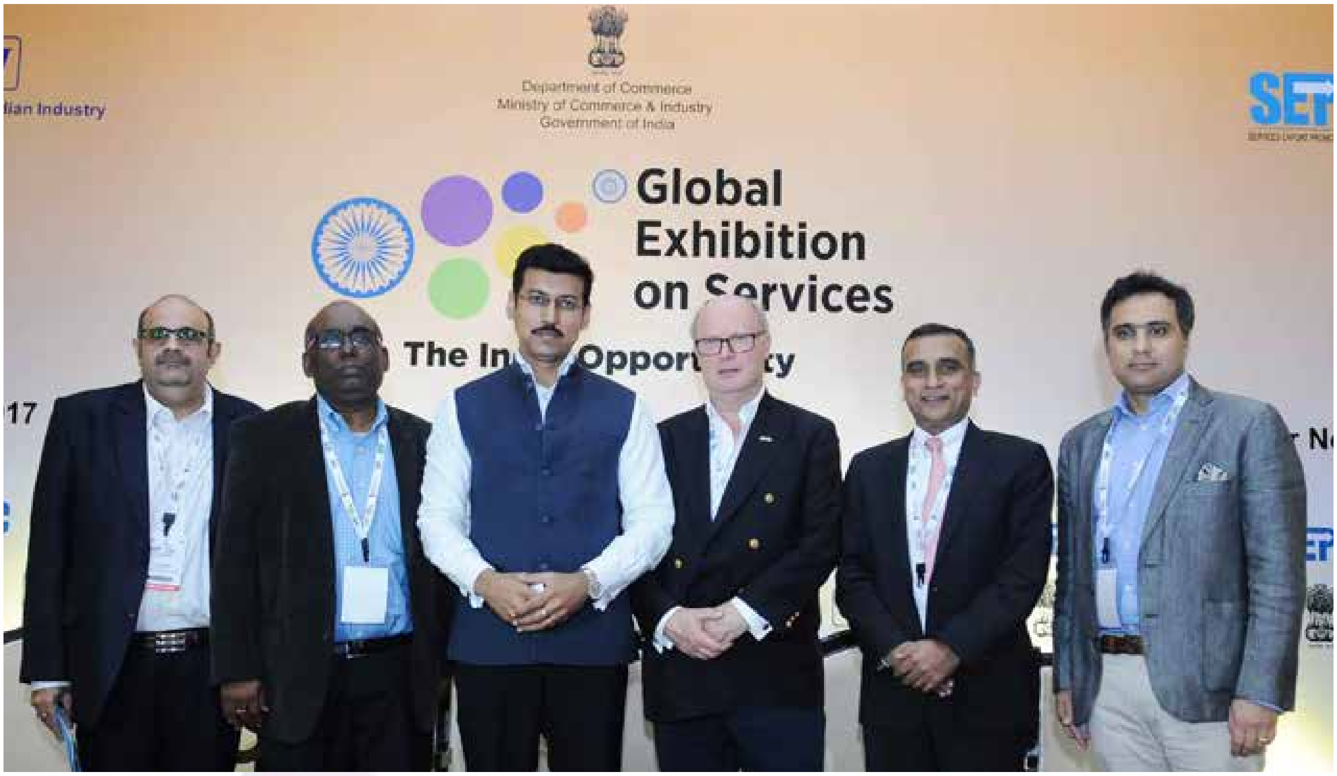

माननीय सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 18 अप्रैल, 2017 को ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.) में इंडिया एक्सपोजिसन मार्ट लिमिटेड में ग्लोबल एक्जीविजन ऑन सर्विसेज में विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ।

12 lrdlrk lc/kh ekeys

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित सतर्कता विभाग मंत्रालय के सचिव की देखरेख में कार्य करता है। मंत्रालय के सतर्कता विभाग का प्रमुख संयुक्त सचिव स्तर का मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) होता है जिसकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता समिति (सीवीसी) के अनुमोदन से मंत्रालय के ब्यूरो प्रमुखों में से की जाती है और वह उपसचिव (सतर्कता), अवर सचिव (सतर्कता) और सतर्कता अनुभाग के सहयोग से कार्य करता है। मंत्रालय का सीवीओ मंत्रालय और उसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालय और सीवीसी एवं सीबीआई के बीच एक कड़ी होता है। सीवीसी के अनुमोदन से प्रसार भारती के लिए एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों की सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। अन्य संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और पंजीकृत समितियों में भी अलग सतर्कता विभाग मौजूद है। मंत्रालय का सीवीओ, सीवीसी के दिशा–निर्देशों के अनुसार संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सतर्कता गतिविधियों के बीच समन्वय करता है।

भ्रष्टाचार की आशंका को कम करने के लिए कार्य प्रक्रियाओं को कारगर बनाने हेतु ठोस प्रयास किए गए। संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारियों को बारी–बारी से बदलने के प्रयास भी किए गए। नियमों और प्रक्रियाओं के समुचित अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित और आकस्मिक निरीक्षण किए गए। 1 अप्रैल, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 के दौरान 81 नियमित और 41 आकस्मिक निरीक्षण किए गए। इसके अतिरिक्त विभिन्न मीडिया इकाइयों और मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में 41 क्षेत्रों को निगरानी के लिए चुना गया। 30 अक्तूबर से 4 नवंबर, 2017 के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और उसकी मीडिया इकाइयों द्वारा एक सप्ताह का सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

एक अप्रैल, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 के दौरान मंत्रालय और उसकी मीडिया इकाइयों को विभिन्न स्रोतों से 571 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनकी जांच की गई और 10 मामलों में प्रारंभिक पूछताछ के लिए आदेश जारी किए गए। इसके अतिरिक्त इस अवधि में 9 मामलों (वर्तमान और पुराने) में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त की गईं। कठोर दंड के 31 और मामूली दंड के 4 मामलों में नियमित विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। इस अवधि के दौरान 7 मामलों में कठोर दंड और 8 मामलों में मामूली दंड दिए गए। आलोच्य अवधि के दौरान 1 अधिकारी को निलंबित किया गया और 7 मामलों में प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्रशासनिक कार्रवाई की गई।

मकोटा (राजस्थान) में एक किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर के उद्घाटन के अवसर पर संबोधित करते हुए।

13 नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का नागरिक चार्टर मंत्रालय की वेबसाइट http://mib.gov.in/documents/citizen.charter पर उपलब्ध है। चार्टर में निम्नलिखित 12 प्रमुख सेवाएं शामिल की गई हैं जो मंत्रालय से सम्बंधित सभी पक्षों के लिए उपलब्ध हैं :

(i) संभावित लाइसेंस धारकों को डीटीएच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंस निर्गत करना।

(ii) मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स को लाइसेंस निर्गत करना।

(iii) संभावित लाइसेंस धारकों को एचआईटीएस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंस निर्गत करना।

(iv) भारत में कार्य संचालन हेतु टीआरपी एजेंसियों का पंजीयन।

(v) अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए टीवी चैनलों द्वारा टेलीपोर्टस की स्थापना।

(vi) भारत से अपलिंक्ड टीवी चैनल्स द्वारा अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति।

(vii) विदेशों से अपलिंक्ड टीवी चैनल्स को डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति।

(viii) स्वयं सेवी संगठनों (एनजीओ), शिक्षा संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों/संस्थाओं द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) की स्थापना।

(ix) विशिष्टता/तकनीकी/वैज्ञानिक संवर्ग में विदेशी निवेश करने वाले किसी व्यक्ति/संस्था को विदेशी पत्र–पत्रिकाओं / आवधिक पत्रिकाओं / समाचार पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण प्रकाशित करने के लिए अनुमति पत्र निर्गत करने के मामले।

(x) समाचारों एवं सामयिक विषयों/समाचार पत्रों से जुडी विदेशी पत्रिकाओं में विदेशी निवेश करने वाले/अथवा नहीं करने वाले/विदेशी समाचार पत्र के प्रतिकृति संस्करण प्रकाशन की सुविधा प्राप्त किसी व्यक्ति/संस्था को विदेशी पत्र–पत्रिकाओं/आवधिक पत्रिकाओं/समाचार पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण प्रकाशित करने के लिए अनुमति पत्र निर्गत करने के मामले।

(xi) शिकायत निवारण तंत्र।

(xii) टीवी/सिनेमा तथा रिएलिटी शोज/वाणिज्यिक (कॉमर्शियल) धारावाहिकों के लिए फीचर फिल्मों की शूटिंग करने वाले विदेशी निर्माताओं को अनुमति पत्र निर्गत करने के मामले।

शिकायत निवारण तंत्र

मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों को कम्प्यूटरीकृत केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण (निगरानी) तंत्र (सीपीजीआरएएमएस) में पंजीकृत और संसाधित किया जाता है। सभी प्राप्त आवेदनों की इस उद्देश्य हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार पावती दी जाती है। पावती पत्र में शिकायत की पंजीयन संख्या, निवारण में लगने वाला अनुमानित समय तथा इस बारे में संपर्क हेतु उपलब्ध व्यक्ति का विवरण दिया जाता है। शिकायत वाले आवेदन सम्बंधित मीडिया एककों/कार्यालयों/विभागों को शिकायतों का सही निवारण करने के लिए इस निर्देश के साथ भेजे जाते हैं कि वे नियमानुसार शिकायतकर्ता को सही उत्तर दें। इनके निवारण की कार्रवाई का ब्यौरा जानने के लिए समय–समय पर सम्बंधित विभागों/कार्यालयों को स्मृति पत्र भेज कर व समीक्षा बैठकें कर निरंतर निगरानी की जाती है। सभी मीडिया इकाइयों में सामान्यतया संयुक्त सचिव/निदेशक/उपसचिव पद के समकक्ष अधिकारी को उस एकक के शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है। महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक प्रकृति के मामलों में उस मीडिया एकक/कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी तत्काल विचार–विमर्श कर मामले का निपटारा करते हैं। आवेदन के पूर्ण रूप से निपटारे की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राधिकरण/वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त शिकायतकर्ता को डाक द्वारा अथवा सीपीजीआरएमएस के माध्यम से दी जाती है।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग से लोक शिकायतों के निवारण/लोक शिकायतों हेतु गठित एकक को सक्रिय करने के बारे में प्राप्त दिशा निर्देशों को मंत्रालय के अधीन कार्यरत सभी मीडिया एककों/स्वायत्तशाषी निकायों इत्यादि में परिचालित (भेजा जाता) किया जाता

है। मंत्रालय से सम्बन्धित शिकायतों की निगरानी स्वयं सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भी की जाती है।

शिकायतों के निवारण हेतु निर्धारित समय सीमा

क्र.सं.	विषय	समय
01	शिकायतकर्ता को पावती/अंतरिम उत्तर जारी करना	03 दिन
02	शिकायत आवेदन को सम्बंधित प्रशासनिक शाखा/उत्तरदायी केंद्र को भेजने में लगने वाला समय	07 दिन
03	शिकायत प्राप्ति की तिथि अथवा शिकायतकर्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण/ शिकायतकर्ता से मांगी गयी अतिरिक्त सूचना की तिथि के बाद शिकायतकर्ता को अंतिम उत्तर भेजे जाने में लिया गया समय, जो भी बाद में पड़े।	02 माह

1.04.2017 से 31.12.2017 तक मंत्रालय में शिकायतों की स्थिति

01.04.2017 तक की पिछली शिकायतें	01.04.2017 से 31.12.2017 तक प्राप्त शिकायतें	कुल शिकायतें	01.04.2017 से 31.12.2017 तक शिकायतों का निस्तारण	31.12.2017 को लंबित शिकायतें
617	5103	5720	4945	771

मंत्रालय में प्राप्त अधिकतर शिकायतों की श्रेणियां निम्नलिखित हैं :

क्रम सं.	शिकायत श्रेणी	01.04.2017 से 31.12.2017 तक प्राप्त शिकायतों का प्रतिशत
1	अन्य मंत्रालयों के बारे में आवेदन	25 %
2	विविध मामले	24 %
3	डीटीएच ऑपरेटरों के खिलाफ शिकायत (एमएस और स्थानीय केबल ऑपरेटर)	14 %
4	सेवा मामले (नियमित और अनियमित)	10 %
5	टेलीविजन पर प्रसारित सामग्री	6 %
6	अन्य मामले	5 %
7	प्रेस सामग्री और पत्रकारों के मामले	4 %
8	भ्रष्टाचार और व्यवहार अनाचार	3 %
9	पेंशन मामले	2 %
10	फिल्म कंटेंट के मामले	1 %
11	संवेक्षाशील नियुक्तियां	1 %
12	प्रकाशन विभाग की पत्र—पत्रिकाओं की सदस्यता संबंधी मामले	1 %
13	उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के मामले	1 %
14	यौन उत्पीड़न के मामले	1 %
15	पंजीकरण और शीर्षक सत्यापन के मामले	1 %
16	सुझाव/पूछताछ	1 %

f'kdk;r fo'yss"k.k v/;;u

शिकायत निवारण प्रणाली को और मजबूत करने के लिए पिछले छह वर्षों यथा 2011 से 2014 तथा 2014 से दिसंबर 2017 तक के दौरान प्राप्त शिकायतों का मंत्रालय ने विश्लेषण किया है। इन शिकायतों के अवलोकन के आधार पर शिकायत निवारण के लिए सुनियोजित बदलाव किए हैं। इस सुनियोजन बदलाव के परिणाम स्वरूप, शिकायतों की संख्या घटी है।

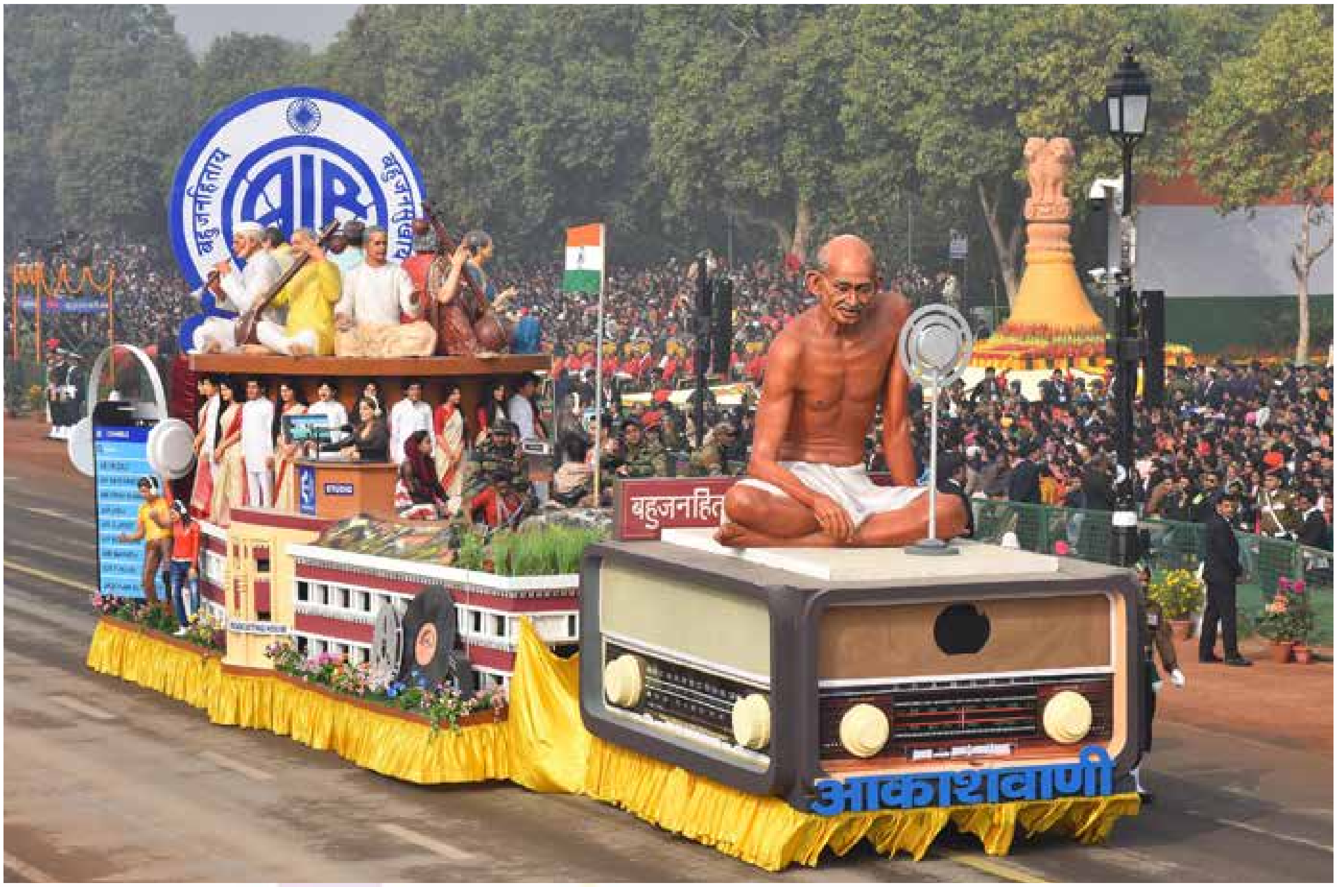

नई दिल्ली में 2018 की गणतंत्र दिवस परेड में आकाशवाणी की झांकी

माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी 17 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग को संबोधित करती हुई।

14 lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 ls lcf/kr ekeys

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई), 2005 देश के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह प्रशासन में खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने तथा संबंधित प्रासंगिक मामलों के बारे में सरकारी अधिकारियों से जनहित की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना के अधिकार का अर्थ है, किसी भी सूचना तक पहुंचने का अधिकार, जो किसी सरकारी अधिकारी के अंतर्गत या नियंत्रण में हो और इसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं–

1. कार्य, दस्तावेज, रिकार्ड का निरीक्षण।
2. टिप्पणियां, सारांश या दस्तावेजों या रिकार्ड की प्रामाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करना।
3. सामग्री के प्रामाणित नमूने प्राप्त करना।
4. सीडी अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रानिक मोड में या मुद्रित रूप में सूचना प्राप्त करना, जहां ऐसी सूचनाएं कंप्यूटर अथवा किस अन्य उपकरण में स्टोर की गई हों।

e|[; lfpoky; e vkjVhvkb vf/kfu;e dk fØ;kUo;u

प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए भारत सरकार के निर्णय अनुपालन में मंत्रालय द्वारा सूचना एवं सुविधा काउंटर की स्थापना 4 जुलाई, 1997 को की गई।

आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मंत्रालय और उसके संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, स्वायत्त निकायों से संबंधित सभी आवेदन, अपील और मुख्य सतर्कता आयुक्त के निर्णय सूचना केंद्र (आई.एफ.सी.) में प्राप्त होते हैं। सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्राप्त करने और अपीलकर्ता द्वारा दाखिल की गई अपील के बारे में निर्णय के लिए 28 मुख्य जनसूचना अधिकारी और 19 अपील प्राधिकारी पद नामित किए गए हैं। इनकी सूची मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध है।

1 जनवरी, 2018 तक आईएफसी में 1540 आवेदन और 193 अपील प्राप्त हुईं और सभी आवेदकों को आरटीआइ अधिनियम, 2005 में निर्धारित उचित उत्तर दिए गए। अप्रैल, 2013 में आरटीआई ऑनलाइन पर http://rtionline.gov.in नामक एक वेब पोर्टल शुरू किया गया। मंत्रालय को 849 ऑनलाइन आवेदन और 111 अपील प्राप्त हुईं। डाक के माध्यम से प्राप्त हुए आरटीआई आवेदनों को आरटीआई के वेब पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार/निरीक्षण प्रभार के रूप में 13,911 रुपयों की धनराशि प्राप्त हुई है। भारत के विभिन्न राज्यों के लगभग 1300 आगंतुकों को आईएफसी द्वारा सेवा प्रदान की गई है जिन्होंने टीवी चैनलों, केबल टीवी आदि के बारे में जानकारी मांगी थी। सूचना और सुविधा केंद्र संगठन के ग्राहकों/उपभोक्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है–

(क) संगठन द्वारा दी गई सेवाओं, कार्यक्रमों और उसके द्वारा समर्थित योजनाओं तथा संबद्ध नियमों एवं प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी ब्रोशर, फोल्डरों आदि के माध्यम से प्रदान की गईं।

(ख) संगठन की सेवाएं अनुकूल ढंग से, समय पर, सक्षमतापूर्वक, पारदर्शी तरीके से प्राप्त करने में ग्राहक/उपभोक्ता को सुविधाएं प्रदान करना और सार्वजनिक उपयोग के लिए अपेक्षित प्रपत्र आदि उपलब्ध कराना।

(ग) संगठन की सेवाओं/योजनाओं/कार्य प्रणाली के संदर्भ में संगठन द्वारा विकसित सेवा गुणवत्ता मानकों, समय संबंधी मानदंड आदि के बारे में सूचना देना।

(घ) संगठन के जनशिकायत निवारण तंत्र के बारे में श्रेणीबद्ध व्यवस्था की जानकारी देना, और

(ङ) शिकायतों/आवेदनों/अनुरोधों/प्रपत्र (संगठन द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे) में को प्राप्त करना, उनकी पावती देना और उन्हें संगठन

में संबद्ध प्राधिकारी को अग्रसारित करना और उनकी स्थिति/निपटान के बारे में सूचना प्रदान करना।

(च) आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत एक सूचना नियमावली सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है, जो सूचना और सुविधा काउंटर पर उपलब्ध है।

लगातार जांच एवं समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम में निहित प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है।

vkjVhvkbl vkonuk d fuiVkj lc/kh 0;oLFkk

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत अनुभाग में प्राप्त सभी आवेदनों की छंटनी की जाती है। जिन आरटीआई आवेदनों का संबंध इस मंत्रालय से नहीं होता, उन्हें संबद्ध मंत्रालय के सीपीआईओ को हस्तांतरित कर दिया जाता है। शेष आवेदन आरटीआई रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि करने के बाद संबद्ध सीपीआईओ को अग्रसारित कर दिए जाते हैं।

बकाया आवेदनों के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई की व्यवस्था के रूप में सीपीआईओ को 'कलर कोडेड रिमाइंडर' जारी किए जाते हैं, अर्थात 15 दिनों के बाद नीले कागज पर और 25 दिनों के बाद गुलाबी कागज पर क्रमशः अनुस्मरण पत्र भेजा जाता है ताकि आवेदक को निर्धारित 30 दिनों की अवधि में सूचना प्रदान किए जाने में कोई भी कोताही नहीं होने पाए।

आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त आरटीआई आवेदन और अपीलों को मंत्रालय के संबंधित सीपीआईओ/एए को अग्रसारित कर दिया जाता है। सभी सीपीआईओ और एए को आवेदन/अपील की स्थिति की जांच और ऑनलाइन उत्तर भेजने के लिए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान किया गया है।

lpuk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 dh /kkjk 4 dk dk;kUo;u

मंत्रालय ने धारा 4 (ख) (I) और 4 (ख) (II) के तहत सरकारी प्राधिकरण में उपलब्ध सूचना को बिना मांगे ही जनता को उपलब्ध कराने और उसे वेबसाइट पर डालने का दायित्व पूरा कर दिया है। आरटीआई आवेदन, अपील और उनके उत्तर मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। आंकड़ों की तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से सीआईसी वेबसाइट पर अंतरित की जाती है जिनमें प्राप्त, रद्द की गई, स्थानांतरित आवेदनों/अपीलों के आंकड़े दिए जाते हैं।

e=ky; d dk;ky;k e lpuk vf/kdkj vf/kfu;e dk dk;kUo;u

इस मंत्रालय के तहत सभी संबद्ध/अधीनस्थ/सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों और स्वायत्त निकायों द्वारा सीपीआईओ और अपील प्राधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वे इस बारे में डीओपीटी (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार काम कर रहे हैं।

माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ. ए. सूर्यप्रकाश से 'सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान– 2017' का स्मृति चिन्ह ग्रहण करते हुए।

हैदराबाद में 20वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह के उद्घाटन के अवसर पर बाल कलाकारों द्वारा भव्य प्रदर्शन।

15

y[kkdu vkj vkrfjd y[kk ijh{kk

lpuk vkj çlkj.k e=ky; dk y[kkdu lLFkku

1. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव, मुख्य लेखा अधिकारी के तौर पर मुख्य लेखा नियंत्रक और वित्तीय सलाहकार की सहायता से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं।

2. जीएफआर 2017 के नियम 70 के अनुसार, मंत्रालय/विभाग के सचिव, जो मंत्रालयधविभाग के मुख्य लेखा अधिकारी हैं –

i. अपने मंत्रालय या विभाग के वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होंगे।

ii. यह सुनिश्चित करेंगे कि मंत्रालय को विनियोजित सार्वजनिक निधियों का उपयोग जिस उद्देश्य के लिये वह थीं के लिये किया जाता है।

iii. उस मंत्रालय के उक्त परियोजना उद्देश्यों को प्राप्त करने में मंत्रालय के संसाधनों का प्रदर्शन मानकों के साथ पालन करते हुए प्रभावी, कुशल, किफायती और पारदर्शी उपयोग के लिए जिम्मेदार रहेंगे।

iv. लोक लेखा समिति तथा अन्य संसदीय समिति के समक्ष निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

v. क्या उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है, यह निर्धारित करने के लिये अपने मंत्रालय को सौंपे गये कार्यक्रमों और परियोजनाओं के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा और निगरानी करेंगे।

vi. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नियमों, दिशा–निर्देशों या निदेशों के अनुसार अपने मंत्रालय से संबंधित व्यय और अन्य विवरण की तैयारी के लिए जिम्मेदार रहेंगे।

vii. यह सुनिश्चित करें कि उनका मंत्रालय वित्तीय लेन–देन का पूर्ण और उचित रिकॉर्ड रखता है और प्रणालियों और प्रक्रियाओं को ग्रहण करता है जो हर समय पर आंतरिक नियंत्रण रखते हैं।

viii. यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका मंत्रालय कार्यों के निष्पादन, साथ ही साथ सेवाओं और आपूर्ति की खरीद के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया का पालन करता है और इसे निष्पक्ष, न्यायसंगत, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लागत प्रभावी ढंग से लागू करता है।

ix. अपने मंत्रालय को आश्वस्त करने के लिए प्रभावी और उपयुक्त कदम उठाएंगे:

(ए) सरकार के लिये सभी देय राशि एकत्रित करें और

(बी) अनाधिकृत, अनियमित और व्यर्थ व्यय से बचें

3. नागरिक लेखा नियमावली के अनुच्छेद 1.3 के अनुसार, मुख्य लेखा नियंत्रक की ओर से मुख्य लेखा अधिकारी जिम्मेदार हैं:

(क) वेतन और लेखा कार्यालयों/प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से सभी भुगतानों को व्यवस्थित करने उसके अलावा, जहां आहरण और वितरण अधिकारी कुछ तरह के भुगतान करने के लिए अधिकृत हैं।

(ख) मंत्रालय/विभाग के खातों का संकलन और एकत्रीकरण और निर्धारित प्रारूप में उनको लेखा नियंत्रक सामान्य को प्रस्तुत करने, अपने मंत्रालय/विभाग के लिये अनुदान की मांग के लिये वार्षिक विनियोग खाते तैयार करने, और उन्हें विधिवत लेखा–परीक्षण और सीजीए को प्रस्तुत करना, मुख्य लेखा प्राधिकरण द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ।

(ग) विभाग के विभिन्न अधीनस्थ संरचनाएं और वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा बनाये गये भुगतान और खातों के अभिलेखों के आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था करना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बनाए गए सरकारी मंत्रालयोंधविभागों के लेन–देन से संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण करना।

4. लेखा के मुख्य नियंत्रक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, अपने कर्तव्यों को नियंत्रित करता है जिसमें नियंत्रक, उप–आयुक्त नियंत्रक, सहायक नियंत्रक, 03 प्रा. मुख्यालय में लेखा अधिकारी और चौदह वेतन और लेखा कार्यालयों की सहायता से, जीपीएफ/पेंशन के उद्देश्य के लिए प्रसार भारती के साथ संलग्न 06 सहित प्रसार भारती (एचक्यू) और उनकी फील्ड संरचनाएं जोनल आंतरिक लेखा परीक्षा दल चेन्नई,

कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में तैनात किए गए हैं, जिनके कार्यों को मुख्यालय में आंतरिक लेखा परीक्षा विंग द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है।

5. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबंध में विभागीय लेखा संगठन की समग्र जिम्मेदारियां हैं: –

* मंत्रालय के मासिक खातों का एकीकरण और उसको सीजीए को प्रस्तुत करना।
* वार्षिक विनियोग खाते
* केंद्रीय लेन–देन का विवरण
* 'एक नजर में खाता' की तैयारी
* केंद्रीय वित्त खाते जो सीजीए, वित्त मंत्रालय और लेखा परीक्षण के प्रमुख निदेशक को प्रस्तुत किये जाते हैं।
* अनुदेयी संस्थानों/स्वायत्त निकायों आदि को अनुदान सहायता का भुगतान।
* यदि डीओपीटी, वित्त मंत्रालय और सीजीए आदि जैसे अन्य संगठनों के साथ परामर्श में आवश्यक हो, सभी पीएओ और मंत्रालय को तकनीकी सलाह प्रदान करना।
* प्राप्ति बजट की तैयारी
* पेंशन बजट की तैयारी
* वेतन एवं लेखा कार्यालय/चेक आहरण डीडीओ की ओर से और उसके लिए चेक बुक प्राप्त और आपूर्ति करना।
* लेखा कार्यालय के नियंत्रक जनरल के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना और लेखांकन मामलों और मान्यता प्राप्त बैंक में समग्र समन्वय और नियंत्रण को प्रभावी करने के लिए।
* मान्यता प्राप्त बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से किए गए सभी प्राप्तियों और भुगतान को सत्यापित और समाधान करना।
* सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित खातों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखना और नकदी शेष राशि का मिलान करना।
* शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना
* पेंशन/भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का त्वरित समाधान।
* सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन मंत्रालय, अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों और उसके अनुदेयी संस्थाएं, स्वायत्त निकाय आदि का आंतरिक लेखा परीक्षण।
* सभी संबंधित प्राधिकरणों/प्रभागों को उपलब्ध लेखा जानकारी उपलब्ध कराना।
* सूचना और प्रसारण मंत्रालय का बजट समन्वय कार्य।
* समय–समय पर नई पेंशन योजना की निगरानी और पेंशन मामलों का संशोधन।
* लेखा और ई–भुगतान का कम्प्यूटरीकरण।
* लेखा संगठन के प्रशासनिक और समन्वय कार्य।
* केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत अनुदेयी संस्थानों सहित पीएफएमएस का रोल आउट।
* सूचना और प्रसारण मंत्रालय में गैर–कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी)

आंतरिक लेखा परीक्षण खंड– आंतरिक लेखा परीक्षण खंड ने मंत्रालय के कार्यालयों के खातों के लेखा–परीक्षा का काम किया है यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं को इन दफ्तरों द्वारा दिन–प्रतिदिन कामकाज में पालन किया जाता है। आंतरिक ऑडिटिंग एक स्वतंत्र गतिविधि है जिसका मूल उद्देश्य मूल्यांकन के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण लाकर अपने उद्देश्यों को पूरा करना और जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और प्रशासन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता में सुधार लाने में संगठन की मदद करना है।

मुख्य लेखा अधिकारी और वित्तीय सलाहकार के समग्र मार्गदर्शन के तहत काम कर रहे आंतरिक लेखा परीक्षण खंड ने एक प्रभावी और आंतरिक लेखा परीक्षा अभ्यास को सुनिश्चित करने के लिए उचित तरीके से प्रशासन संरचनाओं, क्षमता निर्माण और तकनीक को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, 312 निर्धारित इकाइयों में से 73 कार्यालयों का लेखा परीक्षण किया गया था। लेखा परीक्षण का केंद्रबिंदु अधिक भुगतान किए गए वेतन का निर्धारण साथ ही लघु वेतन में भुगतान में त्रुटियों का पता लगाना था। विभिन्न लेखापरीक्षा के अवलोकन के

समग्र वित्तीय अनुमान लगभग 7025.83 लाख रुपये था।

egRoi.kZ vfu;ferrkvksa vkSj dqy jkf'k dk vuqPNsnksa dk lkjka'k uhps foLr`r gS%

Øe la	vfu;ferrkvksa dh çd`fr	vuqPNsnksa dh la[;k	dqy jkf'k¼₹ yk[k esa½
1	केंद्र सरकार के विभागों/राज्य सरकार/सरकारी निकायों/ निजी पक्षों से सरकारी देयों की गैर वसूली	26	3211.67
2	अधिक भुगतान	37	53.82
3	निष्क्रिय मशीनरी/अतिरिक्त भंडार	0	0.00
4	हानि/व्यर्थ व्यय में	10	185.96
5	अनियमित व्यय	20	2066.87
6	अनियमित खरीद	14	108.52
7	अग्रिमों का गैर–समायोजन–		
	* आकस्मिकता अग्रिम	4	180.55
	* टीए ए अग्रिम	5	76.59
	* एलटीसी अग्रिम	6	9 .74
8	सरकार का अवरुद्ध पैसा	8	977.28
9	गैर–लेखाकृत महंगे भंडार/सरकारी धन	0	0.00
10	विशेष प्रकृति का कोई अन्य उत्पाद	7	154.83
	dqy	137	7025-83

vkbZvkj,y, ¼O;fäxr fØ;k'khy ystj ys[kk ç.kkyh½

वेतन एवं लेखा कार्यालय (आईआरएलए) अन्य मंत्रालयों के अन्य विभागीय वेतन एवं लेखा कार्यालयों के साथ अस्तित्व में आया है। आईआरएलए प्रणाली (समूह–ए अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत क्रियाशील लेजर लेखा) का विचार एक केंद्रीय प्रणाली में सभी सेवा और भुगतान विवरण रखने से उत्पन्न हुआ ताकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती के मीडिया इकाइयों के अधिकारी, जिनके पास एक अखिल भारतीय हस्तांतरण देयता है, अपना वेतन सरलतापूर्वक निकाल सकते हैं। वेतन एवं लेखा कार्यालय (आईआरएलए) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों की सेवा और वेतन रिकॉर्ड और देशभर में विभिन्न शहरों में स्थित प्रसार भारती (दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो) के कार्यालयों का रखरखाव कर रहा है।

बैंकिंग व्यवस्थाः – भारतीय स्टेट बैंक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में वेतन एवं लेखा कार्यालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अधिकृत बैंक है। गैर–कर–रसीद पोर्टल (एनटीआरपी) के अलावा संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय/सीडीडीओ कार्यालय द्वारा अधिकृत बैंकों को रसीदें भी प्रेषित की जाती हैं।

कॉम्पेक्ट (वेतन और लेखा 2000):

मौजूदा उन्नत सॉफ्टवेयर को बदलने के लिए वेतन और लेखा कार्यालय स्तर पर उपयोग के लिए एक बहु उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर शामिल किया गया था। यह सॉफ्टवेयर सभी वेतन और लेखा कार्यालयों में कार्य का कम्प्यूटरीकरण करने की दृष्टि से विकसित किया गया था। इस सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित विशेषताएं थीं:

1. पूर्व– जांच (एकीकृत भुगतान और लेखा कार्य और स्वचालित चेक मुद्रण)
2. इलेक्ट्रॉनिक बैंक पुर्नसमाधान
3. सामान्य भविष्य निधि

4. खातों का संकलन

5. पेंशन मामलों का निपटान

6. व्यय बनाम बजट नियंत्रण

b&iseV ç.kkyh

चूंकि, आईटी अधिनियम, 2000, एक्ट की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति या प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल रूप से प्रमाणीकृत डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को मान्यता देता है, खातों के नियंत्रक जनरल ने डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक परामर्श के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (ई–भुगतान) के लिए कॉम्पेक्ट में एक सुविधा विकसित की थी जिसने भुगतान की मौजूदा प्रणाली को बदल दिया।

विकसित ई–भुगतान प्रणाली के अर्न्तगत देय राशि का भुगतान सरकार द्वारा धनराशि का क्रेडिट कॉम्पैक्ट से उत्पन्न डिजिटली स्वामित्व वाली ई–सलाह के माध्यम से एक सुरक्षित संचार चौनल पर 'सरकारी ई–भुगतान गेटवे (जीईपीजी)' के द्वारा सीधा प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में किया जाता था।

ljdkjh b& Hkqxrku xsVos ¼thbZihth½

सरकारी ई– भुगतान गेटवे (जीईपीजी) एक पोर्टल है जिसे सीजीए कार्यालय द्वारा विकसित किया गया है और इसे सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से एसटीक्यूसी प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। जीईपीजी सेवा वेतन और लेखा कार्यालय पर कॉम्पैक्ट आवेदन और बैंकों/भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान के बीच मध्यवर्ती के

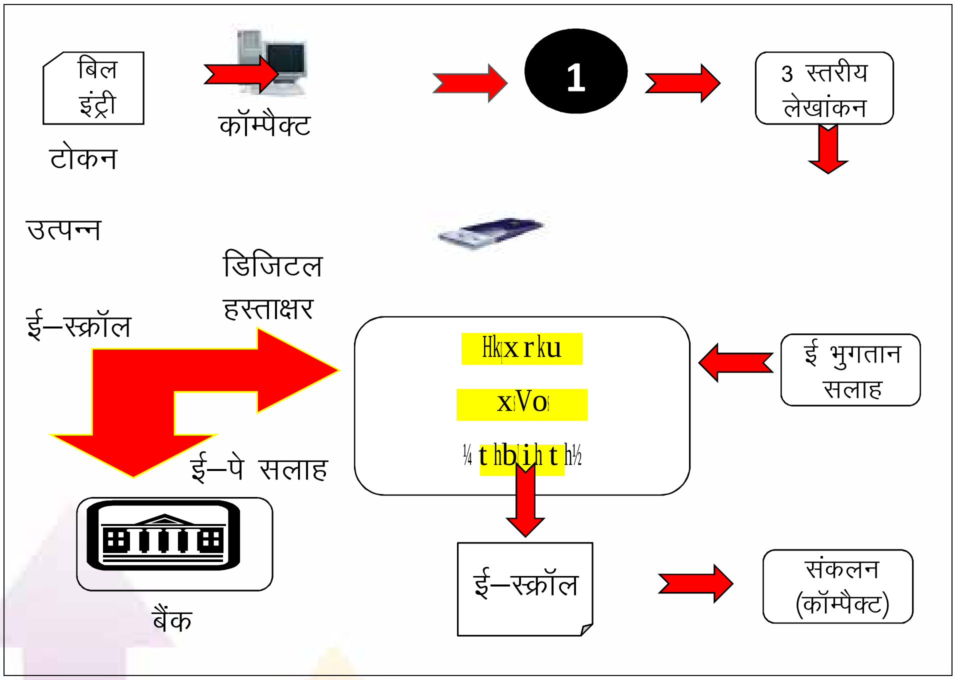

b& Hkqxrku flLVe dh çfØ;k çokg

रूप में कार्य कर और स्वतः पंजीकरण प्रक्रिया, ई–भुगतान परामर्श और ई–स्क्रॉल संचार को स्वचालित करने की सुविधा प्रदान करती है।

b& Hkqxrku vkSj thbZihth ç.kkyh dh eq[; fo'ks"krk,a

उच्च सुरक्षा मानक और लेनदेन के सिस्टम लॉग्स

प्रभावी ई–भुगतान के लिए वेतन एवं लेखा कार्यालय एप्लीकेशन में सुरक्षा आवश्यकताएं शामिल हैं :

* 128 बिट पीकेआई एन्क्रिप्शन (कूटलेखन)
* सूचना की संपूर्णताः हैश एल्गोरिदम (हैश कलन विधि) (एसएचएआई): सुरक्षा मानकों को डेटा के प्रति सुनिश्चित विश्वास, डेटा की प्रामाणिकता और बैंक को वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा इंटरनेट पर अवगत कराए गए डेटा की संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
* गैर–परित्याग– 128 बिट पीकेआई इन्फ्रास्ट्रक्चर (आरबीआई द्वारा सुझाई गई) के आधार पर कुंजी

उत्पादन/डिजिटल हस्ताक्षर।

* प्रत्येक ई–भुगतान प्रमाणीकरण और स्वचालित पुनर्समाधान के मदवार निगरानी के साथ डिजिटली हस्ताक्षरित ई–भुगतान प्रमाणीकरण।

डिजिटल हस्ताक्षर का पंजीकरणः भुगतान और लेखा अधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करता है और जीईपीजी पोर्टल के साथ डिजिटल हस्ताक्षर रजिस्टर करता है। संबंधित बैंक जीओपीजी पोर्टल से भुगतान एवं लेखा अनुभाग डिजिटल हस्ताक्षर डाउनलोड करते हैं तथा साथ ही संबंधित बैंकों के डिजिटल हस्ताक्षर भी बैंकों द्वारा भुगतान एवं लेखा अनुभाग को प्रदान किए गए ई–भुगतान स्क्रॉल के प्रमाणीकरण में सहायता करते हैं।

ई–स्क्रॉलः सभी सफल ई–भुगतानों के लिए बैंक द्वारा जेपीजीपी पर एक डिजिटली रूप से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक स्क्रॉल जनरेट और अपलोड किया गया है। पुनर्समाधान और अन्य एमआईएस प्रयोजनों के लिए पीओएस द्वारा ई–स्क्रॉल डाउनलोड किए गए हैं और कॉम्पैक्ट सिस्टम में शामिल किए गए हैं

b& Hkxrku d Qk;n

- डिजिटली हस्ताक्षरित विशिष्ट ई–प्राधिकरण आईडी का उपयोग करके ऑनलाइन निधि ट्रांसफर के कारण समय और मेहनत की बचत।
- भुगतान का सुरक्षित तरीका
- भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता
- शारीरिक जांच और उनके मैन्युअल प्रसंस्करण का उन्मूलन।
- अपने बैंक खाते में प्राप्तकर्ता द्वारा चेक की मैन्युअल जमा राशि की बाधाओं को खत्म करना।
- समग्र भुगतान प्रसंस्करण दक्षता में वृद्धि।
- भुगतानों के ऑनलाइन स्वतः मिलान
- खातों के कुशल संकलन
- सभी स्तरों पर लेन–देन का पूरा लेखा–परीक्षा।

वर्तमान में, सभी 14 (चौदह) वेतन और लेखा कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण (प्रसार भारती के 06 पीएओ सहित) के पीएफएमएस पर सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। सभी भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किए जाते हैं और ई–पेमेंट सीधे लाभार्थी के खाते में जमा किए जाते हैं।

depkjh lpuk ç.kkyh ¼bvkb, l½ e,Mîy%

पीएफएमएस सिस्टम वेतन बिल और जीपीएफ, आयकर, और एचबीए, एमसीए, और ओएमसीए आदि जैसे ब्याज वाले असर वाले अग्रिमों के लिए आवश्यक कार्यक्रम तैयार करता है।

xj dj jlhn ikVy ¼,uVhvkjih½

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में एनटीआर पोर्टल 1 नवंबर 2016 से कार्यात्मक है।
- 01.04.2017 से 30.11.2017 की अवधि के लिए चालू वित्त वर्ष (2017–18) में मंत्रालय की गैर–कर राजस्व का संग्रह ₹ 1378.87 करोड़ और एनटीआर ई–पोर्टल (https://bharatkosh-gov-in) पर भारतकोष के माध्यम से ₹ 1378.87 करोड़ से अलावा कुल ₹ 1345.94 करोड़ एकत्र किए गए हैं।

fMftVhdj.k d fy, ub igy

d½ xfrfof/k;k ¼1 vçy] 2017 l 30 uocj] 2017½

- डिजिटल लेनदेनः भारत सरकार के आदेशों के अनुसार, ₹ 5,000 और ऊपर का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड (ई–भुगतान) के माध्यम से वितरित किए जाते हैं।
- जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीदः सरकारी ई बाजार (जीईएम) पोर्टल के जरिए माल और सेवाओं की खरीद से संबंधित प्रावधान भारत सरकार द्वारा जीएफआर 2017 के नियम 149 में बनाए गए हैं। जीएफआर 2017 के नियम 149 के प्रावधानों के अनुसार 'मंत्रालयों या विभागों द्वारा माल और सेवाओं की खरीद जीईएम पर उपलब्ध माल या सेवाओं के लिए अनिवार्य होगी'।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी स्वायत्त निकायों/अनुदान संस्थाओं में ईएटी मॉड्यूल का रोल–आउटः

ग्यारह (11) स्थानों पर, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, शिलांग और चेन्नई में व्यापक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था जिसमें प्रसार भारती के 508 केंद्र/फील्ड कार्यालयों को प्रशिक्षित किया गया। 01 अक्टूबर, 2017 से पीएफएमएस के व्यय एडवांस एंड ट्रांसफर (ईएटी) मॉड्यूल पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी स्वायत्त निकायों/अनुदान संस्थाओं को भी रोल आउट किया गया है।

- ड्राइंग एवं डिबर्सिंग ऑफिसर्स (डीडीओ) निर्देशिकाः

पीएओ/सीडीडीओ/एनसीडीडीओ की एक विस्तृत निर्देशिका जून, 2017 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए पहली बार प्रकाशित हुई थी।

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय में आंतरिक लेखा परीक्षा समिति का संविधानः आदेशों के अनुपालन में, सचिव (मुख्य लेखा अधिकारी होने के नाते) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक आंतरिक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है जिसका जनादेश समय–समय पर आंतरिक ऑडिट फंक्शन का प्रदर्शन और प्रशासन की दिशा और समीक्षा के लिए जोखिम क्षेत्र को निर्दिष्ट करने के लिए है, जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा को कार्य करना चाहिए।
- पूर्व 2016 के पेंशन मामलों का संशोधनः 2016 के पूर्व पेंशन मामलों के 26,605 संशोधनों में, लगभग 23,000 पेंशन के मामलों को प्रसार भारती और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पीएओ द्वारा 11 दिसंबर, 2017 को संशोधित किया गया है, जो सीपीएओ को भेजा गया है और डीडीओ/मुख्य कार्यालयों से लंबित मामलों की रसीद प्राप्ति के बाद क्रमशः शेष मामलों को 31 दिसंबर, 2017 से पहले पीएओ द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

[kb foÙkh; o"kZ dk fy, çLrkfor xfrfof/k;k ¼2017&18½

- डीएवीपी के पीडी खाते बंद करने और विभागीय लेखा संगठन में मानव–शक्ति का विकास, सीडीडीओ को निकालने और पीएओ (डीएवीपी) और पीएओ (अन्य मीडिया इकाइयों) में पीएओ (डीएवीपी) की पुनःसंरचना।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड संरचनाओं सहित मुख्य सचिवालय/अधीनस्थ/संलग्न कार्यालयों के पीएफएमएस में कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) मॉड्यूल का कार्यान्वयन।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सीडीडीओ अट्ठाइस (28) कार्यालयों में पीएफएमएस के सीडीडीओ मॉड्यूल का कार्यान्वयन।

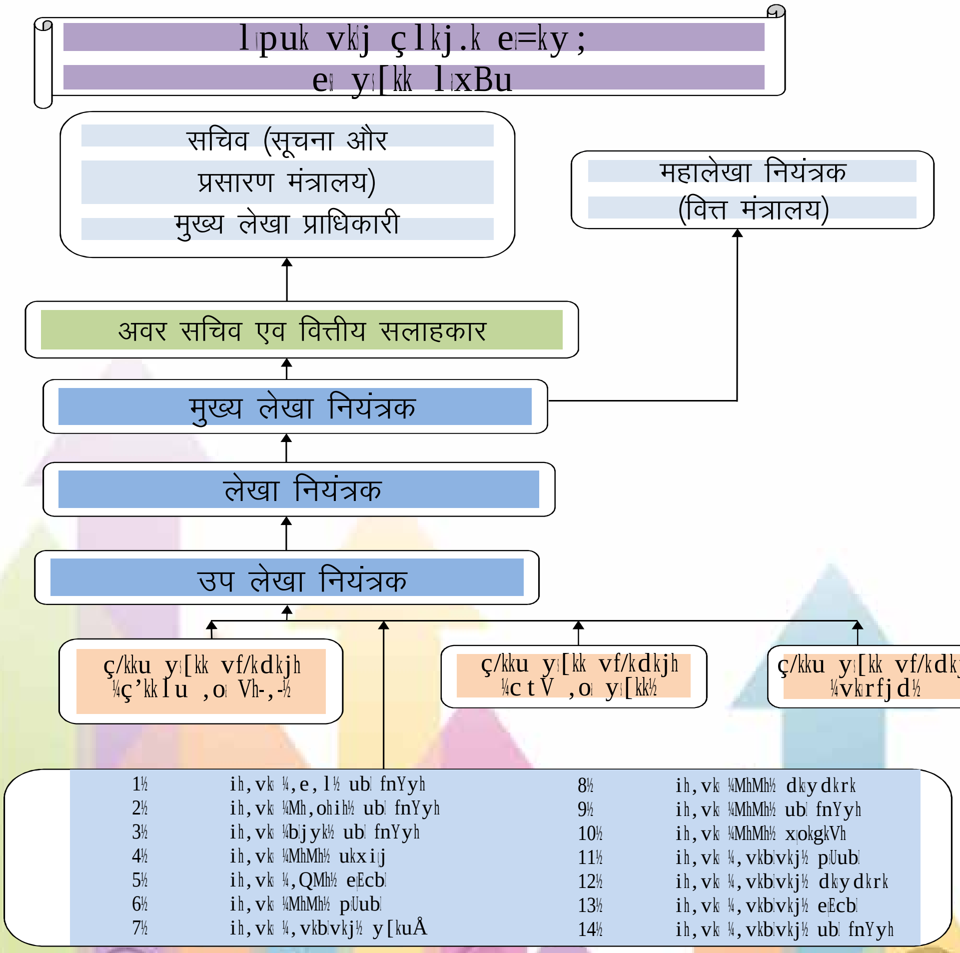

सूचना और प्रसारण सचिव श्री एन.के. सिन्हा भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह– 2017 के दौरान मीडिया सेंटर का निरीक्षण करते हुए

सूचना और प्रसारण सचिव श्री एन.के. सिन्हा भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह– 2017 के समापन समारोह में निर्देशक महेश नारायणन को उनकी फिल्म 'टेक ऑफ' के लिए विशेष ज्यूरी पुरस्कार प्रदान करते हुए

16 fu;=d vkj egky[kk ijh{kd dh fVIif.k;k

20 fnlcj] 2017 dk foÙk o"k 2017 &18 grq çkIr fu;=d ,o egkys[kk ijh{kd dh fVIif.k;k%

Øe l-	çfronu l- ,o o"k	vuPNn l-	fo"k; dk fooj.k
1	2017 का 12 वां	14.1	fQYe ,o Vyhfo tu lLFkku ¼,QVhvkbvkb½ iq.k dh ç'kklfud dfe;k छात्र अपने सम्बंधित पाठ्यक्रमों को निर्धारित समय सीमा में पूरा नहीं कर रहे हैं, जिससे छात्र पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि से अधिक छात्रावासों में रुके हुए हैं। लेखा परीक्षण में यह भी कहा गया है कि शिक्षा सत्र वर्ष 2010 –11, 2014–15 और 2015–16 में प्रवेश रुके रहे तथा छात्र शैक्षणिक सूची और छात्रावास की पंजिकाओं में अपने निर्धारित पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित शुल्क/ छात्रावास शुल्क एवं अन्य शुल्कों का भुगतान किए बिना ही बने रहे, जिस कारण 11. 38 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई। सेवा कर के अनियमित भुगतान, अग्रिम भुगतानों की अतिरिक्त स्वीकृति तथा बिना किसी समानुपातिक लाभ के परामर्शी शुल्क पर अनुत्पादक व्यय का मामला भी सामने आया है।

माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी 20 नवंबर, 2017 को पणजी (गोवा) में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह– 2017 के उद्घाटन के अवसर पर संबोधित करते हुए

17

dIV d: Q:lyk:@vkn:'kk: ij vey

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार, कैट के निर्णयों/आदेशों पर अमल के बारे में मंत्रालय के मुख्य सचिवालय और विभिन्न मीडिया इकाइयों से जानकारी प्राप्त की गई। वर्ष 2016–17 की स्थिति निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	मीडिया इकाइयां	वर्ष 2016–17 के लिए कैट से प्राप्त आदेशों की संख्या	वर्ष 2016–17 में लागू किए गए फैसलों और आदेशों की संख्या
1	'मुख्य सचिवालय'	5	4@
2	महानिदेशकः विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	1	1
3	प्रकाशन विभाग	2	0**
4	पत्र सूचना कार्यालय	2	1
5	गीत एवं नाटक प्रभाग	0	0
6	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	5	5
7	भारत के समाचार पत्रों का पंजीयक	0	0
8	फोटो प्रभाग	0	0
9	न्यू मीडिया विंग	0	0
10	भारतीय प्रेस परिषद	#	#
11	भारतीय जन–संचार संस्थान	1	0***
12	महानिदेशक : आकाशवाणी (सीसीडब्ल्यू सहित)	98	45
13	महानिदेशक : दूरदर्शन	58	30
14	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लि.	0	0
15	केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	1	1
16	सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान	1	1
17	भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान	0	0
18	फिल्म प्रभाग	1	0^
19	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	0	0
20	भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	0	0
21	भारतीय बाल फिल्म समिति	0	0
22	फिल्म समारोह निदेशालय	0	0
23	वेतन एवं लेखा कार्यालय	#	#
24	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर	#	#
	कुल	175	88

* एफ (ए) डेस्क के एक केस को माननीय कैट द्वारा बंद किया गया।

@ दोनों ही आवेदन रद्द होने की स्थिति में, किसी भी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

** आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

*** दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा रही है।

^ केस रद्द कर दिया।

आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी नई दिल्ली में 'इंक्लूसिव इंडिया सम्मिट– 2017' को संबोधित करते हुए

18 ;ktuk ifj0;;

योजना परिव्यय (2017-18):

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संबंध में केंद्रीय क्षेत्र योजना परिव्यय वर्ष 2017-18 के लिए 840 करोड़ रुपये जीबीएस था।

(करोड़ ₹ में)

क्रम संख्या	क्षेत्र	जीबीएस
1	सूचना क्षेत्र	180.00
2	फिल्म क्षेत्र	207.00
3	प्रसारण क्षेत्र	453.00
	कुल	**840.00**

2. योजना-वार वार्षिक योजना 2017-18 का विवरण संलग्न है।

3. पूर्वोत्तर घटक में 84.20 करोड़ रूपये केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए निर्धारित 840 करोड़ रुपये की कुल योजना परिव्यय (जीबीएस) के 10 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। पूर्वोत्तर घटक का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ ₹ में)

सूचना क्षेत्र	
पीआईबी	0.80
डीएवीपी	11.15
आईआईएमसी	2.00
फोटो डिविजन	0.05
डीएफपी	0.50
एस एंड डीडी	0.50
फिल्म क्षेत्र	
एसआरएफटीआई	14.00
मुख्य सचिवालय(फिल्म इकाई योजना)	3.00
प्रसारण क्षेत्र	
आकाशवाणी	25.00
दूरदर्शन	27.00
मुख्य सचिवालय (प्रसारण)	0.20
कुल-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	**84.20**

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
बजट अनुमान 2017-18 (योजना-वार) का विवरण

(करोड़ ₹ में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	कुल योजना प्रावधान (2017—18)	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रावधान (2017—18)	बजट आकलन में दर्शाए गए प्रावधान (2017—18)
1	2	3	4	5
	सूचना क्षेत्र			
A	**मौजूदा जारी योजनाएं**			
1	नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस सेंटर की स्थापना (पीआईबी)	0.00	0.00	0.00
2	आईआईएमएसी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नयन (आईआईएमसी)	4.00	0.00	4.00
3	सूचना भवन का निर्माण (MS)	0.00	0.00	0.00
	कुल	**4.00**	**0.00**	**4.00**
B	**नई योजनाएं**			
4	**मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम**			
4.1	डीएवीपी का सुधार और पुनर्गठन (डीएवीपी)	3.25	0.00	3.25
4.2	पीआईबी का आधुनिकीकरण (पीआईबी)	5.00	0.00	5.00
4.3	आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्रों की शुरुआत (आईआईएमसी)	14.00	2.00	12.00
4.4	प्रकाशन प्रभाग और रोजगार समाचार के पुनर्निर्माण, उन्नयन और आधुनिकीकरण (प्रकाशन विभाग)	6.00	0.00	6.00
4.5	राष्ट्रीय फोटोग्राफी केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष अभियान (फोटो डिवीजन)	1.25	0.05	1.20
4.6	आरएनआई मुख्यालय (आरएनआइ) को सुदृढ़ बनाना	0.50	0.00	0.50
	कुल	**30.00**	**2.05**	**27.95**
5	**विकास संचार और प्रसार**			
5.1	विकास संचार (संकल्पना और प्रसार) के माध्यम से लोगों का सशक्तीकरण (डीएवीपी)	123.20	11.15	112.05
5.2	मीडिया विस्तार कार्यक्रम और विशेष आयोजनों के लिए प्रचार (पीआईबी)	4.00	0.80	3.20
5.3	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी) द्वारा प्रत्यक्ष संपर्क कार्यक्रम	6.00	0.50	5.50
5.4	लाइव कला एवं संस्कृति (एस एंड डीडी)	3.00	0.50	2.50
5.5	सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (एम एस)	4.00	0.00	4.00
	कुल	**140.20**	**12.95**	**127.25**

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल योजना प्रावधान (2017–18)	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रावधान (2017–18)	बजट आकलन में दर्शाए गए प्रावधान (2017–18)
1	2	3	4	5
6	**मानव संसाधन विकास**			
6.1	मानव संसाधन के लिए प्रशिक्षण (प्रसार भारती को छोड़कर)(मुख्य सचिवालय)	4.00	0.00	4.00
6.2	सूचनात्मक मीडिया कार्यक्रम (मुख्य सचिवालय)	0.15	0.00	0.15
6.3	सभी तीन क्षेत्रों के लिए नीति संबंधित अध्ययन, संगोष्ठी, मूल्यांकन आदि (प्रसार भारती छोड़कर) (मुख्य सचिवालय.)	0.15	0.00	0.15
6.4	फिल्म मीडिया इकाई का मानव संसाधन विकास(मुख्य सचिवालय)	1.00	0.00	1.00
6.5	व्यावसायिक सेवा के लिए भुगतान (मुख्य सचिवालय)	0.50	0.00	0.50
	कुल	**5.80**	**0.00**	**5.80**
	समग्र कुल (सूचना क्षेत्र)	**180.00**	**15.00**	**165.00**
	कुल मौजूदा जारी योजनाएं	**4.00**	**0.00**	**4.00**
	कुल नई योजनाएं	**176.00**	**15.00**	**161.00**
	फिल्म क्षेत्र			
A	**मौजूदा जारी योजनाएं**			
7	भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय (एफडी)	8.00	0.00	8.00
8	एसआरएफटीआइ को सहायता अनुदान **(एसआरएफटीआइ) पूर्ण**	0.00	0.00	0.00
	कुल	**8.00**	**0.00**	**8.00**
B	**नई योजनाएं**			
9	**फिल्म क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना विकास कार्यक्रम**			
9.1	सीबीएफसी का उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार तथा प्रमाणन प्रक्रिया (सीबीएफसी)	3.50	0.00	3.50
9.2	सिरी फोर्ट परिसर का उन्नयन (डीएफएफ)	1.00	0.00	1.00
9.3	फिल्म्स डिवीजन के इमारती अवसंरचना का उन्नयन (एफडी)	1.60	0.00	1.60
9.4	जयकर बंगला समे एनएफएआई के बुनियादी ढांचे का उन्नयन और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना	3.00	0.00	3.00
9.5	एफटीआईआई को अनुदान सहायता-एफटीआईआई का उन्नयन और आधुनिकीकरण (एफटीआईआई)	18.00	0.00	18.00
9.6	एसआरएफटीआइ में अवसंरचना विकास (एसआरएफटीआइ)	22.00	14.00	8.00
	कुल	**49.10**	**14.00**	**35.10**

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल योजना प्रावधान (2017–18)	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रावधान (2017–18)	बजट आकलन में दर्शाए गए प्रावधान (2017–18)
1	2	3	4	5
10	**विकास संचार एवं फिल्मी सामग्री का प्रसार**			
10.1	फिल्मोत्सव एव भारत व विदेशों में फिल्म बाजार के जरिये भारतीय सिनेमा को प्रोत्साहन (मुख्य सचिवालय)	20.64	2.00	18.64
10.2	विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्म एवं डाक्यूमंटरी का निर्माण (मुख्य सचिवालय)	17.00	1.00	16.00
10.3	भारतीय सिनेमा का शताब्दी समारोह (मुख्य सचिवालय)	0.00	0.00	0.00
10.4	फिल्म अभिलेखागार की वेबकास्टिंग (एफडी)	0.25	0.00	0.25
10.5	अभिलेखीय फिल्मों और फिल्म सामग्री का अधिग्रहण (एनएफएआई)	2.00	0.00	2.00
	कुल	**39.89**	**3.00**	**36.89**
	मिशन/विशेष परियोजनाएं			
11	**राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (मुख्य सचिवालय)**	50.00	0.00	50.00
12	**पायरेसी विरोधी पहल (मुख्य सचिवालय)**	0.01	0.00	0.01
13	**एनीमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स (मेन सेक्टटी) के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना। (मुख्य सचिवालय)**	60.00	0.00	60.00
	कुल	**110.01**	**0.00**	**110.01**
	समग्र कुल (फिल्म क्षेत्र)	**207.00**	**17.00**	**190.00**
	कुल मौजूदा जारी योजनाएं	**8.00**	**0.00**	**8.00**
	कुल नई योजनाएं	**199.00**	**17.00**	**182.00**
	*क्रम संख्या 10.2 ऊपर के तहत विलय यानी बारहवीं योजना में विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों और डॉक्यूमेंटरी का निर्माण (मुख्य सचिवालय)			
	प्रसारण क्षेत्र			
A	**मुख्य सचिवालय**			
14	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र का सुदृढ़ीकरण (इएमएमसी)	12.00	0.00	12.00
15	भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को समर्थन	4.00	0.20	3.80
16	मंत्रालय में अवसंरचना समर्थन प्रकोष्ठ का डिजिटाइजेशन मिशन के रूप में पुनर्नामांकरण।	5.00	0.00	5.00
17	प्रसारण इकाई का स्वचालन	2.00	0.00	2.00
	कुल (मुख्य सचिवालय)	**23.00**	**0.20**	**22.80**
B	**प्रसार भारती**			
18	प्रसारभारती को सहायता अनुदान	350.00	42.00	308.00
19	किसान चैनल के लिए प्रसार भारती को सहायता अनुदान	80.00	10.00	70.00
	कुल-प्रसार भारती	**430.00**	**52.00**	**378.00**
	कुल प्रसारण क्षेत्र	**453.00**	**52.20**	**400.80**
	बजटीय समर्थन का समग्र योग(सूचना+फिल्म+प्रसारण)	**840.00**	**84.20**	**755.80**

केंद्रीय वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली नई दिल्ली में 2018–2019 का केंद्रीय बजट पेश करने के बाद राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए

माननीय सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नई दिल्ली में आकाशवाणी द्वारा आयोजित 'डा. राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान' समारोह के अवसर पर संबोधित करते हुए

19

ehfM;k bdkbl&okj ctV

ekx l[;k 59&lpuk ,o ilkj.k e=ky;

राजस्व अनुभाग			
वर्ग I केंद्र का स्थापना व्यय (गैर–योजना व्यय)			
			(₹ हजार में)
मीडिया इकाई/क्रियाकलाप नाम	**ब. अ. 2017-18**	**सं. अ. 2017-18**	**ब. अ. 2018-19**
मुख्य शीर्ष .'2251' .सचिवालय सामाजिक सेवा			
मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	**795200**	**611800**	**638500**
मुख्य शीर्ष .'2205' . कला और संस्कृति का प्रमाणन सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सिनेमेटोग्राफी			
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	99000	83400	90400
फिल्म प्रमाणन अपीलीय प्राधिकरण	3300	4800	5100
कुल मुख्य शीर्ष '2205'	**102300**	**88200**	**95500**
मुख्य शीर्ष . '2220' - सूचना, फिल्म और प्रचार			
फिल्म प्रभाग	572300	448200	487200
फिल्म समारोह निदशालय	134200	119900	129800
भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	59950	54000	55500
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निरीक्षण केंद्र	8500	7500	8050
न्यू मीडिया विंग (पूर्व में गवेषण, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग)	33800	21600	23200
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	714200	692500	0
पत्र सूचना कार्यालय (पीओईबी)	735000	663500	693500
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	676000	624600	0
गीत एवं नाटक प्रभाग (एस एंड डीडी)	457000	334000	0
आउटरीच एवं संचार ब्यूरो (बीओसी) (पूर्व में डीएवीपी, डीएफपी एवं एस एंड डीडी)	0	0	1742900
प्रकाशन विभाग	376500	329600	350100
रोजगार समाचार	136000	134000	143600
भारतीय समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार	79500	79550	85300
फोटो प्रभाग	52000	44000	46100
निजी एफएम रेडियो स्टेशन	20000	20000	44800
संचार विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीडीसी) में योगदान	2100	2100	2100
संचार विकास के लिए एशिया प्रशांत संस्थान (एआईबीडी) में योगदान	2600	2600	2600
एसोसिएशन और मूविंग एर्काइविस्ट (एएमआईए) के वार्षिक सदस्यता सबस्क्रिप्शन का भुगतान	40	40	40
एनएफएआई द्वारा अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता में योगदान	210	210	210
कुल: मुख्य शीर्ष '2220'	**4059900**	**3577900**	**3815000**
कुल: केंद्र का स्थापना व्यय	**4957400**	**4277900**	**4549000**

मीडिया इकाई / क्रियाकलाप नाम	ब. अ. 2017-18	सं. अ. 2017-18	ब. अ. 2018-19
			(₹ हजार में)
वर्ग II. केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम (योजना व्यय)			
सूचना क्षेत्र			
आईआईएमसी के अंतरराष्ट्रीय मानकों का उन्नयन	40000	20050	30000
आईआईएमसी के नवीन केंद्रों का उद्घाटन (आईआईएमसी)	140000	121950	130000
मीडिया आधारिक संरचना विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी)	160000	159300	238300
विकास संचार एवं सूचना प्रसार (डीसीआईडी)	1402000	1556200	1820000
मानव संसाधन विकास	58000	58900	66800
कुल (सूचना क्षेत्र)	**1800000**	**1916400**	**2285100**
फिल्म क्षेत्र			
भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय (फिल्म प्रभाग)	80000	109200	0
फिल्म प्रभाग की आधारभूत संरचना का उन्नयन	491000	392000	442000
फिल्मी सामग्री का विकास संचार एवं प्रसार	398900	534400	607400
राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (मुख्य सचि.)	500000	60200	577800
एंडी पायरेसी पहल (मुख्य सचि.)	100	100	10000
एनिमेशन, गेमिंग एवं वीएफएक्स के लिए गुणवत्तापूर्ण केंद्र की स्थापना (मुख्य सचि.)	600000	15400	21200
कुल (फिल्म क्षेत्र)	**2070000**	**1111300**	**1658400**
प्रसारण क्षेत्र			
इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएससी) को सुदृढ़ करना	120000	100000	181000
भारत में सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम को आगे बढ़ाना	40000	10000	40000
मंत्रालय का अवसंरचना सपोर्ट सेल वर्तमान नाम डिजिटाइजेशन मिशन	50000	10000	20000
प्रसारण विंग का स्वचालन	20000	10000	9000
प्रसार भारती को अनुदान सहयोग	3500000	2200000	2600000
किसान चैनल के लिए प्रसार भारती को अनुदान सहयोग	800000	600000	517000
अरुण प्रभा चैनल के लिए प्रसार भारती को अनुदान सहयोग	0	20000	40000
कुल प्रसारण क्षेत्र	**4530000**	**2950000**	**3407000**
कुल केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम	**8400000**	**5977700**	**7350500**
उक्त में से *पूर्वोत्तर के लिए आवंटन*	**842000**	**606300**	**743400**
पूंजी *के अंतर्गत आवंटन*	**291000**	**201200**	**234000**

			(₹ हजार में)
मीडिया इकाई/क्रियाकलाप नाम	**ब. अ. 2017-18**	**सं. अ. 2017-18**	**ब. अ. 2018-19**
वर्ग III. अन्य केंद्रीय व्यय (स्वायत्त निकाय)(गैर योजना व्यय)			
भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) को अनुदान सहयोग	212300	112310	203900
भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) को अनुदान सहयोग	85400	69010	67300
भारतीय बाल फिल्म सोसायटी (सीएफएसआई) को अनुदान सहायता	32000	34700	36000
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे (एफटीआईआई) को अनुदान सहायता	292200	292130	312900
सत्यजीत रे भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता (एसआरएफटीआई) को अनुदान सहायता	143700	143710	164600
प्रसार भारती को अनुदान सहयोग	29967000	25143640	28205600
कुल - अन्य केंद्रीय व्यय (स्वायत्त निकाय)	**30732600**	**25795500**	**28990300**
कुल - मांग संख्या 59	**44090000**	**36051100**	**40889800**

सूचना और प्रसारण सचिव श्री एन.के. सिन्हा नई दिल्ली में मंत्रालय के कर्मचारियों को
'संकल्प से सिद्धि' की शपथ दिलाते हुए

20

lpuk ,o çlkj.k ea=ky; dk laxBfud pkVZ

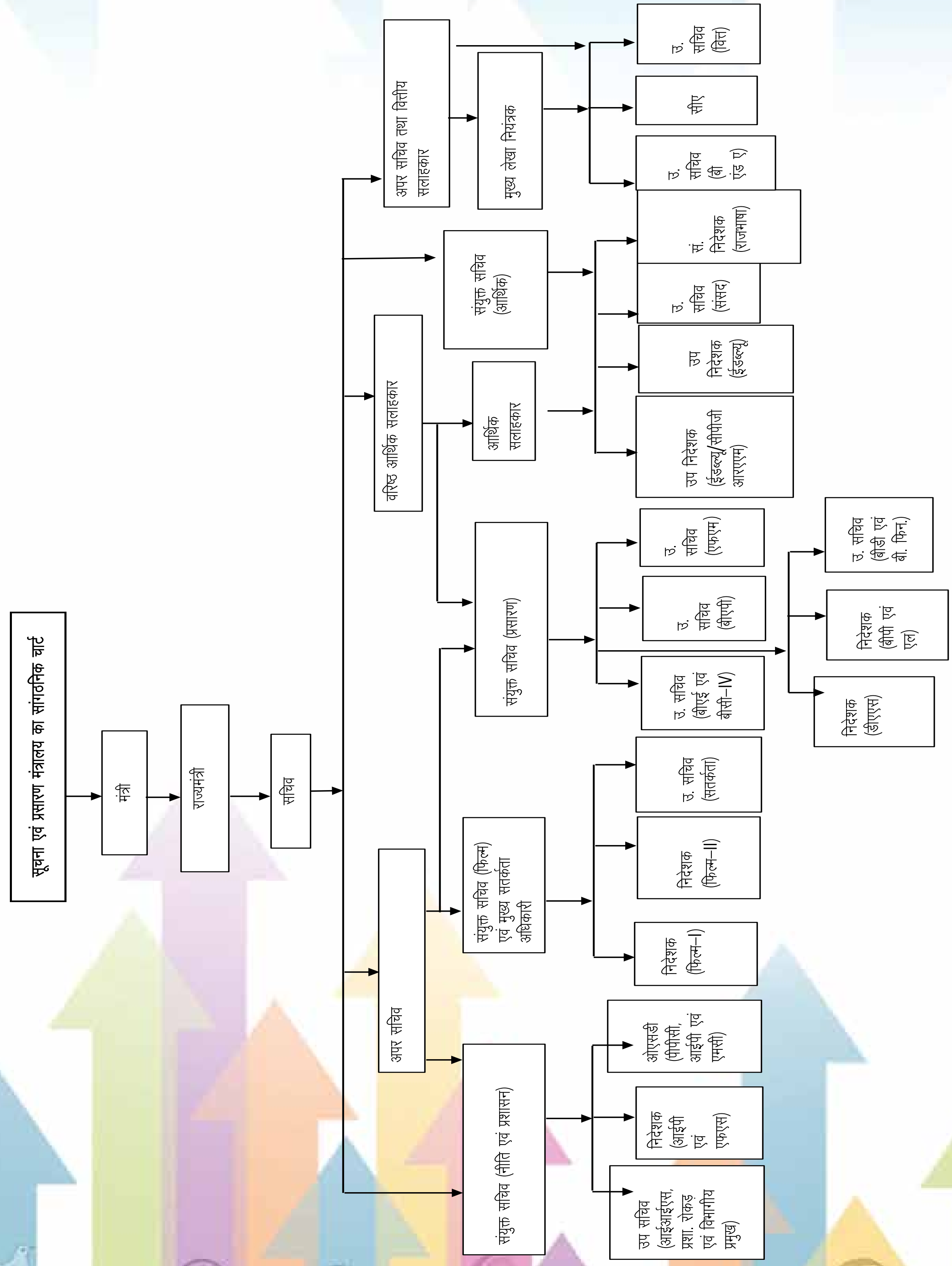

सचिव	सचिव
अप. स/वि.स.	अपर सचिव
अप.स. तथा वि.स.	अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार
व. आर्थिक सलाहकार	वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
सं. स. (नी. तथा प्रशा.)	संयुक्त सचिव (नीति तथा प्रशासन)
सं.स. (प्र.)	संयुक्त सचिव (प्रसारण)
सं. स. (फि.)	संयुक्त सचिव (फिल्म)
सं. स. (आर्थिक शाखा)	संयुक्त सचिव (आर्थिक शाखा)
आर्थिक सलाहकार	आर्थिक सलाहकार
मु.ले.नि.	मुख्य लेखा निरीक्षक
वि.का.अ. (स.)	विशेष कार्य अधिकारी (समन्वय)
निदेशक (फिल्म–1)	निदेशक (फिल्म–1)
निदेशक (फिल्म–2)	निदेशक (फिल्म–2)
निदेशक (प्र.सा.)	निदेशक (प्रसारण सामग्री)
निदेशक (प्र.नी. एवं वि.)	निदेशक (प्रसारण नीति एवं विधिक मामले)
निदेशक (सू.नी. एवं फि.सो.)	निदेशक (सूचना नीति एवं फिल्म सोसायटी)
उप सचिव (प्र.वि. तथा प्र. वित्त)	उप सचिव (प्रसारण विकास तथा प्रसारण वित्त)
उप सचिव (एफ.एम.)	उप सचिव (फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन)
सं. निदेशक (रा.भा.)	संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
उप सचिव (वित्त)	उप सचिव (वित्त)
उप सचिव (बीएपी)	उप सचिव (प्रसारण प्रशासन कार्यक्रम)
उ.स. (भा.सू.से. एवं वि.मु.)	उप सचिव (भारतीय सूचना सेवा, रोकड़, प्रशासन और विभागीय प्रमुख)
उ.स. (डी.ए.एस)	उप सचिव (डिजीटल एड्रेसेबल प्रणाली)
उ.स. (बीएई एवं बीसी–4)	उप सचिव (प्रसारण प्रशासन इंजीनियरिंग एवं प्रसारण सामग्री–4)
उ.स. (ब.ले.)	उप सचिव (बजट एवं लेखा)
उ.स. (स. एवं सं.)	उप सचिव (सतर्कता एवं संसद)
ले.नि.	लेखा नियंत्रक
अ.स. (मी.इ.स.)	अवर सचिव (मीडिया इकाई समन्वय)
अ.स. (एफ.एस.)	अपर सचिव (फिल्म सोसायटी)
अ.स. (प्र. 1, 2, 3, 4 एवं रोकड़)	अवर सचिव (प्रशासन 1, 2, 3, 4 एवं रोकड़)
अ.स. (संसद)	अवर सचिव (संसद)
अ.स. (स.)	अवर सचिव (सतर्कता)
अ.स. (भा.सू.से.)	अवर सचिव (भारतीय सूचना सेवा)
अ.स. (न्यू.मी.वि.)	अवर सचिव (न्यू मीडिया विंग)
अ.स. (नी.यो.प्र., सू.स. एवं मी.स.)	अवर सचिव (नीति योजना प्रकोष्ठ, सूचना नीति एवं मीडिया समन्वय)
अ.स. (प्र.सा. 1, 2 एवं 3)	अवर सचिव (प्रसारण सामग्री 1, 2 एवं 3)
अ.स. (इंसेट टीवी)	अवर सचिव (भारतीय सेटेलाइट टेलीविजन)

अ.स. (प्रे.)	अवर सचिव (प्रेस)
अ.स. (डीएएस)	अवर सचिव (डिजीटल एडरेस्बल सिस्टम)
अ.स. (प्र.नी एवं वि.)	अवर सचिव (प्रसारण नीति एवं विधिक मामले)
अ.स. (प्र.वि एवं प्र.वि.)	अवर सचिव (प्रसारण विकास एवं प्रसारण वित्त)
उ.नि (फ्री.मो.)	उप निदेशक (फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल)
अ.स. (प्र.प्र. का–1)	अवर सचिव (प्रसारण प्रशासन कार्यक्रम–1)
अ.स. (प्र.प्र. का–2)	अवर सचिव (प्रसारण प्रशासन कार्यक्रम–2)
अ.स. (प्र.प्र.अ.)	अवर सचिव (प्रसारण प्रशासन अभियांत्रिकी)
अ.स. (प्र.वि.–4)	अवर सचिव (प्रसारण विकास–4)
अ.स. (वित्त–1 एवं 3)	अवर सचिव (वित्त–1 एवं 3)
अ.स. (वित्त–2)	अवर सचिव (वित्त–2)
अ.स. (ब. एवं ले.)	अवर सचिव (बजट एवं लेखा)
अ.स. (फि.प्र., फि.उ. तथा फि.उ.)	अवर सचिव (फिल्म प्रमाणन, फिल्मोत्सव तथा फिल्म उद्योग)
अ.स. (फि.प्र., एं फि. एवं टे.स., फि.सा.उ)	अवर सचिव (फिल्म प्रशासन, फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, फिल्म एवं सार्वजनिक उपक्रम)
उ.नि. (आ.शा.–1)	उप निदेशक (आर्थिक शाखा–1)
उ.नि. (आ.शा.–2)	उप निदेशक (आर्थिक शाखा–2)
स.नि. (रा.भ.–1)	सहायक निदेशक (राजभाषा–1)
स.नि. (रा.भ.–2)	सहायक निदेशक (राजभाषा–2)
उ.नि. (स.रे.के.)	उप निदेशक (सामुदायिक रेडियो केंद्र)
प्र.–1	प्रशासन–1
प्र.–2	प्रशासन–2
प्र.–3	प्रशासन–3
प्र.–4	प्रशासन–4
रोकड़	रोकड़
संसद	संसद
मी.इ.प्र.	मीडिया इकाई प्रकोष्ठ
फि.सो. डेस्क	फिल्म (सोसाइटी) डेस्क
रा.भा.ई.	राजभाषा इकाई
सतर्कता	सतर्कता
सू.नी. एवं मी.स.	सूचना नीति एवं मीडिया समन्वय
नी.नि.प्र.	नीति नियोजन प्रकोष्ठ
प्रेस	प्रेस
भा.सू.से.	भारतीय सूचना सेवा
फि.(स.) डेस्क	फिल्म (समारोह) डेस्क
फि. (फि. एवं टेली.सं.) डेस्क	फिल्म (फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान) डेस्क
फि. (प्रशा.) डेस्क	फिल्म (प्रशासन) डेस्क
फि. (प्रमा.) डेस्क	फिल्म (प्रमाणन) डेस्क
फि. (उ.) डेस्क	फिल्म (उद्योग) डेस्क

फि. (सा.उ) डेस्क	फिल्म (सार्वजनिक उपक्रम) डेस्क
प्र.वि.व.–1	प्रसारण विषय वस्तु–1
प्र.वि.व.–2	प्रसारण विषय वस्तु–2
प्र.वि.व.–3	प्रसारण विषय वस्तु–3
प्र.वि.व.–4	प्रसारण विषय वस्तु–4
प्र.(वि.)	प्रसारण (विकास)
प्र.(वि.)	प्रसारण (वित्त)
प्र.नी एवं वि.	प्रसारण नीति एवं विधिक मामले
प्र.प्र.–का.	प्रसारण प्रशासन–कार्यक्रम
एफ.एम.प्र.	फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रकोष्ठ
सा.रे.के. प्र.	समुदाय रेडियो केंद्र प्रकोष्ठ
इन्सेट–टीवी	भारतीय सेटेलाइट टेलीविजन
प्र.प्र.–अ.	प्रसारण प्रशासन–अभियांत्रिकी
वित्त–1 एवं 3	वित्त–1 एवं 3
वित्त–2	वित्त–2
यो.स.प्र.	योजना समन्वय प्रकोष्ठ
ब. एवं ले.	बजट एवं लेखा
का.प्र.अ.	कार्यकुशलता प्रबंधन अनुभाग
एनएमसी	नया मीडिया प्रकोष्ठ
वे. एवं ले. अधि.	वेतन एवं लेखा अधिकारी
सू.सु.का.	सूचना सुविधा काउंटर

lpuk o çlkj.k e=ky; dk vrxr vku okyh oclkbV dk irk

Øekd l[;k	ehfM;k bdkb dk uke	oclkbV
1	पत्र सूचना कार्यालय	www.pib.nic.in
2	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	www.davp.nic.in
3	प्रकाशन विभाग	www.publicationsdivision.nic.in
4	भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक	www.rni.nic.in
5	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	www.dfp.nic.in
6	फोटो प्रभाग	www.photodivision.gov.in
7	भारतीय जन संचार संस्थान	www.iimc.nic.in
8	भारतीय प्रेस परिषद	www.presscouncil.nic.in
9	न्यू मीडिया विंग	
10	प्रसार भारती i. दूरदर्शन ii. आकाशवाणी	www.prasarbharati.gov.in www.ddindia.gov.in www.allindiaradio.gov.in
11	गीत एवं नाटक प्रभाग	
12	फिल्म समारोह निदेशालय	www.dff.nic.in
13	ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियर्स कंसलटेंट लिमिटेड(बेसिल)	www.becil.com
14	फिल्म प्रभाग	www.filmsdivision.org
15	बाल चित्र समिति, भारत	www.cfsindia.org
16	भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान	www.ftiindia.com
17	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	www.nfdcindia.com
18	केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	www.cbfcindia.gov.in
19	सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान	www.srfti.gov.in
20	भारतीय फिल्म अभिलेखागार	www.nfaipune.gov.in
21.	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर	www.emmc.gov.in

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के खंड–2 का प्रकाशन रोका जाना

लोकसभा सचिवालय के ओ.एम. संख्या 61/2/ईसी/2009 दिनांक 18.12.2009 द्वारा सूचित संसदीय प्राक्कलन समिति की अनुशंसाओं के अनुसरण में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के खंड–2 का प्रकाशन वर्ष 2009–10 से बंद कर दिया गया है।

हालांकि यह मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in या www.mib.nic.in पर उसी प्रारूप में उपलब्ध है, जैसे कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के खंड–2 में पहले प्रकाशित किया जाता था।